



प्रातः स्मरणीय, पूजनीय एवं स्नेहमयी
माँ स्वर्गीय श्रीमती रामकली शर्मा की
पुण्य स्मृति में सादर समर्पित

समष्टि आर्थिक सिद्धान्त

(MACRO ECONOMIC THEORY)



लेखक

डॉ. एस. सी. शर्मा
रीडर एवं अध्यक्ष अर्थशास्त्र
स्नातकोत्तर एवं शोध अध्ययन विभाग,
नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भोर्गांव (मैनपुरी)
आगरा विश्वविद्यालय

द्वितीय संस्करण

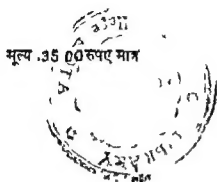
1994

रत्न प्रकाशन मन्दिर

पुस्तक प्रकाशक एवं विंड्रेता

1/185-A, प्रोफेसर कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा-282 002

● लेखक एवं प्रकाशक



प्रकाशक : रतन प्रकाशन मन्दिर

1/185-A, प्रोफेसर कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा-282 002

शाखाएँ :

आगरा	:	अस्पताल मार्ग
दिल्ली	:	21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज
फानपुर	:	तिलक हॉल लेन, मेस्टन रोड
लखनऊ	:	इन्दिरा मार्केट, अमीनाबाद
गोरखपुर	:	18, प्रतिभा कॉम्प्लेक्स, भवशीपुर
मेरठ	:	वेस्टर्न कचहरी रोड
वाराणसी	:	K-62/106, जवाहर मार्केट, सप्तसागर
जयपुर	:	बिचून मार्केट, किशन पोल बाजार

प्रथम संस्करण की प्रस्तावना

वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के अध्ययन को व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ा जाता है। मर्यादित आर्थिक सिद्धान्त की प्रस्तुत पुस्तक अध्यात्म की ११ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमानुसार तैयार की गई है। वैसा ना मर्यादित अध्यात्म पर उनका पस्तक उपलब्ध हैं और उन पर टीका टिप्पणी करना उपयोग नहीं है। नसक का वर्तमान पुस्तक लिखन म यह प्रयास रहा है कि यह पुस्तक स्नातक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी उनकी आवश्यकताओं एवं आवेक्षाओं के मानदण्डों पर सही होगी।

प्रस्तुत पुस्तक का 20 अध्यायों में विभक्त किया गया है। मर्यादित अध्यात्म में सम्बन्धित जटिल समस्याओं का सरल में सरल भाषा शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिसमें स्नातक विद्यार्थीगण समष्टि अध्यात्म का महत्त्व पहचानने की आधारों से समझ लें। प्रत्येक अध्याय के अंत में सम्बन्धित अध्याय की सामग्री के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Questions) का समावेश किया गया है। वर्तमान प्रतिपादिता के युग में विद्यार्थियों को अपने अध्ययन तथा डिग्री प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्ति हेतु परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होती हैं। इन परीक्षाओं की सफलता के बाद उन्हें साक्षात्कार चयन बोर्ड के समक्ष जाना होता है। एक विद्यार्थी की दृष्टि से यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनकी सफलता के लिए अर्थशास्त्र जैसे तकनीकी एवं व्यावहारिक विषय के लिए कौड़ी साबित होंगे। ऐसा विश्वास लेखक को है। विद्यार्थियों की सफलता से सम्बन्धित एक अन्य सामग्री प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट। में परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें के रूप में दी गई है। इसमें उन्हें परीक्षा भवन में प्रश्नों के चुनने से लेकर आदर्शात्मक उत्तर देने तक की प्रक्रिया को समझाया गया है।

लेखक यह तो दावा नहीं करता कि यह पुस्तक अपने में सभी दृष्टि में पूर्ण होगी परन्तु उसका प्रयास पुस्तक को उत्तम से उत्तम तथा आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। विद्वान अध्यापक बन्धु एवं अन्य सज्जनबुद्ध इस पुस्तक को उपयोगी समझेंगे इस विश्वास के साथ लेखक का यह प्रयास उनके विश्लेषण हेतु प्रस्तुत है। सह लेखक के रूप में लेखक की मुद्रा बैंकिंग तथा मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व स्नातक कक्षाओं के लिए, आर्थिक विचारों का इतिहास एवं मुद्रा की रूपरेखा तथा एवमात्र लेखक के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रयासित हो चुकी है जिनको अर्थशास्त्र के विज्ञान विचारों द्वारा सराहा गया है। यही लेखक के लिए उनका सन्नेह पुरस्कार है।

पुस्तक लेखन के प्रेरणास्रोत मेरे अनेक बन्धु शुभचिंतक एवं परिवारीजन रहे हैं। उनकी स्नेहपूर्ण शुभ कामनाएँ सदा मेरे मार्ग के अवरोधकों को पार करने में मेरे लिए बड़ा सहारा रही हैं। पूजनीय माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहा तथा जो रोग शय्या पर होते हुए भी मेरी तथा मेरे कार्य की प्रगति के लिए चिंतित रहती थी। मैं अपनी धर्म पत्नी श्रीमती गायत्री शर्मा का उल्लेख अवश्य करूँगा जिन्होंने मुझे लेखन कार्यावधि में पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रखा। मेरी बच्ची चिन्मी जो अभी अबोध है वह भी मेरे कार्यों में जाने-अनजाने अपना सहयोग देती रही है। मैं अपने श्वशुर श्री ब्रज बिलाम शर्मा वैद्य तथा माम श्रीमती कमला शर्मा का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने प्रीष्ठावकाश से पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु मुझे बाछनीय सुविधाएँ तो प्रदान की ही साथ ही अपना स्नेह एवं शुभकामनाएँ भी दी हैं। मैं अपने मित्र एवं शुभचिंतक श्री विनोद कुमार वर्मा यानपुर का उल्लेख करना चाहूँगा जो मेरे कार्य की

प्रगति के लिए सदैव अपनी शुभकामनाएँ देते रहे हैं । अन्त में, मैं अपने प्रकाशक श्री प्रेम चन्द जैन का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने वर्तमान पुस्तक के लेखन हेतु मुझे निमन्त्रण दिया । उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं एवं बढ़ते हुए दायित्वों के बाद भी पुस्तक को यथामय प्रकाशित करके पाठकगणों के समक्ष रखकर महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान दिया है ।

पुस्तक से सम्बन्धित रचनात्मक सन्भावों की प्रतीक्षा लेखक के लिए मार्गदर्शक होगी ।

नटराज होटल बिल्डिंग,
मैनपुरी-205001
उत्तर प्रदेश ।

— एस. सी. शर्मा

विषय-सूची (CONTENTS)

समष्टि अर्थशास्त्र (MACRO ECONOMICS)

<p>समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics)</p> <p>व्यष्टि अर्थशास्त्र, परिभाषाएँ, विषय क्षेत्र, लाभ एवं महत्व, सीमाएँ, समष्टि अथवा व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ, लाभ एवं महत्व, सीमाएँ एवं दाय, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता, समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न ।</p> <p>राष्ट्रीय आय (National Income)</p> <p>राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ एवं उनकी आलोचनाएँ, राष्ट्रीय आय की अन्य धारणाएँ—कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, वैयक्तिक आय, उपभोग्य आय, वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय का माप-उत्पादन प्रणाली, आय प्रणाली, व्यय प्रणाली, राष्ट्रीय आय की गणना की अन्य प्रणालियाँ, सामाजिक लेखांकन का प्रस्तुतीकरण, मिश्रित प्रणाली, राष्ट्रीय आय के माप के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ, अर्द्ध विकसित देशों में राष्ट्रीय आय की माप सम्बन्धी कठिनाइयाँ, राष्ट्रीय आय विश्लेषण का महत्व, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का वास्तविक सूचकांक नहीं है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि की कसौटी, भारत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समिति, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सम्बन्धी कठिनाइयाँ, परीक्षा-प्रश्न ।</p> <p>बेरोजगारी तथा पूर्ण रोजगार (Unemployment and Full Employment)</p> <p>बेरोजगारी का अर्थ, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार—संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण—अग्रन्ध नीति सिद्धान्त, न्यून माँग सिद्धान्त, व्यापार चक्रीय सिद्धान्त—अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणा, कीन्स की धारणा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा, मरुत्त राष्ट्र सप, र्ण रोजगार के मुख्य तत्व, अर्द्ध-विकसित देश तथा पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार की नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, अन्य उपाय एवं नीतियाँ, निष्कर्ष, रीक्षा-प्रश्न ।</p> <p>रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical Theory of Employment)</p> <p>मिथा, जे. बी. मे. रा. बाजार नियम, मान्यताएँ, मुख्य तत्व, आलोचनाएँ, प्रो. मे. के. यम की क्रियाशीलता, पीगू का भजदरी यटौती सम्बन्धी रोजगार सिद्धान्त,</p>	<p>1-11</p> <p>12-27</p> <p>28-40</p> <p>41-51</p>
--	--

आलोचनाएँ, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त एक दृष्टि में, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की आलोचनाएँ प्रतिष्ठित तथा प्रो. कीन्स की विचारधाराओं में अन्तर, परीक्षा-प्रश्न।

1. **कीन्स का रोजगार सिद्धान्त (Keynesian Theory of Employment)** 52-68
कीन्स विश्लेषण की मान्यताएँ, प्रभावपूर्ण माँग, प्रभावपूर्ण माँग के निर्धारक तत्व – कुल माँग फलन, कुल पूर्ति फलन, कुल माँग फलन तथा कुल पूर्ति फलन का सापेक्षिक महत्व, कीन्स का रोजगार सिद्धान्त, रोजगार का निर्धारण, बचत एवं विनियोग दृष्टिकोण, सिद्धान्त की आलोचनाएँ, कीन्स के सिद्धान्त का महत्व – सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्व, कीन्स का सिद्धान्त तथा अल्प-विकसित देश, कीन्सवादी चरों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध, कीन्सवादी रोजगार मॉडल में स्वतन्त्र तथा निर्भर चर, कीन्स के रोजगार सिद्धान्त की प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त से श्रेष्ठता, परीक्षा-प्रश्न।
2. **उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति (Consumption Function or Propensity to Consume)** 69-81
कीन्सवादी उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, मान्यताएँ, सिद्धान्त का अभिप्राय, चिरकालिक स्थिरता, उपभोग क्रिया का अर्थ, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपभोग क्रिया या फलन, औसत तथा सीमात उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग क्रिया को आय के अलावा प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, वस्तुनिष्ठ तत्व, ध्येयनिष्ठ तत्व, साधारण उपभोग फलन के परिष्कार, प्रो. ह्यूसेन बेरी परिष्कृत, परीक्षा-प्रश्न।
3. **विनियोग क्रिया (The Investment Function)** 82-91
विनियोग का अर्थ, नियोजित तथा अनियोजित निवेश, निवेश का महत्व, कुल तथा शुद्ध निवेश, निवेश के प्रकार, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, निवेश को निर्धारित करने वाले तत्व, परीक्षा-प्रश्न।
4. **पूँजी की सीमान्त क्षमता (Marginal Efficiency of Capital)** 92-99
परिभाषा, पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले अल्पकालीन तत्व, पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक तत्व, आशासाएँ तथा पूँजी की सीमान्त क्षमता, पूँजी की सीमान्त क्षमता विचार की आलोचना, परीक्षा-प्रश्न।
5. **तरलता पसंदगी तथा ब्याज की दर (Liquidity Preference and the Rate of Interest)** 100-110
तरलता पसंदगी का अर्थ, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धान्त, ब्याज एक मौद्रिक तत्व है, तरलता पसंदगी वक्र, तरलता वक्र, तरलता जाल, मुद्रा की माँग – सौदा उद्देश्य, मर्तकता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य, मुद्रा की पूर्ति, सिद्धान्त की आलोचनाएँ, प्रतिष्ठित तथा तरलता पसंदगी सिद्धान्तों की तुलना, ब्याज की दर का निर्धारण, परीक्षा-प्रश्न।
6. **गुणक (Multiplier)** 111-123
गुणक – एककालिक गुणक, अवधि गुणक, गुणक में सामयिक परिवर्तन, गुणक के प्रभाव में शक्ति, गुणक की आलोचना, गुणक सिद्धान्त का महत्व, एक अर्द्ध-विकसित देश तथा गुणक, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न।
7. **त्वरक (Accelerator)** 124-132
त्वरक का अर्थ, त्वरक तथा गुणक में अन्तर, त्वरक की क्रियाशीलता, त्वरक

सिद्धान्त की सीमाएँ त्वरक सिद्धान्त का महत्व त्वरक सिद्धान्त की आलोचनाएँ
गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया परस्पर क्रिया का महत्व, परीक्षा-प्रश्न ।

- 12 मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य (Definition and Functions of Money) 133-146
मुद्रा क्या है ? मुद्रा की परिभाषा—वर्णनात्मक परिभाषाएँ वैधानिक परिभाषाएँ
सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ परिभाषा से सम्बन्धित विभिन्न
दृष्टिकोण, परिभाषाओं की कतिपय सीमाएँ—मुद्रा के कार्य मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण
1 तथा 11, परीक्षा-प्रश्न ।

- 13 मुद्रा का चक्राकार प्रवाह एवं महत्व (Circular Flow and Importance of Money) 147-161

मुद्रा का चक्राकार प्रवाह सन्तुलन की समस्या सरकार तथा गति का आकार । मुद्रा
का महत्व—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा एक निर्योजित
अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व मुद्रा के दोष मुद्रा का नियन्त्रण परीक्षा-प्रश्न ।

- 14 मुद्रा की पूर्ति तथा माँग (The Supply of and the Demand for Money) 162-173

मुद्रा की माँग—कीन्स तथा प्रीडमैन की व्याख्या मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की प्रभावी पूर्ति
मुद्रा का चलन वेग मुद्रा के प्रचलन वेग को निर्धारित करने वाले कारण मुद्रा की
पूर्ति में परिवर्तन, बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप
शक्तिशाली मुद्रा परीक्षा प्रश्न ।

- 15 मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) 174-197

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त—लेन-देन दृष्टिकोण फिशर की व्याख्या मुद्रा का
चलन-वेग फिशर के सिद्धांत की मान्यताएँ फिशर के सिद्धान्त की आलोचनाएँ
सिद्धान्त की ऐतिहासिक पुष्टि, कैम्ब्रिज अधशास्त्रिया का दृष्टिकोण—प्रो माशल,
प्रो पीगू, प्रो राबर्टसन तथा प्रो कीन्स के समीकरण नवद शोध समीकरण की
आलोचनाएँ फिशर की व्याख्या तथा कैम्ब्रिज व्याख्या की तुलना दोनों समीकरणों
में समानता असमानताएँ, दोनों समीकरणों में कौन ना थोड़ा है परीक्षा प्रश्न ।

- 16 स्फीति तथा अवस्फीति (Inflation and Deflation) 198-236

स्फीति की परिभाषा पूर्ण तथा आंशिक स्फीति स्फीति की विशेषता स्फीति के
प्रकार माँग प्रेरित बनाम लागत बद्ध स्फीति स्फीति अंतराल मन्दी स्फीति स्फीति
का कारण स्फीति के प्रभाव स्फीति को रोकने का उपाय अद्ध विकसित अर्थव्यवस्था
में स्फीति स्फीति तथा आर्थिक विकास अवस्फीति की परिभाषा अवस्फीति का
प्रभाव अवस्फीति को रोकने के उपाय स्फीति तथा अवस्फीति के बीच चुनाव
परीक्षा-प्रश्न ।

- 17 व्यापारिक बैंक तथा साख निर्माण (Commercial Banks and Credit Creation) 237-256

बैंकों का महत्व बैंक तथा आर्थिक विकास अद्ध-विकसित देशों में बैंकों का महत्व
बैंकों का वर्गीकरण—व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक कृषि
बैंक, यक्षत बैंक, केन्द्रीय बैंक अन्तराष्ट्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य, बैंक द्वारा
साख-मुद्रा का निर्माण, साख निर्माण शक्ति की सीमाएँ साख सृजन सिद्धान्त की
आलोचना, परीक्षा प्रश्न ।

18 कन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य (Central Bank and its Functions) 257-279

गणितीय पृष्ठभूमि कन्द्रीय बैंक की परिभाषा कन्द्रीय बैंक के कार्य नाट निगमन का कार्याधकार सरकारी बैंकर गजन्त एवं सैलाहवार बैंक का बैंक राष्ट्र की अन्तर्गष्ट्रीय मुद्रा का सरक्षक सदस्य बैंक का समाशाधन गृह अंतिम वृण दाना मास का नियन्त्रण मास नियन्त्रण मास नियन्त्रण की आवश्यकता परिभाषात्मक विधियाँ - बैंक दर नीति की सीमाएँ हाल बाजार की क्रियाएँ न्यूनतम वैध आरक्षण अनपात तरल कापानुपात - मास नियन्त्रण की गुणात्मक विधियाँ - मास मुद्रा गशानिग प्रत्यक्ष कार्यवाही नैतिक अनुयथ चयनात्मक मास नियन्त्रण उद्देश्य विज्ञापन एवं प्रचार अट्ट विकसित अर्थव्यवस्था में कन्द्रीय बैंक परीक्षा-प्रश्न ।

19 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) 280-296

रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य संगठन तथा प्रबन्धन रिजर्व बैंक के विभाग रिजर्व बैंक के कार्य रिजर्व बैंक मास नियन्त्रण में अमपन्न चरा म्हा रिजर्व बैंक तथा अनुमूर्चित बैंक रिजर्व बैंक तथा औसागिक वित्त रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त रिजर्व बैंक की मपन्नताएँ रिजर्व बैंक की अमपन्नताएँ परीक्षा प्रश्न ।

20 व्यापार चक्र (Trade Cycle) 297-309

व्यापार चक्र की परिभाषा व्यापार चक्र के रूप व्यापार चक्र की अवस्थाएँ समृद्धि अवस्था मम्नी अवस्था मदी अवस्था चतना अवस्था व्यापार चक्र नियन्त्रण मध्यमधी नीति निष्पत्ति परीक्षा प्रश्न ।

"There is really no opposition between Micro and Macro Economics Both are absolutely vital You are only half educated if you understand the one while being ignorant of the other " —Samuelson

अध्याय 1

समष्टि अर्थशास्त्र

(MACRO ECONOMICS)

वर्तमान समय में अर्थशास्त्रीय अध्ययन को प्रमुख रूप से व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में बाँटा जाता है। वर्ष 1933 में इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग ओमर्तो विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर रेनर फिश (Prof Raenar Frisch) ने किया था। वर्तमान समय में आर्थिक विश्लेषण के यह शब्द अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का आशय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की छोटी अथवा सघु १६ इयों में होता है। दूसरी ओर समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र का आशय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इसके बड़े-बड़े समूहों जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन कुल राष्ट्रीय आय कुल रोजगार कुल उपभोग, कुल विनियोग कुल बचत, सामान्य कीमत स्तर आदि से होता है। इसके अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय, व्यापार चक्र राजस्व बैंकिंग आदि बहुत से ऐसे विषय हैं जो समष्टि अथवा व्यापक आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत आते हैं।

व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र

(Micro Economies)

व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं जैसे एक फर्म एक उद्योग, एक व्यक्ति एक परिवार आदि। इसके अन्तर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति की स्थिति क्या है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति अपनी आय किस प्रकार अर्जित और व्यय करता है, एक फर्म किस प्रकार से सामर्थ्य की स्थिति को प्राप्त करती है एक उद्योग की उद्योग में रोजगार, उत्पादन तथा बिक्री आदि की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत या सघु इकाइयों के संगठन, स्वरूप एवं उनके व्यवहार से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करते हैं। इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय संतुलन स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम कीमत विश्लेषण में एक उत्पादन या साधन की कीमत का अध्ययन करते हैं न कि सामान्य कीमत स्तर का। इसी प्रकार भूमि विश्लेषण में हम एक व्यक्ति- एक फर्म एक परिवार तथा एक उद्योग की भूमि का अध्ययन करते हैं सामूहिक अथवा समुदाय विशेष की भूमि का अध्ययन नहीं करते। आय विश्लेषण में हम एक व्यक्ति एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग की आय का अध्ययन करते हैं सम्पूर्ण या समुदाय की कुल आय का अध्ययन नहीं करते।

व्यक्ति के पास जैसे-जैसे किसी वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं उनके प्राप्ति उपयोगिता या मनुष्टि का स्तर उन्नततर गिरता जाता है। इसी प्रकार एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम मनुष्टि का स्तर कैसे प्राप्त करेगा आदि का अध्ययन वमन घटती हुई सीमान्त उपयोगिता नियम तथा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के उदाहरण हैं तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री है। एक उपभोक्ता की भाँति एक उत्पादक भी अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ तभी प्राप्त करेगा जबकि प्रत्येक साधन से प्राप्त सीमांत उत्पादनमा तथा उस साधन पर किया गया व्यय दोनों बराबर नहीं हो जाते जैसा कि प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में एक पद तथा एक उद्योग की उत्पादन तथा मूल्य सम्बन्धी नीति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आता है। विनिमय के क्षेत्र में एक वस्तु की कीमत निर्धारण तथा एक बाजार विशेष से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन तथा वितरण के क्षेत्र में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पारिश्रमिक आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से सम्बन्धित अध्ययन कहलायेगा।

व्यष्टि अर्थशास्त्र का लाभ एवं महत्व (Advantages & Importance of Micro Economics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक रूप धारण के समय से ही प्रारम्भ हो चुका है। इसका उपयोग विभिन्न आर्थिक नियमों के निर्माण तथा सिद्धान्तों के विवेचन हेतु किया गया है। मक्रो अर्थशास्त्र का प्रयोग आजकल बहुत बढ़ गया है फिर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्त्व विन्यून नगमना नहीं हुआ है। इसका महत्त्व निम्न बातों से पता चलता है -

(1) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने हेतु—मूल्य अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में सहायक होता है। जैसे हम देश के सामान्य कीमत स्तर (General Price Level) को समझने के लिए व्यतिरिक्त कीमतों का भी अध्ययन करना होगा। ठीक इसी प्रकार से देश की कुल राष्ट्रीय आय को समझने के लिए व्यक्तिगत आयों का अध्ययन जरूरी है।

(2) वस्तु के मूल्य निर्धारण में सहायक—व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है एक उत्पत्ति के साधन का पुरस्कार कैसे निश्चित होता है आदि। एक वस्तु के मूल्य निर्धारण तथा एक साधन की कीमत निर्धारण के अध्ययन में हम माँग और पूर्ति की गतियों का अध्ययन करते हैं अर्थात् कीमत निर्धारण माँग और पूर्ति के मनुष्टन द्वारा होता है। जिस बिन्दु पर माँग और पूर्ति साम्य की स्थिति में होयी वही पर साधन या वस्तु की कीमत निश्चित होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक उत्पादक एक साधन को जो कीमत देता है वह उस साधन की सीमान्त उत्पादकता द्वारा निश्चित होती है। इसी प्रकार एक वस्तु की कीमत सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत (MR तथा MC) के बराबर होने के बिन्दु पर निश्चित होगी।

(3) आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक—व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। जब सरकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है तो इसके प्रभाव को साधनों के वितरण, व्यक्तिगत कीमतों, आयों तथा मजदूरियों पर हमारे प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि सरकार की नीतियाँ समाज के निम्न वर्ग के विरुद्ध हों, तो सुम्ने उनमें सुधार करके उनको पुनर्निर्मित किया जाता है। देश का दिन मन्त्री जब करारोपण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि बरों का बोझ समाज के नीचे या कम आय वाले वर्ग पर कम से कम रहे।

(4) व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायक—
व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति एक कम एक परिवार तथा एक उद्योग आदि का आर्थिक व्यवहार कैसा होगा। जैसे एक उत्पादक का यही प्रथम स्टेप कि वह न्यूनतम लागत मयों पर उत्पत्ति के विभिन्न माध्यमों को आदर्श अनुपात में मिलाकर अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। उसी प्रकार एक उपभोक्ता को अपने सीमित माध्यम में अधिकतम मनुष्यता तभी मिलेगी जबकि विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली अन्तिम इकाइया में उसे सीमान्त उपयोगिता बराबर मिले। यदि उपभोक्ता का व्यवहार इस प्रकार का न होगा तो वह अधिकतम मनुष्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें व्यक्तिगत उपभोग बचत आय, विनियोग आदि की जानकारी देकर उनके आर्थिक व्यवहार में निर्णय लेने में सहायता करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कर्मों तथा उद्योगों की राय प्रणाली उनकी समस्याओं तथा इनमें निपटने हेतु समाधानों का अध्ययन भी करता है।

(5) आर्थिक कल्याण में सहायक - आर्थिक कल्याण की जानकारी प्राप्त करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण के मापन हेतु व्यष्टि आर्थिक विवरणों का महत्त्व दिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जैसे बचत उपभोग आय विनियोग आदि के माप-माप मावजनित व्यय तथा मावजनिक आय का समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी मिलती है। यदि मावजनिक व्यय ने हानि देने वाले लाभ मावजनिक आय में होने वाले बाँटों की तुलना में अधिक हैं तो निश्चित रूप से यह समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक होगा यदि स्थिति इससे विपरीत होगी तो आर्थिक कल्याण पड़ने की ओर निश्चित रूप से कम होगा।

व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitations of Micro Economics)

जहाँ एक ओर व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है वहाँ उसकी कुछ कमियाँ या सीमाएँ भी हैं जैसे—

(1) व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता—
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। बल्कि यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण की रचना व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा होती है परन्तु इनमें हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र नहीं मिलता। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके ही हम सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सही प्रकार में समझ सकते हैं। इसलिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए अपर्याप्त मानित होता है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों पर सीमित रहता है जो गुरुचित्त होता है।

(2) व्यष्टि अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होते—

प्रायः यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण को बनाने वाली व्यक्तिगत इकाइयाँ ही हैं इसलिए जो निष्कर्ष एक व्यक्तिगत इकाई के लिए उचित हैं वह सम्पूर्ण के लिए स्वतः ही उचित समझने चाहिये। यह तथ्य धारक है कि जो बात व्यक्तिगत दृष्टिकोण में सही हो वह सम्पूर्ण के लिए भी सही ही हो जैसे बचत करने उसका विनियोग न करना एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा कहा जाएगा परन्तु यदि सभी वचतकर्ताओं का व्यवहार ऐसा होगा तो इससे बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आ जायेंगी क्योंकि इसमें कुल समर्थ भाग में कमी निम्ने परिणामस्वरूप कुल उत्पादन, कुल रोजगार तथा कुल आय का स्तर गिरेगा।

(factors) की व्याख्या की तथा अर्थव्यवस्था का मदी म उवाग्न हतु ठोम मुनाय दिग । कोन्म ने यह मिद किया वि राष्ट्रीय आर्थिक समस्याआ व समाधान समष्टि आर्थिक विश्लेषण म खाजने चाहिए । कोन्म व अतिरिक्त प्रो० वानरम प्रो० गीगू विबमैन प्रा० फिशर तथा अन्य बहुत स विद्वाना न समष्टि अर्थशास्त्र व विबाम म महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ (Definitions of Macro Economics)

समष्टि अर्थशास्त्र म हम सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था या उमम सम्बन्धित औमता तथा समूहा का अध्ययन करत है । कुल माँग कुन पूर्ति कुन उत्पादन कुन राष्ट्रीय आय कुन बचत कुन विनियोग सामान्य कीमत स्तर कुन राजगार आदि का अध्ययन करत ह । समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएँ निम्नवत हैं —

प्रो० के० ई० बोल्डिंग के अनुसार —

समष्टि पक्ष अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राआ का अध्ययन नहीं करता वरन् इन मात्राआ व समूहा का अध्ययन करता ह व्यक्तिगत आय का नहीं वरन् राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत कीमता का नहीं वरन् सामान्य कीमत स्तर का व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं वरन् राष्ट्रीय उत्पादन का । ¹

प्रो० गार्डनर ऐकले के शब्दों मे -

समष्टि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध एक अर्थव्यवस्था म उत्पादन का समस्त मात्रा जैग चरा माधता का किम सीमा तक प्रयाग किया जा रहा है राष्ट्रीय आय व आकार तथा सामान्य कीमत-स्तर स है । ²

प्रो० शेपीरो के अनुसार -

समष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का नाय प्रणाला स सम्बन्धित हाता ह । ³

समष्टि अर्थशास्त्र के लाभ एव महत्व (Advantages & Importance of Macro Economics)

वर्तमान समय म समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत बढ़ गया है । आज दुनिया व मनी दम अपना प्रगति और विकास म मग हुए ह । आर्थिक विश्लेषण व बहुत स महत्वपूर्ण विषया जैम पूण राजगार सामान्य कीमत-स्तर राष्ट्रीय आय कुन उत्पादन कुन

1. 'Macro Economics deals not with individual quantities as such but with the aggregates of these quantities not with individual incomes but with national income not with individual prices but with price level not with individual output but with the national output' — K E Boulding
2. 'Macro Economics concerns with such variables as the aggregate volume of the output of an economy with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with the general price level' — Gardner Ackley
3. 'Macro Economics deals with functioning of the economy as a whole' — Shepiro

बचत कुल रिनिशेष विदेशी विनिमय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मौलिक तथा राजकाषीय नीति भुगतान स तुषन राजस्व औद्योगिक नीति व्यापार चक्र आर्थिक नियोजन धाकि आदि का अध्ययन समष्टि आर्थिक विश्लेषण की विषय-वस्तु हैं। विनी दश के विकास के लिए इन विषयो के अध्ययन एव उनके माय मे आने वाली वैठिनाइय का अध्ययन एव मुशाव आदि के लिए समष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता होत है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एव सामो को निम्न तथ्यो के आधार पर आवा जा सकता है—

(1) सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियो के निर्धारण मे समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका— यतमान यग मे सावजनिक कयों मे विस्तार हुआ है और सरकार को जनता के कल्याण की विभिन्न योजनाए चालू करनी पडती है। सरकार समष्टिगत तत्वा का महायना से विभिन्न आर्थिक योजनाआ का निर्माण करती है जो अग चलकर देश के रोजगार आय उत्पत्ति का माशा विनियोग उपभोग वचत के स्तर को निर्धारित करत ह। अवव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर सरकार समष्टिगत नीतिया बनाती है।

(2) देश के आर्थिक विकास की जानकारी मे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व—किसा भी देश के आर्थिक विकास की जानकारी के लिए हमे समष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन अथवा व्यापक चरो को निर्धारित करने घाने तजो का अध्ययन करना पडत है। राष्ट्रीय विकास को निर्मित करने घाने त जो का अध्ययन करके ही देश की विकासात्मक स्थिति ता अध्ययन सम्भव हा सकता है। विभिन्न देशो की आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण आधार है। देश म स्पीतिक अथवा अवस्पीतिक जानकारी हेतु हमे सामाय कीमत-स्तर का प्रयोग करना पडता है जो हमे समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन स प्राप्त होता है।

(3) समष्टिगत मात्राओ का प्रयक से अध्ययन करना अनिवाय होता है—समष्टि गत मात्राओ का अपनी एव पृथक विशेषता होती है जिसके कारण इनका पृथक स अध्ययन अनिवाय होता है। समष्टि अर्थशास्त्र मे आवश्यक परिवर्तन हाते रहत है तथा उसका अस्तित्व बना रहता है जैसा कि अवव्यवस्था मे पुराने उद्योग का स्थान नय उद्योग लेने रहते है तथा अवव्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है।

(4) दृष्टि अर्थशास्त्र की म्यास्या के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है—विनी साधन की मजदूरी निर्धारित करन हेतु टम सम्पूर्ण अवव्यवस्था म प्रचलित सामान्य मजदूरा व्यवस्था का अध्ययन करना होगा। उदाहरणार्थ जब सामान्य कीमत स्तर सूचकांक बढ रहा हो तो हमे एव साधन विशेष की मजदूरा बढानी होगी। इसका आशय यह है कि किसी कम या साधन विशेष की मजदूरी पर दण व सामाय कीमत स्तर का प्रभाव पडता है। अर्थात् व्याप्ट अर्थशास्त्र क अध्ययन क लिए समष्टिगत अर्थशास्त्र व अध्ययन की आवश्यकता होती है।

() आर्थिक समस्याओ का समाधान समष्टिपरक अर्थशास्त्र व अध्ययन स अर्थशास्त्री हो आर्थिक समस्याओ मे उपपन्न स काफ़ी सहायता मिलता है।

(6) सामाय रोजगार की प्राप्ति मे सहायक—यतमान कन्याणदारा राष्ट्रा व सम्मुख बेरोजगारा की म षण समस्या है और सभी इसके समाधान के लिए प्रयत्नगत है। पूर्ण रोजगार अथवा अधिक्तम रोजगार की प्राप्ति यतमान समष्टि आर्थिक विश्लेषण व माध्यम से हो सकती है। इस प्रकार सामान्य रोजगार की प्राप्ति की निशा म समष्टिपरक अर्थशास्त्र सहायक हो सकता है।

(7) विकास सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में सहायक— समष्टिपरक अर्थशास्त्र ने राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक सेवाओं जैसे विषयों के अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाया है। इनके द्वारा हम किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण ने अर्द्ध-विकसित देशों की विकास सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन और इनके निराकरण को सम्भव बनाया है।

आर्थिक समष्टिभाव की सीमाएँ एवं दोष

(Limitations and Disadvantages of Macro Economics)

आर्थिक समष्टिभाव के लाभ के अलावा इसके कुछ प्रमुख दोष एवं सीमाएँ निम्न प्रकार हैं —

(1) व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के लिए अपर्याप्त समष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत केवल समूह। ओरतों अथवा कुल का अध्ययन किया जाता है और इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है। जब कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अवश्यवस्था में जरूरी होता है जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अन्तर्गत नहीं होता। इस प्रकार समष्टिगत अर्थशास्त्र अधूरा है।

(2) भ्रामक स्थिति का परिचायक— समष्टिगत अर्थशास्त्र का आधार मानकर जा नीतियाँ बनाई जाती हैं वह कभी-कभी भ्रामक परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरणार्थ यदि देश का कीमत स्तर सामान्य है तो इससे यह अनुमान लगाना गलत होगा कि सभी वस्तुओं की कीमतों में सामान्य स्थिति हो कुछ की कीमत बढ़ रही होगी तो कुछ की गिर रही होगी।

(3) समष्टिगत मात्राओं की प्रगति में असुविधा— जब व्यष्टिगत मात्राओं का योग द्वारा समष्टिगत मात्राओं को प्राप्त किया जाता है तो वह उपयुक्त नहीं हो सकता। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में व्यक्त करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन होता है। यदि अनुसन्धानकर्त्ता का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण हो तो भी त्रुटिपूर्ण नहीं होगी। इस प्रकार समष्टिगत मात्राओं का गही अनुमान लगाने में अनेक कठिनाइयों का अनुभव होता है।

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर

(Distinction between Micro and Macro Economics)

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर निम्न प्रकार में देखा जा सकता है —

(1) व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी-छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग आदि। जब कि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग अर्थात् राष्ट्रीय योगों का अध्ययन करता है जैसे कुल राष्ट्रीय आय कुल उत्पादन कुल बचत, कुल उपभोग तथा कुल रोजगार आदि।

(2) व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के मूलम अथवा एक भाग में सम्बन्धित होता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है।

(3) व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को तोड़ने की प्रिया (Disaggregation) को आधार माना जाता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की प्रिया (aggregation) होता है।

(4) व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत मिद्धान्त का विश्लेषण करना होता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय तथा रोजगार होता है।

(5) व्यष्टि अर्थशास्त्र रोजगार, आय तथा उत्पादन के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील मानता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इन्हें स्थिर मानता है।

(6) व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण के लिए दी हुई परिस्थितियाँ की मान्यता पर आधारित है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य मनुलन के आधार पर कुल कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करता है।

(7) व्यष्टि तथा समष्टि का अन्तर आर्थिक विरोधाभास (Paradoxes) के कारण भी जरूरी हो जाता है। कुछ निष्कर्ष जब एक व्यक्तिगत इकाई पर लागू किए जायें तो उचित प्रतीत होते हैं। परन्तु जब उन्हें समस्त अर्थव्यवस्था पर लागू किया जाये तो अनुचित हो जाता है। जैसे यदि एक जमाकर्ता बैंक से अपनी जमा पूँजी निकाल ले तो वह अनुचित नहीं कहा जायेगा। परन्तु सभी जमा बत्तीओं का व्यवहार ऐसा होगा तो बैंक फेल हो जायेंगे। यह आर्थिक विरोधाभास का उदाहरण है।

(8) समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर की जगल का उदाहरण देवर प्रो० बोल्डिंग (Prof Boulding) ने समझाया है। समष्टि अर्थशास्त्र यदि एक जगल का अध्ययन है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक पेड़ का अध्ययन मात्र है।

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसका कारण यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी समूहों का अध्ययन किया जाता है परन्तु यह समूह उन समूहों से अलग होते हैं जिनका सम्बन्ध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग की वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन तथा रोजगार सम्बन्धी नीतियों का अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग बहुत सी फर्मों का समूह होता है जो एक समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही होती है। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजार माँग और पूर्ति की परस्पर प्रियायों द्वारा एक वस्तु की कीमत निर्धारण की व्याख्या करता है। किसी वस्तु की बाजार माँग व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की माँग का योग होती है।

हमें यहाँ यह बात ध्यान रखना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में जिन समूहों का अध्ययन होता है वे भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरणार्थ समष्टि अर्थशास्त्र उन समूहों की व्याख्या करता है जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इनमें अर्थशास्त्र के बड़े समूहों एवं उनसे उप समूहों की व्याख्या की जाती है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के समूहों से भिन्न होते हैं।

प्रोफेसर गाडनर ऐकले के विचार इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं वे कहते हैं, 'समष्टिपरक अर्थशास्त्र में भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से छोटे समूहों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु इनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के उप-विभाग बन जाते हैं। व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र भी समूहों का प्रयोग करता है परन्तु पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के सन्दर्भ में नहीं।

व्यष्टि तथा समष्टि के बीच स्पष्ट विभाजन रखा सोचना उपयुक्त नहीं है। व्यष्टि चर (Micro Variables) समष्टि का रूप ले सकते हैं और समष्टि चर (Macro-Variables) व्यष्टि की परिधि में पहुँच सकता है। मोटे सौ पर हम कह सकते हैं कि दोनों में सावधानीपूर्वक अन्तर करना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योगों का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के एक भाग से तथा समष्टि अर्थशास्त्र में योगों का सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है। इन दोनों में अन्तर उनकी विषय सामग्री का नहीं बल्कि इन दोनों हेतु प्रयोग की जाने वाली रीति का होता है।

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है

(Micro and Macro Economics are Complimentary to each Other)

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र व उपर्युक्त अन्तर व आधार पर हम इन दोनों का एक दूसरे का प्रतिपादन नहीं समझना चाहिए वरन् यह तो एक दूसरे व पूरक है क्योंकि एक को समझने व लिए दूसरे की आवश्यकता होता है। यह बात निम्न तथ्यों से साबित होती है —

(1) व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता—

(1) बाजार में एक वस्तु का कीमत व वस्तु उम वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर नहीं करता वरन् इसका मूल्य सम्बन्धित वस्तुओं का मांग और पूर्ति द्वारा भी प्रभावित होता है।

(2) उत्पत्ति व एक साधन का कामत या पुनर्स्थापन का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। परन्तु यह पुनर्स्थापन अर्थ प्रयोगों का सा ज्ञान वाली मजदूरियों पर निर्भर करता है।

(3) एक फर्म का उत्पादन नाति क्या है इसका लिए फर्म के उत्पादन का अपना वस्तु के लिए समाज का कुल मांग तथा देश में व्याप्त आय एवं राजस्व का स्तर का भी देखना होगा।

(II) समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता—

(1) सभी फर्मों एक उद्योग का रूप ग्रहण करता है तथा सब उद्योग सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

(2) समाज व्यक्तियों का समूह होता है इस प्रकार समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं।

(3) राष्ट्रीय आय का गणना का आधार व्यक्तिगत आय भी होता है अर्थात् तब तक राष्ट्रीय आय का गणना नहीं हो सकती जब तक व्यक्तिगत आय या उत्पादकों के उत्पादन को जाँच न लिया जाए।

(4) समाज में आर्थिक क्रियाओं का स्तर उपभोग का मात्रा कुल उत्पादन कुल बचत कुल विनियोग कुल राजस्व आदि का मात्रा अनगिनत फर्मों के निर्णयों के कारण निर्धारित होता है।

निष्कर्ष—व्यष्टि तथा समष्टि दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। प्रा० सैम्यु-अमन ने दोनों के महत्व का बताना देते हुए कहा है कि 'वास्तव में व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों ही आवश्यक हैं। यदि आप एक का समझते हैं तथा दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप कब तक अर्थ ज्ञान नहीं है।

"There is really no opposition between Micro and Macro Economics Both are absolutely vital. You are only half educated if you understand the one while being ignorant of the other"

—Samuelson

परीक्षा-प्रश्न

1 व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर बताइए। इन दोनों के मध्य क्या सम्बन्ध है?

(Distinguish between Micro and Macro Economics What is the relationship between the two?)

- 2 समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसके महत्व प्रकृति तथा सीमाओं को बताइए।

(Define Macro Economics Discuss its importance nature and limitations)

- 3 सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र के बीच अन्तर स्पष्ट काजिए तथा आर्थिक विश्लेषण में समष्टि दृष्टिकोण की आवश्यकता बताइए।

(Distinguish between Micro and Macro Economics and explain the need of macro approach in economic analysis)

4 वास्तव में सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों ही आवश्यक हैं। यदि आप एक का समझते हैं तथा दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध-शिक्षित हैं। संयुक्त रूप से इस कथन की व्याख्या कीजिए।

(There is really no opposition between Micro and Macro Economics Both are absolutely vital You are only half educated if you understand the one while being ignorant of the other Discuss this statement)

—Samuelson

[संकेत—यह कथन अर्थशास्त्री प्रा० संयुक्त रूप से का है। दोनों की परिभाषा तथा सीमाएँ दीजिए। फिर दोनों के बीच विरोधाभास की चर्चा काजिए। अंत में बताइए कि फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।]

5 टिप्पणी लिखिए—

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र

(Write notes on Micro and Macro Economics)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही कौन सा सही है और कौन-सा गलत है —

- (i) माइक्रो अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अव्यवस्था से सम्बन्धित है।
- (ii) मैक्रो अर्थशास्त्र का सम्बन्ध अव्यवस्था तथा उसके सम्बन्धित योगों से होता है।
- (iii) समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया (aggregation) है जब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग तोड़ने की क्रिया (Disaggregation) है।
- (iv) समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियाँ व निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- (v) माइक्रो अर्थशास्त्र व अन्तर्गत द्रव्य तथा वित्त का अध्ययन होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) सही है। (iii) सही है। (iv) सही है। (v) गलत है।

National income is the net output of commodities and services flowing during the year from country's productive system into the hands of the ultimate consumers or into net additions to the country's stock of capital goods.¹
— Simon Kuznets

अध्याय 2

राष्ट्रीय आय

(NATIONAL INCOME)

राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्राव अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय आय से हमारा ज्ञान किसे राष्ट्र की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में होता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का कुछ राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न बढ़ गया है। राष्ट्रीय आय का कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार में दी गई हैं—

राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ (Definitions of National Income)—

प्रा० माशन की परिभाषा

प्रा० माशन के शब्दों में— 'एक देश में प्राकृतिक साधनों पर धन तथा पूँजी द्वारा कार्य करने पर प्रत्येक वर्ष भौतिक एवं अर्थव्यवस्था वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उत्पादन होता है। यही शुद्ध वास्तविक आय अथवा देश का आय अथवा राष्ट्रीय राशिका है।'¹

प्रा० माशन की परिभाषा में ज्ञात होता है कि देश की उत्पादित वस्तुओं द्वारा प्राप्त शुद्ध उत्पादन का जोड़ किया जाए तो हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति का पता चल जाएगा। कुछ उत्पादन में से मशीनों का घिसावट का घटकर निरक्षण में प्राप्त शुद्ध आय का राष्ट्रीय उत्पत्ति में जोड़ देना चाहिए।

आलोचना— प्रा० माशन की परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टि में अच्छी लगती है परन्तु इसमें दोष निम्नवत् हैं—

(1) देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनकी कीमती का जोड़ पाना एक कठिन कार्य है।

(2) कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिनका सम्बन्ध मात्रा बाजार में प्रिय व दत्त नहीं आता। एक उत्पादक या निर्याता वस्तु का कुछ मात्रा का अपने उपयोग के लिए अपने पास रख रखा है जिसका मौद्रिक मूल्य ज्ञान करना कठिन होता है।

- 1 The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend

—Marshall

(३) मार्शल के विचारानुसार यदि देश के कुल उत्पादन की गणना की जाएगी तो कुछ वस्तुओं को दो बार गिनने की सम्भावना बनी रहेगी।

प्र० पीगू की परिभाषा—प्र० पीगू के अनुसार

राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का जिसमें नि सन्देह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है वह भाग है जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है।¹

प्र० पीगू के उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय आय में केवल वे ही वस्तुएँ तथा सेवाएँ शामिल की जानी चाहिए जिनको हम मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं। प्र० पीगू की परिभाषा को प्र० मार्शल की परिभाषा के ऊपर एक मुद्धार माना जाता है। इसे अधिक व्यावहारिक सरल और निश्चित माना जाता है।

आलोचना—प्र० पीगू की परिभाषा भी दोष मुक्त नहीं है निम्न तथ्या के आधार पर हमकी आलोचनाएँ की जाती है।

(1) प्र० पीगू की परिभाषा बहुत अधिक संकुचित है। पीगू ने राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया है जिनका बर्ष में न केवल उत्पादन हो बरन जिनको मुद्रा में मापा भी जा सकता हो। वस्तुओं का एक ऐसा समूह भी होता है जिसका विनिमय नहीं होता जबकि इन वस्तुओं का सामाजिक बस्याण पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में न जोड़ना वहाँ तक उचित है।

(2) प्र० पीगू की परिभाषा के अनुसार अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता जितना आदान प्रदान वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत होता है। इनकी परिभाषा अर्द्ध-विकसित देशों के लिए नहीं बरन विकसित देशों के लिए सही हो सकती है।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को अपने उपभोग के लिये रख लेने पर उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जायगा। इसी प्रकार अवैतनिक बर्षचारियों की सेवाओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जायगा। यह सारी बातें असंगतिपूर्ण हैं।

प्र० फिशर की परिभाषा—प्र० फिशर के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक या आय में केवल अन्तिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं चाहे उनकी प्राप्ति भौतिक पर्यावरण से हुई हो या मानवीय पर्यावरण से को शामिल किया जाता है। इस प्रकार एक पियानो अथवा एक जावर बोट का मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, मेरी इस वर्ष की आय का अंश न होकर रूजी में वृद्धि मात्र है। केवल इन वर्ष में इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए की गई सेवाएँ ही इस वर्ष की आय हैं।²

1 'National dividend is that part of objective income of the community including of course income derived from abroad which can be measured in money.
—Pigou

2 'National dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers whether from their material or from their human environment. Thus a piano or an overcoat made for me this year is not a part this year's national income but an addition to capital only the services rendered me during this year by these things are income.'
—Irving Fisher

प्रो० पिजर न राष्ट्रीय आय में केवल उन्ही सेवाओं को शामिल किया है जो उपभोक्ता का पर अवधि विशेष में प्राप्त होती है। उनके अनुसार बहुत सी वस्तुएँ अधिक टिकाऊ होती हैं जिनका उपयोग लगातार चलता रहता है। जब हम एक वर्ष विशेष को राष्ट्रीय आय का लेनो हूँ तब उन उम वर्ष विशेष में अमुक वस्तु का उपयोग मूल्य को ही लेना चाहिए। प्रो० पिजर की परिभाषा आर्थिक कल्याण की दृष्टि में उपयोगी तो है परन्तु यह भी दोष मुक्त नहीं है।

आलोचना—प्रो० पिजर की परिभाषा की आलोचनाएँ निम्नलिखित बातों के आधार पर की जाती हैं

(1) यह जानना अत्यन्त कठिन है कि अमुक वर्ष में अमुक वस्तु का रितना उपयोग हुआ है।

(2) किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय को जानने के लिये पिछले वर्षों में उत्पादित निम्न वस्तुओं का उन भागों की कीमतें मालूम करना होगी जिनका उम वर्ष में उपयोग हुआ है।

(3) टिकाऊ वस्तुओं का हस्तांतरण इस प्रकार हो सकता है कि अन्तिम स्वामी ने वस्तु के प्राग्भित् स्वामी का कोई सम्बन्ध ही न रहे तथा यह पता ही न चल सके कि वस्तु का निर्माण कब हुआ था।

राष्ट्रीय आय की बीन्स धारणा—प्रो० बीन्स प्रो० मार्श, पीगू तथा पिजर की राष्ट्रीय आय की धारणाओं में महत्त्व नहीं है। उन्होंने कहा कि इन विद्वानों ने राष्ट्रीय आय में उन तत्वों की व्याख्या नहीं की जो अर्थव्यवस्था का गही चित्र प्रस्तुत कर सके। प्रो० बीन्स ने बताया कि राष्ट्रीय आय की धारणा कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच की धारणा है। प्रो० बीन्स कहते हैं राष्ट्रीय आय को जानने के लिए सभी मूल्य ह्रास (Depreciation) तथा अप्रचलन का राष्ट्रीय आय में से नहीं घटा देना चाहिए, बल्कि इसमें से केवल प्रयोगकर्ता लागत (users cost) को ही घटाना चाहिए। प्रयोगकर्ता लागत = माल-गर्जना के लिए प्रयोग किए जाने पर मूल्य ह्रास—मूल्य में कमी जब इसे प्रयोग में न लाया जाए—अनुक्षण व्यय। इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। माना कि हम मशीन का उद्योग में खरीदते हैं तो उसकी कीमत 1500 रुपये है परन्तु जब उसकी काम में लाया जाए तो उसकी कीमत 1000 रुपये रह जाती है अर्थात् मशीन को प्रयोग में लाने पर उसकी कीमत में 500 रुपये मूल्य का ह्रास हो गया। यदि हम मशीन को प्रयोग में नहीं लाया जाता तो हमारे मूल्य में थोड़ी सी गिरावट आती क्योंकि हमारे मशीन में थोड़ी जग आदि नष्ट जाती और इसकी सफाई आदि में यदि 50 रुपये का व्यय होता तो हम अनुक्षण व्यय (Maintenance cost or expenditure) कहा जाएगी। इस प्रकार प्रयोगकर्ता लागत 500 रुपये—मशीन के प्रयोग न करने की स्थिति में 200 रुपये मूल्य में कमी हो जाती है + 50 रुपये का अनुक्षण व्यय हो तो प्रयोगकर्ता लागत $500 - 200 = 250$ रुपये होगी। प्रो० बीन्स कहते हैं कि प्रयोगकर्ता लागत को घटाकर अर्थव्यवस्था में किसी अवधि विशेष की राष्ट्रीय आय निकालना चाहिए। प्रो० बीन्स के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय का जानने का निम्न सूत्र है—

$$\text{शुद्ध राष्ट्रीय आय} = A - U - V$$

$$A = \text{कुल राष्ट्रीय आय}$$

$$U = \text{प्रयोगकर्ता लागत}$$

$$V = \text{पूरा लागत}$$

V — पूरक लागत से आशय उस लागत से होता है जो अनिश्चित होती है। इस प्रकार के व्यय अनियन्त्रित तथा अनीच्छित होते हैं। जैसे अप्रचलन व्यय मशीना का पुराना पड़ जाना आदि।

राष्ट्रीय आय की कुछ अन्य परिभाषाएँ— प्रो० बीन्स के बाद राष्ट्रीय आय की कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा परिभाषाएँ दी गई हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषाएँ भी कह सकते हैं।

प्रो० संम्युलसन के शब्दों में— राष्ट्रीय आय अथवा उत्पाद वह अंतिम सरप्ला है जिसे आप विविध वस्तुओं, सेवाओं, सन्तान तथा मशीना जिन्हें कोई समाज उपलब्ध भूमि धन तथा पूँजीगत साधनों से उत्पादित करता है, का मौद्रिक माप देने पर प्राप्त किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आय समिति (Indian National Income Committee) के अनुसार— राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय में वस्तुओं तथा सेवाओं का माप है। इसमें देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है चाहे उसका सम्बंध ज़ूती तथा जहाजों के निर्माण से हो अथवा चिकित्सालय या न्यायालय सम्बंधी सवायें प्रदान करने से हो।

प्रो० साइमन कुजनेट्स के शब्दों में— राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं की वह विगुद उत्पत्ति है जो एक वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के पास पहुँचती है अथवा दबा के पूजागत वस्तुओं का स्टॉक में विगुद रूप से वृद्धि करती है।

राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय की व्याख्या प्रमुख रूप से तीन प्रकार से हो सकती है—

- (1) प्राप्तियों की कुल मात्रा की दृष्टि से
- (2) व्यय की कुल मात्राओं की दृष्टि से
- (3) उत्पादित मात्रा के कुल मूल्य की दृष्टि से।

राष्ट्रीय आय की अन्य धारणाएँ (Other Concepts of National Income)

राष्ट्रीय आय की कुछ प्रमुख धारणाएँ निम्न प्रकार से हैं—

(1) **कुल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product—GNP)** एक वर्ष की अवधि में जो भी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पादित की जाती हैं उन सभी के बाजार मूल्य को कुल राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। इस धारणा की दो प्रमुख बातें हैं—प्रथम तो यह कि एक वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं को मुद्रा के मूल्य में जोड़ा जाता है दूसरे यह कि कुल उत्पादन में केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। ऐसी गणना करते समय माध्यमिक वस्तुओं जैसे रई कच्चा रोहा आदि को शामिल नहीं करना चाहिये।

कुल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में जो मशीन अथवा अवल पूँजी की घिसावट या मूल्य ह्रास हो इसे शामिल नहीं करना चाहिये। कुल राष्ट्रीय आय की यह धारणा राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयोग में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह विचार एक अवधि विशेष में उत्पादन तथा रोजगार सम्बन्धी दशाओं का एक विश्वसनीय सूचकांक है। सांख्यिकीय दृष्टि से यह सरल धारणा है क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास को घटाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(2) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product-NNP) - कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूँजीगत वस्तुओं का जैम मशीन तथा यन्त्र आदि की घिसावट पर हात बांध कर घटाने पर जो कुछ बचता है उस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इस बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय (National Income at Market Prices) भी कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय की धारणा का विशेषता यह है कि यह बाजार उपभोग पर बाजार प्रतिस्थापित निवेश व ऊपर कुल उत्पादन में वृद्धि का स्पष्ट करती है और आर्थिक विकास व विकास की उन्नति का अर्थशास्त्र (Economics of Growth) व विकास विभाग महत्व है।

इस पद्धति की प्रमुख कठिनाई यह है कि एक समय विशेष में मूल्य ह्रास का अनुमान वास्तविकता से काफी दूर होता है। इसका कारण यह है कि मूल्य ह्रास को जानने में विभिन्न माजमज्जा व कुल मूल्य में उतार-चढ़ाव जीवन अवधि व उषों में भाग देना होता है। माजमज्जा व जीवन वित्त का पता लगाना स्वयं कठिन है। इसके अतिरिक्त एक वर्ष विशेष में माजमज्जा की सीमा में वृद्धि हो जाना पर यह समस्या और गंभीर हो जाती है कि पुरानी सीमा पर या नई सीमा पर मूल्य ह्रास निर्धारित जाय। यदि एक मशीन अपने अनुमानित जीवनकाल के बाद में ही अप्रचलित हो जाय तो मूल्य ह्रास की समस्या और भी कठिनाई पैदा कर देती है।

(3) साधन लागत पर राष्ट्रीय आय (National Income at Factor Cost) - इस में कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उत्पत्ति व माधन व सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। इस प्रकार कुल उत्पत्ति का जो मौद्रिक मूल्य होता है उस ही उत्पत्ति व विभिन्न माधन व सेवाओं का मूल्य दिया जाता है। उत्पत्ति व माधन में जितनी आय अर्जित की है उस भूराश्री व नगण भूमि व मजदूरी पूँजीपति व व्याज साहसिक व लाभ आदि प्राप्त किया है इस माधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। उत्पत्ति व विभिन्न माधन व सेवाओं का यह आय उनका अपने माधन लागत पर प्राप्त हुई है।

माधन लागत पर राष्ट्रीय आय जानने के लिए हम शुद्ध राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष कर घटा देना चाहिए तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता जोड़ देना चाहिए। इस पर मूल्य द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं।

माधन लागत पर राष्ट्रीय = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन - अप्रत्यक्ष कर + सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता

National Income at Factor Cost = Net National Product - Indirect Taxes + Subsidies

(4) व्यक्तिगत आय (Personal Income) - यह वह कुल आय है जिस व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया है। इसमें अन्तर्गत मजदूरी तथा बचत लागत व्यय तथा लाभों का मूल्य मजदूरी प्राप्त लागत की आय जैम रिगान डाक्टर दूरानदार आदि की आय से शामिल किया जाता है। परन्तु इसका समयावधि में उत्पादन व माधन द्वारा जो आय अर्जित हो जाती है वह पूर्ण की पूरी उध नही मिलती इसका कारण यह है कि इसमें कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं। उदाहरणार्थ एक सयुक्त पूँजी वस्तुओं व अग्न धारियों द्वारा जोय का कुछ भाग करों के रूप में सरकार को दे दिया जाता है। इसी प्रकार भूमि तथा अन्य बचत भागी व मजदूरी का उन्हें प्रदान की जाय या ही सामाजिक सुरक्षा सेवाओं व उद्योग में सामाजिक व कटौतियों की जाती है। टीक इसी प्रकार उत्पत्ति व माधन का जितना उत्पादन बाय किए हुए कुछ खर्च प्राप्त हो जाती है जैम वृद्धावस्था पेंशन पेंशनकारी भत्ता आदि। इस हस्तांतरण आय भी कहते हैं।

जब हमें राष्ट्रीय आय को वैयक्तिक आय द्वारा मापना हो तो हमें आय के उस भाग को जो कमाया तो गया है परन्तु उसकी वारतविक प्राप्त उत्पत्ति के साधन को नहीं हुई है घटा देना चाहिए, और वह रकम जो बिना कमाए प्राप्त हुई हो उसे जोड़ देना चाहिए।

5 उपभोग्य आय (Disposable Income)— एक व्यक्ति की अपनी समस्त आय पर पूरा अधिकार नहीं होता और न ही वह इसको पूरी तरह से इच्छानुसार व्यय, बचत या अन्य प्रकार से उपयोग कर सकता है। उसे अपनी आय में से आय कर सम्पत्ति कर्तव्य बीमा सम्बन्धी कुछ व्ययों देना होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति के पास उपभोग्य आय वह मात्रा होती है जो व्यक्ति विशेष की आय में से सरकार को दिए जाने वाले करों या अन्य देनदारियों को देने के बाद बचती है। यह जरूरी नहीं है कि समस्त उपभोग्य आय को पूरी तरह उपभोग पर व्यय ही कर दिया जाए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति या परिवार अपनी उपभोग्य आय में से बचा लेता है। उपभोग्य आय को निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है

$$\text{उपभोग्य आय} = \text{उपभोग} + \text{बचत}$$

$$\text{Disposable Income} = \text{Consumption} + \text{Saving}$$

इस विचारधारा की विशेषता यह है कि एक व्यक्ति या परिवार की उपभोग्य आय क्या होगी। यह इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता कि सरकारी वित्तीय नीति कैसी है। यदि सरकार न अधिक कर लगा रखे है तो उपभोग्य आय कम रहेगी।

6 वास्तविक आय (Real Income) राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। परन्तु मुद्रा की क्रयशक्ति में कीमत-स्तर में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। यदि कीमत-स्तर बढ़ जाता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और कीमत-स्तर गिरने का अणाय मुद्रा की क्रय शक्ति के बढ़ने से लगाया जाना है। यदि हमें किसी विशेष समयावधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय का पता लगाना है तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करना चाहिए।

$$\text{वास्तविक आय स्थिर मुद्रा के रूप में} = \frac{\text{नकद आय वर्तमान मुद्रा में}}{\text{वर्तमान समय में सूचकांक}}$$

$$\text{Real Income in Terms of Constant Prices} = \frac{\text{Nominal income in Current money}}{\text{Price Index for Current Period}}$$

राष्ट्रीय आय का माप (Measurement of National Income)—राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में तीन प्रमुख विचारधाराओं का स्थान है। प्रथम कुल आय या प्राप्ति, दूसरे कुल व्यय तथा तीसरे कुल उत्पादन का मूल्य, यह तीनों ही धारणाएँ इस तथ्य पर आधारित हैं कि एक समय में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आय होता है। इसी विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। जैसे (1) उत्पादन प्रणाली (Product Method) (2) आय प्रणाली (Income Method) तथा (3) व्यय प्रणाली (Expenditure Method) इनको प्रत्येक रूप से निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है

(1) उत्पादन प्रणाली (Product Method) - इस विचारधारा को वस्तु सेवा प्रणाली (Commodity Service Method) भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादन के कुल मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है जैसे बिजली-स्वयं उपभोग, स्टॉक में वृद्धि।

सभी क्षेत्रों के कुल उत्पादित मूल्य को ज्ञात करने के बाद उसमें में अन्य उद्योगों या क्षेत्रों में खरीदे गए पदार्थों के मूल्य तथा उत्पादन पूँजी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है और इस प्रकार शुद्ध उत्पादन मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हुए विस्तृत उत्पादन के मूल्यों को जोड़कर तथा विदेशी व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय को जमा करके कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय आय के माप की यह विधि उन देशों में प्रयुक्त होती है, जहाँ राष्ट्रीय उत्पादन की गणना होती है तथा उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध होते हैं।

(2) आय प्रणाली (Income Method) — इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय का जोड़कर राष्ट्रीय आय का निष्पात जाता है। इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय निम्नलिखित समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(i) इनके अन्तर्गत हस्तांतरण भुगतान को नहीं जोड़ना चाहिए जैसे ऋणायुक्त ऋण तथा निधन योगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता आदि।

(ii) जिन सेवाओं के बदले में भुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता उन सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना के समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) उत्पादक द्वारा जो सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और यदि वे लाभ का अंग हैं तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) मयुक्त पूँजी सम्पत्ती या अन्य परमों द्वारा जो धनराशि रिजर्व निधि में डाल दी जाती है उसे शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस धनराशि का लालाभाग के रूप में वितरण नहीं होता है।

इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के राष्ट्रीय आय में से उनके भाग या हिस्से का आसानी से पता चल जाता है और माघन विधेय की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है।

(3) व्यय प्रणाली (Expenditure Method) — इस प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए व्यय को जोड़ा जाता है। एक देश में जितना उत्पादन हुआ है उसे बाजार मूल्यों पर खरीदने के लिए व्यय किया जाता है। जितनी भी आय होती है वह पूरी व्यय नहीं की जाती है, इसका एक भाग बचत के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जानने के लिए एक वर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय + कुल बचत को ज्ञात किया जाता है।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इन देशों में जहाँ व्यक्तिगत उपभोग या व्यय तथा बचत सम्बन्धी विवरणनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करना आसान नहीं है। इसलिए अल्प-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय को जानने के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। विकसित देशों में भी इससे इस अवगुण के कारण उसका उपयोग सीमित है।

राष्ट्रीय आय की गणना की अन्य प्रणालियाँ (Other Methods of Measuring National Income)

4. सामाजिक लेखांकन प्रणाली (Method of Social Accounting) — पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए सामाजिक लेखांकन प्रणाली का विनाम

विया गया है। इस प्रणाली का प्रतिपादन डा० रिचार्ड स्टोन (Dr Richardstone) ने किया था। शून्य में इसे विभिन करने में प्रो० जे० एम० कीस प्रो० मीड प्रो० जे० आर० थिन्ग आदि अधशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया।

सामाजिक लेखांकन अथवा राष्ट्रीय लेखांकन एक ऐसी प्रणाली है जिसने माध्यम से हम को राष्ट्रीय आय की गणना ही नहीं करत बरन इससे देश की समस्त आर्थिक संरचना, क्षेत्रीय अन्तर्सम्बन्ध तथा आर्थिक क्रियाओं का विभिन्न तत्वों के रूप में एक सारिकार्य चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। प्रो० ईडी एलन पीकाक तथा कूपर आदि विद्वानों ने सामाजिक लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार की है—सामाजिक लेखांकन की यह प्रणाली राष्ट्रीय तथा मातृकीय संस्थाओं की सम्पूर्ण क्रियाओं के सारिकार्य वर्गीकरण से इन प्रकार सम्बन्धित है जो इस सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के परिचालन को समझने में सहायक सिद्ध होती है। इसमें अत्यन्त आर्थिक क्रियाओं का मात्र वर्गीकरण ही नहीं किया जाता बरन आर्थिक प्रणाली के चलन की विस्तृत जाँच हेतु एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश किया जाता है।¹

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक लेखांकन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक तत्त्वों का विवरण अथवा लेखा जोखा है जिसे सांख्यिकीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें उद्घाटन आय व्यय विनियोग सम्बन्धी सभी प्रकार के लेख शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक लेखांकन में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का चित्रण होता है। इन क्रियाओं का आपसी सम्बन्ध बताने में सहायक होता है।

सामाजिक लेखांकन का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Social Accounting) सामाजिक लेखांकन प्रणाली की कार्य विधि इस प्रकार है कि जब उद्घाटन विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग हेतु मुद्रा व्यय करत है तो मुद्रा का प्रवाह (Flow) व्यक्तियों से उत्पादन प्रतिष्ठानों की ओर होता है। उत्पादन जब इस मुद्रा को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को देता है तो मुद्रा का प्रवाह इन उत्पादन प्रतिष्ठानों से पुनः व्यक्तियों की ओर होने लगता है। आय व्यय के प्रवाहों (Flows of Income and Expenditure) के पारस्परिक सम्बन्ध ही सामाजिक लेखांकन प्रणाली का आधार है। निजी तत्वों की तरह सामाजिक तंत्रों को भी दोहरी प्रवृत्ति के आधार पर बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यवसायिक इकाई तान प्रसार में अपने खर्चों को रकती है जैसे—(i) उत्पादन तंत्र (Production Account) (ii) आय व्यय तंत्र (Income Expenditure Account) तथा (iii) बचत विनियोग लेखा (Saving Investment Account) ठीक इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के लेख भी होते हैं।

- 1 Social accounting then is concerned with the statistical classification of the activities of human beings and human institutions in a way which help us to understand the operation of the economy as a whole. The field of studies summed up by the words Social accounting embraces however not only the classification of economic activity, but also the application of the information thus assembled to the investigation of the operation of the economic system.

—Edy, Peacock and Cooper

सामाजिक लेखांकन के अनुसार अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है। जैसे—उत्पादन क्षेत्र (Productive Sector), मध्यम्य या व्यापारी क्षेत्र (Intermediate or Business Sector), तथा अन्तिम माँग या अन्तिम उपभोक्ता क्षेत्र (Last Demand or Consumer Sector)। समुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अर्थव्यवस्था को पाँच भागों में बाँटा जाता है (i) उत्पादन मय्यान (ii) वित्तीय मध्यम्य (iii) बीमा व सामाजिक सुरक्षा मय्यान (iv) अन्तिम उपभोक्ता (v) बाह्य जगत (विदेशी लेन-देन)। वर्ष 1949 में भारतीय राष्ट्रीय आय समिति (Indian National Income Committee) ने अर्थ-व्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बाँटा है (i) व्यावसायिक मय्यान (ii) परिवार तथा निजी अताम मय्यान (iii) सरकारी तथा मावर्जनिक मय्यान।

कृत्रु मिलाकर एक क्षेत्र विशेष के लिए 12 लेखें तैयार किए जाते हैं। सामाजिक लेखों के लिए एक लेन-देन अध्याय (Transaction Matrix) का प्रयोग होता है जिसमें वस्तुओं के अन्तर्गत अलग क्षेत्रों को लेनदारियों तथा लेनदारियों दिखाई जाती है। यह माद मय्यान चाहिए कि सामाजिक लेखों में मनुकन बनाए रखने के लिए एक पक्ष के कृत्रु जोड़ उसमें समकक्ष कौनम पक्ष के कृत्रु जोड़ के बराबर होना चाहिए।

सामाजिक लेखांकन का प्रारूप

लेनदारियाँ लेनदारियाँ	आधिक गतिविधि			योग
	व्यावसायिक	निजी	सरकारी	
1. उत्पादन लेखा			...	
2. उपभोग लेखा				
3. पूँजी लेखा		.		
4. बाह्य लेखा				...
योग

सामाजिक लेखांकन का महत्व (Importance of Social Accounting)—सामाजिक लेखांकन प्रणाली का महत्व निम्न तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता है—

(1) यह प्रणाली अर्थव्यवस्था की मरचना रखन वाले तत्वों की विस्तृत जानकारी देती है। जैसे उत्पादन उपभोग बचन विनियोग विदेशी व्यापार आदि।

(2) यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्भावधों की व्याख्या करने में तथा उनमें तुलनात्मक अध्ययन को भी सहायता देता है। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसने मावेधिक योगदान का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(3) इसमें द्राग देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी के माध-माध विदेशी अर्थ व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

(4) यह सरकारी आधिक नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में परिणाम-मय रूप उनके आर्थिक प्रभावों की जानकारी भी प्रस्तुत करता है।

5 मिश्रित प्रणाली (Mixed Method)—राष्ट्रीय आय के माप के लिए कोई भी अकेली विधि पर्याप्त नहीं है। सभी के अपने गुण-दोष हैं। जब हम इस या उसमें अधिक प्रणालियों का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना हेतु करते हैं तो हम प्रणाली को मिश्रित प्रणाली बना देते हैं। एक अर्द्ध-विनिर्मित अर्थव्यवस्था में हम प्रणाली का प्रयोग अधिकांश किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विवरण न होने के कारण हमें निरन्तरनीय माप दे सकना नहीं होता। भारतीय अर्थ विशेषज्ञ डा० पी० के० आर० पी०

राय (Dr V K R V Rao) न राष्ट्रीय आय की गणना हर एक इस प्रणाली का प्रयोग किया और भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों का मिश्रित प्रणाली अपनाय की मनाह दी। यह प्रणाली विकसित देशों में भी लागू किया जा रहा है क्योंकि बहुत से प्रणालियों का ही राष्ट्रीय आय जानने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

राष्ट्रीय आय के माप के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ (Difficulties in the Measurement of National Income)

प्रो० साइमन कुजनेट्स (Prof Simon Kuznets) - न राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय आने वाली सांख्यिक अवधारणाओं का सम्बन्धित कठिनाइयाँ का और हमारा ध्यान आकर्षित किया है जैसा -

(1) राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने सम्बन्धी कठिनाई - राष्ट्रीय आय का परिभाषित करते समय क्या हम एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली आय का ही शामिल कर लें या विदेशों में इस राष्ट्र के नागरिकों द्वारा पूँजी पर अर्जित व्याज या लाभों को भी राष्ट्रीय आय में शामिल करें।

(2) राष्ट्रीय आय मापने हेतु प्रणाली का प्रयोग - राष्ट्रीय आय का मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाय। कोई भी एक प्रणाली वास्तविक राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए पूरा नहीं करी जा सकती। अर्थात् विकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा यह समस्या और भी गम्भीर हो जाती है।

(3) राष्ट्रीय आय की आर्थिक क्रिया - राष्ट्रीय आय का माप न सम्बन्धित एक आय कठिनाई यह आती है कि आर्थिक क्रिया किस स्थिति पर राष्ट्रीय आय जानना। जाए। अर्थात् उपभोग उत्पादन या वितरण में से किस क्रिया को आधार माना जाय।

(4) वस्तुओं तथा सेवाओं की चुनाव सम्बन्धी समस्या - राष्ट्रीय आय की गणना में एक अन्य समस्या वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव की समस्या आती है। वस्तु विनिमय द्वारा होने वाले सादा के क्षेत्र में यह समस्या और भी गम्भीर हो जाती है।

(5) दोहरी गणना सम्बन्धी समस्या - राष्ट्रीय आय का गणना में एक अन्य समस्या दोहरी गणना (Double Counting) सम्बन्धी सामान्य आती है। इसका समाधान हेतु हम प्राथमिक तथा माध्यमिक वस्तुओं के स्तर पर अन्तिम उपभोक्ता वस्तुएँ लनी चाहिये।

(6) हस्तान्तरण भुगतान सम्बन्धी कठिनाई - राष्ट्रीय आय के माप के सम्बन्ध में एक अन्य कठिनाई हस्तान्तरण भुगतान सम्बन्धी सामने आती है। यह भुगतान आय के पुनर्वितरण के कारण होता है।

(7) विदेशी फर्मों की आय की समस्या - इस सम्बन्ध में कठिनाई यह आती है कि विदेशी फर्मों की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय माना जाए अथवा नहीं।

(8) सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन - एक अन्य समस्या यह आती है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य क्या और कैसे आँका जाए।

अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय को माप सम्बन्धी कठिनाइयाँ (Difficulties of Measuring National Income in Under developed Countries)

एक अर्द्ध विकसित देश में राष्ट्रीय आय का मापन सम्बन्धित समस्याओं की कठिनाइयाँ आती हैं। यह कठिनाइयाँ सांख्यिकीय एवं सांख्यिकीय (Statistical and Conceptual) होती हैं।

(1) अमौद्रिक क्षेत्र का होना—अर्द्ध-विवर्णित देशों में अमौद्रिक क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में काफी कठिनाई आती है। एवं उत्पादक या वित्तियन अपने उत्पादन का अच्छा भाग अपने उपभोग के निम्न स्तर में लाते हैं और उम्र बाजार में बेचने को नहीं लाते। इसका एक छोटा-सा भाग यह वस्तु-विनिमय के लिए छोड़ दिया जाता है। यह कठिनाई अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में आती है।

(2) पर्याप्त एवं विषयसमीची आँकड़ों का अभाव—अर्द्ध-विवर्णित देशों में अधिकांश उत्पादकों के अशिक्षित एवं साक्षरताहीन व्यवस्था का समुचित उपयोग न करने से पर्याप्त एवं विषयसमीची आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले के समक्ष यह समस्या आती है कि जो कुछ भी आँकड़े उपलब्ध हैं उन्हें उनमें सत्यता का अंश कितना है।

(3) विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट वर्गीकरण का अभाव—अर्द्ध-विवर्णित देशों में विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट वर्गीकरण के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई आती है। क्योंकि न ही यह आत नहीं हो पाता कि कौन-सा क्षेत्र औद्योगिक और कौन-सा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है।

(4) आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन—अर्द्ध-विवर्णित देशों में आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन के कारण बहुत-सी कठिनाइयाँ आती हैं। इन देशों में प्रायः राग अध-विकासी एवं परम्परावादी होते हैं। वे अपनी आय तथा परिवार में सम्बन्धित विर्मा भी प्रसार की योजना बन में समुचित हैं।

राष्ट्रीय आय विश्लेषण का महत्व (Importance of National Income Analysis)—वर्तमान समय में किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी तथा देश विशेष की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में काफी सहायता मिलती है। इसका ही नहीं राष्ट्रीय आय में सम्बन्धित आँकड़े आर्थिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीतियों के निर्माण में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व निम्नलिखित तथ्यों द्वारा और जा सकता है।

(1) आर्थिक प्रगति का सूचक—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी सांख्यिकीय से हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का ज्ञान होता है अनुमान लगा सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति (Trend) वृद्धि को बताती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख है, यदि राष्ट्रीय आय स्थिर है तो यह अर्थव्यवस्था की स्थिरता का, यदि राष्ट्रीय आय में गिरावट के चिह्न हैं तो इसके अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत मिलते हैं। इन प्रकार राष्ट्रीय आय का आँकड़ा आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं।

(2) आर्थिक नीति निर्माण एवं नियोजन में सहायक—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों में सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्धारण तथा निर्माण में काफी सहायता मिलती है। सरकार को अपनी वर नीति मौद्रिक नीति प्रमुख नीति, तथा अन्य प्रकार की नीतियों के निर्माण में काफी सहायता मिलती है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन के लिए अर्थव्यवस्था तथा दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण में भी सहायता मिलती है।

(3) अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर समुचित प्रकाश डालते हैं। इन आँकड़ों द्वारा जानने से हम पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है।

(4) जीवन स्तर की जानकारी—राष्ट्रीय आय का हम प्रतिव्यक्ति आय द्वारा भा व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिव्यक्ति आय की गति नागा के जीवन स्तर का व्यक्त करती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि को बताती है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दशवासिया का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

(5) समाज में आय के वितरण की जानकारी—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े से हम समाज के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय आय के वितरण की जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय आय के वितरण में व्यय में असमानताओं की जानकारी भी हम आसानी से मिल जाती है।

(6) उपभोग व बचत तथा विनियोग की जानकारी—राष्ट्रीय आय व अनुमानों के आधार पर हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि राष्ट्रीय व्यय उपभोक्ता व्यय तथा निवेश में किस प्रकार बँटा है। इस में उपभोग व बचत तथा निवेश का स्थिति क्या है। इस में रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण माँग स्वयं उपभोग तथा विनियोग द्वारा प्रभावित होता है।

(7) करदात क्षमता का अनुमान—राष्ट्रीय आय द्वारा दशवासिया का करदात क्षमता का अनुमान तथा सकते हैं जिससे सरकार को अपनी कराधान सम्बन्धी नीति व निर्धारण में सहायता मिलती है।

(8) तथैव सरकारों नीतियों के निर्माण में सहायक—राष्ट्रीय आय के तथैव द्वारा राष्ट्रीय सरकार को अपने विभिन्न घटका जैसे वेटेड शासित क्षेत्रों तथा राज्यों को प्रदत्त अनुदान तथा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता व बटवारे में काफी सहायता मिलती है।

(9) सामाजिक तथा निजी क्षेत्रों की जानकारी—राष्ट्रीय आय व आँकड़ों द्वारा हम भारत जसी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में मावजनिक तथा निजी क्षेत्र (Public and Private Sectors) व सापेक्षिक योगदान का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(10) अन्न विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण—राष्ट्रीय आय के अनुमानों का आधार पर अन्न विकसित देशों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान की जानकारी आसानी से पता चल जाती है।

राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण (National Income and Economic Welfare)

कल्याण शब्द का आशय मनुष्य तथा समाज का प्राप्त हान वाला भानिक सुख-सुविधाओं से होता है। कल्याण का सम्बन्ध मनुष्य के रहन-सहन से भी व्यक्त किया जा सकता है। उच्च आर्थिक कल्याण उच्च रहन-सहन का स्तर का प्रतीक है तथा निम्न आर्थिक कल्याण निम्न रहन-सहन के स्तर को बताता है। यदि हम समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों व कल्याण को जोड़ दें तो हमें कुल सामाजिक कल्याण की जानकारी हो जाएगी। श्रोमणू ने कल्याण को दो भागों में बाँटा है (i) आर्थिक कल्याण (Economic Welfare) (ii) पनाथिक कल्याण (Non economic Welfare)। यह तथैव हम प्रकार से एक-दूसरे से सम्बन्धित है कि इसे पृथक करना नहीं है। श्रोमणू ने आर्थिक कल्याण का परिभाषित करते हुए कहा कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिस प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भुक्त-लेखक से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण का घना सम्बन्ध (Positive Correlation) की कल्पना अधिकांश विद्वानों में की है। श्रोमणू का सा स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। उनका अनुमान था राष्ट्रीय आय में वृद्धि नाग के आय वितरण के रहने के समान रहने का हमें पता चला है।

आर्थिक बर्न्याण म वृद्धि होती है अर्थात् उनक रहन-सहन क स्तर म भी वृद्धि हा जाती है। इस आधार पर हम कह सकने हैं कि राष्ट्रीय आय का इस आर्थिक बर्न्याण का सूचकांक कह सकन है।

राष्ट्रीय आय आर्थिक बर्न्याण का वास्तविक सूचकांक नहीं है (National Income is not a Real Index of Economic Welfare)

क्या हम राष्ट्रीय आय का आर्थिक बर्न्याण का वास्तविक सूचकांक कह सकत ह ? यह प्रश्न हम तभी सही रूप म समझ म आ सकगा जब कि हम निम्न तथ्या पर भी ध्यान द।

(1) राष्ट्रीय आय का वितरण—राष्ट्रीय आय म वृद्धि स आर्थिक बर्न्याण बढ़ा है या कम हुआ है। इसक लिए हम देखना होगा कि राष्ट्रीय आय क वितरण की स्थिति क्या है। यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि म धनी तग का इसका हिस्सा अधिक पहुँचना है और निधन का कम ता कुल बर्न्याण नहा बढ़गा।

(2) राष्ट्रीय आय की वृद्धि का स्वरूप—हम राष्ट्रीय आय का वृद्धि क स्वरूप का अध्ययन करना होगा। यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि स्त्रिया तथा बच्चा या भ्रमिका स अधिक षण्ट काम करवा तथा उमर बढ़न म उह उचित पारभ्रमिक न दकर का मर है ता एसी स्थिति म राष्ट्रीय आय की यह वृद्धि समाज क आर्थिक बर्न्याण म वृद्धि का सूचक नहा होगा।

(3) जनसंख्या वृद्धि की दर—यदि जनसंख्या वृद्धि का दर राष्ट्रीय आय म वृद्धि दर स अधिक सज है ता इसका प्रति व्यक्ति आय गिरगा और तग का आर्थिक बर्न्याण गिरगा।

(4) जीमन स्तर म परिवर्तन की स्थिति—हम राष्ट्रीय आय का प्रचलित माद्रिक कामता म आरन । जीमन स्तर म वृद्धि या कामा राष्ट्रीय आय म वृद्धि या कामा का सूचक हानी है। कामन स्तर म यह परिवर्तन बिना बस्तुआ तथा मवाआ क वास्तविक उत्पादन म परिवर्तन क हा मता है। प्राय राष्ट्रीय आय का वृद्धि का अर हम आर्थिक बर्न्याण म वृद्धि म तग बँटन है आ शुनित्व है। वास्तविकता यह है कि कामन स्तर म वृद्धि बिना उत्पादन म वृद्धि क हान पर आर्थिक बर्न्याण बढ़न क स्थान पर गिर जाता है क्योंकि तग क रहन-सहन क स्तर म गिरावट आती ह।

(5) राष्ट्रीय आय वृद्धि की संरचना—राष्ट्रीय आय म वृद्धि क माध यदि प्रति व्यक्ति आय म वृद्धि हा ता हम इस आर्थिक बर्न्याण का वृद्धि का सूचकांक नहीं समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय आय की संरचना का अध्ययन हम भताभाति करवा हा यह पत कर सकत है। यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि उपभाग बस्तुआ क उत्पादन म न होकर पूजोगत बस्तुआ क उत्पादन म वृद्धि क फलस्वरूप हूर है ता यह आर्थिक बर्न्याण म वृद्धि का परिभाषा नहीं कहनाएगा। इसा प्रकार यदि कुछ बस्तुआ (Bar goods) क उत्पादन म वृद्धि क कारण राष्ट्रीय आय बढ़ा है ता म यह आर्थिक बर्न्याण म वृद्धि का सूचक नहीं होगा।

(6) लोग की अभिरचिया तथा मानवीय मूल्यो मे हास यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि क साथ-साथ तग का अभिरचिया तथा मानवीय मूल्यो म गिरावट आर ह ता इसका आर्थिक बर्न्याण घटन क स्थान पर गिरगा। अत्यधिक आय म वृद्धि क कारण तग का रनि मारक बस्तुआ क सबन वष्यावृत्ति तथा जुए आदि का तर्फ मुका है ता एसा स्थिति म समाज क आर्थिक बर्न्याण म तग का आर्थी विगम और आर्थी बर्न्याण गिरगा।

आर्थिक कल्याण में वृद्धि की कसौटी

यहां प्रश्न यह उठता है कि फिर आर्थिक कल्याण में वृद्धि का क्या कसौटी है ? राष्ट्रीय आय में वृद्धि का आर्थिक कल्याण का सूचक तभी माना जा सकता है जब कि (i) राष्ट्रीय आय वितरण निम्न व्यक्ति व अनुब्रूत हो (ii) आर्थिक कल्याण में वृद्धि की साम्यविक कसौटी उपभोग स्तर में वृद्धि अथवा लोगों के वास्तविक रहन-सहन में वृद्धि में लगाया जाना चाहिए। आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण निम्नो व अनुब्रूत होकर उनका रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना होता चाहिए। राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण का निम्नो के पक्ष में करने के लिए हम धनियों पर अधिक कर निम्नो को प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक सहायता आदि के द्वारा किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के पुनर्वितरण की एक शर्त यह है कि राष्ट्रीय आय का आधार किसी भी प्रकार से कम न हो अथवा इससे कुछ आर्थिक कल्याण बरेगा।

भारत में राष्ट्रीय आय (National Income in India) भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान स्वतंत्रता से बहुत पहले लगाया गया था। वर्ष 1866 में उदारवादी भारतीय नेता श्री लाला लाजपत राय ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 70 रुपये मात्र आंकी गई थी। वर्ष 1900 में लाड बज्जत ने समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 30 रुपये मात्र थी। इससे बाद अनेक विद्वानों ने राष्ट्रीय आय आकलन के प्रयास किए परंतु विश्वसनीय आंकड़ा के अभाव में यह अनुमान वास्तविकता से काफी दूर रहे। राष्ट्रीय आय के अनुमानों में सबसे अधिक विश्वसनीय अनुमान प्रो० डा० बी० वे० आर० बी० राव (Dr. B. K. R. V Rao) ने लगाया। वर्ष 1925-26 में उन्होंने भारत की आय 76 रुपये वार्षिक आंकी थी। जो बदलकर 1942-43 में 114 रुपये हो गई।

राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) — स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1941 में प्रो० पी० सी० महलनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई। भारतीय अधशास्त्र के विशेषज्ञ ए० बी० वे० आर० बी० राव तथा पी० गाडगिरी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ा तथा अन्य सम्बन्धी तथ्यों पर सामान्य एकीकृत करना था। वर्ष 1951 में इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जिसमें वर्ष 1946-49 के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1954 में समिति ने अपना अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वर्ष 1948-49 के लिए राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 1950-51 के राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान तथा उनका विस्तारणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इस समिति ने उत्पादन सगणना प्रणाली (Production Census Method) द्वारा खनिज उद्योग वृद्धि वनस्पति पशुधन से प्राप्त आय का अनुमान लगाया गया। व्यापार यातायात धरेलू संघाया तथा दस्तकारी में प्राप्त आय का अनुमान आय सगणना प्रणाली (Income Census Method) द्वारा लगाया गया तथा शेष धन का आय का अनुमान लगाने के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लिया गया।

वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान व आय साम्यविक संगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा लगाया जाता है। इस संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय पर प्रतिवर्ष एक श्वेतपत्र (White Paper) प्रकाशित किया जाता है। इस संगठन द्वारा प्रदत्त आँकड़ा राष्ट्रीय आय के विश्वसनीय आंकड़ा होता है।

भारत में राष्ट्रीय आय की लगभग सम्बन्धी कठिनाइयाँ — भारत में राष्ट्रीय आय का मापन मुख्यतः दो बारीक कठिनाइयों की वजह से राष्ट्रीय आय समिति की

धी। इसमें अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जानकारी में दो कठिनाइयाँ प्रमुख रूप से आती हैं।

(1) धारणामूलक (Conceptual) तथा 2 सांख्यिकीय (Statistical)

1 धारणामूलक कठिनाइयाँ—भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का दैन-दैन मुद्रा के माध्यम से होता है। जब कि वस्तु स्थिति यह है कि बाजार का एक क्षेत्र असंगठित होता है और उभय वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें अतिरिक्त यहाँ के लोग न आंगणित हान एवं अज्ञानता के कारण उत्पादक अपनी उत्पत्ति का लेखा जाता नहीं रख पाते तथा स्वयं उपभोग हेतु रखी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन की गणना करते समय ग्राहक नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग एक वर्ष में बड़े व्यवसायों अथवा कार्यों में लग जाते हैं और जो धन इनमें अर्जित करते हैं उसका गरीब-गरीब हिस्सा नहीं रख पाते इससे वास्तविक राष्ट्रीय आय का सही जमाना नहीं ठिकाना होता है।

(2) सांख्यिकीय कठिनाइयाँ—भारत में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जानकारी में विश्वसनीयता एवं सत्यता का अभाव पाया जाता है। यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है अन्य महायंत्र कार्यों तथा व्यवसायों में जाते तथा आय सम्बन्धी अंकितों का विश्वसनीयता प्रायः सन्देह रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय अंकितों का विश्वसनीय जानकारी का अभाव में राष्ट्रीय आय का अनुमान बचन अनुमान ही रह जाते हैं।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 राष्ट्रीय आय में आय क्या समझते हैं। इस संबंध में प्रा० मार्शल पीगू तथा फिशर के विचार बताइयें।

(What do you understand by National Income / Discuss the views of Prof Marshall Pigou and Fisher in this connection)

- 2 राष्ट्रीय लेखांकन में आय क्या समझते हैं? इसमें विभिन्न अंगों की व्याख्या बताइयें।

(What do you understand by National Income Accounting? Explain its various components)

- 3 राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिये और इस मापन की विधियाँ बताइयें।

(Define National Income and explain various methods for measuring National Income)

- 4 राष्ट्रीय आय का परिभाषित कीजिए। इसका मापन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(Define National Income What are the difficulties faced while measuring National Income?)

- 5 राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण के सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए। क्या यह कहना सही है कि कुल राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि करती है?

(Explain the relationship between National Income and Economic Welfare Is it correct to say that increase in the size of aggregate National Dividend must cause an increase in Economic Welfare?)

- 6 राष्ट्रीय राशाम मे आयतु तात्पर क्या है ? आर्थिक विकाश म इनका सम्बन्ध का स्पष्टीकरण कीजिये ।

(What do you mean by National Income ? Explain its relation ship with Economic Welfare)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

1 कुन राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद म अंतर बर पुर हाता है—

- (i) अन्त्यक्ष बर
- (ii) अत्यंत तर
- (iii) मूल्यह्रास या घिसावट (Depreciation)
- (iv) टिकाऊ वस्तुआ पर उपभाक्ता व्यय
- (v) उपभोग्य आय ।

उत्तर —(iii) सही है ।

2 वैयक्तिक आय (Personal Income [PI]) बराबर होनी है

- (i) राष्ट्रीय आय—तर
- (ii) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—घिसावट
- (iii) राष्ट्रीय आय—हस्तांतरण भुगतान
- (iv) राष्ट्रीय आय—सामाजिक सुरक्षा के अश्वदान—निगम आयकर—अवितरित निगम राश—हस्तांतरण आय
- (v) व्यय योग्य आय—प्रत्यक्ष कर

उत्तर (iv) सही है ।

3 शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNP) बराबर हाती है ।

- (i) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—घिसावट व्यय
- (ii) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—आयात
- (iii) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—हस्तांतरण आय
- (iv) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर
- (v) कुन राष्ट्रीय उत्पाद + निर्यात

उत्तर—(i) सही है ।

Full employment is the point beyond which output proves inelastic in response to further increase in effective demand "
—Dudley Dillard

अध्याय 3

बेरोजगारी तथा पूर्ण रोजगार

(Unemployment and Full Employment)

बेरोजगारी कतमान नहीं प्रचार की अवस्थितयाया म विना न किसी रूप म दगन का मितनी है । बेरोजगारी एउ परिभाषा है और मानव ज्ञानि क रिक्त एक कदम है । बेरोजगारी एउ व्यक्ति क रिक्त मवम बढा कट है इसका कुप्रभाव रक्षन बेरोजगार व्यक्ति पर ही नहीं पढता बरन् सम्पूर्ण समाज का इसर दुष्परिणाम भुगनन परते है ।

बेरोजगारी का अर्थ—बेरोजगारी का अर्थ उम व्यक्ति स रगाया जाता है जबकि व्यक्ति काम करने म मध्यम हा काय करन का इच्छुन हा परन्तु रोजगार अवसर का अपूर्णताभा तथा कमी क कारण उम रोजगार नहीं मित पाता । एउ अपेक्षामयी दृष्टि-कोण से बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है । एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपनी कामकुशलता एउ योग्यता के अनुसार मजदूरी की प्रवर्तित दर पर काम करने की तैयार है परन्तु उसे काम नहीं मित पाता है । (An unemployed person is that person who is seeking work at the prevailing wage rate according to his efficiency and qualifications but he is unable to seek any job)

इस कथन का जागय यह है कि समाज म कुछ लोग दूर समय एग पाए जायेग जा काय करन पाय्य है तथा कार्य करना ही नहीं चाहत । ऐग लोग अपना इच्छा से बेरोजगार रहते है क्यकि ऐमे व्यक्ति कार्य करन के इच्छुन ही नहीं ह्यो । अर्थशास्त्र म इसे ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary unemployment) कहत है और इस प्रकार की बेरोजगारी का अध्ययन एग अर्थशास्त्री नहीं करता । इनके विपरीत कुछ ऐम बी व्यक्ति हात है जा कार्य करन के योग्य है, कार्य करना भी चाहते है परन्तु उन्हें काय नहीं मितता ऐमी बेरोजगारी का, दूय, अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary unemployment), कहन है । एग अर्थशास्त्री का सम्बन्ध अनैच्छिक बेरोजगारी का अध्ययन करे उमरे समाधान हेतु मुद्राव देना है । हम बेरोजगारी के मरूप उमरे कारण तथा इसमे सम्मिलित कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन करेग ।

ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी

(Voluntary and Involuntary Unemployment)

बेरोजगारी के दो प्रमुख रूप है (i) ऐच्छिक बेरोजगारी (ii) अनैच्छिक बेरोजगारी

(I) ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)

ऐच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति कार्य करने की योग्यता रखता है, उसे प्रचलित मजदूरी पर कार्य मिल भी सकता है परन्तु वह अपनी इच्छा से कार्य करना नहीं चाहता। ऐसे लोग समाज में हर समय पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन नहीं करता। ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्न हो सकते हैं—

(1) व्यक्ति आत्मोपनिवेश या पारिवारिक त्याग के कारण मजदूरी मिलने पर भी कार्य नहीं करना चाहता।

(2) प्रचलित मजदूरी की दरें व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप भी न हों तो भी व्यक्ति रोजगार में लगना नहीं चाहता।

(3) अत्यधिक सम्पन्नता एवं धनवान होने के कारण व्यक्ति कार्य करना नहीं चाहते हैं।

(4) आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में जैसे चोर डकैत या समाज विरोधी तत्वों में भी ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है।

(II) अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment)

अनैच्छिक बेरोजगारी का आशय उन स्थिति में होता है जबकि व्यक्ति कार्य करने के योग्य कार्य करने का इच्छुक हो फिर भी उसे उम्मेद प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य उपलब्ध न होता हो। हम अनैच्छिक बेरोजगारी को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

जब कार्य करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने का इच्छुक भी हो परन्तु उसे रोजगार के अवसरों की कमी के कारण रोजगार उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहलाएगी।" एक अर्थशास्त्री का सम्बन्ध अनैच्छिक बेरोजगारी का अध्ययन करते-उसके सम्बन्धन हेतु सुझाव देना होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी कई कारणों से हो सकती है जैसे प्रभावपूर्ण माँग में कमी का होना, तकनीकी परिवर्तन, गम समाज की अपूर्णताओं, मौसमी कारणों तथा वकीय उच्चावचन आदि द्वारा।

अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार (Types of Involuntary Unemployment)—

अनैच्छिक बेरोजगारी कई कारणों से हो सकती है जो ऊपर बताए जा चुके हैं। इन्हीं कारणों के आधार पर अनैच्छिक बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार हैं—

(1) संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)—संरचनात्मक बेरोजगारी का आशय अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण बेरोजगारी के होने में लगाया जाता है। ऐसी बेरोजगारी मुख्य रूप से अर्द्ध-विकसित देशों में पाई जाती है। ऐसी बेरोजगारी क्षमपूर्ति का उसकी माँग से अधिक होने से होती है। देश में भूमि तथा पूँजीगत साधन सीमित हों और जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण लम्बे समय तक व्यक्ति को बेरोजगार रहना पड़ सकता है। क्षमताओं की माँग में पूर्ति नहीं अधिक हो जाती है। प्रो. बेन्हम ने संरचनात्मक बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है "संरचनात्मक बेरोजगारी, निम्नप्रतिफल स्पर्धात्मक बेरोजगारी की अपेक्षा अधिक दीर्घकालिक होती है और इसे अर्थव्यवस्था के स्थायी एवं पर्याप्त आर्थिक विकास से हो दूर करना सम्भव होता है।" इसका आशय यह है कि स्थायी आर्थिक विकास के द्वारा ही इस प्रकार की बेरोजगारी से निपटा जा सकता है। आर्थिक विकास से रोजगार के आधक अवसर उपलब्ध होंगे—अधिक आय बढ़ेगी—अधिक माँग—अधिक साम बढेगा—अधिक पूँजी निविर्षोजन होगा—आर्थिक विकास में निरन्तरता बनी रहेगी।

(ii) घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)—घर्षणात्मक बेरोजगारी में आशय अन्तरिम तार में उत्पन्न होने वाली अस्थायी बेरोजगारी में होता है। ऐसी बेरोजगारी कुछ समय बाद स्वयं ही समाप्त होने लगती है। इस प्रकार की बेरोजगारी बर्त कार्यों में हो सकती है जैसे रोजगार के अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों में व्याप्त गतिहीनता, बच्चे मान की उम्र, मशीनों की टूट-फूट सरकारों नियंत्रण, श्रमिकों में गलत भाव आदि। इस प्रकार की बेरोजगारी भी सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। प्रत्येक देश में उक्त कारणों से कुछ न कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं। प्रो० डी० टिनाई ने अपने शब्दों में घर्षणात्मक बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए कहा है कि “घर्षणात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोगों को थोड़े समय के लिए काम नहीं मिल पाता है।”

घर्षणात्मक बेरोजगारी का स्तर आर्थिक विकास के साथ-साथ बढ़ता घटता जाता है। आर्थिक विकास में नई-नई विधियों की उत्पादन में अपनाते से उत्पत्ति के माध्यमों और उनकी माँग के स्वरूप में परिवर्तन होने रहते हैं, कुछ नए उद्योगों का विकास होने लगता है तथा पुराने उद्योगों का महत्व कम होने लगता है। इस आर्थिक परिवर्तन के कारण कुछ लोग पुराने व्यवसायों को छोड़कर नए व्यवसायों में रोजगार की तलाश करने लगते हैं। इस प्रकार घर्षणात्मक बेरोजगारी दिव्यमाने देती है।

(iii) तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment)—तकनीकी बेरोजगारी का स्वरूप भी अस्थायी होता है। ऐसी बेरोजगारी नवीन तकनीकी के प्रयोग के कारण मशीनों का आधुनिकीकरण विशेषीकरण तथा वैज्ञानिक विधियों आदि के द्वारा होती है। जब उत्पादन के क्षेत्र में लागत घटाने तथा लाभ की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से नई उत्पादन विधियाँ एवं नव-प्रवृत्तियाँ आदि की नीति अपनाई जाती है तो उसके कारण उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है।

(iv) मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—एक अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वहाँ भर कार्य नहीं रहता। इनमें कार्य करने वाला के लिए एक वर्ष में कुछ महीने के लिए काम करना पड़ता है। चूँकि उद्योग वृत्ति क्षेत्र, वर्ष के कार्यों, चारों दिनों आदि में लोगों को पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नहीं होता।

(v) अदृश्य या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)—छिपी बेरोजगारी का अर्थ व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता या कार्यक्षमता के विपरीत कम उत्पादन प्रियाओं में कार्य करना होता है। छिपी बेरोजगारी की स्थिति का आशय किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के अधिक दबाव का आवश्यकता में अधिक बढ़ता होता है। श्रीमती जान गविन्सन के शब्दों में “छिपी या अदृश्य बेरोजगारी यह स्थिति है जिसमें अधिक आलस, अधिकतर के लिए, अपनी योग्यता के विपरीत, कम उत्पादन व्यवस्थाओं में धकेल दिए जाते हैं।”¹ विकासवादी विचारक प्रो० रेसनर नामों का कहना है कि अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति अर्द्ध-विकसित देशों में अधिक दिव्यमाने देती है। वह कहते हैं कि ऐसे देशों में पाया यह देखने को मिलता है कि जहाँ 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होती

1. “Disguised unemployment is a situation in which the wage workers take to less productive jobs because they lose their regular jobs owing to cyclical ebb in economic activity.”

—Smt Joan Robinson

है वहाँ 7 व्यक्ति लगे होते हैं। यदि इस 7वें व्यक्ति को रोजगार में रखा गया तो हमसे उत्पादन में कोई बर्बादी नहीं आती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देवता में 7वा व्यक्ति रोजगार में अवश्य ही लगा मायूम होता है परन्तु वास्तव में वह बेरोजगार होता है। एक उदाहरण द्वारा छिपी बेरोजगारी को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। माना कि एक व्यक्ति किसी प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त है परन्तु रोजगार अवसरों की कमी के कारण उसे अपनी योग्यता से नीचे पढ़ पढ़ कार्य करना पड़े जैसे एक इन्जीनियर को एक मैकेनिक या फोर्मेन के पद पर कार्य करना पड़े तो इसे छिपी बेरोजगारी कहेंगे।

(vi) चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—चक्रीय बेरोजगारी से आशय व्यापार चक्रों अथवा कभी तेजी और कभी मंदी के होने से उत्पन्न होती है। जब कभी वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग उनके उत्पादन से कम हो जाती है तो कुछ माल बिना बिके रह जाता है बीमते गिरने लगती है, उत्पादन के मध्य निराशावादिता दबने की मिलती है, उत्पादन गिरने लगता है और पूँजी निवेश गिरने लगता है। यह स्थिति मंदी काल की स्थिति कहलाती है। मंदी में एक ओर उत्पादन कम होने लगता है क्योंकि उत्पादन कार्य प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण गिर जाता है दूसरी ओर उत्पादन कार्य में लगे हुए श्रमिकों की छुट्टी होने लगती है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। चक्रीय बेरोजगारी पूँजीवादी तथा विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में दिखाई देती है। तेजी तथा मंदी (Boom and Depression) के कारण लोगों के आय के स्तर, मुद्रा की मात्रा विनियोग उपभोग तथा घोमते-स्तर में परिवर्तनों के कारण ऐसी बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है।

(vii) अस्थायी बेरोजगारी (Casual Unemployment)—जैसा कि हम जानते हैं कि श्रमिकों की माँग व्युत्पन्न (Derived Demand) होती है अर्थात् उनकी माँग प्रत्यक्ष न होकर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है। उत्पादन उतना ही किया जाता है जितना कि वस्तुओं की माँग होती है। श्रम की माँग उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है। इस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति अस्थायी होती है। ऐसी बेरोजगारी नियमित उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों में देखने को मिलती है जिनकी वस्तुओं की माँग में उठाव-चढ़ाव आते रहते हैं परन्तु यह उठावचढ़ाव अस्थायी होते हैं।

बेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)—बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसमें कि कोई एक कारण विशेष उत्तरदायी नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर हमसे कई कारण बताए हैं। विभिन्न देशों में बेरोजगारी का स्वरूप भिन्न-भिन्न दिखता है इसलिए बेरोजगारी के लिए न तो एक प्रकार के कारण ही उत्तरदायी हैं और न ही उनके समाधान के लिए एक प्रकार के सुझाव दिए जा सकते हैं। मोटे तौर पर बेरोजगारी के कारणों में सम्बन्ध में निम्न विचारधाराओं का उल्लेख जरूरी है—

(1) बेरोजगारी का अव्यक्त नीति सिद्धान्त (Laissez Faire Theory of Unemployment)—इस सिद्धान्त के समर्थक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। उनका ऐसा विश्वास था कि जब अर्थव्यवस्था के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है तो बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। इस विचारधारा के समर्थक प्रा० एडम स्मिथ, जे० ओ० से, रिचार्ड्स, जे० एच० मिल तथा अन्य प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन विद्वानों का कहना था कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप की नीति के कारण बेरोजगारी होती है। वह विद्वान

(1) जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना—अल्प विकसित देशों में अधिक बराजगारा का एक प्रमुख कारण तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर प्रतिशत से लेकर 2.5 प्रतिशत वार्षिक रहती है। विकसित देशों की अपेक्षा अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। बढ़ा हुई जनसंख्या अधिक भूमि की पूर्ति बनाती है। नवीन रोजगार अवसरों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि का दर तेज होती है और बेरोजगारी की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। आज अल्प विकसित देशों में भूमि की उपलब्धता अधिक होने और उच्च रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने से भूमिहीनता का हास हो रहा है।

(2) कृषि प्रधान अवस्था—अधिकांश अल्प विकसित देश कृषि प्रधान हैं। कृषि प्रधान देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य में मिलने वाली प्रति व्यक्ति में प्रत्यक्ष अधिकांश अनाधिक जोतों का होना कृषि पर अधिक दबाव आदि की स्थिति पैदा होती है। कृषि प्रधान अवस्थाओं में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने में आती हैं प्रथम तो जनसंख्या का दबाव कृषि पर अधिक होता है और उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। दूसरे कृषि व्यवसाय अनिश्चित एवं मौसमी है। आज भी अधिकांश कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के लोगों में निधनता का प्रमुख कारण अधिकांश लोगों की कृषि पर निर्भरता है अपनी निधनता के कारण कृषि पर निर्भर उद्योगों जैसे पशु या मृगी पालन मछली पालन कुटार उद्योगों का अभाव का कारण जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता रहती है।

(3) धीमी औद्योगिक विकास—अल्प विकसित देशों में औद्योगिक विकास की गति धीमी होती है इसका प्रमुख कारण वैज्ञानिक तथा तकनीक का पिछड़ापन पूँजी का अपर्याप्त उपलब्धता तथा माहौल प्रवृत्ति का अभाव होता है। ऐसे देशों में यदि औद्योगिक विकास अधिक तेजी से हो और विविध उद्योग जैसे बड़े उद्योग के साथ मध्यम तथा छोटे उद्योगों का पर्याप्त विकास हो तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी का प्रभाव कम हो जाता है।

(4) आर्थिक पिछड़ापन—अल्प विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन या धीमे आर्थिक विकास के कारण बेरोजगारी की अधिकता बनी रहती है। सामान्यतया ऐसे देशों में विकास की औसत दर 3 प्रतिशत के आस पास या इससे भी कम होती है। आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण न होना कृषि पर निर्भरता औद्योगिक पिछड़ापन परम्परावादी एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है। आर्थिक पिछड़ापन का मोधा मध्यम आर्थिक विकास दर से होता है तथा ऐसे देशों में बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आती है।

(5) निरक्षरता एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली—अल्प विकसित देशों में निरक्षरता एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का कारण बेरोजगारी अधिक दिखाई देती है। शिक्षा प्रणाली व्यवसाय प्रधान नहीं होती है। यह शिक्षा लोगों की कमी के कारण भी रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं होने पाते। इसके लिए हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके इस रोजगार उन्मुख बनाया जाय। लोगों में व्याप्त निरक्षरता को दूर करना होगा जिससे इनके दृष्टिकोण में बदलाव आए और वह परिस्थितियों का अनुरूप अपने को ढाल सकें।

पूर्ण रोजगार (Full Employment)—एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूर्ण रोजगार से आशय देश के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना हो सकता है परंतु सभी व्यक्तियों को रोजगार दिवाना सम्भव नहीं होता। अव्यवस्था वाले विकसित हो या अल्प विकसित उसमें अच्छे धनसाध्यक एवं सरचनात्मक बराजगारा बिना किसी रूप में पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की धारणा में निरक्षरता को दूर करने के विधान में

कहा है कि 3 से 5 प्रतिशत लोग हमेशा ही ऐच्छिक, धर्षणात्मक एवं मरचनात्मक बेरोजगारी के अन्तर्गत रहते हैं इसलिए यदि देश की जनसंख्या का 95 प्रतिशत भी रोजगार में लगा हो तो उसे पूर्ण रोजगार की मंजा देना चाहिए। मर विलियम बेयरिज तथा कोन्स जैसे विद्वानों ने पूर्ण रोजगार का आशय इसी मदर्भ में लिया है। इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी का कोई स्थान नहीं होता।

पूर्ण रोजगार की परिभाषा—पूर्ण रोजगार के मदर्भ में विभिन्न धारणाओं के अध्ययन के बाद ही हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को आगामी में सम्मिलित सकते हैं।

(i) **प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणा—**प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार को एक सामान्य घटना मानते हैं। इनके अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति वह स्थिति है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी पाई नहीं जाती। थोड़ी बहुत मात्रा में ऐच्छिक मरचनात्मक एवं धर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जा सकती है। (Full Employment is Characterised by Absence of Involuntary Unemployment) इन विद्वानों ने पूर्ण रोजगार का अर्थ उस स्थिति में लिया है जिसमें कार्य करने के इच्छुक लोगों को प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य उपलब्ध हो जाता है। प्रो० ए० पी० लनर ने इसी मदर्भ में पूर्ण रोजगार को परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें बिना किसी कठिनाई के प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य चाहने वाले को रोजगार मिल जाता है।¹

(ii) **जे० एम० कोन्स की धारणा—**जे० एम० कोन्स प्रतिष्ठित विद्वानों की उस विचारधारा में बिन्दुल महमत नहीं है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था एक सामान्य घटना है। वे यह तो मानते हैं कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने पूर्ण रोजगार की अवस्था में मरचनात्मक धर्षणात्मक तथा ऐच्छिक बेरोजगारी के होने की जो बात की है वह ग़रीब होती है। वे प्रतिष्ठित विद्वानों के इस विचार में भी महमत नहीं है कि मजदूरी की दर में बढ़ोती ने बेरोजगारी समाप्त हो जायगी। कोन्स ने कहा कि साम्यविक स्थिति अपूर्ण रोजगार के पाग जानने की हाती है तथा बेरोजगारी को मजदूरी बढ़ोती के स्थान पर प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके कम किया जा सकता है।

प्रो० कोन्स ने पूर्ण रोजगार की स्थिति का सामान्य घटना न मानते हुए उसे प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार किया है। कोन्स के शब्दों में "पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें बाद प्रभावपूर्ण माँग में प्रत्येक वृद्धि उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं करती तथा प्रभावपूर्ण माँग में कोई भी वृद्धि कीमतों में वृद्धि लायगी और व्यवहारिक दृष्टि में कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा।"²

(iii) **आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा—**प्रो० ए० पी० लनर ने पूर्ण रोजगार को परिभाषित करते हुए कहा है कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें प्रचलित

- 1 "Full employment is a situation in which all those who want to work at the existing rate of wage get work without any undue difficulty."

—A. P. Lerner.

- 2 "Full employment is a situation which involves an appropriate amount of effective demand, a unique level of employment beyond which no further increase in output and employment are possible and any increase in effective demand will lead to a more rise in prices and practically no increase in employment." J. M. Keynes

मजदूरी की दर पर बिना किसी विशेष बठिनाई के इच्छुक व्यक्ति का काम मिल जाता है। प्रो० सनर के बिना किसी बठिनाई वाक्यांश का अर्थ कुल व्यय में वृद्धि बरके (मुद्रा प्रमाण बिना) रोजगार में अवसरों में वृद्धि करने से है।

१० डिनाट के शब्दों में पूण रोजगार वह बिंदु होता है जिसके पश्चात् प्रभाव पूण मांग में वृद्धि होने पर उत्पत्ति बेसोच सिद्ध होती है।²

संयुक्त राष्ट्र सघ (United Nations Organisations) की एक रिपोर्ट में पूण रोजगार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पूण रोजगार का स्थिति वह अवस्था माननी जानी चाहिए जिसमें प्रभावपूण मांग में वृद्धि होने पर रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

प्रो० ई० नौरस के शब्दों में आदर्श रूप से पूण रोजगार की अवस्था वह होगी जो अधिकतम उत्पादन तथा लोगों की वास्तविक न्यय शक्ति को प्रोत्साहित करेगी।³

सर ब्रिजियम वेबरिज ने पूण रोजगार को परिभाषित करते हुए कहा है कि पूण रोजगार वह अवस्था है जहाँ बेरोजगारी से अधिक रिक्त स्थान पाये जाते हैं जिससे एक कार्य को तीन तथा दूसरे को प्राप्त करने के मध्य समय बिगड़ बहुत ही कम होता है।⁴

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जब एक देश में 3 से 4 प्रतिशत तक बेरोजगारी पाई जाती है तो उस देश में पूण रोजगार की प्राप्ति कर ली गई है। अर्द्ध० एल० ओ० द्वारा पूण रोजगार की अन्य शर्तें यह हैं कि इसमें किसी प्रकार श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए तथा श्रामक बिना किसी विलम्ब के रोजगार प्राप्त करने योग्य होना चाहिए।⁴

पूण रोजगार के मुख्य लक्ष्य—पूण रोजगार की धारणा का समर्थन के लिए हम इससे सम्बन्धित मुख्य तथ्यों को देखना होगा।

(1) पूण रोजगार की स्थिति वह होती है जिसमें बेरोजगारी की न्यूनतम मात्रा 3 से 5 प्रतिशत तक बनी रहती है। इसका आशय यह है कि यदि किसी समय किसी देश

1 Full employment is the point beyond which output proves inelastic in response to further increase in effective demand

—Dudley Dillard

2 Full employment may be considered as the situation in which employment cannot be increased by an increase in effective demand

—Dudley Dillard

3 Ideally full employment would be such as promote continuous maximisation of production and real purchasing power for the people

—Nourse

4 Full employment is a situation where there are more vacant jobs than unemployed men so that normal lag between losing one job and finding another will be very short

—William Beveridge

5 that when only 3 percent to 4 percent unemployment exists in a country the country can be said to have reached full employment Other conditions of full employment mentioned by I L O are that there should be no exploitation of labour and that the workers should be able to find alternate employment early

—I L O Report on Full Employment

म 95 म 98 प्रतिज्ञा तर रायगीर जनमस्या वा गोजगार मिसा हुआ हा ता उगे पूर्ण गजगार की स्थिति मानता चाहिए ।

(2) पूण गजगार वह स्थिति हाती है जिसम प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य चाहत वान की राजगार के अन्तर उपलब्ध हा ।

(3) पूण गजगार की अवस्था मे अभिप्राय उम अवस्था स हाता है जबकि वराजगार व्यक्तियों की तुलना म रिक्त स्थान आधार मात्रा म उपलब्ध हा जिसम कि वराजगार व्यक्त व राजगार प्राप्त करने म अधिक कठिनाई न हा ।

(4) पूण राजगार स्तर प्राप्त हा जान क बाद अव्यवस्था म कुन व्यय या प्रभावपूर्ण माँग म वृद्धि हान पर उत्पादन तथा राजगार म वृद्धि नहीं होगी ।

अर्द्ध-विकसित देश तथा पूर्ण रोजगार—पूण राजगार की विभिन्न धारणाओं विवक्षित अवस्थाओं म सम्मिश्रित है । जहाँ वराजगारी का प्रमुख कारण प्रभावपूर्ण माँग म ध्यात कमी हाती है । अर्द्ध-विकसित अव्यवस्था वान दशा म पूण राजगार की स्थिति कभी नहीं पाई जाती ब्याकि कम दशा म वराजगारी पूँजी के अभाव तथा तकनीकी प्रगति क अभाव क कारण होती ह न कि प्रभावपूर्ण माँग म कमी क कारण । अर्द्ध विवक्षित दशा म अदृश्य वराजगारी संरचनात्मक वराजगारी घणनात्मक वराजगारी आदि पाई जाती है । कम अदृश्य वराजगारी की प्रमुखता रहती है । फिर भी कम दशा म सरकार द्वारा कय प्रकारा राज्य का हस्तगत हातु डा मकल्प किए जात है उनम पूण राजगार का नश्य मानकर वराजगारी दूर करने क प्रयास किए जात ह ।

पूर्ण रोजगार की नीति (Policy for Full Employment)—वराजगारी मानव जानि व शक्ति मजदूरी का अभाव है । वराजगारा क दुप्रभाव म उपरब्ध श्रम शक्ति क हानि हा है हा साथ हा साथ कम मजदूरी आय तथा राष्ट्रीय उत्पादन म कमी म रहन-सहन क स्तर म गिरावट होय तथा हीन भावना तथा रम सचय आदि बुरीनियों पनपत । म इस कारण पूण राजगार की नीति ही लगी हा सबसे है जिस अपनाकर समाज वराजगारी क दुप्रभाव म बच सकता है । पूण राजगार हनु राष्ट्रीय नीति का हाता वान आवश्यक है । परन्तु पूण राजगार की स्थिति का प्राप्त करना आसान काय नहीं है । पूण राजगार हनु निमित्त मौद्रिक तथा राजस्वपोष्य नीतिया का मिश्रण हाता है । जैसा कि हम जानत ह विवक्षित तथा अर्द्ध विवक्षित अवस्थाओं म मौद्रिक तथा राजस्व नीतिया उ उद्देश्य म विभिन्नता पाई जाती है इसलिए पूण राजगार प्राप्ति हनु दूत दशा क प्रयत्न न भी अनिवार्य का मितता है । विवक्षित दशा म आर्थिक स्थिरता का बनाए रखकर पूण राजगार प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तथा महत्वपूर्ण माँग म वृद्धि क द्वारा वराजगारी का दूर किया जाता है । अर्द्ध-विकसित दशा म अधिक विवक्षित नीति का नीति करने का प्रमुख समस्या हाती है और कम दशा म पूँजी के अभाव तकनीकी अज्ञानता का दूर करके तथा उपलब्ध प्रकृतिक साधनों का समुचित विदाहन करके वराजगारा का दूर करने क प्रयास किए जात है । पूण राजगार प्राप्ति हनु निम्नान्वित नीतियाँ कम अपनाने जा सकत ह —

(1) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

मौद्रिक नीति क अन्तर्गत क सभी उपाय वान ह जिसका सरकार जनता द्वारा किए जात वान कुन व्यय का विनियमित करने क लिए करती ह । मौद्रिक नीति विभिन्न उद्देश्यो का पूर्ति क लिए अपनाई जा सकती ह इनम पूण राजगार की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य है । मौद्रिक नीति क अन्तर्गत मुद्रा तथा माँग नीति का नियन्त्रित करने पूँजी विनियोजन प्रभावपूर्ण माँग तथा राजगार के स्तर का प्रभावित किया जाता है । पूँजीवादों एवं विक-

मित अर्थव्यवस्था में संचयी उच्चावचन को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति का भी उपयोग किया जा सकता है। मंदीकाल और तजीकाल (Depression and Boom) जैसे अर्थ-स्थिरता में मौद्रिक नीति कारगर साबित हो सकती है। मंदीकाल में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति (चानूनी तथा साख मुद्रा) में वृद्धि के लिए जो उपयोग के बंध को अपनाना चाहिए उनमें (i) चानूनी तथा साख मुद्रा की पूर्ति बढ़ना (ii) व्याज की दर में कमी करना (iii) प्रारक्षित निधि अनुपात (Cash Reserve Ratio CRR) तथा संचयनिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio SLR) का राष्ट्रीय बैंक के पास देश के विभिन्न व्यापारिक बैंकों के लिए रखना आवश्यक होते हैं। ये सभी करना होना चाहिए। मंदीकाल में यह उपाय मजदूरी मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) कहलाता है। इनका उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके पूर्ण विनियोजन में वृद्धि करना होता है विशेषतः पर सावजनिक व्यय में वृद्धि करना क्योंकि मंदीकाल में निजी व्यय साहसिकता में व्याप्त निराशावादित्वा के कारण प्रायः नहीं होता। तेज काल में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति में कमी करना होना चाहिए जिससे अनावश्यक व्यय पर रोक लग सके। इस प्रकार मुद्रा का मात्रा का प्रभावित करने पूरा रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

एक देश की सरकार पूरा रोजगार का प्राप्ति हेतु मौद्रिक नीति के अलावा राजकोषीय नीति का भी सहारा लेती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सावजनिक आय व्यय कर व्रण तथा बजट सम्बन्धी नीतियाँ आती हैं। इन नीतियों के माध्यम से सावजनिक आय व्यय प्रभावपूर्ण माँग उपभोग विनियाम आदि का प्रभावित करने रोजगार का स्तर को प्रभावित किया जाता है। मंदीकाल में सरकार उपभाग व्यय तथा विनियाम व्यय दोनों में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है जिससे कि प्रभावपूर्ण माँग बढ़ी रहे और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। मंदी के समय सावजनिक व्ययों में वृद्धि अप्रत्यक्ष करों में कमी वरन् उपभाग प्रवृत्ति को बढ़ाया जाता है। तजीकाल में सरकार का सावजनिक व्यय में कमी करने तथा सावजनिक आय वृद्धि हेतु उपाय करने चाहिए।

अन्य उपाय एवं नीतियाँ (Other Measures and Policies)—पूरा रोजगार प्राप्ति हेतु अन्य उपाय तथा नीतियाँ भी अपनाई जा सकती हैं जैसे—

1. मजदूरी नीति (Wage policy)—प्रतिष्ठित अधशास्त्रियाँ का मान्यता थी कि मजदूरी कटौती नीति¹ (Wage cut Policy) द्वारा पूरा रोजगार का स्तर का प्राप्ति किया जा सकता है। परन्तु प्रो० कीन्स प्रतिष्ठित अधशास्त्रियों का इस विचार का सहमत नहीं है उनका कहना है कि रोजगार स्तर को बढ़ाने के लिए मजदूरी को कम करना पर प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करनी चाहिए। परन्तु आधुनिक अधशास्त्रियों का कहना है कि कीन्स के प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि के तर्क में भी बड़ी त्रुटि है जो पौधू के मजदूरी कटौती सिद्धान्त में है।

आधुनिक अधशास्त्रियों का मत है कि रोजगार के लिए मजदूरी नीति क्या है। यह बात कई बातों पर निर्भर करती है। पूरा रोजगार प्राप्ति हेतु एक ऐसा नीति अपनाया चाहिए जिससे स्फीतिक एवं अवस्फीतिक स्थितियाँ न उत्पन्न हों। अर्थात् सन्तुलित मजदूरी नीति (Balanced Wage Policy) होनी चाहिए। मजदूरी नीति पौद्रिक मजदूरी का प्रभाव-

1. प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धान्त में प्रा पौधू ने पूरा रोजगार हेतु मजदूरी कटौती सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसका विवरण अध्याय 4 में किया गया है।

वित्त करती है वास्तविक मजदूरी को नहीं। देखा जाए तो वास्तविक मजदूरी ही महत्वपूर्ण होती है। परन्तु मजदूरी नाति का सम्बन्ध मौद्रिक मजदूरी से ही होता है। मजदूरी नीति ऐसी हो कि जिससे श्रमिक तथा उत्पादक दोनों ही वर्गों के हितों की सुरक्षा हो सके। इसका आशय यह है कि मजदूरी की दर इतनी अधिक न हो जिससे कि लागते इतनी बढ़ जाये कि उसका लाभ श्रमिकों को न मिल सके और मजदूरी इतनी कम भी न हो जिससे कि श्रमिकों के लिए जीवन यापन ही दुर्लभ हो जाए। मजदूरी दर व लाभ के अनुपात में उचित सन्तुलन रहना चाहिए।

मजदूरी नीति इस प्रकार से भी निदिष्ट हो कि उद्योगों व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में मजदूरी दर विशिष्ट रूप से प्रभावित की जाए न कि मजदूरी के सामान्य स्तर को। इसके साथ ही मजदूरी नीति ऐसी हो जिससे मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं की कीमता में स्थिरता बनी रहे। स्थिर कीमता के साथ बढ़ती हुई मजदूरी नीति अपनाता अधिक श्रेयस्कर होता है।

प्रो० ए० पी० लनर का कहना है कि मजदूरी नीति सापेक्ष आकर्षण सूचकांक (Index of Relative Attractiveness) पर आधारित होनी चाहिए। मजदूरी नीति ऐसी हो ताकि उत्पादकता में वृद्धि के साथ मजदूरी में भी वृद्धि की जा सके। उन स्थानों में मजदूरी में तेजी से वृद्धि होना चाहिए जहाँ पर सापेक्ष आकर्षण सूचकांक राष्ट्रीय औसत सूचकांक में नीचा हो तथा उन स्थानों में मजदूरी दर कम हो जहाँ सापेक्ष आकर्षण सूचकांक राष्ट्रीय औसत सूचकांक से ऊँचा हो।

2. कीमत नीति (Price Policy)—पूरा राजगार की प्राप्ति हेतु कीमत समर्थन नीति भी अपनाई जा सकती है। मदी के समय कीमतों जब गिरती हैं तो सरकार का न्यूनतम कीमतें घाटित करना चाहिए परन्तु यदि कीमत स्तर इस निर्धारित कीमत स्तर से नीचे जान की प्रवृत्ति दिखलाए तो स्वयं सरकार को अनिश्चित स्टॉक की खरीद करना चाहिए। जब तेजी काल में कीमत-स्तर अनावश्यक रूप से बढ़ रहा हो तो उसका बाजार में बित्री हेतु लाकर वस्तुओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार मदी तथा तेजी काल दोनों ही स्थितियों में समर्थन कीमत नीति (Price Support Policy) अपनाकर राजगार में वृद्धि करना सम्भव होता है।

3. धम बाजार की अपूर्णताओं को दूर करने की नीति (Policy for Removing Imperfections of Labour Markets)—इस नीति का आशय यह है कि विभिन्न व्यवसायों एवं क्षेत्रों में श्रमिकों की माँग तथा पूर्ति में समुचित स्थापित करना चाहिए। इस के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं —

(i) जिन क्षेत्रों या व्यवसायों में श्रमिकों की माँग अधिक हो उनमें उनकी पूर्ति हेतु निरन्तर सरकार को सजग रहना चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

(ii) रोजगार कार्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे कि बेरोजगार व्यक्ति वहीं पहुँचकर अपना पंजीकरण करा सके तथा राजगार सृजन करने वाले प्रतिष्ठान इन कार्यालयों में रिक्त स्थानों की सूचना दे सके।

4. उपभोग में वृद्धि (Increase in Consumption)—बराबरगरी दूर करने के लिए माँग का निरन्तर बन रहना भी आवश्यक होता है जो बिना उपभोग वृद्धि के सम्भव नहीं होता। इसके लिए विशेषतः पर मन्दोक्त में सरकार को आवश्यकित्व व्यय बढ़ाने चाहिए जिससे लोगों को आय बढ़े तथा उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो क्योंकि उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करेगी। परिणामस्वरूप रोजगार का स्तर भी ऊँचा उठेगा।

5 विनियोग में वृद्धि (Increase in Investment)—पूण काम में विनियोग में वृद्धि द्वारा अल्पकाल में रोजगार के स्तर का ऊँचा उठान का वात कहा था। उद्देश्य मशीनकाल में मावजनिक तथा निजी विनियोग दान का ही बढ़ाने का मुसाम किया था। उनका कहना था कि विनियोग बढ़ाने में रागा का अय बढ़ना तथा राजगार मिलना। वह कहते हैं कि विनियोग दा घाता पर निर्भर करता है (i) व्याज की दर (ii) पूँजी की सीमांत उत्पादकता। व्याज की नीचा दर द्वारा लागो का अधिक पूँजा की माँग बढ़ाने तथा विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नीचा व्याज का दर लागू करना समीचीन मुद्रा नीति भी बहुमत है।

विनियोग में वृद्धि के लिए आवश्यक है पूँजा का सामांत उत्पादकता अर्थात् पूँजा निवेश से होने वाला लाभ से होता है। जब निजी माहगी पूँजी निवेश करता है तो वह पूँजी की सीमांत उत्पादकता तथा व्याज की दर का तुलना करता है। मशीनकाल में पूँजा की सीमांत उत्पादकता या बुनलता में काफी गिरावट आ जाता है और व्याज की दर में भी यह नीची गिर जाता है तो निजी साहसिया के लिए पूँजी निवेश अलाभकर होता है। इसलिए कीस न मरदा काल में मावजनिक निवेश में वृद्धि के लिए सरकार का विभिन्न निर्माण कार्यों का प्रारम्भ करने की योजना दी थी। इसमें लागो का राजगार प्राप्त होगा आय बढ़ना उपभाग में वृद्धि से प्रभाक्पूण योग बढ़ना जिससे निवेश लाभप्रद बन रहेगा।

6 विदेशी व्यापार में वृद्धि (Increase in Foreign Trade)—पूण राजगार हट्टु विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से निर्यात उद्योगों में लग धूमिका का माँग बढ़ना। अर्द्ध विकसित दशा में विदेशी पूँजी की आवश्यकता भी अधिक होती है जिसमें एस देश विदेश से तकनाक तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकें। विदेशी व्यापार में वृद्धि में एक ओर तो देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना सम्भव होगा दूसरी ओर निर्यात उद्योगों का प्रोत्साहन मिलेगा और धूमिका की माँग बढ़ना उनका पर्याप्त राजगार मिलेगा आय बढ़ना उपभाग प्रवृत्ति में वृद्धि होगा और उत्पादकों को भी पर्याप्त प्रोत्साहन उत्पादन का जारी रखने के लिए बना रहेगा।

निष्कर्ष (Conclusion)—पूण रोजगार की नीति एक लक्ष्य के रूप में एक योजना का स्वीकार करना चाहिए। पूण राजगार के लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की नीति की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकार के द्वारा ही विभिन्न प्रकार का नीतियाँ जैसे मौद्रिक राजनीति तथा अय नीतियाँ के मध्य समन्वय तथा उचित तालमेल स्थापित किया जा सकता है। पूँजावाला तथा विकसनशील अर्थव्यवस्था की नीति में समन्वय या नियंत्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य पूण राजगार का प्राप्ति करना थाड़ा मरना होता है। इसका कारण यह है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न नीतियों का आवश्यकता अनुसार उन्हें अपनाया जा सकता है तथा उचित सामग्र्य स्थापित करके उन्हें और अच्छे रूप से किया जा सकता है।

परीक्षा प्रश्न

1. वराजगारा से क्या समझते हैं? वराजगारा के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

(What do you understand by unemployment Explain different types of unemployment)

2. अर्द्ध विकसित दशा में वराजगारा के क्या कारण? समस्या में वराजगारा दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

(What are the causes of unemployment in under-developed countries ? What measures would you suggest to remove unemployment in such countries ?)

- 3 पूर्ण रोजगार म आप क्या समझत ह ? पूर्ण रोजगार नीति की व्याख्या कीजिए ।

(What do you mean by full employment ? Discuss full employment policy)

- 4 निम्नलिखित म म रिन्हो द्वा पर टिप्पणा लिखिए

- (i) घषणात्मक बराजगारी
- (ii) मरचनात्मक बराजगारी
- (iii) अदृश्य बराजगारी
- (iv) चर्तीय बराजगारी
- (v) नौममः बराजगारी
- (vi) एच्छित तथा अनैच्छित बराजगारी ।

Write notes on any two of the following

- (i) Frictional unemployment
- (ii) Structural unemployment
- (iii) Disguised unemployment
- (iv) Cyclical unemployment
- (v) Seasonal unemployment
- (vi) Voluntary and Involuntary unemployment

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्ना म स सान-या सहा है और कौन ना सतत ह ।

- (i) पूर्ण रोजगार का स्थिति का बनाए रखना जबका रोजगारी का समाप्त करन क त्रिण एक राष्ट्रीय नीति अपनाना जरूरी है ।
- (ii) घषणात्मक बराजगारी एक म्वाया प्रका का बराजगारी हती है ।
- (iii) रचनात्मक बराजगारी एक म्वाया बराजगारी हती है ।
- (iv) मरचनात्मक बराजगारी का मुख्य कारण अव्यवस्था की मरचना का दाप-पूर्ण हती है ।
- (v) चर्तीय बराजगारी विकसित देश की दन है जा समय-समय पर रटित व्यापार चर्ता अवात् तर्जीवान और मदावात क कारण हती है ।
- (vi) अदृश्य बराजगारी विकसित अव्यवस्थाआ म पाई जाता ह ।
- (vii) पूर्ण रोजगार का आसय यह ह कि प्रचलित मजदूर का दश पर काम चाहन वाला का काय मिता ह ।
- (viii) पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जहाँ अदृश्य बराजगारी अनुपस्थित रहती है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सहा है । (ii) सतत है । (iii) सही ह । (iv) सही ह । (v) सहा है । (vi) सतत है । (vii) गती है । (viii) सहा है ।

अध्याय 4

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त

(CLASSICAL THEORY OF EMPLOYMENT)

भूमिका

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त का वास्तविक रोजगार का सिद्धान्त भा कहा जाता है। इस सिद्धान्त का समर्थन प्रो. एडम स्मिथ प्रा. रिचार्ड्स, जे. बी. सैय तथा अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों ने किया। प्रतिष्ठित अधशास्त्रियों का विश्वास था कि अव्यवस्था में मईव पूरा रोजगार की स्थिति बनो रहता है और यदि कभी बेरोजगारी हो तो अव्यवस्था में स्वयं ऐसे कारण उपस्थित हो जायेंगे जिनसे बेरोजगारी समाप्त होकर पूरा रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पूरा रोजगार को सामान्य स्थिति प्रतिष्ठित अधशास्त्री मानते थे और बेरोजगारी को असामान्य स्थिति। उनकी इस धारणा का मुख्य आधार प्रा. जे. बी. सैय (Prof. J B Say) का बाजार नियम या जिनके अनुसार 'पनि अपना माँग स्वयं उदा कर देता है।' (Supply creates its own demand) प्रा. जे. एम. सिन्स का कहना था कि 'वार्षिक उत्पादन चाहे कितना हो क्यों न हो यह वाणिज्य माँग से किसी भी हालत में अधिक नहीं हो सकता।' इसी आधार पर इन विद्वानों का दावा था कि अनैच्छिक तथा सामान्य बेरोजगारी की स्थिति पाई नहीं जाएगी।

प्रतिष्ठित अधशास्त्रियों तथा प्रा. जे. बी. सैय का पूरा विश्वास था कि जब अव्यवस्था स्वतंत्र रूप में कार्य करती है तो बेरोजगारी तथा अजिज उपान्त की स्थिति हा ही नहीं सकता। प्रतिष्ठित विद्वानों का कहना था कि पूरा रोजगार की स्थिति वाल समाज में ऐच्छिक तथा सघटक (Voluntary and Fractional Unemployment) हा ही नहीं सकता। ऐच्छिक बेरोजगारी से आशय उस स्थिति से होता है जब प्रचलित मजदूरी पर अधिक काम करने का तयार न हो। ऐसी स्थिति कि जब श्रमिकों का कार्य उपलब्ध हा और वह काम नहीं करना चाहें तो इस बेरोजगारी का मना नहीं दी जा सकता। सघटक बेरोजगारी से आशय उस स्थिति में है जब कि श्रमिकों का रोजगार सम्बन्ध था होता या पूरी जानकारी न हो या बाजार मध्य में अपूर्णता तथा अपना अज्ञानता के कारण श्रमिक बेरोजगार रहें।

प्रतिष्ठित अधशास्त्री कहते थे कि अनैच्छिक तथा सामान्य बेरोजगारी का स्थिति नहीं पाई जा सकती। उनका कहना था कि अनैच्छिक बेरोजगारी सम्भव नहीं है अर्थात् अनैच्छिक बेरोजगारी के न हान पर हा पूरा रोजगार की स्थिति पाई जाएगी। अनैच्छिक बेरोजगारी का न पाया जाना हा प्रतिष्ठित अधशास्त्रियों के बाजार सिद्धान्त का मुख्य निष्कर्ष है। उनका विश्वास था कि जब काम करने वाले व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहते तो ऐसा उन समय होता है जब कि अव्यवस्था के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में बाधा या गड़बड़ हो जाए जैसे—(1) मजदूरी बढ़ाने के लिए श्रम संघों द्वारा हड़ताल

(7) मुद्रा वस्तु विनिमय की अमूर्त धारणा का यह तर्क कि अतिरिक्त आरंभ नहीं है।

से कि नियम की आलोचनाएं (Criticism of Say's Law)

प्रांज वा मर वाजार नियम का आलोचनाएं अनेक अवस्थास्थितियां न की है। प्रा० ज० वा० मर वाजार नियम का सर्वप्रथम आलोचना वर्ष 1929-30 का मद्रास पहुँचाया। मद्रासवासन म पहल ही प्रा० मर वाजार नियम का आलोचना हान लगा थी। प्रा० हासन न मर नियम का सर्वप्रथम आलोचना का पर तु उनका प्रहार 1936 म द्रव्यस्थित आर्थिक ध्याना (The General Theory) म प्रा० मर नियम का बड़ी आलोचना प्रांज तम क म न वा। एमए अलावा अमराकन अध्यापिका न वी० कला अग्रजा अवस्था प्रा० गबटसन न की मर नियम का आलोचना रा। एनर नियम क मद्रास बह आलोचना प्रांज तम कीम है। प्रा० वी० तम स्वाजा का एम मम्ब एम कहता है कि नीम की मद्रास वन मपनता एम अमस्वित अध्यापिका का ज वा मर वाजार नियम म मद्रास स्थिताना था। प्रां मर नियम का प्रमुख आलोचना एं निम्न प्रकार म व्यति रा जा सकता है।

(1) नियम अवास्तविक है— आलोचना रा कहता है कि प्रां मर वा नियम म अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि जितना मांग उपास्थित होता है वह मांग का मारा बिक जाता है। अर्थात् समस्त आय का मांग उपास्थित कर दिया जाता है या फिर उस निवर्ण कर दिया जाता है। आय मद्रास एम बम्बुला पर व्यय कर जाता है जिमम मभा माधन का पूरा राजगार मिल जाता है। आय रा यह प्रवाह (Flow) तथा कार रहता है। प्रां मर कहता है कि मांग म कमी आ सकता है क्योंकि समस्त आय का समस्त उपास्थित रा प्रय वर्ण पर व्यय नही किया जाता।

(2) मुद्रा बल विनिमय का माध्यम ही नहीं है प्रां मर मुद्रा क विनिमय माध्यम काय का हा प्रमुख माना है। प्रां कीम का कहना है कि मुद्रा का एक अर्थ काय मूल्य संचय ना है अर्थात् भावा जावश्यकताओं का पूर्ति अर्थात् विभिन्न उद्देश्यों का पूर्ति हेतु मुद्रा का संचित कर रखा जा सकता है। एम आय व्यय प्रवाह टूट जाता है और अति उत्पादन तथा बराजगारा का स्थिति दखा जा सकता है।

(3) बचत एवं विनियोग की समानता—प्रां मर का कहना था कि व्याज र दर न माध्यम म इन स्थाना म समानता स्थापित का जा सकता है। प्रां काय न कहा कि बचत तथा निवर्ण व्याज की दर का अपा न म का आगता म अर्थिक अभावन हात है। प्रां काय का कहना है कि आय क मद्रास म पावकता उरु वान पर विनियोग म म तुलन स्थापित किया जा सकता है।

(4) सरकारी हस्तक्षेप—प्रां मर का नियम स्वसंचालित एवं समायोजित मानता पर आधारित है। प्रां कीम न कहा कि अर्थ व्यवस्था म म तुलन स्थापित वर्ण क लिए अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र रूप म काय वर्ण न स्थान पर वर्णारा हस्तक्षेप का नाति अपनाना चाहिए।

1 Keynes greatest achievement was the liberation of Anglo American Economists from tyrannical dogmatic Say's law

—P M Sweezy

(5) मजदूरी में कटौती करना आवश्यक नहीं है—प्रो० पयू न रेन नियम का समर्थन करते हुए कहा कि नकद मजदूरी में कमी करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। प्रो० कांस न इस विचार की आलोचना करते हुए कहा कि मजदूरी लागत का अंश ही नहीं बरन एक प्रकार से साधन की आय है। मजदूरी में कटौती का आशय प्रभावपूर्ण माँग में कमी लाएगी उत्पादन कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी।

(6) दीर्घकालीन साम्य विश्लेषण—प्रो० से का नियम दीर्घकालीन साम्य विश्लेषण पर आधारित है अर्थात् दीर्घकाल में माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। प्रो० वीन्स का कहना है कि वास्तविक स्थिति तो अल्पकालीन साम्य की होती है जिसके बारे में प्रतिष्ठित विद्वान कुछ नहीं कहते।

(7) पूर्ण तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता की मान्यता—प्रो० से का नियम नुटि तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जो नुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में आलोचना का कहना है कि हम जिन समाज में रहते हैं उनमें अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है।

(8) मुद्रा आय, उत्पादन तथा रोजगार को भी प्रभावित करती है—प्रो० से के नियम के अनुसार मुद्रा एक आवरण मात्र है जिसमें वस्तुएँ तथा सेवाएँ हमारे पास लिपट कर आती हैं। जबकि प्रो० वीन्स का कहना है कि मुद्रा आय उत्पादन रोजगार तथा अन्य घटकों के निर्धारण में एक स्वतंत्र भूमिका निभाती है।

प्रो० से के बाजार नियम की उपर्युक्त आलोचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रो० से का नियम अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है। प्रो० हेबर्स्टर ने से के नियम का खण्डन करते हुए कहा है कि—आधुनिक आर्थिक सिद्धान्त में से के नियम के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है। नव परम्परावादी अर्थशास्त्रियों ने भी अपने मुद्रा तथा व्यापार चक्र सम्बन्धी सिद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कार्यों में इसको पूरी तरह नकार दिया है।¹

प्रो० से के नियम की क्रियाशीलता (Applicability of Say's Law)

प्रो० जे० बी० से के बाजार नियम के समर्थक इस नियम की प्रियाशीलता को वास्तविकता मानते हैं और बहुत ही कि यह नियम सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होता है। वे ने जिन मान्यताओं की व्याख्या की है यदि वह सही हैं तो नियम भी लागू होगा।

(1) वस्तु विनिमय व्यवस्था में से का नियम (Say's Law in Barter System)—से के नियम के समर्थक कहते हैं कि यह नियम वस्तु-विनिमय प्रणाली में लागू होता है। इसकी मान्यता यह है कि मुद्रा का व्यवस्था प्रवाह तटस्थ रहता है। एक विक्रेता द्वारा धन के लिए अपनी वस्तुएँ बेची जाती हैं जैसे ही इन वस्तुओं से प्राप्त धन उस मिलता है वह अन्य वस्तुओं पर व्यय कर देता है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय सरल बनाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय अनुपात समान रहते हैं।

1. There is no place and no need for say's law in modern Economic Theory and that it has been completely abandoned by neo classical in their actual theoretical and practical work on money and the business cycles'

आधुनिक आशाश्रयी इस कथन में सहमत नहीं है। उनसे अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय अनुपात मरदेब बराबर हो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इनकी माँग और पूर्ति में असम्यग्त्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और नियम लागू नहीं होगा।

(2) मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से बा नियम (Say's Law in Monetary Economy) — परम्परावादी तथा नव परम्परावादी विद्वानों ने कहा कि प्रो० में बा नियम मौद्रिक व्यवस्था में भी लागू होता है। वे इस सम्बन्ध में दो तर्क देते हैं।

(1) मुद्रा विनिमय का एक माध्यम मात्र है। मुद्रा वस्तुओं के एक समूह का विनिमय करने के बाद दूसरी वस्तुओं के समूह का विनिमय सम्पन्न कराने लगती है। (2) उत्पादन बढ़ने के साथ आय में वृद्धि होती है तथा उत्पन्न हो व्यय बढ़ जाता है। जो धन बना लिया जाता है उसका विनियोग हो जाता है तथा धन खर्च नहीं किया जाता। आय वृद्धि जितनी मात्रा में बढ़ती है उतनी ही मात्रा में व्यय भी किया जाता है। इसलिए माँग तथा पूर्ति में मरदेब मनुस्तर स्थापित हो जाता है।

प्रो० पीगू का मजदूरी बढ़ती सम्बन्धी रोजगार सिद्धान्त (Prof Pigou's Wage-cut Theory of Employment) परम्परावादी अर्थशास्त्री प्रो० पीगू (Prof A C Pigou) की यह धारणा थी कि यदि श्रमिक अपनी सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी देने की तैयार रहें तो श्रम बाजार में सभी बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। वे कहते हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण श्रमिका द्वारा उंची मौद्रिक मजदूरी की माँग, मरकारी हस्तक्षेप तथा श्रम संघों (Labour Unions) का प्रभाव पड़ा जाता है। अवस्था यदि स्वतन्त्रतापूर्वक बाय वर का प्रत्यक्ष दशा में मजदूरी का निर्धारण श्रमिका की माँग और पूर्ति के आधार पर तय होगा और मजदूरी की दर मजदूरी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) के बराबर हो जाएगी। प्रो० पीगू कहते हैं कि "स्थिर दशा में श्रमिकों का माध्य मार्ग जब तक पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार से प्राप्त करने और उस बनाए रखने की एक निश्चित गारंटी है।"

यदि किसी समय श्रमिकों की पूर्ति उनकी माँग में अधिक हो जाय तो श्रम-बाजार में मजदूरी की दर गिरने लगेगी और यह तब तक चलेगा जब तक कि श्रम की माँग और पूर्ति में समानता स्थापित नहीं हो जाती। श्रमिका की माँग उनकी पूर्ति में बढ़ने पर मजदूरी की दर तब तक गिरनी रहेगी जब तक कि माँग और पूर्ति दोनों बराबर नहीं हो जायें। इस प्रकार मजदूरी की लोचता ही अवस्था में पूर्ण रोजगार को ला सकती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि किसी समय बेरोजगारी पाई जाए और वह काफी समय बनी रहे तो यह समझना चाहिए कि मजदूरी में लोचनीयता व्याप्त है। किसी दशा में मजदूरी की दर में कमी करने रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मजदूरी में बढ़ती में बेरोजगारी बँधे हुए होगी इसके सम्बन्ध में प्रो० पीगू का स्पष्ट मत है कि इसमें अर्थात् मजदूरी में बढ़ती उत्पादन लागत को गिरावेगी—श्रमिकों को काम होगी—वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी—उत्पादन अधिक होगा—रोजगार का स्तर ऊँचा उठेगा। मजदूरी बढ़ती में लागत घटने का एक प्रभाव यह होगा कि उत्पादकों के लाभ बढ़ेंगे। अधिक पूँजी विनियोजन होगा—उत्पादन तथा रोजगार दोनों बढ़ेंगे। प्रो० पीगू कहते हैं कि 'श्रम बाजार में बेरोजगारी के दबाव के कारण मजदूरी बढ़ती का तब तक तय नहीं रहेगा जब तक कि उस सभी व्यक्तियों जो रोजगार के इच्छुक हैं, रोजगार नहीं मिले जाता।'

पीगू के सिद्धान्त की आलोचनाएँ (Criticism of Pigou's Theory)

(1) मजदूरी बढ़ती का भ्रष्टपूर्ण विचार — प्रो० पीगू का सिद्धान्त बँधे तो देश में मरगदर नहीं प्रतीत हो सकता है परन्तु यह उतना नहीं सही है जितना कि यह दिखता है।

प्रो० पीगू तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मजमें बड़ी भूत यह थी कि विद्वानों ने मजदूरी बढ़ती को एक पक्ष या उद्योग की अपेक्षा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक औपधि मान लिया। यदि यह मान भी लिया जाए कि एक उद्योग ने मजदूरी बढ़ती करने रोजगार बढ़ेगा तो भी उस उद्योग में सग व्यक्तियों की कुल माँग उस उद्योग के उत्पादन की माँग से बड़ी अधिक मात्रा में कम होगी। यदि सभी उद्योगों में रोजगार बढ़ाने हेतु मजदूरी बढ़ती की जायगी तो इससे लोगों की आय (क्षमशक्ति) कम होगी जिससे प्रभावपूर्ण माँग इतनी मित जायेगी कि रोजगार के स्थान पर बेरोजगारी ही बढ़ेगी।

(2) आय पक्ष की अवहेलना—प्रो० पीगू के सिद्धान्त की दूसरी कमी यह थी कि उन्होंने मजदूरी बढ़ती के केवल नामत पक्ष के बारे में सोचा तथा आय पक्ष की अवहेलना की। यदि मजदूरी एक उत्पादक के लिए नामत है तो एक साधन की आय का स्रोत भी है जो माँग को प्रभावित करती है। रोजगार तो कुल माँग पर निर्भर करता है जो आय द्वारा निर्धारित होता है। मजदूरी बढ़ती से क्षमशक्ति (आय) के कम होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी।

(3) व्यावहारिकता की कमी—प्रो० पीगू के सिद्धान्त पर एक अन्य आरोप उसके व्यावहारिक पक्ष का कमजोर होना है। प्रो० कोम्स कहते हैं कि पीगू का मजदूरी बढ़ती का विचार सैद्धान्तिक दृष्टि से तो उचित लग सकता है परन्तु उसका व्यावहारिक पक्ष अत्यधिक कमजोर है।

(4) उपभोग प्रवृत्ति की अवहेलना—प्रो० कोम्स ने पीगू के विचार की आलोचना करते हुए कहा कि पीगू यह नहीं समझ पाये थे कि मजदूरी बढ़ती से उपभोग तथा विनियोग दोनों ही प्रभावित होते हैं। उन्होंने उपभोग प्रवृत्ति पर मजदूरी बढ़ती के पड़ने वाले प्रभावों की अवहेलना करते हुए अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया। मजदूरी बढ़ती रोजगार के स्तर को नहीं बढ़ाने में सफल होगी जब कि इससे उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) बढ़े।

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त एक दृष्टि से (Classical Theory of Employment at a Glance)

रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त से हमारा तात्पर्य उस रोजगार सिद्धान्त से है जिसका समर्थन प्रो० एडम स्मिथ, रिचार्डों जे० बी० से जे० एम० मिन मागल तथा पीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। प्रो० जे० बी० से तथा प्रो० पीगू के रोजगार सम्बन्धी विचार चाहे उन्होंने पुनः रूप से रखे हों परन्तु इन दोनों के विचार प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त के दो प्रमुख स्तम्भ हैं। संक्षेप में तथा एक दृष्टि में हम प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धान्त को निम्न प्रकार रख सकते हैं —

(1) अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजित होने की क्षमता होती है। जो कुछ भी उत्पादित होता है वह सभी बिक जाता है। $SO = SC$ कुल उत्पादन = कुल उपभोग।

(2) अति उत्पादन की स्थिति नहीं पाई जाती। प्रत्येक अनिश्चित उत्पादन अति क्षमशक्ति को जन्म देता है अर्थात् आय = व्यय ($\Sigma I = \Sigma E$)।

(3) अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है।

(4) वस्तु एवं विनियोग में समानता व्याज की दर के माध्यम से होती है।

$$(IS = \Sigma I)$$

(5) जब थमिन अपनी सीमान्त उत्पादनता से अधिक मजदूरी की माँग करते हैं तभी बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है।

(6) इस प्रणाली में अर्थव्यवस्था बराबरी नहीं पाई जाती है।

(7) अर्थव्यवस्था में पूरा रोजगार एवं सामान्य स्थिति है और बेरोजगारी असामान्य स्थिति है।

(8) पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मजदूरी में कमी आने के पूरा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की आलोचनाएं (Criticism of the Classical Theory of Employment)

प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की बड़ी आलोचना प्रो० बीन्स ने की। प्रारम्भ में प्रो० बीन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में हमारे सामने आए परन्तु बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की विशेष रूप में रोजगार सिद्धान्त की आलोचना की। उनका स्पष्ट मत था कि रोजगार के बारे में प्रो० जे० वी० स० म० पी० पी० के मत इस आधार पर असम्यक है कि अर्थव्यवस्था में पूरा रोजगार की स्थिति पाई जाती है और बेरोजगारी नहीं होती। प्रो० बीन्स ने 1929-30 की मन्दी को दखा था और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बेरोजगारी एक असामान्य स्थिति नहीं है। यदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का पूरा रोजगार का विचार सही होता तो मन्दी के समय बेरोजगारी नहीं पाई जाती। बीन्स ने प्रो० जे० वी० स० म० पी० पी० के नियम का खण्डन किया तथा प्रो० पी० पी० द्वारा मजदूरी बढ़ाने द्वारा बेरोजगारी दूर करने के प्रस्ताव की अनुचित और असम्यक टिप्पणी की।

प्रो० बीन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएं की।

(1) पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य घटना नहीं है—प्रो० बीन्स का कहना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य घटना नहीं है। पूँजीवादी प्रणाली तथा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में रोजगार नाना एवं असामान्य घटना होती है।

(2) अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजित नहीं होती—प्रो० बीन्स का कहना था कि अर्थव्यवस्था स्वयं समन्वयन की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेती है। बीन्स ने बताया कि समाज में घनत्व व जनसंख्या की व्याप्त असमानताओं व कारणों के लिए और तो घनी वर्गों की आवश्यकताएँ पहन में ही सन्तुष्ट हो चुका होती है और उमरे द्वारा उपयोग की मात्रा में वृद्धि नहीं होती दूसरी ओर निम्न व्यक्तियों में व्याप्त कमी के कारण उन्हें अपनी स्यूततम आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है जाना है तथा कुछ उपयोग में कमी आती है। कुछ उपयोग कुछ उत्पादन की अपेक्षा कम रहता है और मजदूरी में भी गिरावट आती है। इस असन्तुलन व अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप द्वारा ठीक किया जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था में समायोजित होने की शक्ति नहीं पाई जाती।

(3) मजदूरी में कमी द्वारा रोजगार बढ़ाना एक असमपूर्ण धारणा है—प्रो० बीन्स ने कहा कि प्रो० पी० पी० का मजदूरी बढ़ाने द्वारा रोजगार के स्तर को बढ़ाना एक त्रुटिपूर्ण धारणा है। प्रो० बीन्स कहते हैं कि मजदूरी में कमी द्वारा नहीं बल्कि प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। मजदूरी की कमी रोजगार के स्तर को बढ़ाने के स्थान पर गिराती है। इसके अलावा धर्मसमर्थन व प्रभाव के कारण मजदूरी में कमी करना सम्भव नहीं होता।

(4) दीर्घकालीन मान्यता—प्रो० बीन्स का कहना है कि प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धान्त दीर्घकालीन मान्यता पर आधारित है जब कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अस्थायी स्थिति होती है।

(5) वचत एवं विनियोग की समानता—प्रो० कीन्स का विचार है कि प्रतिष्ठित विद्वानों की यह धारणा है कि वचत एवं विनियोग समान रहते हैं अर्थात् लोग अपनी समस्त आय का उपभोग कर लेते हैं। यदि कुछ वचत होती है तो उसे विनियोजित कर दिया जाता है। उनका कहना है कि वचत एवं विनियोगों में समानता व्याज की दर की अपेक्षा आय के स्तर पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं कुल आय हमेशा व्यय ही कर दी जाए इस बात का भी सफ़टन प्रो० कीन्स ने किया और बताया कि आय का एक भाग बचा लिया जाता है और यदि इस भाग को विनियोग न किया जाए तो बेरोजगारी पाई जाएगी।

(6) अवास्तविक मान्यताएँ—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धान्त पूरा रोजगार पूर्ण प्रतियोगिता अवस्था नीति (Laissez faire) तथा कीमत-प्रक्रिया जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। यह मान्यताएँ वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। इनका प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धान्त अव्यावहारिक है। वर्तमान समय में बिना सरकारी हस्तक्षेप के किसी भी देश में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना हुआ में महान् ब्रह्मान जैसी बात होगी। प्रो० कीन्स ने कहा कि परम्परावादी अर्थशास्त्र में जिन विशिष्ट सिद्धांतों की व्याख्या की गई है वे उस वर्तमान वास्तविक समाज के अनुसार नहीं हैं जिसमें हम रहते हैं। यह सिद्धान्त एवं अवास्तविक एवं अव्यावहारिक है।

प्रतिष्ठित तथा प्रो० कीन्स की विचारधाराओं में अन्तर (Difference between Classical and Keynesian Views)

इन दोनों विचारधाराओं में निम्न अन्तर पाए जाते हैं 96/95

(1) प्रो० कीन्स की विचारधारा अल्पकालीन सन्तुलन की व्याख्या पर आधारित है जबकि प्रतिष्ठित विद्वान दीर्घकालीन सन्तुलन पर जोर देते हैं।

(2) प्रतिष्ठित विद्वान पूँजी निर्माण के लिए वचतों को आवश्यक मानते हैं जबकि कीन्स कहते हैं कि वचतें प्रभावपूर्ण नहीं होती हैं। जिससे रोजगार का स्तर गिरता है।

(3) प्रतिष्ठित विद्वान अव्यवस्था में पूरा रोजगार की स्थिति को सामान्य बात मानते हैं जबकि कीन्स का कहना है कि पूँजीवादी अव्यवस्था में बेरोजगारी एक सामान्य घटना होती है।

(4) प्रतिष्ठित विद्वान प्रचलित मजदूरी की दर में कटौती करने से पूरा रोजगार के स्तर को प्राप्त करने का सुझाव देते हैं जबकि कीन्स का कहना है कि मजदूरी कटौती नीति उचित एवं व्यावहारिक नहीं है।

(5) प्रतिष्ठित विद्वान मूल्य आधिक विश्लेषण पर अधिक जोर देते हैं जबकि कीन्स व्यापक आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं।

(6) प्रतिष्ठित विद्वानों की अधिवाश मान्यताएँ अवास्तविक हैं जबकि कीन्स गतिशील मान्यताओं को अपने सिद्धान्तों में स्पष्टीकरण में प्रयोग करते हैं।

(7) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है जबकि कीन्स का सिद्धान्त एवं सामान्य सिद्धांत है।

(8) प्रतिष्ठित विद्वान सन्तुलित बजट (Balanced Budget) बनाने पर जोर देते हैं, जबकि कीन्स घाटे के बजट (Deficit Budget) आर्थिक सकट निपटने में मंदाकार से निपटने के लिए जरूरी मानते हैं।

(9) प्रतिष्ठित विद्वान् की वह मान्यता है कि पूरुन रोजगार की स्थिति पाई जाने पर मुद्रा की पूरुति करने में कीमत स्तर घटना है। कीन्तु यह कहना है कि पूरुन रोजगार बिन्दु से पहले मुद्रा की पूरुति नतीत कीमत-स्तर में समानुपातिक दर में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उत्पादन भी बढ़ता है। पूरुन रोजगार के बाद मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि कीमत-स्तर को समानुपातिक रूप से बढ़ाणी। क्वाकि तब उत्पादन बढ़ने की सभी सम्भावनाएँ समाप्त हो जायेंगी।

(10) प्रतिष्ठित विद्वान् व्याज का त्याग का पुरस्कार मानते हैं ज़रूकि कीन्तु ने बताया कि व्याज की दर तर-ता समदशी तथा मुद्रा की पूरुति द्वारा तब हाती है।

(11) प्रतिष्ठित विद्वान् स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में सम-वय के अर्थ कीन्तु कहते हैं कि सरकारी नीतियों को कार्यान्विन करन के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

परीक्षा-प्रश्न

प्र० ० जे० बी० से के बाजार नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(Examine critically Prof J E Say's Law of Markets)

अथवा

पूरुति अपनी माँग स्वयं पैदा कर लेती है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(Supply creates its own demand Discuss critically this statement)

[संकेत—पहले प्र० ० जे० बी० से के नियम की नाविक व्याख्या कीजिए बाद में उनके इस सिद्धान्त की आलोचना दीजिए।]

2 रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(Discuss critically the Classical Theory of Employment)

3 प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। किन आधार पर कीन्तु द्वारा इसका तण्डन किया गया।

(Explain the Classical Theory of Employment On what grounds has it been challenged by Keynes)

4 क्या भजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार को बढ़ाना सम्भव है? अपने उत्तर की पुष्टि कारण देकर कीजिए।

(Is it possible to increase employment through wage cut? Give reasons for your answer)

5 किन आधार पर कीन्तु ने प्रतिष्ठित व्यवस्था एवं उसके निष्कर्ष पर प्रहार किया? उनकी व्याख्या प्रतिष्ठित व्याख्या में किन प्रकार भिन्न है?

(On what basis did Keynes attack the classical system and its conclusions? Where does his system differ from that of classical system?)

(अ) सैद्धांतिक महत्व (Theoretical Importance)—प्रो० बीन्स का सिद्धांत ना सैद्धांतिक महत्व निम्न तत्वा द्वारा स्पष्ट होता है

1 प्रो० बीन्स का विनियोग व्यापक आर्थिक सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी है।

2 प्रो० बीन्स के अनुसार आय तथा रोजगार का संबंध अर्थ रोजगार स्तर पर स्थापित हो जाता है।

3 प्रो० बीन्स का सिद्धांत एक सामाजिक सिद्धांत है जो विभिन्न स्थितियों में लागू होता है।

4 प्रो० बीन्स का सिद्धांत का वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक सिद्धांत के साथ समन्वित करने में सफल हुए हैं।

5 प्रो० बीन्स का दृष्टिकोण प्रावर्तित है यह कि बीन्स सिद्धान्त में प्रावर्तित तत्वा का समावेश किया गया है जिससे आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों को विकसित करने में सहायता मिली है।

6 प्रो० बीन्स ने विनियोगों को रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि वृद्धि एवं विनियोग में असंतुलन से अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। उपभोग व्यय तथा आय के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए विनियोगों का सहारा लिया जाना चाहिए।

(ब) व्यावहारिक महत्व (Practical Importance)—प्रो० बीन्स का सिद्धांत व्यावहारिक पक्षों पर आधारित है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है—

1 प्रो० बीन्स का कहना था कि पूरा रोजगार के निर्धारण तत्त्व प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि सरकारी हस्तक्षेप की नीति के द्वारा हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने अर्थव्यवस्था में असंतुलन स्थापित होने पर सरकारी हस्तक्षेप की नीति को महत्वपूर्ण माना है।

2 आर्थिक विकास के लिए सदैव सन्तुलित बजट का सहारा नहीं लिया जा सकता सरकार को विकास की गति तेज करने तथा मंदी से अर्थव्यवस्था को निवारण के लिए घाटे के बजट बनाना चाहिए।

3 प्रो० बीन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) को महत्व की ओर हमारा ध्यान दिनाया।

4 प्रो० बीन्स ने राजकाजीय नीति का महत्व का ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया साथ ही मौद्रिक नीति की कमियों की ओर भी बताया।

5 प्रो० बीन्स का कहना था कि मजदूरी की दरें घटाने से रोजगार में वृद्धि करना उचित नहीं है।

6 प्रो० बीन्स ने एक उचित मजदूरी नीति तथा कीमत नीति अपनाने का व्यावहारिक पहलू हमारे सामने प्रस्तुत किया।

7 प्रो० बीन्स ने कुल राष्ट्रीय आय कुल उपभोग कुल विनियोग कुल वृद्धि आदि विचारों को लेकर अर्थव्यवस्था में सामाजिक लेखांकन नीति (Social Accounting Policy) का तैयार करने की प्रेरणा दी।

कीन्स सिद्धान्त तथा अल्पविकसित देश (Under-developed Countries and Keynes Theory)

अल्प विकसित देशों के लिए कीन्स का योजनात्मक सिद्धान्त निम्न कारणों में लागू नहीं होता—

1. अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप अलग होता है—प्रो० कीन्स का सिद्धान्त विवक्षित तथा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए तो नहीं है परन्तु अल्प विकसित देशों के लिए यह नहीं है। क्योंकि ऐसे देशों में बेरोजगारी की समस्या आर्थिक उन्नत-वचना के कारण नहीं आती। ऐसे देशों में बेरोजगारी परम्परागत एवं लगातार पाई जाने वाली होती है। इन देशों में अदृश्य बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या अधिक होती है। गांधी मकूत परिवार प्रणाली और सामाजिक नीतियों के कारण भी बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें जनता धर्म की अधिपना तथा अन्य कारणों की मूल्यता बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसलिए प्रो० कीन्स का सिद्धान्त अल्प-विकसित देशों में बेरोजगारी दूर करने के लिए कारगर नहीं है।

2. अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करना होता है—प्रो० कीन्स ने कथन कि विकसित देशों में व्याप्त होने वाली आर्थिक स्थिरता की समस्या का अध्ययन किया है। अल्प विकसित देशों के मामले में प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की होती है जिसके लिए पूँजी निर्माण तथा पूँजी विनियोजन अनिवार्य है। पूँजी निर्माण वचना को प्रोत्साहित करने सम्भव होता है। कीन्स वक्तव्य करने को अच्छा नहीं मानते थे।

3. कीन्स सिद्धान्त की मान्यताएँ अल्पविकसित देशों के लिए नहीं हैं—प्रो० कीन्स की मान्यताएँ दो शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं (1) अल्पकालीन विश्रुति सम्बन्धित (2) गुणवत्ता सम्बन्धित। कीन्स कहते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन तकनीक क्षमता धर्म की बाध-मुक्तता आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्प विकसित देशों के विकास के लिए इसी तत्त्व का परिचालन करने की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता सम्बन्धी मान्यताएँ, जैसे—अनैच्छिक बेरोजगारी वस्तुओं तथा सेवाओं की माचपूर्ण पूर्ति, वच्चै मान की लोचपूर्ण पूर्ति, उपभोग पदार्थों को निर्मित करने वाले उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का होना आदि अल्प-विकसित देशों में नहीं पाई जाती। इसलिए इसका सिद्धान्त भी अल्प विकसित देशों में नहीं लागू पाया जाता। ऐसे देशों में अल्प-रोजगार, अदृश्य बेरोजगारी तथा अर्थव्यवस्था की अकुशलता से गतिशील होना आदि वाले गुणवत्ता की श्रियाशीलता में बाधा पहुँचाती है।

4. घाटे की वित्त व्यवस्था और सस्ती मुद्रा नीति का सामना करने में होना—अल्प विकसित देशों में सस्ती मुद्रा नीति और घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाकर विनियोगों को बढ़ाकर बेरोजगारी दूर करना लाभप्रद नहीं है। इनमें स्थिर स्थितियों को जन्म मिलता है। अल्प-विकसित देशों में वचता को बढ़ाकर पूँजी निर्माण द्वारा धन जुटाकर विकास को बढ़ाना सम्भव होता है। प्रो० कीन्स वचता को बढ़ाने के विरोध में थे।

5. अल्प-विकसित देशों का विकास योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा सम्भव है—प्रो० कीन्स की विचारधारा अल्प-विकसित देशों के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। वर्तमान समय में अल्प-विकसित देश योजनाबद्ध तरीके से अर्थानु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपने विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे देशों में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाकर तथा विनियोगों को बढ़ाकर ही विकास करना सम्भव नहीं है। ऐसे देशों में जनसंख्या की अधिकता के कारण उपभोग पर ज़रूरत लगाकर तथा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी विनियोजन का सहारा लिया जा रहा है।

कीन्सवादी चरों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध (Inter-relation between Keynesian Variables)

प्रो० कीन्स के रोजगार मॉडल में रोजगार की मात्रा नुन प्रभावपूर्ण माँग की मात्रा पर निर्भर करती है जो स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है—(i) उपभोग (Consumption) तथा (2) निवेश (Investment) उपभोग की मात्रा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है जवनि निवेश की मात्रा व्याज की दर तथा पूँजी की सीमांत कुशलता या क्षमता (MEC) पर निर्भर करती है। इस प्रकार कीन्स के सम्पूर्ण रोजगार मॉडल के तीन मुख्य आधार हैं (i) उपभोग क्रिया (Consumption Function) (ii) पूँजी की सीमान्त कुशलता अथवा क्षमता (Marginal Efficiency of Capital) तथा (iii) व्याज की दर (Rate of Interest)। यह तीन चर कीन्सवादी प्रणाली के स्वतन्त्र चर बने जा सकते हैं अर्थात् यह अन्य चरों से प्रभावित नहीं होते। परन्तु यह एक दृष्टि से अन्तर निर्भर चर (Interdependent Variables) कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें से किसी एक में परिवर्तन दूसरे चरों को प्रभावित कर सकता है। कीन्स ने इनके बारे में कहा है कि यह निर्धारक (उपभोग प्रवृत्ति पूँजी की सीमांत कुशलता तथा व्याज की दर) अपने आप में स्वयं जटिल हैं और इनमें से प्रत्येक में अन्य चरों द्वारा आशा कीत परिवर्तनों के कारण प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। परन्तु इन्हें इसलिए स्वतन्त्र चर कहा जाता है कि इनके मूल्य अन्य चरों के मूल्यों द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं।¹

प्रो० कीन्स न इन स्वतन्त्र चरों की व्याख्या करते हुए कहा है कि व्याज की दर मुद्रा की माँग तथा उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की पूर्ति बैंक तथा सरकार द्वारा प्रभावित होती है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की माँग तरलता पसंदगी के कारण होती है और यह तीन उद्देश्यों द्वारा प्रभावित होती है जैसे—(i) सेन दान उद्देश्य (ii) सुरक्षा उद्देश्य तथा (iii) सट्टा उद्देश्य। इनमें से प्रत्येक दो उद्देश्य आय की मात्रा में परिवर्तन द्वारा प्रभावित होते हैं और व्याज की दर का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि तीसरा उद्देश्य सट्टा उद्देश्य व्याज की दर द्वारा अधिक प्रभावित होता है इसी बात को प्रो० कीन्स ने निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया है।

$$M = f(r, y)$$

M = मुद्रा की पूर्ति f = फलन r = व्याज की दर y = आय स्तर। इस समीकरण में जा मुद्रा पूर्ति का फलन f तथा y से दिखाया गया है उसे हम तरलता क्रिया (Liquidity Function) की संज्ञा दे सकते हैं। मुद्रा की माँग में परिवर्तन का सीधा सम्बन्ध आय की मात्रा में परिवर्तन से होता है और व्याज की दर से इसका विपरीत सम्बन्ध होता है।

उपभोग की मात्रा में वृद्धि का मुख्य निर्धारक नत्व वास्तविक आय का स्तर है। आय की मात्रा या स्तर में वृद्धि होने से उपभोग की मात्रा बढ़ती है परन्तु आय में होने वाली वृद्धि व अनुपात दर से उपभोग में कम दर से वृद्धि होती है अर्थात् इकाई से कम उपभोग में वृद्धि होती है। उपभोग प्रवृत्ति भी व्याज की दर से प्रभावित हो सकती है। व्याज की दर में वृद्धि होने से लोग अधिक मुद्रा वचाने और उपभोग पर व्यय कम

1 These determinants (propensity to consume marginal efficiency of capital and rate of interest) are indeed themselves complex and each incapable of being effected by prospective changes in all other variables. But they remain independent in the sense that their values cannot be inferred from one another" — J. M. Keynes

करेंगे परन्तु उपभोग प्रवृत्ति का ब्याज की दर में सम्बन्ध अप्रत्यक्ष है और अधिक प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता। यदि हम औसत उपभोग को (C) आय स्तर को y में तथा ब्याज की दर को r में व्यक्त करें तो हमें उपभोग त्रिया (Consumption Function) का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसे हम निम्न प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं—

$$C = f(y, r)$$

विनियोगों का स्तर ब्याज की दर तथा पूँजी की सीमान्त कुशलता या क्षमता द्वारा निर्धारित होता है। यदि I को विनियोग की मात्रा r का ब्याज की दर तथा c को उपभोग की मात्रा द्वारा व्यक्त करें तो हम विनियोग त्रिया (Investment Function) का समीकरण प्राप्त होगा जो निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$I = f(r, c)$$

आय के एक स्तर पर ब्याज की दर मुद्रा की माँग तथा पूँजी द्वारा निर्धारित होती है और ब्याज की दर विनियोग के स्तर को निर्धारित करती है। यदि विनियोग का स्तर उस बिन्दु पर स्थिर रहता है जहाँ ब्याज की दर और पूँजी की सीमान्त कुशलता के बराबर रहता है, तो ऐसी अवस्था को साम्यावस्था में कहा जायेगा। अन्यथा विभिन्न चरणों में जब तक परिवर्तन होते रहेंगे जब तक वे एक-दूसरे के बराबर न हो जाएँ।

कीन्सवादी रोजगार मॉडल में स्वतन्त्र तथा निर्भर चर¹ (Dependent and Independent Variables in Keynesian Model of Employment)

आर्थिक चरों को दो भागों में बाँटा जाता है—(i) स्वतन्त्र चर (Independent Variables) तथा (ii) निर्भर चर (Dependent Variables) स्वतन्त्र चर वे चर होते हैं जो अन्य चरों द्वारा प्रभावित नहीं होते जबकि निर्भर चर वे चर होते हैं जिनका मूल्य अन्य स्वतन्त्र आर्थिक चरों के मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। कीन्सवादी मॉडल में स्वतन्त्र और निर्भर चरों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार की गई है।

स्वतन्त्र चर (Independent Variables)

- (1) उपभोग त्रिया (Consumption Function)
- (2) पूँजी की सीमान्त कुशलता अनुसूची (Schedule of MEC)
- (3) तरलता प्रीरियता अनुसूची (Liquidity Preference Schedule)
- (4) मुद्रा की मात्रा (Quantity of Money)
- (5) मजदूरी इकाई (Wage Unit)

निर्भर चर (Dependent Variables)

- (1) ब्याज की दर (Rate of Interest)

(2) राष्ट्रीय आय उत्पादन तथा रोजगार (National Income, Output and Employment)

- (3) उपभोग (Consumption)
- (4) निनियोग तथा बचन (Investment and Saving)

स्वतन्त्र चरों में प्रथम तीन पर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक त्रियाओं द्वारा शासन होते हैं जबकि चौथे तथा पाँचवें चर देश के मुद्रा अधिकारी द्वारा नियन्त्रित होते हैं। चरों के

1. इन चरों की विस्तृत व्याख्या अधोलिखित अध्यायों में की गई है।

स्वतन्त्र तथा निर्भर चरों में वर्गीकरण द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्धारण इस प्रकार इन तत्वों द्वारा होता है—(i) तीन मनोवैज्ञानिक त्रियाओं (उपभोग, पूँजी की सीमान्त कुशलता तथा तरलता वरीयता) (ii) मजदूरी इकाई तथा (iii) मुद्रा की पूर्ति। मजदूरी इकाई (Wage Unit) का मूल्य सेवायोजकों तथा मजदूरों के बीच मोलभाव की शक्ति पर निर्भर करता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय, रोजगार, वचन तथा विनियोग में वास्तविक निर्धारण में सहायता मिलती है क्योंकि यह कीमतों में परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। व्याज की दर पूँजी की सीमान्त कुशलता विनियोगों के स्तर को प्रभावित करती है जो राष्ट्रीय आय का एक अंग है। इसी प्रकार उपभोग त्रिया उपभोग की मात्रा को प्रभावित करती है जो राष्ट्रीय आय का एक अन्य अंग है। इस प्रकार कुल उपभोग + कुल विनियोग किसी समय कुल आय द्वारा उत्पादन अथवा रोजगार की मात्रा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार उपभोग या विनियोगों द्वारा सृजित अर्थ का प्रभाव यहीं पर समाप्त नहीं होता बल्कि आगे चलकर यह विभिन्न स्वतन्त्र चरों को प्रभावित करता है। स्वतन्त्र चर स्वयं भी निर्भर चरों (Dependent Variables) द्वारा प्रभावित तो होते हैं परन्तु उनके द्वारा निर्धारित नहीं होते। यस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत ही जटिल होती है।

कीन्स के रोजगार सिद्धान्त की प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त से श्रेष्ठता (Superiority of Keynesian Theory of Employment over Classical Theory of Employment)

प्रतिष्ठित तथा कीन्स के रोजगार सिद्धान्तों का अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही सिद्धान्तों की अपनी-अपनी कमियाँ हैं। परन्तु दोनों सिद्धान्तों में कौन सा श्रेष्ठ है? यदि हम प्रश्न का उत्तर खोजें तो हमें यह आगामी से पता चल जायगा कि प्रतिष्ठित अवशास्त्रियों के रोजगार सिद्धान्त की अपेक्षा कीन्स का रोजगार सिद्धान्त निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता निम्नलिखित तत्वों से साबित हो जाती है—

(1) कीन्सावादी दृष्टिकोण वास्तविकता के निकट है—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की स्थिति को एक सामान्य स्थिति मानते हैं। जबकि कीन्स का कहना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था प्रायः पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर समतुलन में होती है अर्थात् अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी हमेशा पाई जाती है। ऐसा करने कीन्स ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह वास्तविकता के अधीन निकट है।

(2) पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखने के सम्बन्ध में—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि पूर्ण रोजगार को बनाये रखने के लिए मजदूरी बढ़ती नीति अपनानी चाहिए जबकि कीन्स का कहना है कि कुल प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

(3) बजट प्रारूप के बारे में—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना था कि समतुलित बजट बनाना चाहिए, इसी विपरीत कीन्स मन्दीबाल में विनियोगों में वृद्धि हेतु पाटे के बजट बनाने का सुझाव देते हैं।

(4) दृष्टिकोण में अन्तर—कीन्स ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि यह पूर्ण रोजगार, पूर्ण से अधिक रोजगार तथा अल्प रोजगार सभी प्रकार की स्थितियों का व्याख्या करता है जबकि प्रतिष्ठित विद्वानों ने पूर्ण रोजगार की स्थिति माना है और उनका दृष्टिकोण समुचित एवं विशिष्ट है।

(१) सरकार की मूमिका—प्रतिष्ठित विद्वान् स्वतन्त्र एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली अवस्था में पूर्ण रोजगार की व्याख्या करेंगे न और बताते हैं कि बेरोजगारी होने पर यदि अव्यवस्था अवाधित रूप से अर्थात् बिना हस्तक्षेप के बाध करती रहे तो दीर्घकाल में बेरोजगारी स्वतः ही दूर हो जायेगी। इसके विपरीत कीन्स का कहना है कि बिना सरकार हस्तक्षेप के पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना उचित कार्य है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 प्रभावपूर्ण माँग से आप क्या समझते हैं? यह रोजगार के स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है?
(What do you understand by effective demand? How does it determine the level of employment?)
- 2 प्रभावपूर्ण माँग क्या है? प्रभावपूर्ण माँग के निर्धारक तत्व कौन से हैं?
(What is effective demand? What are the determinants of effective demand?)
- 3 कीन्स के राजगार सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त से किस प्रकार भिन्न है?
(Discuss critically the Keynesian Theory of Employment. How far is it an improvement over classical theory?)
- 4 कीन्स के राजगार सिद्धान्त का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक महत्व बताइए। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में यह कहाँ तक लागू हो सकता है?
(Discuss the theoretical and practical importance of Keynesian Theory of Employment to what extent is it applicable in a country like India?)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्न कथनों में सही और गलत का चयन कीजिए—

- (i) कीन्स का राजगार सिद्धान्त सरकारों के हस्तक्षेप का पक्षधर है।
- (ii) कीन्स के राजगार सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है।
- (iii) कीन्स रोजगार सिद्धान्त के अनुसार अव्यवस्था प्रायः पूर्ण रोजगार में कम स्तर संतुलन में रहती है।
- (iv) कुल माँग पतन तथा कुल पूर्ति पतन का कटाव निम्न ही प्रभावपूर्ण माँग को बताता है।
- (v) कीन्स का रोजगार सिद्धान्त एक दीर्घकालीन व्याख्या है।
- (vi) पूँजी विनियोजन व्याज की दर पर नहीं बरन् पूँजी की सीमांत बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) गलत है। (iii) गलत है। (iv) गलत है। (v) गलत है। (vi) गलत है।

Keynes most notable contribution was his consumption function

—Hansen

The psychology of the community is such that when aggregate real income is increased aggregate consumption is increased but not by so much as income

—J M Keynes

$$MP_c = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \quad AP_c = \frac{C}{Y}$$

अध्याय 6

उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति

(CONSUMPTION FUNCTION OR PROPENSITY TO CONSUME)

प्रो. कीन्स : उपभोगविदा का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया बताया है। इसलिए प्रो. का यह उपभोग विद्या में सम्बन्धित नियम को उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम (Psychological Law of Consumption) कहा जाता है। उपभोग विद्या में कीन्सवादी आय का उत्पादन तथा राजस्व की व्याख्या में प्रमुख स्थान है। कीन्स ने अपना पुस्तक *The General Theory* में उपभोग विद्या की व्याख्या करते हुए कहा है कि समुदाय की मनोवैज्ञानिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि जब कुल वास्तविक आय का मात्रा में वृद्धि होती है तो वह उपभोग बढ़ता है परन्तु आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि उपभोग में होती है।¹। मतलब आय में वृद्धि से उपभोग पर पड़ने वाला प्रभाव का उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग विद्या की संज्ञा दी है।

कीन्सवादी उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Keynesian Psychological Law of Consumption)

प्रो. कीन्स ने उपभोग विद्या की व्याख्या का उपभोग या मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त में स्पष्ट किया है। प्रो. कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग सिद्धान्त तीन प्रमुख तर्कों पर आधारित है—(1) कुल आय में वृद्धि के साथ उपभोग का मात्रा में वृद्धि होती है परन्तु आय में वृद्धि की दर से कम दर पर वृद्धि होती है क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वेम-वेम उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती जाता है और इसलिए आय में वृद्धि से अनुपात में

1 The fundamental psychological law upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience is that men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases but not by as much the increase in their income.

—J M Keynes

The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) pp 96,

कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि होती है। (2) जब आय में वृद्धि होती है तो यह अतिरिक्त आय उपभोग और बचत में मध्य बँट जाती है। (3) आय में वृद्धि के बढ़ने में उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होती है।

सिद्धान्त की मान्यताएँ

(1) लोगो की उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता अथवा लोगो की व्यय करने की आदतें पहले जैसी ही रहती हैं। आय में परिवर्तन होने पर आय चरा जैसा—आय का वितरण वस्तु की कीमतों तथा जनसंख्या की वृद्धि आदि लगभग अपरिवर्तित रहता है।

(2) अव्यवस्था में सामान्य स्थिति पाई जाती है और अव्यवस्था की स्थिति या युद्ध जैसी असामान्य स्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं।

(3) स्वतन्त्र पूँजीवादी व्यवस्था पाई जाती है। उन अव्यवस्थाओं में यह नियम लागू नहीं होगा जहाँ सरकार द्वारा लोगो की उपभोग प्रवृत्ति पर अनुशासन लगा हो।

कीन्स के सिद्धान्त का अभिप्राय (Implications of Keynes Psychological Law)—अधिकार अर्थशास्त्री प्रो० कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का बीम की प्रमुख दो स्वीकार करते हैं। उपभोग त्रिधा का आर्थिक विश्लेषण का धर्म में एक महान अस्त्र का रूप में जाना जाता है। कीन्स का उपभोग सिद्धान्त की प्रमुख बातों का निम्नलिखित रूप में दर्शा जा सकता है—

विनियोग का महत्त्व—कीन्स ने आय तथा राजस्व का स्तर या ऊँचा उठाने के लिए विनियोग में वृद्धि का महत्त्व का स्वीकार किया है। उपभोग सिद्धान्त यह बताता है कि आय में वृद्धि का साथ उपभोग में वृद्धि का दर आय में वृद्धि या दर में कम होती है और आय तथा उपभोग में अन्तर का घटने का दर विनियोग का महत्त्व का प्रतिफल। यह सिद्धान्त बताता है कि आय में प्रत्येक वृद्धि का साथ उपभोग तथा आय का अन्तर बढ़ता जाता है और आय का उच्च स्तर का बनाये रखने के लिए अधिक से अधिक विनियोग बढ़ाने की आवश्यकता होती है यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रभावपूर्ण माँग में गिरावट आती है जिसमें अव्यवस्था भी नीचे का गिर जाती है। इस प्रकार विनियोग का महत्त्व अधिक होता है।

सामान्य अति-उत्पादन—यह सिद्धान्त बताता है कि अव्यवस्था में सामान्य अति-उत्पादन तथा बराजगारी की स्थिति आ सकती है। आय में वृद्धि का साथ उपभोग में इकाई में कम वृद्धि होती है और आय का उपभोग का स्तर निश्चित होता है जो अन्ततः अति-उत्पादन और बराजगारी में परिणत हो जाता है।

प्रो० से के नियम का सङ्केत—कीन्स ने अपने उपभोग सिद्धान्त में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रो० जे० बी० मे कावाज़ नियम कि 'पूँति अपनी माँग स्वयं पैदा करने लगी है' की कड़ी आशयता की ओर बताया कि माँग उपभोग प्रवृत्ति इकाई में कम होती है इसलिए जितना मान उत्पादन किया जाता है उसी गवनी माँग नहीं होने पाती और पूँति अपनी माँग पैदा करने में समर्थ नहीं होता इसलिए अति-उत्पादन (Over production) की स्थिति पाई जा सकती है।

सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता—सम्पूर्ण आय का व्यय नहीं किया जाता इसलिए कोई भी स्वयं चालित व्यवस्था नहीं होती जिससे कि आय तथा व्यय में बराबरी रहे इसलिए सरकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। सरकार अपनी हस्तक्षेप की नीति द्वारा इस बात का ध्यान रखती है कि कुल प्रभावपूर्ण माँग पूँति में कम न होना पाए।

अति वचन—प्रो० कोन्म कहते हैं कि बाय मे वृद्धि के साथ उपभोग में उमरी मात्रा में वृद्धि नहीं होती है इसलिए वचन का स्तर अधिक बढ़ता जाता है। धनी देशों में निधन देशों की अपेक्षा अधिक वचन बढ़ने का खतरा अधिक रहता है और इसके परिणाम अधिक भयकर होते हैं।

पूँजी की सीमान्त कुशलता का गिरना—लोभों की उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ लगभग अरिक्लिनित रहने की होती है, जिससे पूँजी की सीमान्त कुशलता (नाभ की दर गिरने की सम्भावना) में गिरावट की स्थिति दिखाई देती है। पूँजी की सीमान्त कुशलता में गिरावट को रोकने के लिए बाय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि करना जरूरी होता है। अलग विनियोग के मार्ग दर्शन के लिए उपभोग या प्रभावपूर्ण माँग का बढ़ना जरूरी है।

आय में वृद्धि—कोन्म के उपभोग का मनोवैज्ञानिक मिथान्त बताता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई में कम होती है और लोगों के पास व्ययशक्ति को बढ़ाने के लिए उनकी आय में वृद्धि करना जरूरी होता है जिसको हम थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं।

न्यून रोजगार साम्य—कोन्म ने बताया है कि यह जल्दी नहीं है कि पूर्ण रोजगार बिन्दु पर कुल माँग निया कुल पूर्ति निया के बराबर हो। पूर्ण रोजगार बिन्दु पर साम्य की स्थिति तभी होगी जबकि विनियोग की माँग बराबर हो जाएगी उस अन्तर्गम में जिस पर कुल आय पूर्ण रोजगार पर तथा कुल उपभोग व्यय (उमरी आय पर) दोनों बराबर हो जाएंगे। कोन्म का विश्वास था कि विनियोग माँग आय की राशि और उपभोग माँग (पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर) के बीच अन्तर को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगी इसलिए कुल माँग निया तथा कुल पूर्ति निया मर्दब ही न्यून रोजगार साम्य (पूर्ण रोजगार साम्य से नाचे स्तर पर) एक दूसरे को काटेंगे।

चिरकालिक स्थिरता (Secular Stagnation)

प्रो० कोन्म की ऐसी मान्यता है कि आय में वृद्धि में उपभोग में वृद्धि उभरना होती है कि विनियोग माँग कमजोर होती जाती है और अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर बढ़ती हुई वस्तुओं की निर्यातों के लिए या विनियोग बढ़ाने की सम्भावनाएँ समाप्त हो जाएंगी। (पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए जो जरूरी होता है)। इस अवस्था को चिरकालिक स्थिरता की स्थिति कहते हैं और ऐसी स्थिति को रोकना चाहिए जिसके लिए उपयोग में स्थिरता नहीं आने देना चाहिए।

व्यापार चक्र—कोन्म ने उपभोग के मनोवैज्ञानिक मिथान्त में यह बताने का प्रयास किया है कि व्यापार चक्रों की स्थितियाँ में परिवर्तन कैसे होता है। कोन्म के विचारों में पहले व्यापार चक्र के विभिन्न मिथान्तों का प्रतिपादन किया गया था परन्तु कोन्म पहला अर्थशास्त्री था जिसने बताया कि उपभोग निया के स्थिर रहने पर व्यापार चक्र में विभिन्न अवस्थाएँ कैसे आती हैं। जब व्यापार चक्र समृद्धि के उच्च स्तर पर होता है उस समय आय बढ़ने में, वृद्धि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति इकाई में कम होती है जिसके कारण समृद्धि में निरंतर व्यापारी की डिमा गिरावट की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार जब व्यापार चक्र निम्नतम बिन्दु पर पहुँचता है, तो लोगों की आय बहुत गिर जाती है, परन्तु माँग अपने उपभोग के स्तर को आय में गिरावट के अनुसार कम नहीं करते, तो व्यापार चक्र के ऊपर उठने का प्रथम प्रारम्भ हो जाता है।

उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ (Meaning of Propensity to Consume)

आय तथा व्यय व सम्बन्ध का चित्रण वाणी किया ही उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। उपभोग प्रवृत्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि आय में परिवर्तन व माय-माय उपभोग में परिवर्तन किस प्रकार होता है। उपभोग व्यय आय का फल होता है अर्थात् $C=f(Y)$ । उपभोग फल की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

प्रो० एफ० एस० ड्यूबेन के अनुसार— उपभोग फल इस बात का दर्शाता है कि आय के प्रत्येक सम्भावित स्तर पर उपभोगिता व्यय तथा संचय पर कितना व्यय करना चाहें।¹

प्रो० मॅकडूगल एवं डर्नबर्ग द्वारा— वह सूत्र जो उपभोग का उपभोग आय में सम्बन्धित करता है उसे उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग क्रिया कहते हैं।²

प्रो० कुरीहारा के शब्दों में— यह पूर्ण सूत्र जो आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग की विभिन्न राशियाँ सम्बन्धित करता है। शून्य न हो तो उपभोग प्रवृत्ति अथवा उपभोग फल कहा है।³

उपभोग क्रिया (Consumption Function)

उपभोग क्रिया का अर्थ शून्य न शून्य उपभोग प्रवृत्ति कहा है। उपभोग क्रिया या शून्य उपभोग प्रवृत्ति का आय तथा उपभोग व परस्पर सम्बन्ध द्वारा दर्शाया जाता है जिसका हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं $C=f(Y)$ । शून्य आय पर शून्य उपभोग व विभिन्न स्तर होता है। विभिन्न आय स्तर पर उपभोग व्यय दर्शाने व दिए जा अनुसूची बनाई जाता है उसे उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहते हैं। हम एक तालिका तैयार कर सकते हैं जो आय व उपभोग के सम्बन्ध को दर्शाती है। आय (Y) का स्तर चाहे जो कुछ भी हो उपभोग पर (C) व्यय कर दिया जाता है अर्थात् $C=Y$ । इस स्थिति का हम अग्रवर्ति ग्राफिक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं—

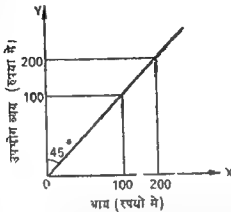
अग्रवर्ति ग्राफिक में दिखाया गया है कि यदि आय 100 रुपये होती है तो उपभोग भी 100 रुपये रहता है और यदि आय बढ़कर 200 रुपये हो जाती है तो उपभोग भी बढ़कर 200 रुपये हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें समान आय का उपभोग व बराबर मान दिया है।

1 Consumption function shows what expenditure consumers will wish to make on consumers goods and services at each possible level of income
—F S Brooman

2 The schedule that relates consumption to disposable income is called the propensity to consume or the consumption function
—Mc Dougall and Dernburg

3 The whole schedule relating to various amounts of consumption and various levels of income is what Keynes calls the propensity to consume or simply the consumption function
—Kurihara

हम वास्तविक स्थिति पर विचार करें तो पता चलता है कि मनुष्य अपनी समस्त आय को उपभोग पर व्यय न करके कुछ एक अंश को व्यय करता है और शेष का बचाव



रक्ता है अर्थात् $S = Y - C$ । व्यय द्वारा आय के वृत्ताय प्रवाह को बनाए रखने के काय पर जो प्रभाव पड़ता है वह महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का एक भाग व्यय कर लेता है तो वह दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है और आगे चक्कर आय का वृत्तीय प्रवाह में यागदान देता है यदि वह व्यय को आय का वृत्तीय प्रवाह से हटा लेता है तो यह एक प्रसार से ह्रास करण (Erosion) पैदा कर देता है।

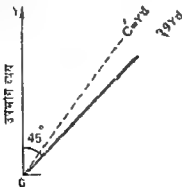
दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपभोग प्रिया या फलन (The Long run and Short run Consumption Function)

उपभोग प्रिया को हम दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपभोग प्रियाओं में बाँट सकते हैं। दीर्घकालीन उपभोग प्रिया का सम्बन्ध दीर्घकालीन आय से होता है। दीर्घकालीन उपभोग फलन का एक सरल रेखाचित्र द्वारा दिखाया जाता है जो मूल बिन्दु से गुजरती है जैसा कि निम्नान्वित रेखाचित्र में दिखाया गया है।

Y_d - स्थायित या उपभोग्य आय

C उपभोग

स्पष्टीकरण—प्रस्तुत रेखाचित्र में OC एक सीधी रेखा जहाँ मूल बिन्दु O से प्रारम्भ होती है जो बताती है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है परन्तु यह वृद्धि

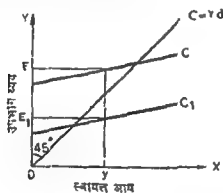


आय अनुपात की दृष्टि में एक-सी रहती है। O बिन्दु से एक आय रेखा OC' खींची गई है जो यह बताती है कि यदि उपभोक्ता अपनी मारी आय खर्च कर देगा तो स्थिति क्या होगी? OC रेखा OC' रेखा की अपेक्षा नीचे की ओर धीरे-धीरे जाती है जिससे आशय यह है कि उपभोग का अनुपात आय की अपेक्षा हमेशा इनाई \square कम रहना है। आय को उपभोग्य आय द्वारा दिखाया गया है।

अल्पकालीन उपभोग प्रिया या फलन (The Short-run Consumption Function)

व्यवहार में वस्तु की माँग की परिस्थितियाँ काफी स्थाई होती हैं। यदि माँग अल्प-कालीन है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव वस्तु की कीमत पर पड़ता है। इसलिए हम अल्पकालीन विश्लेषण में अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करेंगे कि माँग व परिणाम का वस्तु की कीमत के साथ क्या सम्बन्ध है। उपभाग अध्य निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है—

- (1) माँग परिस्थितियों में निर्दिष्ट माधन के अतिवर्धित रहत हुए आय का स्तर
- (2) व सभी माधन जो यह निर्धारित करते हैं कि आय का कितना उपभोग होता है बाह आय का विशेष स्तर कुछ भी हा।



(अल्पकालीन उपभोग फलन का एक स्थान परिवर्तन)

अल्पकाल में उपभोग में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से आय में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम होते हैं। अतः उपभोग को आय स्तर से सम्बन्धित करना और अन्य कारकों "प्राचल" (Parameters) मानना उचित होगा।

स्पष्टीकरण—प्रस्तुत रेखाचित्र में C तथा C_1 के बीच की स्थिति उपभोग और आय के बीच सम्बन्ध को बताती है। चित्र में C तथा C_1 तब तक की गति उभय वर्गी की सूचित करती है जो किसी प्राचल में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में हुई है। अतः आय स्तर OY पर उपभोग OE में घटकर OE_1 हो जाता है। गुणिता की दृष्टि में हम यह मान लेते हैं कि आय में वृद्धि होने के साथ उपभोग में भी वृद्धि हो जाती है।

औसत तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (Average and Marginal Propensity to Consume)

आय तथा उपभोग के सम्बन्ध को नापने के लिए हम औसत तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्तियों को उपयोग करते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति एक ममयावधि में कुल आय के अन्दर में कुल उपभोग की स्थिति को बताती है जबकि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति आय की

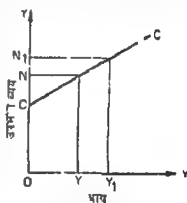
वृद्धि में हुए परिवर्तन के मन्दमं उपभोग में वृद्धि के परिवर्तन की व्याख्या करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति आय के मन्दमं उपभोग की दर को तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के परिवर्तन के अनुपात में उपभोग में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करती है।

$$APC = \frac{C}{Y} \text{ तथा } MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

APC = औसत उपभोग प्रवृत्ति MPC = सीमांत उपभोग प्रवृत्ति
C = उपभोग Y = आय ΔC = उपभोग में होने वाली वृद्धि में परिवर्तन
 ΔY = आय में होने वाली वृद्धि में परिवर्तन

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आय तथा उपभोग का सामान्य सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है परन्तु यह वृद्धि इकाई से कम होती है। इसी बात को एक रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है—

प्रस्तुत रेखाचित्र में दिखाया गया है कि जब आय OY है तो उपभोक्ता ON उपभोग करता है यदि आय बढ़कर OY_1 हो जाती है तो उपभोग व्यय बढ़कर ON_1 हो जाता है। उपभोक्ता OC उपभोग व्यय करेगा चाहे उसकी आय शून्य ही क्यों न हो। इसका आशय यह है कि भूखी मरने से अच्छा उपभोक्ता यह समझेगा कि वह अपनी भूतपूर्व वस्तुओं को व्यय करे अथवा अपनी सम्पत्ति को बेचेगा। आय हा या न हो परन्तु एक निम्न स्तर अर्थात् जीवित रहने के लिए जितना व्यय जरूरी है उपभोक्ता करेगा ही। CC_1 रेखा बताती है कि आय में बढ़ने के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में उपभोग क्रिया विभिन्न रूप ग्रहण कर लेती है और रेखा चित्र का आकार भी उसी प्रकार परिवर्तित होता जाता है।



आय तथा उपभोग को सामान्य रूप से वास्तविक आय तथा वास्तविक उपभोग द्वारा दिखाया जाता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने का प्रभाव उपभोग के स्तर पर देखने के लिए हमें वस्तु की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के समर्थन में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि उपभोक्ता की आय तथा कीमतें दुगुनी हो जाएं तो उपभोग की मात्रा भी दुगुनी हो सकती है एवं व्यय 75 प्रतिशत ही बढ़े तो हम इन दोनों स्थितियों को उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा नहीं दिखा सकते। इस प्रकार कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के उपभोग व्यय में भी परिवर्तन हो जाते हैं और इन परिवर्तनों को वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा पुष्पक रूप से देखना चाहिए। बीजगणितीय भाषा में उपभोग वृत्तन को हम अवलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

$C + C(Yd) C =$ कुल वास्तविक उपभोग

$Yd =$ कुल वास्तविक स्थायित आय

यदि उपभोग फलन ररणीय (Linear) है तो इस ढग प्रकर रर सवतें हैं —

$$C = C_0 + bYd$$

C_0 - शून्य स्थायित आय पर उपभोग की मात्रा

b - सीमात उपभोग प्रवृत्ति

सीमात तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में सम्बन्ध (Relation between MPC and APC)

आय में वृद्धि के साथ APC तथा MPC दोनों ही गिरते हैं परन्तु MPC के गिरने की दर APC से अधिक होती है। निधन तथा विवामणीन ढगों में MPC APC से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि धनी देशों में लोगों की विविध आवश्यकताएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी होती हैं इसलिए जैसे-जैसे आय बढ़ती है उपयोग व्यय बढ़ने की अपेक्षा यक्षत अधिक होने लगती है। निधन देशों में लोगों की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए आय वृद्धि का अधिकांश अनुपात उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है।

उपभोग क्रिया की आय के अलावा प्रभावित करने वाले अन्य तत्व (Factors Other than Income Affecting Consumption Function)

हम उपभोग राशि (Consumption Amount) तथा उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) के मध्य अन्तर का स्पष्ट रूप में समझना चाहते हैं। उपभोग राशि स्थिर नहीं होती क्योंकि यह आय पर निर्भर करती है जो समय परिणतनीन होती है। इसके विपरीत अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर होती है क्योंकि यह व्यष्टि की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर जो कि मनुष्य का एक स्वभाव है जानी है निर्भर करती है। केवल कुछ अति हीनत या अन्य आर्थिक सबटा के समय उपभोग प्रवृत्ति हा जाती है। हालांकि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहने की प्रवृत्ति दिखताती है परन्तु यह पूर्णतया ब्रेलोक नहीं होता। उपभोग प्रवृत्ति में अल्पकाल में मरुतार की राजकापीय नीतियों ब्याज की दर तथा पूंजी मूल्य (Capital Values) के तरल परिवर्तन देखे जा सकते हैं। Prof. Keynes न कहते हैं कि स्वयत्त आय में म किा जाना या न व्यय की राशि पर अनुनिष्ठ तत्व (Objective Factors) तथा व्यष्टिनिष्ठ तत्व (Subjective Factors) दोनों का ही प्रभाव पता है। इनकी अलग-अलग धनी हम इस प्रकार धरेग।

अनुनिष्ठ तत्व (Objective Factors)— यह तत्व निर्मानमित प्रसार में हा सकते हैं—

(i) समुदाय में धन तथा आय का वितरण (The Distribution of Wealth and Income in the Community)— उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारण में आय तथा सम्पत्ति का वितरण का प्रमुख रूप में प्रभाव पड़ता है। धनी व्यष्टियों की अपेक्षा निधन व्यष्टियों में APC तथा MPC दोनों ही ङ्की होती है अर्थात् अपनी आय के अधिक भाग को उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है इसका कारण यह है कि निधन व्यष्टियों की पहल में ही बहुत सी आवश्यकताएँ अनुनिष्ठ बनी रहती हैं। इसका विपरीत धनी व्यष्टि उच्च जीवन स्तर व्यतीत कर रहे होते हैं और उनकी अधिकांश आवश्यकताएँ अनुनिष्ठ रहती हैं इसलिए अतिरिक्त का अधिकांश भाग वे बचा लेते हैं। इस प्रकार धन और आय के अधिक समान रूप में वितरण करने पर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि की जा सकती है।

(ii) उपलब्ध परिसम्पत्तियों का आकार तथा स्वहय (The Size and Nature of Assets Held)— एक व्यष्टि के पास दो प्रकार की परिसम्पत्तियाँ हो सकती हैं प्रथम नवद

परिसम्पत्ति (Liquid Assets) तथा **अनवद परिसम्पत्ति (Illiquid Assets)** नकद परिसम्पत्तियाँ ऐसी परिसम्पत्तियाँ हैं जो कि उद्योग उपभोक्ता (व्यक्ति) भी समय आसानी से कर सकता है जब कि अनवद परिसम्पत्तियों का अर्थ है— भूकान भूमि या अन्य पूँजीगत वस्तुएँ जो कि से होता है। अनवद परिसम्पत्तियों के बहन पर उपभोग में वृद्धि हो सकती है क्योंकि इनके धारक यह समझते हैं कि सवटवान में इन्हें बेचना या बदल कर नकदी प्राप्त की जा सकती है।

(iii) **कीमतों का स्तर (The Level of Prices)**— मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अवस्फीति (Inflation and Deflation) का प्रभाव उपभोग प्रवृत्ति पर आवश्यक रूप से पड़ता है। मुद्रा स्फीतिदाता में आय में अप्रत्याशित वृद्धि होती है इस कारण व्यक्ति स्तम्भतापूर्वक उपभोग व्यय करता है। साथ ही कीमतें बढ़ने से ऋण पत्रों आदि के मूल्य गिरने लगते हैं। जिन व्यक्तियों के पास यह चीजें होती हैं वे समझते हैं कि इनकी लागने गिर रही है और वे बहुत घुरी स्थिति में पहुँच गए हैं इसलिए इनके धारक इन ऋण पत्रों के वास्तविक मूल्य बनाए रखने के लिए कम व्यय करते हैं। स्फीतिकाल में मजदूरी की अपेक्षा उच्च आय वर्ग को अधिक लाभ होते हैं। इसलिए स्फीति में उपभोग गिरता अर्थात् नीचे की ओर चला जाता है जब कि अवस्फीति काल में यह ठपरी हट जाता है। ऐसा उच्च आय स्तरों पर विशेष रूप से होता है हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्फीति में अधिकांश लोग उच्च आय समूह में आ जाते हैं। अतः वास्तविक रूप से वर्द्धमान कराधान से अधिक धनराशि सरकार द्वारा अधिकांश धनराशि वसूल करली जाती है।

(iv) **प्रत्याशाएँ (Expectations)**— व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं की कीमत में भारी परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग नियम पर पड़ता है। यदि उपभोक्ताओं को यह पता चल जाए कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी अथवा वस्तुओं की प्रवृत्ति में कमी आ जायेगी तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएँ खरीदेंगे इनके इस व्यवहार से उपभोग नियम में वृद्धि हो जायेगी ऐसा प्रायः मुँह छिड़ जाने या फिर स्फीतिक स्थितियों के कारण लगातार कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण होता है। इससे विपरीत यदि लोगों को यह आशा हो कि भविष्य में वस्तुएँ अधिक मात्रा में मिलेंगी या वस्तु की कीमतें गिर जायेंगी तो वह थोड़े समय के लिए वस्तुओं की खरीद पर रोक लगा देंगे जिससे उपभोग नियम में गिरावट आ जायेगी।

(v) **सरकार की नीति (Government Policy)**— सरकार की राजकोषीय नीतियाँ जैसे करारोपण व्यय तथा बचत नीतियाँ उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव डालती हैं। ऋणों में थोड़ी छूट देने से लोगों के पास स्वायत्त आय की मात्रा बढ़ जाती है और लोग उपभोग पर व्यय बढ़ा देते हैं। इससे विपरीत अधिक कर लगाने से स्वायत्त आय में गिरावट आती है जिससे परिणामस्वरूप उपभोग गिर जाते हैं। यदि सरकार बहुत अधिक प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाती है तो इससे आय में वितरण की असमानताएँ कम हो जाती हैं तथा उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इससे अनावा किराया खरीद योजना (Hire Purchasing Scheme) तथा बँके ऋण नियामता ढांग लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्रों बचत प्रमाण पत्रों तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ पर दरो में छूट आदि का वचता पर अनुभूत प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में घरेलू बचतें पूँजी निर्माण का प्रमुख स्रोत कही जाती हैं।

(vi) **व्यय पर निजी क्षेत्र के प्रभाव (Influence of Private Sector on Spending)**— समय अपूर्ण शक्तियोंवाला की स्थिति बाजार में पाई जाती है। विज्ञान और प्रचार के माध्यम से निजी फर्म अपनी मंहुगी वस्तुएँ उपभोक्ताओं को बेचने में समर्थ हो जाते हैं,

$C + C(Y_d) \quad C =$ कुल वास्तविक उपभोग

$Y_d =$ कुल वास्तविक आयत आय

यदि उपभोग फलन रैखीय (Linear) है तो इसका प्रसारण रख सकते हैं —

$$C = C_0 + bY_d$$

C_0 शून्य स्वायत्त आय पर उपभोग की मात्रा

b - सीमांत उपभोग प्रवृत्ति

सीमांत तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में सम्बन्ध (Relation between MPC and APC)

आय में वृद्धि के साथ APC तथा MPC राना हो सकते हैं परन्तु MPC के गिरने की दर APC में अधिक होती है। निधन तथा शिवात्मशील राना में MPC APC में अधिक होती है। इसका कारण यह है कि धनी दशा में भाग की विभिन्न आवश्यकताएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी होती हैं इसलिए जैसे जैसे आय बढ़ता है उपभोग धीरे धीरे बढ़ने की अपेक्षा बचत अधिक राना लगती है। निधन दशा में भाग की बढ़ते गाने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए आय वृद्धि का अधिकांश अनुपात उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है।

उपभोग क्रिया को आय के अलावा प्रभावित करने वाले अन्य तत्व (Factors Other than Income Affecting Consumption Function)

हम उपभोग राशि (Consumption Amount) तथा उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) में मध्य अन्तर का स्पष्ट राना में समझना चाहते हैं। उपभोग राशि स्थिर नहीं होती क्योंकि यह आय पर निर्भर करती है जो समय परिवर्तनशील होती है। इसके विपरीत अपेक्षा में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर होता है क्योंकि यह व्यक्ति की मनावैज्ञानिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है जो स्थिर रहता है। तब भी यह सत्य है। कबल युद्ध की स्थिति या अन्य आपदा मरणा के समय उपभोग प्रवृत्ति हो जाती है। हालाँकि अपेक्षा में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहने का प्रवृत्ति राना होती है परन्तु यह पूर्णतया बताने में नहीं आती। उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन में परिवर्तन की राजकाशीय नीतियाँ, व्याज की दर तथा पूँजी मूल्य (Capital Values) का कारण परिवर्तन दिये जा सकते हैं। Prof. Keynes ने कहा है कि स्वयंसेवक आय में परिवर्तन राना या व्यक्ति की रानि पर प्रवृत्ति तथा (Objective Factors) तथा व्यक्तिगत तत्वा (Subjective Factors) दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इनकी अवगमना के लिये हम दो प्रकार के तत्व हैं।

वस्तुनिष्ठ तत्व (Objective Factors)—यह तत्व निम्नलिखित प्रकार में हो सकते हैं—

(i) समुदाय में धन तथा आय का वितरण (The Distribution of Wealth and Income in the Community) उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण में आय तथा सम्पत्ति का वितरण का प्रमुख रूप में प्रभाव डालता है। अर्थात् व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति निधन अधिकता से उपभोग तथा MPC राना हो जाती होती है जयान् अपनी आय का अधिक भाग का उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है इसका कारण यह है कि निधन व्यक्तियों की पढ़ में हो बहुत सी आवश्यकताएँ समन्वुष्ट बनी रहती हैं। इस विपरीत धनी व्यक्ति उच्च जीवन स्तर व्यतीत कर रहे हाने हैं और उनकी अधिकांश आवश्यकताएँ समन्वुष्ट रहती हैं इसलिए अतिरिक्त का अधिकांश भाग व बचाव में है। इस प्रकार धन और आय का अधिक समान रूप में वितरण करने पर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि का जा सकता है।

(ii) उपलब्ध परिसम्पत्तियों का आकार तथा स्वरूप (The Size and Nature of Assets Held)—एक व्यक्ति का पास का प्रकार की परिसम्पत्तियाँ हो सकती हैं प्रथम नवद

परिसम्पत्ति (Liquid Assets) तथा **अनवद परिसम्पत्ति (Illiquid Assets)** के वद परि-
सम्पत्तियों ऐसी परिसम्पत्तियाँ हैं जो कि आसानी से बिक्री के द्वारा नकद में बदल सके हैं।
अनवद परिसम्पत्तियाँ ऐसी वस्तुएँ हैं जो कि आसानी से नकद में बदल नहीं सके हैं।
अनवद परिसम्पत्तियों के वद परि-
सम्पत्तियों से यह अन्तर है कि अनवद परिसम्पत्तियों का अर्थ है—मकान, भूमि या
अन्य पूँजीगत वस्तुएँ आदि से होता है। अनवद परिसम्पत्तियों के वद परि-
सम्पत्तियों से यह अन्तर है कि अनवद परिसम्पत्तियों का अर्थ है—मकान, भूमि या
अन्य पूँजीगत वस्तुएँ आदि से होता है। अनवद परिसम्पत्तियों के वद परि-
सम्पत्तियों से यह अन्तर है कि अनवद परिसम्पत्तियों का अर्थ है—मकान, भूमि या
अन्य पूँजीगत वस्तुएँ आदि से होता है। अनवद परिसम्पत्तियों के वद परि-

(iii) **बीमतों का स्तर (The Level of Prices)**—मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अ-
स्फीति (Inflation and Deflation) का प्रभाव उपभोग प्रवृत्ति पर आवश्यक रूप से पड़ता
है। मुद्रा स्फीति का प्रभाव उपभोग प्रवृत्ति पर पड़ता है। इस कारण व्यक्ति स्तर पर उप-
भोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। भाग ही बीमतें बढ़ने से व्यक्ति स्तर पर उपभोग प्रवृत्ति में
वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति को वे पास यह चीजें होती हैं वे समझते हैं कि इनकी लागतें
गिर रही हैं और वे बहुत बुरी स्थिति में पहुँच गए हैं इसलिए इनके द्वारा इन चीजों
को खरीदने के लिए वे अधिक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्फीतिकाल में मजदूरी
की अपेक्षा उच्च आय बढ़ने से अधिक लाभ होता है। इसलिए स्फीति में उपभोग
प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और पता चलता है कि जब कि अवस्फीति काल में यह उपरी हट
जाता है। ऐसा उच्च आय स्तरों पर विशेष रूप से होता है हमें यह ध्यान रखना चाहिए
कि स्फीति में अधिकांश लोग उच्च आय स्तरों में आ जाते हैं। अतः वास्तविक रूप से वृद्धि मान
कराधान से अधिक धनराशि सरकार द्वारा अधिकांश धनराशि वसूल करली जाती है।

(iv) **प्रत्याशाएँ (Expectations)**—व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं की कीमतों में भारी
परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग प्रवृत्ति पर पड़ता है। यदि उपभोक्ताओं की यह पता चल जाए
कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी अथवा वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी
तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं की खरीद करके इन वस्तुओं से उपभोग
प्रवृत्ति में वृद्धि हो जायगी। ऐसा प्रायः मुद्रा छिड़ जाने या फिर स्फीतिक स्थितियों के कारण
लगातार बीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों को यह
आशा हो कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी तो वे अधिक मात्रा में वस्तुओं की खरीद
करके उन वस्तुओं की खरीद पर रोक लगा देंगे जिससे उपभोग प्रवृत्ति में
गिरावट आ जायगी।

(v) **सरकार की नीति (Government Policy)**—सरकार की राजकोषीय नीतियाँ
जैसे बजट नीति तथा वित्त नीतियाँ उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव डालती हैं। ऋणों में
थोड़ी छूट देने से लोगों के पास स्वायत्त आय की मात्रा बढ़ जाती है और लोग उपभोग
पर व्यय बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत अधिक कर लगाने से स्वायत्त आय में गिरावट आती
है जिससे परिणामस्वरूप उपभोग गिर जाता है। यदि सरकार बहुत अधिक प्रगतिशील कर
प्रणाली अपनाती है तो इससे आय में वितरण की असमानताएँ बढ़ हो जाती हैं तथा
उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा विनाशकारी योजना (Harc Purchasing
Scheme) तथा बैंक ऋण नियामकों द्वारा लोगों को उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरी
ओर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्रों वित्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर
दरों में छूट आदि का वित्त पर अनुपूल प्रभाव पड़ता है। विनाशकारी देशों में घरेलू
वस्तुओं की निर्माण का प्रमुख ग्योन बढ़ती जाती है।

(vi) **व्यय पर निजी क्षेत्र के प्रभाव (Influence of Private Sector on Spending)**—समय अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में फैल जाती है। निजी और प्रसार
के माध्यम से निजी क्षेत्र अपनी महंगी वस्तुएँ उपभोक्ताओं की खरीद में समर्थ हो जाती है।

जिम्हसे उपभोग का स्तर उँचा हो जाता है। उदाहरणार्थ स्मूटर, रशीन टेलीविजन, कारें, एयर कण्डीशनर आदि। ऋण सम्बन्धी नीतियाँ समय समय पर छूट दी जायें तो भी लोग खुलकर व्यय करते हैं और उपभोग का स्तर उँचा उठता है।

(vii) अप्रत्याशित लाभ अथवा हानि (Unexpected Gains or Loss)—कभी-कभी आय में अप्रत्याशित वृद्धि या गिरावट के कारण उपभोग प्रभावित हो जाती है। आय या लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर उपभोक्ता सामान्य उपयोग से अधिक उपभोग करने लगता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को कभी अप्रत्याशित हानि उसकी आय में हो जाए तो उसके उपभोग का स्तर सामान्य उपभोग से कम हो जाता है।

व्यक्तिनिष्ठ तथ्य (Subjective Factors)

प्रो० बीन्स कहते हैं कि लोगों की रुचि करने की प्रवृत्ति या उपभोग प्रवृत्ति पर व्यक्तिनिष्ठ तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति स्वभाव से दूरदर्शी होता है दूरदर्शिता का अर्थ किसी व्यक्ति में अधिक तो किसी में कम होता है। दूरदर्शिता उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथवा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखी जान वाली धनराशि (जैसे—बुढ़ापे, बीमारी, दुर्घटना, बच्चों की शिक्षा तथा वेगजगारी आदि) जैसे—बचचा के लिए सम्पत्ति को एकत्रित करना, भावी आवश्यकताओं या दुर्घटनाओं के लिए धनराशि की बचत पूँजी विनियोजन से होने वाले लाभ की कामना जितनी अधिक होगी उपभोग प्रवृत्ति में उतनी ही गिरावट आएगी।

प्रो० बीन्स ने व्यक्तिनिष्ठ तत्वों के पीछे निम्नलिखित आठ उद्देश्य बताए हैं—

- (1) भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए रक्षित कोष को रखना।
- (2) भविष्य की आय तथा आवश्यकताओं के मध्य सम्बन्ध की दृष्टि से कुछ धनराशि बचाना जैसे—बुढ़ावस्था पारिवारिक शिक्षा अथवा आश्रितों के भरण-पोषण के लिए आदि।
- (3) ध्याज के रूप में धनराशि प्राप्त करने के लिए लोग वर्तमान उपभोग की अपेक्षा भावी उपभोग को महत्व देते हैं।
- (4) भविष्य में अच्छे जीवन स्तर को व्यतीत करने की सावधानी से बचत करना।
- (5) स्वतन्त्रता की अनुभूति का आनन्द लेने के लिए और काम करने की शक्ति की दृष्टि बिना किसी स्पष्ट विचार या स्पष्ट विशिष्ट कार्य की इच्छाओं से।
- (6) मृदा उद्देश्य या व्यापारिक परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए।
- (7) सम्पत्ति अर्जित करने की इच्छा।
- (8) विद्युद्द बजूसी या कृपणता की संतुष्टि के लिए।

प्रो० बीन्स ने उपर्युक्त उद्देश्यों की सुरक्षा, दूरदर्शिता अनुमान या आश्चयन, प्रगतिशीलता, स्वतन्त्रता, माहुरियता, कृपणता आदि की सजा दी है। उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रो० बीन्स ने केन्द्रीय तथा स्वायत्त संस्थाओं या फर्मों द्वारा बचत करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं—

1 वाजार से ऋण या पूँजी प्राप्त करने की अपेक्षा स्वयं पूँजीगत विनियोगों की दृष्टि से।

2 तरलता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिम्हसे कि तरल साधनों की सुरक्षा की जा सके और आपात स्थिति, कठिनाइयों तथा मन्दी में निपटा जा सके।

3 प्रगति के उद्देश्य की दृष्टि से।

4 आधुनिक चतुराई व उद्देश्य की दृष्टि से जिसमें विप्लव शोधन तथा भावी सम्पत्ति की प्राप्ति को समाप्त करने के लिए व्यवस्था हो सके।

इन सभी उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता संस्थाओं तथा संगठनों को आधुनिक समुदाय की आदर्श शिक्षा रीति रिवाजों घम और वर्तमान नैतिक स्तर वर्तमान की आशाओं तथा भूतकालीन अनुभवा पूँजीगत अस्त्रों के पैमाने तथा तकनीक सम्पत्ति के प्रचलित वितरण व्यवस्था तथा लागू द्वारा जीवन-स्तर स्थापित करने आदि बातों पर निर्भर करेगा।

अल्पकाल में व्यक्ति निष्ठ और वस्तुनिष्ठ तत्वा में अधिक परिवर्तन नहीं होते इस लिए हम उपभोग यंत्र की आकृति को अपरिवर्तित मानकर चलते हैं।

साधारण उपभोग फलन के परिष्कार (Refinements of the Simple Consumption Function)

प्रो० बी० ने उपभोग फलन की धारणा निम्नलिखित रूप धारणाओं पर आधारित है—

(1) उपभोग विद्यमान आय का फलन होता है $C = f(Y_t)$ ।

(2) उपभोग फलन आय के सम्बन्ध में परिवर्ती होता है यदि आय में कमी होगी तो व्यक्ति उसी हिसाब से उपभोग में कमी कर देगा जिस प्रकार आय बढ़ने पर उन्होंने उपभोग के स्तर को बढ़ा दिया था।

(3) उपभोक्ता द्वारा व्यय करने की विधि स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। वे आय उपभोक्ताओं के व्यय पर निर्भर नहीं करते।

प्रो० ड्यूसेनबेरी परिकल्पना (Prof Duesenberry Hypothesis)

सन् 1957 में प्रकाशित प्रो० ड्यूसेनबेरी ने अपनी पुस्तक = *Income Saving and the Theory of Consumer Behaviour* में प्रो० कोन्स का संकटन किया और दो मुख्य बातों को बताया जो उपभोग फलन के सम्बन्ध में पाई जाती हैं इन्हें ड्यूसेनबेरी परिकल्पना (Duesenberry Hypothesis) कहा जाता है। प्रथम उनका कहना यह है कि एक व्यक्ति का उपभोग व्यय उसकी वर्तमान आय के द्वारा ही तय नहीं होता। परन्तु भूतकाल में व्यतीत जीवन स्तर के द्वारा भी तय होता है। वे कहते हैं कि जब किसी परिवार की आय उस नये स्तर तक पहुँचती है जिसे स्थायी माना जाता है तो परिवार अन्ततः अपने उपभोग का समायोजन एक उच्च आय स्तर पर करेगा। इस बात को एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यदि एक परिवार की दीपकालीन उपभोग प्रवृत्ति 7 है और स्वायत्त आय 7000 रुपये है तो वह 4900 रुपये उपभोग करेगा। यदि उसकी आय बढ़कर 9000 रुपये हो जाती है तो उपभोग बढ़कर 6300 रुपये हो जाएगा परन्तु यदि किसी कारणवश उस परिवार की आय गिरकर फिर 7000 रुपये रह जाती है तो परिवार अपने भूतकालीन उपभोग घटेराशि 6300 रुपये को घटाकर 4900 रुपये नहीं कर पाएगा क्योंकि वह उसी जीवन स्तर को बनाए रखेगा जिसका वह पहले आदी हो चुका होगा।

प्रो० ड्यूसेनबेरी के तर्क अर्थ यह है कि प्रो० बी० का यह धारणा सही नहीं है कि उपभोग विद्यमान आय का फलन ही नहीं है। वरन् यह पहले प्राप्त आय के उच्चतम स्तर का भी फलन है। वे कहते हैं कि अधिकतम आय वाले वर्ग का उपभोग वह स्तर स्थापित

करता है निम्न वर्गीकृतियाँ की जाती हैं। अधिकतम उपभोग जितना अधिक होगा उपभोग को घटाने उभी स्तर पर जाता होता है उठित होगा।

दूसरे में उपभोग के नतीजे की इस प्रकार धारणा पर भी आश्रय दिया है कि उपभोक्ता द्वारा व्यय करने की विधि स्वतन्त्र रूप से निर्धारित होती है। उनका कहना है कि किसी परिवार का पारिवारिक व्यय या उपभोग उस परिवार की वृद्धि स्वतन्त्र गति या ही चलन नहीं है बरन् उम्मी अथवा उच्च आय के समूह के अन्य उपभोक्ताओं की गति या भी परभाव होता है। निम्न आय वर्ग के लोग की उपभोग प्रिया उच्च आय वर्ग के लोग की उपभोग प्रिया द्वारा प्रभावित होती है। यदि निम्न आय वर्ग या उच्च आय वर्ग के लोग की उपभोग दस्तुआ या उपभोग प्रारम्भ कर देता है तो उच्च आय वर्ग के लोग एसी दस्तुआ के स्थान पर नई दस्तुआ की ओर प्रारम्भ कर देता है इस प्रकार उपभोग प्रिया का विस्तार होता जाता है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 उपभोग प्रिया या फलन का बताइए। औसत तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति में आप क्या समझते हैं और इन दोनों में क्या सम्बन्ध है ?

(Explain consumption function What do you mean by Average and Marginal Propensities to consume ? What is the relationship between them ?)

- 2 कीनेस के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम तथा उनकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए।

(Discuss Keynes's Psychological Law of Consumption and its limitations)

- 3 कीनेस का सबसे उल्लेखनीय योगदान उनकी उपभोग प्रिया की व्याख्या है। (हैनसन) इस कथन के आधार पर उपभोग प्रिया का समष्टि आर्थिक विवेचन में महत्त्व बताइए।

(Keynes most notable contribution was his consumption function (Hansen) In the light of this statement bring the importance of consumption function in macro economic analysis)

- 4 उपभोग फलन में आप क्या समझते हैं ? उपभोग फलन का निर्धारित करने वाले व्यक्तिनिष्ठ तथा दस्तुनिष्ठ तत्वों का समझाइए।

(What do you understand by consumption function ? Explain subjective and objective factors which determine the consumption function)

- 5 उपभोग प्रवृत्ति में आप क्या समझते हैं ? सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में भेद कीजिए।

(What do you understand by the consumption function ? Distinguish between the Marginal propensity to consume and Average Propensity to consume)

■ टिप्पणी लिखिए—

- (i) कुल माँग श्रिया तथा कुल पूर्ति श्रिया
- (ii) कीन्स रोजगार मॉडल के निम्न तथा स्वतन्त्र चर ।

Write notes on —

- (i) Aggregate Demand Function and Aggregate Supply Function
- (ii) Dependent and Independent Variables of Keynesian Model of Employment

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्न प्रश्न सही सही तथा गलत है ।

- (i) उपभोग फलन उपभोग तथा आय के सम्बन्ध को बताता है ।
- (ii) वीन्स वा उल्लेखनीय योगदान उसको उपभोग दिया है ।
- (iii) औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) एक समयवर्धि में कुल आय के सम्बन्ध में कुल उपभोग की स्थिति को बताती है ।
- (iv) सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) आय की वृद्धि में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में उपभोग में होने वाली वृद्धि के परिवर्तनों की व्याख्या करती है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है (ii) गलत है (iii) सही है (iv) सही है ।

"Investment is the net addition to the existing stock of real capital assets"
 - *Dudley Dillard*

अध्याय 7

विनियोग क्रिया

(THE INVESTMENT FUNCTION)

विनियोग का अर्थ (Meaning of Investment)

निवेश का अर्थ इससे सामान्य अर्थ से अलग होता है। साधारण बोधनाम की भाषा में निवेश का अर्थ स्टॉक तथा अर्थात् ऋण-पत्रों गारवाणी प्रतिभूतियों तथा वाण्टो आदि के प्रय करने से होता है। परन्तु प्रो० कीन्स ने विनियोग का अर्थ कुछ व्यापक दृष्टिकोण में किया है। निवेश व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टियों में हो सकता है। निवेश दो प्रकार का होता है। (i) वित्तीय निवेश (Financial Investment) (ii) वास्तविक निवेश (Real Investment)। जब कोई व्यक्ति या फर्म कुछ स्टॉक तथा अन्य ऋणपत्र या सरकारी प्रतिभूतियाँ या वाण्ट ग्योदती है तो हम इसे वित्तीय निवेश कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति या फर्म इन अर्थात् ऋणपत्र, या वाण्टों को बेचती है तो दूसरा व्यक्ति या फर्म इन्हें खरीदती है। यह तो एक प्रकार में तो व्ययित में दूसरे व्यक्ति ग्यामि व वा हस्तांतरण होता है इसमें एक के द्वारा विनियोग या निवेश और दूसरे के द्वारा अविनियोग (Disinvestment) किया जाता है। इसमें राष्ट्र की वास्तविक पूँजी के स्टॉक में वृद्धि नहीं होती।

निवेश का अर्थ (Meaning of Investment)

प्रो० कीन्स ने वास्तविक विनियोग का अर्थ नये पूँजीगत पदार्थों के उत्पादन करने तथा खरीदने के लिए किया है अर्थात् नई फर्मों के अथ, कोष्ठन, ऋणपत्र तथा अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने से लिया है। इसका आशय वर्तमान स्टॉक में वास्तविक पूँजी पदार्थों में वृद्धि से लिया जाता है। वास्तविक विनियोग (Real Investment) की शर्त यह है कि हम नये विनियोग नये पूँजीगत पदार्थों (Capital Assets) में वृद्धि के साथ ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हों तथा अधिक कच्चे माल का उपयोग विभिन्न फर्मों द्वारा किया जाए। प्रो० कीन्स की विचारधारा में मिलती हुई विचारधारा प्रो० टडने रिगाडे ने विनियोगों के अर्थ के रूप में स्वीकार की है। वे कहते हैं कि "पूँजी पदार्थों के वास्तविक उपलब्ध स्टॉक में शुद्ध वृद्धि की विनियोग कहते हैं।"¹

प्रो० पीटरसन के शब्दों में—“निवेश खर्च में उत्पादन द्वारा टिकाऊ यंत्रों पर होने वाले व्यय तथा निर्माण कार्यों में होने वाले परिवर्तनों के व्यय शामिल होते हैं।”²

1. "Investment is the net addition to the existing stock of real capital assets."
 —*Dudley Dillard*

2. "Investment expenditure includes expenditure for 'producers' durable equipments new construction and the change in inventories"

—*Peterson*

नियोजित तथा अनियोजित निवेश (Intended and Unintended Investment)

विनियोग का अर्थ हमें उपलब्ध स्टॉक में केवल वृद्धि से ही नहीं लगाना चाहिए वरन् निमित्त वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादिक अन्य वस्तुओं की वृद्धि से भी लेना चाहिए। इस प्रकार विनियोगों का अर्थ पूँजीगत पदार्थों तथा नई माला (inventories) में वृद्धि दोनों से हो लगाना चाहिए। इस प्रकार inventories में वृद्धि नियोजित तथा अनियोजित दोनों ही तरह में हो सकती है। जानबूझकर (Intentional) उत्पादन क्षमता में वृद्धि दो कारणों से हो सकती है जैसे विप्रे में वृद्धि तथा अग्रिम में वीमता के बढ़ने की आशा के द्वारा। बिना सोचे विनियोग या अनियोजित विनियोग उस समय होता है जब बाजार की भावी अनिश्चितताओं तथा स्थितियों के कारण बिना विनियोग वस्तुओं का मध्य हो जाता है। यदि एक व्यापारी जिसने पास 5 लाख रुपये का स्टॉक है और वह उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर लेता है तो इसका आशय यह है कि उसने अपना वास्तविक विनियोग बढ़ाकर दुगुना कर लिया है और उसने वस्तुओं की नई माँग अधिक धमिकों को रोजगार तथा अन्य उत्पादक साधनों को लगाकर पैदा कर ली है। कर्नन के अनियोजित तथा अनियोजित विनियोग को कोई खास महत्व नहीं दिया है।

निवेश का महत्व (Importance of Investment)

प्रो० वीन्स ने रोजगार सिद्धान्त तथा प्रभावपूर्ण माँग के सिद्धान्त में अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति को स्थिर माना है। इसलिए आय उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण में विनियोगों का महत्व बहुत अधिक है। आय की मात्रा तथा उपभोग की मात्रा के बीच अन्तर को पाटने के लिये विनियोगों का होना जरूरी है। विनियोग उपभोग की अपेक्षा अधिक नीतिगत चर है और आय की मात्रा को निर्धारित करने में विनियोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम पहले ही यह देख चुके हैं कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय बढ़ता है परन्तु यह वृद्धि की दर आय की दर से कम होती है अर्थात् उपभोग इकाई से कम बढ़ता है। यदि हमें बड़ी हुई आय की दर को बनाए रखना है तो उसने लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक निवेश आय और उपभोग के बराबर उसी आय में से कर देना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि दिन-दिवस विनियोगों को बढ़ाये, आय में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। इस प्रकार प्रो० वीन्स ने विनियोगों को आय उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने मन्दीकाल में निम्नी विनियोगों की अपेक्षा सार्वाजनिक विनियोगों की बढ़ाने का सुझाव दिया है।

कुल तथा शुद्ध निवेश (Gross and Net Investment)

अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में जो कुछ वास्तविक निवेश होता है उसे कुल निवेश की संज्ञा दी जाती है परन्तु कुल निवेश का आशय कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि से नहीं लेना चाहिए। परन्तु इसका एक भाग ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है और शेष भाग घिसावट के व्यय, राज-भरजा के खर्च रखाव अथवा प्रतिस्थापन माँग का रूप ग्रहण कर लेता है। इसके विपरीत शुद्ध निवेश कुल निवेश का वह भाग होता है जो अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि का सूचक होता है।

कुल निवेश तथा शुद्ध निवेश का अन्तर स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए नार्थक हो सकता है। स्थिर अर्थव्यवस्था में शुद्ध निवेश की समस्या नहीं होती क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए राजिज नहीं रखा जाता परन्तु स्थिर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल पूँजी स्टॉक को स्थिर बनाए रखने की समस्या बनो रहती है क्योंकि पन्ना तथा राज-भरजा को टूट-पूट तथा घिसावट के कारण पूँजीगत पदार्थों की मात्रा में कमी

आ जाती है। इस कर्म को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष कुछ न कुछ कुछ वास्तविक निवेश आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में कुछ निवेश अन्य होता है।

निवेश के प्रकार (Types of Investment)

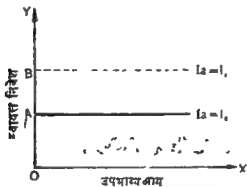
विनियोगों की एक विशेषता यह है कि इसके विभिन्न रूप होते हैं। विनियोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों स्वायत्त मन्त्रालयों विभिन्न फर्मों ध्यनित्या निजी मन्त्रालयों आदि द्वारा हो सकते हैं। विनियोग ध्यय प्लाट तथा मशीनों भवन निर्माण मावजनिक सेवाओं जैसे मठकों, पुलों, रेलवे, जहाज तथा वायुयानों के निर्माण आदि के लिए हो सकता है। सामान्यतः विनियोग दो प्रकार के होते हैं—(1) स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) तथा (2) प्रेरित निवेश (Induced Investment)।

(1) **स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment)**— स्वायत्त निवेश वह होता है जिसका सम्बन्ध आय तथा उत्पादन के स्तर में नहीं होता और लाभ प्राप्ति के उद्देश्य में नहीं किया जाता दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वायत्त निवेश समर्थ माँग (Effective Demand) में होने वाले परिवर्तनों में प्रभावित नहीं होता। स्वायत्त निवेश उत्पादन तकनीक प्रविष्टि, जनसंख्या के आकार, आविष्कार तथा सरकारों नीतियों या सुरक्षा आदि पर किया गया ध्यय कहलाता है। यह आय और लाभ निर्पन्न होता है अर्थात् आय तथा लाभ में परिवर्तनों द्वारा प्रभावित नहीं होता। मठक, अस्पताल अनुसन्धान तथा विकास पर किया गया ध्यय स्वायत्त निवेश के उदाहरण हैं। आय में परिवर्तन होते हुए भी स्वायत्त निवेश स्थिर रह सकता है और आय स्थिर रहते हुए स्वायत्त निवेश परिवर्तित हो सकता है।

स्वायत्त निवेश— $(I_A) = I_1$

I_A = स्वायत्त निवेश

I_1 = स्थिर निवेश



उपर्युक्त रेखाचित्र में स्वायत्त निवेश तथा उपभोग्य आय को दर्शाया गया है। चूँकि स्वायत्त निवेश आय में परिवर्तनों के कारण नहीं होते हैं इसलिए इसे X अक्ष के समानान्तर खींचा गया है। $I_A = I_1$ तथा $I_A = I_2$ वक्रों में ज्ञात होता है कि उपभोग्य आय चाहे जो कुछ भी हो स्वायत्त निवेश में परिवर्तन नहीं होते। यह स्थिति OA तथा OB किमी भी वक्र द्वारा दिखाई जा सकती है।

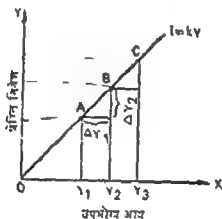
(2) **प्रेरित निवेश (Induced Investment)**— अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश की मात्रा आय तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होती है। निजी क्षेत्र में माहमी या अन्य कोई फर्म उनी समय पूँजीगत का जय अथवा उत्पादन उस समय करेगी जब उसे अपनी वस्तुओं की माँव में माँव बनी रहने की आशा हो। उपभोग वस्तुओं की माँव की

स्वित्त भविष्य में क्या होगा यह उपभोक्ताओं को उपभोग्य आय द्वारा तय होगी और उपभोग्य आय स्वयं आय के स्तर तथा व्यनियोग करो की मात्रा द्वारा तय होने हैं और औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) पर निर्भर होती है। APC के स्थिर रहने हुए आय में वृद्धि होने पर कुल समर्थ माँग में भी स्थिर दर पर वृद्धि होती है। इस प्रकार आय में वृद्धि होने पर समर्थ माँग गिर जाती है। इन प्रकार प्रेरित निवेश आय सापेक्ष (Income elastic) होता है। अन्यथा मूल्य उतारान अनुपात स्थिर होने के कारण आय तथा प्रेरित निवेश के मध्य आनुपातिक सम्बन्ध होता है। प्रेरित निवेश आय में परिवर्तन द्वारा प्रभावित होता है क्योंकि कुल समर्थ माँग में वृद्धि आय में वृद्धि का परिणाम होती है।

प्रेरित निवेश की आय सापेक्षता घनात्मक होती है। प्रेरित निवेश की आय सापेक्षता शून्य तथा अनन्त के मध्य होती तथा यह सामान्य उपभोग प्रवृत्ति तथा मूल्य उतारान अनुपात द्वारा निर्धारित होती अर्थात् प्रेरित निवेश की आय में परिवर्तन के सम्बन्ध में न तो पूर्णतया आय सापेक्ष होगा तथा न ही पूर्णतया आय निरपेक्ष। उपभोग्य आय में परि-

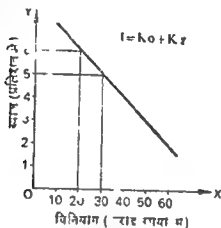
वर्तन द्वारा प्रेरित निवेश में उत्पन्न परिवर्तन घनात्मक होगा अर्थात् $\frac{dIP}{dY} = dIP = \text{प्रेरित}$

निवेश dY उपभोग्य आय में परिवर्तन। इसी बात को निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है



$$I = K_0 + K_1 r \text{ तथा } K_1 > 0$$

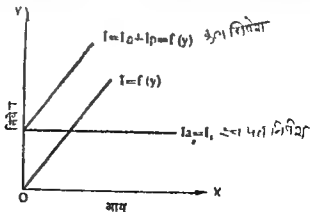
प्रस्तुत रखाचित्र म स्पष्ट है कि जब व्याज की दर 6% से गिरकर 5% रह जाती है तो निवेश राशि भी 20 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रुपय हो जाती है। जैम-जैसे व्याज की दर गिरती जाएगी वैसे वैसे प्रेरित निवेश बढ़ता जाएगा।



प्रेरित निवेश आय के स्तर आय में परिवर्तन की दर, औसत जमा भाग प्रवृत्ति, धन हस्तादि आन्तरिक कारण, में प्रभावित होता है जहाँ सराफत निवेश आविष्कारों नयी प्रविद्याओं, जलमयों वृद्धि बुद्ध अन्तर्गत व्यापार भ्रम आन्दोलन, विज्ञान योजनाओं ऋतुओं आदि में परिवर्तन द्वारा प्रभावित होता है। स्वायत्त निवेश का विचार नियोजित तथा बुद्ध अवव्यवस्थाओं में लागू होता है जहाँ निवेश लाभ के विचार से प्रभावित नहीं होता बरन् अन्य कारणों द्वारा लागू होता है।

एक अवव्यवस्था में कुल निवेश बराबर प्रेरित + स्वायत्त निवेश। वास्तविक कुल निवेश का कुछ भाग निजा क्षेत्र में व्यक्ति निवेश तथा कुछ भाग गावजनिक क्षेत्र में सरकारी निवेश का रूप में होता है। अवव्यवस्था में कुल निवेश का गणना करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों तथा सरकार द्वारा विदेशों में किए गए निवेश का गणना करना अनिवार्य होता है। इन प्रकार वि. शिखा द्वारा दिए निवेश का कुल निवेश में से घटा देना चाहिए।

कुल निवेश अर्थात् प्राप्ति $I = I_0 + I_1$ स्वायत्त निवेश का हम निम्नांकित रखाचित्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं



स्तुत वाचित्र म OY अक्ष पर कुल निवेश (प्रति-स्वायत्त निवेश) तथा OX अक्ष पर उपभोग्य आय दिखाई गई है। $I_0 = f(y)$ वक्र प्रति निवेश तथा $I_1 = I_2$ वक्र स्वायत्त निवेश को व्यक्त करते हैं। $I_1 + I_2$ वक्र कुल निवेश माप को व्यक्त करता है। कुल निवेश $I_1 + I_2$ यह व्यक्त करता है कि कुल निवेश कुल उपभोग्य आय से इस प्रकार सधना मक रूप से सम्बाधित होता है कि कुल उपभोग्य आय में वृद्धि या कमी होने में कुल निवेश में वृद्धि या कमी होती है इसका अर्थ यह है कि उपभोग्य आय में परिवर्तन

तथा कुल निवेश में परिवर्तन का अनुपात धनात्मक होता है अर्थात् $\frac{dI}{dY} > 0$

निवेश को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors Determining the Investment)

अवश्यकता में निवेश प्रति कुल निवेश प्रमुख रूप से दो तत्व निर्धारित करते हैं—(1) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता या कुशलता (Marginal Efficiency of Capital) (2) ब्याज की दर (Rate of Interest)। अब कभी एक कम विनियोग करने का विचार करती है तो या तो इसमें उसे विस्तार महायता कहा से उधार लेना होगा या फिर उस अपने मापनों से बच करना होगा। पहली स्थिति में उसे ब्याज देना होगा जबकि दूसरी स्थिति में उसे धनराशि पर मित्र बनना ब्याज की राशि का त्याग करना होगा। विनियोग लाभ को प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं। एक साहसी विनियोग करने समय पूँजी की सीमान्त क्षमता तथा ब्याज का दर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है जब तक ब्याज की दर या पूँजी की सीमान्त क्षमता अचर रहेगी तब तक विनियोग होते रहेगे अर्थात् साहसी को लाभ मिलेगा।

ब्याज प्रति अवधारण में निवेश इसी दाना शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है परन्तु इन दोनों शक्तियों का निवेश में मात्रा पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों में से पूँजी की सीमान्त क्षमता कुल निवेश को ब्याज का दर की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। ब्याज का दर में जल्दा-जल्दी परिवर्तन नही होने। निवेशों को प्रेरणा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा अधिक मिलती है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC) स्थिर रहते हुए ब्याज की दर में थोड़ी सी गिरावट से कुल निवेश बढ़ने में क्योंकि बका तथा ऋण पदान बनाना संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना संभव हो जाता है। इसके विपरीत ब्याज का दर में वृद्धि हान में उत्पादन लागत में वृद्धि अर्थात् विनियोगों की लागत महंगा हो जाना है और लाभ — माजिन कम हो जाना है और माहिरियों के लिए विनियोगों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं रहता।

प्रतिष्ठित अवधारणा का मत था कि निवेश ब्याज सापेक्ष होता है जबकि प्रो० का ने अपना पुस्तक (General Theory) में यह बताया है कि निवेश इतना ब्याज सापेक्ष नहीं होता जसाकि प्रतिष्ठित अवधारणा समझते थे। प्रो० कोन्स ने कहा कि निवेश ब्याज की अपेक्षा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में अचरता तब तक अस्थिरता तथा चिरव्यवस्थित गतिहीनता का प्रवृत्ति पाई जाती है।

प्रो० कोन्स का कहना है कि मन्त्रालय में निवेश हेतु ब्याज की सापेक्षता बहुत कम होती है तथा धनात्मक ब्याज की दर पर अव्यवस्था में वृद्धि तथा निवेश के बीच पूर्ण रोजगार का स्तर पर में तुलना स्थापित नहीं हो सकता। कोन्स का विश्वास था कि अव्यवस्था में ब्याज का दर (प्रामाण्य) 2% से नीचे नहीं गिरना क्योंकि इस मूल्य में

दर पर लागू द्वारा असीमित मात्रा में मुद्रा की माँग व वारण नक़्दा अधिमान वक्र (Liquidity Preference Curve) पूँजतया व्याज स पक्ष हा जाना है। व्याज की इस दर पर निवेशकर्ता अपन सम्पत्ति का सरवरी प्रतिभूतिया या वाण्डा में न करव नवदी व रूप में रखना अधव पसंद करव। व्याज की इस यूनतम दर पर पूँज रागार वचत (Full Employment Saving) पूँज राजगार निवण (Full Employment Investment) का तुलना में अधिक हाग। और इस दरार का जब तक अतिरक्त निवण अथवा अतिरिक्त उपभाग द्वारा नही पाटा जाएगा तब तक अव्यवस्था में पूँज राजगार का प्राप्त करना कठिन हागा।

जहाँ तक उपभाग में वृद्धि का सवाल है यह आय का मात्रा तथा आय उपभाग प्रवृत्ति द्वारा निर्धारत होता है। यद्यपि निधना व पारि आय का पुनर्वितरण करव उप भाग में कुछ वृद्धि की जा सकत है परंतु पजीवाला अवस्थवस्था में इसका कुछ समाए हागो है। पूँज राजगार प्राप्त व निऐ कोम्म का विचार है कि व्यय बढाए जाए अर्थात् नाव वयाणाय याजनाओं का चालू किया जाए।

दूसरा प्रमुख शक्ति आ निवण का प्रभावित करता है वह पूँजी का सीमान क्षमता (MEC) कहलाती है पूँजी का सीमान क्षमता पूँजी परिमम्पत्ति का वनमान लागत (वृत्ति मूल्य) तथा माहमियों व पूँजी परिमम्पत्ति में व वष्य में हानि वान लाभ का आताओ पर निर्भर करता है। एक माहम का नाम सम्प्राप्ति आसशाए (Expectations) अल्प कालान तथा दापकालान दाना प्रकार का हा सकती है अपकालान आसशाए साहमी तथा व्यापारिया का वनमान पूँजी स निवण आबिष्य में हानि वामा आय हाता है। अल्प कालीन आसशाए = पकालीन आसशाओ की तुलना में अधिक स्थिर हाता है इसका प्रमुख कारण यह है कि पकालीन आसशाओ अधिक अनिश्चित हाता है अपकालान आसशाए मुख्य नाव माँग वतन तथा व्याज का दर आदि आन्तरिक कारणों द्वारा प्रभावित हाता है। दीर्घकालीन आसशाओ युद्ध जनसमय वृद्धि अनुम धान एव आबिष्यकार नवीन प्रक्रिया विज्ञा व्यपार अन्तराष्ट्रीय राजनातिक तथा आर्थिक स्थितिया प्रकृतता तथा विद्वान कार्यो आदि अनेक बाह्य कारणों द्वारा प्रभावित हाता है

माहमी उम समय तब निवण करग जब तक व यह आशा करे कि उह निवण लाभप्रद हागा। यह स्थिति का पति करन व निऐ निम्नलिखित समीकरण दिया जा सकता है।

$$\frac{dR}{dI} > \frac{dC}{dI}$$

अथवा
$$\frac{dR}{dI} - \frac{dC}{dI} > 0$$

dR = आय में परिवर्तन dI = विनियोग में परिवर्तन

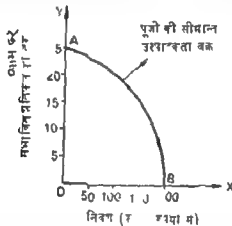
dC = वृत्त नागत में परिवर्तन।

उपयुक्त समीकरण में हम इस निष्पत्ति पर पहुँचत है कि जब फर्म के निवण में परिवर्तन (dI) हान के लिए आय में परिवर्तन (dR) फर्म के निवण में परिवर्तन हेतु उमकी वृत्त नागत में परिवर्तन (dC) का तुलना में अधिक हाता है ता विनियोग हात है अवस्था नहा।

फर्म का दृष्टि में अनिर्दिष्ट पूँजागत परिमम्पत्ति का नागत मनान का कामत हाता है तथा फर्म दगता नवता उम मशीन में प्राप्त हानि वानी आय में करगी। इनके माध ही

फर्म उस व्यय को भा शामिल करगी जो उस मशीन तथा अन्य उत्पादन मज्जा का खरीदन के लिए वित्त य सत्वादा तथा बना से प्राप्त ऋणा पर व्यय के रूप में करना पड़ता है। एक फर्म निवेश करते समय उन विशेष बट्टा दर को ज्ञात करने का प्रयत्न करेगा जिस पर ऋण प्राप्त करने में मशीन तथा अन्य उत्पादन मज्जा की वर्तमान लागत उस मज्जा द्वारा विभज्य वर्षों में प्राप्त हानि वाली कुल आय के समान होगा। यह बट्टा दर वर्तमान व्यय को दर से अधिक होता फर्म निवेश योजना का वायान्वित करके निवेश करेगा अन्यथा नहीं।

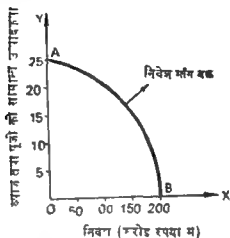
क्रिया का हुई समयवर्ष में एक फर्म के सामने कई ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जिससे फर्म को भिन्न आय दर प्राप्त होती है। अधिक लाभ का दर की अपेक्षा कम लाभ के अवसर अधिक होते हैं। जैसे जहाँ निवेश के माप में वृद्धि होता है वस वैसे लाभ की दर भी कम होती जाता है। इस स्थिति का निम्न रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है।



प्रस्तुत रेखाचित्र में AB वक्र पूजा सामान्त उत्पादकता वक्र है। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु असंशित लाभ दर तथा इस लाभ दर पर किए जाने वाले अधिकतम निवेश की माप का सूचित करता है। पूजा की सीमान्त उत्पादकता का ऋणामक दाता यह व्यक्त करता है कि निवेश का मात्रा तथा लाभ की दर के मध्य इस प्रकार का परस्पर सम्बन्ध है कि निवेश की माप में वृद्धि होने पर लाभ का दर कम हो जाता है। ऐसा प्रायः दो कारणों से हो सकता है (1) क्रिया में उद्योग में निवेश में वृद्धि हो जाने से लाभ की दर में कमी हो जाती है। (2) निवेश में वृद्धि होने से पूजा का सामान्त उत्पादकता (MEC) गिरता है। यदि इराइया की पूर्ति में वृद्धि होने से उनका लागत में वृद्धि हो जाता है क्योंकि उत्पादन योजना तथा कच्चे माल का माँग में वृद्धि से इनकी कीमतें बढ़ जाती है।

हम जब पूजा का सामान्त उत्पादकता पात होते हुए भी व्यय का दर पाते हैं तो उस अधिकतम निवेश मात्रा का ज्ञात किया जा सकता है जिस व्ययमात्र पर वाय रुप में परिणत करेगा क्योंकि निवेश उन माप तक होना जहाँ MEC - Marginal Rate of Interest इस भी अग्रान्वित र्गान्वित द्वारा दिखाया जा सकता है जो उपयुक्त र्गान्वित का भीति है।

प्रस्तुत रेखाचित्र में AB निवेश वक्र है। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु निवेश की उस अधिकतम मात्रा को दर्शाता है जिसमें माहंगी भिन्न भिन्न व्याज दरों पर प्रियाजित करण।



परीक्षा प्रश्न

1. स्वायत्त निवेश का क्या अर्थ है? इस निवेश के अन्तर्गत किम प्रकार के निवेश आते हैं? इस निवेश का आर्थिक महत्व क्या है?

(What is meant by autonomous investment? What kind of investment fall under this category? What is the economic significance of this kind of investment?)

2. प्रारत निवेश में आप क्या समझते हैं? पूँजीवादी अधव्यवस्था में उन तत्वों का बतलाया जा प्ररित निवेश का गामित करते हैं।

(What is meant by induced investment? Discuss those factors which govern the induced investment in a capitalist economy.)

3. विनियोग शिवा में आप क्या समझते हैं? उन तत्वों का व्याख्या काजिए जा विनियोग का प्रभावित करते हैं।

(What do you understand by investment function? Discuss those factors which determine the investment.)

4. टिप्पणी लिखिए—

(अ) कुल तथा शुद्ध निवेश (ब) स्वायत्त तथा प्ररित निवेश (ग) नियोजित तथा अनियोजित निवेश (द) निवेश का निर्धारित करने वाले कारण।

Write notes on —

(a) Gross and Net Investment (b) Autonomous and Induced Investment (c) Intended and unintended Investment (d) Factors Determining the Investment

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही है और कौन गलत है।

- (i) पूजा पदार्थों के वास्तविक उपनयन स्टाक में शुद्ध वृद्धि को विनियोग कहते हैं।
- (ii) स्वायत्त निवेश समय माँग में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होता है।
- (iii) प्ररित निवेश की मात्रा आय तथा इसमें होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होती है।
- (iv) काल के अनुसार निवेश ब्याज की अपेक्षा पूजा का मामूली उत्पादकता द्वारा अधिक प्रभावित होता है।
- (v) पूजा की सीमान्त उत्पादकता में अल्पकालीन तथा चिरकालीन गतिहीनता की प्रवृत्ति पाई जाती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) गलत है। (iii) सही है। (iv) सही है। (v) सही है।

Marginal efficiency of capital is the ratio between the prospective yield of additional capital goods and their supply price "
 Kurihara

अध्याय 8

पूँजी की सीमान्त क्षमता

(MARGINAL EFFICIENCY OF CAPITAL)

पूँजी का सीमान्त क्षमता अथवा उत्पादकता कीमवादा अवधारण में जाय उत्पादन तथा राजपार के स्तर का प्रमुख निर्धारक तत्व है। एक उत्पादकता या फल के लिए पूँजी की सीमान्त उत्पादकता का विषय महत्व है। एक उत्पादक या फल पूँजी विनियोजन करने में पहले पूँजी में प्राप्त प्रतिफल अथवा पूँजी की सीमान्त उत्पादक तथा पूँजी पूर्ति की लागत अथवा व्यय की तुलना करना है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता माहमी की मनावैज्ञानिक विचारधारा द्वारा तय होता है जिसके बारे में माहमी केवल अनुमान ही लगाता है। पूँजी की सीमान्त क्षमता या उत्पादकता उस सम्भावित लाभ की दर होती है जिसका सम्बन्ध वर्तमान में लाभ की दर में नही होता और जिसमें अन्वय में अधिक उच्चावचन दखन का मिनत है।

परिभाषा— विभिन्न विद्वानों द्वारा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की परिभाषाएँ इस प्रकार दी गई हैं—

प्रो० के० कुरीहारा के अनुसार पूँजी की सीमान्त उत्पादकता अतिरिक्त पूँजीगत पदार्थों की अनुमानित तथा उनकी पूर्ति कीमत के मध्य अनुपात का बताती है।¹

प्रो० हिलार्ड के अनुसार किन्हीं विषय पूँजी परिमर्पण की अतिरिक्त इकाई लागत पर आय की जो अधिकतम दर प्राप्त होती है उस पूँजी की सीमान्त उत्पादकता कहा जाता है।²

- 1 Marginal efficiency of capital is the ratio between the prospective yield of additional capital goods and their supply price

—Kurihara

- 2 The marginal efficiency of a particular type of capital asset is the highest rate of return over cost expected from an additional unit of that type of asset

—Dudley Dillard

प्रो० स्टोनिशर तथा हेग के शब्दों में किसी विशेष प्रकार के पूँजीगत पदार्थ की सीमान्त उत्पादकता इस बात को व्यक्त करती है कि एक माहिर एक अनिश्चित पूँजी पर निम्नलिखित लगाकर इससे उस पर व्यय किए गए धन की तुलना में कितनी आय प्राप्ति की आशा रखता है।¹

पूँजी की सीमान्त क्षमता एक पूँजी पदार्थ की उस बढ़ता दर को कहते हैं जिस पर एक पदार्थ की भावी प्राप्ति (Prospective Yield) का वृद्धा इतना होता है कि उस पदार्थ की पूर्ति कीमत में बराबर हो जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि प्रत्याशित वार्षिक प्राप्ति (Qs) का मूल्य का अनुमान तथा उसकी लागत का पता चल जाए तो इन दोनों का अनुपात अथवा दर को पूँजी की सीमान्त क्षमता कहा जाएगा। प्रो० कीस ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूँजी की सीमान्त क्षमता की परिभाषा इस प्रकार दी है। कीस के शब्दों में पूँजी की सीमान्त क्षमता वृद्धा दर को बराबर होती है जो पूँजी पर निम्नलिखित जीवन काल में प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक प्रतिफल की मात्रा के वर्तमान मूल्य को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर दे।²

प्रो० कीस की परिभाषा को एक समीकरण द्वारा भी दिखाया जा सकता है—

पूर्ण कीमत = बढ़ती की गई भावी प्राप्ति

Supply Price = Discounted Prospective Yields

$$\text{अथवा Cr or Sp} = \frac{Q_1}{1+r} + \frac{Q_2}{(1+r)^2} + \frac{Q_3}{(1+r)^3} + \frac{Q_n}{(1+r)^n}$$

Cr अथवा Sp = पूँजी पर निम्नलिखित की पूर्ति कीमत अथवा पुनः स्थापन लागत (Cost of replacement)

Q_1, Q_2, Q_3, Q_n - प्रत्याशित वार्षिक प्राप्ति (Prospective yields in various years)

r = वह बढ्ता दर है जो वार्षिक प्राप्ति को वर्तमान मूल्य को पूँजी पर निम्नलिखित की पूर्ति कीमत के बराबर बना देता है।

व्यवहार में एक पूँजी पदार्थ के जीवन काल में तथा उससे प्राप्त होने वाली सम्भावित प्राप्ति का अनुमान लगाना कठिन होता है। परन्तु इस प्रकार के अनुमान लगाने के अलावा कोई ऐसा मापदण्ड नहीं है जो एक पूँजी पदार्थ के जीवनकाल और उससे प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगा सके। इतना ही नहीं उपयुक्त समीकरण में Q_s के मूल्य का अनुमान हम गतिशील समाज में नहीं लगा सकते जिनमें हम रहते हैं।

पूँजी की सीमान्त क्षमता पूँजी पूर्ति की कीमत तथा पूँजी पदार्थ से प्राप्त भावी प्राप्ति (Prospective Yields of Assets) द्वारा निर्धारित होती है जबकि समाज की दर

1 The marginal efficiency of a particular type of asset shows that an entrepreneur expects to earn from one more asset of that kind compared with what he has to pay to buy it — *Stoner and Hague*

2 Marginal efficiency of capital as being equal to the rate of discount which would make the present value of the series of annuities given by the return expected from the capital asset during its life just equal to its supply price — *J M Keynes*

नयदी अधिमान अनुसूची तथा चलन में मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। निवेशों की मात्रा में परिवर्तन पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं परन्तु व्याज की दर को प्रभावित नहीं करते। पूँजी की सीमान्त क्षमता तथा व्याज की दर दोनों को बराबर नान में निवेशों की मात्रा में परिवर्तन जरूरी होते हैं।

एक समस्यावधि में विभिन्न निवेशों पर पूँजी की सीमान्त क्षमता भी अलग-अलग होती है। हमें जिसकी सीमान्त क्षमता सबसे अधिक होगी यदि अनिश्चित विनियोग उग पर किया जाय तो वह अर्थव्यवस्था की दृष्टि में वही विनियोग सबसे अधिक लाभप्रद समझा जाएगा। इसलिए यदि हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में विनियोगों में वृद्धि करना है तो हमें ऐसी पूँजी परिस्थितियों की मात्रा को बढ़ाना होगा जो अधिकतम क्षमता प्रदान कर सकें। प्रो० बीन्स ने पूँजी की सीमान्त क्षमता को पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में जलग माना है। उनसे अनुसार पूँजी की सीमान्त उत्पादकता पूँजी की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में वृत्त प्राप्ति में होने वाली वृद्धि होती है। इससे विपरीत पूँजी की सीमान्त क्षमता कटौती में वह दर होती है जो पूँजी परिस्थिति में प्राप्त होने वाली वृत्त सीमान्त आय को इसकी पुन स्थापना लागत (Replacement Cost) के बराबर कर देती है। सीमान्त क्षमता का सम्बन्ध वर्तमान वार्षिक लाभ से नहीं बरन् प्रत्याशित भावी प्राप्ति (Expected Prospective Yields) की विनियोग प्रेरणा में रूप में देखा चाहिए।

विनियोग माँग अनुसूची—विनियोग माँग अनुसूची एक समस्यावधि में विभिन्न विनियोग स्तरों पर पूँजी पैदाय के विभिन्न सीमान्त क्षमताओं को बताती है। इस अनुसूची के आधार पर जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे विनियोग माँग वस्तु कहते हैं। यह वस्तु बायें हाथ से दाहिने हाथ नीचे की ओर गिरता हुआ होता है जो बताता है कि जैसा-जैसे विनियोग की मात्रा में वृद्धि होगी जानी है वैसे-वैसे पूँजी की सीमान्त क्षमता में कमी होती जाती है। प्रो० बीन्स कहते हैं कि एक प्रकार की पूँजी परिस्थिति (मणीन) में किसी समय विनियोग की मात्रा में वृद्धि के साथ पूँजी की सीमान्त क्षमता में गिरावट आती है ऐसा सम्भव दो कारणों से होता है—(1) जैसे ही उग सम्पत्ति की पूर्ति बढ़ेगी उसमें भावी प्राप्ति गिरेगी, (2) ऐसी सम्पत्ति की उत्पत्ति की सुविधाओं पर अधिक दबाव बढ़ने में इनकी पूर्ति कीमत भी बढ़ेगी।

विनियोग माँग अनुसूची (Investment Demand Schedule)

विनियोग करोड़ रुपयों में	पूँजी की सीमान्त क्षमता का वार्षिक प्रतिशत
100	15
200	12
300	10
400	8
500	5

विनियोग माँग सूची रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह व्याज की दर में परिवर्तन होने में विनियोग की मात्रा या राशि परिवर्तन को व्यक्त करती है। हालांकि प्रो० बीन्स ने व्याज की दर को विनियोग की मात्रा में घटाना माना है जबकि पूँजी की सीमान्त क्षमता विनियोग की मात्रा का फलन होती है अर्थात् $MEC = f(I)$ । जितनी पूँजी की सीमान्त क्षमता में लोच जितनी अधिक होगी, व्याज की गिरती हुई दर पर उतना ही विनियोग की मात्रा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार जितनी पूँजी की सीमान्त क्षमता में लोच कम होगी उतनी ही कम विनियोगों में वृद्धि एक

गिरती हुई ब्याज की दर पर होंगी। विनियोग माँग अनुसूची की स्थिति जीर उभरा स्वरूप विभिन्न जटिल कारणों पर निर्भर करेगी जो कि प्रत्येक साहसी के अरने-अपने अलग अनुमानों तथा पुनरीक्षण द्वारा शासित होंगे। एक उद्योग निवेश या एक सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की विनियोग माँग सूची का निर्माण करना कठिन होता है। MEC की माँग अनुसूची कम लोचपूर्ण होती है न कि अधिक लोचपूर्ण। ब्याज की दर में परिवर्तन नये विनियोगों को अधिक प्रभावित नहीं कर पाते बल्कि विनाश या वृद्धि तथा तबनीकी गति में सम्मन्वित तत्व विनियोगों की मात्रा को ब्याज की दर की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं।

पूँजी की सीमान्त क्षमता को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों तत्व प्रभावित करते रहते हैं—

(I) पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले अल्पकालीन तत्व

1. उपभोग प्रवृत्ति—अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर जाने की प्रवृत्ति होती है इसलिए इसका पूँजी की सीमान्त क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ने से आशिय रूप से पूँजीगत वस्तुओं की माँग बढ़ती है।

2. माँग, लागत तथा कीमतों का स्वभाव—यदि लागतों के बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहती है तो एक उत्पादक को विनियोगों से प्राप्त होने वाली प्रतिफल की दर में गिरावट आएगी और पूँजी की सीमान्त क्षमता गिरेगी। भविष्य में कीमतों तथा माँग के गिरने की प्रवृत्ति से भी पूँजी की सीमान्त क्षमता में गिरावट आती है। इससे विपरीत लागतों में गिरावट, कीमतों तथा माँग में वृद्धि की आशा होने पर पूँजी की सीमान्त क्षमता बढ़ेगी।

3. आय में परिवर्तन—पूँजी की सीमान्त क्षमता आय में अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती है। आय में परिवर्तन लाभ तथा हानि में अज्ञप्त्याशिन परिवर्तन, बरों में छूट आदि द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। आय में वृद्धि से पूँजी की सीमान्त क्षमता बढ़ेगी और आय में गिरावट होने से MEC गिरेगी।

4. नकद सम्पत्तियों में परिवर्तन—यदि एक साहसी के पास नकद सम्पत्तियाँ अधिक हैं तो विनियोगों से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए जब कभी भी उसे अच्छे अवसर दिखाई देंगे तो वह इनका लाभ उठाएगा और MEC बढ़ेगी इसके विपरीत यदि उसके पास नकद सम्पत्तियाँ (Liquid Assets) नहीं हैं तो वह लाभपूर्ण पूँजी विनियोजनों के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकेगा।

5. वर्तमान प्रतिफल की दर—पूँजीपति पूँजी विनियोजन इस आशा से करते हैं कि उनके विनियोजन से प्राप्त प्रतिफल की दर अच्छी रहेगी और वर्तमान में तापू प्रतिफल की दर से कम नहीं होगी जिस पर कि विनियोग हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान प्रतिफल की दर पूँजी विनियोजन के लिए जरूरी होती है।

6. प्रत्याशाएँ—पूँजी की सीमान्त क्षमता एक साहसी या उत्पादक की प्रत्याशाओं पर भी निर्भर करती है और यह प्रत्याशाएँ आशावादी और निराशाजनक (Pessimistic and Optimistic) दोनों ही प्रकार की होती हैं। आशावादिता की स्थिति में पूँजी, विनियोजन से प्राप्त प्रतिफल को आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाया जाता है जिससे MEC बढ़ती है जबकि निराशावादिता की स्थिति में जरूरत से कम प्रतिफल प्राप्त होने की धारणा रहती है इसलिए MEC गिरती है।

(II) पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक तत्व

MEC को प्रभावित करने वाले प्रमुख दीर्घकालिक तत्व अप्रभावित बताए जा सकते हैं—

1. जनसंख्या का स्वरूप—जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे-वैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए विभिन्न मार्गजन्म सेवाओं, भवनों, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों आदि की माँग बढ़ती है और इनके लिए पूँजी विनियोजन बढ़ता है इसलिए MEC भी बढ़ती है क्योंकि इन सबका मित्रा-जुना प्रभाव सभी क्षेत्रों में माँग में वृद्धि के रूप में होता है।

2 उत्पादन विधियों को अपनाना—उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक विधियों विशेष रूप में पूँजी लगाने वाले क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लागत गिराने के प्रयास बने रहें, विनियोजन बढ़ता है और MEC बढ़ती है। वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में मेसिन, लोहा गैस बपडा ओटोमोबाइल (कार स्कुटर माटरसाइकिल) आदि के उद्योगों के क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति में इन क्षेत्रों में पूँजी विनियोजन का प्रदान में गहायता दी है।

3 पूँजी साधनों की पूर्ति—पूँजी साधनों की पूर्ति बनी रहने पर ही उत्पादन तकनीक बाजार के विस्तार जनसंख्या वृद्धि आदि की माँग को पूरा किया जा सकता है। यदि वर्तमान मशीनों तथा विभिन्न उत्पादन के प्लांटों की क्षमता में ही उपर्युक्त बढ़ती हुई माँग को पूरा किया जा सके तो पूँजी निवेश नहीं बढ़ेगा अन्यथा निवेश बढ़ेगा और MEC भी बढ़ेगी।

आशांताएँ तथा पूँजी की सीमान्त क्षमता (Expectations and Marginal Efficiency of Capital)

पूँजी की सीमान्त क्षमता के दो प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं—(1) पूर्ति कीमत अथवा लागत (2) भावी प्राप्ति या प्रतिफल (Prospective Yield or Return)। अप्रत्याश में पूर्ति कीमत या लागत स्थिर रहती है इसलिए MEC पर भावी प्राप्ति या प्रतिफल का प्रभाव अधिक होता है। भावी प्राप्ति या अनिश्चित होती है। भावी प्राप्ति या विनियोजक की आशमाओं पर निर्भर करती है। एक विनियोजक या पूँजी विनियोजन करने समय वर्तमान प्राप्ति अथवा आय की अपेक्षा भावी प्राप्ति अथवा आय को अधिक महत्त्व देता है।

एक माहमी के लिए भावी प्राप्ति या का सम्बन्ध अपने पूँजी पदार्थ के उत्पाद को बेचने में प्राप्त होने की आशा होती है। यह आशमाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं—(1) अल्पकालीन आशमाएँ, (2) दीर्घकालीन आशमाएँ। अल्पकालीन आशमाओं का सम्बन्ध एक माहमी को अपने कारखाने के प्लांट की उत्पादन क्षमता के अथवा उसकी मशीनों से होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्लांट की क्षमता को स्थिर मान लिया गया है। जबकि दीर्घकालीन आशमाओं का सम्बन्ध नए निवेशों में प्राप्त प्लांट की क्षमताओं में परिवर्तन अथवा नए प्लांट को स्थापित करने में किसी अथवा उत्पादन से होता है। इन दोनों आशमाओं को हम पृथक्-पृथक् रूप में निम्न प्रकार में रख सकते हैं—

1 अल्पकालीन आशमाएँ (Short-term Expectations)—दीर्घकालीन आशमाओं की अपेक्षा अल्पकालीन आशमाएँ अधिक स्थिर होती हैं क्योंकि यह वर्तमान तत्वों पर आधारित होती हैं। वर्तमान में बँते हुए समय की घटनाएँ आने वाले समय के लिए एक अच्छा और सुरक्षित मार्ग दर्शक हो सकती हैं। इन आशमाओं से तात्पर्य वर्तमान दृष्टियों के उत्पादन एवं विपरीत में होता है जिनके बारे में कुछ निश्चित अनुमान लगाए जाते हैं। अल्पकालीन आशमाओं में सनत् होने का गुण अधिक पाया जाता है क्योंकि बहुत सी स्थितियाँ जो वर्तमान उत्पादन को प्रभावित करती हैं, लगभग स्थिर रहती हैं। अल्पकालीन आशमाओं को पिछले अनुभवों के आधार पर नियन्त्रित किया जा सकता है। चूँकि अल्पकालीन आशमाएँ अधिक स्थिर होती हैं इसलिए यह विनियोजकों में उच्चतरचर्चों को व्यक्त करने में अगम्य होती है।

2 दीर्घकालीन आशाएँ (Long term Expectations)—दीर्घकालीन आशाएँ भावी प्राप्तिथी से सम्बन्धित होने के कारण, अल्पकालीन आशाओं की अपेक्षा पूर्णतया अनिश्चित होती है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था में कुल विनियोग तथा कुल रोजगार होने वाले उच्चावचनों को व्यक्त करने में यह अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि आने वाले चार वर्षों की आर्थिक क्रियाओं की क्षमता या प्रवृत्ति पिछले चार-पाँच वर्षों की आर्थिक क्रियाओं की भाँति होगी जहाँ हम अल्पकालीन आशाओं के माध्यम से अधिक निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसा कि विदित है कि दीर्घकाल में सभी तत्व परिवर्तनशील हो जाते हैं उदाहरणार्थ दीर्घकाल में एक कारखाने के स्वरूप उसने उत्पाद की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा सभी में परिवर्तन हो सकते हैं। एक फर्म या उत्पादन की इकाई में स्थापित मशीन तथा कारखाने के सम्भावित जीवनकाल, उसी कार्यशील रखने की लागत, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन उपभोक्ताओं की रुचियों, प्रभावपूर्ण माँग में परिवर्तन, मजदूरी स्तर निर्धारण की स्थिति प्रतियोगिता की स्थिति, सबटकालीन परिस्थितियों तथा भावी राजनैतिक तथा अन्य आर्थिक शक्तियाँ आदि ऐसी तत्व हैं जिनके बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं होता। दीर्घकाल में अनिश्चितताओं के कारण विनियोगकर्ता उन्ही तत्वों को देखते हैं जिनके बारे में वे अधिक आशावादी और विश्वस्त होते हैं। इसलिए दीर्घकालीन आशाएँ विनियोगकों के विश्वास द्वारा शासित होती हैं। भविष्य में विश्वास इतना अधिक निश्चित होगा विनियोग उतना ही अधिक और लाभपूर्ण मगना जायेगा। इसलिए विनियोगों में उच्चावचन, दीर्घकाल में साहसी के विश्वास पर निर्भर करते हैं। विनियोग में अधिकता के बाद निराशावादितता तथा मंदी की स्थिति आती है जिसमें टिकाऊ पदार्थों में विनियोग गिरते हैं।

पूँजी की सीमान्त क्षमता के विचार की आलोचना (Criticism of the Concept of Marginal Efficiency of Capital)

प्रो० कीन्स के पूँजी की सीमान्त क्षमता का विचार आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। प्रो० सालनियर तथा हैनलिट इस विचारधारा के प्रमुख आलोचक हैं—

(1) प्रो० सालनियर (Prof Saulnier) ने अपनी पुस्तक Contemporary Monetary Theory (1947) में कीन्स के इस विचार की आलोचना करने हुए कहा है कि MEC को विशेषणार्थक अध्ययन का तब तक एक अर्थ नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम वितरण के मिद्वान्त का पुरा स्वरूप और विभिन्न उत्पादक साधनों का अंशदान न मालूम हो।¹ वे आगे कहते हैं कि कीन्स ने पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की है और उन तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया है जो कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए जरूरी होते हैं। बाजार की वास्तविक स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता की होती है। कीन्स के विनियोग क्रिया के विश्लेषण को MEC तथा व्याज की दर से सम्बद्ध किया है क्योंकि उन्होंने मजदूरी को धर्म की सीमान्त उत्पादकता के बराबर माना है। यदि मजदूरी से सम्बन्धित इस मान्यता को हम छोड़ दें तो मजदूरी दर भी विनियोग क्रिया के मिद्वान्त का एक आवश्यक अंग बन जाती है।

(2) प्रो० सालनियर कहते हैं कि प्रो० कीन्स ने MEC के विचार को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में देखा है। उचित यह होता कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए MEC का विचार अलग-अलग होता है। इस तत्व का हमारी ज़रूरत अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की व्यवस्था में विशेष महत्व है।²

1 R J Saulnier "Contemporary, Monetary Theory" (1947) pp 340-41.

2 Ibid

(3) प्रो० गाननियर कहते हैं कि बी०म विष्लेषण इस बात का उत्तर देता है कि कुल विनियोग माँग अनुसूची का निर्धारण किस प्रकार होता है। यह इस बात को नहीं बताता कि पूँजी की उत्पादकता परिवर्तन कैसे होते हैं। पूँजी के अलावा अन्य माध्यमों के स्थिर रहने पर पूँजी की सीमान्त क्षमता (MEC) में कैसे परिवर्तन होगा। न ही इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि पूँजी तथा अन्य माध्यमों के परिवर्तनशील होने पर MEC में किस प्रकार परिवर्तन होगा।

प्रो० गाननियर कहते हैं कि बी०म विष्लेषण उन वस्तुओं तथा अवस्तुओं (Economics and Diseconomics) की व्याख्या नहीं करता जो कि विनियोग माँग अनुसूची की आकृति प्रभावित करती है। प्रो० गाननियर का कहना है कि बी०म विष्लेषण न ही पूरा है और न ही उन तथ्यों की संतोषजनक व्याख्या करता है जो पूँजी की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं।

(4) प्रो० हैज़लिट (Prof Hazlitt) कहते हैं कि बी०म ने MEC शब्द विभिन्न अर्थों में दिया है कि इससे सही अर्थ का ज्ञान यदि असम्भव न हो तो रटित अवश्य है। प्रो० बी०म ने MEC शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं बताया है। बी०म के समय MEC शब्द के साथ सीमान्त उत्पादकता और उपयोगिता आदि शब्दों के उपयोग का भी चलन था। परन्तु बी०म ने इन सब शब्दों में सबसे अधिक अस्पष्ट शब्द पूँजी की सीमान्त क्षमता (MEC) का उपयोग ही किया। यदि वे इनके स्थान पर अन्य किसी शब्द का उपयोग अपने विष्लेषण में करते तो यह काफी आलोचनाओं से बच सकते थे।

प्रो० बी०म ने ब्याज की दर के महत्व को अस्वीकार करत हुए कहा था कि पूँजी की सीमान्त क्षमता का महत्व हमारे जैसे प्राथमिक समाज में है जबकि ब्याज की दर की धारणा स्थिर समाज के लिए महत्वपूर्ण है। बी०म ने इस प्रकार ग़लतफ़हमी का कोई औचित्य नहीं है। इस मान्यता के मानने का जय यह होगा कि माहंगी केवल भावी प्रत्याशाओं (Expectations) द्वारा ही प्रभावित होते हैं जबकि श्रृंखला पूर्ति करने वाला धर्म किसी प्रत्याशाओं द्वारा प्रभावित नहीं होता। बी०म ने इससे निराश नहीं कहा है।

परीक्षा प्रश्न

1. पूँजी की सीमान्त क्षमता का क्या अर्थ है? रोज़गार के सिद्धान्त में इस विचार की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

(What is meant by marginal efficiency of capital? Examine the role of this concept in the theory of Employment)

2. उन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तथ्यों की व्याख्या कीजिए जो विनियोग की सीमान्त क्षमता अथवा पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करते हैं।

(Explain the short-run and long-run factors which affect the marginal efficiency of investment or the marginal efficiency of capital)

3. विनियोग माँग अनुसूची से आप क्या समझते हैं? पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले तथ्यों की व्याख्या कीजिए।

(What do you understand by Investment Demand Schedule? Discuss the factors that influence the marginal efficiency of capital)

में इस तरह का 1:2 का गुण (गुणा) यह अनुपात है जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और निनियोग में वृद्धि के परिमाणानुसार सम्बन्ध को बताता है जिसमें आय में वृद्धि होती है।

संयोजकता गुण भाषा में निनियोग $k = \frac{\Delta Y}{\Delta I} k = \text{गुणक}$

ΔY राष्ट्रीय में वृद्धि $\Delta I =$ निनियोग में वृद्धि।

उसी बात को गुण गुण भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में निनियोग 10 करोड़ रुपय का हुआ तो और उसमें राष्ट्रीय आय 50 करोड़ रुपय की

वृद्धि हो तो गुणा $50/10 = 5$ होगा। गुणक का सूत्र 5 गुना होगा अर्थात् $k = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$

or $k = \frac{50}{10} = 5$ । गुणक का सूत्र नीम्नान्त उपयोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नीम्नान्त

उपयोग प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume or MPS) का आधार पर गुणक को जान कर सकते हैं।

प्रो० कीन्स के बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने गुणक को अपने अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। इनमें प्रो० फ्रिट्ज मॅक्लप, गार्डनर एक्ली रिचार्ड गुडविन तथा प्रो० एच० एम्० जॉन्सन (Prof Fritz Machlup, Gardner Ackley Richard Goodwin and Prof H. L. S. Shale) आदि विद्वानों ने अपने-अपने तरीकों द्वारा गुणक सिद्धान्त में महत्वपूर्ण अनेक विचारधाराएँ समझाई हैं।

प्रो० वाहन की व्याख्या - प्रो० वाहन ने संयोजक गुणक का विचार दिया अर्थात् उन्होंने इस बात का जवाब देखा कि निनियोग में वृद्धि होने से संयोजक में कितनी गुना वृद्धि होती है। प्रो० वाहन ने संयोजक गुणक का विचार में प्रो० कीन्स ने आय गुणक का विचार प्राप्त किया अर्थात् प्रारम्भिक निम्न में आय में कितनी गुना वृद्धि होती है। प्रो० कीन्स ने (General Theory) में निम्न गुणक को k का नाम दिया है और इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं - "गुणक हमको बताता है कि जब कुल निवेदन की मात्रा में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आय में वृद्धि होती है जो कुल निम्न में हुई वृद्धि का k गुना होती है।" प्रो० वाहन ने संयोजक गुणक को k^1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि निम्न में ΔI का मात्रा में वृद्धि होती है और उसमें परिणामस्वरूप निम्न उपयोग में आधुनिक संयोजक की मात्रा में ΔN_2 की वृद्धि होती है तो कुल संयोजक की मात्रा में होने वाली वृद्धि ΔN आधुनिक संयोजक की मात्रा में हुई वृद्धि ΔN_2 का k गुना होगी अर्थात् $\Delta N = k^1 \Delta N_2$ ।

K तथा K^1 के मध्य परस्पर समानता होना जरूरी नहीं है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि निम्न उपयोग में कुल गुणक को केवल इस प्रकार के होंगे कि संयोजक वृद्धि तथा माँग वृद्धि के मध्य निम्न उपयोग के समान अनुपात होगा। निवेदन गुणक, जो निम्न में हुए आर्थिक परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप आय में हुए कुल परिवर्तन का

1. Let us call k the investment multiplier. It tells us that when there is increment of aggregate investment, income will increase by an amount which is k times of the increment of investment."

"General Theory" p. 115.

--Keynes

अनुपात है अर्थात् $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$, सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) से इस प्रकार से सम्बन्धित

होता है कि MPC जितनी अधिक ऊँची होगी गुणक k उतना ही अधिक ऊँचा होगा। यदि विपरीत MPC कम होने पर गुणक भी कम होगा।

गुणक (Multiplier)

गुणक प्रत्यक्ष रूप से सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) द्वारा निर्धारित होता है। सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति का उर्दीय मूल्य ज्ञान होने पर गुणक का उर्दीय मूल्य को बीजगणितीय भाषा में निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञान कर सकते हैं—

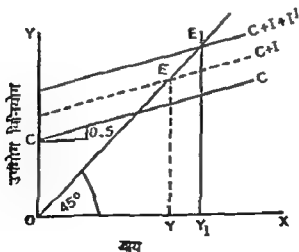
$$k = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} \quad \text{अथवा} \quad \frac{1}{1 - \text{MPC}}$$

चूँकि $\frac{\Delta C}{\Delta Y} \approx \text{MPC}$

उपरोक्त समीकरण के अध्ययन से ज्ञान होता है कि गुणक का उर्दीय मूल्य एक से अधिक MPC के उर्दीय मूल्य घटाने के बाद ज्ञान शेषफल का उल्टा होता है। उदाहरणार्थ यदि

MPC 0.8 है तो गुणक का उर्दीय मूल्य $\frac{1}{1-0.8}$ अथवा $\frac{1}{2} = 5$ होगा।

गुणक का आकार सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) द्वारा परिवर्तित होता रहता है। जितनी सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति ऊँची होगी गुणक उतना ही अधिक होगा। इसके गुणक का हम निम्न ग्राफिक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं—



इससे विपरीत MPC जितनी नीची होगी गुणक उतना ही कम होगा। निश्चय रूप से गुणक का मूल्य हमेशा एक से ज़्यादा (Infinite) कम हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से गुणक का

मूल्य एक से कम नहीं होगा क्योंकि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि जरूर होती है अर्थात् जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी उगरे उपभोग का स्तर पहले की अपेक्षा अधिक होगा जिसका आशय यह है कि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं होती है। व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति $1/3$ से $9/10$ की सीमा के भीतर ही रहती है इसलिए गुणक सामान्यतया 1.5 से 10 के बीच में ही रहता है। प्रो० जैन्ग ने गुणक का वास्तविक मूल्य लगभग 3 के बराबर बताया है जो व्यापार चक्र की भिन्न अवस्थाओं के साथ परिवर्तित होता रहता है। कीन्स कहते हैं कि गुणक बहुत अधिक नहीं होता इसलिए अव्यवस्था को मन्दी से उबारने के लिए वित्तियोग में थोड़ी सी घटि से काम नहीं लवेंगा।

उपरोक्त रेखाचित्र में CC उपभोग वक्र दिखाया है जबकि OY अक्ष पर उपभोग तथा विनियोग और OX अक्ष पर आय की मात्रा दिखाई गई है। गभी आय के स्तरों पर हमने MPC को 5 माना है। YL रेखा मन्तुलन आय स्तर को बताती है। बिन्ही कारणी से यदि विनियोग $C+I$ में बढ़कर $C+I+I'$ हो जाता है तब नया माय बिन्दु E_1 प्राप्त होता है अर्थात् E_1Y_1 रेखा नये मन्तुलन आय स्तर को बताती है जहाँ पुरानी आय के स्तर से अधिक है अर्थात् YY_1 मात्रा में अधिक है। यह YY_1 मात्रा $C+I$ तथा $C+I+I'$ के बीच की दूरी की दुगुनी है। इससे यह बात गामन आती है कि यदि कीमात उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है गुणक 2 होगा अर्थात् विनियोग में आरम्भिक वृद्धि जितनी होगी आय उसकी दुगुनी मात्रा में बढ़ेगी।

मुणव को हम सीमान्त वचत प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Save or MPS) द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। सीमान्त वचत प्रवृत्ति अतिरिक्त आय ΔY तथा अतिरिक्त उपभोग ΔC के अन्तर $\Delta Y - \Delta C$ तथा अतिरिक्त आय का अनुपात होती है। MPS को निम्न सूत्र द्वारा दिया सकते हैं—

$$\begin{aligned} \text{MPS} \left(\frac{\Delta S}{\Delta Y} \right) &= \frac{\Delta Y - \Delta C}{\Delta Y} \\ &= \frac{\Delta Y}{\Delta Y} - \frac{\Delta C}{\Delta Y} \\ &= 1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y} \end{aligned}$$

MPS द्वारा गुणक ज्ञात करने के लिए सामान्यतः यह सूत्र प्रयोग में लाया जाता है

$$k = \frac{1}{S} \text{ अथवा } k = \frac{1}{MPS} \text{ गुणक तथा सीमान्त बचत गवृत्ति (MPS) के बीच इस प्रकार}$$

य सम्वन्ध होता है कि यदि MPS ऊँची होगी तो कुणव कम होगा और MPS नीची होगी

तो गुणक अधिक होगा। उदाहरणार्थ यदि $MPS \frac{1}{S} = 0.2$ है तो गुणक 5 होगा। इससे

विपरीत यदि MPS $4/5$ है अर्थात् 0.8 है तो गुणक 1.25 होगा। इस प्रकार यदि विगत समय हमें सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) तथा सीमान्त प्रयास प्रवृत्ति (MPS) पता हो तो गुणक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।

उपभोग अघायन ग हम हम निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि गुणक का अक्षीय मूल्य

$1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}$ का अक्षीय मूल्य का उल्टा होता है। निम्नलिखित समीकरणों द्वारा यह सिद्ध

किया जा सकता है कि कुल वास्तविक आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल निवेश व्यय का योग होती है।

$$Y = C + I \quad \dots(1)$$

उपभोग तथा भीमान्त उपभोग प्रवृत्ति बताती है कि कुल उपभोग तथा कुल आय के मध्य स्थिर सम्बन्ध रहता है विशेषतः पर अल्पकालिक स्थितियों में। यह सम्बन्ध घनात्मक होता है अर्थात् आय में वृद्धि के साथ-साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है परन्तु यह इकाई से कम होता है अर्थात् जितनी मात्रा में आय बढ़ती है उतनी मात्रा में उपभोग नहीं बढ़ता उदाहरणार्थ यदि आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय 100 रुपये से कम होगा। MPC का C द्वारा व्यक्त करने पर कुल उपभोग तथा कुल आय द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

$$C = CY \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) में C के स्थान पर CY स्थान पर एक तथा समीकरण बताता है जो समीकरण नम्बर 3 कहलाता है—

$$Y = CY + I \quad (3)$$

$$Y - CY = I$$

$$Y(1 - C) = I$$

$$Y = \frac{I}{1 - C}$$

इसमें C का अक्षीय मूल्य एक से कम तथा शून्य से अधिक है।

अब हम यह मान लें कि कुल निवेश में ΔI की वृद्धि होती है तो दूसरे पक्ष-स्वरूप कुल आय में समान मात्रा में वृद्धि हो जायगी क्योंकि कुल निवेश आय के दो अर्थों में से एक है। हम नई कुल आय को हम Y_1 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं हमने लिए निम्न-लिखित समीकरण होगा—

$$Y_1 = CY_1 + I + \Delta I \quad \dots(4)$$

$$= \frac{I + \Delta I}{1 - C} \quad \dots(5)$$

यह ज्ञात करने के लिए कि कुल निवेश में ΔI राशि की वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप अर्थव्यवस्था में कुल आय में कुल कितनी वृद्धि हुई है हमको नई (अधिक) आय में से पुरानी (कम) आय को घटाना होगा। इसके लिए हम निम्न समीकरण द्वारा दिखाना सकते हैं—

$$Y_1 - Y = \Delta Y = \frac{I + \Delta I}{1 - C} - \frac{I}{1 - C} \quad \dots(6)$$

$$\Delta Y = \frac{1 + \Delta I - I}{1 - C} \quad (7)$$

$$= \frac{\Delta I}{1 - C} - \Delta I - \frac{1}{1 - C} \quad (8)$$

उपर्युक्त समीकरणों में यह निश्चित होता है कि कुल आय में हुई कुल वृद्धि (ΔY)

कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि (ΔI) का $\frac{1}{1 - C}$ गुना होता है परन्तु $\frac{1}{1 - C}$

गुणक (k) है। इस प्रकार कुल आय में हुई वृद्धि कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि का गुणक गुना होती है अर्थात् $\Delta Y = \Delta I k$

$$= \frac{\Delta Y}{\Delta I} = k$$

उपर्युक्त निष्कर्षों के सम्बन्ध में केवल एक ही मान्यता है और वह यह कि उपभोग (C) अथवा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) का अन्तः प्रत्यक्ष घनात्मक तथा इकाई में कम (एक से कम) होता है।

गुणक क्रिया (Multiplier Function)

कुल आय में वृद्धि जो कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि का गुणक गुना होती है हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके लिए हम गुणक को दो प्रकार में ध्यान करते हैं।

(1) एककालिक गुणक (Simultaneous Multiplier)

(2) अवधि गुणक (Period Multiplier)

(1) एककालिक गुणक (Simultaneous Multiplier)—एककालिक गुणक की व्याख्या हम मान्यता पर आधारित है कि कुल निवेश, कुल उपभोग तथा कुल आय में एक साथ परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुल आय तथा कुल निवेश में एक ही काल में परिवर्तन होते हैं। कुल आय = कुल उपभोग + कुल निवेश होता है अर्थात्

$$Y = C + I$$

वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश बराबर होते हैं और इस कारण कुल निवेश में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कुल वास्तविक बचत में भी वृद्धि होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में कुल बचत राशि कुल आय राशि तथा सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS) द्वारा निर्धारित होती है। इस कारण अधिक वास्तविक बचत राशि को प्राप्त करने के लिए कुल वास्तविक आय में इतनी वृद्धि होना अनिवार्य है कि सीमान्त बचत प्रवृत्ति के स्थिर रहते हुए कुल बचत में कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि (ΔI) के समान मात्रा में वृद्धि हो सके। इसी बात को एक उदाहरण देकर समझाया जा सकता है माना कि सीमान्त बचत प्रवृत्ति 0.25 है अर्थात् सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 0.75 है। यदि कुल निवेश में एक करोड़ रुपये की वृद्धि होती है तो समस्त आय में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी क्योंकि

$$k = \frac{1}{1 - MPC} \text{ or } \frac{1}{MPS} \quad k = \frac{1}{0.25} = 4 \text{ गुना अर्थात् 4 करोड़ (MPS द्वारा)}$$

$$\text{अब वा } k = \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{1-75} = \frac{1}{25} = 4 \text{ गुना अर्थात् 4 करोड़ रुपय।}$$

आय इससे कम वृद्धि होने पर समस्त व्यय मात्रा में एक करोड़ रुपय की वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार यदि MPC अब वा MPS किसी एक अवधि में ज्ञात है तो सन्तुलन आय का ज्ञात किया जा सकता है जो कुल निवेश में विमी दी हुई राशि की वृद्धि में परिणामस्वरूप प्राप्त होगी।

एककालिक गुणक सिद्धान्त की आलोचनाएँ (Criticism of Simultaneous Multiplier Principle)

एककालिक गुणक सिद्धान्त की भावस्था भी अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांतों की तरह आलोचनाओं में मुक्त नहीं है। इस विरोध की आलोचनाएँ निम्न तथ्यों के आधार पर की जाती हैं—

(1) आलोचना का कहना है कि कुल निवेश तथा कुल उपभोग में एक साथ परिवर्तन नहीं होता। वास्तविकता यह है कि जब कुल निवेश में वृद्धि होती है तो इससे लोगों की कुल आय में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने में थोड़ा समयान्तर देरन का मिलता है। यदि हम यह मान भी लें कि दानों में अर्थात् निवेश तथा उपभोग में समान्तर नहीं है तो भी उपभोग वस्तु उद्योग का विकास एक साथ सम्भव नहीं होता अर्थात् आय में साथ वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि में थोड़ा समय लगता है।

(2) एककालिक विश्लेषण स्थिर विश्लेषण है क्योंकि यह उस भण के अध्ययन नहीं करता जिससे एक से तुलन आय दूसरी सन्तुलन आय को प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में प्रो० हबर्नर (Prof Haberler) का कहना है कि प्रो० कीन्स का गुणक सिद्धान्त सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) का दूसरा नाम मात्र है और कुछ नहीं। इसी प्रकार प्रो० हाट (Prof Hoot) ने कीन्स के गुणक के विचार को ग्राफी के पाँचवें पहिए की सजा दी है अर्थात् इसे अनावश्यक बताया है।

II अवधि गुणक (Period Multiplier)—अवधि गुणक का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि कुल निवेश में वृद्धि द्वारा कुल आय तथा कुल उपभोग वृद्धि होनी तो अवश्य है परन्तु इसमें कुछ समय लगता है। इसी बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विमी दी हुई समयावधि (t) में होने वाला उपभोग व्यय (Ct) अन्य बातें समान रहने पर पूर्ववर्ती समयावधि (t-1) में प्राप्त आय Y_{t-1} द्वारा निर्धारित होता है अर्थात्

$$C_t = f(Y_{t-1})$$

विमी प्रथम समयावधि की कुल आय दूसरी समयावधि में कुल उपभोग को निर्धारित करती है। अवधि गुणक निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है जैसे—

- (1) कुल निवेश में वृद्धि एक बार वृद्धि होती है।
- (2) कुल निवेश में जो आरम्भिक वृद्धि होती है वह आन बासी (पर्यावर्ती) समयावधियों में निरन्तर होती रहती है।
- (3) कुल निवेश में जो वृद्धि होती है वह कुल निवेश के उस भाग से सम्बन्धित होता है जिसे स्वायत्त निवेश कहते हैं।

प्रथम स्थिति जिसमें कुल निवेश में केवल एक बार अथवा एक समयावधि में वृद्धि होती है। यह वृद्धि आरम्भिक समयावधि 1 के अनुरूप अग्रिम समयावधि 2 तक अनवरत

समयावधियों में होंगी। कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि तथा गुणक के गुणनफल के बराबर होंगी। दूसरी स्थिति का आशय यह है कि समयावधि 1 में सन्तुलन आय निवेश में वृद्धि होने के पूर्व समयावधि में आय के स्तर का प्राप्त हो जावेगी। इसी बात को हम एक उदाहरण एवं तालिका द्वारा दिखा सकते हैं। माना कि निम्नी समय सीमात उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 0.75 है और आरम्भिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो गुणक 4 होने पर 1 समयावधि बाद कुल आय में 400 रुपए की राशि की वृद्धि हो जावेगी।

तालिका

आरम्भिक निवेश वृद्धि का उपभोग तथा आय पर प्रभाव

(करोड़ रुपए में)

समयावधि	कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि	कुल उपभोग में हुई वृद्धि $\Delta C = 0.75 \Delta Y$	प्रत्येक अवधि में कुल आय (ΔY) में वृद्धि	कुल आय में हुई मधीय वृद्धि
1	100 करोड़ रुपए	0	100	100
2	, ,	75	75	175
3	, ,	56.25	56.25	231.25
4	, ,	42.19	42.19	273.44
5	, ,	31.65	31.65	305.09
6	, ,	23.73	23.73	328.82
7	, ,	17.79	17.19	346.61

उपरोक्त तालिका वर्णित स्थिति में यह मान्यता मानी गई है कि कुल निवेश में आरम्भिक वृद्धि केवल एक बार आरम्भिक अवधि में होती है तथा उसकी पश्चात्ती अवधियों में दुहराया नहीं जाता। परन्तु यदि स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) समयावधि (t) ΔI राशि की वृद्धि जारी रखी जाए तो अन्त में 1 समयावधि में समस्त आय में निवेश में हुई वृद्धि के गुणक (k) गुना वृद्धि होगी। विभिन्न अवधियों में आय वृद्धि की प्रक्रिया उस समय तक विद्यमान रहेगी जब तक 1 समयावधि के अन्त में कुल वृद्धि होती है वह निवेश वृद्धि गुणक के समान ($100 \times 4 = 400$ करोड़ रुपए) होगी।

एककालिक तथा अवधि गुणक में अवधि गुणक महत्वपूर्ण विचारा जाता है क्योंकि यह हमारा ध्यान निवेश तथा उपभोग के मध्य उपस्थित उस परस्पर सम्बन्ध की ओर केन्द्रित करता है जो अव्यवस्था में अनेक व्यक्तियों के व्यवहार तथा निर्णयों का परिणाम होता है। यह हम उन शक्तियों के सम्बन्ध में भी ज्ञान प्रदान कराता है जो निवेश ध्येय में वृद्धि होने के समय अव्यवस्था में मध्यम रूप में उपस्थित रहती है।

गुणक में सामयिक परिवर्तन—गुणक में होने वाले परिवर्तन सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) में परिवर्तनों से सम्बद्ध होते हैं। दीर्घकाल में उपभोग तथा आय के मध्य आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है जबकि अल्पकाल में ऐसा नहीं होता है। व्यापार चक्र काल में कुल आय में वृद्धि तथा गिरावट के माध्य उपभोग में समानुपात में वृद्धि तथा गिरावट न होने के कारण सीमात उपभोग प्रवृत्ति (MPC) में भी परिवर्तन होते रहते हैं। व्यापार चक्र की चेतना तथा अभिवृद्धि की अवस्थाओं में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति में गिरावट होने के कारण गुणक में भी गिरावट आ जाती है। सन्तुलन की अवस्था में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति बरती

हुई होन व कारण गुणक म भी वृद्धि हा जाती है तथा आरम्भिक मदी प्रचण्ड मने का सा कारण बर लेती है।

गुणक के प्रभाव मे क्षति (Leakages in Multiplier Effect)

अभी तब हमन दस्ता वि जब समुदाय को नई आय प्राप्त होता है वह सारा को मारी उपभोग काय के लिए व्यय नही की जाती है। उनका एक भाग बचा लिया जाता है अर्थात् उपभोग नहा लिया जाता है इसी को क्षति (Leakage) की सज्ञा दी जाती है। इस क्षति का प्रभाव यह होता है कि यह राष्ट्रीय आय म हानि वानी वृद्धि का साधित करता है। यदि सम्पूर्ण आय जो अर्जित की जाती है उसका उपभोग बर लिया जाय अथवा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) इकाई के बराबर है तो निवेश मे थोड़ी मात्रा म वृद्धि पूरा रोजगार नान म संचय हो जाती है और उसका बाद स्तैतिन स्थितिवा उत्पन्न हा जायेगी। व्ययहारक रूप स यह दखा जाता है कि समस्त आय उपभोग नही की जाती अर्थात् MPC इकाई से कम हाता है जिन्हे परिणामस्वरूप प्रारम्भिक निवेश से हानि वाना आय व वृद्धि नगातार गिरती जाती है आर अंत म कुल आय म वृद्धि की दर सीमित हा रहता है। गुणक का क्षति निम्न रूप द्वारा हा सकता है

(i) **आयात तथा निर्यात (Import and Export)**—आयात अधिक बरन स गुणक म कमी आता है जब नि निर्यात अधिक होने म गुणक म वृद्धि हाती है। ऐसा प्राय अल्पकाल म होता है। दाखवान मे ऐसा होता है कि आयात म वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यातक देश की आय बढ जाती है और उस बढी हुई आय का उपयोग धारे धीरे आयात करने वाले देश का वस्तुओं की मांग बढाता है और जिसका आयात करने वाले देश की आय पर अनुकूल प्रभाव पडता है। परन्तु इसका प्रभाव तब सीमित हो जाएगा जबकि निर्यातक देश अपन यन्त्र विदेश से होने वाले आयात को सीमित कर दे या उस पर राज लगा दे।

(ii) **कीमत स्फीति (Price Inflation)**—जब समय तक देश म उत्पादक साधन बेराजगार रहेगे उस समय तक निर्यात जो भी वृद्धि हायी उससे अव्यवस्था का विस्तार होगा और यह प्रवृत्ति उस समय तक नागू रहेगी जब तक पूरा रोजगार का बिन्दु प्राप्त नही कर लिया जाता। जैसे ही पूरा राजगार का बिन्दु या उसके निकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बैंग हा तब निवेश की कीमत बढेगा साथ हा उत्पादक साधन का लागने भी बढ जायेगा क्योंकि उत्पादक के साधन का कम आ जाएगा अथवा उपलब्ध नहा हाग और उपभोक्ता तथा विनियोग उद्योग दोनों म हा इन साधन की मांग बढगा आर उनका कीमत बढगी। इस प्रकार बढी हुई आय का एक भाग उपभोग आय तथा राजगार बन्धान व स्थान पर कीमती की बढन मे व्यय हो जायगा। इस प्रकार कीमत स्फीति का प्रभाव बढा रहेगा। इसी स्थिति म गुणक गिराव क्योंकि वास्तविक कुल उपभोग की बढन नहा दा।

(iii) **पुराने ऋणों की अदाएगी (Payment of Old Loans)**—कभी-कभी एगा दसा आता है कि उपभोक्ता का नई आय प्राप्त हाता है उसका एक हिस्सा वह बैंग या व्यक्तिगत फर्मो स लिए गए पुराने ऋणों का चुकान म चला जाता है और उपभोग का स्थिति म गिराव आने म गुणक म भी गिरावट आता है।

(iv) **सीमांत बचत प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Saving)**—सामान्य बचत प्रवृत्ति ऊँची हान पर गुणक म गिरावट आती है। ऐसा प्राय उस समय दमन का मिलता है जब लाग म लगनना पमदगी ऊँचा होती है और लोग नवद बाया का अपन पाग रखना अधिक अच्छा समझते।

(v) वित्तीय निवेश (Financial Investment)—जब नई आय का उपभोग उपभोक्ता वस्तुओं पर न करके प्रतिभूतियों तथा वाण्डों (Securities and Bonds) पर अपवा पुराने स्टॉकों को खरीदने में व्यय किया जाता है तो इससे उपभोग के स्तर में गिरावट आती है और गुणक भी गिरता है।

गुणक की आलोचना (Criticism of Multiplier)

गुणक सिद्धान्त की विशेष तौर पर प्रो० कीन्स के गुणक विचार की विभिन्न अर्थ-शास्त्रियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। प्रो० हैबरलर (Prof. Haberler) ने अपने एक लेख 'Mr Keynes Theory of Multiplier : A Methodological Criticism' (1936 में प्रकाशित) कीन्स के गुणक सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है कि यह पूर्ण धोषित मूल्य की परिभाषा करना है। यह (गुणक) एक सन्तुलन में दूसरे सन्तुलन अथवा इन दोनों के बीच सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) की व्याख्या नहीं करता यह तोय हलै कहीं हुई बातों का कथन मात्र है। यदि गुणक के विचार को एक विशेष समय में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाय तो यह सम्भव होना चाहिए कि विभिन्न समयों में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति या सीमान्त वचत प्रवृत्ति के स्वभाव से सम्बन्धित उचित परिकल्पनाएँ मानी जाएँ, यदि ऐसा नहीं है तो गुणक का कोई महत्व नहीं होगा। गुणक कोई स्वतन्त्र रूप से प्राप्त नहीं किया जाता। गुणक के मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यह देखना होगा कि कुल कितनी आय गुणक द्वारा सृजित की गई है तब हमें इसे निर्वास से भाग देना होगा। प्रो० हैबरलर कहते हैं कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि विनियोग में वृद्धि (ΔI) इतनी गुना गुणक है जो कुल आय में परिवर्तन के बराबर होता चाहिए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि

$$\Delta I \times \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \Delta Y$$

कीन्स के गुणक विचार को पूर्ववर्ती कथन की आलोचना से यदि

हमें मुक्त करना है तो हमें अल्पकाल में सीमान्त उपभोग तथा सीमान्त वचत प्रवृत्तियों के सामान्य व्यवहार की व्याख्या करनी होगी।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रो० ए० जी० हार्ट (Prof. A. G. Hart) ने कीन्स के गुणक विचार को गाड़ी के पाँचवे पहिये की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त प्रो० हैनरी हैज़लिट (Prof. Henry Hazlitt) का कहना है कि यह कोलावादी प्रणाली का ऐसा विचित्र विचार है जिसकी कोन्स समर्थकों द्वारा बहुत बढा-बढाकर प्रस्तुत किया है जो एक कोरी बल्यता है। ऐसा कोई कारण नहीं है जो यह मोचने पर मजबूर करे कि गुणक नाम की भी कोई चीज है। वे कहते हैं कि सामाजिक आय, उपभोग, विनियोग तथा रोजगार की मात्रा के बीच न तो कोई संक्षिप्त, पूर्व निर्धारित और स्वचालिक सम्बन्ध होता है। वे आगे कहते हैं कि गुणक का विचार अव्यवस्था में बेरोजगारी होने की कल्पना करता है। वे कहते हैं कि ज्ञान का यह सोचना कि बेरोजगारी एक सामान्य घटना है और पूर्ण रोजगार एक विशेष घटना है, भ्रामक विचार है। कीन्स की गुणक सम्बन्धी यह भी मान्यता श्रुतिपूर्ण है कि समुदाय की आय को एक भाग का उपभोग नहीं किया जाता और उसको संचित कर लिया जाता है और इसके किसी भाग का विनियोग नहीं किया जाता। परन्तु उनका यह विचार पहले बड़े हुए वचत के इस विचार से भेद नहीं खाता कि वचत एवं विनियोग बराबर ही नहीं होते बल्कि समरूप (Identical) होते हैं। वचत एवं विनियोग तभी समान हो सकते हैं जबकि उपभोग पर न खर्च किया हुआ धन विनियोजित कर दिया जाए। वे कहते हैं कि गुणक का विचार वचन तथा विनियोग की असमानता सम्बन्धी समस्या की ओर संकेत करता है।

किया जा रहा है। गुणवत्ता अनैच्छिक बेरोजगारी की मान्यता मानकर बनती है अर्थात् मजदूरों या वायसान जनसंख्या का प्रचलित मजदूरी की दर पर काम उपलब्ध नहीं होता। अनैच्छिक बेरोजगारी न हान पर विनियोग से वृद्धि करने से राजगार उत्पादन तथा आय बढ़ने की सम्भावनाएं जाती रहती हैं। यदि अनैच्छिक बेरोजगारी व्याप्त है तो थोड़ी-सी धनराशि का विनियोग करने से वस्तुओं तथा सेवाओं का माँग बढ़ती है परन्तु राजगार का स्तर भी बढ़ता है।

एक अर्थ विवक्षित दशा में अनैच्छिक बेरोजगारी बहुत धाँदा मात्रा में पायी जाती है। जो भी बेरोजगारी पायी जाती है वह छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment) होती है। अधिकतर गाँव या तो देखते हैं कि गाँव में या फिर घरों में उद्योग या कार्य में लग रहे हैं और इनकी संख्या इन बाँटों में इनकी माँग से अधिक है। उन्हें इन बाँटों में जो कुछ बताना या मजदूरी के रूप में पाने वाली है वह उन्हें पता नहीं है। मनुष्य प्रदान करता है जितना भी उन्हें प्रचलित मजदूरी प्राप्त होती। अधिक मजदूरी का प्रलोभन ही उन्हें बतलाता है कि वे काम में लग सकते हैं और वे जानते हैं कि वे काम में लग सकते हैं कि प्रचलित मजदूरी पर अनिश्चित भ्रम की पूर्ति हो जाता है। इस प्रकार अर्थ विवक्षित दशा में व्यवहारिक स्थिति यह है कि अनैच्छिक बेरोजगारी की उपस्थिति में हान का कारण गुणवत्ता अधिक गंभीर नहीं होता। भारत जैसे देश में मनुष्य परिवार प्रणाली तथा अल्प बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी आदि का कारण भी गुणवत्ता में महत्व अधिक होता है। दूसरे अर्थात् गुणवत्ता मिटाने का एक अर्थ मान्यता है कि उदात्त अर्थात् मात्रा में तात्तुल्य होता है। अर्थ विवक्षित दशा में विवक्षित दशा का अपना उत्पादन में बाधना नहीं पायी जाती। अर्थ विवक्षित दशा में कुल उत्पादन का एक उदात्त भाग कृषि क्षेत्र में प्राप्त होता है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन तुलनात्मक दुर्घटना से बचना पड़ता है। दूसरा हाथी आवागमन क्षेत्र में कुल मजदूरी पूँजी मूल्य का भाग अथवा पूँजी बाजारों द्वारा उत्पादन में बतलाता दिखाई देती है। अर्थ विवक्षित दशा में धर्मशक्ति की बढ़ती का उपयोग उत्पादन का बहाना में उपयुक्त कारणों के द्वारा भीमि होता है और गुणवत्ता का प्रभाव मौद्रिक आय का क्षेत्र में दिखाई देता है वास्तविक आय और राजगार में अर्थ नहीं। दूसरा तुलना में एक विवक्षित दशा में उत्पादन तात्तुल्य होता है। मंदी का मतलब अर्थ क्षेत्र में बेरोजगारी ही नहीं दिखाई देता परन्तु अन्य पूँजी बाजारों की भी मंदी रहती है। लम्बी दशा में माँग में थोड़ी वृद्धि हान में (अनिश्चित विनियोग का कारण) उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और आय में वृद्धि वास्तविक आय में वृद्धि करता है। जैसे जैसे अवस्था पूर्ण राजगार की ओर उन्मुख होता है वास्तविक आय और माँग का अन्तर रहता जाता है जैसे ही पूँजी राजगार का मनुष्य का प्राप्ति हो जाती है गुणवत्ता की विवक्षित विवक्षित दशा में भी अर्थ विवक्षित दशा की तरह हो जाती है।

निष्कर्ष - गुणवत्ता गिद्धांत महत्वपूर्ण है। विश्वव्यापी तौर पर मंदी का समय सावधानीपूर्वक निमाण बाँटों के पक्ष में प्रस्तुत है गुणवत्ता आधारित है। मई 1934 ई० में अमेरीका में राष्ट्रीय रोजगार न्यूनीकरण योजना की घोषणा की थी वह ही गुणवत्ता आधारित थी। उस समय 300 मिलियन डॉलर का निधि का अर्थ क्षेत्र में गुणवत्ता राष्ट्रीय आय में बाँट गुणवत्ता वृद्धि गुणवत्ता प्रभाव का कारण हो सकता है।

गुणवत्ता व्यवस्था का मतलब होता है। गुणवत्ता हमारा ध्यान हमें जोर बाँटित करता है कि निवेश में दो-दो बार अधिक वृद्धि करने का अर्थ है निवेश की तुलना में अधिक होती है। गुणवत्ता का प्रभाव का कारण अवस्था में अधिक नीतियाँ विनियोग का कारण महत्वपूर्ण मिनती है। गुणवत्ता के लिए माँगदाता के रूप में कार्य करता है। मंदी का समय अवस्था का उचित उत्तर में मदद मिनती है। मंदी में निवेश गति में वृद्धि करता अवस्था का उचित लाभदायक होता है।

गुणक सिद्धान्त का प्रमुख दाव यह है कि यह स्विच सामान्त उपभोग प्रवृत्ति का मापक पर आधारित है। इसका अभाव गुणक प्रेरित निवेश का और ध्यान नहीं देता। गुणक सिद्धांत सदायस निवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बेचन उपभोग व्यय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। वास्तविकता यह है कि उपभोग व्यय में वृद्धि का परिणामस्वरूप प्रेरित निवेश में जो वृद्धि होता है उसकी उपेक्षा करता है। गुण मापक गुणक सिद्धान्त का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व होता है। अतः सिद्धांतों की भाँति यह विचार भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है।

५।

परीक्षा प्रश्न

1. गुणक से आप क्या समझते हैं? इसकी आलोचनाओं का बताएं।
(What do you understand by Multiplier? Discuss its criticisms)
2. आर्थिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीति में गुणक का महत्व को स्पष्ट कीजिए।
(Explain the importance of Multiplier in economic analysis and economic policy)
3. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कीन्स गुणक एक अद्वि विवर्धित अर्थ व्यवस्था का देश में लागू नहीं होता।
(Do you agree with this view that Keynes Multiplier does not operate in an under developed economy?)
4. टिप्पणी लिखिए—
(i) एकाधिक तथा अवधि गुणक
(ii) गुणक के प्रभाव में क्षति
Write notes on
(i) Simultaneous and Period Multiplier
(ii) Leakages in Multiplier Effect
5. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)
निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही और कौन गलत है।
(i) गुणक वह अनुपात है जो विनियोग में परिवर्तन द्वारा आय में परिवर्तन का बताता है।
(ii) गुणक का अवधी मूल्य एक में से MPC का अवधी मूल्य घटाने से प्राप्त होता है।
(iii) गुणक का MPC तथा MPS दोनों का द्वारा जाना किया जा सकता है।
(iv) गुणक अद्वि विवर्धित दश में पूर्णरूप से लागू होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) सही है। (iii) सही है। (iv) गलत है।

any increase in final demand will give rise to an additional demand for capital goods several times larger than that new final demand

—F A Von Hayek

The acceleration principle serves as useful tool for business cycle analysis and as a helpful guide to business cycle policy

—Kishara

अध्याय 11

त्वरक

(ACCELERATOR)

त्वरक व विषय में चर्चा हानाई कीम स पहल तथा बाद में काफी हा गई है परन्तु कीम न अपना पुस्तक *General Theory* में त्वरक सिद्धान्त का यदाकदा चर्चा की है। सबसे पहल त्वरक सिद्धान्त की व्याख्या का सम्बन्ध प्रो० जे० एम० क्लार्क (Prof J M Clark)¹ से जाड़ा जाता है प्रो० क्लार्क न ही त्वरक विचार का महत्व दिया। अथवा स्त्रिया की हर्चि इस सिद्धान्त में आरंभ जगृत हुई जब उह यह ज्ञात हुआ कि त्वरक सिद्धान्त का कीम व उपयोग क्रिया के माय अध्ययन करने पर यह सिद्धान्त एक स्त्र जनिता चर्चीय प्रक्रिया के घटित होने का व्याख्या कर सकता है। प्रो० क्लार्क के बाद त्वरक सिद्धान्त को विकसित और परिष्कृत करने में कुछ अध्यापिका व नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जैसे हैरार्ड हिंस हयक हैसन हैबरर गुडविन कुजनटम विरवा कालडार फिश फनरर मैथ्यूज रावटसन तथा संम्युसन आदि।

त्वरक का अर्थ (Meaning of Accelerator)

गुणक स्वायत्त निवेश में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभाग व्यवसाय में वृद्धि का माध्यम द्वारा समस्त आय में हुई वृद्धि का वर्णन करता है जबकि त्वरक सिद्धान्त कुन उपभाग में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुन निवेश में होने वाला वृद्धि की व्याख्या करता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि स्वायत्त निवेश में आरम्भिक वृद्धि होने में समस्त आय में हुई कुन वृद्धि का ज्ञात करने के लिए गुणक तथा त्वरक के सम्मिलित प्रभाव का ज्ञात करना आवश्यक है क्योंकि आय में हुई वृद्धि गुणक व त्वरक के सम्मिलित परिणाम होता है।

- 1 जोन मैरिस क्लार्क ने सन् 1917 में *Journal of Political Economy* नामक पत्रिका में अपने लेख द्वारा व्यापार चक्र का सम्बन्ध आ रूप में त्वरक सिद्धान्त का विस्तार किया था। सन् 1934 में प्रो० रगनर फिश ने अपने लेख में त्वरक का सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रो० हिंस ने व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की मयुक्त प्रामाण्यता का ज्ञान क्लार्क के सिद्धान्त के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस दोता के अध्ययन को एक साथ करने का साथ यह है कि हम यह मानूँ माना है कि स्वायत्त निवेश में हुई आर्थिक वृद्धि अथवा कमो हानि का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रभाव होने हैं।

स्वरक निदान निवेश पर कुल उपभोग व्यय में इस परिवर्तन के प्रभाव को व्याख्या करता है। स्वरक प्रेरित तथा उपभोग निवेश की व्याख्या करता है तथा बताता है कि वह निवेश जिनके परिणामस्वरूप गुणक क्रियाशील होता है स्वायत्त अथवा उपभोग निर्धारक निवेश होता है। स्वरक तथा गुणक की सम्मिलित क्रियाओं का हम निम्न रूप में समझा सकते हैं—

स्वायत्त निवेश में → कुल आय में → कुल उपभोग में → प्रेरित निवेश में
 वृद्धि ΔI_s वृद्धि ΔY वृद्धि ΔC वृद्धि ΔI_p

स्वरक निदान बताता है कि अर्थव्यवस्था में कुल निवेश का वह भाग अर्थात् प्रेरित निवेश उपभोग वस्तुओं की माँग में होने वाले परिवर्तन का बताता है। प्रो० बान हेयक ने स्वरक की व्याख्या इस प्रकार की है साधारणतया किसी दी हुई अन्तर्गति में उपभोग वस्तुओं की किसी दी हुई मात्रा का उत्पादन करने के लिए कई गुना अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ने के कारण उपभोग वस्तुओं की माँग में किसी दी हुई मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूँजी वस्तुओं की माँग में तब उपभोग माँग की तुलना में कई गुना वृद्धि होगी।¹

स्वरक तथा गुणक में अन्तर

जैसा कि हम जानते हैं गुणक विनियोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आय तथा रोजगार की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को बताता है जबकि स्वरक उपभोग में परिवर्तन द्वारा विनियोग पर पड़ने वाले प्रभाव को व्याख्या करता है। गुणक मौलिक उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है जबकि स्वरक मशीनों तथा औजारों के विकास पर निर्भर करता है। हमारे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुणक मनेर्वैज्ञानिक तत्त्व पर तथा स्वरक तकनीकी तत्त्वों पर निर्भर करता है। वास्तव में ऐसा जान तो यह अन्तर स्वरक में दार्शनिक प्रतीति होता है। स्वरक भी अपने मौलिक और आन्तरिक रूप में मनेर्वैज्ञानिक है परन्तु हम क्रियाशीलता का वह इसे अधिक तकनीकी स्वरूप प्रदान कर देता है। स्वरक के द्वारा हम निवेश पर उपभोग के विकास की गति को दिखाते हैं जबकि गुणक बड़े हुए निवेश के प्रति उपभोग की प्रतिक्रिया को बताता है। इस प्रकार गुणक और स्वरक दोनों विचार धाराओं में अन्तर है।

स्वरक की क्रियाशीलता (Working of Accelerator)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है स्वरक निदान मशीनों तथा औजारों के विकास पर तथा पूँजीगत साधनों पर निर्भर करता है। एक उदाहरण और समझने के लिए स्वरक निदान की क्रियाशीलता को स्पष्ट किया जा सकता है। हम यह मानकर चलते हैं कि 200 करोड़ की अन्तिम वस्तु के लिए हम 10 करोड़ पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और पूँजीगत वस्तु का जीवन काल 10 वर्ष है और इनमें से 10 प्रतिशत को प्रतिवर्ष पुनर्स्थापित करना पड़ता है।

त्वरक तालिका

(करोड़ रुपये में)

समयावधि	अन्तिम वस्तुओं का उत्पादन	पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता	नई पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता	पुनर्स्थापित	कुल नई पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता
1	1 000	300	0	50	50
2	1 200	600	100	50	150
3	1 300	650	50	60	110
4	13 00	650	0	65	65
5	12 00	600	—50	65	15
6	11 00	550	—50	60	10
7	1 000	500	—50	55	5
8	900	450	—50	50	0

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम समयावधि में 1000 करोड़ रुपये की निमित्त वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए 500 करोड़ रुपये का पूँजीगत माल की आवश्यकता होती है जबकि हम यह पहले ही मान चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत पूँजीगत माल को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है इसलिए 500 करोड़ रुपये के पूँजीगत माल में से 50 करोड़ के पूँजीगत माल अथवा मशीनों की आवश्यकता होगी। दूसरी समयावधि में हम देखते हैं कि अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन की माँग में वृद्धि 1000 से 1200 करोड़ रुपये यानि 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त माँग की पूरा करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपये की मशीनों तथा औजारों (पूँजीगत माल) की आवश्यकता होती है। अर्थात् कुल पूँजीगत वस्तुओं की माँग 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 600 करोड़ रुपये हो जाती है और कुल नई पूँजीगत वस्तुओं की माँग 50 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो जाती है इसका अर्थ यह है कि दूसरी समयावधि में 20 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 प्रतिशत पूँजीगत माल की आवश्यकता होती है। तीसरी समयावधि में स्थिति भिन्न हो जाती है अन्तिम वस्तुओं का उत्पादन 100 करोड़ रुपये से बढ़ता है अर्थात् समयावधि नम्बर दो की अपेक्षा इसमें केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है (1200 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ रुपये) जबकि कुल नई पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता में 26.67 प्रतिशत की कमी आ जाती है (150 करोड़ से गिरकर 110 करोड़ हो रहा जाता है) इसका कारण यह है कि अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में पहले जो 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की कुल मात्रा थी वह आगे आने वाली अवधि में जागे नहीं रखी गई। चौथी समयावधि में अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में तीसरी समयावधि के बराबर 1300 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया है केवल पुनर्स्थापन के अलावा अन्य पूँजीगत माल की आवश्यकता नहीं होगी। इस समयावधि में कुल नयी पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता 110 करोड़ रुपये से घटकर केवल 65 करोड़ रुपये हो रहा जाता है अर्थात् पूँजीगत वस्तु उद्योग में उत्पादन में 40 प्रतिशत में कुछ अधिक की गिरावट आती है। इसी प्रकार अन्य आने वाली समयावधियों में अर्थात् 5, 6, 7 व 8 में समयावधि 4 की अपेक्षा गिरावट आती जाती है और अन्तिम समयावधि अर्थात् समयावधि 8 में समयावधि प्रथम की अपेक्षा 100 करोड़ की अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आ जाती है और पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग का पतन प्रारम्भ हो जाता है।

उत्पादित सामानों में एक महत्वपूर्ण सामान्य बात यह सामने आती है कि जैसे-जैसे अन्तिम वस्तुओं में उत्पादन में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे पूँजीगत वस्तु उद्योग में भी प्रगति होती जाती है। जैसे ही अन्तिम वस्तुओं में उत्पादन में गिरावट आती है वैसे ही पूँजीगत वस्तु उद्योग में हानि होती जाती है और गिरावट की दर इसी प्रकार बनी रहती है। पूँजीगत वस्तु उद्योग पतन के कारण पर पहुँच जाता है। इस प्रकार मदी का युग प्रारम्भ हो जाता है अन्तिम वस्तुओं में उत्पादन में थोड़ी वृद्धि से पूँजीगत वस्तु उद्योग के विस्तार की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यही विस्तार प्रभाव (Magnifying Effect) आर्थिक उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार स्वरक सिद्धान्त व्यापार चक्र के समय अर्थव्यवस्था में व्याप्त कारणों की शक्तिशाली व्याख्या करता है। स्वरक सिद्धान्त से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाना है तो हम धीमी गति की अपेक्षा तेजी से अर्थव्यवस्था का कार्य संचालन करना चाहिये। मदी की स्थिति से निपटने के लिए हम तेजी से अपनी गतिविधियों का वर्णन होगा। प्रो० सैमुएलसन (Prof. Samuelson) का इस सम्बन्ध में कहना है कि यदि व्यापारिक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव होने है तो स्वरक सिद्धान्त इसमें और तेजी का यह व्यापार चक्रों की प्रिया-शीलता बता देता है। यदि दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति का कारण अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है तो स्वरक सिद्धान्त की भूमिका उत्पादकत्व होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूँजी का व्यापक उपयोग होता है जिससे निवेश मार्ग में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का दूर किया जा सकता है।

स्वरक सिद्धान्त की शक्ति दो तत्वों पर प्रमुखतः निर्भर करती है (i) पूँजी उत्पादन अनुपात अथवा पूँजी गुणांक (Capital Output Ratio or Capital Coefficient) (ii) पूँजीगत साधनों का टिकाऊपन (Durability of the Capital Equipment)। पूँजी-उत्पादन का अनुपात जितना अधिक होगा निवेश की वृद्धि भी उतनी अधिक होगी। उपभोग में वृद्धि होने पर निवेश में कम वृद्धि होगी। इस प्रकार पूँजीगत साधनों का टिकाऊपन या जीवन जितना अधिक होगा स्वरक का मूल्य भी उतना अधिक होगा तथा स्वरक के प्रभाव भी उतने ही अधिक दिखाई देंगे। यदि मशीनों या पूँजीगत साधनों का टिकाऊपन कम है तो स्वरक का मूल्य कम होगा और स्वरक के प्रभाव भी कम होंगे।

स्वरक सिद्धान्त की सीमाएँ (Limitations of Acceleration Principle)

अन्य आर्थिक सिद्धान्तों की भाँति स्वरक सिद्धान्त में भी कुछ सीमाएँ हैं जो निम्न प्रकार से बनाई जा सकती हैं—

(1) उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता का अभाव—स्वरक सिद्धान्त उस समय हमारा भाव नहीं देता जबकि उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ने पर प्रेरित निवेश को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्योंकि इन बड़ी हुई माँग की पूर्ति उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से पूरा किया जा सकेगा। अतिरिक्त क्षमता तथा अतिरिक्त काम की परिधियों (Shifts) द्वारा बड़ी हुई माँग की पूर्ति की जा सकेगी। ऐसा प्रायः व्यापार चक्र की उदय अवस्था (Recovery or Revival Phase of Trade Cycle) में दिखाई देता है। उन उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता दिखाई देती है अथवा माहुरी ऐसे उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता बनाए रखते हैं जिन उद्योगों की वस्तुओं की माँग में उच्चावचन अथवा उतार-उत्पाद की माँग में परिवर्तन होते रहते हैं। स्वरक सिद्धान्त की त्रिआशीलता के सम्बन्ध में हम यह मानकर चलते हैं कि अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न नहीं है और सभी पूँजीगत साधनों का उपयोग भूषण रूप में हो रहा है तथा अतिरिक्त कार्य (Overtime) तथा अतिरिक्त परिधियों (Additional Shifts) में कार्य

करने की सम्भावना नहीं है। इसका आशय यह है कि अनिश्चित क्षमता के अभाव में ही त्वरक सिद्धान्त कार्य करता है।

(2) निवेश वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता—एक अन्य सिद्धान्त भी यह है कि निवेश वस्तु उद्योग अथवा पूँजीगत वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है यदि यह अतिरिक्त क्षमता पूँजीगत मान उद्योग में नहीं हो तो पूँजीगत माधनों (मशीनों) की व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) में वृद्धि होने पर उनको पूर्ति बढ़ाना सम्भव नहीं होगी। यदि यह अतिरिक्त क्षमता पूँजीगत वस्तु उद्योगों में उपलब्ध नहीं होगी तो इनकी माँग बढ़ने पर इनकी उत्पादन सम्भव नहीं होगा और इनकी माँग को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच अर्थात् माँग में वृद्धि हेतु पूर्ति में वृद्धि के बीच का समय में पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे और त्वरक सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

(3) माँग का स्वभाव—त्वरक सिद्धान्त लागू होने की एक शर्त यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में होने वाली वृद्धि स्वभाव से स्थायी प्रवृत्ति की हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो त्वरक सिद्धान्त लागू नहीं होगा। यदि माँग में होने वाली वृद्धि अस्थायी है तो पूँजी विनियोजक उपभोक्ता वस्तु में होने वाली इस प्रकार की अस्थायी वृद्धि के परिणामस्वरूप पूँजीगत माल का बढ़ाने में रुचि नहीं लेंगे। चूंकि पूँजीगत माल में टिकाऊपन का गुण होता है साथ ही इसके लिए अच्छी धनराशि की आवश्यकता होती है इसलिए वस्तु का निर्माता तब तक इसके खर्च करने में रुचि नहीं लेगा जब तक उसे यह विश्वास न हो जाए कि उपभोक्ता वस्तुओं की माँग अल्पकालिक नहीं है। यदि निर्माता यह समझता है कि माँग लगातार बनी रहेगी तभी वह पूँजीगत माल अथवा मशीनों में पूँजी लगाएगा। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्वरक सिद्धान्त की प्रियाप्ति तथा शर्तों की तुलना पर ही केवल आधारित नहीं होती बल्कि भविष्य में होने वाली साम की दर पर भी निर्भर करती है।

(4) पूँजी उत्पादन का स्थिर अनुपात—त्वरक सिद्धान्त की एक अन्य मान्यता यह है कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन तथा उच्च उत्पादित करने वाले पूँजीगत माधनों के बीच अनुपात स्थिर रहता है। वास्तविकता यह है कि यह अनुपात स्थिर नहीं रहता। हमारे गणितीय समाज में उत्पादन के क्षेत्र में कई तकनीकी प्रगति एवं आविष्कारों के कारण पूँजीगत माधनों अधिक व्यापक रूप से कार्य करते हैं जिससे कि प्रत्येक पूँजीगत माधनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। इस अथवा भविष्य में व्यापारियों को मजदूरी, मजान तथा माँग की सम्भावनाओं के कारण पूँजी—उत्पादन अनुपात में परिवर्तन हो रहा रहने है। पूँजी-उत्पादन अनुपात जितना अधिक होगा स्वल्प सिद्धान्त भी उतना अधिक प्रभावी होगा।

(5) साधनों की पूर्ति सोचता—त्वरक की एक अन्य मान्यता यह है कि साधनों की पूर्ति सोचपूर्ण होना चाहिए। पूँजीगत माल अथवा मशीनों को उत्पादित करने वाले उद्योगों की क्षमताएँ ऐसी हैं कि सम्भक्ति इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और इनकी आवश्यकता के समय अधिक मशीनों की पूर्ति हो सके। निवेश उद्योगों में प्रसार की क्षमता बनी रहनी चाहिए अर्थात् निवेश उद्योगों में पूर्ण रोजगार की स्थिति न पाई जाए। एक बार जब पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर लिया जाए तो फिर ऐसे उद्योगों में किसी भी प्रकार का प्रसार नहीं होना चाहिए। ऐसे उद्योगों में पूर्ण रोजगार का विन्दु प्राप्त कर लेने के बाद त्वरक सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

(6) सात की सोचपूर्ण पूर्ति—मांग और मुद्रा की सोचपूर्ण पूर्ति त्वरक सिद्धान्त के लागू होने के लिए आवश्यक शर्त है। जब सभी को प्रेरित निवेश की स्थिति हो तो मुद्रा तथा मांग की पूर्ति निवेश उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा चाहिए। मांग

और गुण की तर्फी होगी तो इसका स्थापना की दृष्टि में वृद्धि होगी जिससे निवेश की लागत बढ़ेगी जो भाग नकार निवेश को निरन्तराहित करेगा। स्वरक के स्वतन्त्र और निर्वाचन रूप से कार्य करने के लिए यह जरूरी है कि विनियोग के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होना चाहिए। यदि निवेश हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होगी तो स्वरक सिद्धान्त सफलतापूर्वक कार्य नहीं करेगा।

(7) उत्पादन के टिकाऊ संपत्तियों की उपस्थिति—स्वरक सिद्धान्त की एक अन्य मान्यता यह है कि उत्पादन के टिकाऊ संपत्तियों की उपलब्धता होनी चाहिए। निवेश वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण पाए जाने पर ही स्वरक सिद्धान्त लागू होगा।

स्वरक सिद्धान्त का महत्व (Importance of the Principle of Acceleration)

स्वरक सिद्धान्त इसका महत्वपूर्ण है कि इसकी अधिप्राप्त अवधारणायों ने मान्यता प्रदान की है। स्वरक सिद्धान्त के महत्व को निम्न तथ्यों से अंशित जा सकता है—

(1) आय संरचना को समझने में सहायक—स्वरक सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सिद्धान्त आय संरचना की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करता है। गुणक सिद्धान्त हमको बताता है कि जैसे-जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे-वैसे लागत की आय और रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है परन्तु हम गुणक सिद्धान्त के परिणामों में ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम आय पर निवेश की वृद्धि के कुल परिणाम या प्रभाव को जानना चाहते हैं तो हमें स्वरक के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उपभोग के स्तर में वृद्धि होती है जो अन्ततः भावी निवेश को प्रेरणा देती है और इस प्रकार गुणक प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से कुल आय में वृद्धि होने के बाद आय संरचना की प्रक्रिया का दूसरा चक्र स्वरक सिद्धान्त की प्रक्रिया-शीलता के कारण प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार स्वरक आय संरचना की वास्तविकता को समझने में बड़ा सहायक होता है।

(2) व्यापार चक्रों की प्रकृति समझने में सहायक—स्वरक की एक विशेषता यह है कि यह व्यापार चक्र की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। व्यापार चक्रों के घटित होने पर उपभोग वस्तु उद्योग की अपेक्षा निवेश वस्तु उद्योग में उतार-चढ़ाव की गति तेज होती है। यदि उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में जरा सा भी परिवर्तन होगा तो इसमें निवेश वस्तुओं के उद्योगों में भारी परिवर्तन होंगे। इसलिए व्यापार चक्रों की स्थिति में निवेश उद्योगों में भारी परिवर्तन होने से बचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

(3) स्वरक सिद्धान्त हमें बताता है कि पूँजीगत वस्तुओं की माँग को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए उपभोग को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना जरूरी होता है।

(4) स्वरक सिद्धान्त हमें बताता है कि मदी के घटित होने का प्रमुख कारण उपभोग में गिरावट का आना होता है। मदी के समय उपभोग का स्तर बराबर गिर जाता है, इसलिए अर्थव्यवस्था से मदी उबारने के लिए उपभोग का स्तर को ऊँचा उठाने में सभी प्रयत्न करना चाहिए।

(5) स्वरक सिद्धान्त व्यापार चक्र के विवर्तनकारक अध्ययन में अपनी महत्व रखता है।

स्वरक सिद्धान्त यद्यपि महत्वपूर्ण है परन्तु इसकी मान्यताएँ इस सिद्धान्त का किसी प्रकार माँझों में स्थित करने में बाधा उपस्थित करती हैं। स्वरक सिद्धान्त की कुछ मान्यताएँ जैसे अनिश्चितता क्षमता का अभाव, माँग में अस्थायी वृद्धि पूँजीगत वस्तुओं के प्रति इच्छा वस्तुओं का निश्चित अनुपात, निरंतर बदलाव की माँग आदि हमारे वास्तविक जीवन में निम्नलिखित तथ्यों से— यदि हम वास्तविक मान्यताओं के आधार पर

है जो निवेश वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली आय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है जबकि स्वरक सिद्धान्त बताता है कि उपभोग में परिवर्तन किम प्रकार विनियोगों में परिवर्तन लाते हैं। यदि हमें आय सारवना प्रक्रिया का पूरा चित्र देखना है तो हमें गुणक तथा स्वरक दोनों ही के प्रभावों को देखना होगा।

गुणक तथा स्वरक की परस्पर क्रिया के प्रभावों का अध्ययन उपयोगी हो मही बनने रोचक भी है। प्रारम्भिक निवेश के राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने एवं उनको नापने के लिए हमें गुणक तथा स्वरक दोनों सिद्धान्तों को मिला देना चाहिए। निवेश में होने वाला परिवर्तन राष्ट्रीय आय को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है जिससे उपभोग का स्तर भी परिवर्तित हो जाता है। उपभोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निवेश परिवर्तित होता है इस प्रकार बारण तथा परिणाम के सम्बन्धों का एक चक्र पूरा हो जाता है। निवेश आय तथा आय पुन निवेश को प्रभावित करती है और जिससे गुणक तथा स्वरक क्रिया प्रति क्रिया द्वारा आय में उच्चावचन को हांते हैं उसे निम्न तालिका द्वारा दिया जाकते है

तालिका

(करोड रुपये में)

समयावधि (Period)	स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment)	उपभोग में वृद्धि (Increase in consumption) $\Delta c / \Delta y = 0.5$	प्रेरित निवेश (Induced Invest- ment) $\Delta k / \Delta y = \alpha = 2$	आय में कुल वृद्धि $2 + 3 + 4$
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
1	100	0	0	100
2	100	50	100	150
3	100	125	150	375
4	100	187.5	125	412.5

नोट—अवधि नम्बर तीन के प्रेरित निवेश आनने के लिए तो अवधि नम्बर 2 की उपभोग प्रवृत्ति को अवधि नम्बर 3 की उपभोग प्रवृत्ति में से घटा देना चाहिए। $(125 - 50 = 75)$ जो कुछ आयेगा उसे 2 से गुणा करने पर अवधि नम्बर 3 का प्रेरित निवेश मालूम किया जा सकता है $(75 \times 2 = 150)$ इसी प्रकार से अन्य समयावधियों के प्रेरित निवेश को मात किया जा सकता है। आय में कुल वृद्धि की Column नम्बर $2 + 3 + 4$ के योग द्वारा मालूम किया जा सकता है। यदि रहे स्वायत्त निवेश अश्रितित रहेगा। उपरोक्त सारणी में $MPC = \frac{1}{2} = 0.5$ तथा स्वरक सह-गुणांक (Coefficient) $= 2$ माना है।

उपरोक्त सारणी में 100 करोड रुपये का स्वायत्त निवेश आने वाले समय में वृद्ध आता है जो आगे के समयावधियों में निरन्तर बना रहता है। प्रथम समयावधि में 100 करोड रुपये का स्वायत्त निवेश 100 करोड रुपये द्वारा बढ़ जाता है और इस बात में उपभोग में वृद्धि शून्य दिखाई गई है। इस निवेश वृद्धि का परिणाम दूसरी समयावधि में उपभोग में वृद्धि 50 करोड रुपये की लाता है क्योंकि $MPC = 0.5$ अथवा $1/2$ है। स्वरक का मूल्य 2 होने के कारण दूसरी समयावधि में प्रेरित निवेश 100 करोड हो जाएगा और कुल आय में वृद्धि 150 करोड रुपये होगी। इसी प्रकार तीसरी समयावधि में 150 करोड प्रेरित निवेश कुल आय में 375 करोड रुपये की वृद्धि करता है। आगे आने वाली समयावधियों में भी इसी प्रकार आय में होने वाले परिवर्तन निर्धारित किए जाते हैं।

परस्पर प्रिया का महत्व (Importance of the Interaction)

गुणक तथा त्वरक की परस्पर प्रिया का विचार भी काफी महत्वपूर्ण है। गुणक तथा त्वरक सिद्धान्त की परस्पर प्रियाओं द्वारा व्यापार चक्र का निश्चयनात्मक अध्ययन सम्भव हुआ है। गुणक तथा त्वरक के परस्पर प्रभाव की अनुपस्थिति में व्यापार चक्र का आकार साधारण हुआ होता और इनका नियन्त्रण करना भी सरल होता। प्रा० कुरीहारा ने कहा है कि यह गुणक विश्लेषण के साथ साथ जा कि सामान्य उपभाग प्रवृत्ति का विचार पर आधारित है त्वरक सिद्धान्त व्यापार चक्र विश्लेषण और व्यापार चक्र की नीति के लिए एक महयोगी भाग दर्ज करता है तथा एक उपयोगी अस्त्र है जो हमारी मदद करता है।¹

परीक्षा-प्रश्न

1. त्वरक सिद्धान्त को परिभाषित कीजिए। इसकी कार्य विधि भीमाएँ तथा महत्व बताइए।

(Define the Principle of acceleration Give its working limitations and Significance)

2. त्वरक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए तथा इसकी मान्यताएँ बताइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह सिद्धान्त कम विकसित देशों में कार्य नहीं करता ?
(Explain the principle of acceleration and pointout its assumptions Do you agree with the view that it does not operate in less developed countries ?)

3. टिप्पणी लिखिए—

(i) गुणक तथा त्वरक की परस्पर प्रिया।

(ii) त्वरक सिद्धान्त की आलोचनाएँ।

Write notes on —

(i) Interaction of Multiplier and Accelerator

(ii) Criticism of the Principle of Acceleration

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

4. निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही तथा कौन गलत है।
(i) त्वरक सिद्धान्त कुल उपभाग में वृद्धि के परिणामस्वरूप पुनः निवेश में हानि वाली वृद्धि की व्याख्या करता है।
(ii) यह कहना गलत है कि व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की परस्पर प्रिया द्वारा घटित होते हैं।
(iii) त्वरक प्रमुख दो स्तरों पर निर्धारित करता है। (i) पूँजी गुणक तथा (ii) पूँजीगत माधन का टिकाऊपन।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है (ii) गलत है। (iii) सही है।

"It is in conjunction with the multiplier analysis based on the concept of the marginal propensity to consume that acceleration principle serves as a useful tool for business cycle analysis and as a helpful guide to business cycle policy

Monetary Theory and Public Policy P 234 — A. A. Kurilora

Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e. as a means of settling debts) and that at the same time acts as a measure and as a store of value' — *G Crother*

Money is any thing that passes freely from hand to hand as medium of exchange and is generally received in final discharge of debts — *Ely*

अध्याय 12

मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

(DEFINITION AND FUNCTIONS OF MONEY)

मुद्रा क्या है ? (What is Money ?)

प्रो० वाउवर १ मुद्रा को मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार का सना दी है। प्रो० व उधर का कहना है कि मुद्रा मानव आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। प्रत्येक ज्ञान की शाखा में कोई न कोई मौलिक खोज होती है। जिस प्रकार यंत्रशास्त्र में पहिया विज्ञान में अग्नि तथा राजनीतिशास्त्र में मत आविष्कारों के सूचक हैं ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व के सम्पूर्ण व्यापारिक क्षमता में मुद्रा वह महान आविष्कार है जिस पर अन्य सभी आविष्कार आधारित हैं।

मानव सभ्यता १ विकास के साथ मुद्रा का इतिहास जुड़ा है। प्रारम्भ में चकक वतमान समय पर मुद्रा का स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होते आए हैं। मुद्रा की गणना उन वस्तुओं में से की जाती है जिनको किसी एक परिभाषा द्वारा व्यक्त करना एक दुष्कर काम है।

मुद्रा की परिभाषा (Definition of Money)

मुद्रा जहाँ मानव जीवन के लिए अति आवश्यक एवं अद्वितीय है वहाँ दूसरी ओर इसकी परिभाषा में सम्बन्ध में काफी वाद विवाद रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के विभिन्न गुणों को ध्यान में रखकर मुद्रा की पृथक् पृथक् परिभाषाएँ दी गई हैं। वास्तविकता यह है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोणों एवं अपने मुद्रा के प्रकार मुद्रा की परिभाषा देने का प्रयास किया है। मुद्रा की इतना अग्रिम परिभाषाएँ दी गई हैं कि अर्थशास्त्र के विचारों के समक्ष यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि दोनों

ऐसी मुद्रा की परिभाषा है जो अपने आप में पूर्ण एवं उपयुक्त हो। मुद्रा की परिभाषाओं के विभिन्न वर्गीकरणों से हम मुद्रा की एक उपयुक्त परिभाषा ढूँढ़ने में सफल हो सकते हैं।

हम इन परिभाषाओं को, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार दी गई हैं, अध्ययन की सुविधा के लिये निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएँ (Descriptive or Functional Definitions)

जिन परिभाषाओं में मुद्रा के पायों या वर्णन किया गया है उनका वर्णनात्मक परिभाषाएँ कहते हैं। इनमें मुख्य निम्न हैं —

(क) 'मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे।'¹ — फ्रांसिस वाकर

(ख) 'मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के साधन (अर्थात् वस्तुओं के निपटाने के साधन) के रूप में सामान्यतः स्वीकार्य होती है तथा साथ ही मूल्य के मापक और संचय के आधार का कार्य करती है।'² — फ्राउडर

(ग) 'वर्तमान में मुद्रा, द्रव्य के व्यवहार में, केवल शर्तों को निर्धारित नहीं करती बल्कि विनिमय में माध्यम का कार्य भी करती है..... यह एक माप या मूल्य का प्रमाण के रूप में कार्य करती है जिगकी महायन्त्र से अन्य वस्तुओं की तुलना की जा सकती है।'³ — फ्राउडर

(घ) 'यदि कोई वस्तु-विशेष मूल्य निर्धारित करने, वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदान-प्रदान करने तथा अन्य आर्थिक कार्य करने के लिये सामान्य रूप में काम में लायी जाती है तब वह मुद्रा है चाहे उसकी वैधानिक और भौतिक विशेषताएँ कुछ भी हों।'⁴ — व्हिटलेसी

(ङ) 'मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन हो।'⁵ — कॉलमोन

1. "Money is that money does."
Money in Relation to Trade & Industry. — Francis A. Walker
2. "Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e. as a means of settling debts) and that at the same time acts as measure and as a store of value"
An Outline of Money. — G. Crowther
3. "In every transaction money, now not only fixes the term. But mediates in the exchange..... It acts as a yard-stick or standard measure of value to which all other things can be compared."
An Outline of Money. — G. Crowther
4. 'If a particular unit is commonly employed to state values, exchange goods and services or perform other money functions, then it is money whatever its legal or physical characteristics'
— Whittlesey.
5. "Money may be defined as the means of valuation and of payment
— Coulton

प्रो० नैप जोर हाट्टे सिमरेट व सीपियो आदि तो क्या, वे तो मात्र पत्रा और चैको को भी मुद्रा के अन्तर्गत गणना करने को तैयार नहीं थे क्योंकि, आन्तरिक शक्ति के अभाव में, इनको लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

आलोचना

यह परिभाषा अत्यन्त सन्तुष्ट है। कॉलबोर्न (Coulborn) के अनुसार यह परिभाषाएँ 'मुद्रा से सम्बन्धित दृष्टियों के दृष्टिकोण' (Lawyer's View of Money) हैं। वास्तविकता यह है कि विनिमय एवं ऐच्छित वार्थ है, और यदि यह किया केवल आन्तरिक दबाव के अन्तर्गत की जाय तो सर्व्वे अर्थों में इसे विनिमय कहा जाता है। प्रो० नैप ने देश जर्मनी में सन् 1920 के बाद प्रथम महायुद्ध के दुष्परिणामों के कारण, सिगा हुआरि मार्क की जन स्वीकृति समाप्त हो गई और वह विनिमय का व्यावहारिक माध्यम न रहा। 1944 में हुगरी में उमबी मुद्रा पेन्गोस (Pengos) के साथ भी यही हुआ और लोगों ने उसको विनिमय में लेने से अस्वीकार कर दिया, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् चीन में भी वहाँ की मुद्रा बानूनी मान्यता होती हुए भी प्रचलन में हट गयी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा के लिए राज्यशक्ति नहीं बनू सर्व्वग्राह्य या गुण होना जरूरी है। यदि जनता का विश्वास किसी मुद्रा में सँकट आए तो राज्य कितने ही बड़े नियम बना न बना ले, उसे सभी के द्वारा स्वीकार करना में सक्षम नहीं हो सकता।

सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ

(Definitions based on General Acceptability)

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि सर्व्वग्राह्यता या सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक विशेष गुण है। इसी तथ्य पर चल देने के लिये अनेक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा किया है जिनमें से मुख्य निम्न हैं—

(क) 'मुद्रा म के सब वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना सन्देह या विशेष जाँच-पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और व्यय चुकाने के माध्यम के रूप में साधारणतः प्रचलित होती हैं।'¹

(ख) "मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण और भूय-गन्धर्वा अनुबन्धा को पूर्ण किया जाता है, और जिनमें सामान्य त्रय-शक्ति संचित की जाती है।"² —बीन्स

(ग) "मुद्रा वह वस्तु है जिस सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।"³ —सैलिंगमैन

(घ) 'मुद्रा वह वस्तु है जिसे मात्र के भुगतान, अथवा व्यापारिक दायित्वों के

1 "Money includes all those things which are (at any given time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services and of defraying expenses"
—Prof. Marshall

2 "Money itself is that by delivery of which debt-contracts and price-Contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held"
—Keynes

3 "Money is one thing that possesses general acceptability"
—Saligmen

भुगतान के रूप में विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है।¹

—राबर्टसन

(च) मुद्रा कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय माध्यम तथा मूल्य-मापक के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है।²

—केंट

(छ) मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में, स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है, और जो ऋणों के अन्तिम भुगतान के लिए सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है।³

—एली

(ज) मुद्रा कहलाने के लिए किसी भी वस्तु को विस्तृत धोखे में, विनिमय माध्यम के रूप में, स्वीकृत होने आवश्यक है, जिसका अर्थ यह है कि भारी सत्याम लोग उसे वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।⁴

—पीगू

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ये परिभाषाएँ इस तथ्य पर बल देती हैं कि निरर्थक प्रति के लेन-देन प्रयोजन तथा ऋणों के भुगतान के लिए निरर्थक रूप से स्वीकार की जाने वाली वस्तुओं को मुद्रा कहते हैं। 'परन्तु इन परिभाषाओं में भी एक कमी' है। ये केवल वर्तमान पर ही बल देती हैं जबकि मुद्रा को तीनों कालों—भूत, वर्तमान तथा भविष्य—में स्वीकृत व ग्राह्य होना चाहिए। क्योंकि कौचित्त व रोबर्टसन जैसे अनेक अर्थशास्त्री मुद्रा को 'ऋण सम्बन्धी सौदे (Debt Contract) व व्यापारिक दायित्व (Business Contracts) मानते हैं। इन परिभाषाओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि ये मुद्रा के गहरे आवश्यक कार्यों पर (जिन पर सामान्य स्वीकृति आधारित या जिनसे प्रभावित होती है) समान रूप से दृष्टान्त नहीं डाला गया है। मुद्रा की ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जिसमें मुद्रा के समस्त कार्य और उसने स्वरूप का वर्णन किया गया हो। सम्भवतः मुद्रा की यह परिभाषा हो सकती है—

“मुद्रा वह पदार्थ है जिसको जनता भूत वर्तमान तथा भविष्य के भुगतानों के लिए मुक्त-रूप से स्वीकार करती है और मातृकीय मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ वह मूल्य मापक व मूल्य-मापक भी होती है।”

मुद्रा की परिभाषा से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोण (Different Views Regarding Definition of Money)

मुद्रा की जो परिभाषाएँ सग्रहीत की गई हैं उनके अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुछ परिभाषाएँ बहुत व्यापक हैं तथा अन्य कुछ परिभाषाएँ बहुत संकुचित हैं।

1. 'D H Robertson defines money as "Anything which is widely accepted in payment for goods, or in discharge of other kinds of business obligations" —Robertson
2. 'Money is anything that is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value —Kent
3. Money is anything that passes freely from hand to hand as medium of exchange and is generally received in final discharge of debts —Ely
4. "In order of anything to be classed as money, it must be accepted fairly widely as an instrument of exchange, which means that a good number of people are ready to accept it in payment for goods and services provided by them." —Pigou

साधानों के उत्पादन के लिए सैती खरीदना, लाभ अर्जित करने की दृष्टि में मूल्य-मूल्य अथवा प्रतिभक्तियों को खरीदना इत्यादि। वह लोग जो इन परिणामस्थितियों में धन नहीं लगाते और भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण अपने धन को मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह इस धन का उपयोग आसानी से तथा इच्छानुसार कर सकें। भावी प्रत्याशाओं का हमारे वर्तमान निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग परिणामस्थितियों की अनिश्चित प्रवृत्ति के कारण मुद्रा में अपने धन को संचित रखते हैं।

(ब) भावी भुगतानों का आधार (Standard of Deferred Payments)—मुद्रा की सामान्य स्वीकृति और जनता के विश्वास के कारण मुद्रा में भविष्य के भुगतानों की सुविधा प्रदान की है। अब कुछ स्थितियों में सोदे वर्तमान में लिए जाते हैं और उनका भुगतान भविष्य में किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में साख की सुविधा प्रदान करने हमारे विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम मुद्रा को वर्तमान आर्थिक प्रगति की आधारशिला कहें तो अनुचित न होगा। मुद्रा समाज में वर्तमान भुगतानों को ही सम्पन्न करती है साथ में भावी भुगतानों का आधार भी है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु बन गई है जिसमें भविष्य में होने वाले भुगतानों का हिमाय विताय रखा जाता है। जिससे कि ऋण तथा ऋणदाता दोनों में से किसी की हानि न हो। आयु-निक युग में अधिकांश लेन-देन व्यापारिक क्षेत्र में स्पष्ट भुगतानों के रूप में होता है जिसमें मुद्रा के इस कार्य का महत्व और भी अधिक हो गया है।

(ग) मूल्य शक्ति का हस्तान्तरण (Transfer of Value)—मुद्रा में मूल्य शक्ति के हस्तान्तरण की सुविधा प्रदान की है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को यह हस्तान्तरण कार्य मुद्रा ने ही सम्भव बनाया है। इस कार्य को सम्पन्न करने मुद्रा ने विनिमय को व्यापक बनाया है। यदि मुद्रा में मूल्य शक्ति के हस्तान्तरण की सुविधा न होती तो समाज की आर्थिक प्रगति का चक्र भी रुक गया होता। वर्तमान समय में साथ मुद्रा तथा वैकिंग सुविधाएँ, उद्योग, तथा व्यापार और यातायात के साधन उपलब्ध न हुए होते तो समाज प्रगति नहीं कर सकता था।

मुद्रा तथा साथ मुद्रा में मूल्य अंतरण को एक स्थान से दूसरे स्थान करने तथा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करके मनुष्य को बहुत बड़े अनुविधाओं से नवा दिया है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति कुछ धनराशि का अंतरण कानपुर से बम्बई करना चाहता है तो वह व्यक्ति कानपुर की किसी बैंक में यह धनराशि जमा करे बैंक द्रापट बनवा कर अपना बैंक द्वारा भेज सकता है और बम्बई में प्राप्तकर्ता व्यक्ति को वह धनराशि मिल जाएगी। द्रापट बनवाने में उसे बहुत थोड़ा-सा शुल्क ही देना पड़ता है। यदि भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है तो बैंक भुगतान में थोड़ा ही धनराशि ही व्यय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार एक व्यक्ति जहाँ धनराशि के लेन-देन की अनुविधा से बचन के लिए बैंक द्वारा भुगतान सेते और देते रहते हैं। इस प्रकार मूल्य शक्ति के हस्तान्तरण की यह सुविधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागी धनराशि को ले जाने के जोरिम से मुक्ति प्रदान करती है। व्यापारिक क्षेत्र और विविधित देशों में ऐसी भुगतान करने की एक परम्परा-नी बन गई है। यह कार्य मुद्रा ने ही सम्भव बनाया है।

(3) मुद्रा के आकस्मिक कार्य—मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्न प्रकार से वर्णित किए जाते हैं

(अ) साख का आधार (Basis of Credit)—मुद्रा में मूल्य का आधार दोनकर देश की वैकिंग, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अक्षुण्ण तदा की है। अब हम मुद्रा में अधिक मात्रा मुद्रा को मूल्य देने लगे हैं। विविधित देशों में तो मांग-मुद्रा का प्रचलन

बहुत अधिक बढ़ गया है। आज के युग में बैंक धनी प्राथमिक जमाओं से कहीं अधिक धनराशि की मांग मुद्रा निर्गमित करके व्यापारिक तथा औद्योगिक क्रियाओं के विस्तार और उन्हें सुविधापूर्वक सम्पन्न करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। आज स्थिति यह है कि यदि मांग मुद्रा के गृहण में निर्भीक प्रकार का व्यवहार उपस्थित हो जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था तात्कालिक रूप से प्रभावित होती है। आज विभिन्न देशों में राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रयत्नियों और कर्मचारीय योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि जुटाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जो मांग-मुद्रा हमारे लिए आज इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है उस मांग-मुद्रा का आगार वैधानिक मुद्रा ही है।

(घ) सामाजिक आय का वितरण (Distribution of Social Income)—वर्तमान वैज्ञानिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा सामाजिक आय की उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के मध्य बँटवारा करने का सर्वोत्तम पैमाना है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का उसी योग्यता और श्रम के आधार पर मुद्रा के रूप में मूल्यांकन करके समुचित बिया जा सकता है। वर्तमान समय में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़े पैमाने पर किया जाता जिसमें बहुत से मनुष्य सहयोगी उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार जो भी उत्पादन होता है उसमें असंख्य लोगों का योगदान होता है और उनका वितरण भी सभी साधनों के मध्य होना चाहिए। सभी उत्पत्ति के साधनों की योग्यता और कुशलता एक-ही नहीं होती और न ही उनका उत्पादन स्तर एक-सा होता है। मुद्रा के उत्पत्ति के साधनों के मध्य उत्पादन के बँटवारे की इस जटिल समस्या का समाधान कुशलपूर्वक बिया है। सामूहिक रूप से उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचकर एक उत्पादक द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के मध्य बाँट दिया जाता है और सामूहिक उत्पादन में प्राप्त आय का बँटवारा आभासी से हो जाता है। मुद्रा ने सहयोगी साधनों के मध्य सामाजिक आय के वितरण को गरल बनाकर समाज में बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

(ग) सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादकता में समानता का आधार—(Basis of Equalising Marginal Utility and Marginal Productivity)—मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं और उनके पास साधन सीमित होते हैं। एक उपभोक्ता की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य के सामने सीमित साधनों के कुशलतम प्रयोग में इन आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाय जिससे कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकतम सन्तुष्टि के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। यह उस समय सम्भव हो सकता है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय की जाने वाली अंतिम इकाई से सीमान्त उपयोगिता समान हो जाए। मुद्रा ने उपभोक्ता को द्रव्य रूपी इकाईयों द्वारा सीमान्त उपयोगिता की समानता का माप सम्भव बनाया है और उपभोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि का लक्ष्य अपने सीमित साधनों द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की प्राथमिकताएँ निर्धारित करके तथा उनकी मात्रा के उपयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार एक उत्पादक के लिए भी उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के साधनतम अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने में मुद्रा महाका प्रदान करती है। एक उत्पादक उत्पत्ति के साधनों पर व्यय की जाने वाली अंतिम इकाई से उत्पत्ति के साधनों की सीमान्त उत्पादकता में समानता स्थापित करके न्यूनतम लागत का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

(द) पूँजी की सामान्य रूप प्रदान करने का आधार (Basis of Providing General form of Capital)—मुद्रा ने सभी प्रकार की पूँजी तथा सम्पत्ति को सामान्य रूप प्रदान किया है। अब माँग मुद्रा के रूप में बचन करके अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मुद्रा में गतिशीलता तथा नकदी प्रवृत्ति के कारण मुद्रा को निर्भीक

पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। जिस प्रकार हम पानी को ठोरे या गाल बर्तन में रखें, पानी उसी रंग का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार मुद्रा भी उस वस्तु का रूप धारण कर लेती है जिसमें हम उसे बदलना चाहते हैं अर्थात् मुद्रा द्वारा हम अपनी इच्छा-मुताबक वस्तु को व्यय कर सकते हैं। मुद्रा से संचित धन तथा पूँजी को किसी भी कार्य के उपयोग में लाया जा सकता है।

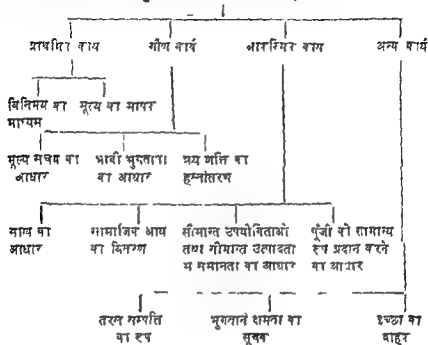
(4) मुद्रा के अन्य कार्य—कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के वर्णित उद्देश्य वार्यों के अतिरिक्त कुछ और कार्य भी बतलाए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(अ) तरल सम्पत्ति का रूप (Form of Liquid Wealth)—प्रो० जे० एम० कीन्स (Prof J M Keynes) ने मुद्रा के इन कार्य को विशेष महत्व दिया है। प्रो० कीन्स का कहना है कि मुद्रा मनुष्य के पास उपलब्ध सम्पत्ति का सबसे तरल रूप है। प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म की अपनी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे मुद्रा सर्वोत्तम परि-सम्पत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की समय-समय पर पूर्ति के लिए अन्य परिस्थितियों के बजाय मुद्रा में संचित करना उचित समझता है। भविष्य अनिश्चित होता है और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति में दूरदर्शिता का गुण होता है। भविष्य की अनिश्चितता तथा दूरदर्शिता की मात्रा को देखते हुए व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आय के कुछ भाग को नकद मुद्रा के रूप में रखता है। इस प्रकार वह इस नकदी से अर्थात् मुद्रा की तरल परिस्थिति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। तरल मुद्रा के बजाय वह जहाँ आय को किसी अन्य परिस्थिति में रखे तो आवश्यकता पड़ने पर वह अन्य परिस्थिति को बेचकर मुद्रा में परिवर्तित करके ही अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है। ऐसा करने में उसे तार्कालिक रूप से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव होगा। इस-लिए मुद्रा रुपी इवाइस द्वारा वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।

(ब) भुगतान क्षमता का सूचक (Guarantor of Solvency)—मुद्रा के इस कार्य का उल्लेख विशेष रूप से प्रो० आर० पी० केंट (Prof R P Kent) ने किया है। वह कहते हैं कि मुद्रा समाज में व्यक्तियों को ऋण भुगतान करने की शक्ति प्रदान करती है। एक व्यक्ति उसी समय तक ऋण चुकान में समर्थ हो सकता है जब तक उसके पास मुद्रा है। जब वही भी मुद्रा रुपी परिस्थिति व्यक्ति या फर्म के पास समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति या फर्म का दिवाला जिया जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति या फर्म अपनी भुगतान करने की क्षमता बचाए रखने के लिए अपनी आय अपना मापना या एक भाग नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं।

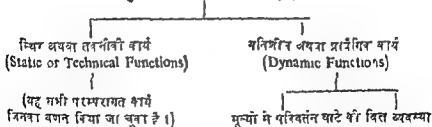
नही हा गव ती त्पारि मुद्रा ती विगी वस्तु म विगी गमय पत्रिबित्त तिया जा गवता हे जवकि अन्य तिसी वस्तु म व्यागानी से वदन पाना कठिन बाय हे । मुद्रा न मनुष्य को इग प्रकार अपन भावी निषया का त्रियावित्त वरन म भूहृत्पूषं भूमिका प्रदान की हे । मुद्रा के उपर्युक्त कार्यो को हम निम्न चट द्वारा प्रस्तुत कर सवते हे—

मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण (I)



मुद्रा के कार्यो का एक अन्य वर्गीकरण अथवा पॉल इन्जिग, (Paul Einzig) का वर्गीकरण

मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण (II)



मुद्रा के स्थिर तथा गतिशील कार्यो का वर्गीकरण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल इन्जिग (Paul Einzig) ने किया है । उन्होंने मुद्रा के स्थिर कार्यो का अर्थ उा सभी कार्यो में किया है जो व्यवस्था का संचालन तो करते हैं परन्तु उसको गति प्रदान नहीं करते । इन कार्यो में मूल्य रूप में के विनियम का माध्यम, मूल्य मापन, स्थिति भुगतानों का मान मूल्य मंचय के कार्य आते हैं । इन्हें अतिरिक्त वे सभी कार्य भी शामिल किए जा सकते हैं जिन्हें मुद्रा पढ़ने से करनी वा रही है ।

मुद्रा के प्राथमिक या गतिशील कार्यों में ऐसे कार्यों को स्थिर रिया जाता है जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। इन कार्यों में मुख्य रूप से मूल्य स्तर को प्रभावित करना एवं घाटे की वित्त व्यवस्था रूपी कार्य जाते हैं।

(1) मूल्यों में परिवर्तन (Changes in the Value)—वर्तमान गतिशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मूल्य स्तर को प्रभावित करना है। अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव अर्थात् मुद्रा एवं स्फीति का न में मुद्रा अर्थव्यवस्था को समुचित गति प्रदान करती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का वातावरण उत्पन्न होता है तो सरकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके पूँजी विनियोजन को बढ़ाती है तथा बैंकों द्वारा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को सस्ती साख उपलब्ध कराती है। इसका मिला-जुला परिणाम यह होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग बढ़ जाती है। उत्पादन तथा रोजगार का स्तर बढ़ता है परिणामस्वरूप समाज की सम्पूर्ण आय बढ़ती है। वस्तुओं और सेवाओं की माँग समाज में प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाती है जिससे मूल्य स्तर बढ़ता है। मूल्यों में घटोतरी साहसियों को पूँजी विनियोजन बढ़ाने में सहायक होती है। इससे विपरीत मुद्रा स्फीतिक काल में मुद्रा की मात्रा तथा ऋण प्रदान प्रवृत्ति को समुचित करने गृहों में थोड़ी गिरावट वस्तुओं की माँग बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में गतिमान करते हैं।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मूल्यों में स्थायित्व अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है परन्तु मूल्यों में परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक ही होने देना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सर्वदा सचेत रहना चाहिए कि मूल्य न तो इतने बढ़ने पाएँ और न ही कम हो जिससे कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति न आने पाए।

(2) घाटे की वित्त व्यवस्था—पॉल इजिंग ने मुद्रा के गतिशील कार्य में घाटे की वित्त व्यवस्था अपना घाटे के बजट को भी महत्वपूर्ण माना है। वर्तमान समय में सरकार के दायित्व एवं कार्य इतने बढ़ गये हैं कि वह अपनी आम खर्चों से इनको पूरा करने में समर्थ नहीं होतीं सरकार या तो देश के केन्द्रीय बैंक से रकम उधार लेकर या फिर घाटे के बजट बनाकर अतिरिक्त मुद्रा की निकासी का कार्य करती है। सरकार की योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करती है। इस दिशा में देश का केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक तथा अन्य ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कार्यों के उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि मुद्रा समाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मुद्रा के बिना आधुनिक युग में मनुष्य के लिए सम्य जीवन बिताना सम्भव नहीं है। मुद्रा का उपयोग मानव सभ्यता के विकास के लिए निरान्त आवश्यक है।

परीक्षा-प्रश्न

1. मुद्रा के स्थैतिक एवं प्राथमिक कार्यों की व्याख्या कीजिए और एक विभागशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कार्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

(Discuss the static and dynamic functions of money and indicate the importance of the latter in a developing economy)

2. मुद्रा के कार्य बताइए। कागजी मुद्रा यह कार्य कहाँ तक कर पाती है ?

Define the functions of money How far does paper money perform them well.)

3 मुद्रा व मुख्य गौण तथा आवस्मिक कार्यों का वर्णन कीजिए ।
(Discuss the main secondary and contingent functions of money)

4 मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है । व्याख्या कीजिए ।

(Money is what money does Discuss)

[संकेत—सरकारी तथा बैंक द्वारा मुद्रा की व्याख्या कीजिए । मुद्रा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।]

5 मुद्रा के कार्य बताइए । वागजी मुद्रा यह कार्य कहीं तक क्या करती है ?

(Define the functions of money How far does the paper money perform them well ?)

[संकेत—सबसे पहले मुद्रा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए तत्पश्चात् बताइए कि वर्तमान समय में संसार के प्रायः सभी देशों में वागजी मुद्रा ही अपनाई गई है । यह मुद्रा भूत प्रसार संसार की सेवा कर रही है । परंतु ऐसी मुद्रा के पीछे बहुमूल्य धातुओं के साथ ही अभाव में मुद्रा की पूर्ति में तर्जों से युक्ति हुई है तथा मुद्रा के मूल्य में तर्जों से निराशंक आर्थ है जिससे तीसरी दुनिया के देशों में साधन विहीन या अल्प साधन वाले व्यक्तियों के लिए काफी अधिक कठिनाईएँ बढ़ी हैं ।]

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

6 निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत है

(i) मुद्रा मानव आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है ।

(ii) मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य करती है ।

(iii) मुद्रा न सभी प्रकार की पूँजी तथा सम्पत्ति का एक सामान्य रूप प्रदान किया है ।

(iv) मुद्रा के स्थान पर अन्य कोई वस्तु व्यक्ति का खर्चा का कार्य नहीं कर सकती ।

(v) मुद्रा को निम्नी वस्तु में किसी समय परिवर्तित किया जा सकता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

(i) सही है । (ii) सही है । (iii) सही है । (iv) सही है । (v) सही है ।

"Money is the pivot around which the whole economic science clusters."

—Prof. Marshall

अध्याय 13

मुद्रा का चक्राकार प्रवाह एवं महत्व

(CIRCULAR FLOW AND IMPORTANCE OF MONEY)

मुद्रा का चक्राकार प्रवाह (Circular Flow of Money)

मुद्रा की चक्राकार प्रवाह की विशेषता के कारण एक अर्थव्यवस्था में द्राव्यिक भुगतानों का प्रभु निरन्तर बना रहता है। जब उपभोक्ता बाजार में उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रयत्न करते हैं तो उनका भुक्तान वह मुद्रा के रूप में करते हैं और वह मुद्रा कुटकर वस्तु विनिर्माताओं तथा सेवामालिकों के पास पहुँचती है। कुटकर विनिर्माता इस मुद्रा को धोक व्यापारियों अथवा विनिर्माताओं को देते हैं जिनसे कि वह वह वस्तुएँ खरीद करके लाए थे और धोक विनिर्माता इन उपभोग्य वस्तुओं के निर्माताओं अथवा उत्पादकों को देते हैं। निर्माता अथवा उत्पादक को जो इस प्रकार से मुद्रा इकाइयाँ प्राप्त होती हैं वे पुनः इनको उत्पत्ति के साधनों के पारिश्रमिक के रूप में जैसे मजदूरी, मगान अथवा किराया, भ्याज, वेतन तथा लाभ के रूप में बाँट देते हैं। उत्पादकों को जो आय प्राप्त होती है उसका कुछ हिस्सा सरकार के पास करों के रूप में चला जाता है और चक्राकार गति में से बाहर आ जाता है शेष भाग को उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त होता है वही चक्राकार गति का हिस्सा बनकर समाज में आर्थिक क्रियाओं के रूप में निरन्तर गतिमान रहता है।

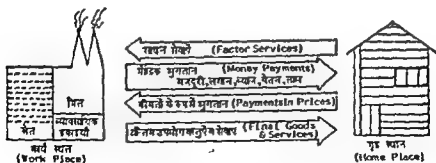
सरकार को जो आय होती है वह उससे द्वारा विभिन्न सेवाओं तथा सुविधाओं के रूप में जैसे प्रशासनिक व्यय, प्रतिरक्षा व्यय, सामाजिक कल्याण सेवाओं और सुविधाओं पर व्यय तथा अन्य रत्याणकारी योजनाओं पर व्यय कर दिया जाता है और पुनः चक्राकार गति में शामिल हो जाता है। इसके अलावा जब सरकार की आय से उगड़ व्यय की पूर्ति नहीं होती तो वह नई मुद्रा की निर्यातों तथा बचतों को बढ़ाती है और नये विनियोगों को करती है। इस प्रकार पूँजी निर्माण तथा नई मुद्रा फिर से चक्राकार गति में शामिल हो जाती है। मुद्रा की इस चक्राकार गति में उच्चावचन अर्थव्यवस्था को अस्थिरता प्रदान करते हैं इसलिए इस चक्राकार गति को सन्तुलन (Equilibrium) में रहना जरूरी होता है जब-जब इस गति में असन्तुलन उत्पन्न हुआ है तब-तब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता एवं अर्थव्यवस्था का वातावरण दिखाई दिया है। विश्व-व्यापी सीमा की मन्दो इस प्रकार की अस्थिरता का उच्चतम उदाहरण है। सीमा की मन्दो ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा पूँजी बाजार को अस्त-व्यस्त कर दिया था। चारों ओर बेरोजगारी, अनि उत्पादन,

बाजारों में स्टॉकों में वृद्धि, उपभोग में विरावट तथा निर्रतता का वातावरण छा गया था। दुनियाँ के अधिकांश देश मन्दी में प्रभावित थे। प्रथम विश्व युद्ध काव में जर्मनी में मुद्रा की चक्रावार गति में तेजी हो जाने से वहाँ अनि स्फीति (Hyper Inflation) की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुद्रा की चक्रावार गति में बिना कोई परिवर्तन हुए अर्थव्यवस्था अतन्तुलन की स्थिति में पहुँच जाती है। ऐसा प्रायः प्राकृतिक प्रयोगों जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के समय दिखाई देता है।

द्रव्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चक्रावार गति से हमारे जीवन की प्रगति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम यह मानूँ चाहिए एक व्यक्ति की दौढ़री भूमिका होती है। एक उपभोक्ता के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग करता है और उसका दूगग रूप उत्पत्ति के साधन के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं की निरन्तर पूर्ति बनाए रखना होगा है। हम यह भली-भाँति जानते हैं कि हम सभी उपभोक्ता भी हैं साथ ही साथ उत्पत्ति के साधन भी। उपभोक्ता की दृष्टि से हम भोजन, वस्त्र तथा सवाव की भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुओं न अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करत हैं। एक कार्यरत व्यक्ति की भाँति हम सभी उत्पत्ति के साधन भी हैं और मरकागी कार्यालयों कारखानों, विद्यालयों, निजी क्षेत्रों व अन्य किसी न किसी व्यवसायों में विभिन्न रूप में सेवाएँ प्रदान करते हैं और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करती रहती है। हम अपनी सेवाओं व बदने में सेवायोजकों से द्रव्य आय प्राप्त होती है जिसका हम विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय करने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाने हैं और अपनी आय के शेष भाग को द्रव्य के रूप में संचित करके भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के निग छोड़ देते हैं।

जिस समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आपमन होता है तो हमके फन्मन्मन् एक लेन-देन कार्य दूगरे लेन-देन कार्य की जगह देता है। उत्पादन सेवाओं की गति का त्रम गृहस्थान (Home Place) से कार्य स्थान (Work Place) जैसे कारखाने, खेन व्यवसायिक दवाइयों आदि की ओर होता है।



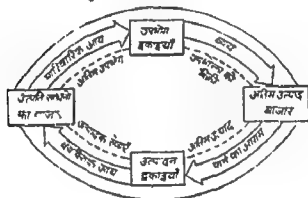
चित्र—(A)

उपर्युक्त चित्र में दिशावा सया है कि हम, अपनी साधन सेवाएँ खेतों, कारखानों अथवा किसी व्यवसायिक दवाइयों आदि में प्रदान करते हैं और इन दवाइयों की आय उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी, लगान, व्याज, वेतन तथा लाभ के रूप में मौद्रिक भुगतानों

के रूप में दे दी जाती है। जिनको पुनः कार्यस्थलों ने उत्पाद की कीमतों के रूप में दे दिया जाता है और अन्तिम उपभोक्ता वस्तुएँ प्राप्त होती है। उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की गति कार्यस्थल से घर की ओर होती है जबकि मुद्रा की गति का प्रभु घर से कार्यस्थल की ओर होता है। एक उत्पादन उत्पत्ति साधनों की सेवाओं की घर से सीधे प्राप्त न करके साधन बाजार (Factor Market) जहाँ यह साधन अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता उपभोग्य वस्तुओं (Consumer Goods) को कार्य स्थल से सीधे प्राप्त न करके वस्तु बाजार (Commodity Market) से जहाँ वस्तुएँ बिनी हेतु प्रस्तुत की जाती हैं प्राप्त करते हैं।

मुद्रा का चक्राकार प्रवाह की स्थिति को निम्नलिखित रेखाचित्र B द्वारा दिखाया जा सकता है।

मुद्रा का चक्राकार प्रवाह



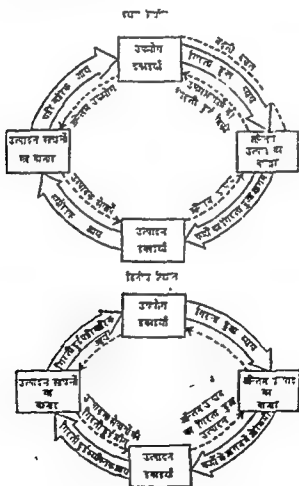
चित्र—(B)

मुद्रा अर्थव्यवस्था में दो विपरीत दिशाओं में बहती रहती है। इसमें से एक धारा ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं की होती है जो अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की उत्पादन क्रियाओं का परिणाम है और दूसरी धारा का सम्बन्ध उन मोद्रिक भुगतानों से होता है जिन्हें उद्योग उद्योगों से प्राप्त होता है। जहाँ अपनी सेवाओं के बदले में उत्पादों के साधनों को मोद्रिक पारिधमिक मिलता है। स्पष्ट है कि उत्पादों के साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसका उपयोग वे साधारण बचत तथा अन्य उपभोग्य वस्तुएँ (Consumer Goods) बाजार से खरीदने में व्यय करते हैं। बाजार के दुबानदार (पूटकर तथा बीच व्यापारी) कारखाना या उत्पादन केन्द्रों से वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और उपभोक्ताओं तथा पँकड़ी के बीच एक मध्यम (Mediator) के रूप में कार्य करते हैं।

मुद्रा अर्थव्यवस्था में जब इस प्रकार की दोनो विपरीत धाराओं में परस्पर समानता रहती है तभी अर्थव्यवस्था में स्थिरता का वातावरण पाया जाता है। जिससे आय तथा उत्पादन दोनों ही में स्थिरता पाई जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह (Circulation of Money) में बढ़ि हो जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि जिस अनुपात में मुद्रा

प्रवाह में वृद्धि हुई है उसी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो जाए। ऐसी स्थिति को स्फीतिक स्थिति (Inflationary Stage) कहते हैं। यहाँ धन का कीमता-स्तर उँचा उठने लगता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा प्रवाह में बर्फी हो जाए तो वह जहरी नहीं है कि उसी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में कम हो जाए। ऐसी अवस्था मुद्रा संकुचन अथवा अस्फीति (Deflation) को होती है। हमारे कीमतों में गिरावट, बेरोजगारी और न्यून उपभोग की स्थिति निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन जैसी दोनों बुराइयों से तभी बची रह सकती है जबकि मुद्रा तथा वस्तुओं का विपरीत दायों की गति सम्बन्धन में रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकतानुसार मुद्रा को मात्रा वृद्धि में उपलब्ध रहे।

अर्थव्यवस्था में त्रिग समय तक सम्बन्धन बना रहता है। उस समय तक जाँच प्रयास, जैसे उत्पादन तथा उपभोग का श्रम भी सुचारु रूप में बना रहता है। परन्तु जैन



चित्र (C)

मुद्रा के बदलावर प्रवाह की स्थितियाँ

इस प्रकार हमने देखा कि प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत उपभोक्ता के व्यवहार आंदोलन-गिक विवास आदि के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को मनुष्य के रखने के लिए यह जरूरी है कि मुद्रा के लिए मुद्रा के चक्राकार प्रवाह में परिवर्तन तथा वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में होने वाले परिवर्तन में समन्वय बनाना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के मुद्रा अधिकारी को मुद्रा की पूर्ति में समय-समय पर इस प्रकार परिवर्तन करने चाहिए जिससे कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन उपभोग तथा वितरण में परिवर्तन होने पर उस दिशा में मुद्रा की पूर्ति भी परिवर्तित रहे। उदाहरणार्थ उत्पादन में वृद्धि होने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़े और कम होने पर मुद्रा की पूर्ति में भी कमी हो। ऐसा उर्ध्व स्थिति में सम्भव होगा जबकि मुद्रा के प्रवाह का आकार सरकारी नियन्त्रण में हो। मुद्रा के प्रवाह का आकार दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम मुद्रा की पूर्ति पर दूसरे मुद्रा के वेग पर। मुद्रा की पूर्ति पर सरकार का नियन्त्रण होता है और सरकार को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर इसमें समय-समय पर परिवर्तन करने चाहिए। जबकि मुद्रा का वेग या प्रचलन वेग कभी स्थिर नहीं रहता और इसमें सदा परिवर्तन होत रहते हैं। मुद्रा के प्रचलन वेग को मुद्रा की मात्रा उपभोग प्रवृत्ति नकद सौदों की प्रवृत्ति तरलता पसदगी साम्य सुविधाएँ आय की भुगतान की अवधि तथा भावी कीमत अनुमान आदि जैसे तत्त्व प्रभावित करते रहते हैं। मुद्रा की पूर्ति किसी समय 10,000 करोड़ रुपये है और उसका औसत प्रचलन वेग 5 है अर्थात् एक रुपया प्रति दिन पाँच रुपये की वस्तुओं तथा सेवाओं के भुगतान में प्रयोग में लाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में $10,000 \times 5 = 50,000$ करोड़ रुपये का वर्ष भर में वस्तुओं तथा सेवाओं के भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। यदि अगले वर्ष मुद्रा की पूर्ति हम हजार करोड़ रुपये से बढ़कर बीस हजार करोड़ रुपये हो जाती है और हमारे प्रचलन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक लाख करोड़ रुपये का व्यय कीमती के दुर्गम हान पर ही सम्भव होगा। यदि हम कीमती का स्थिर रहना है तो हम मुद्रा की पूर्ति तथा इसके प्रचलन वेग पर नियन्त्रण रखना होगा।

सरकार तथा गति का आकार—उपर्वत्त मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की गतियाँ के आकार में हमने सरकारी हस्तक्षेप की उपस्था की है। वास्तविकता यह है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों द्वारा अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा उत्पादन के स्तर को प्रभावित करती रहती है जिससे रोजगार तथा आय के स्तर भी प्रभावित होते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा आयिन उसकी मॉड्रिन तथा राजवाणीय नीतियों मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की गतियाँ के आकार तथा उनके प्रवाह पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

सरकार का विभिन्न प्रकार की सहाय, सुविधाएँ, कर्याणकार्य योजनाएँ तथा अन्य कई प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं जिनमें मुद्रा की गति प्रभावित होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए जनता में विभिन्न प्रकार के कर तथा शुल्क आदि वसूल करती है। जब सरकार विभिन्न कार्यों को करने के लिए जनता से कर वसूल करती है तो मुद्रा की मात्रा की गति तथा भुगतान के रूप में जनता की ओर से हटकर सरकार को कर की ओर होती है। जब सरकार करों की आय को विभिन्न प्रकार की मावजनिक सेवाओं जैसे सड़क, पुल, विद्यालयों के निर्माण, प्रशासनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अन्य विवास की योजनाओं पर व्यय करती है उस स्थिति में मुद्रा की गति सरकार की ओर से हटकर जनता की ओर आर्थिका की मजदूरी, वसंचारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, ऋणदाताओं को व्याज, मजदूरी तथा विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों के भुगतान तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों के रखरखाव आदि पर व्यय कर दी जाती है। जब सरकारी व्यय

उमकी आय से अधिक हो जाता है तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की गति के आकार में वृद्धि हो जाती है। इससे विपरीत जब सरकार अपने व्यय में कमी करती है तो मुद्रा की गति में भी कमी आती है। सरकार अपनी आय-व्यय को प्रतिवर्ष बजट के रूप में सार्वजनिक पेश करती है और इसका उद्देश्य जरूरी व्ययों को समायोजित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना होता है। उदाहरणार्थ वेजी बजट में सरकार को अतिरिक्त बजट (Surplus Budget) बनाकर अपने व्यय में कटौती करना चाहिए और मन्दोदाल में घाटे के बजट (Deficit Budgets) बनाकर अपने व्यय बढ़ाने चाहिए जिससे रोजगार तथा आय का स्तर ऊँचा हो सके और मंदी वान में जो कीमत-स्तर में गिरावट आयी है वह समर्थ माँग (Effective Demand) बढ़ने के कारण ऊँचा हो सके। इस प्रकार सरकार अपने बजटों के माध्यम से अर्थव्यवस्था मुद्रा की गति को वांछित दिशा में लाती रहती है।

मुद्रा का महत्व (Importance of Money)

हम सब भलीभाँति परिचित हैं कि हमारे आधुनिक जीवन में मुद्रा एक अतिमहत्वपूर्ण वस्तु है जिसने उपभोग, उत्पादन, विनिमय विवरण तथा राजस्व के क्षेत्रों में गुणम एवं विवसित बनाया है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा एक पहलू नहीं है जो मुद्रा के प्रभाव से अप्रभावित रहे। आर्थिक विकास एवं प्रगति की कल्पना मुद्रा विहीन व्यवस्था में करना सम्भव नहीं है। कार्ल मार्क्स तथा उनके समर्थकों ने समाज में आर्थिक दोषों के लिए मुद्रा को उत्तरदायी मानते हुए दो नमाम्त करने की सिफारिश की थी और इसी के आधार पर रूस जैसे साम्यवादी देश में मुद्रा चान कोलकोविकी के 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद सत्ता में आने पर लिया गया था परन्तु मुद्रा की समाप्ति से बहुत-सी आर्थिक गणनाओं तथा विकास के माग में बाधाएँ उत्पन्न हो गई थी और पुन मुद्रा व्यवस्था को अपनाया गया था। हम याद रखना चाहिए कि मुद्रा के यह दोष मनुष्य विमित हैं और इनसे समाज को रक्षाया जा सकता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ तथा उनके समर्थक विद्वानों ने लेकर आधुनिक विकास। तब मुद्रा से सम्बन्धित दृष्टिकोण मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालने में समर्थ हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व (Importance of Money in a Capitalist Economy)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व अतिमहत्वपूर्ण है। पूँजीवादी व्यवस्था में इसे निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है —

(1) आर्थिक स्वतन्त्रता—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि हमारे अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति चाहें वह उपभोक्ता हो, उत्पादन अथवा साहसों सभी अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं। अपने हितों की सुरक्षा के लिए स्वतन्त्र रूप से निणय लेकर वे अपनी गति की दिशा को निर्धारित करते हैं। यह कार्य मुद्रा द्वारा मुक्त रूप में किया जा सकता है।

(2) कीमत प्रणाली का आधार—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत प्रणाली पर आधारित होती है। कीमत प्रणाली स्वयं मुद्रा द्वारा निर्दिष्ट होती है।

मुद्रा वर्तमान समय में कीमत प्रणाली का आधार है। मुद्रा समाज में उपभोक्ता को दुर्लभ सामानों का निरूपणितार्पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। कीमत-प्रणाली के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरोडों व्यक्तियों के भिन्न निर्णयों के मध्य समन्वय स्थापित होता है। इसके द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन व विशेषता व लाभ प्राप्त होते हैं तथा केन्द्रीय प्राधिकारों के नियन्त्रण के बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, कीमत

प्रणाली के द्वारा ही अव्यवस्था में अधिक प्रियाओं का योग्यता उपभोग-गणियों, प्रोद्योगिक तथा माधनों की प्रति में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम समन्वय होता है।

पूर्वजादी समाज में अधिक क्षेत्र में होने वाले सभी परिवर्तनों का द्रव्य प्रेरणा स्रोत बीमन प्रणाली होता है। समाज में गति बस्तु की माँग में वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप उम बस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उनके उत्पादन में वृद्धि होती है। कीमत-प्रणाली अव्यवस्था में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों की कीमत परिवर्तनों का रूपा देकर उत्पादन में पर्याप्त परिवर्तनों को सम्भव बनाती है। उदाहरणार्थ यदि उभाक्ताओं की गणियों में परिवर्तन हो जाने के कारण किसी दस्तु की माँग में वृद्धि हो जाती है तो उम बस्तु की कीमत में अन्य वस्तुओं की कीमतों की तुलना में वृद्धि हो जावेगी। इससे उत्पादन उम बस्तु के उत्पादन में वृद्धि तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में घटती करेंगे। परिणामस्वरूप अव्यवस्था में उत्पादन में माधनों का उपभोक्ताओं की गणियों के अनुसार पुनर्वितरण सम्भव हो सकेगा। अव्यवस्था में कीमत प्रणाली के माध्यम द्वारा विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में मध्य उत्पादन माधनों का वितरण तथा पुनर्वितरण होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज मूल्य गणियों का आधार है जिसका सम्पूर्ण अर्थतन्त्र निर्देशित होता है।"

(3) अधिक गतिविधियों के लिए आवश्यक—सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ मुद्रा द्वारा ही निर्देशित होती हैं। उत्पादन उपभोग एवं वितरण के क्षेत्र में यह इस प्रकार काम करती है कि प्रत्येक की मशीन में तेल की बिना (Lubricant) की आवश्यकता होती है। उत्पादन में वर्तमान घड़े पैमाने एवं जटिलताओं को मुद्रा में सुचारु रूप में गति प्रदान करती है। धन-विभाजन विनिर्देशन एवं तबलीकी ज्ञान के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक सुगम बनाया है जिसका पूरा श्रेय मुद्रा व्यवस्था को ही जाता है।

मुद्रा द्वारा वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के सभी साधनों का बँटवारा करने में सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक उत्पादन के माधनों का सेवाओं का मूल्योत्पन्न करने उन्हें उचित वितरित करना सम्भव हो गया है।

(4) सातवाँ आधार—पूर्वजादी अव्यवस्था सात पर आधारित होती है। उत्पादन एवं व्ययों के बीच से धन उधार लेकर पक्का मात करीबन है। मान बनाकर के जोर व्यापारियों को उधार पर देकर है। जोर व्यापारी गुटार व्यापारों के लिए उधार देता है और गुटार व्यापारी अपने ग्राहकों के लिए उधार देता है। उधार लेन-देन का यह तम मुद्रा द्वारा गति प्राप्त करता है। उधार की एवं की गई रकम पर व्याज भी मुद्रा ही द्वारा तय होता है। इस प्रकार वर्तमान में एक व्यापारी वित्त का मात देकर गतिविधियों में वित्त का गुप्तता प्राप्त करता है, इसका आधार मुद्रा ही है। इस प्रकार मुद्रा अर्थतन्त्र का आधार है।

(5) पूर्ण निर्माण का साधन—पूर्वजादी अव्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा वचनों को अधिकतम सामग्री योजनाओं में विनियोजित करने के उत्पादन के स्तर का आवश्यकतानुसार आदर्श बिन्दु तक ले जाया जा सकता है। समाज को छोटी-छोटी वस्तुएँ एकत्रित होकर एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं जिनको छोटी-छोटी पूर्ण विनियोजन करने वाली सभी तथा वेको एक अन्य उधार देन वाली सरथाओं द्वारा विनियोजित करने अधिक ज्ञान की गति को बढ़ाया जा सकता है। वस्तु पूर्ण निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होती है जोर में वचनों का मात की जाती है। इस प्रकार मुद्रा पूर्ण निर्माण करने

पूँजी की आवश्यकता का प्रतिपादन है। प्रो० ट्रेसकाट (Prof Trescott) ने कहा कि मुद्रा हमारे अर्थतन्त्र का हृदय नहीं तो रक्त तो अवश्य ही है।

(6) आर्थिक प्रणाली की रीढ़ के रूप में—मूँजीवादी व्यवस्था में हाँ उहाँ करने सभी प्रकार का व्यवस्थापन म मुद्रा न आर्थिक व्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण धनो अंत उत्पादन, उपभोग, निनिमय, वितरण एवं राजस्व आदि का महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया है। आज राज्य का निश्चित आर्थिक नियंत्रण का आधार ही मुद्रा है। अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में मुद्रा का योगदान किसी में छिपा नहीं है।

इतना ही नहीं मुद्रा न मनुष्य के आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ ही सम्पूर्ण अर्थतन्त्र का प्रभावित किया है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व (Importance of Money in a Socialist Economy)

समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व कम नहीं है। कुछ साम्यवादवादी विद्वानों ने मुद्रा के दायाँ को दसते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्त्व के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण एवं संचालन सरकार द्वारा होता है। जिसका उत्पादन किया किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायें मजदूरी के दर तथा हानी चाहिए उपभोग तथा वितरण व्यवस्था तथा वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा होता है। सरकार का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता बल्कि अधिकतम सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का इन विशेषताओं के कारण दस व्यवस्था के समय में मुद्रा का अनावश्यक वस्तु समझा था। निम्नलिखित कारणों से समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा की भूमिका नगण्य मानी जाना रही है—

(1) मुद्रा समाज में शोषण तथा आर्थिक शक्ति के वन्द्यकरण का साधन होता है इसलिए मुद्रा विहीन व्यवस्था अपनाकर इस शोष से बचा जा सकता है।

(2) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा संचालित एवं नियन्त्रित होती है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति तथा व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती इसलिए मुद्रा अनावश्यक होती है।

(3) मोद्रिक व्यवस्था पूँजी निर्माण तथा निजी संचयन का बड़ा साधन है जबकि समाजवादी व्यवस्था में ऐसी प्रणाली का कोई स्थान नहीं होता। सारी सम्पत्ति राष्ट्र की होती है जिस पर एक मात्र अधिकार राज्य का होता है।

(4) समाजवादी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वितीय समझौता के आधार पर करने के पक्ष में होती है न कि स्वतंत्र व्यापार। द्वितीय व्यापार के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मुद्रा प्रणाली द्वारा किया गया विदेशी व्यापार शोषण को बढ़ावा देता है।

प्रमुख साम्यवादवादी प्रो० कार्ल मार्क्स ने मुद्रा का सभी बुराईयाँ का जड़ माना था और कहा था कि मुद्रा समाज में शोषण को बढ़ावा देती है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (The Theory of Surplus Value) उनसे मुद्रा विरोधी अभियान का उत्तम उदाहरण है। मार्क्स ने इस सिद्धान्त के द्वारा यह बनाने का प्रयास किया है कि धर्मियों का उनके धर्म में बराबर का हिस्सा नहीं मिलता और पूँजीपति मजदूरों का मुद्रा रूप में शोषण में जा भुगतान करते हैं यह जानते हुए जानते हुए मजदूरों को बड़ा नुकसान होता है। धर्मियों का शोषण मुद्रा

व्यवस्था में होता है। वह कहते हैं कि धमिका व श्रम को अंकन में मुद्रा आवश्यक है। साम्यवादी व्यवस्था में मुद्रा का अन्त हो जायगा और वस्तुओं का वस्तुओं में आदान प्रदान किया जाएगा। पाल माक्स व विचारों में प्रभावित होकर मन् 1917 में वा-जेविक पार्टी केन में सत्तारूढ़ हुए और जिनके रूप में मुद्राविहीन अव्यवस्था का अगनात का सत्त्व किया। वा-जेविक पार्टी ने सत्ता में आने के बाद सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए रुपये सरकार ने अधिक मुद्रा का निर्यात की। मन् 1918 में मुद्रास्फीति स्थिति में सामान्य रूप धारण कर लिया। मुद्रास्फीति स्थिति पर चार् पान की दृष्टि में सरकार ने मुद्रा समाप्ति की घोषणा की परन्तु कुछ ही महीना बाद रुपये सरकार के सामने बहुत सी गणना सम्बन्धी कठिनाइयाँ आने लगी। आर्थिक योजनाओं के मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति तथा अन्य गणनाएँ बिना मुद्रा में सम्भव नहीं थी। सरकार के सामने मुद्रा के अभाव में बहुत सी कठिनाइयाँ आई। मन् 1921 में महान् शान्तिकारी चरित्र न होने के कारण का मुद्राविहान अव्यवस्था अपनाई का आलोचना करते हुए कहा था वा-जेविक का यह विचार उनके जीवन की महान् भूल थी कि समाजवादी गणना तथा नियन्त्रण की अवधि के बिना साम्यवाद आ सकता है। अक्टूबर 1921 में साम्यवादी विचारक ट्राट्स्की ने (Trotsky) यह घोषणा की थी मुद्रा के बिना आर्थिक योजनाओं की प्रगति का नहीं मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। प्रा० ट्राट्स्का के शब्दों में सरकारी कार्यालयों में बनायी गयी योजनाओं की आर्थिक मापदण्ड वाणिज्य गणनाओं के आधार पर जाँची जानी चाहिए। बिना एक सुदृढ़ मौद्रिक इकाई के व्यापारिक उत्पादन एवं गडबडी हो पड़ेगी।¹ लनिन तथा ट्राट्स्का जैसे महान् साम्यवादी विचारक भी मुद्रा का समाजवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक मानते थे। ट्राट्स्की ने तो यहाँ तक कहा है कि एक समाजवादी व्यवस्था में शक्तिशाली मुद्रा का होना नितान्त आवश्यक है।

एक प्रसिद्ध विचारक प्रा० ए० बी० लर्नर का कहना है कि समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा अनावश्यक नहीं है। वे कहते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में कीमत प्रक्रिया (Price Mechanism) का विशेष महत्व है परन्तु समाजवादी व्यवस्था में भी यह आवश्यक है। उन्हें के शब्दों में किमी भी प्रकार की कठिनाइयाँ गंभीर अव्यवस्था का निम्न कीमत-प्रक्रिया के कुलतत्त्वों के कारण सम्भव होता है।² ए० अन्य मौद्रिक अवशास्त्री जार्ज एन० हॉल (George N Halm) का कहना है कि समाजवादी अव्यवस्था में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं कि यद्यपि उत्पादन के लक्ष्य एवं मानाग्राह ग्राहों

1 The blue prints produced by offices must demonstrate their economic expediency through commercial calculations Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos "

—L. D. Trotsky

2 It is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency without a price—mechanism "

—A. P. Lerner

क्यों न निर्धारित किए जाएँ तो भी इन तथ्यों के अनुसार साधना का गृही प्रारंभ में बंट-
पारा कीमत-प्रणाली के पक्षस्वरूप ही सम्भव होगा क्योंकि इसी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में
रोजगार के उपलब्ध साधनों की उपयोगिता की तुलना की जा सकती है ।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है ।
बिना मुद्रा को अपनाए हुए हम अर्थव्यवस्था को सूचारु रूप से चला नहीं सकते । वर्तमान
समय में इस चीन तथा अन्य कई समाजवादी देशों का उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ
कि एक शक्तिशाली मुद्रा इकाई अपनायी जा रही है और वहाँ आर्थिक शोषण तथा आर्थिक
शक्ति का केन्द्रीयकरण का अभाव पाया जाता है । वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण
व्यवस्था राज्य के अधीन है और वहाँ फिर भी विनिमय का माध्यम तथा हस्ताक्षर-विताव
की इकाई के रूप में मुद्रा कार्य कर रही है । उत्पत्ति के साधना का पारिश्रमिक मुद्रा के
रूप में जाना जाता है आर्थिक स्वतन्त्रता जो भी है वह राज्य के नियमों के अधीन है ।
राष्ट्रीय वेतन नीति के अनुसार तथा अधिकतम वेतनों की दृष्टि से निर्धारित है । रंग तथा धीन
जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक साधनों का बंटपारा कीमत-प्रणाली
(Price-Mechanism) द्वारा नहीं होता फिर भी मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मुख्य
मापन का कार्य करती है ।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व किसी भी प्रकार में कम नहीं है । इससे
कुछ अपवाद समाजवादी व्यवस्था में हो सकते हैं जिनसे यह अर्थ बचापि नहीं लगाना
चाहिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मुद्रा को अपनाए बिना काम कर सकती है ।
प्रसिद्ध मौद्रिक अर्थशास्त्री जॉर्ज एन. हॉम (George N. Halm) ने ठीक ही लिखा है
कि "सामाजिक अर्थव्यवस्था सदैव एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था होती है और सम्भवतः ऐसी
ही रहेगी ।"

प्राचीन एक परिवर्तित निश्च प्रणाली हम बात का जखत उदाहरण है कि भले ही
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था साम्यवादी हो या पूँजीवादी या फिर एक नियोजित मुद्रा
के अभाव में अर्थव्यवस्था को सूचारु रूप से चलाना सम्भव नहीं है । यह सही है कि एक
समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उतना महत्व नहीं है जितना कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
में होता है परन्तु फिर भी समाजवादी व्यवस्था मुद्राबिहीन अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती ।
एक अन्य स्थान पर प्रो० आस्कर लॉन्गे (Prof. Oscar Lange) कहते हैं कि "समाजवादी
अर्थव्यवस्था में मुख्य पद्धति आर्थिक कार्य एवं व्यापारों के कुशल मापन निर्देशन का कार्य
करती है किन्तु जब तक मूल्य मुद्रा के अभाव में प्रकट न किए जाएँ तब तक मूल्य पद्धति
निरर्थक रहेगी ।"

एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व (Importance of Money in a Planned Economy)

नियोजित अर्थव्यवस्था का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका संचालन पूर्ण
नियोजित कार्यक्रमानुसार किया जाता है । यह अर्थव्यवस्था इस की तरह समाजवादी,
भारत की तरह मिश्रित या फिर किसी प्रकार की पूँजीवादी व्यवस्था हो सकती है । नियोजित

1. "Even if the aims of production should be determined by a dictator the allocation of resources according to these aims would have to be the result of the working of a pricing process by means of which it is possible to compare the usefulness of the available resources in different fields of employment"

—George N. Halm

अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दी जाती हैं और फिर उन्हीं के अनुसार कार्य होता है चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, या उपभोग या अन्य आर्थिक विभाग का हो, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय सहायता की प्राप्ति एवं उनके वितरण का कार्य तथा सरकार की विभिन्न नीतियाँ नियोजित कार्यक्रमों के आधार पर लागू होती हैं। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से भाँपा जा सकता है—

(1) मुद्रा का निर्देशित उपयोग—नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को निर्देशित एवं वांछित दिशा में करने का प्रयोग किया जाता है। देश के केन्द्रीय बैंक एवं अन्य ऋण प्रदान एवं सृजित करने वाली संस्थाओं का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन जल्दी-जल्दी न हो सके और राज्य की नीतियों में जनता का विश्वास बना रहे। प्राथमिकताओं को निश्चित करने उन्हीं के आधार पर कार्य किया जाता है जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास समुचित हो सके।

(2) धन के संवेक्षण पर रोक—ऐसी अर्थव्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों की आय तथा धन के संप्रहण पर भी उचित नियन्त्रण रखने का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि देश की सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में सकेन्द्रित न हो सके। पूर्वी विनियोजन एवं आय सम्बन्धी नीतियाँ इस प्रकार निर्मित की जाती हैं जिनसे शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिल सके तथा वितरण योजना देश के अधिन में अधिन नागरिकों को राहत पहुँचा सके।

(3) विकास में सहायक—नियोजित अर्थव्यवस्था में विभाग-वार्यों की पूर्ति घाट के बजट बनाकर की जाती है। इस प्रकार नई मुद्रा विकास-वार्यों को बढ़ावा देती है।

मुद्रा के दोष (Evils of Money)

हम देख चुके हैं कि वर्तमान समय में चाहे अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो बिना मुद्रा के उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की गति प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा इस प्रकार से काम करती है जैसे कि मशीन को चलाने के लिए चिक्नाई या तेल डालने की आवश्यकता पड़ती है ठीक उसी प्रकार से मुद्रा भी आर्थिक क्रियाओं को मुबारक रूप से चलाने के लिए चिक्नाई का कार्य करती है। यहाँ एवं और मुद्रा में हमारे लिए विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचाये हैं वही दूसरी ओर इसके कुछ दोष भी हैं। मुद्रा के यह दोष मुद्रा के स्वयं के न होकर अनुप्य निर्मित हैं। मुद्रा के बहुत से दोषों से बचा जा सकता है यदि व्यक्ति या समाज मुद्रा का उपयोग एक माध्यम के रूप में करे न कि साध्य के रूप में। मुद्रा तो हम एक सेवक ही मानें इसे स्वामी कभी न बनने दें। जब कभी भी हम अनावश्यक रूप से मुद्रा को महत्व देने लगते हैं या हमारे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक जीवन की क्रियाकलापों का मूल्यांकन जब मुद्रा द्वारा ही किया जाने लगता है तो निश्चित रूप से मुद्रा में दोष हमारे तमस प्रकट होता है। मुद्रा के दोषों को सक्षिप्त रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

(1) मुद्रा ने समाज को दो वर्गों अर्थात् हजूर-मजूर, धनी-निधन (Haves and Have-nots) में बाँट कर एक-दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न की है। धनी वर्ग निधन वर्ग का शोषण अपनी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के कारण करता है। इसके दोष बढ़ता का वातावरण उत्पन्न हुआ है।

(2) मुद्रा ने आर्थिक और राजनैतिक गति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है जिससे नई-नई बुगदयी समाज में उत्पन्न हो रही हैं।

(3) मुद्रा के जान से उधार लेना देना सम्भव हुआ है और लोग अपनी आय से उधार देकर व्यय करने लगे हैं।

(4) मुद्रा ने समाज में स्वीकृत सिद्धियों को जन्म दिया है जिससे कीमती वस्तुओं की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी हुई है और निम्न वर्ग जो पहले बेत काम भोजन से ही गुजारा करना करता है। महेश्वर के अनुपात से मजदूरी या वेतन बढ़ि न होने से लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा है।

(5) मुद्रा ने लोभ लालच भ्रष्टाचार तथा अन्य नैतिक दोष उत्पन्न किए हैं। आज समाज में चोरी, चूकती भ्रष्टाचार गिलाबट बम नाप लौ लाल आदि बुराईयाँ अधिक मुद्रा को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का परिणाम दिखाई देती हैं।

(6) सामाजिक स्तर तथा व्यक्ति के म मान का आधार व्यक्ति के गुणों के स्थान पर मुद्रा ने ले लिया है।

मुद्रा के प्रति लोगों के बढ़ते हुए श्रुति से यह महसूस किया जाने लगा है कि आज समाज में जहाँ मुद्रा ने विकास और प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है वही दुर्गति और मुद्रा के प्रति लोगों का रश्न बहुत अधिक बढ़ गया है। आज सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है मुद्रा के कारण धार्मिक आपसी सौहार्द का वातावरण समाप्त होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ के आगे किसी का भी बर् से बड़ा मुकसस करने में नहीं हिचकिचाते हैं। मुद्रा जो अर्थोपेक्ष के रूप में मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण आविष्कार मानी जाती है मनुष्य जाति की बड़ी सेवा की है परन्तु आज के भौतिकवादी युग में मुद्रा के प्रति लोगों के बढ़ने के रश्न और मुद्रा की आवश्यकता से अधिक महत्व देने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि मुद्रा हमारी र्थाभिनी बन गई है। मुद्रा के दोष मुद्रा की स्वामिनी रूप का ज्वलत उदाहरण है।

मुद्रा का नियन्त्रण - मुद्रा के बतए गए उपर्युक्त दोष मुद्रा के स्वयं के नहीं हैं परन्तु यह दोष तो मुद्रा की आवश्यकता से अधिक महत्व देने तथा इन्में दुरयोग के कारण उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य जाति के लिए मुद्रा की एक बरदान के रूप में स्वीकार करते हुए तथा इसके अनियन्त्रित होने पर मनुष्य के लिए अधिशाप बतते हुए प्रो० राबर्टसन (Prof Robertson) का कथन उपर्युक्त ही प्रतीत होता है। वे कहते हैं मुद्रा जो मानव समाज के लिए अनेक बरदानों का स्रोत है, यदि इस पर नियन्त्रण न रखा जाए तो यह सकट और अपदस्था का कारण भी बन सकती है।¹

प्रो० राबर्टसन के उपर्युक्त कथन का अर्थ यह है कि यदि हम मुद्रा की मनुष्य जाति का बरदान ही माने रहने देना है तो हम इसकी नियन्त्रित करना चाहिए। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक प्रो० वाल्टर बेगहोट (Prof Walter Bagehot) ने भी मुद्रा पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका कहना था कि मुद्रा स्वयं अपनी व्ययस्था नहीं कर सकती इसलिए मुद्रा अधिकांश को समय-समय पर देश की आवश्यकता-मुसार इसकी प्रति रखनी चाहिए। जिस समय दुनिया के विभिन्न देशों ने स्वयंमान तथा रजतमान अपना रखा था उस समय मुद्रा की प्रति में परिवर्तन देश के व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होते थे वरन् स्वयं तथा रजत धातुओं की उपलब्धि के अनुसार इनमें परिवर्तन हुआ करते थे। इन धातुओं की मात्रों मिलने पर इनकी प्रति बढ जाती थी परिणाम-

1 'Money which is a source of so many blessings to mankind becomes also unless we can control it a source of peril and confusion'

—D. H. Robertson

स्वयं इनका वनन या भी मुद्राओं की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती थी। वर्तमान समय में मुद्रा अधिराशत पत्र-मुद्रा है जिसका स्वरूप तथा स्वरूप से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। आज के विकासवादी या प्रगतिशील युग में मुद्रा का उपयोग बहुत बढ़ गया है। मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन (Fluctuations) को रोकने का दायित्व देश के मुद्रा अधिकारी और वहाँ के केन्द्रीय बैंक पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके मूल्य में गिरावट (मुद्रा-स्फीति) तथा इसके मूल्य का बढ़ना (अनस्फीति) दोनों ही स्थितियाँ समाज के लिए घातक हैं और इनसे तभी बचा जा सकता है जबकि मुद्रा की पूर्ति इसके मूल्य में स्थिरता बनाए रखे। बढ़ते हुए मतिरवादी युग में जहाँ मुद्रा ने मनुष्य जाति के लिए अनन्त सुविधाएँ जुटाई हैं वही हमारी ओर इसके अनियन्त्रित प्रयोग से नैतिक और सामाजिक नुकसान में गिरावट आई है। मुद्रा के दोषों में सबसे बड़ा सही तरीका यही है कि हम इस नियन्त्रण में रहें और हमको उतना ही महत्व दें जितनी कि आवश्यकता है।

परीक्षा-प्रश्न

1. एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चक्राकार प्रवाह से क्या समझते हैं? रेखा चित्र द्वारा चक्राकार प्रवाह की स्थितियों को समझाएँ।

(What do you understand by the circular flow of money in an economy? Explain the stages of circular flow of money through diagrams)

2. अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रवाहों तथा मौद्रिक प्रवाहों में विभेद कीजिए। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के सुचारु रूप में संचालन के लिए मौद्रिक प्रवाह क्या आवश्यक है?

(Distinguish between Real Flows and Money Flows in an economy. Why are the money flows considered essential for the smooth working of modern Economics?)

[संकेत—अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाहों तथा मौद्रिक प्रवाहों की चर्चा कीजिए। प्रवाह की स्थितियों को चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अतः मौद्रिक प्रवाहों की बढ़ती हुई आवश्यकता को बताएँ।]

3. एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है? पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से यह किस प्रकार भिन्न है?

(What is the role of money in a Socialist economy? How is it different from that in a Capitalist economy?)

4. 'मुद्रा एक अच्छा सेवक किन्तु बुरा स्वामी है।' इस कथन की व्याख्या कीजिए।

("Money is a good servant but a bad master" Explain this statement)

[संकेत—मुद्रा के लाभ एवं दोषों को बताएँ।]

एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को बताएँ।

(Discuss the importance of money in a planned economy?)

स्तुतिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

6 निम्नलिखित प्रश्नों में सही और गलत बताइए—

- (i) द्रव्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चक्रावार गति से हमारी इकत का चिनिष्ठ सम्बन्ध है ।
- (ii) मुद्रा की चक्रावार प्रवाह की गति में बाधा उत्पन्न होत से गमयते अर्थ-व्यवस्था सङ्कटाङ्ग जाती है ।
- (iii) मदी के समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चक्रावार गति बढ़ती है ।
- (iv) मुद्रा सिहीन अर्थव्यवस्था वर्तमान युग में सम्भव है ।
- (v) मुद्रा का दोष स्थिति के न होकर अनुप्य निमित्त है ।

स्तुतिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है । (ii) सही है । (iii) गलत है । (iv) गलत है । (v) सही है ।

‘When we say that the value of a thing depends on supply and demand, we do not or at any rate ought not to mean more than that we think it will be convenient to arrange the causes of changes in value under those two heads
—Cannon

अध्याय 14

मुद्रा की पूर्ति तथा माँग

(THE SUPPLY AND DEMAND FOR MONEY)

अर्थशास्त्र में माँग और पूर्ति एक सामान्य सिद्धान्त है जिसका मूल्य निर्धारण सिद्धान्त में विशेष महत्व है। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी माँग से बढ़ जाती है तो उस वस्तु का मूल्य गिरता है और जब वस्तु की माँग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है। माँग और पूर्ति का यह सामान्य सिद्धान्त जब मुद्रा पर लागू किया जाए तो इसको मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त कहा जाता है। हम मुद्रा की माँग और पूर्ति मुद्रा मूल्य निर्धारण अथवा मुद्रा परिमाण सिद्धान्त, से पहले अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) की व्याख्या मुद्रा की माँग और पूर्ति पर निर्भर करती है।

मुद्रा की माँग (Demand for Money)

मुद्रा की माँग मुद्रा को प्राप्त करने के लिए नहीं बरन् इसलिए की जाती है कि यह मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अथवा इसकी माँग मुद्रा द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होती है। मुद्रा तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है, साध्य नहीं। मुद्रा की माँग बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान अथवा प्रय-विप्रय से सम्बन्धित होती है। मुद्रा की माँग निम्नलिखित कारणों से घी जाती है—

(1) विनिमय के माध्यम के लिए मुद्रा की माँग—परम्परावादी अर्थशास्त्रियों (Classical Economist) के दृष्टिकोण से मुद्रा की माँग केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए ही होती है। मुद्रा की माँग केवल इसलिए की जाती है कि उसमें प्रय-शक्ति की क्षमता होती है जिसके द्वारा बाजार से वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। मुद्रा की माँग प्रत्यक्ष न होकर व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) होती है। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की माँग उसमें निहित वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रय करने की क्षमता है। इस प्रकार मुद्रा की माँग का निर्धारण वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति द्वारा होता है। यदि किसी समय समाज के अन्दर लेन-देन अथवा विनिमय के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति बढ़ जाती है तो इससे आदान-प्रदान के लिए मुद्रा की माँग भी बढ़ जाएगी इससे विपरीत यदि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति गिर जाती है तो मुद्रा की माँग भी कम

हो जाएगी। यदि हम ऐसा मान लें तो हमें पता चलता है कि किसी देश में एक निश्चित समयवाचधि में विनिमय के हेतु उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा मुद्रा की माँग का निर्धारण करती है। इस प्रकार मुद्रा की माँग तीन बातों पर निर्भर करती है (i) वर्तमान समय में उत्पादन से प्राप्त होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य (ii) अन्तिम वस्तुओं का उत्पादन मूल्य (iii) उन वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जो भूतकाल में उत्पादित की गई थी अथवा जो वक्तमान में भी उपलब्ध हैं।

एक समयवाचधि में विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की पूँति अनेक बातों से प्रभावित होती है जैसे उत्पत्ति के साधनों की स्थिति उत्पत्ति के साधनों के रोज-गार की मात्रा उत्पत्ति के साधनों की कार्य-क्षमता अथवा दक्षता तथा तकनीकी ज्ञान उत्पत्ति का पैमाना (Scale of Production) उत्पादन तथा उपभोग में अन्तर, वस्तुओं के हस्तान्तरण की गति तथा बाजार की स्थिति आदि। इससे अतिरिक्त जनसंख्या का आकार, प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति, मुद्रा की पूँति तथा लोगों की आय आदि भी मुद्रा की माँग को प्रभावित करते हैं। मुद्रा की माँग अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं संरचना द्वारा भी तय होती है। एक अर्द्धविकसित देश में मुद्रा की माँग विकसित देश की अपेक्षा घम होगी। मुद्रा की माँग से सम्बन्धित उपर्युक्त कारण अल्पकाल में स्थिर रहते हैं इसलिए अल्पकाल में मुद्रा की माँग भी स्थिर रहती है। इस प्रकार अल्पकाल में विनिमय के माध्यम के लिए मुद्रा की माँग स्थिर प्रवृत्ति की ओर सकेत करती है। प्रो० इरविंग फिशर (Prof. Irving Fisher) ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की ध्याय्या मुद्रा के विनिमय माध्यम के कार्य से प्रभावित होकर की है। प्रो० फिशर भी प्रतिष्ठित अथवा परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के विचार से प्रभावित होकर की मुद्रा माँग से सम्बन्धित मान्यता अर्थात् मुद्रा की माँग वस्तुओं तथा सेवाओं की पूँति पर निर्भर करती है। परन्तु प्रतिष्ठित विद्वानों तथा प्रो० फिशर की यह मान्यता एक पक्षीय है क्योंकि मुद्रा की माँग भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तथा सट्टे से लाभ अर्जित करने के लिए भी की जाती है।

नकदों के लिए मुद्रा की माँग²—प्रो० फिशर की मुद्रा की माँग सम्बन्धित आलोचना को करते हुए कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों तथा कुछ आधुनिक विद्वानों को कहना है कि मुद्रा की माँग मुद्रा के विनिमय के माध्यम कार्य की सम्पन्न करने के लिए ही केवल नहीं की जाती वरन् मुद्रा की माँग उनके एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य मूल्य संचय (Store of Value) के लिए भी की जाती है। इन विद्वानों की मान्यता है कि मुद्रा की माँग एक निश्चित समयवाचधि में लोगों द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय आय में से नकदी रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की माँग का अर्थ नकद शेष (Cash Balances) से लगाया जाता है। हम यह याद रखना चाहिए कि जब कभी मुद्रा की माँग विनिमय माध्यम कार्य के लिए की जाती है तो इसका सम्बन्ध मुद्रा के चलन वेग (Velocity) तथा सभी प्रकार के लेन-देन से होता है जबकि नकद शेष के रूप में मुद्रा की माँग तथा उसके चलन-वेग का सम्बन्ध केवल उन वस्तुओं के विनिमय से होता है जो एक देश की कुल वास्तविक आय में शामिल होती है। इस प्रकार चलन वेग की आय-चलन वेग (Income Velocity of Circulation) की सजा दी जाती है। इसमें स्पष्ट है कि आय चलन वेग का आधार लेन देन चलन वेग की अपेक्षा छोटा होता है।

उपर्युक्त दोनों स्थितियों में मुद्रा की माँग की ध्याय्या हमें यह बताने में सहायता प्रदान करती है कि मुद्रा की माँग समाज में लोगों द्वारा विभक्त की जाती है। परन्तु इन दोनों उद्देश्यों के लिए की गई मुद्रा की माँग जिस उद्देश्य के लिए कितनी है अर्थात् मुद्रा की कितनी माँग लेन-देन के उद्देश्य (प्रतिष्ठित तथा प्रो० फिशर के दृष्टिकोण से)

तथा मुद्रा की रितनी माँग उनके मूल्य सचय कार्यों (प्रो० रैम्ब्रिज तथा आधुनिक सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से) के लिए की जाती है।

मुद्रा की माँग को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं—

$$M = M_1 + M_2$$

M = मुद्रा की कुल माँग

M_1 = मुद्रा की माँग जो कि लेन-देन तथा गतवृत्ता उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है।

M_2 = मुद्रा की माँग जो पट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है।

मुद्रा की माँग से सम्बन्धित मिल्टन फ्रीडमैन की व्याख्या—अर्थव्यवस्था में मोनेन पुरस्कार विजेता शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा की माँग का आशय जनता के पास संचयित मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के विदेशी कोष एवं उनके चलन-योग से लिया है। उनका कहना है कि मुद्रा की माँग और मूल्य-स्तर का विपरीत सम्बन्ध होता है। अर्थात् जब मूल्य-स्तर बढ़ेगा तो मुद्रा की माँग (नगदी प्रवृत्ति) भी बढ़ जाती है वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने पास नकद मुद्रा रखता एवं आवश्यक प्रिया समझता है। अन्य परिसम्पत्तियों को आगमदायक तथा विलासता सम्बन्धी आवश्यकताओं की भाँति समझता है। आय में वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में परिसम्पत्तियाँ न बढ़ि होती हैं। परन्तु आय मुद्रा तथा परिसम्पत्तियाँ की मात्रा आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित होती है। प्रो० फ्रीडमैन की मुद्रा की माँग के विचार को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं—

$$M = f\left(P, Y, \frac{1}{P} \frac{dp}{dt}, r_b, r_e, w, u\right)$$

M = मुद्रा की कुल माँग

f = फलन है

P = मूल्य स्तर (Price Level)

Y = कुल राष्ट्रीय आय (Total National Income)

$\frac{1}{P} \frac{dp}{dt}$ = मुद्रा की एक् इकाई के बदले में उपलब्ध भौतिक माल की मात्रा (Quantity

of Material Units Available Against one Unit of Money)

r_b = बाण्ड्स पर मिलने वाली व्याज की दर (Rate of Interest Available on Bonds)

r_e = जशों पर लाभांश (Yields on Equities)

w = सम्पत्तियों का मानवीय सम्पत्ति से अनुपात (Wealth and its Ratio with Human Wealth)

u = उपयोगिता निर्धारित करने वाले वे तत्व जो अभिरचियों तथा प्रापमिवताओं को प्रभावित कर सकते हैं। (Utility Determining Variables which tend to Influence Preferences)

प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि मुद्रा की माँग अर्थव्यवस्था में विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित होती है जैसे व्याज की दर, आय, सम्पत्ति, मूल्य स्तर इत्यादि।

वास्तविक आय M जो परिवर्तन हाते है उसका विनिमय का स्तर प्रभावित होता है जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है। मुद्रा की मांग की लोन आय की मांग की लोन स आधार होती है।

$$\text{अर्थात् } \frac{\Delta M}{\Delta Y} > 1$$

ΔM = मुद्रा की मांग में परिवर्तन

ΔY = वास्तविक आय में परिवर्तन

प्रो० फ्रीडमैन व मुद्रा की मांग के समीकरण से स्पष्ट होता है कि मुद्रा नकदी की मात्रा जिस व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है उसकी आय में परिवर्तन व अनुपात से अधिक होता है। मिस्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा की मांग का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money)

मुद्रा की पूर्ति में वैधानिक मुद्रा अथवा साधारण मुद्रा तथा गलत मुद्रा अथवा ऐच्छिक मुद्रा दोनों ही होती है। एक देश की सरकार की जो मुद्रा होती है उसे सामान्य तथा उस देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकार व आदेश पर निकाला जाता है। सरकार द्वारा निकाली जाने वाली मुद्रा को विधिप्राप्त मुद्रा (Legal Tender Money) कहते हैं। ऐसी मुद्रा को स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। इस मुद्रा में कागजी मुद्रा तथा उसकी सहायक मुद्रा (Token Money) को शामिल किया जाता है। कानूनी मुद्रा व अतिरिक्त साख मुद्रा का भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। यह गलत मुद्रा व्यापारिक बैंकों द्वारा नियमित की जाती है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि साख मुद्रा की स्वीकृति अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होती है। साख मुद्रा का उपयोग साख मुद्रा सृजित करने वाली बैंकिंग तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। ऐसी मुद्रा प्रायः साख नियमित करने वाली संस्थाओं में निहित विश्वास पर आधारित होती है। साख मुद्रा एक प्रकार का ऐसा अधिकार अथवा दावा होता है जिसके आधार पर बैंक से साधारण अथवा कानूनी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार व अधिकार एक दावा को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे साख मुद्रा बैंक मुद्रा, जमा मुद्रा, चेक बुक मुद्रा अथवा प्रतिस्थापित मुद्रा (Credit Money Bank Money Deposit Money, Cheque Book Money or Money Substitutes)। बैंकिंग साख-मुद्रा का प्रयोग भी विनिमय के माध्यम तथा अन्य मुद्रा के कार्यों के रूप में होता है इसलिए इसे भी मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। एक विकसित देश में विरासतीन दान का अंश भाग मुद्रा व चलन की परम्परा अधिक एवं सुविधाजनक समझा जाती है।

बैंक व पास जितनी जमा मुद्रा होती है वह भी विभिन्न प्रकार व जमा होता है रहती है। चालू जमा खाते (Current Accounts) में मुद्रा जमा होती है उन राशि को जमाकर्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व निवाला जा सकता है अथवा उन बैंक पर चैर काटकर निकाला जा सकता है इन्हें मांग जमा (Demand Deposits) कहते हैं। इससे अलावा सेविंग्स बैंक खाते (Savings Bank Accounts) में जमा राशि का भी नियम-नुसार एक सप्ताह में धनराशि निकालने की सुविधा होती है इन्हें भी मांग जमा राशि में रखा जाता है अर्थात् मुद्रा की मांग जमाकर्ता द्वारा निकालने की सुविधा दी जाता है। एक जमाखाता निश्चितकालीन जमाखाता (Fixed Deposits) होता है जिसमें जमा का जान वाली राशि जमाकर्ता को एक निश्चित समयावधि अथवा एगो जमाकर्ता को परिपक्वता अवधि पर ही दी जाती है। ऐसी जमाका को गान जमा (Time Deposits) भी कहते हैं।

यदि किसी जमाकर्ता को बाल जमा से अपनी धनराशि निकालनी पड़ जाए या उसे परिपक्वता अवधि से पहले ही धनराशि की आयम्यकता पड़ जाए तो बैंक ऐसी धनराशि के निकालने पर व्याज की दर थोड़ा अधिक लेकर जमाकर्ता को धनराशि दे सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जमाकर्ता को व्याज की सम्पूर्ण राशि के स्थान पर कम व्याज देकर बैंक यह धनराशि वापस कर सकता है अथवा बैंक ने यदि इस सम्बन्ध में जो भी नियम बना रखे है उन्हीं के अनुसार इस प्रकार की जमा राशि परिपक्वता अवधि (Maturity Period) से पहले दी जा सकती है। बाल जमा राशि में तरलता उतनी नहीं होती इसलिए इन्हें मुद्रा न कहकर अर्द्धजमा अथवा निम्न मुद्रा (Quasi Money or Near Money) की संज्ञा दी जाती है। बैंक मुद्रा की मात्रा निर्धारित करते समय बैंक मांग जमाआ (Demand Deposits) को ही लिया जाता है। क्योंकि ऐसी जमाआ को हम बैंक पर चेक लिख कर बाट सकते हैं।

मुद्रा की मात्रा निर्धारित करते समय हमें कुल मुद्रा में तीन प्रकार की मुद्रा शामिल करनी चाहिए (1) देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित कागजी नोटों की मात्रा, (2) सरकार द्वारा बैंकों की मात्रा (3) बैंकों में मांग जमा धनराशि। इन प्रकार किसी समयोपधि में हमें मुद्रा की कुल मात्रा ज्ञात करने में उपयुक्त तीन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।

मुद्रा की प्रभावी पूर्ति (Effective Supply of Money)

सरकार या देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जो भी मुद्रा की मात्रा निकाली जाती है वह समस्त मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं की जाती। इसमें केवल प्रभावी मुद्रा की पूर्ति को ही लेना चाहिए। प्रभावी मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय उस मुद्रा की मात्रा में होता है जो कि चलन (Circulation) में होती है। मुद्रा की कुल पूर्ति का भी सामान्यतया हम दो भागों में बाँटते हैं। प्रथम वह भाग जो केन्द्रीय बैंक सरकारों खजाने तथा व्यापारिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा (Reserve Money) के रूप में रखा रहता है। ऐसी मुद्रा कोप या पण्ड के रूप (Basic or Reserve Money) में रहती है प्रचलन (Circulation) में नहीं। इसलिए मुद्रा की पूर्ति गणना में इनके चलन उसी भाग को लिया जाता है जो प्रचलन में आ जाता है। दूसरे भाग में मुद्रा जिसका प्रचलन जनता के मध्य होता है जिसमें व्यक्ति, फर्म, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाया तथा निगम आदि आते हैं। मुद्रा की प्रभावी पूर्ति में कुल मुद्रा की मात्रा में हम दूसरे भाग यानि उस मुद्रा को शामिल करते हैं जो व्यय योग्य जनता के हाथों में पहुँचती है। इस प्रकार प्रभावी मुद्रा जानने के लिए हम मुद्रा की कुल पूर्ति में से उस भाग का निकाल देना चाहिए जो कि केन्द्र सरकार, बैंक आदि के पास आरक्षित मुद्रा (Reserve Money) के रूप में रहती है। मुद्रा सून्य निर्धारण में मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को ही मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त औसत रूप से मुद्रा की एक इकाई दिन में दो बार समसमय में चिक्की मुद्रा का कार्य करती है। इसे मुद्रा का चलन-वेग कहते हैं और मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को उससे चलन-वेग से गुणा करने के बाद ही प्रभावी पूर्ति का पता किया जा सकता है। प्रो० इरविन पिशर ने अपन मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में बालूनी मुद्रा तथा मास्य मुद्रा के प्रचलन वेग को मुद्रा की पूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

मुद्रा का चलन वेग (Velocity of Money)

मुद्रा के चलन वेग में आशय एक समयोपधि में औसत रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा जितनी इकाइयों का कार्य किया जाता है, से होता है। उदाहरणार्थ यदि एक समयोपधि में औसतन एक रुपया पाँच हाथों में गुजरता है तो सामान्य में वह पाँच रुपया है परन्तु

चूँकि वह पाँच लोगों के हाथों से गुजरता है तो वह एक रुपये का कागज न बरखे पाँच रुपये का कार्य करता है इसलिए मुद्रा की प्रभावी पूर्ति $1 \text{ रुपया} \times 5 = 5 \text{ रुपये}$ मानी जानी चाहिए।

मुद्रा विभिन्न प्रकार की होती है और उनका चलन-वेग भी अलग-अलग होता है। वानूनी मुद्रा तथा साख मुद्रा का प्रचलन में भी अन्तर पाया जाता है। इसी प्रकार माहेतिक अथवा सिक्कों के प्रचलन-वेग में अन्तर होता है। हम सभी प्रकार की वानूनी मुद्रा तथा साख मुद्रा का चलन-वेग औसत रूप से निकाल लेते हैं।

मुद्रा के चलन-वेग को हम राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित भी कर सकते हैं। अब हम मुद्रा के चलन वेग को राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित करते हैं तो हम एक निश्चित समयावधि (सामान्यतया एक वर्ष) में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को लेन-देन में शामिल करते हैं जो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income) का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे मुद्रा आय प्रचलन-वेग (Income Velocity of Money) कहते हैं। मुद्रा के आय प्रचलन वेग की विचारधारा को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में अपनाया था जबकि प्रो० रिशर ने मुद्रा के नगद भुगतान-वेग (Transactions Velocity of Money) को मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में अपनाया है।

कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि वास्तविक आय में शामिल वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मुद्रा के प्रयोग की स्थिति उसी समय मानी जायेगी जबकि वह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के रूप में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार मुद्रा के आय प्रचलन वेग में मुद्रा के उस औसत की व्यक्त किया जाता है जो कि मुद्रा की एक इकाई के एक निश्चित समयावधि में अंतिम आय प्राप्तकर्ताओं के नगद शेषों में शामिल होती है या उनसे बाहर निकलती रहती है। राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित मुद्रा के प्रचलन-वेग को हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं

$$V = \frac{NNP}{M} \text{ अथवा } \frac{PQ}{M}$$

$V = \text{Velocity of Money (मुद्रा का प्रचलन-वेग)}$

$NNP = \text{Net National Product at Current Prices (वर्तमान मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय)}$

$P = \text{Price-Level (कीमत स्तर)}$

$Q = \text{Total Quantity of Goods Relating to National Income (कुल वस्तुओं की मात्रा जो राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित होती है।)}$

$M = \text{Money Supply (मुद्रा की पूर्ति)}$

मुद्रा के प्रचलन वेग को निर्धारित करने वाले कारण (Factors Determining Velocity of Money)

मुद्रा के प्रचलन-वेग में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा का प्रचलन वेग निम्न तथ्यों द्वारा प्रभावित होता है—

(1) मुद्रा की उपलब्ध मात्रा—किसी समय अवस्था में मुद्रा के प्रचलन वेग पर मुद्रा की मात्रा अपना प्रभाव डालती है उदाहरणार्थ यदि उपलब्ध मुद्रा की मात्रा अथवा पूर्ति उगरी मांग की अपेक्षा अधिक होगी तो मुद्रा की एक इकाई का औसत चलन-वेग

कम होगा और मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग से कम होगी तो मुद्रा का चलन-वेग भी अधिक होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में मुद्रा की एक इकाई औसत रूप से अधिक बार वस्तुओं तथा सेवाओं के लेन-देन में प्रयोग में लाई जाएगी।

(2) भुगतान की विधि—यदि लोग उधार लेन-देन की अपेक्षा नकद रूप से भुगतान करेंगे अथवा लोगों द्वारा भुगतान नकद मुद्रा के रूप में होगा तो मुद्रा का चलन-वेग औसत रूप से अधिक होगा।

(3) उपभोग प्रवृत्ति—लोगों में अधिक उपभोग प्रवृत्ति पाई जाएगी और वस्तु कम होगी तो मुद्रा का प्रचलन-वेग बढ़ेगा जबकि इसके विपरीत की स्थिति में होने पर यह कम होगा।

(4) उधार सौदों के भुगतान की अवधि—मुद्रा का चलन वेग इस बात पर भी निर्भर करता है कि अवस्थितियों में जिन सौदों का उधार लेन-देन होता है उनके भुगतान की अवधि कैसी है। उदाहरणार्थ यदि उधार लेन-देन की औसतन भुगतान अवधि कम है तो मुद्रा का चलन-वेग अधिक होगा और इसके विपरीत यदि उधार सौदों के भुगतान की अवधि अधिक है तो चलन वेग भी औसतन कम होगा।

(5) तरलता पसंदगी—जब लोग नकदी अपने पास रखना अधिक पसन्द करेंगे तो मुद्रा का चलन-वेग औसतन कम होगा। इसके विपरीत लोग में तरलता पसंदगी कम होने पर चलन वेग अधिक होगा।

(6) मजदूरी भुगतान का तरीका—सामान्यतया यदि अवस्थितियाँ में उत्पादक या साहसी अपने सन्धान में कायरत मजदूरों या देनदारों को कम-चाहियाँ को भुगतान सम्बन्ध समय के बाद करते हैं तो चलन-वेग कम होगा क्योंकि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग नकदी अपने पास रखना अधिक पसन्द करेंगे। इसके विपरीत यदि भुगतान की विधि दैनिक या प्रति सप्ताह होगी तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा।

(7) मातायात तथा मदेसवाहन के साधनों की स्थिति—यदि देश में मातायात तथा मदेसवाहन के साधन उपरतिर्णाल ह तो इसमें बाजार तथा विनिमय का क्षेत्र व्यापक होगा और मुद्रा का चलन-वेग भी अधिक होगा।

(8) देश के भीमत स्तर की प्रवृत्ति—यदि लोगों को यह आभास हो जाय कि भावें बाने समय पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो लोग वस्तुओं को अधिक से अधिक संचय करके अपने पास रखें जिससे मुद्रा की इकाइयाँ को जन्दी-जन्दी विनिमय कार्यों के लिए उपभोग में लाया जाएगा और उसका चलन वेग बढ़ेगा।

(9) आर्थिक विकास की स्थिति—यदि देश की आर्थिक विकास का स्तर ऊँचा होगा तो इसमें विनिमय का स्तर भी ऊँचा होगा और मुद्रा का चलन-वेग बढ़ेगा इसके विपरीत स्थिति में मुद्रा का चलन वेग गिरगा।

(10) आर्थिक सम्पन्नता तथा बैंकिंग प्रणाली—जब देश में आर्थिक सम्पन्नता अधिक होगी और बैंकिंग प्रणाली का विकास होगा तो मातृ मुद्रा का प्रचलन-वेग भी बढ़ेगा इसके विपरीत स्थिति होने पर प्रचलन-वेग गिरगा।

(11) राजनैतिक स्थिति—जिा देश में राजनैतिक स्थान्ति का बानावरण रहता है वही लोग स्वतन्त्रतापूर्वक उधार विनिमय क्रियाओं में भाग लेते हैं, परिणामस्वरूप मुद्रा का प्रचलन वेग में वृद्धि होती है। वहीं राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है वही

लोगों में विश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और यहाँ तक कि नष्ट नष्ट मन-दन अधिक करते हैं परिणामस्वरूप मुद्रा का प्रचलन बेग में वृद्धि होता है।

मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन (Changes in the Money Supply)

मुद्रा की पूर्ति न प्रायः तीन स्रोतों ही प्रमुख हैं (1) सरकार द्वारा मुद्रा की पूर्ति, (2) देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति (3) बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति अथवा सार्वजनिक मुद्रा। यह तीनों ही मुद्रा पूर्ति के स्रोत विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियाँ (Assets) का प्राप्त करत हैं और इन्हीं के आधार पर मुद्रा की पूर्ति का प्रभावित करत हैं और यही इन सस्याओं के दायित्व (Liabilities) होते हैं जिनके भुगतान की जिम्मेदारी इन स्रोतों पर होती है। चूँकि यह दायित्व माँगने पर सामायित्व (Payable on Demand) हान है इसलिए इन्हें प्रणाली तथा अन्य भुक्तानों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। सरकार के केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक द्वारा कुल मुद्रा की पूर्ति में समय समय पर परिवर्तन इन सस्याओं की मौद्रिक नीति द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। विपरीत समय पर देश में मुद्रा की पूर्ति में नरक परिवर्तन हो जाते हैं। इससे निम्न हम उपर्युक्त वर्णित तीन स्रोतों की मुद्रा निर्माण या पूर्ति प्रक्रिया को समझना होगा।

सरकार तथा कन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन दण की बानून मुद्रा की पूर्ति उस दण की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा की जाती है। इन दोनो का कार्यविधि तथा मौद्रिक नीति का देश की मुद्रा पूर्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सरकार तथा कन्द्रीय बैंक को नोट निगमन तथा सहायक मुद्रा निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य सापेक्ष मुद्रा का नियन्त्रण करना भी है इस कारण दण का केन्द्रीय बैंक अपने पास उपरद्वारा सापेक्ष नियन्त्रण विधियों (Methods of Credit Control) द्वारा दण में व्यापारिक बैंक की सारा निर्माण शक्ति या याचित दण में राज में निष् अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। वह मौद्रिक तथा राजकाशाय नीतियों का माध्यम श अध्ययन तथा कुशलतापूर्वक संचालन कर सकता है। दण का केन्द्रीय बैंक सरकार के एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है परन्तु फिर भी कुछ मामलों में वह स्वायत्त रूप भी बनाए हुए है।

भारत में रिजर्व बैंक आंक इण्डिया देश का राष्ट्रीय बैंक है। इसका कार्य करना होता है और 2, 5 10 20 50 100 तथा 500 रुपये के नोट रिजर्व बैंक द्वारा उभाए गये हैं। इसके साथ ही एक रुपय का टाट निकाला तथा 50, 25 20 10 5 3 2 तथा 1 पैसे के सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। किसी भी देश का राष्ट्रीय बैंक चूंकि सरकार का नियंत्रण में होता है इसलिए वह नाटा की उत्पत्ति को रोकता जारी करता है जिससे लिए सरकार से उसे आदेश प्राप्त होता है। अपने सामान्य काम में वह पुराने नाटे को प्रचलन से हटाकर नए नोटे का निगमन कर सकता है। सरकार के वृद्ध हुए दायित्वों को देखते हुए अथवा सरकार की राजकोषीय नीतियों से प्रभावित होकर मुद्रा का पूर्ति में निरन्तर परिवर्तन होने रहता है। जब सरकार घाटे में चलने लगती होती है तो इसका पूर्ति के लिए होनाथ प्रबंध (Deficit Financing) की नीति अपनाती है। होनाथ प्रबंध सरकार के राष्ट्रीय बैंक में जमा मुद्रा का निष्कर्षण तथा आन्तरिक ऋणों (व्यक्तियों तथा बैंकों) द्वारा अथवा विदेशी ऋणों द्वारा कर सकता है। जब यह ऋण व्यक्तियों अथवा बैंकों से लिए जाने हैं तो सरकार इन ऋणों पर बंधन प्रत्युत्पादन (Securities) बनती है जिसका प्रभाव यह होता है कि बैंक का पास बांध में पैसा रुक जाता है। सरकारी मुद्रा का एक भाग सश्रिय मुद्रा का रूप धारण कर लेता है। सरकार बना से जो

ऋण प्राप्त करती है उसे घाटे की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है जिनमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की इस पूर्ति का एक भाग सरकार द्वारा व्यय करने पर पुन बँकों के पास जमा राशि का रूप में पहुँच जाता है जो कि बँकों की प्रारम्भिक जमाओं को बढ़ाता है परिणामस्वरूप बँकों की साख निर्माण शक्ति बढ़ जाती है। यह स्थिति एक विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देश में पाई जाती है। अर्द्धविकसित अथवा विकासशील देशों में माधनों की स्वल्पता सावजनिक ऋणों पर सरकार की निर्भरता को सीमित करती है। इसलिए अर्द्धविकसित देशों में हीनार्थ प्रबन्धन का मुख्य स्रोत सरकार द्वारा देश के केन्द्रीय बैंक से अधिक नोट निर्गमित कराने पर ऋण प्राप्त करना होता है। ऐसे ऋण की जमानत के रूप में केन्द्रीय बैंक को सरकार द्वारा वापसागार विपन्न अथवा प्रतिभूतियाँ (Treasury Bills or Securities) दी जाती हैं जिनके आधार पर नोट छापता है। इस प्रकार सरकार अपने बड़े हुए व्यय को पूरा करती है। इस प्रकार नोटों के प्रचलन से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और बँकों की जमा पूँजी तथा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा भी प्रभावित होती है। चूंकि सरकार के पास अधिक कोषों की मात्रा कम होती है और बाध्य ऋणों के लेन की मात्रा भी सीमित होती है इसलिए नोट निर्गमन बढ़ता है और कुल मिलाकर मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती है।

देश में मुद्रा की पूर्ति बहुत कुछ उस देश की भौतिक तथा राजकोपीय नीतियाँ तथा उनके पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है। सरकार को देश की व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थितियाँ तथा आर्थिक विकास के स्तर द्वारा भी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन समायोजित तथा आवश्यकतानुसार करना पड़ता है। देश की आवश्यकताओं के अनुमान से अधिक अथवा कम मुद्रा की पूर्ति होने पर देश के मूल्य-स्तर (Price-Level) वृद्धि अथवा कमी आती रहती है। जन-जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि देश के उत्पादन तथा राजगार के स्तर को बढ़ाती है तो इससे अवस्थिति की प्रगति तथा लाभदायकता का संकेत मिलता है।

बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा—मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा भी शामिल होती है जिसे प्राथमिक बँकों द्वारा निकाला जाता है। बैंकों की जमाएँ दो प्रकार की होती हैं (i) प्राथमिक जमाएँ (Primary Deposits) (ii) व्युत्पन्न जमाएँ (Derivative Deposits)। जब कभी भी लोग बैंक के पास अपनी नकदी को जमा कराते हैं तो इन्हें बैंक की प्राथमिक जमा राशि कहा जाता है। बैंक चूंकि वर्डेंट एकाउण्ट में जमा राशि को छोड़कर अन्य प्रकार की जमा राशियाँ पर अपने ग्राहकों को व्याज का भुगतान करता है और यह व्याज वह जमा धनराशियों पर तभी दे सकता है जबकि वह इन्हें ऋण माँगने वाले व्यक्तियों की उधार दे दे और ऐसे ऋणों पर व्याज की समूची बैंक ऋणियों से कर। बैंक ऋण माँगने वालों को नकद भुगतान न करके उनके नाम का खाता खोल देता है और उन्हें बैंक बुक देकर बैंकों द्वारा भुगतान देने की सुविधा प्रदान कर देता है। बैंक अपने नियमानुसार इस ऋण की कुल राशि का एक प्रतिशत नकद रखकर शेष धनराशि को पुन अन्य ऋणों को ऋण के रूप में देकर उसका खाता खोलकर उसके एक भाग को नकद रखकर शेष राशि को पुन ऋण के रूप में वितरित कर देता है। प्राथमिक जमा के आधार पर ऋण जो दिए जाते हैं वह बैंक की व्युत्पन्न जमा या साख जमा (Derivative or Credit Deposits) कहलाती है। बैंक साख जमा या साख मुद्रा वितरित निकालेगा यह बात बैंक की प्रारम्भिक जमा राशि की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। बैंकों को प्राप्त होने वाली प्रारम्भिक जमा का एक अनुपात नकद कोष में रखकर शेष को अग्रिम (Advance) अथवा ऋण (Loan) के रूप में दे दिया जाता है। बैंकों की व्युत्पन्न जमा फिर बैंक मुद्रा का रूप धारण कर लेती है जिसे ऋणों का निगमन या बैंक के नाम गारंटी निगमन कहा जाता है। इसी के आधार पर

कहे जाते हैं कि ऋण जमा की सृष्टि करते हैं और जमा पुनः ऋण की सृष्टि करती है। व्युत्पन्न जमा (Derivative Deposits) का निर्माण साख निर्माण कहलाता है। बैंकों के पास जितनी प्रारम्भिक जमा राशि होती है बैंक उससे 4-5 गुनी साख मुद्रा का सृजन कर लेते हैं। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि बैंक के पास कोई व्यक्ति 1000 रुपये जमा कराता है तो यह बैंक की प्रारम्भिक जमा कहलाएगी। बैंक इस प्रारम्भिक जमा का एक प्रतिशत यानि 10 प्रतिशत अपने पास रखकर अर्थात् 100 रुपये रखकर शेष 900 रुपये ऋण के रूप में उठा देगा। अब बैंक के पास यह 900 रुपये की धनराशि जमा हो जायेगी जो व्युत्पन्न जमा (Derivative Deposit) कहलाएगी। बैंक फिर इस 900 रुपये में से 10 प्रतिशत यानि 90 रुपये रखकर शेष 810 रुपये अन्य किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा और यह उमरा उस समय तक चलेगा जब तक कि उसके पास और ऋण पर उठाने के लिए धनराशि उपलब्ध ही नहीं रहेगी।

बैंकों की साख निर्माण शक्ति कुछ बातों पर निर्भर रहती है जैसे—(1) बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की माँग नकद रूप में न करके बैंकों द्वारा निवालन की सुविधा होती है। (2) कुल जमाओं के एक निश्चित अनुपात से अधिक बैंकों को अपने पास नकद कोष नहीं रखने पड़ते हैं। (3) बैंकों से जनता द्वारा ऋण या अधिषो की माँग लगातार घनी रहती है। (4) बैंक अपनी अधिकतम क्षमता तक ऋण देने को तैयार हों। बैंक की साख निर्माण शक्ति भी असौमित्र नहीं होती। यह भी नकद कोषों द्वारा निर्धारित होती है। साख निर्माण दश में मुद्रा की मात्रा जनता की बैंकिंग आदतों, कुल देयताओं (Liabilities) का नकद कोष में प्रतिशत व्यापारिक बैंकों का केन्द्रीय बैंक के पास जमा धनराशि या कोष, केन्द्रीय बैंक की साख सम्बन्धी नीति, जमाकर्ताओं की बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्थिति, प्रतिभूतियों के स्वभाव तथा वानुनी सरल कोषानुपात पर निर्भर करती है। फिर भी हम यह समझते हैं कि अनुसूचित परिस्थितियों में बैंक अधिक साख मुद्रा का निर्माण कर लेते हैं।

भारत में मुद्रा की पूर्ति की माँग—भारत में मुद्रा की पूर्ति क्या है इसमें सम्बन्धित हम रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक स्टॉक की व्याख्या करेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के लिए मुद्रा को चार भागों में बाँटा है जैसे M_1 , M_2 , M_3 तथा M_4 आदि।

M_1 = जनता के पास उपलब्ध चलन की मात्रा + बैंक के पास माँग जमाएँ (अन्तर बैंक जमाओं को छोड़कर) + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ (अर्द्ध सरकारी तन्त्राया की माँग जमाएँ + विदेशी सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की माँग जमाएँ)

$M_2 = M_1 +$ पोस्ट ऑफिस बचत खातों में वचन जमाएँ

$M_3 = M_2 +$ बैंकों के पास काल जमाएँ (शुद्ध अन्तर बैंक जमाएँ)

$M_4 = M_3 +$ पोस्ट ऑफिस में कुल जमाएँ (न कि केवल वचन जमाएँ)

भारत में M_1 की जो परिभाषा दी गई है उसका संकुचित अर्थ है। मुद्रा की परिभाषा अत्यंत दश के संस्थागत कार्यप्रणाली के आधार पर दी जाती है। ब्रिटेन में M_1 की गणना करते समय बैंकों के तुलन-पत्र (Balance Sheet) में 60 प्रतिशत चलन-मसदा (Transit Items) को घटा देते हैं। इसी प्रकार M_3 में M_1 + निजी क्षेत्र की काल जमाओं (Time Deposits) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी जमाओं (विदेशियों की जमाओं को छोड़कर) की गणना की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A) में M_2 को दर्शाया जाता है जिसमें चलन मुद्रा, व्यापारिक बैंक की जमाएँ तथा बैंक की आपसी जमाएँ (Mutual Deposits) तथा ऋण संघ (Loan Associations) तथा बन्ने जमाओं का समस्त पैत्रा आदि का शामिल किया जाता है।

मुद्रा की पूर्ति (M_1) को परम्परागत विचारधारा के अनुसार हम वकल चाने मुद्रा तथा माँग जमाआ का ही शामिल किया जाता है क्योंकि यही विनिमय व माध्यम तथा मूल्य संचय काय को मनोमौलि सम्पन्न करती है। आज की आधुनिक अवस्था में बहुत सी ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ (Assets) हैं जो विनिमय के माध्यम तथा मूल्य संचय काय को सुनिश्चित रूप से सम्पन्न करती हैं। इसानए शिवागो सम्प्रदाय (जिसमें प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन तथा लॉय जॉर्ज हैं) के अनुसार चलन मुद्रा तथा माँग जमाआ व साथ बाँक जमाआ (Time Deposits) को भी मुद्रा की पूर्ति M_1 में जानना चाहिए। प्रो० गुर्ली तथा प्रो० शा (Prof Gurley and Prof Shaw) का कहना है कि चलन मुद्रा तथा माँग जमाआ वित्तीय माध्यम के परिवार के दो बड़े सदस्य हैं आ तरल व साथ ही मूल्य संचय का भी कार्य करते हैं। इन दो व अतिरिक्त वचत खात में जमाएँ काय जमाएँ यूनिट्स (Units) अंश (Shares) तथा ऋण पत्र (Debentures) आदि कुछ अन्य मद भी हैं आ तरल मुद्रा तथा मूल्य संचय काय को मनोमौलि सम्पन्न करती हैं।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्षों का सुझाव है कि विभिन्न पापों के लिए विभिन्न प्रकार के मौद्रिक औसत (Monetary Aggregates) का प्रयोग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रो० सुनमय चन्द्रवर्ती समिति ने सुझाव दिया है कि M_2 का उपयोग मौद्रिक नीति के निर्धारण में मौद्रिक चर (Monetary Variable) के रूप में करना चाहिए।

शक्तिशाली अथवा उच्च शक्ति युक्त या प्रारक्षित मुद्रा (High Powered or Reserve Money)

भारत में उच्च शक्ति युक्त अथवा शक्तिशाली मुद्रा अथवा प्रारक्षित मुद्रा की धारणा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा इन प्रकार की गई है।

उच्च शक्ति युक्त मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें निम्नलिखित मद शामिल की जाती हैं—

- (1) जनता व पाग चलन मुद्रा।
- (2) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास व्यापारिक तथा सहकारी बैंक के शेष (Balances)।
- (3) व्यापारिक तथा सहकारी बैंक के पास नकदी।
- (4) रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ।

शक्तिशाली अथवा उच्च शक्ति युक्त मुद्रा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा की पूर्ति से होता है। किसी भी प्रकार शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा बढ़ा से मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होगी। 1970 के दशक में यह तथ्य सामने आया है कि इन दोनों चरों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। प्रो० सुनमय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि भारत में शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा में वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को प्रदान की जाने वाली मात्रा के कारण हुई है। इसलिए यदि सरकार वास्तव में मुद्रा की पूर्ति पर काय पाना चाहते हैं तो उस शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण करना होगा।

भारत में 1980 के दशक में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा भारत सरकार को साव (Credit) अधिक प्रदान करने के कारण शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। सरकार को ऋण प्रदान करने या सरकार द्वारा अपन बढ़ाव हुए दायित्व जैसे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक में ऋणों का माँग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता। मई 1970 से भारत में

प्रारक्षित अथवा शक्तिशाली मुद्रा की माँग के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति में तत्ती स वृद्धि हुई है। सन् 1970 के दशक में बाजार बंधों की माँग विचार योजना में ध्यान में रखते हुए प्रारक्षित मुद्रा की माँग की इस वृद्धि का परिणाम यह हुआ है कि पतन-जमा-अनुपात में गिरावट आई है। चूँकि रिजर्व बैंक का इस प्रारक्षित मुद्रा की माँग पर कोई नियन्त्रण नहीं है इसलिए उस मुद्रा गुणवत्ता जैसे नकद-बाप-अनुपात (Cash Reserve Ratio—CRR) को मुद्रा की पूर्ति के नियन्त्रण हेतु चुनना पड़ा है।

परीक्षा-प्रश्न

1. मुद्रा की माँग से आप क्या समझते हैं? यह किन उद्देश्यों के लिए की जाती है? (What do you understand by the demand for money? For what objectives the demand for money is made?)
 2. मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न अंगों का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि उनमें परिवर्तन किन कारणों से होता है? (Analyse the various components of the supply of money and explain the factors responsible for variation in them)
 3. मुद्रा की माँग और पूर्ति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। (Discuss the factors determining the demand and supply of money.)
 4. शक्तिशाली मुद्रा की परिभाषा कीजिए। इसमें परिवर्तन के बौत-बौत से स्रोत हैं? (Define High Powered Money. What are the sources of its changes?)
- [संकेत—उच्च शक्ति युक्त मुद्रा का अर्थ बताने के बाद हमने विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए तथा अन्त में बताइए कि मुद्रा की पूर्ति का शक्तिशाली मुद्रा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसमें परिवर्तन सरकारी इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। सरकार रिजर्व बैंक में वसु श्रृंखला से तो उचित होगा।]

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

5. निम्न कथनों में कौन सही तथा कौन गलत है—
 - (i) मुद्रा की माँग व्युत्पन्न होती है।
 - (ii) मुद्रा की माँग केवल विनिमय माध्यम के वायं हेतु होती है।
 - (iii) मुद्रा की पूर्ति में बैंक-निर्गत तथा साख मुद्रा शामिल होती है।
 - (iv) भारत में एक रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
 - (v) शक्तिशाली मुद्रा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा की पूर्ति से होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर:

- (i) सही है। (ii) गलत है। (iii) सही है। (iv) गलत है। (v) सही है।

"There cannot, in short, be intrinsically a more insignificant thing in the economy of society than money, except in character of a contrivance of sparing time and labour"

—J S Mill

अध्याय 15

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त

(QUANTITY THEORY OF MONEY)

पुराने अथवा परम्परावादी अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने मुद्रा को अधिक महत्व नहीं दिया था उनकी दृष्टि से मुद्रा से अधिक महत्वहीन कोई वस्तु नहीं होती है। एडम स्मिथ जैसे विद्वान ने मुद्रा की तुलना उस पक्की सड़क से की है जिस पर स्वयं एक घास की पत्ती भी नहीं उगती। मुद्रा को अनुत्पादक एवं महत्वहीन बताते हुए इन विद्वानों ने यह विश्वास व्यक्त किया था कि मुद्रा किसी भी प्रकार से अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव नहीं डालती। यह विद्वान फ़ामीली अर्थशास्त्री प्रो० जे० बी० ने (Prof J B Say) व बाजार नियम जिसके अनुसार 'पूर्ति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न कर लेती है।' (Supply Creates its own Demand) से प्रभावित थे। इन विद्वानों की ऐसी धारणा थी कि मुद्रा की आवश्यकता केवल वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रय-विश्रय करने के लिए होती है अर्थात् मुद्रा विनिमय मीढ़ों को निपटाने का एक साधन मात्र है। उनकी दृष्टि से एक मौद्रिक व्यवस्था में नून रोज़गार की मात्रा, कुल उत्पादन की मात्रा, विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रकार और उनके अनुपात जिनका उत्पादन तथा उपभोग होता है, बाजार में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, समाज के सम्पत्ति और आय का वितरण आदि एक विकसित अव्यवस्था में समाज के लोगों के बीच ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि एक कुशल वस्तु-विनिमय अव्यवस्था में होता है। इन विद्वानों का कहना था कि अव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मुद्रा के माध्यम से दिन-देन हो या फिर वस्तुओं तथा सेवाओं का दिन-देन वस्तुओं तथा सेवाओं द्वारा हो, इसमें कोई फ़ास अन्तर नहीं पड़ता।

प्रतिष्ठित विद्वान यह तो समझत थे कि मुद्रा ने विनिमय को सुविधाजनक एवं सरल बना दिया है परन्तु इसका अतिरिक्त मुद्रा स्वयं कोई उपयोगिता प्रदान नहीं करती, मुद्रा एक अनुत्पादक (Unproductive) वस्तु है। प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक प्रो० जे० एम० मिल (Prof J B Mill) ने मुद्रा के महत्वहीन स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहा है कि "सधोप म, मुद्रा में महत्वहीन वस्तु सामाजिक अव्यवस्था के अन्दर कोई हो ही नहीं सकती, यह समय और थम की वचत करने का कार्य करती है। यह उस मशीन की भाँति है जो कि कार्य को जल्दी और सुविधापूर्वक करती है और इसकी अनुपस्थिति में यह कार्य कम शीघ्र और सुविधापूर्वक सम्पन्न होगा, अन्य बहुत सी मशीनगिरियों की भाँति,

दमना पर अलग और अपना स्वतन्त्र प्रभाव होता है उसी पर तर्क करने योग्य न रहे।¹

मुद्रा अब मे अस्तित्व में आई है इसमें स्थिरता का अभाव पाया गया है। मुद्रा ने अपने बावों को इसनिष्ठ भरी प्रहार में नहीं निभा पाया है क्योंकि इसके मूल्यों में उच्चा-चरनों को समय-समय पर अनुभव किया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मोक्षने से कि मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन क्षणिक या अन्य समय के लिए तो हो सकते हैं परन्तु दीर्घकाल में स्थिर अर्थव्यवस्था में स्थिर शक्तियों वित्यागीय हो जावेगी जो इसके मूल्य में स्थिरता के धारणी। प्रतिष्ठित विद्वान् कहने से कि मुद्रा अपने बावों को मुखारूप में करती है अर्थात् विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन का कार्य मुद्रा भरीभरि सम्पादित करती रहती है। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि प्रतिष्ठित विद्वानों का यह धारणा मानने योग्य नहीं है। आधुनिक विद्वान् कहने हैं कि मुद्रा हमेशा एक प्रहार में कार्य नहीं कर पाती इसकी शक्ति और मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होने रहने हैं जिनसे रोजगार तथा उत्पादन की कुल मात्रा, स्थितिगत वस्तुओं की कीमतें जिनका त्रय-विषय होता है तथा समाज के लोगों के मध्य वास्तविक सम्पत्ति तथा आय का वितरण प्रभावित होता रहता है। अन्तराल में मुद्रा के यह प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होने हैं और जो कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक व्यवहार की प्रभावित करने हैं क्योंकि दीर्घकालिक व्यवस्था छोटी-छोटी या अन्तरालिक व्यवस्था की ही एक श्रृंखला मात्र ही रहो जा सकती है। मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन ही इन तारी पदार्थों के लिए उत्पत्ताशी होता है। यदि मुद्रा की आवधिक वस्तुओं तथा स्थिति भूतानों का एक अन्तोलम्बक मात्र बनना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि मुद्रा के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। परन्तु अनुभव इस बात का सार्थी है कि इसमें स्थिरता नहीं रहती।

प्रो० जे० एम० बीन्स ने परम्परावादी विद्वानों के इन विचारों का खण्डन किया कि मुद्रा एक आवश्यक मान है। प्रो० बीन्स कहने हैं कि मुद्रा हमेशा भी महत्वपूर्ण है शक्तिशाली और विविध वस्तु है जो कि विनिमय का माध्यम मूल्य मापन, स्थिति भूतानों का मान तथा वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक बड़ी है और यह आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीन्स कहने हैं कि मौद्रिक क्षेत्र सामान्य आर्थिक व्यवस्था का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। बीन्स की जनरल थ्योरी (The General Theory of Employment Interest and Money—1936) मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था के मिडान्स के रूप में जानी जाती है अर्थात् जिनमें हम उत्पादन का मौद्रिक मिडान्स कहने हैं जिनमें व्याज की दर, जो कि मुद्रा की माँग और पूर्ति द्वारा निर्मित होती है, एक

1. "There cannot in short, be intrinsically a more significant thing, in the economy of society, than money, except in the character of contrivance of sparing time and labour. It is a machine for doing quickly and commodiously, what would be done though less quickly and commodiously, without it, and like many other types of machinery, it only exerts a distinct and independent influence of its own when it gets out of order"

—J. S. Mill

महत्वपूर्ण भूमिका जरा करती है। बीन्स के अनुसार मुद्रा व्यापार की दर को प्रभावित करती है जिससे द्वारा निम्नलिखित प्रभावित होना है और जो सामान्य आर्थिक क्रिया उत्पादन तथा रोजगार पर अपना प्रभाव डालती है।

एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में एक साहसी या उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करता होता है। एक साहसी द्वारा अधिक उत्पादन उनी समय निरा जाएगा जबकि उस लाभ मिलने की सम्भावना हो। मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन साहसी या उत्पादन की आशंकाओं को प्रभावित करते हैं जो कि उनकी व्यापारिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो साहसियों के साम बढ़ते हैं क्योंकि बड़ी हुई लागत से अधिक कीमतें बढ़ जाती हैं और साहसी इस बड़े हुए लाभ से प्रभावित एवं उत्पादित होकर अधिक उत्पादन और पूँजी निर्यात करने लगते हैं। जब कीमतें गिरती हैं तो उनका यह उद्देश्य सम्पन्न होना लगता है और उन्हें हानि उठाने पड़ती है।

ऐसी स्थिति में हम यह जानना जरूरी होता है कि मुद्रा के मूल्य को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री समझते थे कि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति महत्वपूर्ण होती है जिसको उन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के द्वारा बताया है। वे कहते हैं कि किसी देश का सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति द्वारा ही तय होता है यदि अन्य बातें समान रहें (Other Things being Equal)। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या से सम्बन्धित हम निम्नलिखित विद्वानों के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त—लेन-देन दृष्टिकोण (Quantity Theory of Money—Transaction Approach)

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर (Prof Irving Fisher) के नाम से विख्यात है। परन्तु प्रो० फिशर से पहले भी इस सिद्धान्त की व्याख्या के चिह्न मिलते हैं। इससे प्रतिपादन सोहरो शताब्दी में इटली के लेखक देवन्जत्ती (Devanzatti) के। बॉटिन (Bodin) कैंटिलॉन (Cantillon) तथा डेविड ह्यूम (David Hume) के लेखन कार्यों में भी इसका उल्लेख है। बाद में प्रो० जे० एम० मिल तथा प्रो० एच० एन्ड्रू० टॉसिंग (Prof J S Mill and Prof F W Taussing) ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या अपना-अपने ढंगन कार्यों में की है।

प्रो० जे० एम० मिल के शब्दों में

‘अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा की मूल्य अपनी मात्रा के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसने मूल्य में बची तथा मात्रा में प्रत्येक कमी में उसने मूल्य में आनुपातिक वृद्धि होती है।’

प्रो० टॉसिंग के शब्दों में

“अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो वस्तुओं का मूल्य पहले से दुगुना और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो वस्तुओं का मूल्य पहले से आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जाएगा।”

प्रो० जे० एम० मिल तथा प्रो० टॉसिंग की मुद्रा मूल्य की परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि इन विद्वानों ने मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध उसकी मात्रा से जोड़ा है, जिसमें मुद्रा की माँग को कोई महत्व न देकर मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है इसलिए इसे मुद्रा परिमाण की सज्ञा दी गई है।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के चार प्रमुख निष्कर्ष हैं—

- (1) मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के मूल्य में उल्टा या विपरीत सम्बन्ध होता है।
- (2) मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तु के मूल्य में सीधा सम्बन्ध होता है।
- (3) मुद्रा की पूर्ति तथा उसके मूल्य में जो सम्बन्ध होता है वह आनुपातिक होता है।
- (4) मुद्रा की पूर्ति तथा उसके मूल्य वा आनुपातिक सम्बन्ध उभी स्थिति में आनुपातिक होगा जबकि अन्य बातें समान रहे।

अन्य बातें जो समान रहनी चाहिए—इसका आशय यह है कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त तभी लागू होगा जबकि निम्नलिखित स्थितियाँ बनी रहें अर्थात् कुछ दशाओं में ही मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के निष्कर्ष लागू होंगे जैसे—

(1) मुद्रा की माँग स्थिर रहनी चाहिए अर्थात् व्यापारिक औद्योगिक तथा धनिकत उपभोग के लिए मुद्रा की माँग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(2) मुद्रा द्वारा ही समाज में सम्पूर्ण लेन-देन (Transactions) होना चाहिए। यदि वही वस्तु-विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत केम देन हो रहा है तो उसकी उपेक्षा करके उसे मुद्रा मूल्य में परिणतित करके उसकी गणना करनी जानी चाहिए।

(3) साल तथा मुद्रा का निश्चित अनुपात बना रहता है। इसका आशय यह है कि सैबा में कुल जमा राशि वा एक निश्चित भाग भन्वद भद्रा के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार जमा रकम तथा भन्वद कोष और जमा रकम तथा उधार में एव निश्चित अनुपात बना रहता है। इसी अनुपात पर किसी देन में साख की मात्रा निर्भर करती है।

(4) मुद्रा का चलन-वेग (Velocity) मुद्रा की कुल मात्रा की प्रभावित करता है। यदि इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहे तो इसका प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर भी पड़ता है। इसलिए मुद्रा के चलन-वेग को स्थिर मान लिया गया है।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त से सम्बन्धित फिशर की ध्याख्या

अथवा

लेन-देन अथवा सीदा दृष्टिकोण

Prof. Fisher's Approach Regarding Quantity Theory of Money

Or

Transactions Approach

अमरीकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर (Prof. Irving Fisher) ने सन् 1911 में अपनी पुस्तक 'Purchasing Power of Money' में मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या की है। प्रो० फिशर के मन्दा में 'परिमाण सिद्धान्त' बताता है कि (यदि चलन वेग और व्यापार की मात्रा अपरिवर्तित रहे) हम डॉलर की मात्रा में वृद्धि करे चाहे वह वृद्धि सिक्कों की जगह नाम देने वा सिक्कों की वृद्धि द्वारा हो किन्तु 'उसी अनुपात में बढ़ेगी।' प्रो० फिशर की मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में मुद्रा के विनिमय व

1 'The quantity theory asserts that (provided the velocity of circulation and the volume of trade are unchanged) if we increase the number of dollars whether by increasing coins or by increasing coinage prices will be increased in the same proportion'

—Irving Fisher

मध्यम कार्य (Medium of Exchange Function) की प्रमुखता दी गई है। प्रो० पिशर की व्याख्या की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का प्रयोग किया है। प्रो० पिशर अमरीका के गणितीय सम्प्रदाय के प्रमुख अर्थशास्त्री थे।¹ उन्होंने आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण एवं निष्कर्षों को जानने के लिए गणित का प्रयोग करके उनमें अधिक निश्चितता लाने का प्रयास किया है। उनके मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या का समीकरण लेन-देन अथवा विनिमय सौदों का समीकरण कहलाता है। उन्होंने बताया कि $MV = PT$

$MV =$ Supply of Money मुद्रा की पूर्ति

$PT =$ Demand for Money मुद्रा की माँग

$$\text{अथवा } P = \frac{MV}{T}$$

$P =$ कीमत स्तर

$M =$ मुद्रा की मात्रा

$V =$ मुद्रा का चलन वेग

$T =$ कुल सौदों की मात्रा जिनका विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है।

(इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं एवं प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं जो व्यापार की भौतिक मात्रा के बराबर होती हैं)

उपर्युक्त समीकरण की आलोचना हम तथ्य की ओर संकेत करने की गई भी कि इसमें साख मुद्रा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में साख-मुद्रा तथा उसके चलन-वेग का स्थान प्रमुख होता है। इसलिए प्रो० पिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या हेतु एक संशोधित समीकरण दिया है जो निम्न प्रकार है—

$$PT = MV + M'V'$$

$$\text{or } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$P =$ कीमत स्तर (Price Level)

$M =$ मुद्रा की मात्रा जो चलन में होती है (Quantity of Money in Circulation)

$V =$ मुद्रा का चलन-वेग (Velocity of Money in Circulation)

$M' =$ साख मुद्रा की मात्रा (Credit Money)

$V' =$ साख मुद्रा का चलन-वेग (Velocity of Credit Money)

$T =$ उन वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा जिनका विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। (Total Number of Goods and Services which are Exchanged Through Money)

1. प्रो० इरविंग पिशर के नाम से अर्थशास्त्र के विद्यार्थी काफी परिचित हैं। उनके मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या का समीकरण नबद व्यवसाय से नाम से जाना जाता है। प्रो० पिशर ने अर्थशास्त्र में गणितीय रीति का काफी प्रयोग किया। वे आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण गणितीय समीकरणों द्वारा करने में अधिक रचि रखते थे। वह अमरीकी गणितीय सम्प्रदाय के प्रमुख सदस्य थे।

मुद्रा का चलन-वेग (Velocity of Money)

मुद्रा के चलन वेग से आशय एक समयवधि में मुद्रा की एक इकाई द्वारा सम्पादित या किए गए मोदों के मूल्य से होता है। इसका अर्थ सामान्य मुद्रा के चलन-वेग से न होकर मुद्रा की एक इकाई के औसत चलन-वेग से होता है। मुद्रा का चलन-वेग निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित होता है—

मुद्रा के चलन-वेग को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Affecting the Velocity of Money)

(1) मुद्रा की मात्रा—मुद्रा का चलन वेग विभिन्न अवस्थानों में उत्पन्न मुद्रा की पूर्ति या उगनी मात्रा द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरणार्थ यदि चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो चलन-वेग कम होगा और मुद्रा की मात्रा कम होने पर यह अधिक होगा परन्तु धारणा है कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का चलन वेग भी अलग अलग हो सकता है। मुद्रा का चलन-वेग विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का औसत चलन-वेग ही कहलाता है।

(2) जनता द्वारा नकदी रखने की प्रवृत्ति—जितनी लोगों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए (जैसे मोटा उद्देश्य, दूरदशिता उद्देश्य तथा मृदा उद्देश्य) नकदी रखी जायगी उतनी ही मुद्रा की चलन गति धीमी होगी। इनके विपरीत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितनी नकदी या नकद शेष कम रखे जायेंगे मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। हम कह सकते हैं कि मुद्रा का चलन वेग लोगों द्वारा रखी जाने वाली नकदी की मात्रा पर निर्भर करेगा। यह प्रवृत्ति अर्थात् नकदी की प्रवृत्ति मुद्रा बाजार के संगठन तथा मजदूरी भुगतान की विधियों द्वारा प्रभावित होती है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे।

(3) मजदूरी भुगतान की प्रणाली—यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह है तो लोगों में नकदी रखने की प्रवृत्ति कम होगी और जल्दी-जल्दी उपभोग पर व्यय होगा जिससे मुद्रा का चलन-वेग बढ़ेगा। यदि मजदूरी भुगतान प्रति पन्चाश या प्रतिमाह है तो प्रति सप्ताह या प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले की अपेक्षा अधिक नकदी रखी जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मजदूरी प्राप्ति की अवधि जितनी अधिक होगी तो उतनी ही नकदी अधिक रखी जाएगी और इस प्रकार मुद्रा के चलन-वेग में मजदूरी भुगतान की अवधि महत्वपूर्ण होती है।

(4) संगठित मुद्रा-बाजार—मुद्रा-बाजार जितना संगठित होगा मुद्रा का चलन-वेग उतना ही अधिक होगा। इसका कारण यह है कि संगठित मुद्रा बाजार में ऋण प्रदान करने, व्यय तथा उधार देने की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण मुद्रा का चलन-वेग प्रभावित होता है।

(5) जनश्रद्धा, तदानीकी परिवर्तन मोटिव नीति तथा राजकोषीय नीति आदि भी मुद्रा के चलन-वेग को प्रभावित करती रहती हैं। इसका कारण यह है कि इन तरिका में उपभोग, बचत तथा विनियोग के स्तर प्रभावित होते हैं जो चलन-वेग को भी प्रभावित करते हैं।

(6) व्यावसायिक परिस्थितियाँ—व्यापार चक्रों अथवा तेजी वाले और मंदी वाले में व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन मुद्रा के चलन-वेग में परिवर्तन लाते रहते हैं। तेजी वाले में मुद्रा का चलन-वेग में तेजी आती है क्योंकि व्यय की क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोग जल्दी-जल्दी वस्तुओं का खय करने सक्षम बनते हैं। इनके विपरीत मंदी वाले में कीमत स्तर में गिरावट के कारण उपभोग और कीमतों में गिरावट होने

की प्रतीक्षा में उपभोग को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। परिणामस्वरूप व्यापारिक प्रियाएँ शिथिल पड़ जाती हैं और चलन-व्यय गिर जाता है।

(7) प्रतिफल की सम्भावनाएँ—जब माहगियों को यह पता चल जाए कि वह जो पूँजी लगा रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाला प्रतिफल अच्छा है अर्थात् पूँजी की सीमान्त क्षमता पूँजी लागत अथवा ब्याज की दर से अधिक है तो वे पूँजी विनियोजन बढ़ावेंगे और मुद्रा का चलन-व्यय अधिक होगा।

(8) राष्ट्रीय आर्थिक विकास की स्थिति—विवसित राष्ट्रों या देशों में औद्योगिक विभाग उच्च तपनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान कुशलता के उच्च स्तर समष्टि मुद्रा-बाजार आदि के कारण शिथिल तेजी से होता है और मुद्रा का चलन-व्यय बढ़ जाता है। जबकि अन्य शिथिल देश में जहाँ गरीब तथा वित्तीय सुविधाएँ कुशलता से साथ उपलब्ध नहीं हैं, मुद्रा का चलन-व्यय कम रहता है। वर्तमान समय में ऐसे अल्प-विकसित देशों में मुद्रा के चलन-व्यय में वृद्धि हुई है क्योंकि इन देशों में वित्तीय संस्थाओं के विभाग तथा कुशलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

(9) आय वितरण की स्थिति—यदि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण समानता की ओर है तो चलन-व्यय में वृद्धि होगी अन्यथा मुद्रा के चलन-व्यय में गिरावट आएगी।

फिशर के सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of Fishers' Theory)

प्रो० फिशर का सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं को उन्होंने अन्य बातें समान रहे' (Other things being Equal) काव्याण द्वारा व्यक्त किया है। यह मान्यताएँ मुद्रा के चलन-व्यय, व्यापार की मात्रा तथा लागत-मुद्रा आदि से सम्बन्धित हैं। यह मान्यताएँ निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं—

(1) समाज में मुद्रा तथा लागत-मुद्रा का चलन-व्यय स्थिर रहता है। मुद्रा तथा लागत-मुद्रा का चलन-व्यय ऐसे सस्यागत कारणों पर निर्भर रहता है जिनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होते इसलिए V तथा V' स्थिर रहते हैं।

(2) एक अन्य मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा (T) में कोई परिवर्तन नहीं होता। T प्राकृतिक साधनों, उत्पादन विधियों, धर्म की उत्पादनता, यातायात आदि तत्वों पर निर्भर करता है। T के स्थिर रहने की मान्यता इस मान्यता पर आधारित है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। देश में कोई भी उत्पादन साधन बेरोजगार नहीं होता यही कारण है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा अपरिवर्तित रहती है।

(3) सीमांत-स्तर पर लागत मुद्रा के पड़ने वाले प्रभावों की सम्भावना को यह मान कर समाप्त कर दिया गया है कि 'मानूनी मुद्रा (M) तथा लागत-मुद्रा (M') का अनुपात स्थिर रहता है।

(4) एक अन्य मान्यता यह है कि सीमांत-स्तर (P) एक निष्पक्ष तत्व है अर्थात् मुद्रा की मात्रा तथा अन्य तत्वों की मात्रा में परिवर्तन P को प्रभावित करते हैं, परन्तु P में परिवर्तनों का प्रभाव मुद्रा तथा अन्य तत्वों की मात्रा पर नहीं पड़ता। प्रो० फिशर के शब्दों में—

'सीमांत-स्तर में P एक निष्पक्ष तत्व है। यह स्वयं समीकरण के दूसरे तत्वों से निर्धारित होता है, परन्तु दूसरे तत्वों पर स्वयं कोई प्रभाव नहीं डालता।'

(5) फिशर की व्याख्या दीर्घकालिक है क्योंकि इनका विचार है कि दीर्घकाल में मुद्रा का चलन-व्यय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा स्थिर रहती है। अतः तब V तथा T में परिवर्तन हो सकते हैं।

फिशर के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Fisher's Theory)

फिशर के सिद्धान्त की आलोचनाएँ अधिकांशतः वैयक्तिक तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न आधारों पर की गई हैं। इसमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार से बताई जा सकती हैं।

(1) प्रो० फिशर ने $MV = PT$ माना है जो एक तार्काक्य तथ्य का बतलाना है अर्थात् यह समावर्णन के दोनो पक्ष MV तथा PT का निरर्थक्यवस्था में होना का दो रूप हैं उनको व्याख्या करता है। इसमें अनुसार जहाँ द्वारा जो मुद्रा वस्तुओं तथा सामानों के विनिमय के लिए दी जाती है (MV) = विनिताओं द्वारा वस्तुओं तथा सामानों के बदले में प्राप्त धनराशि (PT) का। इस प्रकार यह समीकरण ही मुद्रा तथा कीमती चीजों के बीच कोई तर्क जोड़ने वाली नहीं देता। इस प्रकार इस सिद्धान्त का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है।

(2) अद्यतन विषय सामान्यताओं पर आधारित सिद्धान्त का अधिगम आलोचनाएँ इस सिद्धांत द्वारा अगनाई जान पायी अवस्थाओं में बताता है ऊपर आधारित है जैसे—

(अ) यह सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा कीमती चीजों का सापेक्ष परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। इसमें मुद्रा के चलन-व्यय (V) को स्थिर माना गया है जो वृद्धिपूर्ण है। तत्पश्चात् V बढ़ जाता है तथा कीमती चीजों में इसमें कमी आती है।

(ब) सारा मुद्रा का चलन-व्यय (V') को स्थिर मानना वृद्धिपूर्ण है। वस्तुओं की मांग भी ऐसा माना जाता है कि बिना मुद्रा की मांग में वृद्धि की अपेक्षा V तथा V' में बहुत वृद्धि हो जाती है और कीमती स्तर बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ 1920 और उसी बाद जर्मनी में अति-स्फीति का नाम मुद्रा की मांग में वृद्धि का ही था। परन्तु मुद्रा का चलन-व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा था अर्थात् मुद्रा की मांग में वृद्धि के अनुसार वही अपेक्षा अनुपात में कीमत स्तर में वृद्धि इस तथ्य का आरंभ है कि कीमत स्तर की मुद्रा की मांग में वृद्धि से अधिक उसका चलन-व्यय प्रभावित करता है।

(ग) मुद्रा की मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर (P) बढ़ेगा नहीं बढ़ता। जिस अनुपात में मुद्रा का मांग में वृद्धि हो और उसी अनुपात में T की मांग में वृद्धि हो जाए तो P नहीं बढ़ेगा। T का स्थिर रहने की मायता वृद्धिपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती। उत्पादन की मांग तथा कीमत-स्तर एक-दूसरे में अप्रभावित नहीं रहते।

(द) मुद्रा तथा सारा मुद्रा M तथा M' का अनुपात स्थिर मान जना भी वृद्धिपूर्ण है।

(ए) P अर्थात् कीमत-स्तर एक निश्चित तत्व नहीं है P स्वयं अपेक्षाकरण के अन्य तत्वों को प्रभावित करता है।

कुछ मितान्तर हम यह कह सकते हैं कि V , V' , T और M तथा M' का सम्बन्ध सापेक्ष हो अपरिवर्तित रहते हैं। यह तत्व दोषपूर्ण है। यह तत्व अपेक्षाओं में भी परिवर्तित होते रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर अपेक्षा का मांग मुद्रा का चलन-व्यय तथा मुद्रा तथा सारा मुद्रा आदि तत्वों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।

(3) दोषराशील व्याख्या—आलोचक कहता है कि प्रो० फिशर ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त दोषपूर्ण है। इस सम्बन्ध में प्रो० फिशर का कहना है कि 'अधिक से अधिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि दीर्घकाल में मुद्रा की उपस्थिति मांग का कीमत स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है परन्तु अल्पकाल

मे.... यह कीमतों की गतियों पर अपना प्रभाव डाल भी सक्ती है और नहीं भी और यह इस बात पर निर्भर रहता है कि क्या मुद्रा की मात्रा परिवर्तन मुद्रा के चलन-वेग में परिवर्तन द्वारा निष्प्रभावित हो जाते हैं अथवा नहीं।¹

प्रो० फिशर ने प्राउफर द्वारा कहे गए इस तथ्य को स्वीकार किया है। प्रो० फिशर कहते हैं कि चलन-वेग तथा व्यापार की मात्रा (V तथा T) अल्पकाल में परिवर्तित हो सकती है परन्तु दीर्घकाल में जहाँ अव्यवस्था साम्य की स्थिति में पहुँच जाती है तो यह तत्त्व स्थिर हो जाते हैं।

प्रो० वीन्स न फिशर की इस दीर्घकालिक मान्यता की आलोचना करते हुए कहते हैं कि दीर्घकालिक सन्तुलन आने वाले काल की भाँति होता है जो कभी नहीं आता। वर्तमान परिस्थितियों में असार में दीर्घकालिक सन्तुलन (Long-run Equilibrium) जैसी स्थिति नहीं होती। वीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में हम तब मर जाते हैं। इस प्रकार फिशर की धारणा अल्पकालिक स्थिति, जा वास्तविकता के अधिक निकट है, की अनदेखी करती है।

(4) समीकरण का यह मानना कि T तथा V हाने कीमत-स्तर तथा मुद्रा की मात्रा (P तथा M) स्तनम्न रहे उचित नहीं है—आलोचक कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की यह मान्यता उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि M में परिवर्तन मुद्रा के चलन-वेग (V) का प्रभावित करने कीमत-स्तर (P) का प्रभावित कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मुद्रा का चलन-वेग (V) में परिवर्तन न, न कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन (M) में कीमत-स्तर को प्रभावित किया है। 1920 के बाद जर्मनी में अति-स्फीति (Hyper Inflation) के लिए मुद्रा का चलन-वेग अधिक उत्तरदायी था न कि उसकी चलन-मात्रा (इसका कारण यह था कि जर्मनी की मुद्रा मार्क में नैजी में गिरावट के कारण लोग जल्दी-जल्दी सम्पत्ति तथा सचाई का तब करने के लिए मार्क का प्रयोग कर रहे थे)।

मार्च 1920 में ही जहाँ एक ओर जर्मनी में कीमत-स्तर बढ़ने का प्रमुख कारण जर्मनी की मुद्रा मार्क के चलन वेग था, वहीं इतने समय अमरीका में मन्दोद्वि शिवाई दे रही थी। वहाँ व्यापार की मात्रा (T) में वृद्धि तो मुद्रा की मात्रा (M) में वृद्धि हो रही थी जबकि कीमत-स्तर (P) में वृद्धि नहीं पाई जा रही थी। हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि समीकरण के सभी चर (Variables) आपस में परस्पर पर निर्भर रहते हैं और यह जानना बड़िन होता है कि कौन-सा तत्त्व किम तथ्य की ओर कौन-सा प्रतिफल किसके कारण है। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त विभिन्न चरों की वास्तविक निर्भरता की भूनापर यह कहना है कि M में परिवर्तन का कारण P प्रभावित होता है, वृष्टिपूर्ण ध्याम्य है।

(5) परिमाण सिद्धान्त में पाई जाने वाली असंगतियाँ—यह आलोचना प्रमुखतः प्रो० जॉर्ज एन० हाल्म (George N. Halme) द्वारा की गई है। प्रो० फिशर के समीकरण के कुछ चरों की तुलना नहीं की जा सकती उदाहरण के लिए M समय क्षण (Point of

1 the most we can say for the quantity theory is that the quantity in existence seems to be dominant influence on the Price-level on the average of long period But in the short period... it may or may not control the movements of prices. And whether it does or does not depend on whether changes in the quantity of money are offset by changes in velocity of its circulation." --Crowther

time) तथा V समय-वधि (Period of Time) से सम्बन्धित होना है और इस प्रकार MV का अर्थ दो विभिन्न चीजों को गुणा करने रहता है। इसी प्रकार P अर्थात् कीमत-स्तर में भी सभी प्रकार की चीजों शामिल होती हैं जैसे—घोड़े मूख्य तथा पट्टर मूख्य, मजदूरी तथा लाभ। कुछ वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं जबकि कुछ कीमतें तेजी से नहीं बढ़ती। इसी प्रकार T के अन्तर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। प्रो० हॉम कहते हैं कि हम परिमाण समीकरण को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए अन्यथा हम बहुत सी कठिनाइयों में पड़ जायेंगे।

(6) मिद्धान्त तब समाज के लिए तो सही है प्रयत्नशील समाज के लिए नहीं—आलोचक कहते हैं कि मुद्रा परिमाण मिद्धान्त की मान्यताएँ स्थिर समाज के लिए तो सही हो सकती हैं, परन्तु दारिद्र्य अथवा अनिश्चित समाज के लिए यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रो० ब्रॉगम का कहना है कि ऐसे मिद्धान्त का सामाजिक परामर्श की प्रावणिकता को जानना उन तत्त्वों का विवेचन इस प्रकार में हो जो कीमत-स्तर निर्धारण की अस्थिर प्रक्रिया तथा विभिन्न साम्य स्थितियों की प्रणाली का अध्ययन करती हो।¹

(7) कीमत-स्तर तथा मुद्रा की पूर्ति के बीच सीधा तथा हेतुक सम्बन्ध नहीं होता—यह आलोचना विशेष रूप से Prof. Von Hayek ने अपनी पुस्तक "Prices and Production" में की है। वे कहते हैं मुद्रा परिमाण मिद्धान्त यह तो बनाता है कि एक समय विशेष में कीमत-स्तर क्या है परन्तु यह उन कारणों की व्याख्या नहीं करता जो कीमत-स्तर में परिवर्तन लाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह मारते हैं कि यह उन छुपे हुए कारणों की व्याख्या नहीं करता जो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार यह मिद्धान्त M तथा P का अवास्तविक हेतुक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है तथा यह चीजों में होने वाले उन संशोधन परिवर्तनों को जो मौद्रिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, की व्याख्या नहीं करता।

(8) व्यापार चक्रों की उपेक्षा—आलोचक कहते हैं कि बिना मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हुए कीमत-स्तर में व्यापार चक्रों के कारण परिवर्तन होते हैं जिससे बारे में यह मिद्धान्त कुछ नहीं कहता। विवश्याभि तीमा की मन्दी इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह मिद्धान्त तो यह कहता है कि मन्दीमान में कीमत-स्तर ऊँचा करने की दृष्टि से चक्रों में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अमरुषा म मन्दी के समय चक्र में अधिर अनिरिक्त मुद्रा की मात्रा डारने पर भी कीमत-स्तर में आगातीन वृद्धि नहीं हुई थी।

(9) मुद्रा की मात्रा (M) को कीमत-स्तर के निर्धारण का एकमात्र कारण मानना उचित नहीं है—प्रो० ब्रॉगम कहते हैं कि मुद्रा परिमाण मिद्धान्त में कीमत-स्तर निर्धारण में मुद्रा की मात्रा को एकमात्र कारण मान लेना उचित प्रतीत नहीं होगा। ऐसा कहता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन में ही कीमत-स्तर परिवर्तित नहीं होता बल्कि इसमें परिवर्तन आय, व्यय, बचत एवं विनियोग जैसे मुख्य कारणों द्वारा भी होते हैं जिससे बारे में यह मिद्धान्त कुछ नहीं कहता।

(10) मिद्धान्त कुछ मौद्रिक कारणों की ही नहीं बल्कि अमौद्रिक कारणों की भी उपेक्षा करता है—आलोचक कहते हैं कि प्रो० दारिद्र्य निगर ने उन अमौद्रिक कारणों की

1 'The real task of such a theory is to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a number as to exhibit the causal process by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another.'

बर्चा की है जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं परन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्त की व्याख्या में इन तथ्यों की उपेक्षा की है। अमौद्रिक कारणों जैसे मातायात सुविधाओं, उद्योगों में विस्तार तथा मानव आदर्शताओं की भिन्नता आदि ऐसे अमौद्रिक तत्व होते हैं जिनसे व्यापारिक प्रियायात में वृद्धि होती है जिससे परिणामस्वरूप कीमत स्तर में गिरावट आती है। इसी प्रकार बहुत से अमौद्रिक कारणों से मुद्रा में चलन-वेग में वृद्धि कीमत-स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है जिसको प्रो० पिशर अपने सिद्धान्त में महत्व नहीं देते जो वृद्धिपूर्ण है।

(11) पूर्ण रोजगार की मान्यता वृद्धिपूर्ण है—आलोचक कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्तपूर्ण राजगार की स्थिति को मानकर चलता है जबकि व्यावहारिक रूप से पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी देश में नहीं मिलती। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त केवल उन्नी अवस्था में नहीं हो सकता है जबकि उत्पादन की मुद्रा लोच मुख्य होगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन की मुद्रा लोच घनात्मक है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि लाएगी और मुद्रा परिमाण सिद्धान्त सभू नहीं होगा। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त केवल उन्नी अवस्था में लागू होगा जहाँ बेरोजगार साधन नहीं पाए जाते। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगार साधन हैं तो उत्पादन का पूर्ति वन आंचदार होगा और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि लोगों की आय तथा उत्पादन में वृद्धि करेगी न कि कीमत-स्तर में।

(12) यह सिद्धान्त व्यापारियों के सीधों का माप करता है न कि मुद्रा की प्रय-शक्ति का—प्रो० बीन्स कहते हैं कि पिशर की व्याख्या में मुद्रा व्यापार की व्याख्या करता है जिसे मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। बीन्स कहते हैं कि मुद्रा वस्तु माँदा की ओर संचित करता है जबकि मुद्रा का पुरा वस्तु माँदा में अतिरिक्त बहुत से व्यापारिक औद्योगिक और विधायी मुद्रा दिए जाते हैं जिनके कारण से यह सिद्धान्त कुछ नहीं करता। धन्य माँदे मुद्रा माँदा का एक छोटा सा भाग होते हैं।

(13) यह सिद्धान्त अपूर्ण है क्योंकि यह मुद्रा के विनिमय माध्यम कार्य की व्याख्या करता है, मुख्य संचय कार्य की नहीं—आलोचक कहते हैं कि पुराने अर्थशास्त्रियों की इस मान्यता को प्रो० पिशर न स्वीकार किया है कि मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य केवल विनिमय का माध्यम ही है और दूसरा सम्पादित करने के लिए ही केवल मुद्रा की माँग की जाती है वरन् मुद्रा एक महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रो० बीन्स कहते हैं कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के अलावा भू-संचय (Store of Value) का कार्य भी करती है जिसकी उपेक्षा प्रो० पिशर नहीं करते। मनुष्य मुद्रा की माँग वतमान आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भविष्य की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए भी रखता है जिनके लिए मुद्रा संचित की जाती है। मुद्रा ने घन मरम भाग को भरन बना दिया है। समाज में मुद्रा का महत्व इस कारण होता है क्योंकि यह वतमान तथा भविष्य के बीच एक बड़ी का कार्य करती है। प्रो० पिशर न मुद्रा के भू-संचय जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है।

(14) कीमत-निर्धारण विधि वृद्धिपूर्ण है—यह आलोचना प्रमुख रूप से प्रो० डम्बू० सी० मिचेल (Prof. W. C. Mitchell) ने की है। वे कहते हैं कि कीमत निर्धारण मुद्रा को कुछ वस्तुओं से भाग देकर होता है अर्थात् $P = \frac{M}{T}$ । कीमत-निर्धारण की यह

विधि गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि कीमत निर्धारण में माँग के अलावा भविष्य का भी प्रभाव पड़ता है। Prof. Mitchell कहते हैं कि "अधिकतर समय P तथा T समो-बर्णन में परिवर्तित होता है न कि M का भाग करत है और वे M तथा V में परिवर्तन लाते हैं। इसके अतिरिक्त वे M पर भी प्रभाव डालते हैं।"

(15) कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त की उपेक्षा—आलोचक कहते हैं कि प्रो० पिशर की व्याख्या कीमत-निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त से अत्यन्त दूर है। सत्यता यह है कि सभी वस्तुओं के समान मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति का घटिया द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति पक्ष की अधिक महत्व देता है तथा एक पक्षीय है एवं अधूरा है।

(16) कीमत-स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रभाव—प्रो० पिशर के सिद्धान्त की एक आलोचना यह भी की जाती है कि इन्हीं दश वा कीमत-स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का वजन कम प्रभाव की उपेक्षा की है। एक दश वा मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे दश पर पड़ना एक स्वाभाविक घटना है।

(17) व्याज की दर की उपेक्षा—आलोचक कहते हैं कि प्रो० पिशर ने व्याज की दर जैसे मौद्रिक तत्त्व की उपेक्षा की है जो कि मुद्रा की माँग (M) तथा कीमत स्तर (P) के मध्य एक कड़ी का काम करता है।

(18) यह सिद्धान्त यह तो बताता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन क्यों होता है परन्तु यह नहीं बताता कि यह परिवर्तन क्यों होते हैं—प्रो० आल्फ्रेड न उत्त आलोचना करते हुए कहा है कि यह नहीं बता सकता कि क्योंकि ऐसा होता है कि मुद्रा की माँग डायन पर कीमत स्तर बढ़ता है जबकि दूसरे समय उतनी ही मुद्रा की माँग जान पर कीमत स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।¹

(19) यह सिद्धान्त उन कारणों की व्याख्या करता है जो चलन-वेग को नियन्त्रित करते हैं—आलोचक कहते हैं कि जब कीमता में गिरावट का चिह्न प्रथम हो तो मुद्रा के चलन वेग का तीव्रता नीचा तथा कीमता का बढ़ने का स्थिति में मुद्रा का चलन-वेग ही तीव्रता ऊँचा होती है। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त इन कारणों की व्याख्या नहीं करता जो चलन-वेग को प्रभावित एवं नियन्त्रित करते हैं।

(20) प्रो० कैनन का कहना है कि अन्य वस्तुओं की माँग मुद्रा माँग और पूर्ति के प्रमाणी नियम द्वारा नियन्त्रित नहीं होते—प्रो० कैनन का इस सम्बन्ध में कहना है कि मुद्रा की माँग व्यापारिक सौदा की मात्रा पर निर्भर न करके तोला द्वारा नक्का रण की योग्यता और द्रव्य पदों के उभे प्रकार निर्भर करती है जिन प्रकार मराना की माँग मरानों में रहने वाला व द्रव्य होता है न कि उन व्यक्तियों के द्वारा जो मराना का प्रत्यक्ष विषय अथवा विषय पर उठाते हैं।²

निष्कर्ष (Conclusion)—प्रो० हरविंग पिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की इन आलोचनाओं को रटते रहता ऐसा लगता है कि यह सिद्धान्त अब एक श्रुति में भरा पड़ा है और शायद ही इसका कोई उपयोग अवसरों जैसे विज्ञान का होगा, परन्तु ऐसा मोक्षता उचित नहीं है। सिद्धान्त की उपर्युक्त आलोचनाओं के बाद भी मुद्रा परिमाण सिद्धान्त इन बातों की ओर संकेत करता है कि मुद्रा की माँग में वृद्धि होने से कीमत-स्तर सामान्य दशा में बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कीमत-स्तर में वृद्धि का एक मात्र नहीं तात्पर्य सचम एक प्रमुख कारण मुद्रा की माँग में वृद्धि होना होता है।

1. It cannot even explain why it is that a creation of money will some times take and start off a rise in prices, while at another an equal creation may have no effect at all "
-Cronicker

2. Edwin Cannon

यह सिद्धान्त तर्कानुसार सरकारी ने लिए एक स्रोत पर एक चैतावी अवश्य प्रस्तुत करता है और वह यह है कि अव्यवस्था को मनुष्य में बनाये रखने के लिए सरकार को मुद्रा की मात्रा पर समय समय पर अनुचित लगाना चाहिए अर्थात् देश की मौद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मुद्रा की पूर्ति करनी चाहिए। सरकार को उन तत्त्वों पर भी नियन्त्रण रखना चाहिए जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुद्रा स्फीति मात्र में चलन में मुद्रा की मात्रा कम तथा अवस्था की मात्रा में चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ानी चाहिए अथवा स्फीतिमान में लोगों की प्रयत्न-शक्ति पर नियन्त्रण के उपाय तथा अवस्था की मात्रा में लोगों के लिए प्रयत्न-शक्ति प्रदान करने के उपाय करने चाहिए। इस प्रकार अव्यवस्था को मनुष्य की स्थिति में रखने के लिए सरकार की मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मौद्रिक नीति के माध्यम-साथ अन्य उपाय भी सरकार को आतन की गलाह हो जाती है।

सिद्धान्त की ऐतिहासिक पुष्टि—मुद्रा परिमाण सिद्धान्त स्पष्ट नहीं है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब-जब मुद्रा की मात्रा घटती है तो मूल्य-स्तर में वृद्धि हुई है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा बेल्जियम में मोनो-मोदी की मात्रा में इन घातकों की पूर्ति बढ़ी और योरोप में इन घातकों के निर्धारण होने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ी थी जिससे मूल्य-स्तर बढ़ा था। इसी प्रकार प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की मात्रा-स्तर में वृद्धि का कारण बना। वर्ष 1923 में जर्मनी में तथा 1917-45 में चीन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का कारण अति स्फीति (Hyper-Inflation) की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में छोटे देशों में दुनिया में स्वयं तथा चीन के उत्पादन में गिरावट आने से कीमत-स्तर में गिरावट के चिह्न दिखाई दे रहे थे। प्रो० गुस्ताव कैसल (Prof Gustav Cassel) ने मासिक-मासिक आंकड़ों का माध्यम से यह बताने का प्रयास किया था। 1914 के बाद नोट चलन में बढ़ रहे थे जिससे कारण कीमत-स्तर भी बढ़ रहा था।

भारत में भी पिछले वर्षों से लगातार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत-स्तर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की नवद शेष व्याख्या अथवा कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण (Cash Balance Approach of Quantity Theory of Money or Cambridge Economists View)

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या नवद शेष मनीकरण द्वारा भी की जाती है। मुद्रा परिमाण की इस व्याख्या को प्रमुख रूप में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों जैसे प्रो० एल्फ्रेड मार्शल प्रो० पीगू प्रो० रायटमन तथा प्रो० एम० कीन्स (Prof Alfred Marshall, Prof Pigou Prof Robertson and Prof J M Keynes) आदि अर्थशास्त्रियों ने समर्थन दिया जाता है। परन्तु इन अर्थशास्त्रियों में पहले भी प्रो० एल्फ्रेड मार्शल, विनिमय पैटी, जॉन मेनॉ तथा रिचर्ड स्ट्रॉस आदि विद्वानों के लेखन कार्यों में इससे चिह्न मिलते हैं। कैम्ब्रिज विद्वानों ने प्रो० फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आलोचना प्रमुख रूप से मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के विनिमय माध्यम का पर आवश्यकता से अधिक महत्व देने का प्रयास करत हुए की है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नवद शेष व्याख्या मुद्रा की मात्रा में सम्बन्धित होती है जो लोग अपने पास निरर्थक वस्तुओं के साथ रखते हैं न कि एक सम्पदाधि में रखते हैं। दूसरे शब्दों में उन विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की मात्रा और पूर्ति द्वारा एक समय-क्षण में मुद्रा का मूल्य निर्भर रहता है न कि एक सम्पदाधि में। इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। इससे पहले के अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति तथा माँग के महत्वपूर्ण माना

धा और मुद्रा की माँग को स्थिर मानकर उस उपस्थित कर दिया पुनः विभिन्न विद्वानों ने मुद्रा की प्रकृति व माँग मुद्रा के माँग पक्ष को अधिक महत्व दिया है।

विभिन्न विचारधाराओं अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की माँग पर निर्भर करता है और मुद्रा की माँग विनिमय के माध्यम अर्थात् व्यापारिक लेन देन सम्पादन हेतु नहीं होती बल्कि मुद्रा का मूल्य सचय वाच्य (Store of Value) अर्थात् नकद रक्का की प्रवृत्ति पर जो विभिन्न उद्देश्यों द्वारा प्रभावित होती है निर्भर करती है। यह विद्वान कहते हैं कि मुद्रा की दो विशेषताएँ प्रमुख हैं। प्रथम बैठी हुई मुद्रा (Sitting Money) दूसरी उड़ती हुई मुद्रा (Money on Wings) जो मूल्य सचय (Store of Value) तथा विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) भावों से विभक्त होता है। विभिन्न विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की वास्तविक माँग उन लोगों का द्वारा की जाती है जो कि मुद्रा का विभिन्न उद्देश्यों की प्रकृति व प्रयोग अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। विभिन्न सम्प्रदाय के सहायक अर्थशास्त्री प्रो० भागवत ने नकद को संचयन व सार का अभाव हटा निम्नांकित बातें लिखी हैं।

समाज की प्रत्येक अवस्था में लोग अपनी आय का एक भाग को पान मुद्रा अर्थात् नकद में रखना चाहते हैं यह भाग 1/5 1/10 तथा 1/20 हो सकता है। इस नकद मुद्रा को पान के कारण उनको अपने व्यक्तियों को संचयित करने में आसानी तथा सुविधा हो जाती है तथा उनका मौन भाव करने से हानि का भाव मिट जाता है परन्तु दूसरा ओर यह अनाधिकांगी साधन के रूप में रखा हो सकता है जो कि विनिमय करने में आय प्राप्त तथा पराक्रम दिखाने का साधन होता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आय का भाग को मुद्रा तथा अन्य किसी रूप में संचयित रखने व निवेश करने समय इस विचार का कि वह पान भाव लाभ का उपाय जोग्य करता है। यह उस भाव को कि उस अपना आय तथा धन का नकदी में संचय रखने का कारण प्राप्त होती है सुविधा अथवा लाभ तथा उस हासिल से परमा है जो उसकी आय तथा धन को विनियमित व कराने का कारण उठानी पड़ती है - हम यह मानकर चलें कि एक देश के निवासी भिन्न-भिन्न धन सम्पत्ति व इस भाग को अपने पास वय शक्ति व रूप में संचयित करते हैं तो सम्पूर्ण मुद्रा की पान माता इन सब धनसाधनों का योग व बराबर होगी।¹

1 In every state of society there is some fraction of their income which people find it worthwhile to keep in the form of currency it may be a fifth or a tenth or a twentieth. A large command of resources in the form of currency renders their business easy smooth and puts them at an advantage in bargaining but on the other hand it locks up in a barren form resources that might yield an income or gratification if invested. Every man finds the appropriate fraction after balancing one against another, the advantages of a further ready command and the disadvantages of putting more of his resources into a form in which they yield him no income or income or other benefit.

Let us suppose that the inhabitants of a country find it just worthwhile to keep by them on the average ready purchasing power to the extent of a tenth part of their property then the aggregate value of the currency will tend to be equal to the sum of these amounts.

—Prof Alfred Marshall

वैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण निम्नलिखित रूप में बताए जा सकते हैं—

(1) प्रो० मार्शल का समीकरण—प्रो० मार्शल वैम्ब्रिज सम्प्रदाय के स्थापक अर्थशास्त्री थे। जैसा कि मार्शल की उपर्युक्त व्याख्या से ज्ञात होता है उन्होंने बताया है कि लोग अपनी वार्षिक आय तथा सम्पत्ति का एक भाग नगदी के रूप में रखते हैं। लोगो द्वारा मुद्रा की माँग का सम्बन्ध उनके द्वारा कुल बाय तथा सम्पत्ति के नगद रूप अथवा नगद शक्ति (नगदी में मुद्रा तथा बैंक जमाएँ शामिल होती हैं) का सम्बन्ध इस सम्पत्ति तथा आय की मात्रा के स्थिर अनुपात से होता है जिससे हम औसत रूप में $1/5$, $1/10$ या $1/20$ भाग में व्यक्त कर सकते हैं। मार्शल का समीकरण निम्न रूप से दिया जा सकता है—

$$M = KY + K'A$$

M = मुद्रा की मात्रा। Y = कुल आय। K = कुल आय का वह भाग जिसे लोग समाज में मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं।

K' = कुल सम्पत्ति वह भाग जिसे उसका स्वामी मुद्रा के रूप में रखता है।

A = कुल सम्पत्ति का द्रव्य मूल्य

मार्शल के उपर्युक्त समीकरण को हम दो रूपों में दलते हैं प्रथम आय भाग, दूसरा सम्पत्ति भाग। प्रो० मार्शल के समझना के सम्पत्ति भाग को अनावश्यक समझते हुए इसे हटा दिया और उनका समीकरण का सामान्य रूप इस प्रकार हो गया—

$$M = KY$$

M = मुद्रा की मात्रा

K = आय का वह भाग जिसे लोग नगद रूप में रखना चाहते हैं अर्थात् वह का आपसी सम्बन्ध (That Portion of Income which People Want to Hold in the form of Money or Reciprocal of Velocity)

यदि Y के स्थान पर PO को रखा जाये अर्थात् कुल वार्षिक आय कुल वास्तविक उत्पादन (Output or O) तथा कीमत-स्तर (Price-Level or P) का गुणनफल होती है तो समीकरण का रूप इस प्रकार होगा—

$$M = KPO$$

$$\text{अथवा } P = \frac{M}{KO}$$

M = मुद्रा की मात्रा

P = कीमत-स्तर

O = कुल वास्तविक उत्पादन

K = वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं।

(2) प्रो० पोर्ग का समीकरण—प्रो० ए० सी० पोर्ग प्रो० मार्शल के शिष्य थे और वैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद में अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। उनके समीकरण के भी दो रूप हैं जो निम्नलिखित हैं—

$$(a) P = \frac{KR}{M} \quad (\text{मुद्रा की एक इकाई के मूल्य की व्याख्या के रूप में})$$

$$\text{or } P = \frac{M}{KR} \quad (\text{वस्तु की एक इकाई के मूल्य के रूप में})$$

P = मुद्रा का मूल्य अथवा प्रत्यक्ष शक्ति

M = कुल मुद्रा की मात्रा अथवा मुद्रा इकाइयों की कुल मात्रा

K = कुल वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नगदी के रूप में रखाते हैं।

R = कुल वास्तविक आय

प्रो० पीगू कहते हैं कि सभी लोग पूर्णरूप से नगदी नहीं रखते अर्थात् वानूनी मुद्रा को अपने पास नगद रूप में नहीं रखते। कुछ लोग इन धनराशि का एक भाग बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रो० पीगू ने समीकरण का विस्तृत रूप निम्न प्रकार से सामने आता है

$$P = \frac{KR}{M} [C + h(I - C)]$$

$$\text{अथवा} \quad M = \frac{KR}{P} [C + h(I - C)]$$

समीकरण P, M, K, R का अर्थ पहले वाले समीकरण के समान है। C = विधि-प्राप्त अथवा वानूनी मुद्रा की वह राशि जिसे लोग नगदी के रूप में रखते हैं। $I - C$ विधि-प्राप्त नगद कोषों का वह भाग जिसे लोग बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं। h = बैंक जमाओं का वह भाग जिसे बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं। प्रो० पीगू ने अपने समीकरण में बैंक जमाओं को अलग स्थान देने के कारण ही समीकरण को विस्तृत कर लिया है। बैंकिंग परम्परागत रूप से बैंक जमा भी नगदी की भाँति ही तरफ होती है इसलिए व्यापहारिक दृष्टि से प्रो० पीगू के प्रथम समीकरण को ही अधिक मान्यता प्राप्त है अर्थात्

$$P = \frac{KR}{M} \quad \text{or} \quad P = \frac{M}{KR}$$

प्रो० पीगू के समीकरण के तत्व P, K, R को स्वतन्त्र चर (Independent Variables) के रूप में नहीं माना जाता है और न ही यह आवश्यक है सभी चर एक ही दिशा में गतिशील हों। M सरकार द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि M में परिवर्तन होने पर P में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। इसका कारण यह है कि M में परिवर्तन के साथ-साथ K तथा R तत्त्वों में भी परिवर्तन हो सकता है। समीकरण में K द्वारा वास्तविक आय आत की जा सकती है।

(3) प्रो० राबर्टसन का समीकरण—प्रो० डी० एच० राबर्टसन वैभिन्न सम्प्रदाय के सदस्य थे। उनका नगद कोष समीकरण निम्न प्रकार दिया जाता है—

$$M = PKT \quad \text{or} \quad P = \frac{M}{KT} \quad \text{or} \quad P = \frac{KT}{M}$$

प्रो० राबर्टसन का समीकरण प्रो० पीगू के समीकरण से थोड़ा ही भिन्न है। प्रो० राबर्टसन का समीकरण प्रो० पीगू समीकरण से अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रो० रिशर के समीकरण से इसको उल्टा करना आसान है। वैभिन्न समीकरण में यह सबसे सगन है। प्रो० राबर्टसन ने P, M, T आदि तत्वों को प्रो० रिशर के समीकरण के अनुसार तथा K को माँगों के समीकरण के अनुसार मान लिया है।

(4) प्रो० वीन्स का समीकरण—प्रो० जे० एम० वीन्स पहले कैम्ब्रिज सम्प्रदाय के अर्थशास्त्री और प्रो० मार्शल के समर्थक तथा शिष्य थे। प्रो० वीन्स के समीकरण को कैम्ब्रिज समीकरण में संशोधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इस समीकरण को वास्तविक शेष व्याख्या (Real Balance Approach) के नाम से अपनी पुस्तक "A Tract on Monetary Reform" में अलग से दिया है। उनका कहना था कि उपभोग इकाइयों में सम्बन्धित वास्तविक लेन-देन की एक निश्चित राशि के बराबर व्यक्ति अपने पास वास्तविक शेष (Real Balance) रखते हैं।

प्रो० वीन्स का कहना है कि मुद्रा को रखने वाले व्यक्ति को वास्तविक शेषों की उतनी मात्रा की आवश्यकता होगी जो कि उपयोग इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक लेन-देन की मात्रा जिस पर उन्हें व्यय किया जाता है के आपसी सम्बन्ध क्या है? उन्होंने वास्तविक शेषों को उपभोग इकाइयों द्वारा मापा है और इस निष्पत्ति पर पहुँचे थे कि यदि वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन-देन की मात्राओं का आपसी सम्बन्ध पूर्ववर्ती या पहले जैसा ही रहता है तो नकद शेषों (Cash Balances) की राशि, जिसकी आवश्यकता होगी वह वास्तविक शेषों की उस राशि के बराबर होगी जिसका निर्धारण उपर्युक्त आपसी सम्बन्धों (वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन-देन) द्वारा होता है। प्रो० वीन्स का यह समीकरण निम्न प्रकार से है—

$$n = p(K + rK')$$

n = नकद मुद्रा की कुल मात्रा

p = उपभोग इकाइयों की कीमत-स्तर

r = बैंक की नकद निधि तथा कुन जमाओं का अनुपात

K = वास्तविक शेषों की राशि जिन्हें नकद रखा जाता है अथवा उपभोग इकाइयों की मात्रा जिनको जनता मुद्रा के रूप में संचित रखती है।

K' = वास्तविक शेष जो बैंक जमा के रूप में रहते हैं अथवा उपभोग इकाइयों की वह मात्रा जिनको प्राप्त करने के लिए समाज मुद्रा को बैंकों में जमाओं के रूप में रखता है।

प्रो० वीन्स के इस समीकरण को इस प्रकार भी रखा जाता है—

$$P = \frac{n}{K + rK'}$$

प्रो० वीन्स के समीकरण में K तथा K' के मध्य अनुपात लोगों की बैंकिंग आदतों पर निर्भर करेगा जबकि उनका विस्तृत मूल्य लोगों की अपनी आदतों पर निर्भर करेगा। r का मूल्य बैंकिंग व्यवस्था द्वारा नकदी रखने की प्रथा पर निर्भर करेगा। प्रो० वीन्स यह मानकर चलते हैं कि K , K' तथा r अल्पकाल में लगभग अपरिवर्तित रहते हैं और P में परिवर्तन n में परिवर्तनों के आधार पर होते हैं।

प्रो० वीन्स के उपर्युक्त समीकरण को हम कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेणी में लेते हैं

क्योंकि प्रो० पीगू के समीकरण $P = \frac{M}{KR}$ तथा $P = \frac{n}{K + rK'}$ में कोई विरोध अलग नहीं है।

कैम्ब्रिज समीकरण नकद शेष की आलोचनायें (Criticisms of Cambridge Cash Balances Equation)

नकद शेष समीकरण भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। निम्नांकित तथ्यों के आधार पर इसकी आलोचनाएँ निम्नांकित हैं।

(1) अर्थव्यवस्था में मूल्यों की गत्यात्मक प्रवृत्ति के प्रति उदासीनता—आलोचक कहते हैं कि कैम्ब्रिज व्याख्या अर्थव्यवस्था में मूल्यों की गत्यात्मक प्रवृत्ति के बारे में कुछ नहीं कहती। इन प्रकार यह व्याख्या भी अधूरी है।

(2) मुद्रा के सर्वव्यापी रूप की अवहेलना—कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचना का एक आधार यह है कि यह समीकरण मुद्रा की माँग निर्धारण में सभी तथ्यों की व्याख्या नहीं करता उदाहरणार्थ मुद्रा की माँग के उस पक्ष की व्याख्या नहीं करता जो सट्टा उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है तथा जिनका मूल्य की कुल माँग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(3) समीकरण के विभिन्न तरकों की अस्थिरता—कैम्ब्रिज व्याख्या की एक अन्य आलोचना यह है कि समीकरण में K तथा T को स्थिर माना गया है। इस कारण नकद शेष समीकरण में ये सभी आलोचनाएँ लागू होती हैं जो विश्व के समीकरण के बारे में की जा चुकी हैं।

(4) मुद्रा की माँग में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव अस्पष्ट है—आलोचक कहते हैं कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री यह विक्षेपण नहीं कर पाए कि मुद्रा की माँग में किसी भी हुई माँग की वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यों तथा उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है।

(5) सीमित स्तर को प्रभावित करने वाले सभी तरकों की उपेक्षा—कैम्ब्रिज व्याख्या उन सभी शक्तियों की व्याख्या नहीं करती है जो P को प्रभावित करने हैं— जैसे व्याज की दर मुद्रा की पूर्ति आदि।

(6) बचत जमा राशियों की स्पष्ट व्याख्या—यह आराग्य भी कैम्ब्रिज व्याख्या पर लगाया जाता है कि यह उन बैंक जमा राशियों के बारे में कुछ नहीं कहती जो व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

प्रो० फिशर की व्याख्या (लेन-देन) तथा कैम्ब्रिज व्याख्या (नकद शेष) की तुलना (Comparison of Prof. Fisher's (Transactions) and Cambridge's (Cash Balance) Approaches)

प्रो० फिशर एवं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की मुद्रा परिमाण मिद्धान्त की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि दोनों विचारधाराओं की व्याख्या के लिए जो समीकरण प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कुछ समानताएँ तथा अलग-अलग अर्थों में अन्तर देखने को मिलते हैं। जबकि पहले हम समानताओं और उनके बाद अलग-अलगताओं का अवलोकन करेंगे।

दोनों समीकरणों में समानता—प्रो० फिशर तथा कैम्ब्रिज विचारधारा में समानता अंशजित आधार पर पाई जाती है—

(1) प्रो० पिन्गन व समीकरण में मुद्रा व चलन-वेग (V) को अधिक महत्व दिया गया है जबकि रैम्सिज व्याख्या में नरद राजि (K), जो गणितीय दृष्टि में मुद्रा के चलन-वेग का विपरिणत है, को अधिक महत्व दिया गया है। यदि दोनों समीकरणों को मुद्रा मूल्य निर्धारण में मिला मुद्रा को अलग से महत्व न देकर उसे भी मुद्रा ही मान लिया जाए तो

गणितीय दृष्टि में प्रो० पिन्गन और रैम्सिज व्याख्या समान माना जायेंगे जहाँ $P = \frac{MV}{T}$

or $P = \frac{M}{KR}$ का तात्पर्य MV तथा M दोनों एक समान हैं। समीकरण व नीचे वाले

भाग अर्थात् T तथा KR ही यथार्थ निर्धारक होते हैं। T को प्रो० पिन्गन न समझ सकने का अर्थ यह होता है कि जो नरद मुद्रा द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं जबकि KR का रैम्सिज अर्थशास्त्रियों ने उस नरद मुद्रा के व्यक्त किया है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रदान करने हेतु व्यक्ति नरद रूप में खर्चते हैं। इस प्रकार $1/V$ तथा V के स्थान पर $1/K$ द्वारा भी इन दोनों में समानता स्थापित की जा सकती है।

(2) दोनों ही समीकरण एक ही घटना के दो रूप नजर आते हैं जैसा कि प्रो० टी० एन० गनरमन कहते हैं। नरद व्यापार्य समीकरण मुद्रा व बहाव (Flow) को अधिक महत्व देता है जबकि नरद-शेष समीकरण T मुद्रा व स्टॉक (Stock) को अधिक महत्व दिया गया है। नरद शेष समीकरण में प्रो० पीगू के KR तथा प्रो० रैम्सिज के $K + rK'$ प्रो० पिन्गन के T द्वारा एक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम्बन्ध मन-वेग में सम्मिश्रित कार्यों में है। इस प्रकार दोनों समीकरण एक ही घटना के दो रूप नजर आते हैं।

(3) दोनों ही मुद्रा की मात्रा का मूल्य-निर्धारण का एक आधारभूत तत्त्व मानते हैं। दोनों समीकरणों में असमानताएँ

प्रो० पिन्गन तथा रैम्सिज व्याख्या दोनों में जहाँ एक ओर कुछ समानताएँ दिखाई देती हैं वहीं दूसरी ओर कुछ महत्वपूर्ण असमानताएँ भी देगन भी मिलती हैं जो दोनों व्याख्याओं को एक-दूसरे से पृथक् करती हैं। यह असमानताएँ निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जा सकती हैं—

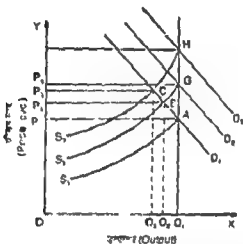
(1) कीमत-स्तर का अर्थ—प्रो० पिन्गन के समीकरण में कीमत स्तर (P) का अर्थ सामान्य कीमत-स्तर (General Price Level) है जबकि नरद शेष समीकरण में कीमत-स्तर का अर्थ उपभोग वस्तुओं की कीमतों में है। प्रो० ए० एन० रैम्सिज (Prof A H Hansen) ने दोनों में अन्तर करते हुए कहा है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत को नरद शेष व्याख्या $M = KY$ कीजिए रूप में मुद्रा तथा कीमतों की पूर्णतया एक नयी व्याख्या है।

(2) गणितीय दृष्टि से अन्तर—सामान्यतः यह कहा जाता है कि नरद शेष समीकरण गण-बीजगणितीय परिधान में मुद्रा परिमाण सिद्धांत ही है न कि नहीं है। प्रो० एम० एच० हेमन कहते हैं कि गणितीय दृष्टि में K नरद व्यापार्य समीकरण $MV = PO$ में V का उल्टा है। वे आगे कहते हैं कि गणितीय समानता की दृष्टि में $T = 1/K$ में यह सिद्ध नहीं हो जाता कि मार्गनारी सिद्धेयन मानव में ह्यूम-पिन्गन (Hume-Fisher) विरो-

के रूप में प्रयोग में लाई जाती है तथा परिणामस्वरूप प्रथम वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने से अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होगी।

सापेक्ष वृद्धि स्फीति का रेखाचित्र

निम्न रेखाचित्र सापेक्ष वृद्धि स्फीति को बताता है। चित्र में पूर्ण रोजगार उत्पादन सम्बन्धित बिन्दु पर OQ_1 प्राप्त होता है जहाँ DI तथा HI एक-दूसरे को काटते हैं अर्थात् A बिन्दु पर। इस बिन्दु A पर उत्पादन OQ_1 है तथा कीमत OP_1 है। अब कुल पूँति का



S_1 से S_3 पर जाता है तो उत्पादन की कुल मात्रा निरन्तर OQ_1 हो जाती है और कीमत-स्तर O बिन्दु पर OP_3 हो जाता है। इसी प्रकार अब पूँति चलन बढ़कर S_3 हो जाता है तो कीमत-स्तर बढ़कर OP_3 हो जाता है। यह स्थिति उन्त समय तक रहेगी जब तक कि पूँति चलन बढ़ने की प्रवृत्ति दिसलाएगा।

उदाहरणार्थ जहाँ इस्पात मिन में काम करने वाले श्रमिकों के वेतनों में वृद्धि हो जाने से हेतु इस्पात के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो परिणामस्वरूप कृषि वगैरह मोटर साइकिलों आदि वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो जायगी। मोटर बसों तथा ट्रकों की कीमत में वृद्धि होने से परिणामस्वरूप परिवहन तथा यात्रा करने के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। कृषि वगैरह के मूल्यों में वृद्धि होने से हेतु साधान के मूल्य में वृद्धि होगी तथा रहन-सहन की लागत में वृद्धि हो जायगी जिससे परिणामस्वरूप सामान्य वेतनों में वृद्धि होगी। इस प्रकार मूल्य-वृद्धि की यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेगी। स्फीति के निम्न प्रकारों को अगले पृष्ठ पर दिने चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है —

माँग प्रेरित स्फीति व साम्य सापेक्ष वृद्धि स्फीति (Demand Pull Inflation Versus Cost Push Inflation)

कुछ आर्थशास्त्रियों का विचार है कि स्फीति न केवल माँग वृद्धि अथवा न केवल लागत वृद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि इसमें माँग और लागत दोनों ही प्रकार की वृद्धि के तत्त्व पाए जाते हैं। ये कहते हैं कि साम्य वृद्धि स्फीति नाम की स्फीति होती ही नहीं है, क्योंकि बिना माँग तथा नद वृद्धि के वृद्धि हुए, साम्यों में

केरोजगारी तथा खाद में मंदी लाएगी न कि स्फीति । इसी प्रकार में यह कहा जा सकता है कि माँग वृद्धि स्फीति को नहीं लाती है जब तक लागतों में वृद्धि न आ जाए परन्तु यह स्थिति एक प्रमुख अन्तर की उद्घोषा करती है । जैसे कि क्या सामान वृद्धि पूर्व अधिक माँग के सम्मुख अथवा उगकी पूरा कर लेती है अथवा क्या यह अमन्तन की स्थिति में से जाती है अथवा क्या यह अतिरिक्त पूर्ति (अथवा उत्पादन क्षमता) को सृजित करती है जिसकी प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने से या स्थिति दिया जा सकता था ।

प्रो० एच० जी० जॉन्सन (Prof H G Johnson) ने दोनों प्रकार की स्फीति के सम्बन्ध में वाद-विवाद को समाप्त करते हुए कहा है कि ' दोनों विद्वान् स्फीति के स्तम्भ एक अपने आप में पूर्ण विद्वान् नहीं बने जा सकते बल्कि उन्हें मौद्रिक वातावरण में स्फीति प्रक्रिया (Mechanism) से सम्बन्धित विद्वान् के रूप में देना चाहिए ।'¹ यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि इस बात का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन एक जटिल कार्य है कि विशेष प्रकार की स्फीति माँग प्रेरित अथवा लागत प्रेरित स्फीति है ।

दोनों प्रकार की स्फीति में अन्तर पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं है परन्तु फिर भी हम जान से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके अन्तर से माँग तथा लागत प्रेरित शक्तियाँ को अलग करने में गहनता मिलती है । इन दोनों का अन्तर नीतिगत दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पता जा सकता है ।

स्फीति अन्तराल ² (Inflationary Gap)

इंग्लैण्ड के वित्त मंत्री ने अपने अप्रैल 1941 के बजट भाषण में परिभाषित किया था । उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि ' यह (स्फीति अन्तराल) सरकारी व्यय वह माया है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में माणव-शक्ति अथवा भौतिक सामानों की अथवा समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा साधनों की कोई अनुरूप मात्रा प्राप्त न होती हो ।'³ स्फीति अन्तराल अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को बनाता है जिसमें स्थिर कीमतों पर

1 " ... The two theories are therefore not independent and self contained theories inflation but rather theories concerning the mechanism of inflation in a monetary environment that permits it ' Essays in Monetary Economics—H G Johnson

(London, 1967) P 128

2 स्फीतिक अन्तराल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन प्रो० जे० एम० कींग ने मई 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "How to Pay for War" में किया था जिसका अर्थ अत्यधिक सरकारों के व्यय से लगाया जाता था, परन्तु स्फीति अन्तराल की घटना उस समय आ सकती है जब पूर्ण रोजगार की अवस्था में कुल निच माँग में वृद्धि के कुल उपयोग में समान नहीं होती हो ।

3 "Inflationary gap is the amount of the government's expenditure against which there is no corresponding release of real resources of manpower or material by some other member of the community "

—(Budget Speech of the Chancellor of Exchequer in England, April 1941)

वस्तुओं की कुल पूर्ति की तुलना में कुल माँग अधिक हो जाती है। स्फीति अन्तराल की विचारधारा को वास्तविक आय के स्तर में पूर्ण रोजगार की दिशा में लेना चाहिए। हमको परिभाषित करने के लिए वर्तमान कीमतों पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पर कुल उत्पादन की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है। प्रो० कुरीहार (Prof. Kurihara) ने स्फीति अन्तराल को परिभाषित करते हुए आधार कीमतों पर कुल उत्पादों की तुलना में कुल सम्भावित व्यय की अधिकता माना है। प्रो० क्लीन (Prof. Klein) ने स्फीति अन्तराल का अर्थ उम अन्तर में लिया है जो जनमर्या अपनी आय में से उपभोग करने की बंटेता करनी के मध्य तथा स्फीति से पहले की कीमतों पर जो धनराशि उपभोग के लिए उपलब्ध होगी। यदि यह मान भी लिया जाए कि कुछ साधन बेकार रहते हैं जिनको रोजगार मिल जाने पर वर्तमान आय की अपेक्षा अधिक बढ़ि होगी तो भी पूर्ति की अपेक्षा माँग अधिक होने से कीमतों में बढ़ि होगी, क्योंकि इससे साथ उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए मशीनों तथा स्टाफ की क्षमता को घटाने में समय लगता है। कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाने के लिए कृषि और खनिजों का उत्पादन बढ़ाना होगा। श्रमिकों को नई तकनीक के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इन सबके लिए अधिा समय की आवश्यकता होगी। बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए अधिा समय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जब व्यय बढ़ते हैं तो कीमतें बढ़ेंगी और स्फीति अन्तराल उम समय तक दिखाई देगा जब तक कि वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ाई जाती।

स्फीति अन्तराल को एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम एक मुद्रा अर्थव्यवस्था को लेते हैं जिसमें लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इसमें कुल राष्ट्रीय आय कुल सरकारी तथा निजी व्यय के बराबर होगी जो विनियोग तथा उपभोग के रूप में किया जाता है। माना कि कुल राष्ट्रीय आय 1,200 करोड़ रुपये वर्तमान कीमत-स्तर पर है। अब इस कुल उत्पाद में से सरकार 300 करोड़ की उत्पत्ति मुद्रा बाजारों के लिए ले लेती है तो जनता के उपभोग के लिए 900 करोड़ की कुल उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय बचेगी। यह 900 करोड़ रुपये वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए रह जाते हैं। माना कि हम समयावधि में समुदाय की मोद्रिक आय के रूप में 1,200 करोड़ रुपये दिए जाने हैं इसमें से सरकार 100 करोड़ रुपये करो से रूप में ले लेती है। इस प्रकार लोगों के पास 1,100 करोड़ रुपये उपभोग्य आय (Disposable Income) के रूप में बचे रहते हैं। समुदाय के लोग समस्त उपभोग्य आय को व्यय नहीं कर देंगे और इसके कुछ भाग को बचा लेंगे। यदि यह मान लें कि लोग अपनी आय का 10% भाग बचाकर रखते हैं, तो हम 1,100 उपभोग्य आय में 110 करोड़ रुपये बचा लिए जायेंगे और द्राव्यिक आय 990 करोड़ रुपये बचेगी जो वस्तुओं के उपभोग पर व्यय की जाएगी (1,100 करोड़ बचत 110 करोड़ = 990 करोड़ रुपये) इस प्रकार वर्तमान कीमत-स्तर पर स्फीति अन्तराल (Inflationary Gap) 90 करोड़ रुपये का होगा (990 करोड़ - 900 करोड़ रुपये)। इस प्रकार जब 900 करोड़ रुपये की वस्तुओं के लिए 990 करोड़ रुपये उपभोग व्यय हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे, तो 90 करोड़ रुपये का स्फीतिक अन्तराल होगा। इसी बात को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है :—

माँग पक्ष (Demand Side) करोड़ रुपये

पूर्ति पक्ष (Supply Side) करोड़ रुपये

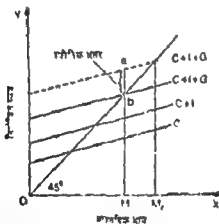
1. मोद्रिक आय जो समुदाय 1,200
को भुगतान के रूप में दे
जाती है

1. कुल राष्ट्रीय उत्पादन 1,200
(GNP) वर्तमान आय
पर

2 घर	100	2 मुक्त व्यय अथवा कुल	300
3 कुल उपभोग आय	1 100	राष्ट्रीय आय का मूल्य	
4 समुदाय द्वारा 10% की दर से बचत करारा	110	जो मुक्त व्यय का पूर्ति हेतु जाता है।	
5 (मुक्त उपभोग्य आय यह राशि जो कुल अनुमानित व्यय है)	990	3 भूय स्पीति कीमता पर सामान्य सामरिकता के लिए उपभोग हेतु धारारणि	900

विवरण योजना यान्त्रिक भी इस प्रकार का स्वीकृति अन्तरान हो सकता है। मौद्रिक व्यय के रूप में विभाजित योजनाओं के लिए धारारणि अधिक हो सकती है। घर-गु व्यय का साथ उपभोग वस्तुओं का उत्पादन में साथ-साथ वृद्धि नहीं हो सकती मर्यादा विभाग योजनाओं के लिए विवेक की जाने वाली धनराशि तथा उपयुक्त विनियोजन के परिणामस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन में समय-विलम्ब (Time lag) होता है। इसमें एक भौतिक लम्बाय यह सामने आता है कि जब तक समुदाय के पास उपभोग्य आय की धनराशि तथा उपलब्ध वस्तुओं की धनराशि परावर होगी तो कीमत-स्तर स्थिर रहेगा। लेकिन जब उपभोग्य आय उपलब्ध वस्तुओं के मूल्य से अधिक हो जाएगी तो स्वीकृति अन्तरान दिखाई देगा। दूसरी विपरीत यदि उपलब्ध वस्तुओं की मर्यादा या मूल्य उपभोग्य आय से अधिक हो जाएगा तब इसी अवस्तीति अन्तरान (Deflationary Gap) की मर्यादा की जाएगी।

स्वीकृति अन्तर के विचार को रेखाचित्र द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।



स्पष्टीकरण—राशि OY_1 तथा OY_2 पर निक्षेपित व्यय तथा OY_1 तथा OY_2 पर वास्तविक आय की दरों का क्या है। C = उपभोग I = निवेश तथा G = सरकारी व्यय। OM आय के स्तर B बिन्दु पर निजी व सरकारी उपभोग एवं निवेश का स्तर Y_1 दिया गया कुल व्यय $(C+I+G)$ प्रचलित कीमता पर कुल आय OM का संगत है। इसी बिन्दु पर प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है तथा स्वीकृति अन्तर शून्य है। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाता है तब $C+I+G$ द्वारा दिखाया गया है कि सामुन्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय और

कुन उत्पादन म भी उमी अनुपात म वृद्धि हानी चाहिए। जैम MM^1 की वृद्धि हाना आवश्यक नहा ता। अमनुन की स्थिति आ जायगी तथा कीमत स्तर बढ़ना। रसाचित्र म ab द्वारा स्फीति अंतर को दिखलाया गया है अर्थात् $ab = C + I + G$ तथा $C + I + G$ के अंतर का दिखता है। यह अंतर उस समय तब बराबर रहता है जब तक अव्यवस्था म वास्तविक आय म वृद्धि MM^1 न बराबर नहा हो जाती। आय म MM^1 मात्रा म वृद्धि से स्फाति अंतर समाप्त हो जायगा तथा कीमता का बढ़ना भी स्थिति हो जायगा।

स्फाति अंतरान का तीन तरीका म कम किया जा सकता है जैम—

(i) जनता से अधिक बचत करवाना।

(ii) अतिरिक्त प्रयोजन को बराबर रूप म बतून कर देना।

(iii) उपभोग्य आय का बराबर बचाव उत्पादन की मात्रा का न जाना। एक अच्छा सरकार स्फाति अंतरान का दूर करन का लिए प्रथम दो तरा अर्थात् दो तरीके जे जे जे कि एन घुसा सरकार नीमत। का बढ़न देता है और स्फीति अव्यवस्था म दिखता है देता है।

स्फीति अंतरान का महत्व (Significance of the Inflationary Gap)—स्फीति अंतरान का महत्व देश म बहुत उपयोगी है। यह मोद्रिय तथा राजस्व आय अधिकारियों का जे स्फीति न बिन्दु पर्याप्त बढ़न उठान का लिए मागदण्ड प्रस्तुत करता है और उह बताता है कि निम्न और कम निम्न में स्फाति का बिन्दु काय करन है। प्रो० गुरींगम म स्फीति अंतरान का महत्व को बताते हुए कहा है— स्फीति अंतरान विनियमन जैसत का रूप में जैम राष्ट्रीय आय निवेश की मात्रा तथा उपभोग व्यय का स्पष्ट व्यख्या करता है जा कि सरकार की नीति का बराबर माननिय व्यय बचत अभियाना साग नियंत्रण मजदूरी समायोजन का नियंत्रण में सहायता करती है। सक्षम म इन्फ्लेशन अंतगत सभी स्फाति बिन्दु उपाय जोकि उपयुक्त प्रवृत्ति बचत निवेश आदि का प्रभावित करत है निम्न कामन-स्तर का निर्धारण होता है सामान्य किया जाता है। इन प्रकार यह उह प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष अथवा अत्यंत रूप म प्रभावित करत हुए मोद्रिय तथा राजस्व अधिकारियों का स्फाति अंतरान का समाप्त करन का लिए एक प्रकार का उपाय होता है निम्न कि जैम आनकारी नीमता में वृद्धि का करा जा सता।¹

1. Analysis of the inflationary gap in terms of such aggregates as national income investment outlays and consumption expenditures savings compaigns credit control wage adjustment—in short all the conceivable anti inflation measures affecting the propensities to consume to save and to invest which together determine the general price level. It is by influencing those propensities directly or indirectly that the monetary fiscal authorities hope to wipe out the inflationary gap therefore prevent further price increases
—Kenneth A. Lurillara

आर्थिक गतिहीनता के साथ स्फीति अथवा मन्दो स्फीति (Stagflation or Slumpflation) —

वर्तमान युग में आर्थिक दुर्दशा एवं स्फीति दोनों साथ-साथ दिखलाई पड़ते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसको मन्दो स्फीति या आर्थिक गतिहीनता के साथ स्फीति को संज्ञा दी है। यूरोप, अमरीका तथा विस्तृत देशों (भारत सहित) में जहाँ एक ओर स्फीति के चिह्न बीमारी के लक्षणों के साथ उत्पादन में दुर्दशा अर्थात् उत्पादन मात्र के बिकने में कठिनाई की स्थिति दिखलाई देती है। पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति दिखलाई दे रही है। यह नयी स्थिति है।

प्रो० सेम्युलसन ने मन्दो स्फीति को परिभाषित करते हुए लिखा है "मन्दो-स्फीति एक नई बीमारी का नया नाम है। स्टैगफ्लेशन के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किन्तु साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकता कठिन हो जाता है।"

('Stagflation is a new name for a new disease Stagflation involves inflationary rise in prices and wages at the same time that people are unable to find jobs and firms are unable to find customers for what their plants can produce.')

मन्दो स्फीति में महँगाई, बेरोजगारी तथा वस्तुओं का न बिकना एक ऐसी स्थिति है जो सामान्य स्फीति में भिन्न है। सामान्य स्थिति में महँगाई तो पायी जाती है, परन्तु उससे साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा उत्पादित किया हुआ माल बिक जाता है। उत्पादन की बढ़ावा का प्रोत्साहन मिलता है तथा व्यापारिक क्षेत्रों में वृद्धि होती है।

मन्दो स्फीति के कारण

- (1) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि।
- (2) धनी देशों के व्यापार में घाटा।
- (3) मजदूरी की दरों में वृद्धि।
- (4) प्राकृतिक प्रकोपों जैसे सूखा, बाढ़ तथा हड़तालों में वृद्धि।
- (5) स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि।

प्रो० सेम्युलसन ने मन्दो स्फीति के कारणों में एशिया का तथा अफ्रीका के देशों में निरन्तर पड़ने वाले सूखे एवं बाढ़ से उत्पादन में कमी का माना है। पैट्रोनियम पदार्थों एवं कोयले की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से सामान्य मूल्यों में वृद्धि हुई है।

प्रो० सेम्युलसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था में मन्दो स्फीति को आवश्यक माना है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उदार मौद्रिक नीति द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के प्रयास एवं आवश्यक वस्तुओं के थकते उत्पादन के बाद भी बीमारी में स्थायित्व माने में अगम्यता द्वारा भी बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है। भारत तथा अनेक एशियाई देशों में ऐसी स्फीति के चिह्न देखे जा सकते हैं।

आयातित स्फीति—मन्दो स्फीति के लिए अमरीका, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे देशों द्वारा उदार आयात नीति भी उत्तरदायी है। इन देशों के विदेशों से आयात के बढ़ने से जो भुगतान किया है उसमें स्वस्थानीय देशों के बीजों के बीजों में वृद्धि के परिणामस्वरूप तथा विकासशील देशों के ऋणों में वृद्धि से भार निर्माण में वृद्धि हुई है तथा स्फीतिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिला है। इस रोजगार तथा उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाई।

भारत जैसे विकासशील देश में कपड़ा तथा इन्जीनियरिंग उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की माँग कम होने पर भी इनके मूल्यों में गिरावट नहीं आती है। अर्थशास्त्र की माँग और पूर्ति में सतुलन का सामान्य नियम त्रियाशील नहीं हो पाया है। बड़े-बड़े उत्पादक सरकार की मन्दी का भय दिखाकर तथा तरह-तरह की रियायतें प्राप्त करके मूल्यों में नहीं आने देते। मन्दी तथा स्फोटिक स्थितियाँ साथ-साथ चलती हैं।

स्फोति के कारण (Causes of Inflation)

मुद्रा-स्फीति का अर्थ उम अवस्था स लिया जाता है जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में वृद्धि तो होती है परन्तु उमने साथ-साथ इनकी पूर्ति में उमी अनुपात में या फिर बिल्कुल वृद्धि नहीं होती। स्फीति उन कारणों से आती है जो माँग में वृद्धि लाते हैं और माँग में वृद्धि दो प्रकार के कारणों से आती है।

(1) वे कारण जो माँग को बढ़ाते हैं।

(2) वे कारण जिनसे पूर्ति में गिरावट आती है। इन दोनों प्रकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है—

वे कारण जो माँग को ऊपर की ओर ले जाते हैं (Factors Causing an Upward Shift in Demand) —

यह कारण निम्नलिखित हैं—

(i) हीनार्थ प्रवर्धन (Deficit Financing)—विकासशील देशों में सामान्य रूप से विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रवर्धन नीति का सहारा लिया जाता है इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। लोगों के हाथों में अनिश्चित मुद्रा पहुँचती है और उसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

(ii) मुद्रा के चलन-वेग में वृद्धि (Increase in the Velocity of Money)—यह कारण विशेषकर अभिवृद्धि (Boom) के समय अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस काल में पूँजी की सीमांत उत्पादनता में वृद्धि अथवा तरसता परसंदगी में गिरावट अथवा उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण मुद्रा का चलन-वेग बढ़ जाता है।

(iii) साख वृद्धि (Credit Expansion)—देश में साख का स्वरूप सरकार तथा व्यापारिक बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर में जब कमी कर देता है अथवा जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है तो साख वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक ऋणों की माँग के कारण जब अपने ग्राहकों को अधिक ऋणों के लिए मात्र मुद्रा सृजित की जाती है और इन बैंकों की नकद जमा कम होने लगती है। जब साख में वृद्धि का दौर, चाहे केन्द्रीय सरकार अथवा व्यापारिक बैंकों की पहल पर हो, प्रारम्भ हो जाता है तो वह काफी समय तक रुकने का नाम नहीं लेता।

(iv) सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि (Rapid Increase in Public Expenditure)—वर्तमान प्रजातान्त्रिक युग में सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। चाहे यह वृद्धि सुरक्षा सम्बन्धी व्यय विकास योजनाओं तथा जनता के बुनियादी योजनाओं अथवा अन्य प्रकार के सार्वजनिक प्रगति सम्बन्धी योजनाओं की पूर्ति हेतु व्यय हो। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग को बढ़ाती है।

(v) निर्यातों में वृद्धि (Increase in Exports)—वर्तमान समय में प्रत्यक्ष देशों अपने भुगतान गणना तथा व्यापार सातुलन की बातों का पता में रखने के लिए अग्रिम निर्यात के लिए प्रयत्नशील हैं। अधिक निर्यात की प्रवृत्ति संश्लेषक उद्योगों तथा कृषि उद्योगों के वस्तुओं की बिक्री में महसूस होती है। यदि उन वस्तुओं का माँग पहले जैसी हो बनी रहे जिनका निर्यात प्रारम्भ किया गया है तो भी इनके मूल्य में वृद्धि स्वीकृत स्थिति के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) जनसंख्या में तेजी से वृद्धि (Rapid Growth of Population)—वस्तुओं तथा सेवाओं की अतिरिक्त माँग का एक प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। विकासशील और अर्द्ध-विकासशील देशों में स्वीकृत का प्रमुख कारण जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ने से जनसंख्या वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में वृद्धि के लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी होती है।

(vii) युद्ध व्यय (War Expenditure)—जब कोई देश युद्ध में प्रभावित हो जाता है तो सामाजिक-व्यय युद्ध व्ययों को पूरा करने के लिए बढ़ जाता है। युद्ध के समय पड़ोसी देशों के उत्पादन हेतु धन को उपभोक्ता वस्तुओं से हटा दिया जा रहा है। सुरक्षा संबंधी वस्तुओं का प्रति हेतु देश के साधन युद्ध सामग्री के उत्पादन हेतु हस्तांतरित हो जाते हैं।

(viii) श्रम संघों के काम (Activities of Trade Unions)—वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम संघों के बढ़ते हुए दबाव के कारण भी अग्रिम मजदूरी का माँग बढ़ रहा है। अग्रिम छुट्टियों के लिए संघों की चिन्ता बढ़ती है। वर्तमान प्रजातन्त्र में युगबोध की सरकारों का अपने आप को श्रमिकों के हितों के लिए उत्तरदायी रूप में प्रस्तुत करने का कारण श्रमिक संघों की अनुचित माँगों को मानना पड़ता है। श्रमिकों द्वारा उत्पादनता घिना घटाए हुए जब उनकी मजदूरी बढ़ाना पड़ती है तो इससे सामान के मूल्य में वृद्धि होती है। मजदूरी में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि को लाती है और काम में बढ़ोतरी लाती है।

(ix) उत्पादन तथा बिक्री कर में वृद्धि (Increase in Excise and Sales Taxes)—जब सरकार उत्पादन तथा बिक्री कर बढ़ा देती है तो इससे बिक्री के बिक्रय (Shifing) उत्पादकों द्वारा किया जाता है और इनका अन्तिम भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिससे वस्तु का कीमत में जोड़ दिया जाता है।

(x) अवमूल्यन (Devaluation)—जब कोई सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है तो देश के निर्यात बढ़ जाते हैं। दूसरे ओर आयातों के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार देश के निर्यातों के लिए अच्छे कामों का सामना करना पड़ता है।

(xi) अन्तर्राष्ट्रीय कारण (International Factors)—एक देश का स्वीकृत दूसरे देश तक पहुँच जाता है। स्वीकृत देशों की वस्तुओं के आयात करने पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और इसकी भरपाई के लिए आयातित वस्तु का हो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। दूसरे देशों में वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्य प्रकार के लेन-देन अग्रिम होते हैं। इस प्रकार एक देश की स्थिति अथवा अवस्थाएँ का प्रभाव दूसरे देशों पर अग्रिम ही पड़ता है।

के कारण जो पूँति नी गिराते हैं। (Factors Causing a Downward Shift in Supply)

यह कारण निम्नलिखित हैं—

(i) प्राकृतिक प्रकोप (Natural Calamities) — प्राकृतिक प्रकोप, जैसे बाढ़ सूखा भूकम्प या पतन, अथवा कृषि कीमती नष्ट होने आदि कारणों से वस्तुओं का उत्पादन घटित होता है। वर्ष 1987 में भारत में पश्चिम व्यापक सूखा कीमती में वृद्धि के लिए विशेष तौर पर उत्तरदायी समझा जाता है।

(ii) उत्पादन की स्थिति (Stage of Production) — वस्तुओं की पूँति में कमी उच्च समय भी होती है जब उत्पादन के क्षेत्र में नया प्रवर्तन तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। शीघ्र ही उत्पादन ह्रास नियम प्रियशील हो जाता है। उत्पादन में वृद्धि लागता में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है और बीमते बढ़ने लगती है।

(iii) संचय की आदत (Habit of Hoarding) — जब स्फीतिक स्थिति होती है तो बीमते स्तर तेजी से बढ़ता है और भुद्धा की नय-शक्ति गिरती है। व्यक्ति भावी कीमती में वृद्धि की आशा में वस्तु का संचय आवश्यकता से अधिक करने लगते हैं और वस्तुओं की कमी महसूस होती है।

(iv) कुछ उत्पादन के साधनों की कमी (Shortage of some Factors of Production) — उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण साधन जैसे पूँजीगत साधन, भूमि प्रशिक्षित श्रमिका, कच्चे भाग आदि की कमी तभी काल में अधिक महसूस की जाती है। बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन का विस्तार उनमें तेजी में नहीं होता और वस्तुओं की कमी व्याप्त रहती है।

स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

स्फीति का अर्थ बीमते-स्तर में होने वाली लगातार वृद्धि से लिया जाता है परन्तु कीमती में यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में एक समान (Uniform) नहीं होती। यदि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमती में एक समान रूप से वृद्धि हो तो विभिन्न आय अर्जित करने वाले वर्गों की सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और स्फीति के आर्थिक प्रभाव तटस्थ होंगे। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से होता यह है कि स्फीतिक प्रक्रिया में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमती में परिवर्तन भी विभिन्न दरों से होता है। इस कारण समुदाय के विभिन्न वर्गों की आय के वितरण की स्थिति में परिवर्तन भी अलग-अलग होता है। किसी वर्ग की स्थिति सुदृढ़, तो किसी की बहुत कमजोर तथा किसी की समान रहती है।

मुद्रा-स्फीति के समुदाय के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव निम्न प्रकार से देखा जा सकता है—

(1) कृषक वर्ग (Farmers) — मुद्रा-स्फीति का कृषक वर्ग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनमें अनेक द्वारा उत्पादित कृषिपदार्थों की बीमते अधिक मिलती है साथ ही कृषक वर्ग ऋणी वर्ग होता है इसलिए स्फीति के समय जब वे अपना ऋण अदा करते हैं, तो उन पर ऋणा की अदायगी स्वल्प जो बोझ पड़ता है उसका वास्तविक भार कम पड़ता है। किसानों की स्फीति का लाभ यह मिलता है एक तो उनकी उत्पादन की कीमती का मूल्य बढ़ जाता है दूसरे जो बीमते वृद्धि या स्फीतिक काट में वस्तु की लागत होगी है। वह स्फीति की प्रार-

मित्र जगन्नाथ से जैसे व्याज करो तथा मजदूरी के रूप में जो उनके उत्पाद की लागत में वृद्धि होती है यह बहुत कम होती है विशेष तौर पर उनको मिलने वाली कीमतों की वृद्धि की दर की तुलना में।

(ii) उद्यमकर्त्ता (Entrepreneurs)—उद्यमकर्त्ताओं को भी स्फीति में लाभ बहुत कुछ निमानों की प्राप्ति होता है। उद्यमकर्त्ता का मिलने वाला लाभ पूँजी निर्माण का बढ़ात एवं प्रोत्साहित करता है निष्प्रिय साधना को उत्पादन एवं उत्पादित शक्तों बढ़ाने के लिए प्रयुक्त करके अर्थव्यवस्था को निरक्षित किया जा सकता है।

दुपार तथा उद्यमकर्त्ता को मिलने वाले लाभ स्फीति काल में होने ला है, परन्तु यदि स्फीति का प्रभाव दीर्घकालिक है तो अर्थव्यवस्था को हानि हानी है क्योंकि अमीमिन काल तक स्फीति का लाभ अजिन नहीं किए जा सकन। एक मीमा क बाद जो तरह पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहन करने वाले होते है वे निवेशों के लिए बाधक साबित होने हैं। मन् 1920 क दशक में प्रो० नर्से (Prof Nurkse) ने यूरोप के दशा क अध्ययन क आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि स्फीति का सफलता पूँजी-निर्माण क यन्त्र के रूप में अधिराज-तथा भावी तथा गैर सम्भावित कीमतों में वृद्धि की मात्रा पर निर्भर हाती है।¹ जब आगे आन जाने समय में यस्तुआ की कीमतें बढ़ने की आशा निश्चित रूप से होती है ता मुद्रा के चलन-वग में वृद्धि होती है बचने नहीं होती है और स्फीति तेजी से निवेशों का प्रोत्सा-हित नहीं करता। यह स्फीति भी सचची प्रवृत्ति होती है।

(iii) विनियोगकर्त्ता बर्ग (Investors)—विनियोगकर्त्ता बर्ग का दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम व विनियोगकर्त्ता निजकी आय विनियोग द्वारा लगभग निश्चिन रहनी है अर्थात् व गलतारी प्रतिभूतियों एवं बाण्डा में विनियोग करने निश्चिन आय प्राप्त करते रहते है। दूसरी श्रेणी में व विनियोगकर्त्ता आते है जिनका कार्य विभिन्न बन्धनित क अशा तथा अणुनयन आदि का खरीदना और बेचना हाता है तथा तजी बाज की स्थिति का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि करते रहते हैं। प्रथम प्रकार क विनियोगकर्त्ता की स्फीति काल में वास्तविक आय घट जाती है क्योंकि उनकी निश्चिन एवं अपरिवर्तनशील आय होती है और उनकी इस आय की वास्तविक ब्रय शक्ति मुद्रा के मूल्य पटन के साथ कम हाती जाता है। दूसरी आर अनिश्चित आय प्राप्त करने वाले विनियोगकर्त्ता के लाभ बढ़ते है क्योंकि उन्हें अपने पाम रगे हुए अंशों पर लाभान की मात्रा बड़ी हुई दर में प्राप्त होती है।

(iv) ऋणी तथा ऋणदाता बर्ग (Debtors and Creditors)—क्योंकि क समय ऋणदाता बर्ग को हानि तथा ऋणी बर्ग को लाभ होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऋणदाता की ऋण की बाधसी जो होती है उसका वास्तविक मूल्य स्फीति काल में घट जाता है जबकि ऋणी स्फीति में जो मूलधन सोटाता है तो उसे कम ब्रय शक्ति की अदाएगी करती पडता है।

(v) माध्यम बर्ग तथा निश्चित आय बर्ग (Middle and Fixed Income Class) स्फीति काल में सबसे ज्यादा नुकसान निश्चिन आय वाले बर्ग के अधिनियों पर होता है

1 Success of inflation as an instrument of capital formation depends largely on the degree to which rise in prices is unforeseen and unexpected.—Nurkse

जैसे पेन्शन प्राप्त करने वाले नागरिक या ऐसे असंगठित क्षेत्रों (Unorganised Sectors) काम करने वाले व्यक्ति जिनकी आय प्रायः निश्चित रहती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा के मूल्य में ह्रास के होने पर भी उनकी आय नहीं बढ़ती और उनसे पाग वास्तविक उपभोग्य आय बहुत कम रह जाती है। लोग के जीवन की समस्त वस्तुओं की स्फीति निगल लेती है। साथ ही बुद्धावस्था का सहारा समाप्त कर देती है। जहाँ तब मध्यम वर्ग का प्रश्न है उस पर भी स्फीति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रो० एन्जेल (Prof J W Angell) ने मुद्रा स्फीति के समय जर्मनी में मध्यम वर्ग पर पड़ने वाले स्फीति के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा है कि "स्फीति के कारण उम्र वर्ग को सबसे अधिक बचत गृह बनना पड़ा था जो स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए बचत कर रहे थे। शहर में रहने वालों में मध्यम वर्ग जिसमें अधिकतर छोटी निश्चित आय प्राप्त करने वाले लोग जैसे यंत्रचाली कर्मचारी तथा क्लर्क पेन्शन प्राप्त करने वाले छोटे विनियोजक जो बैंक व्याज तथा लगान पर अपना भुजारा करने वाले थे। संक्षेप में यह लोगों का ऐसा वर्ग था जो मुद्रा के ह्रास की बुराईयाँ से बहुत प्रभावित था। उस वर्ग की स्फीति से तब तक का न तो ज्ञान प्राप्त था और न अवसर प्राप्त था।" प्रो० कैमरेर ने मध्यम वर्ग की स्थिति की चर्चा इस प्रकार की है "मध्यम वर्ग जो अपने बड़े परिवार तथा बचत द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा देने के उद्देश्य से कुछ बचत का समय करता है स्फीति के दिनों में अपने को सम्पूर्ण स्थिति में पाता है। आय का तुलना में रहने-सहने का व्यय अधिक बढ़ जाता है। सारी बचत समाप्त हो जाती है। वांछित परिधम, स्वतन्त्रता, बचाव करने का विचार झूठे दृष्टांत के समान हो जाने से। इस स्थिति में वर्ग पर निराशा तथा असफलता की भावना अपना अधिकार जमा लेती है।"²

स्फीति का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति पर होता है जो कि वित्तमान प्रजातन्त्र की रीढ़ होते हैं। जर्मनी, आस्ट्रिया, पोलैंड तथा प्राग में अति स्फीति ने प्रथम विश्व-युद्ध के बाद इन देशों में रहने वाले मध्यम वर्ग को विलुप्त कर डाला था। प्रो० गो० एन० कबील ने स्फीति की तुलना दर्शाते हुए कहा है कि "दोनों ही किसी की कोई वस्तु छीनने के अन्तर केवल इतना है एक बारूद जिसलाई देता है जबकि स्फीति अदृश्य होती है, बारूद का शिक्का एक समय में एक या कुछ ही व्यक्ति

1. 'The group which suffered most from the inflation, however, was the group which was also least able to defend itself, The middle class among the low-dwellers composed largely of people with small fixed incomes, such as salaried Officials and clerks, recipients of pensions, and little investors living on interest and rent. They were precisely the group most exposed to the evil consequences of currency depreciation, While they lacked both the knowledge and opportunity to combat it.'

J.W Angell

2. E. W. Kemmerer

होते हैं जबकि स्फीति का विचार पूरा स्पष्ट होता है। जहाँ नो न्यायालय भ्रष्ट होने के लिए भेजा जा सकता है परन्तु स्फीति कानूनी अखिर प्राप्त होती है।¹

अन्य प्रभाव (Other Effects)

(i) व्यापारिक क्रियाओं पर प्रभाव (Effects on Business Activities)—स्फीति में व्यापारिक क्रियाओं एवं योजनाओं तथा विनियमों को गहरा रहता है। स्फीति में हाथ लागत तथा लाभ का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है और यह व्यापार की भुगतान क्षमता तथा मुद्रा विनिमय को बड़ा चतुर उत्पन्न करती है। इसमें व्यापार की दरें बढ़ती हैं और मुद्रा बाजार में एक प्रकार से असन्तुलन पैदा होती है।

(ii) करों में वृद्धि (Increase in Taxation)—स्फीति बाजार में बढ़ने हुए सामाजिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार करों की मात्रा बढ़ाती है। सभी प्रकार के कर बढ़ते हैं जिनका बोझ देश के सभी नागरिकों को उठाना पड़ता है।

(iii) बचतों पर प्रभाव (Effects on Savings)—स्फीति से बचतें घुरी तरह से प्रभावित होती हैं। मुद्रा के मूल्य में होने वाली लगातार गिरावट से लोगों का नकदी अधिमान गिरता है जो बचत निषेध की हानिवाहक करता है। बचतों में नमी पूँजी निर्माण क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(iv) धनी तथा निर्धन के बीच घुरी का बढ़ना—स्फीति में धनी और निर्धनों के बीच असमानता बढ़ती है। धनी और धनी हो जाते हैं तथा निर्धन और अधिक निर्धनों की श्रेणी में आ जाते हैं। समाज में आर्थिक असमानताओं के बढ़ने से एक वर्ग दूसरे वर्ग से द्रोण और ईर्ष्या करता है। सामाजिक कटुता बढ़ती है।

(v) भुगतान समुत्पन्न (Balance of Payments)—स्फीति के समय एक देश का भुगतान समुत्पन्न प्रतिबलता की ओर जाता है ऐसे देशों के पास विदेशी मुद्राओं के भण्डार भी कम होने लगते हैं।

नैतिक प्रभाव

स्फीति का एक बड़ा असर लोगों के नैतिक-स्तर में गिरावट के रूप में सामने आता है। विशेषतः पर व्यापारी वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों का नैतिक-स्तर काफी गिर जाता है। प्रायः वर्ग भौतिक रूप से समृद्धिवादी बनने की होड़ में झटकाधार का विचार हो जाता है। काला बाजारों विश्वस्तरीय झटकाधार, भोरो, मिलावट आदि आम बनने लगे जाते हैं। जब लोगों की सेहत से भी दरें बढ़ने समाप्त हो जाती हैं तो जल्द ही विश्वास सरकार से उठने लगता है। प्रो० व्हाइट (Prof. A. D. White) ने काम की शक्ति के समय क्रिस में लोगों की हासत जो स्फीतिक प्रभाव से हुई थी उसकी पर्चा करने

1. "Both deprive the victim of some possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or a few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal."
— C. N. Patel

हूए लिया है कि फ्रांस के प्रमुख शहरों में विलासिता तथा दुराचार जा लूटो की अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर दोष थे चारा ओर दियाई दे रह थे। इस में जुग की भावना बढती जा रही थी। यह दुराचार केवल व्यापारिया तथा नतावा में भी फैल गया था जा कुछ समय पूर विलासिता बेईमानी तथा सापरवाही के दोषों ग मुक्त ममत्र जाते थे।¹

जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इससे भी अधिक नैतिक सर्कट उत्पन्न हो गया था। लोगों का इतना अधिक नैतिक पतन हा गया था कि आदमी स्त्रिया के कपड़े पहनकर चलिन के नाच घरों में पुनिम अधिकांश के मामने नाचा करते थे। जर्मनी में अति स्फीति का नया नाच चल रहा था। 'नव युवतियाँ अपन दोषों की घमण्णशाली ढंग में व्याख्या करती थी। सातह वर्ष की अवस्था तक यदित्र कुयारी रहता उन दिना वनिन में लज्जाजनक माना जाता था। सड़कियाँ अपने दूषित अनुभवों को बतान में गव समझती थीं।'²

राजनैतिक प्रभाव—

मुद्रा-स्फीति का लगातार रहना तथा अतिस्फीति की स्थिति आर्थिक व्यवस्था को ही प्रभावित नहीं करती बरन यह सामाजिक तथा राजनैतिक गढबढी का त्रिगु भी उत्तरदायी होती है। जर्मनी में अति स्फीति (Hyper inflation) न डॉ० कुनो (D Cuno) की उदार सरकार का पतन किया था और हिटलर को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांस्टान्टीना ब्रेमियानी तुरोनी (Constantino Bresciani Turrone) न जर्मनी में अति स्फीति की स्थिति का वर्णन करते मुद्रा मार के मूय की विसादट बीगवी शताब्दी के इतिहास की एक प्रमुख घटना है। यह इतिहास में अपन प्रकार की एक सयत अधिक भयानक घटना थी और शायद महान युद्ध के बाद हमारी पीढी की अधिराज राजनैतिक तथा आर्थिक कठिनाइया की जिम्मेदारी इसी पर थी। इनने जर्मन समाज के स्थाई वर्गों के धन को बर्बाद कर दिया था और इनने अपन पीछे राजनैतिक तथा आर्थिक असन्तुलन को छोडा था और आने वाले समय में कमिश्नरता के लिए पृष्ठभूमि छाडी। हिटलर स्फीति की ही गीग उलाति था। इसी प्रकार महान मन्दी तीमा की (मन्दी)

- 1 ' In the leading French cities now arose a luxury and licence which was a greater evil than the plundering that ministered to it. In the country the gambling spirit confined to businessmen, it began to break out in official circles, and publicmen who a few years before had been thought above all possibility to taint became luxurious, reckless cynical and finally corrupt '

—Andrew D White

- 2 ' Young girls bragged proudly of their perversion, to be sixteen and the suspicion of virginity would have been considered a disgrace in any school of Berlin at that time, even girl wanted to be able to tell of her adventures and the more exotic the better " (In the World Yesterday by Sidfan Zweig quoted on Page 111 From Hyper Inflation "

—S K Muranjan

नित्तीय कठिनाइयाँ भी काफी अथ तब अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग प्रणाली ११ उद्योग प्रणाली या परिणाम भी निम्न इस बात की स्थिति को बताता है। यदि हम यूरोप की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें जर्मनी की अनिश्चितता का अध्ययन करना ही भुजाना चाहिए। यदि हम अल्पकाल में अधिकाधिक स्थिरता चाहते हैं तो हमें सीमा का चाहिए कि हम उन समस्याओं को दूर करें जिनसे कारण इसकी वृद्धि है।¹

स्फीति को रोकने के उपाय (Measures to Check Inflation)

मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपायों को हम प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं—

- (i) मौद्रिक उपाय
- (ii) राजकोषीय उपाय तथा
- (iii) प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा अन्य उपाय।

प्रथम दो प्रकार के उपायों की विस्तृत चर्चा मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति सम्बंधी अध्यायों में की गई है। यहाँ पर हम उपायों की संक्षिप्त व्याख्या हमारी वर्तमान आवश्यकतानुसार है।

(1) मौद्रिक उपाय (Monetary Measures)—मौद्रिक उपायों का अर्थ है उपाय है जिससे सम्बंध मुद्रा निर्यात तथा उधारों नियंत्रित करके धारणी होता है। जब अति स्फीति की स्थिति होती है तब निम्न-मुद्रा की समाप्ति का बाद जमा देना में हुआ था। जर्मनी सरकार ने इस समय पुरानी मुद्रा को विपुल समाप्त करने की माँग मुद्रा प्रणाली में डाली थी।

इस पर केन्द्रीय बैंक स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा तथा साग मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण तथा करता है। इसके लिए केन्द्रीय बैंक का काम तीन तरीके प्रमुख रूप से है जिससे प्रयोग केन्द्रीय बैंक करता है।

- (i) बैंक दर नीति

1 The depreciation of the mark of 1914-23 which is the subject of this work is one of the outstanding episodes in the history of the twentieth century. It was the most colossal thing of its kind in history and next probably to the great war itself. It must bear responsibility for many of the political and economic difficulties of our generation. It destroyed the wealth of the more solid elements in German society and it left behind a moral and economic disequilibrium apt breeding ground for the disasters which have followed. Hitler is the foster-child of the inflation. The financial convulsions of the great depression were in part at least the product of the distortions of the system of international borrowing and lending to which it ravages had given rise. If we are to understand correctly the present position of Europe we must not neglect the study of the great German inflation. If we are to plan for greater stability in the future we must learn to avoid the mistakes from which it sprang.

(ii) खुले बाजार की नियाँ तथा

(iii) सदस्य बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास रखी जाने वाली निधि की मात्रा। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक द्वारा अधिक साख सृजन की नीति पर रोक लगाने की दृष्टि से केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर बढ़ा देता है जिससे व्यापारिक बैंकों के लिए केन्द्रीय बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाता है। परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी बैंक दर बढ़ा देने के लिए बाध्य होना महंगा हो जाता है। केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की प्रियाओं (Open Market Operations) द्वारा प्रतिभूतियों तथा ऋण पत्रों को मुद्रा बाजार में बेचकर अतिरिक्त मुद्रा अपने पास रख लेता है और स्फीति पर काबू पाने में सफल हो जाता है। इससे अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक द्वारा न्यूनतम निधि अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है जिससे व्यापारिक बैंकों की नवदी कम हो जाती है और साख-सृजन की उनकी सीमा भी कम हो जाती है।

एक अर्द्ध-विकसित देश चुने हुए साख नियन्त्रण के तरीके सामान्य साख नियन्त्रण के तरीकों में अच्छे समझे जाते हैं। परन्तु साख नियन्त्रण की विभिन्न विधियों को अपनाने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वही नियन्त्रण इतने न हो जाएँ कि विकास योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता न हो। अर्द्ध-विकसित देशों के अनायास विकसित देशों में भी स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय अधिक फलदायक साबित नहीं हुए हैं। प्रो० हैन्सन का विचार है कि मौद्रिक उपायों को स्फीति के नियन्त्रण के लिए मौलिक उपायों के रूप में ही देखना चाहिए। वे कहते हैं कि स्फीति रोकने के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियन्त्रित करना एक उपाय हो सकता है परन्तु यदि स्फीतिक प्रभावों को रोकने के लिए मौद्रिक उपायों को अपनाने से अन्य बहुत सी बुराइयों से बचना चाहिए।

(II) राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures)—मौद्रिक उपाय जब स्फीति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होते तो सरकार राजकोषीय उपाय अपनाती है। मौद्रिक उपायों के साथ ही राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं। राजकोषीय उपायों में विशेष रूप से करारोपण, सरकारी व्यय तथा सार्वजनिक ऋण आदि आते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है—

(i) करारोपण (Taxation)—इसके अन्तर्गत सरकार अतिरिक्त अथवा प्रत्यक्ष-शक्ति की जनता से करारोपण में वृद्धि करके प्राप्त करती है। इसके अन्तर्गत पुराने करों की मात्रा में वृद्धि तथा नए करों को लगाना सम्मिलित उपाय आते हैं। करारोपण सम्बन्धी नीति ऐसी होती है जिसमें जनता का पाम की अतिरिक्त प्रत्यक्ष-शक्ति को अधिक में अधिक अपने पास की सरकार लेने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार उपलब्ध आय (Disposable Income) में कमी आती है। कुल समर्थ भाग घटती है तथा स्फीतिक प्रभाव कम होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में करों में चोरी जैसी बुराई दिखाई देती है, इसलिए करारोपण के वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में विशेष बल उठाने और सतर्कता बरतनी चाहिए।

(ii) सरकारी व्यय (Government Spending)—स्फीति को रोकने का राजकोषीय उपाय एक यह भी है कि सरकार को अपने खर्चे हुए व्यय विशेष रूप में अनुत्पादक तथा बेकार के व्ययों पर रोक लगानी चाहिए। वर्तमान समय में कुछ व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए सरकार को अपने व्यय में मितव्ययता की नीति अपनाना चाहिए।

में पूँजी विनियोजन किया जाना चाहिए जो शीघ्र उत्पत्ति अथवा प्रतिफल प्रदान करने वाली हो।

(iii) मजदूरी नीति (Wage Policy)—स्फीति के समय सभी वग ने कमचारी स्फीतिक प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए मजदूरी बढ़ाने पर जोर देते हैं। उत्पादकता पर ध्यान दिए बिना मजदूरी या भत्ते बढ़ाये जाते हैं तो इसका प्रभाव स्फीति को और बढ़ाता है। अति स्फीति का नया तेजी से बढ़ती हुई स्फीतियों में मजदूरी लाभ जामनीति (Wage-Profit Freeze Policy) अपनाया चाहिए और मजदूरी वृद्धि का सम्बन्ध उत्पादकता से कर देना चाहिए। मजदूरी-लाभ बन्धन अथवा जाम-नीति से लोगों के पास उपभोग्य आय में गिरावट आती है और प्रभावपूर्ण माँग का स्तर भी नीचा रहता है।

(iv) विदेशी पूँजी (Foreign Capital)—एक उपाय यह है कि अधिक विदेशी पूँजी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएँ। विदेशी पूँजी द्वारा किए जाने वाले निवेश स्फीति को अधिक नहीं बढ़ाते।

(v) आयात नीति (Import Policy)—स्फीतिक प्रभाव कम करने की दिशा में उदार आयात नीति कारगर साबित हो सकती है यदि यह आयात आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाएँ। साथ ही निर्यातों में कमी करनी चाहिए परन्तु आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी सभी कारगर साबित हों गवती है जबकि देश की भुगतान सन्तुलन की स्थिति अच्छी हो।

अधिकार विद्वान समझते हैं कि यदि स्फीति अपने प्रारम्भिक चरण में हो तो इस पर बाध पाना आसान है परन्तु यदि यह उग्ररूप धारण कर चुकी है तो इसको नियन्त्रित करना काफी कठिन हो जाता है। अति स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए समस्त पुरानी मुद्रा हटाकर नई मुद्रा चलाने में डालनी होती है जैसाकि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जर्मनी में किया गया था।

स्फीति एक भयानक स्थिति है इसलिए इसे नियन्त्रित करने के लिए किसी एक तरीके से काम नहीं चल सकता बल्कि विभिन्न उपायों को एक साथ अपनाने की आवश्यकता होती है। किसी एक कारण पर निर्भरता निर्णय एक भ्रष्टपूर्ण होती है।

अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में स्फीति (Inflation in an Under-developed Economy)

जैसाकि हम जानते हैं प्रो० कोन्स ने स्फीति का सम्बन्ध पूर्ण रोजगार की स्थिति से जोड़ते हुए बताया है कि स्फीति पूर्ण रोजगार के बिन्दु के बाद प्रारम्भ होती है क्योंकि इस बिन्दु में पहले के रोजगार माधन पाये जाते हैं और प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि से उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार बढ़ेंगे और कीमतें अधिक नहीं बढ़ेंगी। वास्तविकता एक व्यवहारिक पक्ष यह है कि पूर्ण रोजगार से बहुत पहले कीमतें बढ़ना प्रारम्भ हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति न तो पूर्णतया सन्तुष्ट और न ही अन्य साधन जो कि उत्पादन लागत का बढ़ाते हैं। प्रो० कोन्स ने पूर्ण रोजगार से पहले स्फीति स्थिति के लिए निम्न कारण बताये हैं

(1) प्रभावपूर्ण माँग में परिवर्तन उच्च अनुपात में नहीं होगा जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति होती है।

(2) विभिन्न साधन एक जैसे नहीं होते इसलिए पूर्णतया स्थानापन्न नहीं होते और रोजगार के माधनों में वृद्धि के साथ घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है।

(3) चूंकि विभिन्न साधन एक-दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। कुछ वस्तुओं की पूर्ति की लोच बेलोचदार स्थिति में पहुँच जाती है जबकि कुछ साधनों में बेरोजगारी अन्य वस्तुओं को उत्पादित करने हेतु बनी रहती है।

(4) मजदूरी-इकाई पूर्ण रोजगार की शक्ति में पहले बढ़ना प्रारम्भ हो जाती।

(5) वह माध्यम जो सीमान्त मागत में प्रवेश कर चुका है उनका वास्तविक उमी अनुपात में परिवर्तित नहीं होगा।

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में कुछ और कमियाँ पायी जाती हैं। जिनके मापन रूप में वस्तुओं की पूर्ति में कठिनाई होती है और कीमती में तेजी में वृद्धि पाई जाती है। ये कारण निम्न प्रकार से हैं—

(1) ऐसी अर्थव्यवस्था में बाजार की बहुत सी अपूर्णताएँ देगन को मिलती हैं जैसा बाजार की जानकारी का अभाव साधना की अपूर्ण अविश्वस्यता तथा कुछ विशेष माधनों की गतिशीलता का अभाव आदि। इन तथ्यों के कारण उत्पादन व माधनों का आदर्शतम अनुपात अधिक उत्पादन हेतु प्राप्त नहीं होने पाता।

(2) एक विकसित देश में बेरोजगारी होने पर भी प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि व कारण उत्पादन में वृद्धि होती है जबकि एक अर्द्ध विकसित देश में अर्द्ध-बेरोजगारी (Under-employment) तथा छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised unemployment) की स्थिति होने पर प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि नहीं होने देती। इस प्रकार मुद्रा प्रसार के कारण उच्च माँग तक पूर्ति नहीं बढ़ेगी जिस माँग तक प्रभावपूर्ण माँग बढ़े है और कीमती में वृद्धि बढ़ने की प्रवृत्ति दिसाएगी।

इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और कारण भी हैं जो कि एक अर्द्ध-विकसित देश में स्फीतिक प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक प्रमुख कारण है वित्तीय माधनों की कमी और विज्ञान योजनाओं की पूर्ति हेतु ऋणाय प्रयत्न (Deficit financing) का सहारा लेना पड़ता है जिससे स्फीतिक प्रभाव अधिक मात्तूम पड़ता है। विकास योजनाओं की पूर्ति हेतु पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी दिगाई देती है। इस प्रकार नए मजदूरी बढ़ने के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुकूल उत्पादन नहीं बढ़ने पाना और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है।

स्फीति तथा आर्थिक विकास (Inflation and Economic Development)

स्फीति तथा आर्थिक विकास का सम्बन्ध में अग्रगण्य एकमत नहीं है। पहले हम उन अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करेंगे जिनका कहना है कि आर्थिक विकास के लिए स्फीति आवश्यक है जबकि दूसरी ओर ऐसे अर्थशास्त्रियों की स्थिति की जाती है जिनका मत है कि स्फीति आर्थिक विकास के लिए जरूरी नहीं है बल्कि स्फीति आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है।

प्रो० कोन्स का कहना है कि आर्थिक विकास के लिए स्फीति सहायक होती है। ऐसा माना जाता है कि स्फीति माधनों में गतिशीलता लाती है और मजदूरी प्राप्त करने वाले साधनों से आय तथा मजदूरी का पुनर्वितरण करके लाभ प्राप्त करने वाले साधनों तक ले जाती है। चूंकि लाभ प्राप्त करने वाले वर्ग की बचत करने की सीमान्त प्रवृत्ति मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग की अपेक्षा उंची होती है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग अपनी बचत को उत्पादन क्षेत्र में लगाकर आर्थिक विकास को दूर कर देता है। प्रो० कोन्स आगे कहते हैं कि दोरी-सी स्फीति से कीमती बढ़ती है और उपभोक्ताओं में आशावादित्व की चिरण दिगाई देती है और अर्थव्यवस्था में माँग की मात्रा व कारण के निर्देश को बढ़ाते हैं। प्रो० मारिश डाव न स्फीति का आर्थिक विकास के लिए जरूरी माना है। प्रो० बालेश्वर का बचप भी हम संदर्भ में उल्लेखनीय है एक छिपी स्फीति

प्रगतिशील दर में स्फीति या हाना आर्थिक प्रगति की दर में तेजी लाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली आधार है।¹ प्रो० राबर्टसन ने आर्थिक विकास के लिए हल्की स्फीति को जरूरी माना है। एक अर्द्ध-विकसित देश में ऐसी नीति अधिक बारगर साबित होती है क्योंकि इन देशों में श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या स्व रोजगार प्राप्त होती है तथा हल्की स्फीति द्वारा कीमती म प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

बहुत में अर्थशास्त्री हल्की स्फीति (Mild Inflation) को आर्थिक विनाश के लिए अनावश्यक नहीं मानते। इन विद्वानों का कहना है कि हमारे वर्तमान संस्थानिक ढाँचे में (Institutional set-up) कीमती म वृद्धि साधना का बंटवारा की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को प्रगतिशीलता की ओर ले जाती है जबकि कीमती म गिरावट से अर्थव्यवस्था में गति-हीनता (Stagnation) की स्थिति आती है। ऐसा कहा जाता है कि संघा तथा फर्मों की एकाधिकारिक शक्ति ऐसी है जिसमें कीमती म वृद्धि आवश्यक है ऐसी स्थिति में अधिकारियों को चाहिए कि वे समुच्चयकारी नीतियाँ (Deflationary Policies) को न अपनाएँ जिनसे कीमती म गिरावट की अपेक्षा बेरोजगारी अधिक बढ़ती है।

कुछ अर्थशास्त्री स्फीति को आर्थिक वृद्धि की उत्पत्ति मानते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में छोटी की स्फीति से बचा नहीं जा सकता। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मौद्रिक आधेन वृद्धि का साथ उत्पादन में वृद्धि होने में थोड़ा सा समय लगता है और यही कारण है कि कीमती म स्तर में वृद्धि दिखाई देती है। यदि नियोजन मिश्रित देश में वास्तविक रचना में अधिक हाथों में निश्चित रूप में स्फीति का प्रभाव दिखाई देगा।

अर्थशास्त्रियों का एक अन्य वर्ग है जो कहता है कि स्फीति आर्थिक विकास के स्थान पर आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन (Prof. Milton Friedman) का कहना है कि स्फीति द्वारा आर्थिक विकास की नीति अपनाना कोई निश्चयपूर्ण तर्क नहीं है। वह इस बात से भी सहमत नहीं है कि स्फीति आर्थिक विकास का निरापेक्ष अनिवार्य तत्व है। वे कहते हैं कि इस रचने में भी कोई बचन नहीं है कि स्फीति साधना का पुनर्वितरण द्वारा आर्थिक विकास को शक्ति प्रदान करती है। उनका मत है कि विगत समय में साधना का पुनर्वितरण ने प्रभाव कुछ हद तक आर्थिक विकास का लिए अनुकूल रहे हैं परन्तु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह अनुकूल प्रभाव (Favourable Effects) सभी स्थितियों में दिखाई देवे। प्रो० फ्रीडमैन का विश्वास है कि मुद्रा की पूर्ण जानबूझकर की गई वृद्धि में हमारे अनुकूल प्रभाव प्राप्त नहीं किए जा सकते। जब स्फीति प्रक्रिया जानबूझकर अपनाई जाए तो बहुत में लोगों को उनकी जानकारी हो जाएगी और उनका व्यवहार पुनर्वितरण प्रभाव को रोकने का होगा। प्रो० रैगनर नर्कसे (Prof. Ragnar Nurkse) ने कहा है कि स्फीति की सफलता पूँजी निर्माण के चरण के रूप में वितरित है, यह अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करेगा कि भावी तथा गैर सम्भावित कीमती म वृद्धि की मात्रा वितरित है। यदि कीमती म में वृद्धि निश्चित एवं सम्भावित है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ने से वचनों के स्थान पर व्यय होने है तथा स्फीति पूँजी निर्माण को शक्ति कम करती है।

स्फीति मुद्रा का वास्तविक मूल्य का कम करती है इसलिए लोग वचन के स्थान पर गैर जिम्मेदारी व्यय करते हैं। स्फीति पूँजी निर्माण में बाधा हो उत्पन्न नहीं करती बल्कि

1. "a slow and steady rate of inflation provides a most powerful aid to the attainment of a steady rate of economic progress" Nicholas Kaldor-Economic Growth and Problem of Inflation, Economica 1959.

दम की पूँजी का बाहर भी ल जाती है। स्फीति में व्यापारिक श्रियाओं का शक्ति एवं दिशा उत्पादक कार्यों व स्थान पर मुद्रा क्षेत्र का क्रियाशीलता की ओर जाती है। स्फीति का मत कीमती व बढ़ने में दम व निर्यात व्यापार का घटता चलता है। निर्यात उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ती है तथा आयात बढ़ि रहित है। कुछ विचारों पर दम की भूमिका मनुष्य को स्थिति प्रतिबन्धित जाती है। विदेशी बाजारों में स्फीति वान दम की भाग को घटता चलता है विदेशी ऋण का वाप बढ़ जाता है।

अवस्फीति (Deflation)

अवस्फीति की परिभाषा (Definition of Deflation)

अवस्फीति स्फीति का विपरीत विचारों में स्थिति होता है। इसमें कीमती व घटता चल गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रो० पाउल इन्जिग (Prof Paul Einzig) ने अवस्फीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि अवस्फीति अस-वृद्धि का वह स्थिति है जिसमें वय गति में समुच्चय कीमत स्तर में गिरावट का कारण अथवा उसका परिणाम होता है।¹ प्रो० बोल्लोन्गे ने अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी अवस्फीति की बमौती है।² प्रो० पाणू की अवस्फीति की परिभाषा इस प्रकार है— अवस्फीति कीमत-स्तर व गिरने की वह अवस्था है जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय का तुलना में तनी व बढ़ता है। प्रो० पीगू ने कीमत-स्तर को प्रत्यक्ष गिरावट को अवस्फीति का लक्षण कहा है। उनका अनुसार अवस्फीति की स्थिति निम्न बातों व होने पर पाई जाएगी

(1) जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़ें परन्तु उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो।

(2) जब उत्पादन की मात्रा बढ़े वहीं हो और मौद्रिक आय स्थिर हो।

(3) जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों कम हो परन्तु मौद्रिक आय तेजी से गिरने की प्रवृत्ति दिखता।

(4) जब मौद्रिक आय घटता हो तथा उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे।

(5) जब उत्पादन की मात्रा बढ़े तथा मौद्रिक आय घटे।

मुद्रा अवस्फीति की उपर्युक्त परिभाषाओं ने प्रो० पाउल इन्जिग की परिभाषा अति उपयुक्त एवं तर्कमय मान्य पड़ती है। कीमत-स्तर में होने वाला प्रत्यक्ष गिरावट का अवस्फीति को लक्षण नहीं हो जा सकता। कीमत-स्तर में मुद्रा गिरावट मुद्रा पूँजी में बमौती का ही परिणाम नहीं होती परन्तु कीमत-स्तर में मुद्रा बमौती का कारण भी हो सकता है। यदि कीमती व गिरावट उमात्तर होता है तो अवस्थिति व मुद्रा की मात्रा की उत्तरी आवश्यकता नहीं होती जिससे कि घटने होती है। इस प्रकार कीमत स्तर मुद्रा पूँजी में मुद्रा बमौती का परिणाम भा है और कारण भी।

अवस्फीति उन समय उत्पन्न होता है जब कि समुदाय द्वारा रिया लक्ष्य वृद्धि वय वयमान कामता पर उपलब्ध मुद्रा उत्पादक मूल्य में कम हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तथा कीमती व गिरावट दमन का मिलती है। हम यह धारणा

1 Deflation is a state of disequilibrium in which a contraction of purchasing power tends to cause or is the effect of a decline of the price level —Paul Einzig

2 Involuntary unemployment is the hall mark of Deflation

—Coulborn

चाहिए कि कीमता में प्रत्येक तथा सभी प्रकार की गिरावट को अवस्फीति नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ जब हम स्फीति के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रभावपूर्ण मोद्रिक तथा राजकोपीय उपायों द्वारा नियन्त्रित करते हैं। उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार बढ़ता है परन्तु कीमतें गिरना प्रारम्भ हो जाती हैं तो इस अवस्फीति नहीं मानना चाहिए।

मुद्रा-विस्फीति (Disinflation)—वह प्रक्रिया जिसमें स्फीति को समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं तथा जिसमें बेरोजगारी तथा उत्पादन में गिरावट नहीं होती उस अवस्फीति में बहुर मुद्रा-विस्फीति (Disinflation) कहते हैं। अवस्फीति प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण उत्पन्न होती है और सामान्य मन्दी की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है जबकि विस्फीति (Disinflation) का उद्देश्य लागतों तथा कीमता में गिरावट लाना होता है जबकि कीमता में वृद्धि अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही हो। कीमतों में इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि को विस्फीति द्वारा नीचे लाना वाछनीय होता है, क्योंकि इस प्रकार की कीमता में गिरावट से उत्पादन तथा रोजगार का स्तर नीचे नहीं गिरता। इससे विपरीत अवस्फीति (Deflation) समुदाय के लिए घातक एवं नाशकारी होती है क्योंकि कीमता में प्रत्येक गिरावट बेरोजगारी में वृद्धि उत्पादन तथा नोका की आय में गिरावट लाती है।

प्रत्यवस्फीति अथवा प्रतिस्फीति (Reflation)

एक अन्य स्थिति जो कि मन्दी और स्फीति के बीच पाई जाती है उस प्रत्यवस्फीति (Reflation) कहते हैं। प्रो० जी० डी० एच० कोल ने प्रत्यवस्फीति का लक्षण बताते हुए कहा है 'प्रत्यवस्फीति उस विशेष प्रकार की स्फीति को कहते हैं जिससे जानबूझकर मन्दी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है।' ¹ जब नामत-स्तर तभी से गिरने लगता है तो अर्थव्यवस्था को मन्दी में मुक्त करने के लिए मुद्रा-विस्तार किया जाता है तो इस प्रतिस्फीति अथवा प्रत्यवस्फीति कहा जाता है। इस अन्तर्गत कीमत-स्तर धीरे-धीरे ऊपर उठने लगता है और अर्थव्यवस्था को मन्दी की स्थिति से छुटकारा मिलने लगता है। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा प्रतिस्फीति (Reflation) दोनों में ही कीमत-स्तर ऊपर की उठता है, परन्तु दोनों ही स्थितियाँ में कुछ मौलिक अन्तर निम्न प्रकार से बतलाए जा सकते हैं :

(1) मुद्रा स्फीति ऐच्छिक एवं प्राकृतिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है जबकि प्रतिस्फीति ऐच्छिक होती है और सरकार द्वारा इस सोच समझकर उठाया गया कदम कहना गलत नहीं होगा।

(2) कीमत व अनुसार स्फीति पूर्ण राजगार बिन्दु तक बढ़ती है जबकि प्रतिस्फीति पूर्ण राजगार बिन्दु से पहले ही होती है।

(3) दोनों में ही कीमतें बढ़ती हैं परन्तु प्रतिस्फीति की तुलना में स्फीति में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं।

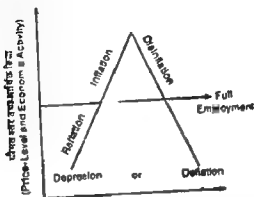
(4) मुद्रा स्फीति को यदि नियन्त्रित न किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देती है जबकि प्रतिस्फीति का नियन्त्रण सरकार के हाथ की बात रहती है।

हम एक रणचित्र द्वारा स्फीति, अवस्फीति, प्रतिस्फीति तथा मुद्रा विस्फीति (Inflation, Depression, Reflation and Disinflation) को व्यक्त कर सकते हैं।

1. 'Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve depression.'
—G. D. H. Cole

मुद्रा अवस्तीति के प्रभाव (Effects of Deflation) .

मुद्रा अवस्तीति मुद्रा स्फीति का तुलना में अधिक हानिकारक एवं भयावह होना है। समाज में विभिन्न वर्गों पर दत्त प्रभाव अधिक दूरगामी एवं गहन होता है। इसमें



उत्पादन व्यापारिक क्रियाओं तथा रोजगार में स्तर पर बहुत ही प्रतिबन्ध प्रभाव पड़ता है। हमारे अन्तर्गत जब कीमतें तजी से गिरती हैं परन्तु उन्नी अनुपात में माँग में गिरावट नहीं होती और उत्पादन की काफी हानि उठानी पड़ती है। साथ ही उत्पादन तथा रोजगार भी गिरते हैं। इसका प्रभाव कुल आय में गिरावट तथा कुल माँग में गिरावट के रूप में दृश्य होने लगता है। परिणामस्वरूप कीमती म और अधिक गिरावट आती है और यह प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। व्यापारिक क्रियाओं में गिरावट और निराशावादी दृष्टिकोण छा जाता है जो अंत में अव्यवस्था को मजबूत में पहुँचा देता है। अवस्तीति में अर्थव्यवस्था माधन व अनुपयोग होने से बाधित बर्बादी को होती ही है साथ ही उनकी कुशलता में गिरावट उन्हें हतोत्साहित कर देती है। बेरोजगार व्यक्ति का भ्रष्ट बना देती है और बेरोजगार व्यक्ति समाज में लिए सिरदर्द बन जाते हैं। बेरोजगार अवस्तीति को भयंकर स्थिति एवं अभिशाप है।

अवस्तीति का समाज में विभिन्न वर्गों पर प्रभाव स्थिति व प्रभाव व विन्तुन विपरीत होता है। उदाहरणार्थ यदि मुद्रा स्फीति में निश्चित आय वार तथा मध्यम वर्ग की स्थिति सबसे खराब होती है जबकि अवस्तीति में निश्चित आय वार वर्ग की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ने अथवा कीमत-स्तर में समानता गिरावट के कारण इस वर्ग की वास्तविक उपभोग्य आय (Real Disposable Income) अधिक हो जाती है। वर्तमान आय से यह वर्ग अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद कर सकता है। इसी प्रकार यह व्यापारिक तथा उद्यमकर्ता पर प्रतिबन्ध प्रभाव डालता है। उनकी कुल आय गिरती है, टैक्स व रूप में सरकार से भुगतान तथा उत्पादों के व्यय माधन के पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली छनराशि प्रारिक्तित रहती है। प्रभावपूर्ण माँग में गिरावट के कारण उपभोग उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग तो नही हो पाता साथ ही कुछ उत्पाद महीना बेकार पड़े रहते हैं। वित्तीय दृष्टि से कमजोर इरादों दिशाविषय हारर बन्द हो जाती है। अवस्तीति स्थिति में कृषक का स्थिति भी बुरी सराब हो जाती है क्योंकि निमित्त वस्तुओं का अफस कृषि क्षेत्र में उत्पादन का कीमतें तेजी से गिरना है।

अवस्तीति में निश्चित किराया तथा मजदूरी अर्जित करने वाले माहविषय को माध होता है। सभी निश्चित आय वाले वर्गों को साथ तथा परिणामस्वरूप आय वार वर्ग को मुक्तान उठाना पड़ता है। ऐसे तो अवस्तीति नाम में बचता को बड़ा पिनडा

है परन्तु माधारणतया आय में निरन्तर गिरावट से बचत करने की योग्यता भी गिर जाती है।

मुद्रा अस्फीति के उपायों का उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था को सक्रिय और समतुल्य बनाया जा सके। अस्फीति में उत्पादन राजस्व आय सभी गिरती है। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती है। आज भी दुनिया के देश सन् 1930 की मन्दी का इतना समय बीत जाने के बाद भी नहीं भुला पाए हैं। कीमत-न्तर में गिरावट आज भी किसी देश को तीसरी मन्दी की याद से चौंका देती है।

अस्फीति को रोकने के उपाय (Measures to Control Deflation)

अस्फीति का रोकने के लिए हम मूल्य रूप से ऐसी नीति अपनाती चाहिए जिससे कुल उत्पादन तथा रोजगार में स्तर में वृद्धि हो। परन्तु यह तर्क गम्भीर है जबकि ऐसी नीतियाँ उत्पन्न हो जायें प्रभावपूर्ण माँग में बढ़ाएँ। चूँकि अस्फीति का कारण निजी क्षेत्र में व्यापारिक क्रियाओं में सुस्ती आ जाती है और चारा और निराशावादी दृष्टि-बाण दमन का भिन्नता है इसलिए सरकारी क्षेत्र में आर्थिक नीतियाँ मोड़नी तथा राजस्व आय में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय जिससे कि कुल उपभोग तथा कुल निवेश माँग में वृद्धि होकर कुल प्रभावपूर्ण माँग बढ़ना चाहिए।

मुद्रा अस्फीति (Deflation) की स्थिति में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य एक उपाय का अपनाना है जिससे कि प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि हो। अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं निवेश का बढ़ाना हेतु कदम उठाने चाहिए। प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि उपभोग एवं निवेश का बढ़ना से प्रभावित होता है जिससे कि राजस्व का स्तर बढ़े। कुल मिलाकर इन दिशा में निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं

(1) करों में छूट (Tax Relief)—अस्फीति में मूल्य प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि हेतु सरकार का ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे लोग का वास्तविक उपभोग्य आय बढ़े। इसका नियम यह है कि आय में छूट दे, परन्तु ऐसा करते समय सरकार का यह ध्यान होना चाहिए कि करों में छूट से लोग की उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) बढ़े। यदि करदाताओं की सीमान्त व्यय प्रवृत्ति ऊँची है तो कर-छूट नीति सफल होगी। इसके विपरीत यदि करदाताओं की सीमान्त व्यय प्रवृत्ति कम है तो कर-छूट से कुल समर्थ माँग में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होगी।

(2) सरकारी व्यय में वृद्धि (Increase in Government Expenditure)—अस्फीति में निजी क्षेत्र में निम्न गिरावट है क्योंकि व्यापारिक क्रियाएँ स्थिर पड़ जाती हैं। इसलिए निवेश में वृद्धि के लिए सार्वजनिक निम्न खर्च के लिए सरकार का मूल्य सार्वजनिक को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकार का ऐसी योजनाओं को हाथ में लेना चाहिए जिससे कि लोग को अधिक से अधिक राजस्व प्रदान किया जा सके। सरकार का व्यय खर्च हेतु घाट के बजट (Deficits Budget) बनाना चाहिए ऐसा करके कुल उपभोग माँग में वृद्धि की जा सकती है।

सन् 1930 में अमेरिका की न्यू डील नीति (New Deal Policy) तथा फ्रांसोसो ब्लम प्रयोग (Blum Experiment) यह बताते हैं कि इन दिशा में उद्यम के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर गणतन्त्र प्राप्त की थी और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। मन्दी में मूल्य सरकार को ऐसी बड़ी योजनाओं का हाथ में लेना चाहिए जो निजी साहसिकता को प्रोत्साहित करें। अर्थात् निम्न निम्न करने वाली हो। सार्वजनिक कार्य निम्न प्रभाव-शाली हैं, यह हम बात पर निर्भर करता है कि इन योजनाओं के लिए वित्तीय साधन कैसे जुटाए जा रहे हैं। वे सार्वजनिक कार्य जिनकी वित्तीय व्यवस्था कर-वसूली द्वारा हो

रही है। अवस्फीति से निपटने के लिए उतने कारगर साधित नहीं होते जितने कि माँग-जनित श्रृंखला तथा पाटे के बजट द्वारा प्राप्त वित्तीय साधनों की प्राप्ति में होता है।

(3) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)—अवस्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक नीति का भी महत्त्व लिया जाता है। देश के वित्तीय ढँच द्वारा माँग नियन्त्रण के उपायों में दोनो देकर माँग गुंजन शक्ति व्यापारिक क्षेत्रों की बढ़ाई जाती है। बैंक दरों में कमी करने व्यापारिक क्षेत्रों के लब्ध होय बढ़ाए जाते हैं। मुद्रा बाजार की गिरावट गुंजन वृद्धि आरक्षित अनुपात तथा अन्य सामाजिक-नियन्त्रणों का उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति तथा निवेशों में वृद्धि करने प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने रोजगार उत्पादन तथा आय के स्तर में वृद्धि करना होता चाहिए।

मौद्रिक नीति द्वारा निवेशों में वृद्धि सभी सम्भव है जबकि व्यापारिक वर्ग भविष्य में प्रति आशावादी एवं उत्साही प्रतीत हो। यदि साहसी निराशावादी है तो वह वित्तीय ढँच द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति उत्साही एवं आशानुभूत व्यवहार नहीं करेंगे और निवेशों में वृद्धि नहीं होगी।

(4) पुराने ऋणों का भुगतान (Repayment of Old Loans)—सरकार को चाहिए कि वह पुराने सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करके लोगों के पास न्यून शक्ति में वृद्धि करे। ऐसा करके सरकार अवस्फीति (Deflationary) स्थिति पर कृष्ट गीमा तक काबू पान में सफल गिड़ हो सकती है।

स्फीति तथा अवस्फीति के बीच चुनाव (Choice between Inflation and Deflation)

मुद्रा स्फीति तथा अवस्फीति दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती हैं, क्योंकि दोनों ही अर्थतन्त्र की स्थिति को खराब करती हैं। दोनों में अवस्फीति मुद्रा-स्फीति की तुलना में अधिक भयानक साधित होती है। निम्न तथ्यों में इसकी पुष्टि होती है—

(1) मानव धन का विनाश—स्फीति में कीमती म वृद्धि होती है और वह वृद्धि व्यर्थ गह सेते है। स्फीति में रोजगार बढ़ान की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अवस्फीति में मूल्यों में गिरावट होने से अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थिति बनी रहती है। परमुद्रा के स्टॉकों में वृद्धि के कारण सेवायोजन अपने उत्पादन को पटाने लगते हैं। बेरोजगारी भीषण रूप धारण कर लेती है। अवस्फीति तर्जान समृद्धि (Wealth) के गुंजन में बाधा उत्पन्न करने बेरोजगारी बढ़ान के साथ उत्पादन में कटौत के लिए भी उत्तरदायी होता है। बेरोजगारी श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में ह्रास लाती है और यदि मन्दी अधिक समय तक रहे तो बेरोजगारी उन्हें कार्य करने योग्य भी नहीं रखती। बेरोजगारी के कारण धन दिवसों (Man days) की बहुत बड़ी हानि होती है। मानव धन क्षिण उत्पादन बढ़ा। तथा अन्य विकास कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मितनी है बर व्यर्थ जाता है और राष्ट्र एवं समाज को प्रगति की दृष्टि में घोटकाकारी पीछे पटक दिया जाता है।

(2) समाज पर भार के नैतिक पतन—अवस्फीति बेरोजगारी को बहुत बड़ी पीड़ बना देता है जो एक प्रकार से समाज पर एक बोझ साबित होते हैं। वे अयोग्य तथा अनुपयुक्त बनकर रह जाते हैं। समाज में ऐसा बेकार लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। घृणा और अपराध बढ़ जाते हैं। स्फीतिमान में नैतिक पतन, घृष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के रूप में सामा जाता है। व्यक्ति को मर्यादा के कारण स्फीतिमान में दोना समय पेटभर भोजन प्राप्त करना एवं कठिन समस्या बन जाती है।

(3) धन्य करने का अधिकार—प्रो० कीन्स कहते हैं कि स्फीति यद्यपि लोगों को धन्य करने का अधिकार प्रदान करती है परन्तु व्यय उपरान्त प्राप्त होने वाले फलफला को छीन लेती है। जब कि अवस्फीति में स्थिति इससे भी भयानक होती है क्योंकि बेरोजगारी व्यक्ति को व्यय करने के अधिकार से वंचित कर देती है। इस सत्य को नहीं भुलाया जा सकता कि वित्तुल रोटी न मिलने की तुलना में आधी रोटी मिल पाना वही अधिक सतोष-प्रद एवं अच्छा है। स्फीति में थमिक की राशियाँ प्राप्त होने से आधी रोटी का सहारा तो रहता है जबकि अवस्फीति में थमिक बेकार रहने से वाग्य उस आधी रोटी के उपभोग से वंचित रह जाता है।

(4) विनियोजन की शक्ति—मुद्रा स्फीति उत्पादक वगैरे का भाग में वृद्धि करके विदेशों के लिए आयातानुसार वातावरण उत्पन्न करने में वृद्धि करती है जिससे निवेशों का स्तर ऊँचा बना रहता है। इससे विपरीत अवस्फीति उत्पन्नकर्ता के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देती। निरन्तर हानि उठाने के कारण उत्पन्नकर्ता भविष्य में प्रति निराशा-वादी हो जाते हैं। अवस्फीति लभान तथा विरामे की आय (Rentier Class) प्राप्त करने वाले अनुत्पादक वर्ग का उत्साह प्रदान करती है। प्रो० कीन्स के विचारानुसार समाज में बेरोजगारी उत्पन्न करने तथा उत्पादक वर्ग को हतोत्साहित करने का तुलना में विनाश की आय पर रहने वाले अनुत्पादक वर्ग को निराश करना अधिक अच्छा है।

अवस्थवस्था में स्थिति स्फीति तथा अवस्फीति (Inflation and Deflation) दोनों ही बुराइयाँ हैं और अधिक प्रणाली की स्थिरता की दृष्टि से दोनों में ही कुछ न कुछ दाप पाए जाते हैं परन्तु जब कभी भी दो बुराइयाँ में से एक को चुनने की बात सामने आती है तो हम निश्चित रूप से अधिक बुराई पर अपना ध्यान बुराई वाली स्थिति का चयन करेंगे। ठीक इसी दृष्टि से स्फीति तथा अवस्फीति दोनों ही समाज के लिए बुराइयाँ हैं फिर भी दोनों में अवस्फीति अधिक बुरी है। प्रो० कीन्स के विचारानुसार स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अवस्फीति अनुपयुक्त है। इन दोनों में शायद अवस्फीति अधिक बुरी है।¹ कीन्स ने अवस्फीति का स्फीति की तुलना में अधिक बुरा माना है। थोड़ी सी स्फीति आर्थिक माँगों की उद्योग में चिकनाई का कार्य करके उसे स्थिर बनाती है जिससे पुनः उत्पादन में वृद्धि होती है जबकि अवस्फीति पुनः उत्पादन को गिराती है।

स्फीति समाज में आय तथा सम्पत्ति के बँटवारे में असमानता लाकर निधन का और निधन तथा धनी का और धनी बनाती है परन्तु यह अवस्फीति की भाँति वास्तविक आय की पुनः मात्रा को कम नहीं करती। स्फीति की रोकना उतना कठिन नहीं है जितना कि अवस्फीति को रोकना कठिन होता है। यदि देखा जाय तो वास्तविकता यह है कि भयानक मन्दी के समय लगभग सभी व्यक्ति जिसमें वृद्धिदाता भी शामिल होते हैं जिनके पास बहुत से ऋण वसूल करने की पड़े हैं। उसको भी चुनना होता है। हालाँकि प्रो० कीन्स ने स्फीति और अवस्फीति के मध्य चुनाव की समस्या उत्पन्न होने पर मुद्रा-स्फीति को चुनने का सुझाव दिया है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि अवस्फीति को अच्छा मानते हैं।

स्फीति तथा अवस्फीति दोनों ही बुरी हैं और इनके मध्य चुनाव करने जैसी बात हानी ही नहीं चाहिए। हम तो अवस्थवस्था में स्थिरता एवं सन्तुलन बनाए रखने का प्रयास करते हुए दोनों बुराइयों से बचना चाहिए।

1 Inflation is unjust and deflation is inexpedient of the two, perhaps deflation is the worse' — J. M. Keynes

परीक्षा-प्रश्न

- 1 मुद्रा-स्फीति क्या है ? स्फीतिक प्रक्रिया को बताइए और साथ ही स्फीति के प्रमुख प्रकार बताइए ।
(What is inflation ? Give inflationary process along with main types of inflation)
- 2 स्फीति के प्रभाव क्या हैं तथा स्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ?
(What are the effects of inflation and how can inflation be controlled ?)
- 3 स्फीतिक अन्तराल क्या है ? यह कैसे उत्पन्न होता है और अव्यवस्था में इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है ?
(What is inflationary gap ? How does it arise and how can it be removed in the economy ?)
- [सकेत लागत प्रेरित तथा माँग प्रेरित स्फीति की विस्तृत व्याख्या दीजिए फिर बताइए कि वास्तविक स्थिति को समझने में दिए दोनों जरूरी हैं ।]
- 4 माँग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्फीति में भेद कीजिए । क्या आप इन दोनों प्रकार की स्फीतियों में किए गए भेद को उपयोगी मानते हैं ?
(Distinguish between demand pull and cost push inflation Do you regard the distinction between these two kinds of inflation as useful ?)
- [सकेत—पहल माँग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्फीति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए । फिर बताइए कि उस्तु स्थिति समझने में दिए दोनों की उपयोगिता अपनी-अपनी जगह है ।]
- 5 मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए । देश के विभिन्न वर्गों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है ?
(Explain clearly the meaning of inflation and deflation How do they effect different sections of society in the country ?)
- 6 मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन का अन्तर स्पष्ट कीजिए । उनका देश की आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
(Distinguish between inflation and deflation How do they affect the economic growth of any country ?)
- 7 “स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अवस्फीति अनुपयुक्त इन दोनों में शायद अवस्फीति अधिक बुरी है ।” क्या आप कीन्स के इस बयान से सहमत हैं ?
(Inflation is unjust Deflation is inexpedient of the two perhaps deflation is the worse ' Do you agree with Keynes's state ment ?)
- [सकेत—पहले स्फीति तथा अवस्फीति का अर्थ बताइए उसके बाद इस अध्याय के अन्त में दोनों के बीच चुनाव शीर्षक की सामग्री दीजिए तथा निष्कर्ष बताइए कि दोनों में अवस्फीति अधिक बुरी है ।]

निर्माण करने उह लाभप्रद योजनाओं में उगत हैं । बैंकी का देश के व्यापारिक विकास में भी योगदान है । बैंक 'यस्तु बाजारा ना ध्यापक रूप दवर व्यापारिक क्रियाओं क विस्तार में सहायता दते है । व्यापारिक बक निम्नलिखित रूप में देश का आर्थिक प्रगति में सहायता पहुँचात है ।

बैंक व्यापार तथा उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं

दुनिया के आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि 200 वर्षों से अधिक समय में हानि वाली आर्थिक प्रगति में वैश्वीकरण का मदद की है। व्यापक व्यापारिक श्रियाओं तथा देशों के आधोयोग में वैश्वीकरण का भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जैसा कि हम देख चुके हैं व्यापारिक वैश्वीकरण साख निगमों के मुद्रा की पूंति को बढ़ाता है। जब वैश्वीकरण उभरता है अर्थिक दत्ता है तो साख-मुद्रा की पूंति का बढ़ता है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण का जिसको सामान्यतया वैश्वीकरण माध्यम से निगमों का जाता है तथा जिसको वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के लिए किया जाता है कुल मुद्रा पूंति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। वैश्वीकरण वैश्वीकरण तथा ट्रापेट जैसे साख मुद्रा को चलन में आने पर व्यापारिक विनियम सुगम एवं औद्योगिक गति बढ़ा दिया है। आज जितनी ही बनी राशि का भुगतान वैश्वीकरण ट्रापेट विनियम हण्डिया द्वारा सम्भव हो पाया है। साख मुद्रा का चलन न स्वदेशी व्यापार के अलावा विदेशी व्यापार के विकास में काफी सहायता दी है। व्यापारिक श्रियाओं तथा बाजारों के विस्तृत हानि विशिष्टीकरण औद्योगिक विकास आदि बहुत कुछ काय उन्नत वैश्वीकरण प्रणाली पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण श्रियाओं तथा उद्योगपतियों को अल्पकालिक मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक वित्तीय सहायता का प्रदान करता है साथ ही इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय सलाहकार तथा पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है।

बैंकों द्वारा देश में उपयुक्त उद्योगों का विकास करना

बैंक देश में निवेशकर्ताओं का उत्पादक कार्यों के लिए चपवासी तथा दीर्घकालीन ऋणा की व्यवस्था करने उन्हें नवद पूर्ण उपलब्ध कराने है। बैंक की भूमिका आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसका प्रोत्साहित करने में बैंक का योगदान भी कम नहीं है। बैंक ऋणा की सहायता से साहस अपना इवाई की उत्पादकता बढ़ाकर नई उत्पादन तकनीकी को अपना घर तथा नव नय यंत्रा तथा मशीन की सहायता से अपने उत्पादन की लागत को कम करने बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों से सामन दिव सचता है। बैंक सामान्यतया उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान करके देश में उद्योगों का समुचित विकास करके देश का उत्पादकता बढ़ाने में प्रयोक्ष रूप से योगदान करत है। परिणामस्वरूप देश में उत्पादन साधना की कार्यक्षमता में वृद्धि ता हाता हो है साथ में राष्ट्रीय आय का स्तर ऊँचा रहता है जिससे उपभोग तथा विनियोग का स्तर भी ऊँचा रहता है। कुल मिला कर, देश, बाधित, प्रगति, के लिए बैंक, न्याय, सहायता, प्रत्यक्ष करते, है १.

देश में पूँजी वितरण असमतन को दूर करना

वैव देश म व्याप्त पूजा वितरण व असन्तानन का दूर करत हैं। व्यापारिक वैव देश व पूजा साधना को उन क्षेत्रों म ल जाते ह जहाँ इनका अभाव पाया जाता है। इस प्रकार अधिक असन्तानन को दूर करने म वैव का योगदान भी किसी प्रकार से नहीं है। देश व विकसित क्षेत्रों स पूजा का हटाकर अविकसित क्षेत्रों की आँखों से जान म वैव आपस दुष्टि स पछिछे हुए क्षेत्रों व विकास म मदद करत है। वैव न राष्ट्रीय आपस असमानता को धाई का पाटन म महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

देश में पूँजी संचय तथा पूँजी का निर्माण को प्रोत्साहित करना

बैंक बचतकर्ताओं की बचतों को एकत्रित करके पूँजी संचय तथा पूँजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बैंक बचत सुविधाओं को प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण संस्था है। जहाँ बचतों को एकत्रित करके बैंक पूँजी संचय को सम्भव बनाते हैं वहीं दूसरी ओर बैंक छोटे-छोटे बचतकर्ताओं की पूँजी को एकत्रित करके एक बड़े पूँजी कोष को जन्म देते हैं तथा ऋण माँगने वाले ग्राहकों को एक ही स्थान पर ऋण मिल जाते हैं। बचतें पूँजी निर्माण का आधार होती हैं इसलिए बैंक का देश में पूँजी निर्माण करके आर्थिक विकास में सराहनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं बैंक बेकार तथा फालतू पड़ी हुई पूँजी को उत्पादन कार्यों में लगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपनी भागीदारी बनाए रखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की बचतों तथा निवेशों का परिणाम होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में उपभोग का स्तर ऊँचा और बचत का स्तर नीचा होता है जिससे आर्थिक योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन कम पड़ जाते हैं।

साख निर्माण द्वारा व्यापार को विकसित करना

व्यापारिक बैंक साख-निर्माता होते हैं। साख मुद्रा की पूर्ति में होने वाले उच्चावचनों का देश की आर्थिक प्रगति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। जब अर्थव्यवस्था में पूँजी निवेश की अधिक आवश्यकता हो तो व्यापारिक बैंकों को अधिक साख-निर्माण करने की नीति देश का केन्द्रीय बैंक अपना सकता है। व्यापारी तथा निर्माता वर्षों को अधिक ऋण प्रदान करके निवेशों को बैंक धड़ा सकता है। जिससे देश में आय तथा रोजगार का स्तर ऊँचा हो जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों में व्यापारिक बैंकों द्वारा साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके बैंक व्यापार तथा उद्योगों को ऋण प्रदान करके पूँजी निवेश बढ़ा सकते हैं जिससे कि देश का विकास तीव्र गति से हो सके।

बैंक द्वारा ऋणों का मुद्रीकरण करना

व्यापारिक बैंक अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक ऋणियों के बदले में माँग जमाओं (Demand deposits) को लेकर समुदाय की सेवा करती है। व्यापारिक बैंक उधारकर्ताओं से ऋण, जिनमें द्रव्य के नकदी गुण का अभाव होता है, जय करके उनके बदले में उन उधारकर्ताओं को भाग जमा देती है जो लोगों द्वारा साधारणतया मुद्रा के समान स्वीकार की जाती है। बैंक इस प्रकार की विनियम क्रियाओं को करके ऋण का मुद्रीकरण करती है। बैंक केवल मुद्रा का व्यापार ही नहीं करती वरन् मुद्रा का निर्माण भी करती है। हम बैंकों द्वारा साख निर्माण के अन्तर्गत देख चुके हैं कि बैंक व्यापार तथा उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देकर साख-निर्माण किस प्रकार करती है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में व्यापारिक बैंक केवल साख-निर्माण ही नहीं करते वरन् उस साख के उपयोग को सम्भव बनाकर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं।

बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रभावित करना

व्यापारिक बैंक व्याज की दर को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, बचत, निवेश तथा रोजगार के स्तरों को प्रभावित करती है। बैंक मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन उत्पन्न करके मुद्रा बाजार में प्रचलित व्याज दर पर अपना प्रभाव डालकर उपभोग तथा उत्पादन की क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अर्थव्यवस्था में सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) अपनाकर बैंक व्याज की दर गिराती है जस्य वास्ते समान रहते हुए, परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है।

अर्द्ध विकसित देशों में बैंकों का महत्व (Importance of Banks in Underdeveloped Countries)

बैंकों की विकसित देशों में अलावा अर्द्ध विकसित अवस्थावस्था वाले देशों में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्प विकसित देशों में बैंक विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी बचतों को समाज में एकत्रित करने, पूँजी संचय तथा पूँजी निर्माण को सम्बल प्रदान करते हैं। अर्द्ध विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या छोटे छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वहाँ बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में सम्पूर्ण आय का उपयोग अनुत्पादक कार्यों तथा उपभोग पर व्यय हो जाता है। ऐसे देशों में राशियों की बचतों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना इनकी दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के प्रथम तथा द्वितीय चरण (वर्ष 1969 तथा 1980) के बाद गारंटेड बैंक और इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे छोटे कस्बों में अपना शाखाएँ खोला है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रवर्तित (Sponsored) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता तक अपना घर-घर बैंकिंग प्रणाली की सुविधाएँ पहुँचाने का काम किया है जिससे राशियों में बैंकिंग आदतें विकसित हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बचतों का देश में विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीयकृत एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में हम अभी और आगे बढ़ना है। भारत की विधानसभा को दसत हुए बैंकों की पहुँच से अब भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र छूट हुए हैं। जब तक सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्प नहीं लेगी तब तक सुखद भविष्य का आशा करना व्यर्थ है।

अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी बाजार तथा मुद्रा बाजार का अभावसहित होने के कारण पूँजी का अभाव की स्थिति बनी रहती है और औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय सुविधाएँ नहीं जुटाई जा सकती। देश में पूँजी बाजार को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में स्थित व्यापारिक बैंक उद्योगों तथा अन्य फर्मों के धनो तथा ऋणपत्रों (Shares and Debentures) को खरीदें। ऐसा करना स्वयं बैंक के हित में भी होता है क्योंकि बैंकों का विकास उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है। हमें अलावा निर्यातक इण्डिया का बट्टा करके देश के निर्यात व्यापार को विकसित करने में भी व्यापारिक बैंक सहायक हो सकते हैं। अर्द्ध विकसित देशों के सामने सदा मुश्किलों का असंतुलन का समस्या तथा विदेशी विनिमय का अभाव की स्थिति बना रहती है। ऐसा स्थिति से निपटने के लिए इन देशों में निर्यातक उद्योगों तथा निर्यात सम्बन्धित योजनाओं (Export promotion Programmes) द्वारा पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित करने विदेशों में बहुत ही आवश्यक आयात किए जा सकते हैं।

बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Banks)

यद्यपि कार्यों के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण करना कठिन है क्योंकि सभी देशों में बैंक का काम एक समान नहीं होता परन्तु ऐसा होता हुआ भी बैंकों का वर्गीकरण सामान्य तथा उनके कार्यों के आधार पर ही किया जाता है। सामान्यतया कार्यानुसार बैंकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है।

- (1) व्यापारिक बैंक (Commercial Bank)
- (2) औद्योगिक बैंक (Industrial Bank)
- (3) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank)

- (4) कृषि बैंक (Agricultural Bank) (महवागी एवं भूमि विकास बैंक)
- (5) बचत बैंक (Saving Bank)
- (6) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank)

(1) व्यापारिक बैंक (Commercial Bank)—व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो माध्यान्तक व्यापार और उद्योग को अल्पावधि ऋण सहायता प्रदान करते हैं। ये बैंक जनता से जमाओं के रूप में नकदी प्राप्त करते हैं। जमाकर्त्ताओं का यह जमा उनके माँग पर स्वयं उनको अथवा उनके आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को वापस लौटाती है। वर्तमान समय में वाणिज्य बैंक जमाओं का स्वीकार करने तथा व्यापारिक को ऋण देना के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ भारत में लगभग सभी व्यापारिक बैंक ऋणियों का नये विवरण करते हैं। इससे अतिरिक्त ये ग्राहकों के ड्राफ्टों द्वारा द्रव्य का एक स्थान दूसरे से स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। बड़ी बड़ी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों का ताकत आदि की सुविधा भी प्रदान करती हैं।

(2) औद्योगिक बैंक (Industrial Bank)—औद्योगिक बैंक प्रमुख रूप से उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण सहायता प्रदान करने तथा औद्योगिक विकास में विशेष रूप से योगदान देती हैं। इन बैंकों द्वारा बड़ी बड़ी औद्योगिक फर्मों का अनेक ऋण तथा बान्ड्स तथा अग्रा आदि की विधि करवाने में सहायता देते हैं और उनके ऋण पत्रों की हामी (Underwriting) भी करते हैं।

उद्योग का अचन (Fixed) तथा कार्यशील (Working) पूँजी की आवश्यकता होती है क्योंकि दीर्घावधि तक इसका वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस विपरीत वस्तु निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल को खरादने तथा धमिका का वेतना का भुगतान करना के लिए अल्पावधि के लिए कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील तथा अचन पूँजी की मात्रा उद्योग की प्रकृति तथा इसके आकार द्वारा निर्धारित होती है। छान तथा श्रम प्रधान उद्योगों को कम अचन तथा कम कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है। इस विपरीत लोहा तथा इस्पात के समान जैसे आकार के उद्योगों को अधिक कार्यशील तथा अचन पूँजी की आवश्यकता होती है। जमनी फाग भण्डार आदि औद्योगिक चिह्नित दशा में इन बैंकों का काफी विभाग हुआ है।

अधिकांश औद्योगिक बैंक दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं तथा इन कारण से जमाकर्त्ताओं में अचल अथवा दीर्घावधि जमा प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देती हैं। भारत में यह प्रकार के बैंकों का विकास सम्भव नहीं हो पाया है यद्यपि कुछ समय पूर्व दश में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1964 ई० में औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) की स्थापना की है। यह बैंक देश के औद्योगिक विकास के लिए सहायता दे रहा है।

(3) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank)—विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य देश के विदेशी मुद्राओं को प्रतीत होता है विदेशी ऋणियों के नये विनिमय द्वारा देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। साधनों की उपस्थिति के अनुसार कभी-कभी ये बैंक घर के व्यापार का भी विदेशी सहायता प्रदान करते हैं।

विदेशी विनिमय बैंक का मुख्य कार्य विदेशी मुद्राओं का परिवर्तित करके आयात निर्यात में सहायता प्रदान करना होता है। यह बैंक विभिन्न दशा की मुद्राओं अपने पास

रखत है तथा अन्य देशों में अपने बैंक की शाखाएँ खोलकर विदेशी व्यापार का सुगम बनाने हेतु करते हैं। इन बैंकों की कार्य पद्धति इस प्रकार होती है। जब कोई विनिमय बैंक विनिमय बिजनेस करनेवाला है तो उस विनिमय बैंक की गति उसी देश की मुद्रा में होती है। तब वह बैंक उस बिजनेस का विदेश में स्थित अपने शाखा का भेजता है तथा देश की वह शाखा आहार्य (Drawee) से उस बिजनेस में निहित धनराशि का विदेशी मुद्रा में वसूल कर लेती है। ऐसा करने में विभिन्न देशों की मुद्राओं का स्थानान्तरण बिना ही अन्तर्गोष्ठीय भ्रमण होता रहता है। इसका अन्तार्थ यह बैंक अग्रिम विनिमय प्रतिभूतियाँ का आयात निर्यात आदि विदेशी व्यापारिक क्रियाओं को सम्पन्न करते हैं। यह बैंक विदेशी विनिमय देश में होने वाले उतार चढ़ाव का शेखर उनमें होने का जोखिम का कम करते हैं।

(4) कृषि बैंक (Agricultural Bank) कृषि बैंक वे होती हैं जो कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कृषकों को अत्यावश्यक मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋण सहायता प्रदान करती हैं। कृषि में सम्बन्धित कुछ विशाल कठिनाइयों का कारण व्यापारिक बैंक कृषि का ऋण सहायता प्रदान नहीं कर पाते हैं। प्रथम कृषि उत्पादन करने वाली है तथा यह प्राकृतिक प्रभावों से अधीन है। दूसरा पालन में होने की स्थिति में बैंक के लिए कृषक को ऋण समन करना काफी कठिन है तथा बैंक को पत्र प्राप्त होना भी भय रहता है। भारत में कृषि बिजनेस की समस्या का आज भी समाधान नहीं हो सका है। यद्यपि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1955 ई० में तथा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए की गई थी। अगस्त 1967 ई० में भारत सरकार ने कृषि रित्त का समन्वय का समाधान करने हेतु एक राष्ट्रीय मार्ग परिषद (National Credit Council) की स्थापना की है जो वाणिज्य बैंकों द्वारा अव्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों की मार्ग का वितरण पर नियन्त्रण रखेगी। भारत में कृषि का दीर्घावधि तथा अल्पावधि का भूमि विकास बैंक तथा कृषि नायक समितियाँ द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

(5) भूमि विकास बैंक (Land Development Bank) — भूमि विकास बैंक किसानों की दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह 5 से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किसानों का ऋण देता है। इस ऋण का आधार किसानों का भूमि को बंधन का रूप में रखना है। इन ऋणों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है तथा निश्चित अर्जाय का बाद आरम्भ होता है। यह बैंक सहकारी के आधार पर संगठित होता है। दुर्भाग्यवश यह अन्तर्गत सफलता नहीं मिल पाई है।

(6) कृषि सहकारी बैंक (Agricultural Co-operative Banks) — यह बैंक किसानों की अल्पकालीन ऋणों का पूर्ति करता है। भारत में सहकारी बैंक का स्वरूप इस प्रकार है। ग्रामीण स्तर पर सहकारी साज्य समिति (Village Coop Credit Society) जिसमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति मित्राकार इस समिति का गठन करते हैं। इस समिति की पूर्ण प्रवेश शुल्क अंशों की विपरीत जनता तथा मददगारों द्वारा जमा किए गए निधियों के अन्तर्गत कोषों के द्वारा तथा राज्य सहकारी बैंक से ऋणों द्वारा प्राप्त होता है। इस समिति द्वारा कृषकों को ऋण सहायता दी जाती है जिसमें यह समितियाँ सम्बद्ध होती हैं और इन सहायकों से ऋण प्राप्त करती हैं। इन सहकारी सहायकों के अन्तर्गत केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks) होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सहकारी सहायकों को ऋण देते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। इनके अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Banks) होते हैं जो जिले के केंद्रीय सहकारी बैंकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन राज्य सहकारी बैंकों के अन्तर्गत राजस्व बैंक और इण्डिया का कृषि साज्य विभाग होता है।

अधिव है वे बैंक रिजर्व ऑफ इण्डिया की दूधरी भूमी में सम्मिलित बैंक कहलाती हैं। जिन व्यापारिक बैंकों की चुवता पूँजी व आरक्षण 5 लाख रुपये से कम है वे बैंक गैर अनु-सूचित बैंक कहलाती हैं। व्यापारिक बैंक जमाकर्त्ताओं से जिनमें व्यक्ति, उद्योग, वाणिज्यिक संस्थान तथा अन्य सम्मिलित हैं चालू भियादों तथा बचत जमाएँ स्वीकार करते हैं। ये बैंक व्यापार तथा उद्योग को अल्पवर्षीय ऋण तथा अग्रिम प्रदान करते हैं। कुछ भारतीय बैंक विदेशी विनिमय लेन-देन भी करती हैं तथा इन बैंकों की विदेशों में शाखाएँ भी हैं। गत कुछ वर्षों में बड़े व्यापारी बैंकों ने अभियोग्य के रूप में कार्य करने उद्योगों के माध्यम से अग्रिम का अभियोग्य भी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने गारन्टी योजना के अधीन लघु उद्योगों को भी ऋण सहायता प्रदान की है।

व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति

अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की कुल जमा राशियाँ जुलाई 1988 में 1 26 009 करोड़ रुपये थीं। 23 मार्च 1990 को कुल जमा राशि 1 66 005 करोड़ पी जबकि 24 अगस्त 1990 को जो बढकर 1 75 000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई अर्थात् 5 महीनों में बैंक 5.3% प्रतिशत की वृद्धि हो रिवाज की गई। बरिग मुद्रा व अनुसार विगत वर्षों में बैंकों में जमा की उल्लेख वृद्धि ने सामान्य अभी तथा बैंकों की जमा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। बैंकों में समयावधि जमा राशि में वृद्धि की दर भी काफी धीमी है। इस वर्ष यह 6 प्रतिशत की दर से 8 242 करोड़ तक पहुँची जबकि पिछले वर्ष पहले 6 महीने में इसकी वृद्धि 7.8 प्रतिशत की दर से बढकर 9 146 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। वर्ष 1989-90 की जमा वृद्धि 19.1 प्रतिशत की तुलना में रिजर्व बैंक ने 1990-91 में निम्न जमा वृद्धि दर का अनुमान 16.6 प्रतिशत लगाया है। जमा वृद्धि दर में लम्बे समय से आ रही गिरावट का अभी बने रहने की सम्भावना है।

व्यापारिक बैंकों का कार्य (Functions of Commercial Banks)

व्यापारिक बैंकों का कार्य निम्नलिखित है—

(1) जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करना—बैंक को पूँजी दो प्रकार से प्राप्त होती है। प्रथम जनता या हिस्सों की मुद्रा बाजार में बैंक पर दूसरे व्यापारिक बैंक जाता जमा स्वीकार करते हैं तथा इन जमा राशियों पर व्याज देते हैं, ये बैंक चार प्रकार के जमा ग्रहण करते हैं—(i) चालू खाता (ii) बचत खाता, (iii) निष्पक्षता नीति खाता (iv) धन कर्षण खाता।

(i) चालू खाता (Current Account)—यह एक महत्वपूर्ण खाता होता है इसमें धारक कितनी ही बार बैंक में लेन-देन इस खाते में माध्यम से करते हैं। इन खातों पर बैंक सामान्यतः कोई व्याज नहीं देते बल्कि उल्टे ही बैंक ऐसे खातेदारों से आरम्भिक शुल्क वसूल कर लेता है। इस खाते की स्वयं का प्रयोग बैंक अपने हितों के लिए न करवाकर करता है क्योंकि इसकी स्वयं का भी सीमा है। इस खातेदार को एक न्यूनतम धनराशि अपने खाते में रखनी होती है।

(ii) बचत खाता (Savings Bank Account)—यह खाते अधिकतर छोटी बचतों या सामान्य व्यक्ति के द्वारा रखे जाते हैं। इन खातों पर सम्बन्धित बैंक व्याज देता है। ऐसे खातों में कम जमा तो कई बार की जा सकती है परन्तु धन निवाचने की सुविधा मर्यादा में दो या तीन बार ही दी जाती है। वर्तमान समय में ऐसे खातों की स्वयं पर 5% से 6% व्याज दिया जाता है।

(iii) निश्चिततासीन बचत (Fixed Deposit Account) इन सातों में एक निश्चित अवधि के लिए तोग अपनी रकम जमा करवाने है। यह समयावधि सामान्यतः 3 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। इस पर व्याज जमा करवाई जाने वाली अवधि के अनुसार दिया जाता है। इसमें धन जमा करने वाले को बैंक एक रसीद दे देती है।

इस जमा खातदार अपनी रकम निश्चित समयावधि के बाद ही ले सकते हैं परन्तु यदि उन्हें इस अवधि से पहले ही धन की आवश्यकता हो जाय तो बैंक इन सातों पर दिए जाने वाले व्याज से अधिक गणना करता है। यह खात उन्हीं व्यक्तियों द्वारा खोल जाते हैं जिनको व्याज के पर्याप्त आस तो प्राप्त करनी हो जाती है और जो एक निश्चित अवधि के लिए रकम देने की स्थिति में हों। इसी रकम का बैंक विनियोजित करती रहती है।

(iv) घरेलू बचत खाता (Home Safe or Savings Account)— कुछ बैंक घरेलू बचत खात की सुविधाएँ अपने ग्राहकों को देते हैं। सामान्यतः बैंक अपना ग्राहकों के लिए छोटी छोटी मुल्यते या गिजोरी देते हैं और उसमें तारा लगाकर बचत कर सकते हैं। अपने पास रख लेता है एक निश्चित समय के बाद बैंक का प्रातिनिधि ऐसे ग्राहकों के पास जाता है और तारा खोलकर रकम उस ग्राहक के सामने गिनकर दे जाता है और उसकी जमा रसीद देकर उस रकम को ग्राहक के खात में डाल देता है। बैंक इस पर साधारण व्याज देता है। अल्प बचत तथा बच्चे या गृहणियों की सुविधा तथा छोटी छोटी बचतों को आवण्टित करने के लिए ऐसे खाते खोले जाते हैं।

(II) ऋण प्रदान करना— ये बैंक अतिरिक्त धन को उत्पादकों तथा व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार की जमानता पर ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देते हैं क्योंकि ऐसा करने में बैंक को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ये बैंक व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसा करने में बैंक को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। भारत में ऐसी व्यवस्था का अभाव है जो बैंक को अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सही सही सूचना दे सके। व्यापारिक बैंक अपना अतिरिक्त धन व्यापारियों को ही अल्पकालीन ऋणों में देते हैं क्योंकि इनमें एक ओर तरलता रहती है तो दूसरी ओर उन्हें ऐसे ऋणों पर अपेक्षाकृत अच्छी व्याज दर प्राप्त होती है।

ऋणों के प्रकार— व्यापारिक बैंक द्वारा निम्न प्रकार से ऋण दिए जाते हैं—

(i) नकद साख (Cash Credit)— व्यापारी वर्ग को निश्चित रूप से धन की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारी को कितने धन की आवश्यकता होती है इसका अनुमान पहले से लगा लेता है और उतनी ही रकम उधार लेने का समझौता बैंक से कर लेता है। यह रकम व्यापारी नकद न लेकर समय-समय पर बैंक से लेता रहता है। उसे निराली गई रकम पर ही व्याज देना पड़ता है। यह रकम पर्याप्त जमानत पर दी जाती है। व्यापारी वर्ग सामान्यतः अर्थ या सरकारी प्रातिभूतियों को धरोहर के रूप में बैंक के पास रखते हैं इस पर साभाश तथा व्याज ग्राहक को मिलता है।

(ii) अधिविर्ष (Overdrafts)— यह सुविधा सामान्यतः बचत खातदार से देती है। यह खातदार बैंक से जमा रकम से अधिक रकम लेने का समझौता कर लेते हैं। यह रकम अधिविर्ष कहलाती है। ग्राहक के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने जितनी रकम अधिविर्ष के रूप में लेने का समझौता किया है उतनी रकम एक बार में निकाल ले। आवश्यकतानुसार वह अधिविर्ष की रकम लेता रहता है और ग्राहक को वास्तविक निकासी जान वाला राशि पर व्याज देना होता है। अधिविर्ष की रकम पर्याप्त जमानत तथा ग्राहक को साख पर दी जाती है।

(iii) अग्रिम (Advances)—बैंक की अधिकांश रकम ऋण अथवा अग्रिमा के रूप में जाती है। ऋण एक निश्चित रकम के निर्धारित व्याज की दर पर दिए जाते हैं। जब बैंक किसी व्यक्ति का अग्रिम देता है तो यह रकम खातेदार के हिसाब में लिये दी जाती है। रकम बैंक के खाने में निम्न जान के बाद उसी दिन से व्याज ग्राहक पर लगता है। चाहे ग्राहक यह रकम एक मास ले ले अथवा बिस्तरा में बैंक से निम्नाने। इससे विपरीत नकद साप तथा आधिविक्रय में जितनी रकम ग्राहक लेता है उसी पर व्याज लगता है।

ऋण जमानत पर तथा निश्चित रकम अर्वाध के लिए दिए जाते हैं। यह ऋण पूणत सुरक्षित ही होने हैं।

(iv) व्यापारिक बिलों की कटौती (Discounting of Trade Bills)—बैंक अपना चानू पूजा का एक भाग व्यापारिक बिलों में लगाना है। बैंक मारधित्रिता (Usance bills) की कटौती तुरन्त करता है। बिलों की कटौती करते समय बैंक टग बात का ध्यान रखता है कि मध्यस्थित बिज व्यापारिक बिज ही ह। विवमित दशा में बिलों की कटौती करने के लिए कटौती गृह (Discount House) स्थापित किये गये हैं।

व्यापारिक बिजों में धनराशि लगाने पर व्यापारिक बैंक का अल्पमान के लिए पैसा लगाना पता है दूसरे व्यापारिक बैंक का आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दण के मन्द्रीय बैंक में भुनाया जा सकता है। व्यापारिक बिजों के लन-दने द्वारा ऋणदाता एक ऋणी दोनों को लाभ रहता है।

(III) एजेंसी अथवा प्रतिनिधि कार्य (Agency or Representative Functions) व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए कुछ सवाएँ उमके द्वारा माँगी जाते पर उपलब्ध करता है। कुछ सवाएँ सगुण्य तथा कुछ निशुल्क प्रदान की जाते हैं। यह सुविधाएँ निम्नलिखित ह। मकती हैं—

(i) ग्राहकों के चेक, बिलों आदि के भुगतानों को सग्रहीत करना—बैंक ग्राहक के चेक विनिमय बिल टूण्डी आदि का भुगतान प्राप्त करके ग्राहक के खाते में डाल देता है। चानू यातेदारा को यह सुविधा प्रायः निशुल्क दी जाती है अन्य स्थान के लिए बैंक शुल्क लेता है।

(ii) ग्राहकों के चेक, बिल आदि का भुगतान देना—बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान करत है। कमी-कमी तो ग्राहकों के आदस पर स्थानार किए गये बिजों का भुगतान कर देने ह और इस काय के लिए ग्राहकों से शुल्क ले लेत हैं।

(iii) नियमित भुगतान करना और सग्रह करना—ग्राहकों के स्टाई आदस (Standing Order) पर बैंक ग्राहकों के मकान के विराय, बीमा पारिगा की निश्चित तथा अन्य दायित्वा का निगतरा अर्थात् भुगतान प्राप्त करने तथा उन्हें सग्रहीत करने का कार्य करत रहत हैं। बैंक ग्राहकों के इन कार्यों का करने के लिए कुछ शुल्क लेत है।

(iv) विप्रेषण सुविधाएँ (Remittance Facilities)—बैंक अपने ग्राहकों के लिए रकम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का व्यवस्था करता है।

(v) अता तथा प्रतिभूतियों का प्रय विव्रय—बैंक अपने ग्राहकों के आदस पर विभिन्न प्रकार की कपानिया के अम, सरकार प्रतिभूतियों आदि पारीदत और बचत रहते हैं।

(vi) सन्दर्भ पत्र—बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना विदशा तथा दण के विभिन्न स्थानों पर ग्राहकों की आवश्यकतानुसार देत है यह सवा प्रायः निशुल्क होती है।

(vii) ट्रस्टी तथा प्रबंधक के रूप में—बच अपने ग्राहकों की सम्पत्ति की व्यवस्था विभाजन तथा प्रबंध का कार्य भी कर लेते हैं।

(viii) वित्तीय सलाहकार—एक अपने ग्राहकों के लिए पूँजी विनियोजन में सहायकारी क्षमता की जानकारी देकर ग्राहकों को सुदृढ़ क्षमता में पूँजी विनियोजन की सलाह भी देते हैं।

(IV) विविध कार्य (Miscellaneous Functions)—उपयुक्त कार्यों के अलावा बैंक कुछ कार्य और करता है जिन्हें सहाय्य कार्य कहा जाता है जैसे—

(i) सम्पत्ति तथा बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना—बैंक अपने ग्राहकों का बहुमूल्य चीज सम्पत्ति जैसे—सोना चाँदी हथोरे-जवाहरात तथा कीमती पत्रों को रखने के लिए लाकड़ सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इन लाकड़ का एक खाता बैंक के पास तथा दूसरी ग्राहक के पास रहता है। जब तब दोनों चाबियाँ नहीं लगनी तबिलारी या लाकर नहीं सुवेगा। लाकड़ सुविधा के लिए बैंक वार्षिक बिराया लेता है।

(ii) विदेशी विनियम तथा साख पत्रों अथवा यात्रों चक की सुविधा—व्यापारिक बच ऐसे ग्राहकों के लिए यह सुविधाएँ देता है जो विदेशी यात्रा पर जाते हैं या विदेशों से लेन देन करते हैं। विदेशों पर जाने यात्रा यात्रों जोखिम से बच जाते हैं।

(iii) उपभोक्ता साख देना—बच अपने ग्राहकों के लिए उपभोक्ता पस्तुनी जैसे—स्टर मोटर साईकिल कार फ्रिज एयर कंडीशनर कूलर आदि की परीक्षण का सुविधा देते हैं। ऐसी सुविधाएँ औद्योगिक विकास के लिए प्रायः दी जाती हैं।

(iv) अक सग्रह एवं शिक्षण—प्रायः सभी बच एक बर्किंग बिल तथा व्यापार आदि सम्बंधी आँकड़ सग्रह कर उन्हें समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। इनके प्रकाशन से जनता एवं बच के ग्राहकों के लिए जानकारी मिलता रहती है।

(v) साख का निर्माण—व्यापारिक बच के प्रमुख कार्यों में साख निर्माण का कार्य आता है। बच अपना जमा राशि स कई गुना साख मुद्रा की मात्रा निर्मित करते ऋण प्रदान करते हैं।

बैंकों द्वारा साख मुद्रा का निर्माण (Credit Creation by Banks)

बैंकों को साख मुद्रा निर्माण कार्य के कारण वर्तमान मौद्रिक अवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रो० सेपस ने कहा है कि बैंक बचल मुद्रा का आदान प्रदान करने वाले नहीं होते परंतु महत्वपूर्ण अर्थ में वह मुद्रा के निर्माता होते हैं (Banks are not merely surveyors of money but also in an important sense manufacturers of money) बैंकों के साख निर्माण के कार्य द्वारा बैंकों की कुल जमा पूँजी कई गुना बढ़ जाती है। एक बैंक का साख निर्माण शक्ति सामित होती है। बैंकों का अर्थ में आर्थिक जमा पूँजी का एक भाग नकद के रूप में रखना पड़ता है जिससे कि वह अन्य बर्किंग कार्यों या सुगमतापूर्वक निपटा सकता है।

वर्तमान समय में साख मुद्रा का एक दश वां अव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस साख मुद्रा का निर्माण बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंक अपने पास राशि का जमा धनराशि के आधार पर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। साख मुद्रा निर्माण के समय दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती हैं। प्रथम तो यह है कि वर्तमान अव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तिगत बैंकों (Individual banks) होता है कोई एक बैंक अपना कुल नकद जमा का केवल कुछ प्रतिशत भाग ऋण के रूप में उधार पर दे सकता है परंतु एक अव्यवस्था में सम्पूर्ण बर्किंग प्रणाली कुल नकद जमा (Total cash)

deposits) का कई गुना राशि उधार देकर मांग मुद्रा का निर्माण कर सकती है। दूसरी जो सांग मुद्रा निर्माण का विषय है वह यह कि हम प्राथमिक जमाआ (Primary deposits) तथा गौण जमाआ (Secondary or derivative deposits) के बीच अन्तर पाते हैं। प्राथमिक जमाआ का निर्माण अथवा प्रत्यक्ष जमा तथा गौण जमाआ का सन्निध्य अथवा अप्रत्यक्ष जमा (Indirect deposits) भी कहते हैं। प्राथमिक जमाआ का निर्माण जमाआ का वास्तविक जमा के आधार पर होता है और वह द्वारा इनका निर्माण नहीं होता जबकि गौण अथवा सन्निध्य जमाआ का निर्माण बैंक करत है और इनका आधार प्राथमिक जमा आ होता है। गौण जमा आ का द्वारा व्यापारिक तथा ऋणिया का अग्रिम तथा ऋण प्रदान करने के फलस्वरूप होता है। गौण जमाआ प्राथमिक जमाआ का परिणाम होती है और गौण जमाआ के निर्माण का कारण अव्यवस्था में मुद्रा का गुन पूर्ति में वृद्धि होता है।

एक तरह व्यापारिक संस्था में गमान होता है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यह लाभ बैंक जमाआ का प्राप्त करने उर ऋण के रूप में उठाकर ब्याज तथा अन्य वैयक्तिक भराआ का प्रदान करने उठाते हैं। बैंक प्राथमिक जमाआ के आधार पर सांग मुद्रा का निर्माण करता है। ऋणियों का ऋण प्रदान करने है और इन ऋणों पर मिलने वाले लाभ में से जमाआताओं का जमा पूँजी पर ब्याज देकर शेष धन ब्याज के रूप में प्राप्त करके लाभ करता है। इस प्रकार बैंक निष्क्रिय जमाआ का सन्निध्य जमाआ में बदल देते हैं जिसका उपयोग व्यवसाय तथा अन्य संस्थाओं के विस्तार हेतु किया जाता है। एक कुशल बैंक यही होता है जो आवश्यकता तथा नियमानुसार नकदी से ज्यादा नकदी पाने में सफल उस उपयुक्त समय पर ऋण तथा अग्रिमों का माँग करने वाला का देकर अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सके।

सांग निर्माण प्रक्रिया (Process of Credit Creation)

सांग निर्माण प्रक्रिया का आरम्भ बैंक के पास जमा जमाआताओं की धनराशि का प्राथमिक जमाआ के रूप में अपना नकदी को जमा करके का साथ होता है। बैंक अपने सामान्य अनुभव के आधार पर यह जानते हैं कि जो भी जमाकर्ता बैंक के पास अपनी धनराशि जमा करते हैं वह एक साथ एक मुश्त अपना धनराशि का वापस लेने नहीं जाते। बैंक विभिन्न प्रकार की जमा पूँजी प्राप्त करते हैं जैसे सामान्य बचत खाते में, सावधि जमा खाते में आदि। बचत खाते (Savings Bank Account) में जो धनराशि जमा की जाती है उसका बैंक से नियमानुसार जमाकर्ता निशान सकता है। सावधि जमा खाते अथवा निश्चित अवधि (Fixed Deposit Account) खाता में जो धनराशि जमा की जाती है उसका बैंक पर निश्चित अवधि तक आमाना से उधार दे सकता है जबकि बचत खाते में प्राप्त जमा पूँजी के एक निश्चित भाग का नकद अपने पास रखकर बैंक शेष धनराशि का उधार दे देता है। इस प्रकार बैंक बचत नकद जमाआ का ऋण चाहने वाला का जमाआ को प्रदान कर अनुसार उधार देकर एक ऋण पर ब्याज प्राप्त करता है। सम्पूर्ण वैयक्तिक प्रणाली का दृष्टि से सांग मुद्रा निर्माण का प्रवृत्ति बहुगुणक होता है। इस जमा गुण के जमाय मूल रूप से अधिक परन्तु अनन्त में नहीं होता है। परन्तु एक बैंक का दृष्टि से सांग एक बैंक के प्राथमिक जमा आ केवल कुछ प्रतिशत भाग ही उधार देकर सांग मुद्रा का निर्माण करता है। एक बैंक की अधिक सांग मुद्रा निर्माण शक्ति जमाआताओं द्वारा प्राथमिक जमा राशि के ऊपर निर्भर करती है।

सांग मुद्रा निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में दश का मुद्रा अधिकारी अथवा राष्ट्रीय बैंक वैयक्तिक प्रणाली अथवा बैंक जमा जमाकर्ता तथा प्रत्याहारकर्ता शामिल होते हैं, तथा उधारकर्ता वय के चार पक्ष होते हैं। सांग-मुद्रा निर्माण के सम्बन्ध में उधारकर्ता वय

वा यह महत्व होता है कि इस धन द्वारा साख-मुद्रा की उस वास्तविक माँग राशि का निर्धारण होता है जिसका सम्पूर्ण बैंकिंग जमाआ निर्माण करती है अन्य तीन। पक्ष बैंकिंग प्रणाली का इष्टतम साख-मुद्रा प्रति धारता अथवा साख मुद्रा की उस इष्टतम राशि का, जिसका निर्माण बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया जा सकता है निर्धारित करते हैं।

प्रो० रिफार्डो कहते हैं कि बैंक का साख मुद्रा निर्माण धन का उत्पन्न उग मध्य होता है जब बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के धन का उपयोग करती है। जब तक बैंक अपनी पूँजी को उत्पन्न करती है तब तक वह बचत पूँजीपति उग का धन प्राप्त करती है। सक्षम गृह्य पर गाने है कि बैंक अपने जमाकर्ताओं की धनराशि का उपयोग करती है इस कारण बैंक द्वारा साख मुद्रा निर्माण का सम्बन्ध इसका अपना जमाकर्ताओं की धनराशि का निवेशकर्ताओं का उधार देने से होना चाहिए। देश के केन्द्रीय बैंक का साख मुद्रा का विस्तार एवं संकुचन में बड़ा महत्व होता है। साख मुद्रा का विस्तार एवं संकुचन बैंक जमाआ का विस्तार एवं संकुचन से सम्बन्धित होता है। केन्द्रीय बैंक के पास साख नियन्त्रण के विभिन्न अस्त्र होते हैं जिनका उपयोग वह आवश्यकतानुसार करता रहता है।

बैंक जमा का प्रकार से सुचित की जाती है। बैंक जमा का एक रूप उग मध्य हमारे सम्मुख आता है जबकि ग्राहक को नकदी या या उसका पास जमा होती है। ऐसी जमा प्राथमिक जमा कहलाती है। यह प्राथमिक जमाएँ बैंक की परिसम्पत्ति (Assets) तथा दायताओं (Liabilities) दोनों में ही वृद्धि करती है। प्राथमिक जमा ही बैंक की जमा माना जा आकार का निर्धारण करती है। प्राथमिक जमाओं से चलन मुद्रा जमा मुद्रा के रूप में परिचित हो जाती है और समुदाय के लिए उपलब्ध मुद्रा की प्रति अपरिवर्तित रहती है।

बैंक दूसरे प्रकार की जमाओं को प्राप्त करती है जिन्हें गौण जमा (Derivative deposits) या (Secondary deposits) कहते हैं यह जमा ऋणों का दान अथवा प्रतिभूतियों को सौंपने अथवा बैंक की परिसम्पत्ति में वृद्धि होने से होती है। व्युत्पन्न जमा अथवा गौण जमा (Derivative or Secondary Deposits) की मात्रा बैंक द्वारा ऋण प्रदान नीति तथा बैंक की विनियोग नीति पर निर्भर करती है। जब बैंक एक ग्राहक का ऋण प्रदान करता है अथवा एक विनियोग से प्रतिभूति सौंपता है तो सामान्यतया वह इसका भुगतान नकद में करके ऋणी अथवा प्रतिभूति के विनियोग का अपना मही सातों राशन देता है और इतनी धनराशि उस खाते में शाल देता है जितना वह ऋण दिया है अथवा प्रतिभूति उसने सौंपी है। ऋणी अथवा प्रतिभूति विनियोग का यह धनराशि बैंक पर बैंक लिखावर अदा करने या उस धन का प्रावधान होता है। बैंक के इस प्रकार के चलन (Customs) के आधार पर यह कहावत प्रचलित है कि प्रत्येक ऋण एक जमा का निर्माण करता है। (Every loan creates a deposit)।

व्युत्पन्न जमा बैंक द्वारा निर्मित होने से समुदाय की माँग जमाओं पर अधिकारों में वृद्धि बिना योग्य के पास मुद्रा में बर्ती निरह होती है। इस प्रकार व्युत्पन्न जमाएँ समाज में मुद्रा के कुल स्तर में वृद्धि करती हैं। सामान्य रूप से बैंक गौण अथवा व्युत्पन्न जमाओं को प्राथमिक जमा के आधार पर निर्गत करते हैं। प्रत्येक बैंक यह अनुभव करता है कि कुछ प्राथमिक जमाएँ उससे पास जमा होती हैं और कुछ उगम पास में निवर्तित रहती हैं। सामान्य अनुभव के आधार पर एक तथ्य यह भी माना जाता है कि जितना जमा कर्ता अपनी पूँजी बैंक के पास जमा करता है वह सारी का सारी पूँजी एवं साथ में निकालते अथवा कुछ प्राथमिक जमाओं के एक भाग को ही बैंक से एक समय निकाला जाता है। बैंक नकदी रक्षण का कार्य करता है जिससे कि वह माँग पर जमा धनराशि का भुगतान कर सके इस प्रकार नकदी रक्षण का Customary cash reserve ratio जो कि

10 प्रतिशत या फिर कुछ और हो सकता है। Customary cash reserve ratio भी बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है। बैंक इस नवदी को आशियन रूप से तरल मुद्रा तथा आशियन रूप से कन्द्रीय बैंक के पास रखी जाने वाली नवदी का करता है।

ऋण प्रदान करने के व्युत्पन्न जमा बैंक द्वारा होती है उनका भुगतान को ऋण लेने वाला बैंक पर बैंक नियंत्रण निवाल सकता है परन्तु जिनको यह धनराशि प्राप्त होती है वह दूसरे बैंक या नवदी या बैंक जमा करा सकते हैं। दूसरे बैंक के पास इस प्रकार नवदी या बैंक जमा होने से उसका व्युत्पन्न जमा बढ़ जाती है और उसका आधार पर वह अधिक मात्रा मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। यह बैंक किसी अन्य बैंक से प्राप्त करता जाता है और फिर यह उसकी प्राथमिक जमा का रूप धारण कर लेता है और यह प्रथिमा उस समय तक चलता रहता है जब तक कि मास की कुछ मात्रा अथवा व्युत्पन्न जमाएँ सभा बैंक द्वारा पहली वाली बैंक का प्राथमिक धनराशि से बढ़ गुना बढ़ जाती है।

हम व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली में सात निर्माण प्रथिमा का एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं इस उदाहरण द्वारा हमने यह भी माना है कि बैंक अपना जमा का 10 प्रतिशत नवदी का रूप में रखता है। माना कि एक व्यक्ति बैंक A के पास 10,000 रुपये जमा करता है तो बैंक A का तुलन पत्र (Balance sheet) निम्न प्रकार होगी

बैंक 'A' तुलन पत्र-1 (Balance Sheet)

दयताएँ (Liabilities)		परिसम्पत्तियाँ (Assets)	
मांग जमाएँ (प्राथमिक)	10,000 ₹०	नवदी जमा	10,000 ₹०
		आवश्यक बाप	1,000 ₹०
		अतिरिक्त बाप	9,000 ₹०

बैंक A के पास 9,000 ₹० का अतिरिक्त राशि है। बैंक 1,000 ₹० नवदी बाप का करता है तथा 9,000 ₹० का अवशेष का व्युत्पन्न जमा (Derivative deposits) का निर्माण कर सकता है। बैंक का तुलन-पत्र परिवर्तित होकर निम्न प्रकार से होगा—

बैंक 'A' तुलन-पत्र 2

दयताएँ (Liabilities)		परिसम्पत्तियाँ (Assets)	
मांग जमाएँ (प्राथमिक)	10,000 ₹०	नवदी बाप	10,000 ₹०
मांग जमाएँ (व्युत्पन्न)	9,000 ₹०	ऋण	9,000 ₹०

माना कि बैंक 'A' से उधार लेने वाला X व्यक्ति 9000 रु० का चेक मिस्टर Y के लिए देता है और Y इस चेक को बैंक B में जमा कर देता है ता बैंक B का तुलन-पत्र इस प्रकार होगा —

बैंक 'B' तुलन पत्र-1

देयताएँ (Liabilities)		परिसम्पत्तियाँ (Assets)	
मौल जमाएँ (प्राथमिक) (Deposits Primary)	9 000 रु०	नकद काष (Cash Reserve)	9 000 रु०
		नकदी जिस रकमत अवश्य है (Required Reserve)	900 रु०
		अतिरिक्त कोष (Excess Reserve)	8 100 रु०

उपयुक्त तुलन-पत्र दर्शाता है कि बैंक B के पास अतिरिक्त काष 8100 रु० के हैं और B इन 8100 रु० की व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण कर सकता है। अब बैंक B अपने ग्राहकों का विस्तार करता है तथा अपनी अतिरिक्त कोष व बराबर जमा कर लेता है ता इसका तुलन पत्र निम्न प्रकार में होगा —

बैंक 'B' तुलन पत्र 2

देयताएँ (Liabilities)		परिसम्पत्तियाँ (Assets)	
मौल जमाएँ (प्राथमिक)	9 000 रु०	नकद कोष	9 000 रु०
मौल जमाएँ (व्युत्पन्न)	8 100 रु०	ग्राहक	8,100 रु०

बैंक B 8,100 रु० का धूण जब किसी व्यक्ति का देता है और यह व्यक्ति मिस्टर C इस 8,100 रु० धूण राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करता है जो बैंक C में अपने खाते में जमा करा देता है तो बैंक C का तुलन पत्र निम्न प्रकार में होगा—

बैंक C तुलन-पत्र

देयताएँ (Liabilities)		परिसम्पत्तियाँ (Assets)	
मौल जमाएँ (प्राथमिक)	8 100	नकद काष	8 100 रु०
		नकदी जिस रकमत अवश्य है	810 रु०
		अतिरिक्त काष	7 290 रु०

उपयुक्त तुलन-पत्र दर्शाता है कि बैंक C के पास अतिरिक्त कोष 7,290 रु० के बराबर हैं अर्थात् बैंक C 7,290 रु० के बराबर व्युत्पन्न जमा का सृजन कर सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक बार बैंक की स्यताओं में वृद्धि होती है परन्तु यह वृद्धि घटती हुई लग्न में होती है। मान्य सृजन का प्रक्रिया उम समय तक चालू करता रहता जब तक कि प्रथम बैंक का मौद्रिक अतिरिक्त बाय 1 000 रुपय का विभिन्न बैंक का महा हो जाता और यह बैंक का अतिरिक्त बाय (excess reserve) नहीं हो जाते। मान्य सृजन का इस प्रक्रिया में परिणामस्वरूप कुल महा स्यताओं का योग प्राथमिक जमा का 10 गुना होना पर यह प्राप्ति का चालू रहता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मान्य सृजन प्राप्ति का अनुपात अव्यवस्था में मुद्रा का प्रतिगुण प्रणाली का प्रचलित होना पर एक बैंक में प्राथमिक योग जमा का 10 गुना होना पर दूसरे मान्य मुद्रा का मात्रा अथवा व्यय न जमा हो जाता है। इस मान्य मुद्रा के स्तर का आर्थिक उदाहरण का आधार पर इस प्रकार समझाया जा सकता है -

साख का गुणक विस्तार (Multiple Expansion of Credit)

1	2	3	4
बैंक	दियाए (प्राथमिक जमाएँ, रुपया में)	नकद बाय जो जरूरी होते हैं (रुपया में)	अग्रिम (धुल्यता जमा रुपया में)
A	10 000	1 000	9 000
B	9 000	900	8 100
C	8 100	810	7 290
D	7 290	729	6 561
E	6 561	656 10	5 904 90
Total	1 00 000	10 000	90 000

आजगतितीय रूप में स्तरन सख्या (2) = 10 000 रुपय + 10 000 रुपय $(9/10) + 10 000 रुपय (9/10)^2 + 10 000 रुपय (9/10)^3 + \dots + 10 000 (9/10)^n$ यह गुणात्मक प्राप्ति का योग (sum of Geometric progression) होता है $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n$ जहाँ $n \rightarrow \infty$ अर्थात् अनन्त (infinity) अथवा $n = 1/1 - r$ जहाँ उपयुक्त उदाहरण में $r = 9/10$ अर्थात् 90 प्रतिशत तथा $a = 10,000$ । इन सूत्रों का एक काम न ग गणन पर हम यह पाते हैं -

$$10 000 \left(\frac{1}{1 - 9/10} \right) = 10 000 \frac{1}{1/10} \\ = 10 000 \times 10 \\ = 1 00,000 \text{ रुपय}$$

हम यह देखते हैं कि मान्य सृजन प्रक्रिया का अंत उम समय होता है जब कि सा बैंक का बाय का अतिरिक्त बाय (excess reserve) न्यून हो जाये। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मान्य-सृजन अथवा धुल्यता, जहाँ प्रक्रिया उम समय तक चलती रहता है जब तक कि बैंक का अतिरिक्त बाय का स्तरण दूसरे बैंक का नकद बाय अनुपात (reserve ratio) का आधार पर होता रहता है।

इस जमा गुणक विस्तार प्रक्रिया में प्रमुख रूप में तीन पक्ष बाय करते हैं (i) बाय जो बैंक को बैंक में जमा करते हैं (ii) बैंक जो कि अपना जमा का एक भाग

ही नकदी के रूप में रखता है (iii) उधार लेने वाले (सावजनिक अथवा निजी) व्यक्ति जिनसे बैंको को अपनी परिसम्पत्तियों को अर्जित करने में सहायता मिलती है।

बैंक की साख निर्माण शक्ति की सीमाएँ (Limitations on Bank's Power of Credit Creation)

वर्तमान समय में वैश्व प्रणाली के अंतर्गत साख निर्माण व्यापारिक बैंको द्वारा किया जाता है परंतु बैंक की यह साख निर्माण शक्ति असीमित नहीं होती। प्रत्येक बैंक किसी दी हुई सीमा तक ही साख निर्माण कर सकता है। बैंको की साख निर्माण शक्ति कई बातों पर निर्भर करेगी यह बातें निम्न प्रकार से हैं—

(1) नकदी की मांग—बैंको की साख निर्माण की सीमा बैंको के पास उपलब्ध प्राथमिक जमाओं (Primary deposits) की मात्रा पर निर्भर करेगी। प्राथमिक जमाएँ ही बैंको को नकदी प्रदान करके बैंको को साख निर्माण का आधार होती हैं। प्राथमिक जमाओं की मात्रा जितनी अधिक होगी बैंको की साख निर्माण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि उतने ही अधिक अतिरिक्त कोष साख निर्माण के लिए उपलब्ध होंगे। प्रो० कोक्स ने प्राथमिक जमाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस दर तक कोई बैंक ऋण देकर बिना कठिनाई के भाग मुद्रा का निर्माण कर सकता है वह दर जमाकर्ताओं से नकदी के रूप में प्राप्त प्राथमिक जमाओं की दर पर निर्भर होती है।¹ बैंक के पास नकदी की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है जैसे देन में कुछ नकद मुद्रा की मात्रा कितनी है लोगों में वैश्व आदत कौसी है तथा व्याज की दर कितनी है आदि-आदि।

(2) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति साख मुद्रा के निर्माण की सीमा देश के केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर भी निर्भर करती है। देश के अर्थ सदस्य बैंको को केन्द्रीय बैंक की नीति तथा आदेशों को मानना पड़ता है। केन्द्रीय बैंक देश में साख नियंत्रण कई तरीकों से कर सकता है जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएँ, आनय जमा, सरत कोषानुपात, साजिश भाँग समझौते मुद्राओं की कायवाही तथा प्रत्यक्ष कायवाही आदि आदि। वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक विभिन्न देशों में साख नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की वैश्व व्यवस्था केन्द्रीय बैंक नियंत्रण एवं मांग निर्देश पर काम करती है।

(3) नकद कोष अनुपात—जैसा कि हम जानते हैं कि साख निर्माण नकद कोषानुपात की मात्रा पर निर्भर करता है। नकद कोष जितने अधिक रहने का चलन होगा उतना अतिरिक्त कोष की मात्रा कम रहेगी और इसका माध्यम नियंत्रण भी कम होगा इसका विपरीत स्थिति में साख निर्माण अधिक होगा। नकद कोष अनुपात कई बातों पर निर्भर करेगा जैसे देश में वैश्व वस्तुन जैसे हैं लोगों की वंशों में जमा तथा निश्चयों की भावनाएँ तथा आवश्यकता के समय बैंको की आपसी गेन देने की व्यवस्था कौसी है आदि-आदि।

(4) अर्थ सदस्य बैंको का व्यवहार—व्यक्तिगत बैंक की साख निर्माण शक्ति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अव्यवस्था में अर्थ बैंक किस सीमा तक साख निर्माण कर रही है। यदि कोई बैंक अर्थ बैंक की परवाह नहीं करे अर्थ बैंक की तुलना में अर्थ साख निर्माण कर रही है तो शीघ्र ही उक्त बैंक की समस्याएँ बढ़ा समाप्त हो जाएंगी और बैंक दिवालिया हो जाएगी क्योंकि बैंक के नाणियों द्वारा अर्थ व्यक्तियों को दिए गए बैंक अर्थ बैंक को प्राप्त होंगे और इस कारण बैंक विशेष रूप से उन सभी बैंको का वैश्व प्रणाली की अर्थ सदस्य बैंको को नकदी देकर भुगतान करना पड़गा। इस विपरीत यदि

बैंक विशेष अन्य साथी बैंक की तुलना में कम मात्रा में साख मुद्रा का निर्माण करती है तो शीघ्र ही उसे इस बात का अनुभव हो जाएगा कि उसकी पालतू नबंदी में वृद्धि हो रहा है। जिस प्रणियाँ या व्याज पर उधार देकर बैंक को साख प्राप्त करता चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रा. हामर विचार उल्लेखनायक है कि 'यदि एक व्यक्तिगत बैंक सामान्य सार-विस्तार की दर से साथ अपने को नहीं रख पाता तो यह बैंक नबंदी अधिक प्राप्त करेगी और इससे पास इस प्रकार अतिरिक्त बाधा का संचय होगा जिसका कि यह प्रणियाँ रूप में देने की तैयारी होना। यदि एक व्यक्तिगत बैंक अन्य बैंक की तुलना में अधिक पैसा विस्तार या विनियोग की नीति अपनाता है तो इसकी नबंदी कम होगी और यह आवश्यक तोषा का रखने की शक्ति नहीं रख सकता और इससे प्रणियाँ तथा निवर्णों को कम करना होगा।'¹

(5) वैयक्तिक आदतें तथा वैयक्तिक प्रणाली मात्रा की वैयक्तिक आदतों तथा वैयक्तिक प्रणाली की नीति मात्रा साधा सम्बन्ध साख मुद्रा की मात्रा में होता है और साख की मात्रा में निर्धारण में यह तथ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि 'रोम शोध' या निपटारा नबंदी द्वारा करना पसंद करते और साख मुद्रा अपना बैंक द्वारा मुद्रागत नहीं करता तो बैंक ने निगुण साख विस्तार करना सम्भव नहीं होगा। 'रोम' या वैयक्तिक आदतें तभी कारगर होती हैं जहाँ देश में वैयक्तिक प्रणाली का विस्तार मंद है। स्थिर रूप में हो।

(6) रखी जाने वाली जमानत की प्रकृति बैंक की प्रणियाँ करने की शक्ति को प्रभावित करती है। बैंक जो भी प्रणियाँ करता है उगार शीघ्र जमानत के रूप में सम्पत्ति जैसे बिला अक्षा तथा स्टॉक आदि (bills shares and stocks) को अपने पास रखता है। इसी आधार पर प्रा. ब्राउणर का कहना है कि 'बैंक मुद्रा का सृजन नहीं करते यह तो अन्य प्रकार की सम्पत्ति को मुद्रा में परिवर्तित करते हैं।' जब बैंक साख का सृजन करता है तो वास्तव में यह अंतराल जमानतों के धारकों का संपत्ति प्रदान करता है। बैंक की साख निर्माण शक्ति उधार देने वालों द्वारा से जाना जाता परिसम्पत्तियाँ तथा जमानतों के धारकों के प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि जमानत के रूप में अनुमोदित प्रकृतिभूतियाँ नहीं होती हैं तो बैंक द्वारा साख सृजित करने में जोरिम अधिक होगा।

साख सृजन सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Theory of Credit Creation)

कुछ अर्थशास्त्रियों की गयी धारणा है कि बैंक साख या मुद्रा का सृजन नहीं करता। इन अर्थशास्त्रियों में प्रमुख रूप से डॉ० वॉल्टर लीक तथा डॉ० एडविन बर्नर का नाम आता है। इन सिद्धान्तों का कहना है कि यह शोचनीय दृष्टिपूर्ण है कि साख सृजन का पारम्परिक दृष्टिकोण है जबकि वास्तविकता यह है कि साख सृजन का प्रारम्भ जमानतों से।

- 1 If an individual bank fails to keep up with the general rate of credit expansion it will receive more cash than it loses and it will therefore, accumulate excess reserves which it will tend to loan out. If an individual bank expands loans or investments more rapidly than other banks it will lose cash, may not be able to fulfil the reserve requirements and will tend to reduce its loans or investments. —G N Halin

- 2 'The bank does not create money out of thin air, it transmutes other forms of wealth into money. —G Crowther

द्वारा होता है जिनके धन को बैंक ऋण पर उठाते हैं। बैंक उस राशि में अधिक राशि उधार नहीं दे सकते जितनी कि जमाकर्ताओं ने जमा की हुई है। डॉ० वाल्टर लीफ एन व्यावहारिक बैंकर थे और वे कहते थे कि जब बैंक किसी जमा का निर्माण करता है तो वह जमा धनराशि बैंक से कुछ समय बाद निकाल ली जाती है इस प्रकार बैंक जमा धनराशि से अधिक उधार नहीं दे सकता। वास्तविकता यह है कि बैंक साख विस्तारण नहीं कर सकते।

डॉ० एडविन केनन (Dr Edwin Cannan) ने अपनी *An Economist's Protest* में बैंकिंग प्रणाली की तुलना रेलवे स्टेशन में सामान रखने वाले स्थान (Cloak Room) से की है। वे कहते हैं माना कि एक रात्रिकेवल में 100 सदस्य नियमित रूप से आते हैं और एक छाता लाते हैं। जैसे कि वनबूट काउन्टर पर जमा कर देते हैं। काउन्टर क्लर्क अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि एक घण्टे में दस सदस्य ही छातों की मांग करते हैं और 90 छातों को वह रात्रि भर के लिए बिराए पर उठा देता है और इससे उसे कुछ मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसका यह अर्थ नहीं माना चाहिए कि काउन्टर पर बैठ व्यक्ति ने 90 छातों का निर्माण कर दिया है? ऐसा कदापि नहीं हुआ है। इसी प्रकार बैंक भी यह जानते हुए कि सभी जमाकर्ता एक साथ अपनी जमा धनराशि को नहीं निकालते हैं इस जमा राशि का कुछ भाग उधार पर उठा देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बैंक ने साख का निर्माण कर दिया है। सामान घर का बपरासी उन छातों से अधिक छातों उधार पर नहीं दे सकता जितने कि उसने पाम जमा कराये गए थे और एक वापसवाह बैंकर भी अपने पास की धनराशि तथा दूसरे गोषा की धनराशि से अधिक नहीं उधार दे सकता है।¹ इस प्रकार साख निर्माण सही तरीके से उस प्रणाली की व्याख्या नहीं है जिसके द्वारा बैंक मुद्रा की उत्पत्ति होती है।

प्रो० क्राउथर व प्रो० केनन ने उपर्युक्त तर्कों के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दो प्रकार के उत्तर दिए हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बात एक बैंकर की दृष्टि से सही हो सकती है परन्तु यह उस समय सत्य नहीं होती जब कि हम इसे सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली के सदस्य में देखें। जब एक बैंक साख का निर्माण करती है तो यह साख दूसरे बैंक में जाता है तो यह बैंक ऋणों को देकर मुद्रा निर्माण का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित मुद्रा का एक भाग प्रथम बैंक के पास वापस आ जाएगा जो कि इस प्रकार अपना कुछ नकदी को वापस प्राप्त कर लेगा। परन्तु यदि इसके अतिरिक्त कोष मौलिक रूप से बैंकिंग प्रणाली से कहीं बाहर से आये ह तो इसे दूसरे बैंक के नकद कोष का विस्तार करना चाहिए और जब तक बैंकिंग प्रणाली में नई जमा के गुणक रूप में कहीं इसका निर्माण नहीं होता तो इन बैंकों की नकद जमा अनुपात अत्यंत रूप से इनका सामान्य सक्षमता से अधिक होगा। घटती हुई जमा तथा नकदी वापसी का क्रम उस समय तक चलना चाहिए जब तक कि अतिरिक्त गुणक धनराशि का निर्माण नहीं हो जाता।

प्रो० क्राउथर कहते हैं कि इसका व्यावहारिक पक्ष यह है कि बैंक जमा का आकार हम सभी समय में आया जबकि इनकी तुलना हम चरम में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष से करें। उन्होंने उदाहरण के रूप में नवम्बर 1934 में ग्रैंट ब्रिटेन के

1 The most abandoned cloak room attendant cannot lend out more umbrellas than have been entrusted to him and the most reckless banker cannot lend out more money than he has of his own plus what he has of other peoples

व्यापारिक बैंक की शुद्ध जमा पूंजी की चर्चा की जो उस समय 6500 मिलियन पौंड थी। जबकि चरन में मुद्रा राशि उस समय 16477 मिलियन पौंड तथा बैंकों के सकल बोधों की राशि 237 मिलियन पौंड थी। इस प्रकार यदि बैंक ने साख्य निर्माण नहीं किया तो फिर यह 4615 मिलियन पौंड की अतिरिक्त धनराशि यदि साख्य निर्माण से प्राप्त नहीं हुई तो यह वहाँ से आई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक कई गुना अनुपात में साख्य निर्माण करते हैं।

परीक्षा-प्रश्न

1. व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
(Discuss the main functions of the Commercial Banks)
2. बैंक आधुनिक व्यापार एवं उद्योग की आधारशिला है। व्याख्या कीजिए।
(Bank is the foundation stone of modern Commerce and Industry Explain)
[संकेत—बैंक का महत्व बैंक तथा आर्थिक विकास, बैंक व्यापार तथा उद्योग का लिए आवश्यक होता है तथा औद्योगिक विकास में बैंक की भूमिका कीजिए। अतः से बताइए कि विगत दशक में व्यापार एवं उद्योग बिना बैंक की सहायता से चल पाने में सक्षम है। अतः यह कहिए कि उपर्युक्त बयान सत्य ही प्रतीत होता है।]
3. एक व्यापारिक बैंक द्वारा साख्य-निर्माण कार्य की व्याख्या कीजिए।
(Discuss the credit creation function of a Commercial Bank)
4. साख्य निर्माण में क्या आशय है? व्यापारिक बैंक की साख्य निर्माण शक्ति की सीमाएँ क्या हैं?
(What is Credit creation? What are the limitations on Bank's Power of Credit creation?)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत चयन है—

- (i) आर्थिक विकास तथा बैंक एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर है।
- (ii) व्यापारिक बैंक साख्य-निर्माता होता है।
- (iii) बैंक की साख्य निर्माण शक्ति प्रसीमित होती है।
- (iv) व्यापारिक बैंक दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं।
- (v) व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) गलत है। (iii) सत्य है। (iv) सत्य है। (v) गलत है।

A central bank: a bank that the government sets up to handle its transactions in co-ordinate and control the commercial banks and most important to help and control the nation's money and credit conditions

— Samuelson

अध्याय 18

केन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य

(CENTRAL BANK AND ITS FUNCTIONS)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

केन्द्रीय बैंकिंग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से पश्चिमी बणिज्य प्रणाली के विकास में काफी सहायता मिली है। विश्व का सबसे पुराना केन्द्रीय बैंक स्थापित या रिज़र्व बैंक था जिसकी स्थापना सन् 1656 में निजी पूंजी द्वारा की गई थी। ठीक 12 वर्ष बाद अर्थात् सन् 1668 में इसकी समस्त पूंजी केन्द्रीय नियंत्रण में आ गई। इसे प्रारम्भ में नोट निगमन का अधिकार मिला। सन् 1897 में कानूनी रूप से इसे नोट निर्गमित करने का अधिकार मिल गया था। समय की दृष्टि से हम स्वीडन के रिज़र्व बैंक को सबसे पहला केन्द्रीय बैंक मानते हैं परन्तु एक आदर्श केन्द्रीय बैंक के रूप में वह ऑफ इंग्लैंड ने सबसे पहले राय दिया जिसकी स्थापना सन् 1694 में हुई थी। इसे केन्द्रीय बैंक की माता (Mother of the Central Banks) कहा जाता है। ऐसा कहने का मुख्य कारण यह है कि यह ऑफ इंग्लैंड विश्व के अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का मार्ग दर्शक रहा है और उसी को पर्याप्त एवं परम्पराओं की नींव डाली। उनका दुनिया के अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों ने पालन किया। सन् 1826 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को देश के अन्य भागों में अपनी शाखाएँ खोलने का अधिकार प्राप्त हो गया। सन् 1833 में इसने द्वारा निर्गमित नोटों को कानूनी मुद्रा (Legal Tender Money) घोषित कर दिया गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड का साथ साथ वहाँ समुक्त पूंजी बैंकों का भी नोट निगमन का अधिकार मिला हुआ था यदि वे सदन के चारों ओर 6 मील दूर से बाहर बसे हों। नोट निगमन का अधिकार एकाधिकार एवं सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उसका बढ़ाते हुए वर्षों में उसे वहाँ एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया। उसी के द्वारा वर्षों में प्रभावित होकर इंग्लैंड के अन्य समुक्त पूंजी बैंकों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपने साथ ही जाने से सफलतापूर्वक किया जिससे प्रभावित होकर विश्व के अन्य भागों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गयी।

सन् 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड 1817 में बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया तथा बैंक ऑफ नॉर्वे 1818 में नेशनल रीजर्व बैंक 1850 में नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम 1856 में बैंक ऑफ स्पेन 1860 में बैंक ऑफ एशिया में 1875 में रिजर्व बैंक ऑफ जर्मनी 1882 में बैंक ऑफ जापान आदि ने केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य प्रारम्भ कर दिया।

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा (Definition of a Central Bank)

केन्द्रीय बैंक को एक सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। केन्द्रीय बैंक की प्रथि-
वाश परिभाषाएँ केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर आधारित हैं। समय-समय पर केन्द्रीय बैंक के
कार्यों तथा उससे अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है इसी को ध्यान में रखकर विभिन्न
विद्वानों ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषाएँ दी हैं। प्रो० किश तथा एल्किन ने केन्द्रीय बैंक की
परिभाषा देते हुए कहा है कि 'केन्द्रीय बैंक वह बैंक होती है जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा
मान की स्थिरता को बनाए रखना होता है।'¹

प्रो० थोरा स्मिथ के अनुसार 'केन्द्रीय बैंकिंग का अभिप्राय उस बैंकिंग प्रणाली से
है जिसके अन्तर्गत किसी एक बैंक का नोट जारी करना का पूर्ण एवं अवशिष्ट अधिकार
प्राप्त होता है।'² प्रो० आर० पी० कैंडल ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी
है 'केन्द्रीय बैंक वह संस्था होती है जिसका कर्तव्य जनता के सामान्य कल्याण के हित में
मुद्रा की मात्रा का विस्तार एवं संकुचन करना होता है।'³ प्रो० आर० जी० हार्ट के अनु-
सार, 'केन्द्रीय बैंक, बैंकों की बैंक होती है तथा इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि बैंक
के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करती है।'⁴ प्रो० शॉ के अनुसार 'केन्द्रीय बैंक वह
बैंक होती है जो देश में माध्यम पर नियंत्रण रखती है।'

नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सेम्युलसन के शब्दों में 'केन्द्रीय बैंक एक ऐसा
बैंक है जिसे देश की सरकार अपने समन्वय के काम करने व्यापारिक बैंकों या नियंत्रित
करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं माध्यम व्यवस्था के नियंत्रण में महयोग देने के लिए
स्थापित की जाती है।'⁵

प्रो० डी० कॉक (Prof M H De Kock) के मतानुसार 'केन्द्रीय बैंक उस बैंक
को कहते हैं जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली का शिखर होती है तथा जो सम्पूर्ण
देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। केन्द्रीय बैंक का जनता से
प्रत्यक्ष रूप में संबंध इस प्रकार के सम्बन्ध रहने चाहिए जो इसकी मौद्रिक तथा बैंकिंग
नीति की सफलता के लिए आवश्यक हो। इसकी जनता से जमाबंदी के रूप में नकदी को
स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा न ही जनता को प्रत्यक्ष रूप में ऋण इत्यादि प्रदान करने
चाहिए। यह सब कार्य केन्द्रीय बैंक को देश की व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली के द्वारा
सम्पन्न करना चाहिए।'⁶

- 1 "A central bank is that bank the essential duty of which is the maintenance of stability of the monetary standard"

—Kisch & Elkin

- 2 'The primary definition of central banking is a banking system in which a single bank has either a complete or residuary monopoly of note issue'

—Peira Smith

- 3 The central bank is an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare"

—R P Lutt

- 4 R G Howtrey

- 5 'A Central bank is a bank that the government sets up to handle its transactions to co-ordinate and control the commercial bank and most important to, help and control the nation's money and credit conditions'

—P. A Samuelson

- 6 M H De Kock :

केन्द्रीय बैंक की उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन कर। से हमें केन्द्रीय बैंक के स्वभाव एवं स्वरूप के बारे में जानकारी हो जाती है। अधिकांश अध्यात्मों केन्द्रीय बैंक द्वारा सम्पादित कार्यों को आधार मानकर केन्द्रीय बैंक की परिभाषा करते हैं। निम्न रूप में हम कह सकते हैं कि 'केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का स्रोत होता है। इसका देश के सभी व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण होता है यह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। नोटों व प्रचलन का एक मात्र स्रोत हुए देश को मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार साख मुद्रा का नियमन एवं नियंत्रण करती है।'

केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of a Central Bank)

प्रो० डी० फाक के अनुसार केन्द्रीय बैंक के कार्य निम्न निम्न हैं—

- (1) नोट निगमन का एकाधिकार
- (2) सरकारी बैंकर एवं तथा सहायक
- (3) सदस्य बैंकों की नकदी धनराशि का सरक्षण
- (4) राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का सरक्षण
- (5) अन्तिम ऋणदाता
- (6) सदस्य बैंकों का समाशोधन गृह
- (7) व्यापारिक तथा मौद्रिक नीति की आवश्यकता अनुसार साख मुद्रा का नियंत्रण

करना।

प्रो० डी० फाक ने केन्द्रीय बैंक के कार्यों को 7 भागों में प्रस्तुत की थी उसी के आधार पर बाद में केन्द्रीय बैंक के कार्य बताए जाते हैं। इन कार्यों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है—

(i) नोट निगमन का एकाधिकार (Monopoly of Note Issue)—केन्द्रीय बैंक की स्थापना से ही। यदि न देशों में पत्र मुद्रा अथवा नोटों को निगमित करने का एक मात्र अधिकार (monopoly) उस देश के केन्द्रीय बैंक को मिला हुआ है। प्रो० डी० फाक (Prof De Lock) कहते हैं कि केन्द्रीय बैंक के नोट निगमन का अधिकार के कारण केन्द्रीय बैंकों को 20 वीं शताब्दी में नोट निगमन बैंक (Bank of Note Issue) कहा जाता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा निगमन का कोई नाम तथा विशेषताएं हैं।

(ii) एकरूपता—जब केन्द्रीय बैंक नोट छापता है तो उनमें एकरूपता का गुण पाया जाता है। जिससे धोरा धंधी को सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।

(iii) जनता का विश्वास—जब केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंक होता है और नोट निगमन वह किसी न किसी विद्या में एवं देश की आवश्यकता पड़े पर ही इसे छापता है इसलिए जनता का विश्वास नोट निगमन में निहित रहता है।

(iv) साख निर्माण पर नियंत्रण—जब केन्द्रीय बैंक मुद्रा नियमन का एकाधिकार अधिकारी होता है तो साख मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण करने का काम स्या ही होना होता है। नोट मुद्रा में वृद्धि या कमी स्वयं सरकार द्वारा मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण करता है और साख मुद्रा का आधार स्वयं का मुद्रा होता है।

(v) मुद्रा के मातृत्व एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता—केन्द्रीय बैंक मुद्रा का मात्र रक्षक बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाए रखती है। यदि मुद्रा निगमन का कार्य व्यापारिक बैंक का होता तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखना सम्भव नहीं था।

(vi) स्थिति सापेक्षता—केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट निगमन का एकाधिकार से देश का मुद्रा प्रणाली स्थिति में सापेक्षता का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि

कन्द्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा में दश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करता है।

(vi) सरकार को लाभ प्राप्त होता है जो उसका सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

2. सरकारी बैंकर एजेंट एवं सलाहकार (Government's Banker Agent and Advisor) — कन्द्रीय बैंक का दूसरा मुख्य कार्य यह है कि यह सरकार के लिए बैंकर का कार्य करता है। अभिवृत्ति तथा बैंक के रूप में कन्द्रीय बैंक सरकार की वृद्धि का संरक्षण करता है तथा विभिन्न सरकारों के बीच संपर्क का कर्ता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार का अन्वेषणीय तथा भी देती है। यह सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों में सरकार का सलाह देती है। कन्द्रीय बैंक सरकार का आर्थिक विनिर्माण मुद्राओं का प्रत्यक्ष भी कर्ता है तथा सरकार के द्वारा बैंक का माध्यम से हो जाता है तथा भी कर्ता है। स्मरण रहे कि यह सभी कार्यों में कन्द्रीय बैंक सरकार का विनिर्माण प्रदान करता है।

3. बैंक का बैंक (Bankers Bank) — वर्तमान समय में कन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह बैंक में अन्य बैंकों का बैंक बैंकर का कार्य करता है। कन्द्रीय बैंक का अन्य बैंकों का साथ यही सम्बन्ध होता है जो अन्य बैंकों का अपना प्राधान्य का साथ होता है। यह उनकी मदद का संरक्षण करती है तथा बैंक प्रदान करती है तथा समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर उनकी वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में सहायता देता है तथा कन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के बीच समाशोधन गृह (Clearing House) का कार्य भी करती है जिसमें नवद मुद्रा का उपयोग में बहुत होता है। व्यापारिक तथा अन्य बैंकों को अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत न्यूनतम बैंक आरक्षण अनुपात के रूप में कन्द्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है जिसका कारण नवदों का कन्द्रीयकरण हो जाता है इससे यह लाभ होता है कि दश की मात्रा मुद्रा प्रणाली काचदार हो जाती है तथा साग मुद्रा नियंत्रण की समस्या भी हल हो जाती है। इससे अतिरिक्त नवद आरक्षण कन्द्रीय बैंक के पास हो जाना से किसी भी दश की सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली शक्तिशाली बन जाती है तथा नवद आरक्षण का संरक्षण में इष्टतम उपयोग किया जा सकता है।

4. राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का संरक्षक (Custodian of the Nations Reserve of Foreign Currency) वर्तमान समय में कन्द्रीय बैंक राष्ट्र की सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा के संचय का संरक्षण करती है। यह कन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि दश की मुद्रा द्वारा देश की मूल्य की स्थिर रखना कन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिए कन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं का आरक्षण संचित करती है। उदाहरणार्थ यदि किसी देश की मुद्रा का मूल्य घटने लगता है तो बैंक उस देश की मुद्रा का खरीद लेता है। फलस्वरूप उस देश की मुद्रा की कीमत स्थिर आता है। इसी प्रकार यदि किसी देश की मुद्रा की कीमत स्थिर आती है तो उस देश की मुद्रा प्रारम्भ कर देती है फलस्वरूप कीमत बढ़ने लगती है। इस प्रकार कन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की कीमतों में स्थायित्व बनाय रखता है।

5. सदस्य बैंकों का समाशोधन गृह (Clearing House of Member Banks) — वर्तमान समय में सम्मिलित बैंकों को समाशोधन गृह अथवा निवास गृह (Clearing house) की सुविधा प्रदान करना भी कन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य बन चुका है। यह कार्य बैंक द्वारा 1854 में सम्पन्न किया गया था। कुछ समय परचात अन्य कन्द्रीय बैंक भी इस कार्य का करने लग गयीं। शा (Shaw) विलिस (Willis) तथा जांसी (Jauncey) के विचारों से सदस्य बैंकों के मध्य समाशोधन गृह द्वारा सदस्य बैंकों के बीच परस्पर व्यवसाय सम्बन्धी मुक्ताना को सम्भव बनाना कन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। इस कन्द्रीय बैंक के पास समस्त सम्मिलित बैंकों के खाते होते हैं। कन्द्रीय बैंक के इस

कार्य के द्वारा प्रत्येक बैंक को अन्य बैंकों के साथ अलग-अलग जन देन को मजदूरी के द्वारा नियंत्रित की समस्या समाप्त हो जाती है और इस प्रकार देश की समुचित बैंकिंग प्रणाली को काफी सुनिश्चित होती है ।

6 अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort)—वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक अथवा बैंकों को साठवाया में वित्तीय सहायता प्रदान करके अन्तिम ऋणदाता का कार्य भी करती है । जब किसी बैंक को सफट का सामना करना पड़ जाता है तब केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में उस बैंक को ऋण देकर दिवालिपिया होने से बचाती है । इस प्रकार से अन्तिम ऋणदाता के रूप में केन्द्रीय बैंक सफटकास में देश की सम्पत्ति बैंकों की सहायक बनकर उनसे विश्वास उत्पन्न करती है । बेंजहार्ट (Benjamin) ने 1873 ई. में प्रकाशित अपनी Lombard Street शीषक नामक पुस्तक में केन्द्रीय बैंक का इस कार्य के सहित का वर्णन किया था तथा बैंक आफ इंग्लैंड का ध्यान सफटकास में देश में अन्य बैंकों को ऋण देकर इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आकर्षित किया था । बेंजहार्ट की पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात् बैंक आफ इंग्लैंड ने अन्तिम ऋणदाता का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था । वर्तमान समय में प्रत्येक केन्द्रीय बैंक इस कार्य को करती है भारत में 1960 ई० में पालाई सेंट्रल बैंक के दिवालिपिया हो जाने पर देश का आर्थिक व्यापारिक बैंकों से जब जमाकर्ताओं ने भारी मात्रा में अपनी जमाओं को वापस लेना आरम्भ कर दिया था तब व्यापारिक बैंकों को जमाकर्ताओं को भूतकान करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अन्तिम ऋणदाता के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की थी ।

7 साख नियन्त्रण (Controller of Credit)—केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा पर नियन्त्रण करने अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाये रखना । इस कार्य का महत्व वर्तमान समय में इतना अधिक हो गया है कि साख मुद्रा नियन्त्रण के कार्य को ठीक प्रकार से सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय बैंक को देश की समुचित बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने के लिए शक्ति तथा अधिकार दिए जाते हैं । साख मुद्रा नियन्त्रण के कोमल स्तर में स्थिरता विदेशी विनियमन द्वारा स्थापित बनाया जा सकता है । व्यापार तथा को नियंत्रित करने देश की स्वयं निधियां को बचाने तथा उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं । अतएव साख नियन्त्रण अति आवश्यक है और यह केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य बन चुका है ।

साख नियन्त्रण (Credit Control)

साख नियन्त्रण की आवश्यकता (Need for Credit Control)

साख मुद्रा की हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है । हमारा वर्तमान सम्पूर्ण वित्तीय ढांचा साख मुद्रा प्रणाली पर आधारित है इसलिए साख हमारी अर्थव्यवस्था का अद्वितीय अंग बन गई है । इस हम अपनी वर्तमान व्यापारिक अवस्था का जीता रक्त नहीं तो अतिस्थिति नहीं होगी । साख एक ऐसा अद्वितीय एवं नाजुक अंग है कि इसका दुरुपयोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एवं अभिजात भी मिट हो सकता है इसलिए साख मुद्रा को नियंत्रित एवं नियमित करने की आवश्यकता होती है । प्रो० डी० फॉर्क साख मुद्रा की आवश्यकता बताते हुए कहते हैं कि 'बहुत वर्षों से सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि साख का संचयन तथा वितरण बहुत से देशों में नियंत्रित जटिल आर्थिक समझन की दृष्टि से किसी प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए । इसका मुख्य कारण यह था कि साख सभी प्रकार के मौद्रिक तथा अवसाधिक निपटारों में एक मुख्य

भूमिका निभाती है और इस प्रकार यह अच्छाई या बुराई का एक शक्तिशाली तत्व के रूप में प्रतिनिधित्व करता है।¹

बैंदीय बैंक द्वारा नियंत्रण का प्रकार में करता है—

(I) साख नियन्त्रण की परिमाणात्मक विधियाँ

(II) साख नियन्त्रण की गुणात्मक विधियाँ।

साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियाँ का अर्थ उन साधनों में है जो बैंक द्वारा साख का प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। इसमें विपरीत साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ का अर्थ उन साधनों में है जिनसे द्वारा बैंक का साख प्रकार से बिना संशय बोधा का प्रभावित किए हुए नियन्त्रण किया जाता है। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ द्वारा दण्ड का आवश्यकतानुसार साख वितरण आयाग एवं दिशा का निर्धारित किया जाता है।

अब हम साख नियंत्रण का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अर्थात् परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियों का पृथक् पृथक् अध्ययन करेंगे—

I परिमाणात्मक विधियाँ (Quantitative Methods)

- (1) बैंक दर अथवा कटौती दर (Bank Rate or Discount Rate)
- (2) खुल बाजार का क्रियाएँ (Open Market Operations)
- (3) न्यूनतम बैंड आरक्षित अनुपात (Minimum Legal Reserve Ratio)
- (4) तरलता का अनुपात (Liquidity Ratio)

II गुणात्मक विधियाँ (Qualitative Methods)

- (1) साख मुद्रा की रसनिग (Rationing of Credit)
- (2) प्रत्यक्ष बाध्यकारी (Direct Action)
- (3) नैतिक अनुपय या समझाना (Moral Suasion)
- (4) चयनात्मक साख नियंत्रण (Selective Credit Controls)
- (5) विज्ञापन द्वारा प्रसार (Publicity)।

I परिमाणात्मक विधियाँ

(1) बैंक दर अथवा कटौती दर (Bank Rate or Discount Rate)—सन् 1939 में इसका प्रयोग किया यह साख बैंदीय बैंक के अन्तिम प्रणाली का साख का कारण है। बैंक दर बाजार की वह दर है जिस पर राष्ट्रीय बैंक मदस्य बैंक को प्रथम श्रेणी तथा उत्तम ऋणपत्रों का बट्टा करता अथवा इनका गृहायक आह्वान करके उधार ऋण प्रदान करता है। प्रो० पीटर फॉक्स ने अनुमान कटौती दर नीति यह है जिससे अंतर्गत बैंक अपने द्वारा चयन की हुई अन्यत्र गति सम्पत्ति की पुन संयोजन का प्रयोजन प्रतिष्ठापित में सक्षम बनता है। अर्थात् सुरक्षित प्रणाली होता है।

For many years it has been almost universally accepted that the creation and distribution of credit under the intricate economic organisation existing in most of the countries should be subjected to some form of control. The main reason was that credit comes to play a predominant part in the settlement of monetary and business transactions of all kinds and thus represent a powerful force for good or evil'

—De Roock Central Banking

('Discount Policy may conveniently be defined as the varying of the terms, and of the conditions in the broadest sense under which the market may have temporary access to Central Bank Credit through discounts of selected short term assets or through secured advances)

वाणिज्य बैंक व्याज का जिस दर पर व्यापारियों का ऋण देती है उस दर में तथा बैंक दर में इस विषय प्रचार का सम्बन्ध है कि जब बैंक की दर में वृद्धि हो जाती है तो वाणिज्य बैंक भी अपना व्याज की दर में समान अथवा अधिक वृद्धि कर देती है। इसके विपरीत बैंक दर में कमी होने पर वाणिज्य बैंक भी अपनी व्याज की दर में कम कर देता है। बैंक दर में परिवर्तनों के द्वारा केन्द्रीय बैंक अव्यवस्था में सात मुद्रा को मात्रा पर नियन्त्रण रखती है। यदि केन्द्रीय बैंक को यह ज्ञात होता है कि देश में स्फीति उत्पन्न हो गई है तो केन्द्रीय बैंक अव्यवस्था में स्फीति को समाप्त करने के उद्देश्य से बैंक दर में उपयुक्त वृद्धि कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि वाणिज्य बैंक भी अपनी व्याज की दर में वृद्धि कर देते हैं। जब वाणिज्य बैंक व्यापारियों से अपने ऋणों पर पहले की तुलना में अधिक व्याज लेने लगते हैं तो वस्तुओं की उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि व्याज की दर उत्पादन लागत का भाग है। वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहते हुए उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर व्यापारी बैंकों से उधार लेना कम कर देते हैं। परिणामस्वरूप अव्यवस्था में समस्त निवेश की मात्रा कम हो जाती है। निवेश की राशि में कमी हो जाने से उत्पादन साधनों की माँग में कमी हो जाने के कारण वे बेरोजगार हो जाते हैं और उनकी आयें कम हो जाती हैं। उत्पादन साधनों की माँग में कमी हो जाने के कारण कुल उपभोग में कमी हो जाती है क्योंकि उपभोग व्यय आय द्वारा निश्चित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में कमी हो जाती है तथा इनकी कीमतों में भी कमी हो जाती है।

इसके विपरीत देश में अवस्फीति तथा बेरोजगारी उत्पन्न हो जाने पर केन्द्रीय बैंक द्वारा दर में कमी कर दी जाती है। बैंक दर में कमी हो जाने पर वाणिज्य बैंक भी अपनी उधार दान दरों में कमी कर देती है। इससे उद्यमकर्ताओं को पहले से अधिक निवेश करने का उत्साह प्रदान होता है। अधिक निवेश होने पर अव्यवस्था में उत्पादन साधनों को अधिक रोजगार प्राप्त होने लगता है जिससे कारण उनकी आयों में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग माँग में वृद्धि हो जाती है माँग में वृद्धि हो जाने के कारण कीमतों में गिरावट समाप्त हो जाती है। अव्यवस्था में बैंक दर में होने वाले परिवर्तन आर्थिक स्थिति के सूचक का कार्य करते हैं। बैंक दर में वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चेतावनी देती है परन्तु बैंक दर में कमी इस बात की सूचित करती है कि देश की अव्यवस्था अभिवृद्धि से दूर है तथा देश में अधिक निवेश किया जा सकता है।

बैंक दर में प्रभाव—बैंक दर में परिवर्तन के दो प्रभाव होते हैं—(1) आन्तरिक प्रभाव (2) बाह्य प्रभाव।

(1) आन्तरिक प्रभाव—इसका आशय उन प्रभावों से है जिनका दश में अन्दर अनुभव किया जाता है जैसे—

(1) साख की मात्रा पर प्रभाव—जब केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर बढ़ा देता है तो इससे बाजार की व्याज दर बढ़ जाती है तथा यह होने लगता है तथा उनकी माँग में गिरावट आती है तथा साख संकुचन होता है। इसके विपरीत बैंक दर घटने से बाजार की व्याज दर भी घटती है। इसका प्रभाव से ऋण लेना सस्ता हो जाता है ऋणों का माँग बढ़ता है और साख का विस्तार होता है।

(11) आन्तरिक मूल्य स्तर तथा मजदूरी पर प्रभाव—बैंक दर में वृद्धि के कारण ऋण महंगे हो जाते हैं जिससे व्यापार तथा उद्योग गिरता जाता है। राजगार का स्तर गिरता है। नाण्य की शक्ति में गिरावट आता है और वस्तुओं की माँग गिरती है। पत्र-स्वरूप उनका मूल्य में भी कमी आता है। नाण्य वस्तुओं की माँग सचय हेतु नहीं बरत, इस कारण वस्तुओं की माँग में और भी गिरावट आता है। बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि माँग में कमी से उत्पादन का स्तर गिरता है। उत्पादन इवाइयाँ उत्पादन बन्द करने लगता है। लागू की आय गिरता है। इससे विपरीत अर्थात् बैंक दर में कमी के कारण इससे वस्तुओं की विपरीत परिणाम होता है।

(12) बाह्य प्रभाव—इनका सम्बन्ध देश का बाह्य अर्थव्यवस्था में होता है।

(1) विदेशी-विनिमय दर पर प्रभाव—जब विदेशी देश का आन्तरिक बैंक अपनी बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो विदेशी पूँजी का आयात कम हो जाता है। देश में निर्यात में वृद्धि होता है। आयात घट जाते हैं क्योंकि अन्तराष्ट्रीय की क्रयशक्ति में गिरावट आती है। इन सबका प्रभाव यह होता है कि देश का मुद्रा का विदेशी विनिमय दर अनुभूत हो जाता है। मुद्रास्तर में सन्तुलन तथा व्यापार सन्तुलन भी अनुभूत होने का प्रवृत्ति दिखाता है। इससे विपरीत बैंक दर में गिरावट होने से वस्तुओं की विपरीत परिणाम होता है।

(2) विदेशी पूँजी आयातगमन पर प्रभाव—बैंक दर में परिवर्तन से विदेशी पूँजी का आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। जब बैंक दर घटता है तो विदेशी पूँजी विनिमय दर में कमी आती है। पूँजी लगाकर देश में वृद्धि बैंक दर का लाभ होता है। बैंक दर घटने से देश की पूँजी एवं विदेशी पूँजी का आयात में कमी आती है।

दर में परिवर्तन निम्न कारणों से किया जाता है

बैंक दर में वृद्धि निम्न कारणों से की जाती है

- (1) देश का बाह्य पूँजी प्रवाह रोकने के लिए।
- (2) विदेशी विनिमय दर की प्रातिकूलता का रोकने हेतु।
- (3) देश का बाह्य स्वर्ण प्रवाह को रोकने हेतु।
- (4) देश में बढ़ती हुई मुद्रा प्रवृत्ति पर अनुश्रुति हेतु।
- (5) मुद्रा गजार में मुद्रा प्रवृत्ति का अतिक्रमण से मूल्य स्तर वृद्धि रोकने हेतु।

बैंक दर में कमी निम्न कारणों से की जाती है—

- (1) देश में विनिमय दर में वृद्धि के लिए।

(2) पूँजी की माँग में गिरावट होना पर उभर वृद्धि के लिए जिससे कि बैंक का कोष स्वयं में भर पड़े।

- (3) विदेशी पूँजी का अन्धाधुन्ध आयात का स्थिति पर रोक पाने के लिए।

(1) बैंक दर नीति की सीमाएँ (Limitations of the Bank Rate Policy)

मात्रा मुद्रा का मात्रा पर नियन्त्रण करने केन्द्राव बैंक का बैंक दर नीति सीमित रूप में ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का धनायक बन सकती है। बैंक दर का सीमाएँ कई बातों पर निर्भर होती है।

(1) केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक का सम्बन्ध—यह देश की बात पर निर्भर होता है कि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक का सम्बन्ध किस प्रकार का परस्पर सम्बन्ध है। यदि यह सम्बन्ध अति निकट तथा गहरा है तो व्यापारिक बैंक बैंक दर में परिवर्तन का अनुसार अपना व्यापार का दर में उपयुक्त परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक की नीति का समर्थन करने में सहयोग देगा। इससे विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में दूर का सम्बन्ध है और व्यापारिक बैंक केन्द्राव बैंक से विनिमय मात्रा में आधार नहीं

लेती है तो केन्द्रीय बैंक की बैंक दर नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं होगी। अतिरिक्त देश में जहाँ केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों का गूँथी तथा कण्ठदाता के रूप में विशेष सम्बन्ध नहीं होता है बैंक दर नीति को अपने उद्देश्य में विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। जब दर नीति की सफलता के लिए देश में केन्द्रीय बैंक तथा बाणिज्य बैंकों में मध्य गहरा सम्बन्ध एवं सम्बन्ध होना आवश्यक है।

(2) निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति—बैंक दर नीति को सफलता निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति पर भी निर्भर होती है। स्थिति में जब कीमतों में प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है व्यापारी भविष्य के सम्बन्ध में आशावादी होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्रीय बैंक कीमत स्तर को स्थिर रखने के उद्देश्य से अपनी बैंक दर में वृद्धि करती है और देश में बाणिज्य बैंक भी केन्द्रीय बैंक के साथ अपनी व्याज की दर में वृद्धि करके सहयोग देता है तो भी केन्द्रीय बैंक को अपने उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं मिलेगी। व्याज की दर में वृद्धि होने पर भी यदि देश में निवेशकर्ता भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की आशा करते हैं तो वे बैंकों से अधिक धन प्राप्त करने के लिए ऊँची व्याज की दर पर धन लेकर भी उनको लाभ प्राप्त होने की आशा होती है। इसका एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। यदि भविष्य में निवेशकर्ता यह आशा करते हैं कि कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी तो व्याज की दर में यदि 19 प्रतिशत की वृद्धि भी हो जाती है तो भी वे बैंकों से धन लेने के लिये नहीं रुकेंगे। भविष्य में बाजार में मांग मुद्रा की मांग पूर्णतया व्याज निरपेक्ष हो जाती है और बैंक दर में वृद्धि होने का प्रभाव कुल उत्पादन लागत पर बहुत कम पड़ता है क्योंकि व्याज का उत्पादन लागत का एक बहुत कम भाग होता है। इससे अतिरिक्त बहुत से व्ययसामानों में पूँजी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है और इस कारण ऐसे व्ययसामानों पर व्याज की दर में परिवर्तनों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि दीर्घकाल में बैंक दर का निवेश पर अपेक्ष प्रभाव पड़ता है परन्तु अल्पकाल में यह प्रभाव अतिरिक्त तथा कम होता है और जीवन में अल्पकाल का महत्व दीर्घकाल की तुलना में अधिक होता है।

मर्दी में बैंक दर का मध्य अभिवृद्धि (boom) का भाग की तुलना में अधिक असफल सिद्ध होता है। मर्दी काल में जब निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति निराशावादी तथा धारण कर लेती है तथा भविष्य में वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर विरोध होने की आशा होने के लिये भविष्य अनिश्चित हो जाता है तब बैंक दर में कटौती भी आसानी से नहीं की जाये निवेशकर्ता कम व्याज की दर पर भी बैंकों से धन प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं चाहते हैं। यदि निवेशकर्ता यह अनुमान लगाता है कि भविष्य में 10 प्रतिशत का कमोत्तम तो 9 प्रतिशत गूँथालेख व्याज की दर (जो सम्भव नहीं है क्योंकि बाणिज्य बैंकों का उद्देश्य धन लेकर लाभ प्राप्त करना है) पर धन लेकर भी उनका हानि होगी। मर्दी में बैंक दर नीति की शीघ्रता की कठिनाई में एक सुन्दर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। अर्थ-स्थिति में निवेशकर्ता वगैरह की तुलना छोड़े तो तथा बैंक दर प्राप्त होने वाली धन लागत की तुलना पानी से करते हुए कठिनाई में निर्यात है कि केन्द्रीय बैंक छोड़—निवेशकर्ता समझें—तो सामानों की कीमतें के लिए पानी (धन) रस भरता है परन्तु वह पाइ को पानी पीने पर बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि पाइ को प्यास नहीं है तो अधिक पानी सामानों होते हुए भी वह पानी नहीं पियेगा। मर्दी में मर्दा पड़े की प्यास बिल्कुल समाप्त हो जाती है और यदि उसको मुँह भी पानी मिलता है तो भी वह नहीं पीता है।

(2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

खुले बाजार की क्रियाएँ केन्द्रीय बैंक की सात मुद्रा नियन्त्रण की दूसरी प्रमुख रीति है। इस रीति का प्रयोग केन्द्रीय बैंक बहुधा बैंक दर के पूरक के रूप में करती है। इस

रोति के अन्तर्गत वन्द्रीय रीति मुद्रा बाजार में स्वीकृति तथा उत्तम ऋण तथा तथा प्रतिभूतिया का प्रयोजन करके अर्थव्यवस्था के संचालन में मुद्रा की मात्रा में उपयुक्त रमी अथवा वृद्धि करके साख-मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखती है। स्थिति—अभिवृद्धि—में वन्द्रीय बैंक ऋणपत्रों का कम कीमत पर बेचकर अर्थव्यवस्था में सख-मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करके स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्था में जब प्रतीक ऋणपत्रों का खरोदने है तो वाणिज्य बैंक व पास नकदी कम हो जाती है और उनके अपनी साख-मुद्रा निर्माण का मात्रा में वृद्धि करने पड़ती है। ऐसा व नए ऋणपत्रों को ऋण न करके तथा पुराने ऋणपत्रों से अपने ऋणों का भुगतान करके करती है। साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का कारण निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत स्तर भी कम हो जाता है।

इसके विपरीत मन्दी में वन्द्रीय बैंक प्रतिभूतिया तथा ऋणपत्रों को अधिक कीमत पर खरीद कर अर्थव्यवस्था में संचालन में वृद्धि करके मन्दी को समाप्त करने की चपटा करती है। नकदी बढ़ जाने पर वाणिज्य बैंकों की नकदी में वृद्धि हो जाती है और वे अधिक नकदी का आधार पर अधिक साख-मुद्रा का निर्माण करती है। जिसका कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था को मन्दी से मुक्ति मिलती है।

खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए आवश्यक बातें—(1) बाजार में दृष्टिगत का प्रयोजन साख-मुद्रा नियन्त्रण का अप्रत्यक्ष रीति है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वाणिज्य बैंक अपने नकदी आपूर्ति में वृद्धि करती है अथवा नहीं। खुले बाजार में दृष्टिगत की खरीद तथा बेचने की रीति इस मामला पर आधारित है कि साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा वृद्धि की नकदी में वृद्धि तथा वृद्धि पर निर्भर होता है। परन्तु ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं है। अभिवृद्धि में बैंक व पास कम नकदी होते हुए भी साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे विपरीत मन्दी में यद्यपि वाणिज्य बैंक की कुल नकदी में वृद्धि हो जाती है परन्तु फिर भी वे अधिक साख-मुद्रा का निर्माण नहीं करती हैं।

(2) वन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वन्द्रीय बैंक व पास उपयुक्त ऋणपत्रों की कितनी मात्रा है और कितनी मात्रा में वह ऋणपत्रों को मन्दी व वास्तव में अधिक मूल्य पर खरीदने का तैयार है। यदि वन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का उद्देश्य रखे तो वह निश्चय ही तैयार हो जाती है तो भी यह सम्भव है कि इसका अपने इस उद्देश्य में सफलता में प्राप्त हो। यह सम्भव है कि स्थिति व समय वन्द्रीय बैंक के पास बेचने योग्य ऋणपत्रों की मात्रा इतनी कम हो कि सार ऋणपत्रों को बेचकर भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त न हो सके। वन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की सीमाओं की व्याख्या करते हुए बॉन्स ने लिखा है कि वन्द्रीय बैंक अभिवृद्धि या गिरावट के लिए केवल उतनी ही बारूद का प्रयोग कर सकते हैं जितनी कि उनके यदी स तदन व समय प्राप्त हुई है और बारूद की यह मात्रा अभिवृद्धि पर काबू पाने के लिए अपर्याप्त हो सकती है।

(3) खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दण्ड का मुद्रा बाजार में दृष्टिगत एवं विकसित हो। यदि ऐसा नहीं होता तो वन्द्रीय बैंक व लिए प्रतिभूतिया व प्रयोजन द्वारा वांछित परिणाम मिलने की आशा नहीं होगी।

(4) खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यापारिक बैंकों प्रतिभूतियों में धन विनियोजित करने के लिए एक प्रकार से आदी हो गई हो।

(5) न शीघ्र बैंक का बाह्य नि अनुमोदित या सरकारी प्रतिभूतियां जितना कि न्य वित्त मंत्री शीघ्र बैंक करता है उनका मूल्य म शीघ्र परिवर्तन न होने द यदि मूल्य म शीघ्र परिवर्तन हुआ तो विनियामकता इनका पूजा विनियोजन स कतरायेगी और नियाएँ सफन दशा हा सत्ता ।

खुले बाजार की क्रियाओं को लोकप्रियता क कारण

प्राधान्य समय म साधन निय प्रण न उपाय क रूप म खुल बाजार का प्रियाजा को सीमांतप्रता निम्ननिष्ठित कारणता म अधिब हा गई है—

(1) खुल बाजार का प्रियाएँ तुरन्त बैंका क नकद काया को बाह्यत दिशा म त जान म सहायक होती है ।

(2) यह विधि प्रथम विषय युद्ध क बाद साधन नियन्त्रण क लिए अधिक उपयोगा निष्ठ हुई है ।

(3) मुद्रा बाजार म सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां क न्य विषय का बचत बढता जा रहा है इसलिए वन्दोबस्त बैंक को खुले बाजार की प्रियाएँ सपादित करन म काफी सुविधा मिली है ।

(4) बैंक दर नीति क बाह्यत परिणाम न निम्नन तथा इसकी सीमाभा एवं अन्य शोधा म सयदनशासता को दसते हुए खुल बाजार की प्रियाएँ बैंक दर नीति क बढे विवरण क रूप म साबित हुई है ।

यह दर नीति तथा खुल बाजार की क्रियाओं म अन्तर भयवा दोनों मे कौन अछे है ?

साधन नियन्त्रण की परिमाणात्मक अथवा प्रत्यक्ष रीतियां म बैंक दर एवं खुल बाजार का प्रियाएँ दाना ही महत्वपूर्ण है परन्तु बैंक दर नीति की अपेक्षा खुल बाजार का प्रियाएँ अधिक अछे है । यह बात दाना म निम्ननिष्ठित अन्तर द्वारा स्पष्ट हो जाती है

(1) नकद कोषा पर प्रभाव—बैंक दर नीति की अपेक्षा खुल बाजार की प्रियाएँ व्यापारिक बैंक क नकद काया को तुरन्त एवं प्रत्यक्ष रूप म प्रभावित करती है । जब केन्द्रीय बैंक खुल बाजार की प्रियाजा द्वारा प्रतिभूतियां खरीदता है तो व्यापारिक बैंक द्रा प्रतिभूतियां को बचते है तो तुरन्त ही इन बैंका को नकद काया प्रभावित अर्थात् बढ पाता है । यदि वन्दोबस्त बैंक प्रतिभूतियां को मुद्रा बाजार म बचता है तो बैंका क नकद कोष तुरन्त ही कम हा जाते है । बैंक दर नीति इतना आघात म प्रत्यक्ष रूप म बैंका क नकद कोष का प्रभावित नहा करती ।

(2) बारम्बारता—बैंक दर म बार बार परिवर्तन करना सम्भव नही हाता । कदाकि बैंक दर नीति द्वारा स्पष्टता बैंका क नकद काया ही प्रभावित नहा हात दरन् दिशा बैंका एवं पूजा क आवागमन पर भी प्रभाव पढता है । इसका साथ व्यापारिक बैंका क कोषा म होने वाल परिवर्तना का पूर्वानुमान लगाना कठिन हाता है इसका विपरीत खुल बाजार की प्रियाजा को किन्तु ही बार केन्द्रीय बैंक अपना सक्ता है और निम्नित तथा बाह्यत दिशा म साधन परिवर्तन करना सम्भव हो सक्ता है ।

(3) ऐच्छिक—खुल बाजार की प्रियाएँ ऐच्छिक होती है अर्थात् यह व्यापारिक बैंका पर अनुचित दबाव नहा खाता । व्याज क दर म परिवर्तन द्वारा व्यापारिक बैंक साधन वसानी की दृष्टि म प्रतिभूतियां का न्य विषय करत है । इसका विपरीत बैंक दर नीति म जब परिवर्तन होते है तो पूजन प्रदान करने वाले बैंक एवं सम्साभा का अपनी व्याज दर म इसी परिवर्तनानुसार परिवर्तन जान क लिए बाध्य होना पढता है ।

वैयर्थ्यासीन दरों पर प्रभाव—वैयर्थ्य नीति व्याज की अल्पवासीन दरों को प्रभावित करती है। क्योंकि व्यापारिक बैंक आपवासीन ऋण प्रदान करते हैं। इससे विपरीत खुले व्यापार की प्रियाया में सरकारों प्रतिभूतियाँ दीघवासीन समय के लिए भी बेची जाती हैं इसलिए इनके द्वारा व्याज की दीघवासीन दरें तथा मांग नीति की भी प्रभावित किया जा सकता है।

सार नियन्त्रण की दोनों रीतियाँ एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे की पूरक व रूप में ही समायोजनीय होनी चाहिए। आवश्यकता की आवश्यकतानुसार ही दोनों का समय समय पर प्रयोग वांछित होगा। यदि आवश्यकता ही तो दोनों को एक साथ भी उपयोग में लाना चाहिए। दोनों विधियाँ में कौन सी भी विधि श्रेष्ठ है इसका उत्तर इन के लिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैयर्थ्य नीति की अपेक्षा खुले बाजार की प्रियाएँ अधिक श्रेष्ठ एवं उत्तम हैं।

(3) न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात अथवा परिवर्तनशील तरल कोषानुपात (Minimum Legal Reserve Ratio or Variable Reserve Ratio)

अवश्यकस्था में वाणिज्य बैंक के लिए निर्धारित न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात में जो प्रत्येक बैंक को केंद्राध्यक्ष बैंक के पास अपनी कुल जमाआ का निर्धारित प्रतिशत दर पर आरक्षण के रूप में रखना पड़ता है उपर्युक्त परिवर्तन करने की केंद्राध्यक्ष बैंक अवश्यकस्था में बैंक की मांग मुद्रा निर्माण प्रियाया पर नियन्त्रण कर सकती है। प्रत्येक देश में जहाँ केंद्राध्यक्ष बैंक होती है वाणिज्य बैंक की अपना कुल जमाआ का विधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत भाग केंद्राध्यक्ष बैंक के पास न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात के रूप में जमा रखना पड़ता है। इस अनुपात में परिवर्तन करके केंद्राध्यक्ष बैंक वाणिज्य बैंक के पास नकदी की मात्रा में वृद्धि अथवा घटा करके अवश्यकस्था के संचालन में कुछ सार मुद्रा की मात्रा में घटा अथवा वृद्धि कर सकता है।

अमेरिका में इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम अगस्त 1906 ई० में न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात में 50 प्रतिशत की वृद्धि के रूप में अत्यधिक मांग-मुद्रा निर्माण की हानियों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से किया था। इस अनुपात में वृद्धि ही जाने पर सदस्य बैंक की नकदी 3,100 मिलियन डॉलर गति से घट कर 1,800 मिलियन डॉलर रह गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 1937 ई० में इस अनुपात में पुनः वृद्धि की गई थी। यह कुछ वर्षों में न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात रीति का प्रयोग 1951 ई० में कोरिया युद्ध (Korean War) के कारण उत्पन्न स्थिति को गैराने के उद्देश्य से किया गया था।

सांग-मुद्रा नियन्त्रण की अन्य रीतियाँ के समान इस रीति की भी सीमाएँ हैं। प्रथम जब वाणिज्य बैंक के पास अधिक नकदी होता है तो वह केंद्राध्यक्ष बैंक की न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात रीति का अनदेख कर सकता है। दूसरे वाणिज्य बैंक अपना जमाआ के ढाँचे में लपटू या खन करके केंद्राध्यक्ष बैंक की रीति का उत्प्रेषण कर सकता है। उदाहरणार्थ यदि चाँू तथा मियादी जमाआ पर केंद्राध्यक्ष बैंक के पास इन जमाआ का 2 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत भाग न्यूनतम वैध निधि के रूप में जमा करना पड़ता है तो गुमा रिक्ति के वाणिज्य बैंक अपना मांग में मियादी जमाआ में घटा तथा चाँू जमाआ में वृद्धि दिलाने पर केंद्राध्यक्ष बैंक की कम नकदी भोजन में सफल हो सकता है।

मांग की मात्रा मांगे का पूर्ण पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि उसका मांग पर भी निर्भर करता है। व्यापारिक बैंक की मांग सृजन की क्षमता में परिवर्तन द्वारा

वांछित उद्देश्या की पूर्ति सफलता में केन्द्रीय बैंक को उम समय नहीं मिलेगी यदि माँग में परिवर्तन उम दिशा में नहीं होता जिसमें केन्द्रीय बैंक चाहता है। उदाहरणार्थ मन्दी के समय प्रारम्भित निर्धि अनुपात में कमी होना पर भी साग में विस्तार नहीं होना पाता।

जन्दी उद्देश्य निर्धि माँग में परिवर्तन करना उचित नहीं होता। इसको यत्नमाँ मन्दी को पूर्ति देने का-का प्रयाग में नहीं जाना चाहिए। यह एक प्रकार से गैर-नचाना (Inflexible) अरु होता है। प्रा० डी० काँ इस सम्बन्ध में कहते हैं जबकि यह बैंक नरुद माँग उपनरुद पूर्ति तथा वांछित परिवर्तन का बहुत चुम्न एक प्रभावशा की तरफा है इसकी कुछ तकनाग तथा मनावेज्जानिक भीमाएँ हैं जो बताते हैं कि इसका मोच ममम-कर और क्चडानुमाँ करन अमाधारण परिस्थितिया में ही प्रयाग करना चाहिए।¹

आलोचनाएँ—(1) निर्भिन्न बैंका र माग निर्भिन्न प्रकार की वृत्तिरुक्त निर्धियाँ होती हैं इनमें विमो प्रकार के परिवर्तन का प्रयाग निर्भिन्न बैंका पर एक सा नहीं पड़ता। कुछ बैंका पर इसका प्रभाव बहुत गहरा तथा कुछ पर बहुत अधिर होता पड़ता है। इस पर एक आशय यह मा उगाया जाता है कि गैर बैंकिग वितीय मध्यमा जैम बासा कम्पनिया विबाय बैंक जावाम समितिया आदि पर जो कि व्यापारिक बैंका की प्रतिमर्धों होती हैं कोड प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) निर्धि माँगों में परिवर्तन कुछ व्यापारिक बैंका र विण अनिश्चितता लाना है। कभी कभी इनमें म्रिय कथ परिवर्तना का प्रभाव बहुत ही कम्पूण होता है इसनिए दूध बडे मोच-मममकर अपनाता चाहिए। मिस कहते हैं कि निर्धि माँग में परिवर्तन कोना लाना में महा जोड पश्य के बाद म्रिय जाना चाहिए।

(3) यह माग की गमत् में वृद्धि करता है। चूँकि केन्द्राय बैंक व्यापारिक बैंका द्वारा न्यूनतम बैंध आरक्षित निर्धि पर कोई व्याज नहीं देता इसनिए व्यापारिक बैंक न्यूनतम निर्धि की माँग बढ़ने से अपन व्याज की म्रतिपूर्ति अपने कणिया से अधिक व्याज की कसूकी द्वारा करते हैं।

(4) इसका आलोचना इस आधार पर भी की जाता है कि इसका प्रतिमृत्तिया के बाजार पर प्रतिरून प्रभाव पड़ता है। जब केन्द्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंका को न्यूनतम बैंध आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो व्यापारिक बैंक की नरुदी का एक भाग केन्द्रीय बैंक को हस्तातरुखि होन लगता है और ब अपन पाम रगी हुई प्रतिमृत्तिया (Securities) को बचन लगत है। इस प्रकार के प्रभाव का रोजन के निए अर्ति प्रतिमृत्तिया के मूल्या में मिराकट न आन देने के निए यह सुझाव दिया जाता है कि केन्द्रीय बैंक का लूने बाजार की म्रियाजा द्वारा प्रतिमृत्तिया का श्रय कर लना चाहिए जिससे कि इसकी मुद्रा बाजार में म्रति म्रिवि न बढ़न पाए और उनरी कीमते स्थिर रहे।

न्यूनतम बैंध आरक्षित अनुपात की उपरुबत सीमाजा तथा आनचनआ के माँ मा साम नियन्त्रण एक उपयोगी एवं शक्तिमान अरु है। प्रा० सथस कहते हैं कि

1 While it is a very prompt and effective method of bringing about the desired changes in the available supply of bank cash, it has some technical and psychological limitations which prescribe that it should be used with moderation and discretion and only under obviously abnormal conditions."

यह सब ऐसा अस्त्र है जिसको केन्द्रीय बैंक 'हाथ' में रहना चाहिए।
केन्द्रीय बैंक को सभी शक्ति देना राष्ट्रीय बैंक उपयोगी तरीके में बना कर सचता है।
जिसका वि व्यापारिक बैंकों से करने की आशा नहीं की जा सकती है।¹

(4) तरल कोषानुपात (Liquidity Ratio)

(4) तरल कोषानुपात (Liquidity Ratio)
 देश व व्यापारिक बैंक को अपनी कुल पूँजा का एक भाग तरल रूप में रखना पड़ता है। इस तरल मुद्रा का एक भाग नकद राशि और एक भाग अनुमानित प्रतिभूतियाँ रूप में रखना पड़ता है। इस प्रकार एक निश्चित मामा व अन्तर तरल मुद्रा पद तथा प्रतिभूतियाँ के रूप में रखा जाता है। जब देश का कुल बाजार का विश्वास व गण्यता मित्त का एक कारण बनता है कि देश का अपने माधना का एक अंग अविश्व रूप में सरकारी प्रतिभूतियाँ में रखा जाता है। एक प्रकार द्वारा यह बात नियंत्रण करता है।

व अत्रान परिसम्पत्तिया (Assets) का नुक़्सा म न बढन पाएँ और उापी माग़ सुान म धिस्तान की क्षमता म य़ुडि न हो पाए ।

म विस्तार की क्षमता में घटने से ही पार्श्व
मुद्रा स्थातिक स्थितियाँ घर काबू पाने के लिए सागर नियंत्रण का यह तराज
महत्वपूर्ण होता है। कुछ स्थितियाँ में इनका उच्च भित्तिवर प्रभाव सरकार की हानाधि
प्रबंधन नाति से सम्बंधित होता है। जब कानून द्वारा कटौत पर व्यापारिक यका का
जपता पूजा का एक भाग सरकारी प्रतिभूतियाँ में उगाता अनिवार्य घर देता है तो सरकार
के लिए हानाधि प्रबंध (Deficit financing) को अपनाता थाता है।
वित्तीय प्रबंधन का यह नीति स्थातिक विरुद्ध होता है क्योंकि जितना धियाय सहायता
सरकार को दाताता है व्यापारिक बच उस राजि को सामान्य व्ययसाय के लिए सागर-नृजन
में नहीं पाता। यह आयिक विपान तथा अन्य असाधारण परिस्थितियाँ के कारण व्य
स्थातिक दबाव बढ़ रहा है ता मौद्रिक नाति के सरस्पीति नीति के लिए सागर नियंत्रण
की यह राति नाभवारी हाती है।

॥ गुणात्मक विधियाँ

(1) साख मुद्रा राशिनियम (Credit Rationing or Rationing of Credit)

(1) साख मुद्रा रमनिय (Credit Rationing or Rationing of Credit) :- इसी शक्ति व अन्तर्गत के साथ एक देश में वाणिज्य का विकास आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर साख मुद्रा निर्माण की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है तथा विभिन्न व्यवसायों व लिए अल्प्य (quota) निर्धारित कर दिया जाता है। निता मा वक् को उसका निर्धारित अल्प्य से अधिक साख मुद्रा उत्पन्न करता है आना नही होता है। यह शक्ति साख मुद्रा नियंत्रण का बनी प्रभावित शक्ति है परन्तु इस शक्ति में कुछ व्यापक शक्ति शामिल है।

(1) तट्टायक का लक्ष्य गति तथा तृतीय आवश्यकता तथा तत्तु
मध्यम मार्ग मद्रा निर्माण का मान्यता का ग. अमुमान उगाना पत्त ३ जीय दत्त
वटिन वाय है ।

It is a weapon which should always be placed in the hands of a central bank whose technique is circumscribed by the conditions hindering the effective utilisation of open market operations. Given such power the central bank can perform useful functions that commercial banks cannot be expected to perform.

—R S Sayers

(2) केन्द्रीय बैंक को प्रत्येक बैंक के अभ्युक्तों की मात्रा को निर्धारित करना होता है।

(3) इस रीति में व्यापार का विकास साल मुद्रा की मात्रा से सीमित हो जाता है। जर्मनी में रीचम बैंक जो यहाँ की केन्द्रीय बैंक थी ने इस रीति का प्रयोग 1924 ई० 1629 ई० तथा 1931 ई० में किया था।

(4) जर्मनी के अतिरिक्त रूस तथा मेक्सिको आदि देशों में भी इस रीति का प्रयोग उपलब्ध साल मुद्रा का भिन्न व्यवसायों में व्यापक वितरण करा व उद्देश्य से किया गया है। साल मुद्रा तथा पूँजी का राशनिंग तानाशाही दशा में गहन तथा विस्तृत योजनाओं को सफलता के लिए अतिआवश्यक होता है। तानाशाही राज्या में अतिरिक्त अधिकतम दशों में भी साल मुद्रा अभ्युक्तों की राशि को विभिन्न व्यवसायों के लिए निर्धारित करना देश के आर्थिक हितों के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ मेक्सिको में साल मुद्रा राशनिंग की रीति का उस दश में साल मुद्रा पर नियन्त्रण करने के लिए उपयोग किया गया है।

(2) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

प्रत्यक्ष क्रिया का अभिप्राय प्रतिरोधी क्रियाओं से होता है। जब कोई बैंक केन्द्रीय बैंक के आदेशों का पालन नहीं करता है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक के विरुद्ध अनेक प्रकार की सीधा कार्यवाहियाँ — उस बैंक को हुण्डियों को न भुनाना तथा उसको ऋण देने से इन्कार करना इत्यादि करके उस बैंक को अपने आदेश मानने पर बाध्य कर सकती है। प्रवरात्मक साम्य नियन्त्रण (Selective Credit Control) की रीति के द्वारा केन्द्रीय बैंक दश में साल मुद्रा का अच्छे प्रकार से नियन्त्रण कर सकती है। अमरीका में फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) ने 1928 1929 ई० में इसके आदेश का उल्लंघन करने वाली बैंकों को हुण्डिया को भुनान से इन्कार करके प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्रयोग किया था। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 1956 ई० में प्रवरात्मक साल मुद्रा नियन्त्रण की रीति का सफल प्रयोग कर रही है।

केन्द्र नियोजित देशों में केन्द्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों के साल नियन्त्रण का पूरा एवं प्रत्यक्ष अधिकार होता है। साम्य निर्माण संस्थाएँ अर्थात् बैंक केन्द्रीय बैंक द्वारा आदेशों तथा निषेधों के लिए निर्धारित नीति का अनुसरण करते हैं। केन्द्रीय बैंक द्वारा यह तय कर दिया जाता है कि अग्रिमों की राशि उद्देश्य तथा व्यापार की दर क्या होगी केन्द्रीय बैंक स्वयं सरकार के अधीन कार्य करने वाला बैंक होता है। इस सम्बन्ध में इन सरकारी निर्देशों का पालन भी व्यापारिक बैंकों से कराना होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का अधिकार मुद्रा तथा अन्य असाधारण परिस्थितियों में सरकार द्वारा केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाता है।

प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) उन देशों में साल नियन्त्रण की एक अग्रणी विधि मान्यता प्राप्त हो सकती है जहाँ मुद्रा बाजार में बड़ी बड़ी संस्थाएँ हों तथा उनकी

- 1 Rationing of credit and capital is a logical concomitant of the intensive and extensive planning adopted in regimented economies. Not only is this method resorted to in authoritarian economies but as Wagemann rightly claims even in more primitive economic conditions the setting of credit quotas is the only decisive method which the central bank has in order to prevent excessive credit demands on the part of business "

—E Wagemann

शाखाएँ बहुत अधिक मात्रा में पायी जायें। इसमें अतिरिक्त व्यापारिक बैंक के लिए वन्द्रीय बैंक पर काफी बुरा प्रभाव रहना पड़ता है। पुनर्गोती सुविधाओं के लिए व्यापारिक बैंक के वन्द्रीय बैंक के पास जात हो आदि आदि।

प्रत्येक वित्तियोगी रीति में बहुत सी बाधनाएँ पाई जाती हैं। वन्द्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंक का सारा निस्तार करना भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वन्द्रीय बैंक को यह भी मान्य होना चाहिए कि उचित एवं अनुचित में किस भेद किया जाय। साथ ही साथ के उपयोग का दूसरी-तीसरी तथा चौथी पार्टी द्वारा निवृत्तना किया जा रहा है। सभी बातें एक साथ पाई नहीं जाती इसलिए केवल बैंक द्वारा प्रत्येक कामवाही के प्रयोग से सभी-कामों का वांछित परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक कामवाही करते समय वन्द्रीय बैंक का काफी संचालन में काम करना चाहिए।

(3) नैतिक अनुग्रह या समझना (Moral Persuasion)

वन्द्रीय बैंक अव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का सम्बन्ध की रीति के द्वारा सुझाव के रूप में प्राप्त करना एवं अपने माध्यमों द्वारा नियन्त्रण के कार्य में बैंक का सहयोग प्राप्त करता है। देश में स्थिति उत्पन्न हो जाना पर वन्द्रीय बैंक देश में सभी वाणिज्य बैंक का उत्तर प्रश्नों का मात्रा में उपयुक्त काम करने का सुझाव देती है। इसके विपरीत यदि देश में मंदी विद्यमान है तो वन्द्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को उदार उधारदान नाति का अपना कर उभराने का मात्रा में प्रयास कर देती है। वाणिज्य बैंक साधारणतया वन्द्रीय बैंक के सुझावों का पालन करती है। इसलिए काम स्वतन्त्र हानिपूर्ण तथादि देश में जहाँ वाणिज्य बैंक वन्द्रीय बैंक का अपना नती मानती है इस रीति का काफी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें अतिरिक्त भारत आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आदि देशों में भी जहाँ वन्द्रीय बैंक का स्थापित हुए अधिक समय नहीं हुआ है यह रीति काफी सफल सिद्ध हुई है।

भारत में सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इस रीति का प्रयोग 1949 ई० में अपने के अवसूच्य के समय किया था। 1949 ई० में रिजर्व बैंक के सचिव ने वही वाणिज्य बैंक के प्रतिनिधियों का सम्पर्क में एवं अधिवेशन आयोजित किया था जिसमें सचिव ने बैंक से गटटवाजी के लिए प्रश्न करने का सुझाव दिया। वन्द्रीय बैंक का इस सुझाव का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा तथा वाणिज्य बैंक ने गटटवाजी के लिए विज्ञान का अधिक मात्रा में प्रयोग करके रिजर्व बैंक का अपने सहयोग का परिचय दिया। तब से रिजर्व बैंक द्वारा इस रीति का प्रयोग किया जा रहा है तथा वाणिज्य बैंक ने रिजर्व बैंक का इच्छाओं का आदर किया है।

(4) चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control)

चयनात्मक साख नियन्त्रण की विधियाँ वन्द्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक व्यवस्था की वर्तमान नीतियाँ हैं। इन विधियों की विशेषता इसलिए भी और अधिक है क्योंकि इनका उद्देश्य किसी विशेष कार्य के लिए साख की दिशा निर्धारित करना होता है और साथ ही कुछ मात्रा का प्रभावित करना इनका उद्देश्य नहीं होता। सभी-सभी मामलों में प्रयोग करना अव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और साथ ही उपयोग उन कामों में अधिक मात्रा में हो जाता है जिनकी आवश्यकता अव्यवस्था के लिए नहीं होती। साथ ही बहुत उच्च क्षति तथा काफी तक सीमित रहना चाहिए जिनका प्रयोग अव्यवस्था के लिए उपयोग तथा लाभप्रद हो। इसमें लिए बहुत से देशों में वन्द्रीय बैंक चयनात्मक साख नियन्त्रण का अपनाता है जो स्वतन्त्र होता है। साख नियन्त्रण के यह तरीके साख की स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हुए अच्छे परिणाम सामने लाते हैं जबकि

इन्हें सही समय तथा सही दिशा में अपनाया जाय। इनकी उपयोगिता उस समय और भी बढ़ जाती है जबकि सामान्य साक्षर रीतियों के साथ इन्हें अपनाया जाता है।

चयनात्मक साक्षर नियन्त्रण के उद्देश्य (Objectives of Selective Credit Control)

चयनात्मक साक्षर नियन्त्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) बैंक साक्षर के जरूरी तथा और जरूरी उपयोगों के मध्य भेद करना तथा अर्थ-व्यवस्था के और-जरूरी क्षेत्रों के लिए बैंक अधिमो के सम्बन्ध में प्रथम नीति अपनाना।

(2) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्थान पर अर्थव्यवस्था के केवल कुछ क्षेत्रों अथवा बिन्दुओं को प्रभावित करना जिनकी अधिक आवश्यकता महसूस की जाती हो।

(3) बिस्ती अथवा किराये पर खरीद योजनाओं (Installment and Higher Purchase Schemes) के अन्तर्गत खरीदी जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर रोक लगाना। स्फीतिक स्थितियों से निपटने के लिए सामान्यतया बैंक द्वारा आयात किस्ती तथा किराये पर खरीद योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं पर खरीद के लिए साक्षर पर रोक लगाई जाती है।

(4) दश व भुगतान सन्तुलन की स्थिति को प्रभावित करना। इसके अन्तर्गत निर्यात उद्योगों के विनिमय बिलों की पुनर्वटोती सुविधा देना। भुगतान सन्तुलन की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय बैंक आयात हेतु विनिमय बिलों को हतोत्साहित करने के लिए पुनर्वटोती दर (Re-discount rate) उंची कर देता है तथा निर्यात बिलों के लिए यह दर नीची रखता है।

(5) इसका उद्देश्य सभी प्रकार के साक्षर को नियन्त्रित करना होता है इसमें व्यापारिक तथा वित्तीय साक्षर भी शामिल की जा सकती है।

साक्षर-मुद्रा नियन्त्रण की इस रीति का निर्माण सबसे प्रथम अमरीका में राष्ट्रपति के आदेश अनुसार अगस्त 1941 ई. में हुआ था। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उपभोक्ताओं को ऋण देने का आदेश देती है। अमरीका तथा यूरोप के देशों में जहाँ उपभोक्ता बैंकों से ऋण प्राप्त करके वस्तुओं को खरीदते हैं साक्षर-मुद्रा की इस रीति का विशेष महत्व है। इस नीति का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग किया जा सकता है—

(क) विभिन्न कटौती दर— इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के विनिमय बिलों के लिए भिन्न प्रकार की कटौती दरें निर्धारित कर देता है। इसका उद्देश्य कुछ क्षणों में ऋण की उपलब्धता को सरस तथा कुछ क्षेत्रों में कम करना होता है। यदि सरकार कृषि के लिए ऋण सुविधाओं को बढ़ाना चाहती है तो कृषि विनिमय बिलों की कटौती दर कम कर दी जाती है। इससे कृषि कार्यों तथा व्यापार हेतु विनिमय बिल बढ़ेंगे।

(ख) उपभोक्ता बिस्ती साक्षर का नियन्त्रण— इसमें अलग-अलग केन्द्रीय बैंक उपभोक्ता वस्तुओं के खय के लिए दिये जाने वाले ऋण को संश्लेषण अथवा ऋण बन्धन अपनाता है। कभी-कभी उपभोक्ता वस्तुओं को दिये जाने वाले ऋण को सीमा निर्धारित कर दी जाती है अथवा बिस्ती की न्यूनतम धनराशि तथा ऋण अदायगी की सीमा तथा समय निर्धारित कर दिया जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यूरोप के सभी देशों में ऐसी नीति अपनाई गई थी। इस रीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं के वस्तुओं को खरीदने, बिस्तीओं द्वारा उधार पर भाल बेचने तथा बैंकों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर ऋण बन्धन लगाना होता है जिससे कि साक्षर-प्रसार न हो।

(ग) अन्तर निर्धारण—व्यापारिक बैंक जो भी ऋण देते हैं वह किसी न किसी जमानत या सम्पत्ति की धरोहर पर दिय जाते हैं। जमानत की धनराशि का प्रायः ऋण का मूल्य या अन्तर 20 से 50 प्रतिशत रखा जाता है। परन्तु कभी-कभी वन्द्रीय बैंक इस प्रकार निश्चित अन्तरों में हस्तक्षेप करके इस अन्तर निर्धारण को सीमा की बद्ध करता है। उदाहरणार्थ, यदि व्यापारियाँ ने मोदामा में गहूँ अधिक मात्रा में भर दिया है और बाजार में दृष्टिमान कमी कर दी है। मान लीजिए कि बैंक ने गहूँ पर ऋण दान का 25% माजिन रखा है, तो वन्द्रीय बैंक इसकी सीमा 25% में 40% कर देता है तो व्यापारियाँ 15% अतिरिक्त जमानत का रूप में या तो धनराशि या फिर उतने मूल्य का गहूँ रखा पड़ता है। इस प्रकार बाजार में गहूँ की पूर्ति बढ़ा से उतने मूल्य में गिरावट आती है। इस प्रकार वन्द्रीय बैंक अन्य उपभोक्ता अथवा अन्य कमी वाली वस्तुओं का सम्बन्ध में यह रीति अपना सकती है।

(घ) आयात पूर्व जमा वन्द्रीय बैंक आयातों का प्राथमिकता पत्र का माप ही आयात राशि का एक भाग जमा करता है। इस प्रकार इस धनराशि पर मिलने वाली व्याज की हानि होती है। इस रीति का उद्देश्य आयातों का निरन्तराहित करना होता है।

(ङ) नकद खोपों का चयनात्मक प्रयोग—इस निधि का अंतर्गत वन्द्रीय बैंक ने पाप व्यापारिक बैंक अनिवार्य रूप में जो तरह खोपें रखा है उसमें भी पृथक् नाति अर्पाई जाती है वन्द्रीय बैंक कुछ विशेष क्षेत्र में निर्विवाजित धनराशि का अपन पाप नकद जमा का रूप में करता है। इसका आगम निर्भीक रूप विशेष में पूँजी निवेश बढ़ाया जाता है।

(च) ऋणों की जाँच तथा नियन्त्रण वन्द्रीय बैंक एक निश्चित धनराशि से अधिक ऋण दान पर इस प्रकार की पाबन्दी लगा करता है। इस रीति का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में ऋणों का प्रोत्साहित करना तथा कुछ क्षेत्रों में निरन्तराहित करता होता है। प्रथम विश्व-युद्ध के पड़न समय नीदरलैंड तथा आस्ट्रिया वन्द्रीय बैंक इस रीति का प्रयोग हुआ था।

विज्ञापन प्रचार (Publicity)

वर्तमान युग में वन्द्रीय बैंक अपनी माप मुद्रा नियन्त्रण रीति का सफल बनाना का उद्देश्य से विज्ञापन का द्वारा जनता तथा निवेशकर्त्तों का ध्यान अपनी नीति की ओर आकर्षित करती है। उन दशा में जहाँ सामाजिक शिक्षित हात है विज्ञापन प्रकार की रीति वन्द्रीय बैंक की माप-मुद्रा नियन्त्रण रीति का एक मुख्य अंग हो जाती है। इस रीति का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में ऋणों का प्रोत्साहित करता तथा कुछ क्षेत्रों में निरन्तराहित करता होता है। प्रथम विश्व-युद्ध के पड़न समय तथा नीदरलैंड में इस रीति का प्रयोग हुआ था।

सारांश

यद्यपि वन्द्रीय बैंक का अर्थव्यवस्था के संचालन के माप मुद्रा की पूर्ति पर नियन्त्रण करता है तथा अन्तः यन्त्र प्राप्त होता है परन्तु अनुभव बताता है कि यह अधिकार अस्थिरता पर पूर्ण नियन्त्रण करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाती है। वन्द्रीय बैंक की माप-मुद्रा नियन्त्रण नीति की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि स्फीति तथा अवस्फीति अब भी समय-समय पर देश की अर्थव्यवस्था के मनुष्य को भय करती रहती है। वन्द्रीय बैंक का अधिकारों का विस्तार हानि का साथ साथ स्फीति की समस्या पड़न की अपेक्षा अधिक गम्भीर होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्फीति तथा अवस्फीति उत्पन्न होना का अनेक मौद्रिक तथा अमौद्रिक कारण होता है। वन्द्रीय बैंक केवल मौद्रिक कारणों पर अपनी माप मुद्रा नियन्त्रण नीति का द्वारा प्रभाव डाल सकती है। अतः वन्द्रीय बैंक पर विजय पान के लिए यह आवश्यक है कि वन्द्रीय बैंक अपने यन्त्रों का आर-

शुभव अवस्था में ही पूरी शक्ति के साथ प्रयोग करें। परन्तु दुभाग्यवश राजनातिक कारणों से केन्द्रीय बैंक ऐसा करने में असमर्थ रहती है। वास्तव में अभिवृद्धि तथा भन्दी को कभी भी आरम्भिक अवस्था में खोलने का प्रयास नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक निवेशनर्ताओं की मनोवृत्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। यही कारण है कि केन्द्रीय बैंक अपना मौद्रिक तथा मांग मुद्रा नियन्त्रण नीतियों के द्वारा एवं निश्चित सीमा तक ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का बनाय रख सकती है। परन्तु यह होते हुए भी केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक तथा मांग मुद्रा नियन्त्रण नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता स्थापित करने में एवं बड़े अंश तक सरकार की सहायता करने में सक्षम भी सक्षम रहती है।

अधिकांशित अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय बैंक

अधिकांशित अर्थव्यवस्था में जहाँ बैंकिंग प्रणाली का विकास नहीं हुआ होता है जहाँ वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का अभाव तथा मुद्रा बाजार अविनियमित होता है केन्द्रीय बैंक का कार्य अर्थव्यवस्था में केवल मांग मुद्रा का नियन्त्रण करना नहीं है। इसका अधिक महत्वपूर्ण कार्य देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली का संतुलित विकास को सम्भव बनाना अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान देना है। यदि देश में बैंकिंग का विकास नहीं हुआ है तो केन्द्रीय बैंक का वाणिज्य बैंक का भी कार्य करना देश में साधारण बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी उदार नीति तथा सरकार पर अपना उदार प्रभाव डाल कर केन्द्रीय बैंक का देश में वाणिज्य बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

केन्द्रीय बैंक को देश में संगठित मुद्रा बाजार की भी स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए अविनियमित अर्थव्यवस्था में संगठित मुद्रा बाजार का होना अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मुद्रा बाजार के माध्यम द्वारा ही अर्थव्यवस्था में पूँजी उपलब्ध होती है। मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था की औद्योगिक प्रगति का आधार होता है इससे माध्यम द्वारा उद्योग तथा वाणिज्य का वित्तीय सहामता प्राप्त होती है। केन्द्रीय बैंक का अर्थव्यवस्था में संगठित वित्त बाजार का विकसित करने पर विचार करना चाहिए। अर्द्ध विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक की भूमिका इति तथा सभी उद्योगों के विकास के लिए सालों को प्रोत्साहित करना होता चाहिए। देश में सहायता के आधार पर सहकारी तथा भूमि विकास बैंक की स्थापना एवं उससे संगठन में केन्द्रीय बैंक की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक का काम व्याज की दर पर इस बैंक के लिए मध्य-कालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक का देश में पूँजी बाजार की भी विकास एवं संगठित करना चाहिए जिससे देश में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त धन मिल सके। पूँजी बाजार के द्वारा औद्योगिक निगम तथा संस्थाओं के ऋण पत्रों तथा अंशों (Debentures and Shares) का वितरण होता है और उद्योगों के लिए तथा अन्य उत्पादन कार्यों के लिए पूँजी प्राप्त हो जाती है।

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (केन्द्रीय बैंक का रूप में) अर्थव्यवस्था के नियंत्रण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य तथा संतुलित आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रही है। भारत में रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के वैदेशिक विकास की स्थापना सन् 1950 में की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे बन्धों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना है, यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। वृद्धि साक्ष सम्बन्धी नीति निर्माण हेतु रिजर्व बैंक ने वृद्धि साक्ष विभाग की स्थापना की है। आवश्यकता पड़ने पर यह विभाग भारत सरकार, राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं के लिए वृद्धि साक्ष सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करता है। सन् 1947 में

भारत सरकार ने निम्नी निम्नलिखित नियंत्रण एकट पास किया। रिजर्व बैंक के इस विभाग द्वारा समस्त विदेशी विनिमय का प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाता है।

भारत में बिज बाजार को नियंत्रित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी 1952 को बिज बाजार योजना प्रारम्भ की जिसमें अन्तर्गत अनुमोचित बैंकों को मृत्वी प्रतिज्ञा पत्रों (Usance Promissory Notes) के आधार पर मौज ऋण प्राप्त करने का अधिकार दी गई थी। सन् 1970 में नई बिज पुनर्दोती योजना (Bill Re-discounting Scheme 1970) प्रारम्भ की गई। इसमें अन्तर्गत रिजर्व बैंक उस बिजों को पुनर्दोती करता है जिसमें गृहगत हो गया था जो सरकारी विभागों का मात्र का वृत्ति करता है उस पर हात पड़े। 1976 में रिजर्व बैंक ने अपनी माज सङ्घटन नीति (Credit Squeeze Policy) के अन्तर्गत अनुमोचित बैंकों को मूल पर बट्टा 11% (Basic Re-discount Quota) तब तक दिया था। सन् 1978 में रिजर्व बैंक ने नवीन बैंक शाखा स्थापना नीति (New Branch Licensing Policy) की घोषणा की जिसमें मात्र बाता पर मात्र दिया गया था।

- (i) उस बैंक में बैंक को शाखाएं जहाँ जहाँ पहले बैंक नहीं था।
- (ii) समस्त बैंकों का अधिकार बैंक माज प्रदान की जाए।
- (iii) बिजों की निम्न योजनाओं में बैंकों को भागीदारी बढे।

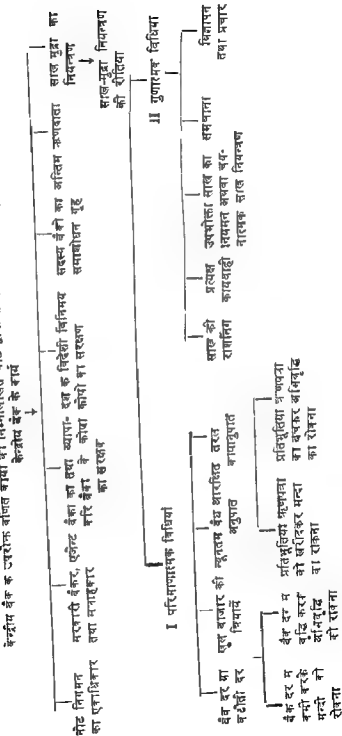
भा नीचे अङ्कित गद्यांश प्रदान है जिसमें हमारा विचार है कि यह गम्भीर नहीं है कि यह बिजों का विकास हो रहा है। रिजर्व बैंक ने बिजों को निम्न माज विभाग में बिजों दिया जिसमें मुख्य रूप से बिजों में गम्भीर समस्याओं का अध्ययन एवं प्रत्यक्ष भाग लेता है। बिजों को निम्न बिजों रिजर्व बैंक ने दो बाता को स्थापना की थी—

(i) राष्ट्रीय बिज माज (दीघकालीन बिजों) कोष [National Agricultural Credit (Long Term) Operation Fund] जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1956 में की गयी।

(ii) राष्ट्रीय बिज माज (स्थानीयकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] जिसकी स्थापना 30 जून 1956 को की गई। बिजों मा (दीघकालीन बिजों) कोष की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकारों को बिजों में उद्देश्य के बिजों प्रदान करना था जैसे—(अ) महसारी बैंकों एवं प्राथमिक बिजों माज समितियों को शर पूँजी में हिस्सा देना (ब) बिजों उद्देश्य के बिजों राज्य महसारी बैंकों को मध्यमकालीन ऋण प्रदान करना (स) अ राष्ट्रीय भूमि बन्दार बैंकों के ऋण पत्रों को सरादना तथा उन्हें दीघकालीन ऋण प्रदान करना। इसी प्रकार राष्ट्रीय बिजों माज (स्थानीयकरण) कोष की स्थापना का उद्देश्य राज्य महसारी बैंकों को मध्यमकालीन प्रत्यक्ष बिजों उद्देश्य के बिजों देना था जैसे (अ) मृदा बाढ आदि प्राकृतिक बिजों बाताओं के समय बिजों में अन्तर्गत बिजों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित करना (ब) बिजों बाताओं के बिजों घोषणा करना।

उपरोक्त बाता कोषों को 12 जुलाई 1982 को नवस्थापित बिजों एवं ग्रामीण बिजों के राष्ट्रीय बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) में बिजों दिया गया है। इसका अन्तर्गत 1963 में स्थापित बिजों पुनर्दोती एवं बिजों माज (Agricultural Refinance and Development Corporation) का भी NABARD में बिजों दिया गया है। NABARD ने बिजों पुनर्दोती एवं बिजों माज नियमों के अन्तर्गत माज प्राप्त कर बिजों है। इतना ही नहीं राजकीय महसारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (State Co-operative Banks and Regional Rural Banks) में गम्भीर बिजों सभी माज NABARD को गोप दिए गए हैं। बिजों माज के क्षेत्र में NABARD राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था के रूप में सामने आई है।

केन्द्रीय बैंक के उपरोक्त वर्णित कार्यों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है—



औद्योगिक वित्त व विकास हेतु गिजवं बैंक ने पृथक् रूप में औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त व्यवस्था में सहायता देना है। इस अतिरिक्त हमने विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगमा (State Financial Corporations) की अण्ड पुँजी में भी भाग लिया है। रिजर्व बैंक इन निगमा का अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इनके अलावा औद्योगिक साग एवं निवेश निगम तथा पुनर्वित्त निगम (Industrial Credit and Investment Corporation and Refinance Corporation) की स्थापना की गई थी। मन् 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India IDBI) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास में सहायता देना है। इस प्रकार भारत में रिजर्व बैंक आर इण्डिया कन्द्रीय बैंक व रूप में सकलतापूर्वक कार्य कर रहा है। देश में मुद्रा बाजार एवं पुँजी बाजार में पर्याप्त विकास व अभाव में रिजर्व बैंक का भागीरतीत मफनता नहीं भित पाई है। आन गल समय में रिजर्व बैंक की निर्णायक एवं और अधिक प्रभावी भूमिका होगी ऐसी आशा हमें करनी चाहिए। रिजर्व बैंक ट्राप तथा औद्योगिक विकास हेतु दिशा निर्देश राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक का देता रहता है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 कन्द्रीय बैंक क्या है? कन्द्रीय बैंक व कार्यो का विवरण कीजिए।
(What is a Central Bank? Discuss the functions of a Central Bank)
- 2 कन्द्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? कन्द्रीय बैंक व रूप में रिजर्व बैंक आर इण्डिया व कार्य बताइए।
(What do you mean by a Central Bank? Give functions of the Reserve Bank of India as a Central Bank)
[संकेत—रिजर्व बैंक भारत का कन्द्रीय बैंक है तथा रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यो में जा यह कन्द्रीय बैंक व रूप में करता है, व्याख्या कीजिए। रिजर्व बैंक व कार्यो का अध्याय 19 में दिये हैं। हमने पहले इसी अध्याय में अर्द्ध-निरुमित अवस्थिति में कन्द्रीय बैंक नामक शीपक का matter भी दिये हैं।]
- 3 "माग नियन्त्रण की दृष्टि से खुल बाजार की प्रियाएँ बैंक दर नीति की पूरक हैं।" विवरण कीजिए।
(From the standpoint of credit control open market operations are complementary to bank rate policy" Discuss)
[संकेत—मागप्रथम बताइए कि बैंक दर नीति तथा खुले बाजार की प्रियाएँ, कन्द्रीय बैंक की परिमाणमात्मक विधि व अन्तर्बन्त महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। दोनों की आवश्यकता मात्र नियन्त्रण व लिए हाती है। दोनों में अन्तर बताइए तथा अन्त में निष्कर्ष दीजिए कि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं प्रति-भ्यर्त्ती नहीं।]
- 4 कन्द्रीय बैंक की परिमाणमात्मक एवं गुणात्मक विधियाँ में अन्तर कीजिए तथा उनका अनुनात्मक महत्व का बताइए।
(Distinguish between quantitative and qualitative methods of credit control and examine their relative importance)

[सकेत—दोनों विधियों की सक्षिप्त व्याख्या कौज़िए अन्त में बताइए कि साख्त नियन्त्रण के लिए कभी-कभी केन्द्रीय बैंक का दोनों प्रकार की विधियों को आंशिक रूप में प्रयोग करना पड़ सकता है।]

5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही तथा कौन गलत है

- (i) जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो साख्त सकुचन होता है।
- (ii) बैंक दर में कमी साख्त विस्तार हेतु की जाती है।
- (iii) खुले बाजार की क्रियाएँ बैंक दर नीति से थोड़ी होती हैं।
- (iv) खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए मुद्रा बाजार विकसित एवं संगठित होना चाहिए।
- (v) कन्द्रीय बैंक आर्थिक अस्थिरता को नियन्त्रित करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है। (ii) सही है। (iii) सही है। (iv) सही है। (v) सही है।

बैंक का मुख्य कार्यालय बम्बई में स्थित है। केन्द्रीय कार्यालय में बैंक के प्रधान शासनिक वा कार्यालय सचिव का कार्यालय वैधानिक विभाग वृषि शाखा विभाग वैश्व विकास विभाग विनिमय नियन्त्रण विभाग तथा अनुसन्धान शास्त्र व सस्या शास्त्र विभाग स्थित है।

दश में केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों का सफलतापूर्वक करन व उद्देश्य ॥ रिजर्व बैंक न दश व विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ स्थापित की हैं। मद्रास कावरा बम्बई तथा मद्रास में स्थानीय प्रधान कार्यालय तथा कापुर बगरी पटना हदरावाद, नागपुर इत्यादि स्थानों पर बैंक न अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं। इसमें अतिरिक्त जयपुर गजपुर तथा अन्य स्थानों पर भी रिजर्व बैंक व सावजनिक श्रृण कार्यालय स्थित है। जिन स्थानों में रिजर्व बैंक का शाखा नही है। वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा रिजर्व बैंक व कार्यों का सम्पादन किया जाता है। बैंक का एक कार्यालय लंदन में भी है जिसका कार्य अभिकर्ता व कार्यों का करन व अतिरिक्त भारत में उच्च आयुक्त (High Commissioner for India) का हिसाब रचना भी है।

रिजर्व बैंक के विभाग

(Departments of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक आप इण्डिया व वर्तमान समय में विभिन्न कार्यों का सम्पादन करन व लिए 20 विभाग हैं जो निम्नलिखित हैं —

(1) छपन या निगमन विभाग (Issue Department)—रिजर्व बैंक का यह प्रमुख विभाग है जिसका मुख्य कार्य नाटा का निगमन करन होता है। नाटा छपन व काय नागिव में स्थिति प्रग में होता है। यह नाटा का दश व विभिन्न सरकारी गजाना में उनकी माँग व अनुसार भजता है। निगमन विभाग की शाखाएँ बम्बई वनर ता गागपुर वानपुर बगरी हैदरावाद पटना तथा नई दिल्ली में स्थित हैं।

(2) बैंकिंग विभाग (Banking Department)—इस विभाग की स्थापना 1 जुलाई 1950 को हुई थी। इस विभाग का प्रमुख कार्य अनुसूचित बैंकों का पुनर्जमा पूँजी का एक निश्चित प्रतिशत अपन पाग जमा करवाना होता है। यह विभाग अनुसूचित बैंकों व लिए गमाशान गृह (Clearing House) का भी कार्य करता है। इसका अनावा सरकार व लिए श्रृण व्यवस्था तथा अन्य प्रकार व नन दन का कार्य भी यह विभाग करता है।

(3) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)—यह विभाग कृषि साख तथा कृषि सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का समाधान व लिए कार्य करता है।

(4) बैंकिंग विकास विभाग (Department of Banking Development)—दश में बैंकिंग सुविधाओं व विकास का कार्य इसी विभाग का सौंपा गया है। प्रामाण्य वचता का प्रास्ताहित करन का दायित्व भी इस विभाग का है।

(5) बैंकिंग विभागा का विभाग (Department of Banking Operations)—इस विभाग का मुख्य कार्य अनुसूचित बैंकों का निरोक्षण एवं परामर्श रना है। नय बैंकों का स्थापन व लिए यह विभाग सडमें दता है तथा पुराने बैंकों की नई शाखाओं का स्थापन की अनुमति भी इसी विभाग में दा जाता है। अनुसूचित बैंक अपनी पूँजी में वृद्धि इस विभाग का पुन अनुमति व नहा कर सकते हैं।

(6) विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department)—विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों की समस्त दस्त रर इस विभाग व गुपुद हाती है। भारत सरकार न 1947 में विनिमय नियन्त्रण एक्ट व अन्तर्गत रिजर्व बैंक का

विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कानून एवं माग निर्देशन के लिए व्यापक अधिकार प्रदान किए थे। विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों का देश की अव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसकी महत्ता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी विभाग की स्थापना की है जिसका काम विनिमय नियन्त्रण के बारे में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना एवं सरकार की ओर से विदेशी विनिमय का प्रयोजन करना होता है।

(7) औद्योगिक वित्त विभाग (Industrial Finance Department)—इस विभाग का मुख्य काम औद्योगिक वित्त सम्बन्धी मामलों में राज्य वित्त विभागों को परामर्श देना तथा छोटे पैमाने और मध्यम स्तरों के उद्योगों का वित्तीय सहायता देना होता है।

(8) कानून विभाग (Legal Department)—इस विभाग में कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो रिजर्व बैंक को विभिन्न क्षेत्रों पर कानूनी सलाह देते हैं। इस विभाग द्वारा समय-समय पर आदेशों एवं विज्ञप्तियों को जारी किया जाता है और उसमें कानूनी पहलू पर भी विचार किया जाता है।

(9) गैर बैंकिंग कम्पनीज विभाग (Non Banking Companies Department) इस विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में हुई और इसका मुख्य कार्यालय कनकपुरा में स्थित है। जैसा कि इसका नाम से ही विदित है यह विभाग गैर बैंकिंग कम्पनीज एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए परामर्शदाता एवं उनके कार्यों पर निगरानी रखता है।

(10) अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Research and Statistics) इस विभाग का मुख्य काम अव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित आंकड़ों का संकलन कर उन्हें प्रकाशित करना होता है। रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रकाशकों में माध्यम से यह विभाग रिजर्व बैंक की मौद्रिक वित्तीय एवं उत्पादन सम्बन्धी नीतियों का प्रचार करना होता है। इससे सरकार को अपनी आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों में निर्माण में काफी सहायता मिलती है।

रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक का प्रमुख काम सरकार का आर्थिक नीति में अनुसार भारतीय मुद्रा प्रणाली का इस प्रकार नियंत्रण करना है कि आर्थिक स्थिरता के साथ देश का अव्यवस्था का गन्तुवर्तित आर्थिक विकास सम्भव हो सके। संक्षेप में बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं —

(1) कागजी मुद्रा का निर्वहन (Issue of Paper Currency)

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को देश में नोट प्रचलन का पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। नोट प्रचलन काय बैंक का नोट प्रचलन विभाग करता है पहले स्वर्ण तथा विदेशी ऋण पत्रों के आरक्षणों व आधार पर नोटों का प्रचलन करता था।

आरम्भ में अधिनियम के अनुसार नोटों का प्रचलन अनुपाती आरक्षित प्रणाली (Proportional Reserve System) के अनुसार किया जाता था। अधिनियम के अनुसार कुल नोट प्रचलन राशि का 40% स्वर्ण धातु स्वर्ण सिक्का तथा विदेशी ऋणपत्रों के रूप में तथा शेष 60% भारत सरकार के रूपमा ऋणपत्रों, सरकारों के रूपमा ऋणपत्रों के रूप में रक्षित कोष में रखना आवश्यक था। नोट प्रचलन की अनुपाती आरक्षित प्रणाली देश में लगभग 20 वर्षों से अधिक समय तक विद्यमान रही।

सन् 1957 में योजना को सफल बनाने के कारण अनुपाती आरक्षित प्रणाली को विद्यमान रखना कठिन हो गया। अनुपाती आरक्षित प्रणाली के अन्तर्गत अधिक मुद्रा का

प्रचालन जो याजना की पूर्ति के लिए आवश्यक था आरक्षणा में स्थण अथवा विदेशी ऋण-पत्रों को बढ़ावा देना सम्भव नहीं था। वास्तव में विदेशी आयातों में वृद्धि होने पर वारण रिजर्व बैंक व विदेशी विनियम आरक्षणा में बन्नी होती जा रहा थी। अतः अक्टूबर 1956 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में पर्याप्त संशोधन करने के उपरान्त अनुपाती आरक्षित प्रणाली को परिष्कार करके न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपना दिया गया। जिसके अनुसार रक्षित बाण में 115 करोड़ रु० की राशि का स्थण तथा 400 करोड़ रुपय की विदेशी प्रतिभूतिया की मात्रा न्यूनतम आरक्षण निर्धारित की गयी। परन्तु दुर्भाग्यवश विदेशी ऋणपत्रों की मात्रा कुछ ही समय पश्चात् 400 करोड़ रुपय की न्यूनतम राशि में भी कम हो गयी। ऐसी चिन्ताजनक स्थिति में रिजर्व बैंक अधिनियम में पुनः संशोधन करना आवश्यक हो गया अतः कुछ समय पश्चात् रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (द्वितीय संशोधन) अधिनियम बना जिसके अनुसार रिजर्व बैंक के प्रचालन विभाग आरक्षित बाणों में स्थण का राशि जोर विदेशी ऋणपत्रों की न्यूनतम राशि 400 करोड़ से घटाकर 200 करोड़ कर दी गया जिसमें 115 करोड़ रुपय का सोना अथवा गौन व सिक्के तथा 85 करोड़ रुपय का विदेशी प्रतिभूतिपूर्ण होना आवश्यक था।

चलन तिजोरियाँ (Currency Chests)

रिजर्व बैंक का चलन तिजोरियाँ से आशय उन तिजोरियाँ से है जो मुद्रा की पूर्ति हेतु हाती है और उनमें नाट हात है। देश भर में ऐसा 3506 चलन तिजोरियाँ हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का शाखाएँ सभी स्थानों पर नहीं हैं इसलिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया उसकी गहायन बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रमुख शाखाओं में इस प्रकार की तिजोरियाँ रहती हैं इन चलन तिजोरियाँ व अनावा 487 स्थानों पर 34 तिजोरियाँ (Sub chests) रहती हैं जो मुद्रा डिपो भी रहती हैं। रिजर्व बैंक शाखाएँ जहाँ नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक रिजर्व बैंक की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जब कभी व्यापारिक बैंक का साख का आवश्यकता होती है तो इसकी पूर्ति के लिए वे उस बैंक से सम्पर्क करते हैं जिसके पास चलन तिजोरी है। रिजर्व बैंक की प्रतिनिधि सम्बंधित व्यापारिक बैंक में इस मांग की जमानत के रूप में अनुमादित प्रतिभूतियाँ तथा विनियम बिना की (Bills of exchange) रखवा लेता है तथा चलन तिजोरा में से मुद्रा निकालकर व्यापारिक बैंक को देता है।

चलन तिजोरियाँ में से कितना धनगणि निगानी गइ है उसका ज्ञासक तथा तिजोरी रखन बांर अथवा रखना पड़ता है। जब बांड बैंक चलन तिजोरा में जा भा पैसा तथा उस रिजर्व बैंक का नाम निम्न दिया जाएगा और धारागणि बाणता त समय भा ऐसी धारागणि रिजर्व बैंक का जमा त रूप में अतिन कर दा जाएगा। जितना धारागणि इस चलन तिजोरी से निगना जाती है उस ही मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। जो भी धनगणि चलन तिजोरा में रहगी वह मुद्रा की पूर्ति नहीं माना जाएगा। सम्बंधित प्रतिनिधि बैंक में चलन तिजोरा का हिमाव रखना है तथा इसका सूचना रिजर्व बैंक कायालय में सप्ताह में एक बार या फिर जैसा भी निर्देश रिजर्व बैंक दे उपाय अनुसार भजता रहता है तथा तिजोरियाँ का हिमाव लगात समय तिजोरियाँ में जमा धनगणि रिजर्व बैंक के वैविध विभाग में जमा गमनी जाती है।

वर्तमान समय में भारत में रिजर्व बैंक द्वारा 2.5, 10, 20, 50, 100, 500 रुपय के नाट निर्धारित किए जाते हैं। जबकि उन 1,000, 5,000 तथा 10,000 रुपय के नाट निगालन का अधिकांश निगना जाता है। वर्ष 1977 में अवलोकन स्थापना से इन धन की गमाप्ति में हुए अभियान चलाया गया था। उस समय यह समझा जात लगा कि बांड धन का अधिवाश राशि 1,000, 5,000 तथा 10,000 रुपय के नाटों में छिपाकर रखी

अतः रिज़र्व बैंक व सामान साम्य नियन्त्रण की एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी। इस समस्या को हल करने के लिए 15 नवम्बर 1951 का बैंक ने बैंक दर में $\frac{1}{2}\%$ (अर्थात् 3 प्रतिशत में वृद्धाकर $3\frac{1}{2}\%$) की वृद्धि की साथ ही रिज़र्व बैंक ने यह भी घोषणा की कि वह इस तिथि से सरकारी प्रतिभूतियाँ की जमानत पर छूट देगा परन्तु उन्हें गरीबदानी नहीं। इस प्रकार रिज़र्व बैंक ने साम्य नियन्त्रण करने में उद्देश्य से बैंक दर में पहली बार वृद्धि की। इस वृद्धि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि मुद्रा बाज़ार में साम्य मुद्रा महंगी हो गई तथा बैंक ने अपनी उधारदान में वृद्धि कर दी। इसी अतिरिक्त बैंक ने व्यापारियों को निमन्त्रण पाया कि वे अग्रिम देने बन्द कर दिये।

16 मई 1957 का रिज़र्व बैंक अपनी बैंक दर $3\frac{1}{2}\%$ से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया और बाद में 2 जनवरी 1963 का इस 4 प्रतिशत से बढ़ाकर $4\frac{1}{2}\%$ प्रतिशत कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय प्रचलित मुद्रा स्फीति का नियन्त्रित एवं नियमित करना था। बदती हुई मुद्रा स्फीति का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए 26 सितम्बर 1964 तथा 17 फरवरी 1965 को बैंक दर बढ़ाकर क्रमशः 5% और 6% कर दी। लेकिन 2 मार्च 1968 का रिज़र्व बैंक ने बैंक दर घटाकर 6% से 5% पर दिया। 8 जनवरी 1971 को पुनः बढ़ाकर 5% से 6% कर दी गयी। 30 मई 1973 का बढ़ाकर 7% कर दी गई तत्पश्चात् 23 जुलाई 1974 का बैंक दर में पुनः वृद्धि कर 9% कर दी गयी। बैंक दर में इस प्रकार वर्षों में जो वृद्धि अथवा कमी की गई उस हमें तालिका द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।

भारत में बैंक दर

परिवर्तन की तिथि	बैंक दर
15 नवम्बर 1951	3.5%
16 मई 1957	4.0%
2 जनवरी 1963	4.5%
26 सितम्बर 1964	5%
17 फरवरी 1965	6%
4 मार्च 1968	5%
8 जनवरी 1971	6%
30 मई 1973	7%
23 जुलाई 1974	9%
11 जुलाई 1981	10%

27 फरवरी 1982 का रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने घोषणा की कि अनुसूचित बैंक द्वारा जमा भण्डारण पर 0.5 प्रतिशत का 1.5 प्रतिशत व्याज की धनराशि। मार्च 1982 में दब गयी।

रिज़र्व बैंक ने बैंक दर को 23-7-74 का 9 प्रतिशत घातित की थी उसका बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने आशा की है कि वर्ष 1981-82 में अन्य तत्काल व्यावसायिक क्षेत्र में मार्ग विभाग की वृद्धि 19 प्रतिशत रहेगी जो देश में उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि लगभग साम्य मध्यम-धीरे-धीरे बैंकालिब मीग का पूरा कर सकेंगी। अब 1981-82 में बैंक औसत मार्ग का 36% (Aggregate Bank Credit) प्राप्तमिवता वाल क्षेत्र को दिया जाएगा जसकि 1979 में इन क्षेत्रों को औसत बैंक मार्ग का 33% ही मिलता था। छोटी परम्परायि योजना व अन्य तत्काल यह बढ़ाकर 40% कर दी जा रिचार था। 1 मार्च 1982 में बैंक ने रिज़र्व बैंक वारिनी वषत गाता पर षोडी भी वृद्धि कर दी है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक ने यह वृद्धि 5% से 1.5% तक की है। यह वृद्धि दर नव वषत गाता

एव पुराने बचत खाते की परिष्कृता पर लागू होगी। निम्न तालिका द्वारा निश्चित राशियों व बचत खातों पर ब्याज की दरों का हिसाब लगाया जा सकता है —

निश्चित बचत खातों व बचत	2 मार्च 1981 से लागू	1 मार्च 1982 से लागू
15 दिन से 45 दिन तक	2.5%	3%
46 दिन से 90 दिन तक	3.0%	4%
91 दिन से 6 महीने तक	4.0%	5%
6 महीने से अधिक तथा 9 माह से कम	4.5%	6%
9 माह से अधिक परन्तु 1 वर्ष से कम	5.5%	7%
1 वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	7.5%	8%
2 वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	8.5%	9%

(ii) खुले बाजार को नियामक—देश में सावधान नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक खुले बाजार को नियामक भी अपनाता है। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है कि देश का केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों प्रथम श्रेणी के वित्तों एवं प्रतिभा पत्रों का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक सावधान नियंत्रण करने के लिए भारतीय मुद्रा बाजार में समय-समय पर सरकारी ऋणपत्रों का क्रय विक्रय करता है। दूसरे शब्दों से पूर्व रिजर्व बैंक की मुद्रा बाजार की क्रियाएँ केवल सीमित मात्रा में ही की जाती थी। उस समय इन क्रियाओं का उद्देश्य मुद्रा बाजार में होने वाली मौसमी कमी को दूर करना था। मुद्रा बाजार में भी खुले बाजार की क्रियाओं में विशेष वृद्धि नहीं हुई। मुद्रा के पश्चात् केन्द्रीय बैंक द्वारा देश में भागी मुद्रा का नियंत्रण करने हेतु बड़े पैमाने पर खुले बाजार की क्रियाएँ अपनायी गयीं। अब भी मुद्रा बाजार की परिस्थिति को देखते हुए केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) समय-समय पर खुले बाजार की क्रियाएँ अपनाता है।

(iii) परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात (Variable Reserve Ratio)—प्रारम्भ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम के अनुसार सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमाओं तथा भिमादी जमाओं का 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत न्यूनतम वैधानिक आरक्षित अनुपात के रूप में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास नकदी के रूप में जमा करना पड़ता था। सन् 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में सभी बैंकों पर अधिकतम तथा न्यूनतम परदे के उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

इस संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को यह अधिकार दिया गया कि यह अनुसूचित बैंकों की मौज तथा भिमादी जमाओं सम्बन्धी न्यूनतम वैधानिक आरक्षित अनुपात में श्रमश 5% से 20% और 2% से 8% तक वृद्धि कर सकता है। अगर अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम प्रतिशत के अलावा कुछ और भी नकद कोष जमा करने के लिए आग्रह दे सकता है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में 1962 में एक और संशोधन हुआ जिसके अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास न्यूनतम वैधानिक आरक्षित अनुपात में सभी प्रकार की जमाओं पर 3 प्रतिशत जमा करना होगा परन्तु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का यह भी अधिकार दिया कि वह चाह तो इसे बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। वर्तमान समय में यह 15% है।

हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कुछ कोषों में परिवर्तन करने का नीति का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने समय-समय पर अपनाया है। 29 जून 1973 को अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली न्यूनतम राशि का अनुपात 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया। तत्पश्चात् 8 सितम्बर 1973 को यह अनुपात 6% तथा 22 सितम्बर 1973 से यह प्रतिशत 7% कर दिया था। वर्ष 1982-83 के लिए यह अनुपात 8% था। वर्तमान समय में यह 10% है।

(iv) तरलता अनुपात अथवा वैधानिक तरलता अनुपात (Liquidity Ratio or Statutory Liquidity Ratio SLR) एक अन्तर्गत समस्त अनुसूचित बैंक को अपनी गण्यता का एक निश्चित भाग तरल मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश के केंद्रीय बैंक की नीति मांग नियमन के लिए वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके सात्व का नियंत्रण करता है। 28 नवम्बर 1978 का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अनुसूचित बैंक का यह आदेश दिया था कि वे अपने वैधानिक तरलता अनुपात का 33% से बढ़ाकर 34% कर दें। जिस व्यापारिक बैंक ने मान लिया। वर्ष 1989 में इस दर को 3% कर दिया गया है जो वर्तमान समय तक लागू है। मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया हमेशा प्रयास करता है।

(v) चयनात्मक सावधि नियंत्रण (Selective Credit Control)—चयनात्मक मांग नियंत्रण में अभिप्राय उक्त नियंत्रण से है जिसमें अन्तर्गत केंद्रिय बैंक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही न केवल बैंक का मांग प्रदान करता है। वास्तव में एक नियोजित एवं विवक्षित। यह अव्यवस्थित चयनात्मक मांग नियंत्रण अनिवार्य हो जाता है क्योंकि नियोजित में कुछ उद्देश्यों का प्राथमिकता दी जाती है।

रिजर्व बैंक भी कुछ वर्षों में मांग नियंत्रण के लिए चयनात्मक मांग नियंत्रण का प्रयोग कर रहा है। उदाहरणार्थ वर्ष 1971 में भारत में मृदुलाब्जा का अत्यधिक प्राप्ति इन मित्तों जिसमें देश के कामकाज में अत्याधिक वृद्धि हुई। इस दिक्का शकन के लिए रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का यह आदेश दिया था कि वह मृदुलाब्जा के लिए मांग प्रदान न करें। इस प्रकार भारतीय व्यापारिकों में माद्य पदार्थों के संचय करने का प्रवृत्ति का रोक्ने के लिए अनुसूचित बैंक का यह आदेश दे रहा है कि वे माद्य पदार्थों का आह पर व्यापारियों का कम से कम मात्रा में ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार समय समय पर अन्य वस्तुओं के संचय का रोक्ने के लिए अनुसूचित बैंक का इसका आह पर कम ऋण देने का आदेश दिया है। 7 अक्टूबर 1982 रिजर्व बैंक ने मण्डला उद्योग में अधिक स्टॉक जमा हान तथा कम निष्पादन हान के कारण धराहर पर ऋण देने के मर्यादा (Margin) में 10% छूट देने की घोषणा की थी जिसमें इस उद्योग में मंदी के वातावरण ने पनप सका।

इसके अलावा भी रिजर्व बैंक चयनात्मक मांग नियंत्रण विधि के अंतर्गत कुछ क्षेत्र में ऋण देने पर प्रतिबंध लगा तथा अनुसूचित बैंक को यह भी आदेश उसने समय समय पर दिया है कि अल्प गणित से अधिक कोई भी बैंक ऋण देता है तो उसकी पूरा अनुमति उस रिजर्व बैंक से लेना होगा।

(vi) नैतिक प्रभाव की नीति उपरान्त नीतियां के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अपने मन्स्य बैंक का समझा बुझाकर अपना निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर मन्स्य बैंक के प्रतिनिधियों की मंशा बुझाता है और समय समय पर मन्स्य बैंक का परिपक्व भ्रष्टाचार भी उद्देश्य सात्व का मात्रा का नियंत्रण करने का सुभाव देता है। उदाहरण के लिए मिनर 1949 में भारतीय रुपय का अवन्यूना के पश्चात रिजर्व बैंक के यवनेर ने देश के सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधियों का मांगि बुलाई थी और उनमें अनुरोध किया था कि वे मृदुलाब्जा के कार्यों के लिए व्यापारिकों को मांग प्रदान न करें।

(3) सरकारी बैंकर प्रतिनिधि एवं सहायक (Government Banker Agent and Adviser)

देश में मुद्रा प्रचलन का एकाधिकार प्राप्त होने तथा मांग मुद्रा का नियमन करने की शक्तियां प्राप्त हान के अतिरिक्त रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश में केंद्रिय तथा राज्य

सरकार के प्रति बैंक का बाय भी करती है। यह सरकार का आर्थिक मौद्रिक सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देती है। सरकारी बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक का बाय सरकारी ऋणपत्र बाजार में सरकार की उधार तथा भुगतान नीतियों को सफल बनाना होता है। यह केन्द्रीय व राज्य सरकारों की ओर से बजों का चालू करती है तथा उनको कजों की राशि तथा बजों को चालू करने के समय सम्बन्धी परामर्श भी देती है। यह सांख्यिक ऋण का प्रबन्धन भी करती है। रिजर्व बैंक के राज्यपाल पदों पर केन्द्रीय सरकार की ओर से दण्डन द्वारा साप्ताहिक नीलाम में राजकोष पत्रों का भी बेचती है। रिजर्व बैंक के द्वीय व राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋण भी देती है जिनका भुगतान ऋण देने की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाता है। सरकार वहुधा नए कजों को चालू करने तथा व निवेश रूपि साख औद्योगिक वित्त तथा नियोजन एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी वित्तीय समस्याओं आदि विषयों पर रिजर्व बैंक से परामर्श प्राप्त करती है।

(4) विदेशी विनिमय की व्यवस्था (Regulation of Foreign Exchange)

रिजर्व बैंक मुद्रा के विनिमय मूल्य को स्थिर रखता है। स्पष्ट व विनिमय मूल्य को निर्धारित दर पर स्थिर बनाए रखा व उद्देश्य से रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी विनिमय दर का प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। रिजर्व बैंक भारत में विदेशी विनिमय एवं भुगतानों तथा स्वण एवं अन्य वहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण भी होता है।

(5) बैंकों की बैंक (Banker's Bank)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया देश में अन्य बैंकों के प्रति बैंक का कार्य करती है। बैंकों व बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के प्रति वे सब कार्य करती है जो कोई बैंक अपने ग्राहकों के प्रति करती है। अन्य शब्दों में यह बैंक से जमा स्वीकार करती है, उनको वज देती है, उनका प्रति शोधन गृह का कार्य करती है तथा अन्तिम ऋणदाता के रूप में परिणाम के समय उनका वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह बैंकों को कठिनाई के समय परामर्श भी देती है।

(6) अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के बाद उसने अन्य अनुसूचित बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता की भूमिका निभायी है। जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग जमाओं तथा मियादा जमाओं (Demand Liabilities and Time Liabilities) का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना होता है अर्थात् न्यूनतम आरक्षित अनुपात (VRR) तथा कानूनी तरल कोषानुपात (SLR) जो कि वर्तमान समय में 15% तथा 38% है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों का एक विशेष पहुँच रहता है और इसी में से वह आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित बैंकों को ऋण प्रदान करता रहता है। संवत्परिचालन परिस्थितियों में अनुसूचित बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ही अन्तिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है।

(3) समाशोधन गृह कार्य (Clearing House Functions)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया देश का केन्द्रीय बैंक है इसलिए यह विभिन्न बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में समाशोधन गृह को सुविधाएँ प्रदान करता है।

औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इण्डिया (Industrial Development Bank of India) जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 का हुआ भी पूर्णतया ग्जिव बैंक का सहायक है। इस बैंक का उद्देश्य राज तथा नि. क्षेत्रों की औद्योगिक दवाइया का वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका अतिरिक्त रिजर्व बैंक न एक राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दायागि व बाय) फण्ड (National Industrial Credit Longterm Operation Fund) 1 जुलाई 1964 का स्थापित किया था जो फण्ड का उपयोग ग्जिव बैंक औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किया गया था और नि. क्षेत्रों का सहायता तथा औद्योगिक विकास बैंक का अन्य वित्तीय संस्थाओं से अर्थात् बैंक तथा नि. क्षेत्रों का सहायता का नि. क्षेत्रों में न किया कर सकती है।

नमू उद्योगों का सहायता प्रदान करने के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 1 मजदूरों का और नमू उद्योगों योजना भी चला कर गया है जिसका अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक आधुनिक नि. क्षेत्रों का सहायता बैंक का द्वारा नमू उद्योगों को दिया गया योजना के मुताबिक की गणना करता है। यह योजना 1960 में चलायी गयी थी। जिसकी सामग्री गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) कहा जाता है। यह योजना एपेक्स गैरकारी बैंक (Apex Co-operative Banks) द्वारा नमू उद्योगों को दिया गया गारंटी प्रदान करता है। अर्थात् पर राज होती है। अर्थात् अतिरिक्त 1964 के आरम्भ में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का स्थापन करने का ग्जिव बैंक ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। नमू उद्योगों का नि. क्षेत्रों का सहायता बैंक द्वारा नि. क्षेत्रों का 100 करोड़ रुपये की पूंजी से नमू उद्योगों का विकास करने का स्थापना हुई जिसका IDBI से भी सहायता मिली।

रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त

(Reserve Bank and Agricultural Finance)

हम जानते हैं कि विकास के लिये सभा सम्भव सहायता देने के उद्देश्य से 1935 में आरम्भ से ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में एक नवीन भाग विभाग का स्थापित किया गया। कृषि का वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों का 9 पि इण्डिया का जमानत पर 15 सहकारी बैंक दर से भी कम व्याज दर पर प्रदान करता है। मौसमी कृषि के लिये नि. क्षेत्रों का सहायता प्रदान करने हेतु रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को एक दर से 2% तक का व्याज दर पर 1967-68 में 314 16 करोड़ रुपये का राज का स्वीकृति पत्र का था।

सक्षम में रिजर्व बैंक 2 पि वित्त सम्बन्धी निम्न कार्य करता है—

- (1) यह बैंक राज्य सहकारी बैंकों तथा नि. क्षेत्रों के वित्तीय विकास का स्वीकृति प्रति भूतिया अन्य ऋणपत्रों के आधार पर अ. क्षेत्रों का सहायता प्रदान करता है।
- (2) यह बैंक नार्वेस प्राप्त गारंटी गारंटी गारंटी कृषि उपज के आधार पर ऋण देता है।
- (3) कृषि राज के आधार पर नि. क्षेत्रों का ऋण पर व्याज में 2% का छूट दी जाता है।
- (4) भूमि विकास योजना के प्रणाली का नि. क्षेत्रों का सहायता पूंजी को बढ़ाने का योगदान देता है।
- (5) यह राज्य सहकारी बैंकों का नि. क्षेत्रों का सहायता देता है कि यह सहकारी गारंटी गारंटी के अर्थ में सहायता देता है।
- (6) यह राज्य सहकारी बैंकों का नि. क्षेत्रों का सहायता देता है कि यह सहकारी गारंटी गारंटी के अर्थ में सहायता देता है।

यह राज्य सहकारी बैंकों का नि. क्षेत्रों का सहायता देता है कि यह सहकारी गारंटी गारंटी के अर्थ में सहायता देता है।

फरवरी 1956 में कृषि को और अधिक सहायता देने के नये नये कोषों की स्थापना की गई थी—

- (1) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष (National Agricultural Credit Long-Term Fund)
- (2) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) कोष (National Agricultural Credit Stabilisation Fund)

इन कोषों की सहायता से राज्य सहकारी बैंकों 7 सा.नो. में काफी वृद्धि हुई है। 30 जून 1977 तक राष्ट्रीय कृषि साख कोष में कुल धनराशि 334 करोड़ रुपये थी। सन् 1975-76 में रासायनिक खाद की खरीद एवं उसने वितरण के लिए भी रिजर्व बैंक ने 28 20 करोड़ रुपये स्वीकार किये थे।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी रिजर्व बैंक ने कृषि विकासार्थ मध्यमकालीन ऋण प्रदान किये हैं, जिनकी राशि 1977-78 में 81 32 करोड़ रुपये थी। विगत कुछ वर्षों से रिजर्व बैंक ने भूमि विकास बैंकों को भी मध्यमकालीन ऋण प्रदान किये हैं।

सन् 1963 में रिजर्व बैंक ने एक कृषि पुर्नवित्त नियम स्थापित किया था जिसे अब पुर्नवित्त एवं विकास निगम कहा जाता है। इस नियम का उद्देश्य कृषि सधु सिंचाई, मुर्गीपालन एवं मछली पालन आदि है। इस नियम को केन्द्रीय बैंक ने सन् 1874-75 में 40 करोड़ रुपये के एवं 1979-80 में 85 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये हैं।

12 जुलाई, 1982 को कृषि एवं ग्रामीण विकास का दायित्व कृषि एवं ग्रामीण विकास ■ राष्ट्रीय बैंक (NABARD) को मिल गया है। अब केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण साख प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। अब दोनों कोषों, राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन काय) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्विकरीकरण) कोष का विलय NABARD में हो चुका है। अब कृषि एवं ग्रामीण विकास की साख हेतु रिजर्व बैंक के स्थान पर NABARD अपना दायित्व निभा रहा है। नाबाड (NABARD) की स्थापना एक कृषि विकास के लिए एक शीर्ष संस्था की स्थापना हुई है। अब नाबाड ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए बहुत से ऋणों के पुर्नवित्त की व्यवस्था करता है। भारत जैरे कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बाहुल्य अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए इन प्रकार की शीर्ष संस्था की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी।

रिजर्व बैंक की सफलताएँ

{Achievements of the Reserve Bank}

रिजर्व बैंक की सफलता का मूल्यांकन निम्न तथ्यों से लगाया जा सकता है —

(1) सरकार के बैंकर के रूप में— रिजर्व बैंक न सरकारी बैंकर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सरकारी आय व्यय का सम्पूर्ण लेने-देन का ज्योरा यह रखता है। सरकार के लिए पर्याप्त आय जुटान की दृष्टि से यह उसके लिए ऋण उपलब्ध कराता है। समय समय पर केन्द्रीय सरकार के लिए ऋण लेने एवं उनके भुगतान तथा व्याज आदि की अदाएँ की R B I हिसाब रखता है।

(2) सरकार का परामर्शदाता—रिजर्व बैंक व पाम अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का दल होता है जो अपनी विशेषज्ञ सेवाएँ समय-समय पर प्रदान करते हैं। केन्द्र सरकार के आदेश पर यह विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, IBRD, तथा अन्य देशों की सरकारों का तथा देश में जीवन बीमा निगम, यूनिट

स्टेट ऑफ इण्डिया, इपि पूनवित निगम औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक तथा क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंको आदि न वाय कर रहे ह।

(3) औद्योगिक वित्त दश 1 औद्योगिक विकास का सुचारु रूप तथा सतुलित रखन की दृष्टि से उद्योगों का वित्त अल्पवानी तथा दीर्घवानी का ऋणों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वित्त निगमों को सहायता प्रदान की है।

(4) इपि वित्त रिजर्व बैंक की स्थापना न तुरन्त बाद ही इसने इपि व विभाग का वित्त कृषि साधन विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना की। साथ ही दश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की स्थापना द्वारा भी इपि क्षेत्र के विस्तार का वित्त काफी प्रयत्न किए हैं।¹

(5) समाशोधन गृहों की व्यवस्था—रिजर्व बैंक न विभिन्न बैंक द्वारा आपसी लेन-देन के निपटारे के लिए समाशोधन गृहों की स्थापना की है। वर्तमान समय में लगभग 100 अधिक समाशोधन गृह स्थापित किए गए हैं। जहाँ R B I के कार्यालय नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यह सुविधा प्रदान करता है। इस गृह में एक निश्चित तिथि पर सभी बैंकों का प्रतिनिधि एकत्रित होता है और आपसी लेन-देन को नकद न करके बैंकों के माध्यम से देनदारों एवं लनदारों निपटाता है।

(6) अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आंकड़ों का प्रकाशन—रिजर्व बैंक अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मुद्रा एवं साख संबंधी सहकारिता विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों का सङ्कलन कर उन्हें प्रकाशित करता है। इससे अध्ययन के आधुनिक एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलता रहता है तथा सरकार का इन क्षेत्रों में अपना नीतियाँ निर्माण में इन आंकड़ों से काफी सहायता मिलती है।

(7) विदेशी विनिमय के सरक्षक का कार्य—रिजर्व बैंक न विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्पूर्ण विदेशी विनिमय का प्रत्यक्ष तथा विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी सभी कार्य इसी का दायरग में सम्पन्न होते हैं। देश की बहुमूल्य धातुओं के सरक्षक के अलावा यह विदेशी विनिमय बाजार का सरक्षक होता है। यह विनिमय दरों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य पर भी नजर रखता है। यह सरकार का समय समय पर विदेशी विनिमय बाजार में स्थिति की जानकारी भी देता है। आयात एवं निर्यात सम्बन्धी राज्यों के लिए भी रिजर्व बैंक में तालमेल प्राप्त करना जरूरी है।

(8) देश के वैकिंग विकास में सहायता—रिजर्व बैंक न अधिनियम के अनुसार इनमें विभिन्न बैंकों का कार्य विस्तार तथा वैकिंग प्रियाओं द्वारा वैकिंग विकास किया है।

उपयुक्त कार्यों के अलावा धन के स्थानान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ साख नियन्त्रण तथा वैकिंग विकास आदि के लिए भी रिजर्व बैंक का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के शीप बैंक का नात भी रिजर्व बैंक का सवाएँ सहायता रहा है।

रिजर्व बैंक की असफलताएँ (Failures of the Reserve Bank)

इनकी असफलताओं का निम्नलिखित तथ्यों में आता जा सकता है —

(1) मुद्रा बाजार में समय का अभाव—भारतीय मुद्रा बाजार में विभिन्न अर्थ-व्यवस्था के असाधित एवं असाधित मुद्रा बाजारों के बीच समन्वय का अभाव पाया जाता है। अधिकांश मुद्रा बाजारों का क्षेत्र असमर्थित है और उस पर रिजर्व बैंक का कोई प्रभाव नहीं

1. अधिनियम के लिए रिजर्व बैंक तथा इपि वित्त शीपक दिये।

रहता। रिजर्व बैंक की अपनी नीतियों के विर्यान्वयन में इस कारण भी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है।

(2) साख नियन्त्रण में कठिनाई—रिजर्व बैंक को साख मुद्रा व नियन्त्रण में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। हाँ कि रिजर्व बैंक ने समय-समय पर विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न गतियों का अपनाया है। इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक का असफलता की जर्दी हमने दया अध्याय में का है।

(3) व्याज की दरों में असमानताएँ—रिजर्व बैंक की भारतीय मुद्रा बाजार व ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण एवं सम्बन्ध व अभ्यास में गया व मुद्रा बाजार में व्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है। जब तक कि रिजर्व बैंक 10 दशमिक दक्ष एवं असंगठित मुद्रा बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डालता तब तक व्याज की दरों की यह असमानताएँ बना रहनी।

(4) बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विकास—रिजर्व बैंक की स्थापना व 47 वर्षों के बाद भी देश में बैंकिंग सुविधाओं का सन्तुलित विकास नहीं हो पाया है। स्टेट बैंक तथा 20 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में इनकी शाखाओं का विस्तार काफी हुआ है परन्तु बहुत कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सुविधाएँ जनता व बहुसंख्यक वर्ग तक नहीं पहुँच सकी हैं। इस ओर अभी प्रयास करना बाँप है।

(5) मुद्रा स्फीति को रोकने में असमर्थ—रिजर्व बैंक अपना नीतियों का माध्यम से मुद्रा स्फीति जैसा घातक बुराई पर अकुशल प्रणतया नहीं लाया गया है। आशा है कि रिजर्व बैंक अपनी साख एवं मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्थाओं द्वारा मुद्रा-स्फीति जैसी बुराई पर काबू पा लेगा। अग्रे, 1982 तक सरकार का दावा है जसने मुद्रा-स्फीति की दर शून्य तक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करली थी परन्तु यदि यह सही भी मान लिया जाय तो कौनतो में बढ़ने की प्रवृत्ति जो अब भी बनी हुई है उस क्या बहा जायेगा। रुपये का वार्षिक मूल्य बराबर गिरता जा रहा है। कीमत वृद्धि पर अकुशल यह नहीं लगा पाया है।

(6) बिल बाजार के विकास में असफलता—अपनी स्थापना के 37 वर्षों के बाद भी रिजर्व बैंक एक अच्छे बिल बाजार के विकास में सफल नहीं हो पाया है। बिल बाजार योजना व अन्तर्गत और अधिक उदारतापूर्ण व्यवहार अपना कर रिजर्व बैंक व्यापारिक गतिविधियों में और तेजी ला सकता है।

परीक्षा-प्रश्न

1. रिजर्व बैंक के कार्यों पर प्रकाश डालिए।

(Discuss the functions of the Reserve Bank)

अथवा

रिजर्व बैंक के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(Examine critically the functions of the Reserve Bank)

अथवा

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कार्यशालता का मूल्यांकन कीजिए।

(Evaluate the working of the Reserve Bank of India)

2. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की साख नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखिए।

(Write a short essay on Reserve Bank of India's credit control policy)

व्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए मुद्रा एवं साख नियंत्रण व विभिन्न तरिका को बताइए ।

(Describe various methods of monetary and credit control adopted by the Reserve Bank of India)

[संकेत—साख नियंत्रण वा विभिन्न रीतियों वा बताइए भारत में मूलतः निधि प्रणाली अपनाकर रिजर्व बैंक मुद्रा की निरामा करता है । साख नियंत्रण वा विभिन्न रीतियों वा मूल्यांकन करते हुए इसकी असफलता का भी चर्चा कीजिए ।]

- 3 रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति का प्रमुख विशेषताओं का बताइए । यह कहाँ तक प्रभावशाली रही है ?

(Explain the chief characteristics of credit control policy of the Reserve Bank How far they have been effected ?)

[संकेत—रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण की विभिन्न रीतियों का बताइए । उसका दाव बताइए कि साख नियंत्रण की उम्मीदें अधिक प्रभावशाली नहीं रही हैं । इस ओर उसका असफलता का चर्चा कीजिए ।]

- 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत बताइए ।

- (i) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भारत का केंद्रीय बैंक है ।
- (ii) रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था ।
- (iii) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को साख नियंत्रण के क्षेत्र में आभासी सफलताएँ मिली हैं ।
- (iv) रिजर्व बैंक साख नियंत्रण हेतु परिमाणों में तथा गुणात्मक दोनों ही दिशाओं में असफल रहा ।
- (v) रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में अमर्गल बन गया था नियंत्रण करता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है । (ii) सही है । (iii) गलत है । (iv) सही है । (v) गलत है ।

A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages

—J M Keynes

Business cycle is nothing more than rhythmic fluctuations in the overall level of employment income and output

—D Dillard

the business cycle is peculiarly a manifestation of the industrial segment of the economy from which prosperity or depression is redistributed to other groups in the highly interrelated modern society

—I H Flunet

अध्याय 20

व्यापार चक्र

(TRADE CYCLE)

व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की गतिशीलता जिनका सम्बन्ध रोजगार उत्पादन आय कीमतों तथा सঞ্চय होता है से सम्बन्धित होता है। परन्तु प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं की गतिशीलता को हम व्यापार चक्र (Trade or Business Cycle) की सहा नहीं दे सकते। हम बसल उन्ही आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र की सहा देते हैं जिनको हम एक निश्चित समय अंतराल के बाद महसूस करते हैं। यदि हम संचय की आर्थिक ऐतिहासिक दृष्टिभूमि का अवलोकन करें तो हम जाते होंगे कि दुनियाँ का विभिन्न अर्थव्यवस्था विशेषरूप से पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ दाग विधि और अल्पवधि तथा आकार का दृष्टि से नम या अधिक उच्चावच के रूप पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य घटनाएँ साबित हुई हैं।

आर्थिक क्रियाओं में उच्चावचन अर्थव्यवस्था में विभिन्न रूप का हो सकते हैं। सामान्यतया यह दीर्घकाल अथवा अपघात के होते हैं। इसी प्रकार से कुछ उच्चावचन का आकार तथा अवधि अधिक तथा कुछ का आकार कम होता है कुछ उच्चावचनों की अवधि केवल कुछ महीनों की होती है और इनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी सीमित तथा हल्का होता है जबकि कुछ कुछ उच्चावचन कई वर्षों की समयवधि वाले होते हैं जो अर्थव्यवस्था पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दुनियाँ के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इन उच्चावचनों का अध्ययन करके इनकी प्रकृति प्रभाव तथा विशेषताओं का और हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

व्यापार चक्र की परिभाषा (Definition of Business Cycle)

अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रो० डब्ल्यू० सी० मिचल (Prof W C Mitchell) के शब्दों में व्यापार चक्र को अग्र प्रकार से परिभाषित किया गया है

‘... व्यापार चक्र उच्चावचना का यह रूप होते है जो उन राशियों की जो अपना वाय प्रमुख रूप से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में संगठित करत हैं नीचे सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं में पाए जाते हैं। व्यापार चक्र में सामान्य विस्तार की स्थिति में लगभग एक ही समय में बहुत सी आर्थिक क्रियाओं में विस्तार होता है। प्रायः बाद सामान्य मुश्किलें (गिरावट) मंदी विमुक्ति की अवस्थाएँ पाई जाती हैं जो अनेक व्यापार चक्र की विस्तार अवस्था में मिल जाती हैं। परिवर्तना का यह क्रम आरंभ होता है।’¹

प्रा० मिचिन की व्यापार चक्र का उन परिभाषा द्वारा उद्घाटन यह बताने का प्रयास किया है कि वह उच्चावचन जिन तीन अर्थव्यवस्थाओं में होता है। व्यापार चक्र कहना है। उनमें अनुसार व्यापार चक्र उन चक्र उच्चावचना से अलग होते हैं जो अर्थव्यवस्था के किसी भाग में पाए जाते हैं। वैन यहाँ यह कहना उचित है कि हम उन क्रम उच्चावचना तथा ऐसे चक्रों उच्चावचना में भेद करना चाहिए जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के किसी भाग में विद्यमान होते हैं। ऐसा करना उचित भा आवश्यक है क्योंकि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का समस्याएँ अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों से मिलती हैं। प्रा० मिचिन ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि व्यापार चक्र का तात्पर्य उन उच्चावचना से होता है जो व्यापारिक क्षेत्र में जाते हैं तथा नियमित रूप से आवर्तीय हान का प्रवृत्ति बना है।

प्रा० ज० एम० बी० ने अपना दान पुस्तिका (A Treatise on Money (1930) तथा The General Theory of Employment Interest and Money (1936) में व्यापार चक्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अपना पुस्तिका A Treatise of Money में वह कहते हैं ‘व्यापार चक्र उत्तम व्यापार अवधि जिसमें मूल्य में वृद्धि तथा बरोजगारी में आकार में गिरावट होती है तथा छराव व्यापार अवधि जिसमें मूल्य में गिरावट तथा बरोजगारी में वृद्धि होती है का भाग होता है।’²

General Theory में भी व्यापार चक्र की परिभाषित करत हुए लिखते हैं चक्रवर्त गति से हमारा ज्ञान उस स्थिति में होता है जिसमें अर्थव्यवस्था प्रगति करती है अर्थात् ऊपर दिशा में गतिमान होती है ता उन शक्तियों का जो उन अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर बढ़ता है अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और यह एक दूसरे पर संचयी रूप से प्रभाव डालती है किन्तु उनकी शक्ति क्रमशः घटती जाती है और कुछ समय के बाद एक बिन्दु पर आकर इनका स्थान विरोधी दिशा में गतिमान शक्तियों का प्राप्त हो जाता है। यद्यपि यह शक्तियाँ भी अपने पूर्वज (विरोधी शक्तियाँ) के समान आरम्भ में कुछ समय तक अधिक शक्ति प्राप्त करती हैं परन्तु अपने अधिकतम विकास का प्राप्त कर

- 1 business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of nations that organise their work mainly in business enterprises. A cycle consists of expansions occurring at about the same time in many economic activities followed by similar general recessions, contractions and revivals which merge with the expansion phase of the next cycle, this sequence of changes in recurrent but not periodic’
—W. C. Midell

2. ‘A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentage alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages’
—J. M. Keynes

यह भी कम हो जाती है तथा अन्त में अपनी निरोधी शक्तियों को रथा दे देती है। इससे अतिरिक्त व्यापार चक्र की एक अन्य विशेषता सवट की घटना है अर्थात् उपरी प्रवृत्ति के स्थापन पर नीचे की ओर प्रवृत्ति का स्थापनापन्न आकास्मा रूप से प्रचलता के साथ होता है किन्तु जब नीचे की ओर की प्रवृत्ति का जगह उपरी प्रवृत्ति का स्थापनापन्न होता है तो इस प्रकार तोक्षण निर्वाण अवस्था विद्यमान नहीं होती है।¹

जे० एम० कीन्स द्वारा प्रस्तुत व्यापार चक्र की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम व्यापार चक्र की निम्नलिखित विशेषताएँ प्राप्त करते हैं -

(1) व्यापार चक्रों में प्रसार तथा संकुचन (expansion and contraction) की सापेक्ष वैकल्पिक क्रियाएँ विद्यमान रहती हैं। चक्रीय उत्तर चढ़ाव की प्रवृत्ति तब ही होती है।

(2) व्यापार चक्र की उपरी एवं नीचे की ओर की गतिशा की अवधि में तथा गमय के अनुक्रम में एक प्रकार की नियमितता पाई जाती है।

(3) व्यापार चक्र में सवट की घटना उपरिष्ठ होती है इसका अर्थ यह है कि ऊँच बिन्दु (Peak) तथा गड्ढा बिन्दु (trough) यथाप्रमाण नहीं होते दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि उपरी दिशा की गति में जब परिवर्तन होता है तब यह परिवर्तन एकाएक होता है तथा नीचे की ओर की दिशा की गति में होने वाला परिवर्तन की अपेक्षाकृत अधिक अनन्त होता है। इसके वृत्तरेख व्यापार चक्र की बोटी मोरिती तथा तनी बपटी होती है।

एक अन्य प्रमुख अर्थधारत्री प्रो० बेनहम ने व्यापार चक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है 'व्यापार चक्र वैभव तथा सम्पन्नता की वह अवधि है जिसके बाद अवसाद और मन्दो की स्थिति आती है।'²

प्रो० रेगनर क्रिश् (Prof Ragnar Frisch) द्वारा दी गई व्यापार चक्र की परिभाषा निम्न प्रकार है -

'बाह्य प्रवृत्तियाँ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालकर इसे लहर की तरह उठी प्रकार गतिमान करती हैं जिस प्रकार कोई बाहरी धक्का पड़ी लहर को डुबा देता है। लेकिन लहरवत गति की सम्झाई झूठी है अर्थव्यवस्था में आन्तरिक ढाँचे द्वारा निर्धारित होती है अर्थव्यवस्था का हलचल नीचे के ऊँचे दर्जे की नियमितता हो सकती है चाहे इन हलचलों (oscillation) को जन्म देने वाली प्रवृत्तियाँ बिल्कुल अव्यवस्थित हों।'³

व्यापार चक्र की उक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम व्यापार चक्रों की प्रवृत्ति के बारे में कह सकते हैं कि इसका आशय आर्थिक क्रियाओं के उन उल्लास-चला (Fluctuations) में होता है जो निश्चित अवधि के बाद बार-बार उत्पन्न होते हैं। इससे की विभिन्न पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के पिछले लगभग 200 वर्षों का इतिहास बताता

1 J M Keynes

2 Benham

3. 'Impulses from outside operate upon the economy, causing it to move in a wave-like manner just as an external shock will set a pendulum swinging. But it is the inner structure of the swinging system which determines the length of the wave movement. The oscillation of the system may have a high degree of regularity, even though the impulses which set it going are quite irregular in their behaviour'

—Quoted by A H Hansen

है कि यह देश व्यापार चक्र से पीड़ित रहे ह। नोर्ड भी दो चक्र एन से नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में प्रो० सेम्युएलसन (Prof Samuelson) ने व्यापार चक्र के उल्लेखनीय हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि वे एक जैसे बच्चे नहीं होते परन्तु उन्हें एक ही पाठ्यक्रम का सदस्य होने का रूप में पहचाना जा सकता है। व्यापार चक्र में सामयिकता (Periodicity) तथा समन्वयिता (Synchronism) जैसी दो प्रमुख विशेषताएँ पाई जाती हैं। सामयिकता से आशय व्यापार के उतार चढ़ाव अर्थात् विस्तार (Expansion) तथा संकुचन (Contraction) एक दूसरे के ऊपर निर्धारित रूप में घटित होते दिखाई देते हैं। जरूरी समन्वयिता से आशय उम स्थिति से होता है जरूरी व्यापार चक्र के समय देश की सभी फर्मों पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है अर्थात् नमूदित बात में सभी फर्मों का लाभ तथा भंडी राज में सभी फर्मों का हानि उठानी पड़ती है।

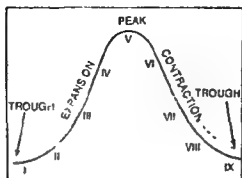
व्यापार चक्र के रूप अथवा आर्थिक उतार-चढ़ाव के रूप (Types of Trade Cycle or Types of Economic Fluctuations)

आर्थिक उतार-चढ़ाव अथवा व्यापार चक्र का नापने के लिए विभिन्न अवधारणाएँ न इसको नापने की व्यवस्थाएँ बढिआई का ध्यान में रखते हुए इनमें विभिन्न रूपों तथा आवृत्तियों की चर्चा की है। इतिहास इस बात का पुष्टि करता है कि एक एक तथा एक शक्तिवाने चक्रों में गति असम्भव है परन्तु एक भी आर्थिक उतार-चढ़ाव इतने अनियमित नहीं हुए हैं कि उनको अनुपयुक्त मान लिया जाए। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ आज भी किसी न किसी रूप में इनसे पीड़ित रहती हैं परन्तु इन आर्थिक उतार-चढ़ावों की तीव्रता में अन्तर हो सकता है जो अनियमितताएँ उपस्थित रहती हैं वे मुख्य रूप से इस स्थिति का परिणाम होती हैं कि एक साथ विभिन्न प्रकार के चक्र संचलित होते रहते हैं।

सतार के आर्थिक इतिहास के अध्ययन में ज्ञात होता है कि व्यापार चक्र की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 12 वर्ष तक की रही है। अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० एल्विन एच हैन्सन (Prof Alvin H Hansen) ने अपने अध्ययन के आधार पर व्यापार चक्रों को छोटे तथा बड़े व्यापार चक्र में बाँटा है। उनसे अनुसार बड़े व्यापार चक्र की औसत अवधि 8 वर्ष तथा छोटे व्यापार चक्र की औसत अवधि लगभग 3½ वर्ष की होती है। प्रो० हैन्सन ने अमरीका का अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की घटनाक्रम का नापने के लिए 142 वर्षों अर्थात् 1795 से 1937 तक की अवधि का अध्ययन किया और इन निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस अवधि में 17 बड़े व्यापार चक्र उपस्थित हुए जिनकी औसत अवधि 8.35 वर्ष की थी। 1807 से 1937 तक की 130 वर्ष की अवधि में अमरीका में 37 छोटे व्यापार चक्र विद्यमान रहे जिनकी औसत अवधि 3.1 वर्ष की थी। प्रो० हैन्सन बड़े व्यापार चक्र की अवधि 8 वर्ष से थोड़ी अधिक मानते हैं। यद्यपि बड़े व्यापार चक्र 6 वर्ष की न्यूनतम अवधि में लेकर 12 वर्ष की अधिकतम अवधि के हात में परन्तु साधारणतया न्यूनतम तथा अधिकतम अवधियाँ 7 से लेकर 10 वर्ष तक की होती हैं।

छोटे व्यापार चक्र की समयावधि साधारणतया 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। प्रो० हैन्सन (Prof A H Hansen) ने 130 वर्ष की समयावधि अर्थात् सन् 1807 से 1937 तक अमरीका के आर्थिक इतिहास के अध्ययन द्वारा ऐसे 37 छोटे व्यापार चक्रों के घटित होने की पुष्टि की है। इस समयावधि के अध्ययन में एक रोचक तथ्य यह भी सामने आया कि छोटे व्यापार चक्र एक भी समयावधि में नहीं हैं। प्रो० हैन्सन ने यह भी नोट किया कि अर्थशास्त्र विद्वानों ने व्यापार चक्र की नियोज्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री क्लेमेंट जेफर (Prof Clement

बिन्दुओं का I तथा IX द्वारा दिशाया गया है। प्रो० मिचिल तथा बर्नस द्वारा वर्णित इन



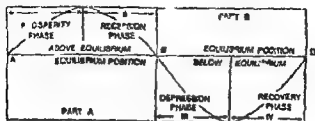
चित्र 1

स्थितियों को निम्नलिखित षाट् द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है जो चित्र 1 की पुष्टि करता है।

अवस्थाएँ	उप-अवस्थाएँ	व्यापार चक्र में स्थिति
ऊर्ध्वबिन्दु (trough)	I तथा IX	ऊर्ध्वबिन्दु (Trough)
प्रसारण (Expansion)	II III तथा IV	ऊर्ध्वबिन्दु से अधोबिन्दु के प्राग्गम्य की स्थिति।
अधोबिन्दु (Peak)	V	अधोबिन्दु (Peak)
संकुचन (Contraction)	VI VII तथा VIII	अधोबिन्दु की समाप्ति से ऊर्ध्वबिन्दु का आरम्भ तक।

प्रो० शुम्पीटर (Prof. J. A. Schumpeter) प्रो० मिचिल तथा प्रो० बर्नस के उक्त वर्णन में सन्तुष्ट नहीं थे। उनका कहना है कि व्यापार चक्र को एक मन्तुन की अवस्था से दूसरे मन्तुन की अवस्था तक विभाजित करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने दो अवस्था यात्रा व्यापार चक्र को व्यक्त किया है जैसे भाग A तथा B जिसका निरूपण अध्याय की चित्र मर्यादा 2 द्वारा व्यक्त किया गया है। चित्र ने A भाग ऐसी दो अवस्था वाले व्यापार चक्र को व्याख्या करता है जिसमें सम्पूर्ण अवधि में आवधिक प्रियाओं का स्तर मन्तुन की अवस्था से ऊपर होता है तथा भाग B में दो अवस्था यात्रा ऐसी व्यापार चक्र का दिशाया गया है जिसमें सम्पूर्ण व्यापार चक्र की अवधि में आवधिक प्रियाओं का स्तर मन्तुन की अवस्था में नाब रहता है। प्रस्तुत चित्र 2 में चार मन्तुन बिन्दु हैं। भाग A में मन्तुन अवस्था A में B बिन्दु तक तथा भाग B में मन्तुन अवस्था बिन्दु C में D तक बढ़ाई गई है। भाग A में एक मन्तुन बिन्दु A में और दूसरे मन्तुन बिन्दु B तथा व्यापार चक्र की समयावधि अच्छी नहीं जाती है। इन वर्षों को समृद्धि की अवस्था

रहा जाता है। नीचे प्रकार भाग II में भी दो अवस्था या दो व्यापार को दिखाया गया है जिस अवधि में अर्थव्यवस्था गतिमान से नीचे स्तर पर रहती है।



चित्र 2

प्रो० शुम्पीटर (Prof J A Schumpeter) ने व्यापार चक्र की जिन चार अवस्थाओं का वर्णन किया है सामान्यतः उन्हें ही व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में स्वीकार कर दिया जाता है।

1 समृद्धि अवस्था अथवा प्रसारण [Prosperity (Boom) or Expansion Phase]

2 सुस्ती अवस्था अथवा गमदी से मन्दी की ओर (Recession phase the Turn from prosperity to Depression)

3 मन्दी अवस्था अथवा संकुचन का स्थिति (Depression Phase or State of Contraction)

4 चेतना अवस्था अथवा मन्दी से समृद्धि की ओर (Revival Phase or the turn from Depression to Prosperity)

1 समृद्धि अवस्था (Prosperity Boom or Expansion Phase)-- व्यापार चक्र की समृद्धि अवस्था को सर्वोत्तम माना जाता है। प्रो० हेबरलर ने समृद्धि अवस्था या अथ उस अवस्था से लिया है जिससे वास्तविक आय का उपभोग वास्तविक अर्थ का उत्पादन तथा रोजगार का स्तर ऊँचा होता है और इसमें बेकार साधन या बेरोजगार श्रमिक या तो होते ही नहीं हैं या फिर इनकी संख्या कम होती है।¹

समृद्धि अवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं— (1) उत्पादन तथा व्यापार का मात्रा में वृद्धि तथा विस्तार (2) रोजगार के स्तर में बहुमुखी वृद्धि (3) बढ़ता हुआ कीमत स्तर, (4) व्यापार का दौरा में वृद्धि तथा सटके बाजार की गतिविधियों में बढ़ोतरी (5) सारा तथा लेन-देन कार्यों में वृद्धि (6) वास्तविक विनियोग में वृद्धि (7) मजदूरी तथा लाभ में वृद्धि अथवा समाज की आय में वृद्धि (8) व्यापार के क्षेत्र में आशावादिता (9) अर्थव्यवस्था का अपनी पूर्ण कार्यक्षमतानुसार कार्य करना आदि।

समृद्धि अवस्था में चारों ओर आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है और इसमें ऐसे प्रावणिक तत्व स्वयं सामंतीय हो उठते हैं जिससे व्यापारिक क्रियाओं को नई स्फूर्ति मिलता है। बीमारी बढ़ने से लाभ बढ़त है जिससे साहसियों द्वारा विनियोगों में लिए सदैव

1 Prosperity is a state of affairs in which the real income consumed and the level of employment are high or rising, and there are no idle resources or unemployed workers or very little of either
—G Haberler

प्रभावित होता रहता है। नये विनियोगों का प्रतिकूल प्रभाव बाजार में रहता है। प्रत्यक्ष उत्पादन अपनी व्यापारिक गतिविधि की वृद्धि करने में सक्षम रहता है। नये विनियोग नये राजगार अवसरों में वृद्धि जिसमें उत्पादन तथा आय में भी वृद्धि होती है। प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है जिनका राजगार का स्तर पुनः बढ़ता है। इस प्रकार समृद्धि चक्र में प्रमाणों का जो अनुसंधान रहता है वह स्वयं सृजित तथा संचयी होता है।

समृद्धि अवस्था का अन्त उम्र समय होता है जब कि प्रसारण की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। समृद्धि के अन्त में ही ट्रांसिशन का चिह्न दृष्टिगोचर होने लगता है। जब विनियोग वृद्धि की उपायों प्रवृत्ति दिशा में जाता है तब अधिक विनियोग हेतु वित्तीय माध्यनों में काफी दिशा देना पड़ती है परिणामस्वरूप बैंक द्वारा व्याज की दर ऊँची कर दी जाती है। कर्मी न भ्रम तथा अन्य उत्पादन माध्यनों की कमी महसूस होने लगती है और इनका पारिस्थितिक (prices) बढ़ने लगते हैं। इन सबका मित्रा युक्त परिणाम यह होता है। माँग धीरे धीरे बढ़ जाता है जिससे उपभोक्ता तथा उत्पादन दोनों ही प्रभावित होते हैं। चक्र कुछ समय धीरे धीरे पूरा करने के लिए उत्पादन अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाता है उपभोक्ता में गिरावट विधियों में गिरावट पार्कों के नाम में गिरावट आती है। प्रत्यक्ष हम अपने उत्पादों को शीघ्र बचन का प्रयास करते हैं। कर्मचारी कुछ फर्मों में ह्रास में अपनी बचतों की कीमतें गिरा देती हैं और कुछ फर्मों को हानि उठाना पड़ती है। कुछ मित्रा का समृद्धि चक्र में अधिक आशावादित अंत में निराशावादित (Pessimism) का जन्म देती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि समृद्धि अवस्था स्वयं अपना जन्म गौरी देती है।

2 **मुस्ती अवस्था (Recession Phase)** — जैसा कि ऊपर कहा गया है कि समृद्धि स्वयं मुस्ती अवस्था का जन्म देती है। उल्टा उल्टा होता है। मुस्ती को एक अवस्था कहने की अपेक्षा एक माह की सजा देना चाहिए जो समृद्धि का गंदी अवस्था में ले जाती है। मुस्ती अवस्था थोड़े समय ही दिखाई देती है। इस अवस्था में साहसिकता (entrepreneurs) को अपनी वृद्धि का आभाम हानि लगता है और वह यह अनुभव करने लगते हैं कि उनका द्वारा समृद्धिनाल में प्रारम्भ किए गए कार्य लाभप्रद नहीं रहे। उममें व्याप्त निराशावादी दृष्टि का उनका मानव का घटाता है परिणामस्वरूप बढ़ने भी फर्मों एक एक करके बन्द होना प्रारम्भ हो जाती हैं। उन सबका मित्रा युक्त परिणाम यह होता है कि राजगार का स्तर में गिरावट आती है विनियोग मित्ते है क्योंकि उत्पादन करना लाभप्रद नहीं आता, बैंक अधिक बैंक द्वारा व्याज की दर नीची करने पर भी नहीं बढ़ते। प्रभावपूर्ण माँग में गिरावट आती है जिससे कीमतें और लाभ दोनों का ही स्तर गिरता है। सट्टा बाजार में नये का वातावरण छा जाता है और उनकी गतिविधियाँ में गिरावट आ जाती है। प्रा० एम० डब्ल्यू ली० (Prof M W Lee) ने मुस्ती अवस्था की सजा उम्र जगल से दी है जो एक बार लगने में अपने माँग में आन में भी माँग का ध्वस्त कर देती है।¹

3 **मंदी अवस्था (Depression Phase)** — मंदी का समृद्धि अवस्था का विपरीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यापार चक्र की मंदी अवस्था में अधव्यवस्था में उत्पादन तथा राजगार का स्तर में काफी गिरावट आता है। बाजार और निराशावादित हो दिखाई देती है। प्रा० हबर्नर ने मंदी की अवस्था का बड़ मुन्दर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है 'मंदी का आगमन उम्र अवस्था में होता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय के उप-

1 'A recession once started tends to build upon itself much as forest fire once underway tends to create its own draft and given impetus to its destructive ability.' — M W. Lee Economic Fluctuation

योग एवं उत्पादन तथा रोजगार के स्तर गिरते हैं और यह एक प्रकार से एक ऐसी असाधारण स्थिति होती है जिसमें बेकार साधन विशेषरूप से श्रम का उपयोग नहीं होने पाता।¹

मंदी अवस्था में अर्थव्यवस्था के चारों ओर गिरावट के चिह्न अवश्य दिखाई देते हैं परंतु यह एक समान प्रभाव चान नहीं होते। उदाहरणार्थ फुटकर व्यापार पर उतारा प्रभाव पड़ता जितना कि थोक व्यापार पर पड़ता है इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मौसमी बशाओं तथा कृषि में गैर व्यापारिक क्षेत्र की बहुलता के कारण यह क्षेत्र अधिक प्रभावित नहीं आता। जब कि दूसरी ओर मंदी का अधिक प्रभाव निर्मित उद्योगों स्नान निर्माण परिवहन विशेष तौर पर पूँजीगत वस्तुओं बनने मशीनों आदि पर दिखाई देता है।

मंदी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही मुद्रा का उपयोग भी घटता है। मंदी में केवल मुद्रा ही ऐसी निधि होती है जिसका धन्य वडता है। सभा में अधिक क्रिया में गिरावट व्यापार के क्षेत्र पर एवं प्रकार से काले बादलों की भाँति देख जाते हैं जिससे बैंक जमाओं में (banks deposits) गिरावट आती है नये ऋणों का माँग गिर जाती है। कोई भी साहसी किसी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता। स्टॉक बाजार (Stock exchanges) में विभिन्न फार्मों के अगो तथा प्रतिभूतियों के मूल्य गिरते हैं।

मंदी अवस्था में राष्ट्रीय आय के वितरण में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। साहसी के पास गिरते हैं और कभी कभी यह असाधारण भी होत है। केवल उन लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है जो कि मंदी के बाद भी रोजगार पर लगे हुए होते हैं इसका कारण यह है कि कीमतों में गिरावट होने से उनके पास उपलब्ध आय (Disposable income) बढ़ जाता है।

एक प्रगतिशिल अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति भी हुयेला नहीं बनी रह सकती इसका कारण यह है कि वे तत्त्व जो मंदी के लिए उत्तरदायी होते हैं स्वयं ही कमजोर पड़ने लगते हैं। साहसियों द्वारा अपनी प्लांट तथा मशीनों को बदलने की वायदाही एक जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा कुछ समय के लिए टिकाऊ वस्तुओं की माँग कम हो जाती है। धीरे धीरे टिकाऊ वस्तुओं की माँग उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ने लगती है (सावजनिक विनियोगों में कुछ प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाती है) परिणामस्वरूप कुछ समय पश्चात् उत्पादकों द्वारा प्लांट तथा मशीनों को बदलने का काम प्रति प्राप्त करता है उत्पादन को बढ़ाया मिलता है रोजगार के अंतर बढ़त है जिससे आय तथा प्रभावपूर्ण माँग में भी वृद्धि होती है। बैंक भी सारा बढ़ाने के लिए तैयार रहने हैं। निराशावांशिता से ही आशावादिता के बिन्दु दृष्टि मोचर होने लगते हैं और आर्थिक क्रियाओं की बढ़ावा मिलता है। यहाँ से ही चेतना अवस्था अथवा मंदी से समृद्धि की ओर अर्थव्यवस्था बढ़ती है।

4 चेतना अवस्था (Revival or Recovery phase) अर्थव्यवस्था कुछ समय मंदी की अवस्था में रहने के पश्चात् चेतना अवस्था का अनुभव करने लगती है। हमने अतगत मंदी से समृद्धि की ओर अर्थव्यवस्था गतिमान होता है। चेतना अवस्था में पूँजीगत वस्तुओं की माँग बढ़ाने लगती है कस्वरूप पूँजी उद्योगों में विनियोग तथा रोज

1 Depression means a state of affairs in which real income consumed or volume of Production per head and the rate of employment are falling or are subnormal in the sense that there are idle resources and unused capacity especially unused labour

भार बढ़ता है और आय बढ़ती है। आय में वृद्धि प्रभावपूर्ण भाग को बढ़ाती है। कीमतें, लाभ विनियोग, रोजगार तथा आय सभी में दृष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं। एक बार प्रसारण अवस्था के प्रारम्भ होने से रोजगार उत्पादन तथा आय धीरे धीरे बढ़ती है। इसी चेतना अवस्था में सट्टा बाजार (stock exchange) अधिक सक्रिय हो जाते हैं।

चेतना अवस्था में सहस्रियों में आशावादिता (Optimism) व्यापार में आशावाद को जन्म देकर विनियोग के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। साध की माँग तथा बैंक ऋणा की माँग बढ़ने लगती है। व्यापारिक क्रियाओं में तथा साधना की कीमतें बढ़ने से धन्य बढ़ते हैं। जिसने पुनः समाज में साधना की आय बढ़ती है जिससे पुनः धन्य बढ़ते हैं। इस प्रकार चेतना अवस्था के एक बार प्रारम्भ होने पर अवस्था का पुनः एक नई शक्ति मिलती है और चेतना की अवस्था शीघ्र ही समृद्धि की धारा में मिल जाती है और चक्र की पुनरावृत्ति होती है।

चेतना की अवस्था शक्ति और समयावधि की दृष्टि अलग-अलग होती है अथवा यह कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि किन शक्तियों द्वारा इस का जन्म हुआ है। उदाहरणार्थ चेतना अवस्था का प्रारम्भ नव प्रवर्तन अथवा नये क्षेत्रों में, नये उत्पादों अथवा मनुष्य के समय की पूजा जो व्यय थी उसे कार्यशील बनाकर अथवा सरकार द्वारा नये कार्य आरम्भ करके आदि आदि कारणों से चेतना अवस्था का प्रारम्भ हो सकता है और यही कारण है कि चेतना अवस्था का रूढ़ शक्ति और प्रभाव कैसा होगा इसे जानने के लिए हम इस अवस्था को प्रारम्भ करने वाले कारणों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

जो (i) अर्थात् गुणव और (ii) अर्थात् चक्र के विभिन्न मूल्या पर निर्भर करती है। यह स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं—

(i) आय में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर घटती दर से परिवर्तन होता है। और आय नये संतुलन प्राप्त कर लेती है।

(ii) आय होने वाले उच्चावचन समय चक्र के आधार पर होता है।

(iii) आय में बढ़ती हुई समय सारणी के अनुसार परिवर्तन होता है।

(iv) आय में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर बढ़ती हुई दर से परिवर्तन होता है।

(v) स्थिर आयों के समय चक्र के अनुसार आय में परिवर्तन होता है।

व्यापार चक्र नियन्त्रण सबन्धी नीति (Policy to control Trade cycle)

व्यापार चक्र एक जटिल प्रक्रिया है इनमें घटित होने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। व्यापार चक्र को नियन्त्रित करने हेतु कौन सी नीति अपनानी चाहिए इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद नहीं है। अधिकांश विद्वानों व्यापार चक्र की घटनाओं को एक आवश्यक और स्वयं घटित होने वाली प्रक्रिया मानते हैं परन्तु इन बातों से सभी एकरूप प्रतीत होता है कि व्यापार चक्रों की तीव्रता को कम तथा इनमें घटित होने में विलम्ब अवश्य किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्न नीति प्रयासों की प्रवृत्ति अवरोधक एवं उपचारमय हो सकती है।

व्यापार चक्र के रूप में उत्पन्न संकट के रोकने अथवा उसको समाप्त करने की बात संकट उत्पन्न करने वाले कारणों पर निर्भर करती है। सामान्यतः व्यापार चक्र का रोकना के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाने की सलाह दी जाती है अर्थात् निम्न नीतियों को अपनाने से व्यापार चक्र के संकट या उसका तीव्रता को कम तथा किसी हद तक समाप्त किया जा सकता है।

(1) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)—व्यापार चक्रों को रोकने एक उचित मौद्रिक नीति अपनाने की सलाह दी जाती है। एक उचित मौद्रिक नीति का अनुसरण करके तेजी तथा मंदी की स्थिति को रोका जा सकता है। यदि किसी कारणवश इन्हे रोकना सम्भव न भी हो तो भी उचित मौद्रिक नीति द्वारा व्यापार वृद्धि तथा मंदी के परिणामों को घटाता तथा आर्थिक स्थिरता की यथासम्भव प्राप्त किया जा सकता है।

मौद्रिक नीति में ऋण तथा ब्याज से सम्बन्धित बैंकिंग तथा साख्य नीति, मौद्रिक मानक (monetary standard) तथा इनके प्रबन्ध को शामिल किया जाता है। मुद्रा की मात्रा को प्रभावित बैंक साख्य तथा उसके द्वारा कीमतों तथा आर्थिक क्रियाओं के सामान्य स्तर को प्रभावित किया जा सकता है। इसके सहस्रपूर्ण साधनों में बैंक दर निर्धारण तथा स्वतन्त्र बाजार कार्य आते हैं। जब व्यापारिक क्रियाएँ विस्तार की प्रवृत्ति दिखा रही हो तो बैंक दर बढ़ जाती है व्यापारिक क्रियाओं के अनुचित विस्तार के कारण साख्य की मात्रा कम हो जाती है। बैंक साख्य पर रोक लगाकर निरन्तरशील प्रवृत्ति पर रोक लगाते हैं। मंदी के समय अर्थव्यवस्था में निराशावादिता को सह्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में शुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) अपनाना चाहिए जिससे कि व्यापारिक क्षेत्र में निवेश की मात्रा बढ़ाई जा सक।

बैंक साख्य नीति द्वारा दो प्रकार से नियन्त्रण होता है मुद्रात्मक तथा परिमाणात्मक। परिमाणात्मक नियन्त्रण का सम्बन्ध सामान्य साख्य अवस्था से है। इनके द्वारा बैंक की प्रतिभूतियाँ प्रभावित होती हैं। साख्य नीति द्वारा व्यापारिक क्रियाओं को वांछित दिशा में लाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

वर्ष 1930 से पहले व्यापार चक्र विरोधी नीति के रूप में मौद्रिक नीति एक उपयुक्त तथा प्रभावशाली नीति मानी जाती थी। मौद्रिक नीति की सफलता के लिए यह जरूरी है कि देश के केन्द्रीय बैंक के नेतृत्व को व्यापारिक बैंक इतना सहत्व देते हैं। बैंक अपने ऋणियों को दी जाने वाली साख्य का प्रयोग करने के लिए जितना तैयार पाने हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें साख्य प्रदान की गई है तथा क्या व्यापारी वर्ष बदलती हुई बैंक दरों के अनुरूप अपने आप को समायोजित कर सगा या नहीं।

मौद्रिक नीति सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ आसिक्त रूप से सत्य होती हैं इसलिए मौद्रिक नीति की उपयोगिता सीमित होती है। मंदी के समय मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध रहती है जैसा कि तीसरा की विश्वव्यापी मंदी से विदित है। मंदी की अवस्था में व्यापारिक क्षेत्र में निराशावादिता की सह्य हो जाती है और सस्ती मुद्रा नीति तथा ब्याज की दर में समुचित कटौती करों पर भी निवेशों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। नीची ब्याज की दर केवल मुद्रा की तरलता बढ़ाता है। मंदी के समय पूँजी की सीमान्त उत्पन्न-दकता की दर ब्याज की दर से निवेशों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। केवल सरकारी प्रयासों द्वारा प्रभावपूर्ण माँग बढ़ाकर पूँजी निवेश का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है।

(ii) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)—राजकोषीय नीति का प्रयोग मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में हुआ या जब मौद्रिक नीति अप्रभावी और अनुपयुक्त हो जाती है तो राजकोषीय नीति व्यापार चक्रों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इससे दो साधन प्रमुख हैं। (i) सरकारी राजस्व तथा (ii) सरकारी व्यय। इसका मतलब वजट नीति, बचत को प्रोत्साहन ऋण सम्बन्धी नीति आदि द्वारा राजकोषीय नीति अपनाई भवमान समय में बहुधा यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी व्यय के रूप में होता है। राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व व राशियों

तथा सरकारी व्यय का महत्वपूर्ण योगदान है जैसा कि हमने देखा प्रो० योन्स का विचार है कि व्यापार चक्रों के लिए बचत एवं निवेश के मध्य असन्तुलन की स्थिति का आना होता है। ऐसी स्थिति में सरकार तथा उसने निश्चायो के पूंजीगत व्ययों को गैर सरकारी निवेशों के साथ संभाव्योजन किया जा सके तो असन्तुलन की स्थिति को रोका जा सकता है तो आर्थिक स्थिरता का वातावरण बनाया जा सकता है। यदि फिर भी इन दोनों अर्थात् बचत एवं निवेश के मध्य असमानता बनी रहे तो उस सरकारी व्यय द्वारा समायोजित करने के प्रयास हो सकते हैं। तेजीवात में जब सरकारी व्यय अधिक हो रह हा, साग्र की मात्रा अधिक हो तो सरकार को सन्तुलित बजट नीति का सहारा लेना चाहिए।

जब अर्थव्यवस्था मन्दी की खपेट में हो तो सरकार को घाटे के बजट (Deficit Budget) बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विभिन्न करों को हटा कर कम करों में छूट उदार शर्तों पर ऋण आकर्षण आदि करना चाहिए जिससे वि प्रभावपूर्ण मांग बढ़े रोजगार के साधनों को अधिनाधिक रोजगार मिले और आयातवादिता के दूषितकरण को सागर अर्थव्यवस्था को मन्दी से उबार जा सके।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय (International Measures)—व्यापार चक्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना है इसलिए इसे रोकने में एक देश द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय उपायों को अपनाने की सलाह दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादनी नियन्त्रण अर्थात् प्राथमिक उत्पादनों की कीमतों तथा उत्पादन सम्बन्धी उपाय अपनाने से सहाह दी जाती है। इस प्रकार के नियन्त्रण की अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जैह कई देशों में कृषि छोटे स्तर पर होते हुए भी जीविका का प्रमुख साधन है। परन्तु यह लाभदायक न होते हुए भी चालू रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादना नियन्त्रण मांग और पूर्ति में होने वाले आवस्मिक परिवर्तनों को समुक्त करके उनकी कीमतों में होने वाला वृद्धि और नियन्त्रण रखकर अर्थव्यवस्था को उच्चावचनों (fluctuations) से रोकता है।

इसी प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशों को नियन्त्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय निवेश नियन्त्रण प्रायः विकासशील अर्थव्यवस्था में लागू किया जाता है।

(iv) नियमित विकास (Steady growth)—ऐसा कहा जाता है व्यापारिक उतार चढ़ाव आधुनिक औद्योगिक जीवन की तीन मूलभूत विशेषताओं के अभाव में नहीं पाए जायेंगे। जैसे अनेक वस्तुओं का टिकाऊपन, उत्पादन की जटिल तथा समय लगने वाली संरचना तथा मुद्रा का प्रयोग। यदि वस्तुओं में टिकाऊपन की कमी है तो जो चीजें अन्तिम रूप से उत्पादित होगी वे उपभोक्ताओं की मांग के ठीक बराबर रहेगी। यदि मांग में परिवर्तन होगा तो आनुपातिक रूप से पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा।

यह तीनों पहलू एक औद्योगिक समाज की व्यापक तथा केन्द्रीय विशेषताएँ हैं। यह एक नियन्त्रित एवं नियोजित समाजवादी व्यवस्था में भी पाई जा सकती हैं। ऐसा समाज में भी यह विचार करना पड़ता है कि नव-प्रयत्नों को वहाँ जल्दी लाया जाए या धीरे-धीरे। व्यापारिक उतार-चढ़ाव आज के औद्योगिक पूंजीवादी समाज के आवश्यक अंग हैं। हमें नियमित विकास के विचार के साथ अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ हमें व्यापार चक्र के मोड़ों (turning points) तथा व्यापार चक्र की शिखा तथा प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखना चाहिए।

व्यापार चक्र एवं जटिल एवं महत्वपूर्ण घटना है और इसके लिए एक नहीं बरन् अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। हमने निवारण हेतु हम विभिन्न उपाय अपनाने पड़ते हैं। यह समझना कठिन नहीं है कि व्यापार चक्र दीर्घकालीन विकास पथ को और दीर्घकालीन विकास पथ व्यापार चक्र को प्रभावित बना देता है।

निष्कर्ष—व्यापार चक्र जैसी गैरवादी घटना के समाधान के लिए कोई एक सरल एवं निश्चित उपाय नहीं है। वाल्ट फावर्स ने व्यापार चक्र को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यक बीमारी की सजा दी है उनका कहना था कि यदि अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र की बुराईयों से दूर करना है तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके ऐसा किया जा सकता है। प्रो० हैन्सन के विचार इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं वे कहते हैं कि 'व्यापार चक्र आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी विचित्र विशेषता है कि इस पर नियन्त्रण करना सरल कार्य नहीं है। व्यापार चक्र यतिशील समाज की एक ऐसी निहित विशेषता है जिसकी उपस्थिति का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में निवेश के आकार में होने वाले निरन्तर परिवर्तन हैं। यह परिवर्तन उस समय भी विद्यमान रहेंगे जब अर्थव्यवस्था की स्वस्थ अवस्था हो जायेगी। व्यापार चक्रों को नियन्त्रित करने के लिए समय-समय पर मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का समान्यतः प्रयोग किया गया है।

परीक्षा प्रश्न

1. व्यापार चक्र क्या है ? इससे सक्षम विशेषताओं तथा निवारण को बताइए।
(What is trade cycle ? Give its characteristics phases and remedies)
2. व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं ? व्यापार चक्र के विभिन्न रूप क्या हैं ?
(What do you understand by trade cycle ? What are the types of trade cycle ?)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत का चयन करें।

- (i) व्यापार चक्र पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य घटना है।
- (ii) व्यापार चक्रों को मापना एक कठिन कार्य है।
- (iii) व्यापार चक्र एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी लागू होते हैं।
- (iv) व्यापार चक्रों को नियन्त्रित करना आसान है।
- (v) व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

(i) सही है। (ii) सही है। (iii) गलत है। (iv) सही है। (v) गलत है।

1. A H Hansen